TEXT LITE & DARK WITHIN THE BOOK ONLY

FLYING TEXT WITH IN THE BOOK ONLY.

UNIVERSAL
LIBRARY
OU_176559
UNIVERSAL
LIBRARY

भारत

(वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ)

1954

पब्लिकेशन्स डिवीजन
मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग
भारत सरकार

प्रसार तथा सूचना मन्त्रालय के रिसर्च एण्ड रैफरेन्स डिवीजन द्वारा संगृहीत तथा पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा सम्पादित ।

(7 रुपया 8 आना)

मैनेजर, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित
तथा
डाइरैक्टर, पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड सैक्रेटेरियट, दिल्ली द्वारा प्रकाशित

वक्तव्य

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से देश में जो असाधारण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे है और जिस रफ़्तार मे भारत उन्नति पथ पर अग्रसर हो रहा है, उनके कारण भारत के सभी क्षेत्रो के सम्बन्ध मे विश्वसनीय और प्रामाणिक सूचनाओ और गणनाओं का महत्व और भी अधिक बढ गया है। इसी कारण 1953 मे अंग्रेजी में एक सन्दर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन जारी किया गया था। इस वर्ष हिन्दी में भी इस सन्दर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन प्रारम्भ करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता अनुभव हो रही है।

इस सन्दर्भ ग्रन्थ के लिए रिसर्च एण्ड रैफरेन्स डिवीजन ने सामग्री एकत्र की और इसका सम्पादन पब्लिकेशन्स डिवीजन ने किया है। भविष्य में हम इस प्रकाशन को और भी अधिक उपयोगी बनाने का अधिकाधिक प्रयत्न करेगे।

दीपावली
26 अक्तूबर, 1954

पब्लिकेशन्स डिवीजन

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ
1.	भारत भूमि और उसके निवासी	1—34
2.	संविधान	35—45
3.	राष्ट्र के प्रतीक	46—48
4.	यूनियन सरकार और पार्लियामेंट	49—78
5.	न्याय विभाग	79—93
6.	सार्वजनिक सेवा	94—97
7.	प्रतिरक्षा	98—104
8.	सार्वजनिक वित्त	105—151
9.	पंचवर्षीय आयोजना	152—166
10.	कृषि	167—190
11.	सामूहिक विकास	191—197
12.	विद्युत शक्ति तथा सिंचाई	198—218
13.	वैज्ञानिक शोध	219—227
14.	उद्योग धन्धे	228—253
15.	वाणिज्य	254—263
16.	परिवहन	264—285
17.	डाक और तार	286—299
18.	सहकारी आन्दोलन	300—309
19.	शिक्षा	310—324
20.	स्वास्थ्य	325—344
21.	श्रम	345—378
22.	पत्र पत्रिकाएं, फिल्में और रेडियो द्वारा प्रसार	379—387
23.	पुनर्वास	388—402
24.	अनुसूचित जातियां, अनुसूचित उपजातियां और पिछड़े हुए वग	403—414
25.	"क" भाग के राज्य	415—485
26.	"ख" भाग के राज्य	486—518
27.	"ग" भाग के राज्य तथा "घ" भाग के प्रदेश	519—535
28.	खेल	536—544
29.	1953 की घटनाओं की सूची	545—551
30.	वर्ष के कानून	552—556
31.	सामान्य जानकारी	557—578

बच्चे को प्रसन्न रखिए

जब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाये तो उसे
अत्यन्त स्वादिष्ट 'नरिशिंग बिस्कुट' दीजिए और वह तुरन्त
हंसने लगेगा। नरिशिंग बिस्कुट' में भरपूर विटामिन होते हैं

जे० बी० मंघाराम के

NOURISHING

'नरिशिंग बिस्कुट'
विटामिनों से भरपूर हैं

J. B. MANGHARAM & CO.
GWALIOR

जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी, ग्वालियर
फ़तेहपुरी, दिल्ली और कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में भी दुकानें हैं

राम तीर्थ ब्राह्मी तैल

(स्पेशल नं० १)

आयुर्वेदिक औषधि (रजिस्टर्ड)

स्मरण शक्ति बढ़ती है, गाढी निद्रा आती है तथा बाल काले होते है । आखो मे डालने से आखो की रोशनी बढ़ती है ।

कान मे डालने से कान के सब रोग मिटते है । गजापन दूर होता है । सब ऋतुओ मे उपयोगी ।

कीमत --बड़ी शीशी ३।।) छोटी शीशी २) रु०

प्रत्येक स्थान पर मिलता है ।

५।।।-) का मनीआर्डर बड़ी शीशी के लिये तथा ३।।-) का मनीआर्डर छोटी शीशी के लिये (डाक व्यय मिलाकर) भेजे ।

उपरोक्त पते पर प्रात ७।। बजे से ९।। बजे तक और सांयकाल ६ से ७।। बजे तक योग की कक्षाएं नियमित रूप स (रविवार की छुट्टी) लगती है । स्वस्थ बनने और ठीक रहने के लिये हमारा आकर्षक मानचित्र मंगाइये जिसमें योग के आसन दिखाये गये है और जो एक रुपया बारह आने मिलने पर भेज दिया जायेगा । घर पर इन आसनों को बड़ी सरलता से किया जा सकता है ।

श्री रामतीर्थ योगाश्रम

दादर (सैन्ट्रल रेलवे) बम्बई १४

टेली :--६२८९९ ग्राम्स :—"PRANAYAM"

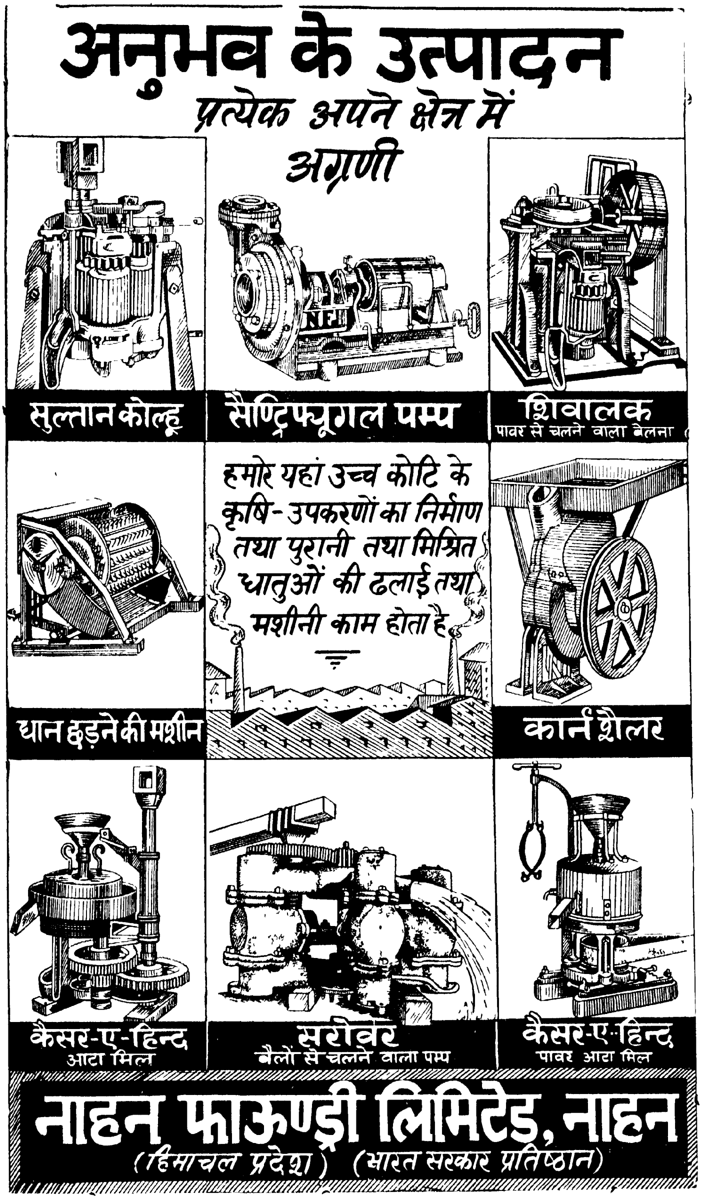
अनुभव के उत्पादन
प्रत्येक अपने क्षेत्र में अग्रणी
सुल्तान कोल्हू
सैण्ट्रिफ्यूगल पम्प
शिवालक
पावर से चलने वाला बेलना
हमारे यहां उच्च कोटि के कृषि-उपकरणों का निर्माण तथा पुरानी तथा मिश्रित धातुओं की ढलाई तथा मशीनी काम होता है
धान छड़ने की मशीन
कार्न शैलर
कैसर-ए-हिन्द
आटा मिल
सरोवर
बैलों से चलने वाला पम्प
कैसर-ए-हिन्द
पावर आटा मिल
नाहन फाऊण्ड्री लिमिटेड, नाहन
(हिमाचल प्रदेश) (भारत सरकार प्रतिष्ठान)

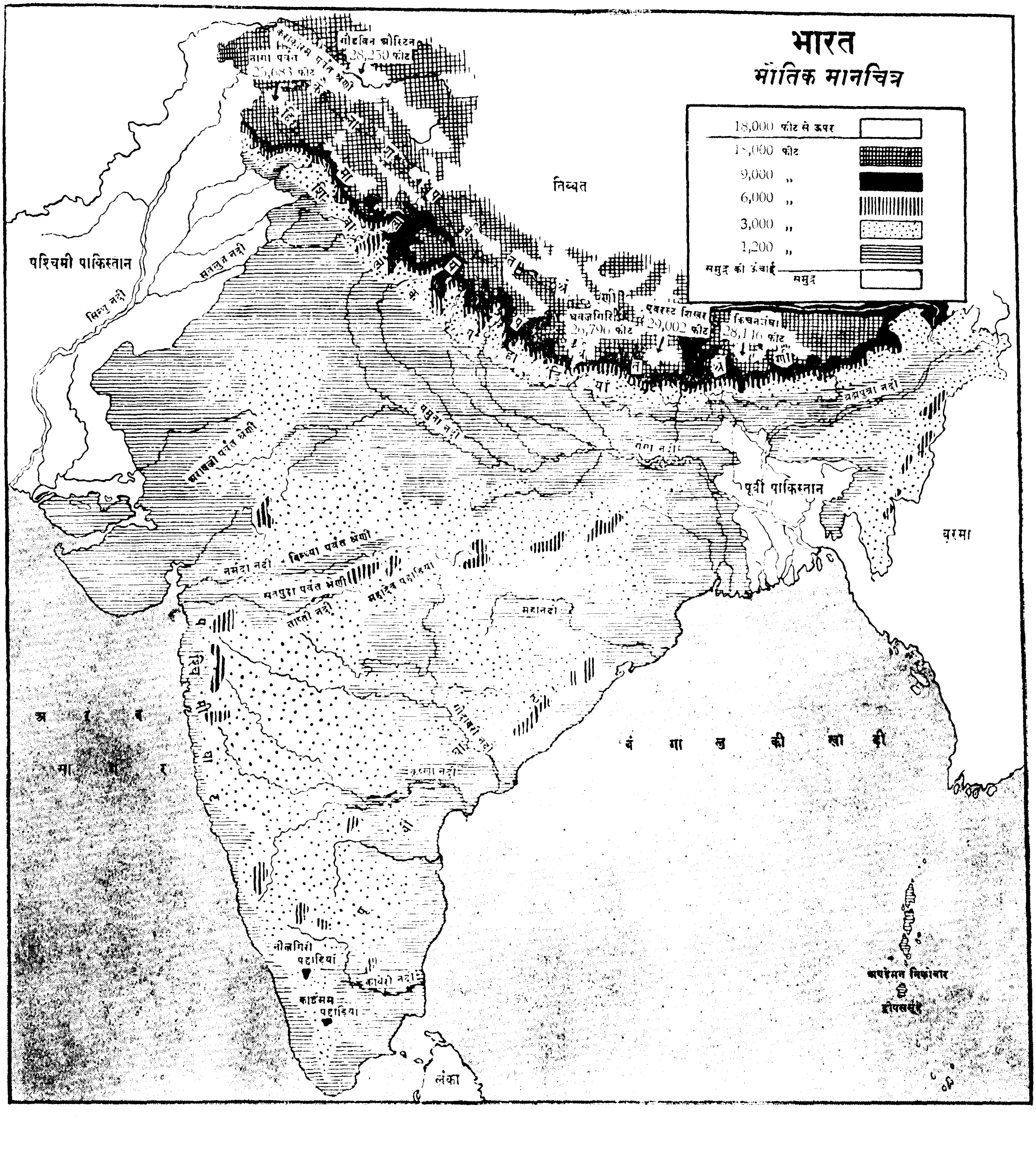

भारत
भौतिक मानचित्र
18,000 फीट से ऊपर
18,000 फीट
9,000 ,,
6,000 ,,
3,000 ,,
1,200 ,,
समुद्र की ऊंचाई
समुद्र
तिब्बत
पश्चिमी पाकिस्तान
सतलुज नदी
सिन्धु नदी
गौडविन ऑस्टिन 28,250 फीट
नागा पर्वत
काराकोरम पर्वत श्रेणी
धवलगिरि 26,795 फीट
एवरेस्ट शिखर 29,002 फीट
किंचनजंघा 28,146 फीट
ब्रह्मपुत्र नदी
गंगा नदी
यमुना नदी
अरावली पर्वत श्रेणी
पूर्वी पाकिस्तान
बरमा
विन्ध्या पर्वत श्रेणी
नर्मदा नदी
सतपुरा पर्वत श्रेणी
महादेव पहाड़ियां
ताप्ती नदी
महानदी
गोदावरी नदी
कृष्णा नदी
नीलगिरी पहाड़ियां
कावेरी नदी
कार्डमम पहाड़ियां
लंका
अण्डेमन निकोबार द्वीपसमूह
बं गा ल की खा ड़ी

पहला अध्याय

भारत भूमि और उसके निवासी

भूमि

एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि मे से जो तीन टेढे-मेढे प्रायद्वीप समुद्र मे बाहर की ओर निकले हुए है, उनमे से बीच का प्रायद्वीप भारत है । एशिया के मध्य-दक्षिणी भाग से वह हिमालय की ऊची पर्वतमाला द्वारा जुडा हुआ है और यह उसका उत्तरी छोर है, जहा से दक्षिण की ओर सुदूर हिन्द महासागर तक उसका विस्तार है । उसके पूर्व मे बगाल की खाडी है और पश्चिम मे अरब समुद्र । भूमध्य रेखा के उत्तर मे 8° से लेकर 37° उत्तरी अक्षाश रेखाओ तथा 66°20 से लेकर 97° पूर्वी देशाश रेखाओं के बीच यह देश अवस्थित है । कर्क रेखा इसे प्राय दो बराबर के भागो मे बाटती है । देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबन्ध मे पडता है और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबन्ध मे । देश की भू-सीमा रेखा 8,200 मील लम्बी है और समुद्रतट रेखा 3,500 मील ।

शानदार हिमालय ससार की सबसे अधिक दुर्लघ्य प्राचीर है, और वही भारत की उत्तरी सीमा है जिस पर तिब्बत, भूटान, सिक्किम और नेपाल अवस्थित है । पूर्व मे कुछ पर्वतमालाए भारत और वर्मा को अलग करती है । उत्तर-पूर्व मे पश्चिमी बगाल और आसाम के बीच पूर्वी पाकिस्तान अवस्थित है । उत्तर-पश्चिम मे भारत और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाए मिलती है । बगाल की खाडी मे स्थित अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह भी भारतीय सघ के अन्तर्गत है ।

लगभग 12,69,640 वर्गमील मे फैले हुए इस भारतीय यूनियन मे कुल 29 राज्य है, जिनमे जम्मू और काश्मीर भी सम्मिलित है । इनमे से सब से नया राज्य आन्ध्र है, जिसका जन्म अक्तूबर 1953 मे हुआ था । क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत ससार का सातवा देश है । वह सयुक्त राज्य ब्रिटेन से प्राय: 13 गुना और जापान से 8 गुना बडा है । उसका क्षेत्रफल कैनाडा के क्षेत्रफल का एक तिहाई और रूस का सातवा भाग है ।

प्राकृतिक बनावट

सम्पूर्ण देश को तीन सुनिश्चित प्रदेशो मे बाटा जा सकता है :—(1) महान हिमालय पर्वत-शृङ्खला वाला प्रदेश, (2) सिन्ध-गगा का मैदान और (3) प्रायद्वीप का दक्षिणी पठार । हिमालय प्राय: तीन समानान्तर पर्वत श्रेणियो से मिल कर बना है, जिनके बीच मे लम्बे चौडे पठार और घाटियां है, जैसे काश्मीर और कुल्लू की घाटिया, जो बडी उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न है । इन पर्वत श्रेणियो मे ससार की कुछ सबसे ऊची चोटिया पाई जाती है, जैसे एवरस्ट (29,141 फीट), माउण्ट गॉडविन ऑस्टिन (28,250 फीट), और कंचनजघा (28,146 फीट)। अधिक ऊचाई के कारण कुछ ही दर्रों से आना-जाना सम्भव है,

विशेषत "जेलेप ला" और "नाट् ला" दर्रे जो दार्जिलिंग के उत्तर मे चम्बी की घाटी से होकर जाने वाले भारत-तिब्बत व्यापार के मुख्य मार्ग है । उत्तर पश्चिम स्थित पामीर की शृङ्खला सन्धि से लेकर आसाम की सीमा तक पर्वत की दीवार प्राय 1500 मील तक फैली हुई है । पूर्व मे बर्मा और भारत के बीच पर्वत श्रेणियो की ऊंचाई अपेक्षाकृत काफी कम है और विभिन्न स्थानो मे उनके विभिन्न नाम है, जैसे आसाम के उत्तर-पूर्व मे पटकाई और नागा पहाडियां और दक्षिण-पश्चिम मे जैन्तिया, खासी और गारो पहाडिया ।

एक ओर हिमालय पर्वत और दूसरी ओर प्रायद्वीप के बीच स्थित सिन्ध-गगा का मैदान पूर्वी पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक प्राय 1500 मील लम्बा है । इस में पजाब की सतलुज, व्यास के अतिरिक्त गगा और उसकी सहायक नदिया, यमुना, गोमती, घाघरा और गण्डक नदिया बहती है । ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार से निकलती है, और भारत मे धुर पूर्वीय सीमा पर प्रवेश करती है । आसाम और पूर्वी बगाल से होकर बहती हुई वह गगा के बगाल की खाडी मे गिरने से पहले ही उससे मिल जाती है ।

प्रायद्वीप का पठार सिन्ध-गगा के मैदान से कई पर्वत श्रेणियों द्वारा, जिनकी ऊंचाई 1500 फुट से लेकर 4000 फुट तक है, पृथक है । इनमे से प्रमुख श्रेणिया अरावली, विन्ध्य, सतपुडा, मैकल और अजन्ता है । प्रायद्वीप के एक ओर पूर्वी घाट पर्वतमालाए है, जिनकी औसत ऊचाई 1500 फुट है । दूसरी ओर पश्चिमी घाट पर्वतमालाए है, जिनकी औसत ऊचाई 3000 फुट है पर कही कही वह 9000 फुट तक भी ऊची है । प्रायद्वीपी पठार चट्टानी और ऊबड खाबड है और दूर दक्षिण की उन पर्वत श्रेणियो तक फैला हुआ है, जिनकी ऊचाई कही कही 4000 फुट तक है । इनमे से नीलगिरि और कार्डेमम श्रेणिया उल्लेखनीय है । पठार के आरपार नर्मदा और ताप्ती नदिया बहती है, जो अरब सागर मे गिरती है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बहती है, जो बगाल की खाडी मे गिरती है ।

जलवायु

भारत का जलवायु मुख्यत वर्षा प्रधान सम-शीतोष्ण है। निस्सन्देह स्थानीय परिवर्तन इसमे विद्यमान है । भारत के जलवायु पर मौसम की हेर-फेर का स्पष्ट और सीधा प्रभाव रहता है और यहा मौसम का बटवारा इस प्रकार किया जा सकता है —

(क) अक्तूबर से फरवरी के अन्त तक सर्दी का मौसम,

(ख) मार्च के आरम्भ से जून के अन्त तक गर्मी का मौसम,

(ग) जून के अन्त से सितम्बर के अन्त तक वर्षा का मौसम ।

उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम का उप-विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है —(1) जनवरी से फरवरी तक सर्दी का मौसम, (2) मार्च से जून तक गर्मी का मौसम । इसी प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसून का उप-विभाजन इस प्रकार है :—(1) जून से सितम्बर के मध्य तक वर्षा का मौसम और (2) अक्तूबर से दिसम्बर तक मानसून की वापसी का मौसम ।

जनवरी मे सब से अधिक सर्दी पडती है, फिर भी उत्तर से दक्षिण तक के तापमान म बहुत अन्तर रहता है । दिन प्रायः गर्म होते है और राते निश्चित रूप से सर्द । जनवरी के तापमान का औसत पंजाब मे 55° फारनहाइट, गगा की घाटी मे लगभग

60° फा० और मद्रास में लगभग 75° फा० होता है। अप्रैल और मई में भारत में सूर्य की किरण सीधी पडती है, और इसी से ये सबसे अधिक गर्म महीने होते है। मई मे उत्तर-पश्चिम भारत मे मैदानों का अधिकतम तापमान 110° फा० से भी बढ़ जाता है, यद्यपि औसत तापमान 100° फा० से कुछ ऊपर होता है। गंगा के डेल्टा में औसत तापमान 85° फा० होता है। प्राय. जून के मध्य में वर्षा शुरु हो जाती है और तेज गड़गडाहट और कौंध के साथ मूसलाधार पानी पडने लगता है। भारत के अधिकांश भागो मे, जहा उत्तर-पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है, जून और सितम्बर के बीच वर्षा होती है। मद्रास के समुद्र तट को छोड़ कर भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा केवल तिरुवाकर कोचीन और मद्राम के कुछ भागो मे होती है।

भारत

वर्ष का औसत धरातल तापमान

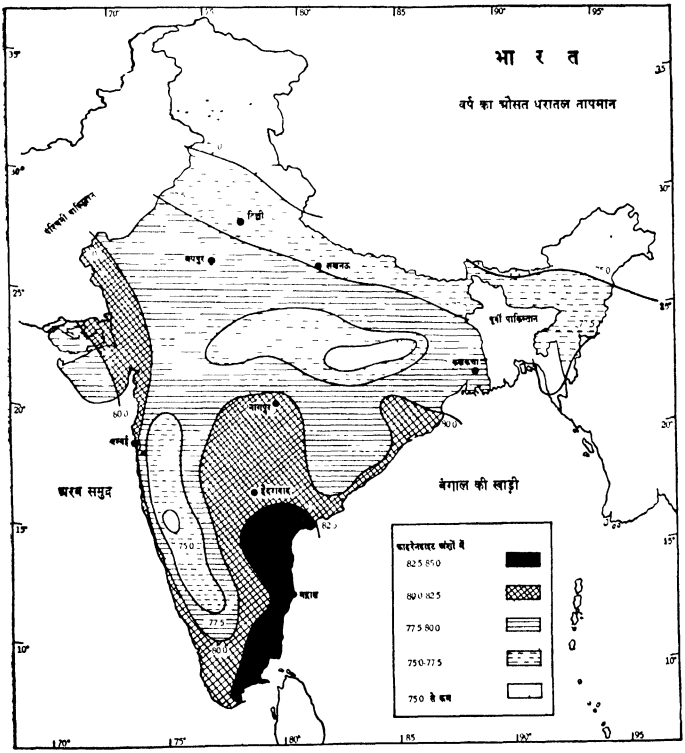

तालिका 1

छाया मे मासिक और वार्षिक अधिकतम तापमान (फाहरेनहाइट अंशों में)

केन्द्र	फुटो मे ऊचाई	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	वार्षिक
पार्वत्य केन्द्र:														
दार्जिलिंग	7,432	47·0	47·8	55·4	61·2	62·9	64·9	65·7	65·6	64·6	61·7	55·6	50·5	58·6
शिलांग	4,921	60·1	62·5	70·4	74·1	74·0	74·5	75·3	75·1	74·3	71·1	66·0	61·6	69·9
शिमला	7,224	47·5	48·8	57·0	65·9	73·2	75·1	70·9	68·4	68·4	64·3	58·3	50·6	62·4
तटीय केन्द्र:														
बम्बई	35	83·2	83·1	86·2	89·1	91·1	88·5	85·5	85·0	85·5	88·8	89·4	86·6	86·8
मद्रास	51	85·3	88·3	91·4	95·5	101·3	99·6	96·3	94·8	93·9	90·1	85·4	84·1	92·2
मैदानी केन्द्र:														
इलाहाबाद	332	74·8	79·2	91·7	102·6	107·1	102·7	92·1	89·4	91·5	90·4	83·4	75·7	90·1
कलकत्ता	21	79·6	83·7	92·5	96·8	95·6	92·4	89·5	89·0	89·9	89·2	84·2	79·4	88·5
कानपुर	413	71·9	77·0	89·4	99·4	106·2	102·7	92·4	89·7	90·9	91·2	82·8	74·0	89·0
कटक	87	83·1	88·2	96·6	101·2	101·4	95·5	89·5	89·0	90·0	89·7	85·0	81·2	90·9
नई दिल्ली	710	70·5	74·7	85·0	96·6	104·8	102·4	95·3	93·0	93·5	92·5	83·2	73·7	88·8
लखनऊ	371	73·9	78·6	90·8	101·4	105·4	100·2	92·4	90·5	91·9	91·4	83·9	75·9	89·7
पटना	173	73·0	77·8	89·8	98·9	100·3	96·2	90·7	89·1	89·7	88·6	82·1	74·6	87·6
पठारों के केन्द्र:														
देहरादून	2,239	66·1	69·3	79·4	90·0	96·0	93·7	86·5	84·5	84·8	82·9	75·4	68·7	81·4
नागपुर	1,010	83·7	88·2	96·7	104·2	108·7	99·5	88·3	87·3	89·8	90·6	85·5	81·7	92·0

तालिका 2

छाया म मासिक तथा वार्षिक न्यूनतम तापमान (फाह्रेनहाइट अशो मे)

केन्द्र	फुटो मे ऊचाई	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	वार्षिक
पार्वत्य केन्द्र.														
दार्जिलिंग		35.4	36.6	43.0	48.8	52.4	56.5	58.0	57.7	56.0	50.2	43.1	36.6	47.9
शिलांग		38.8	42.4	50.8	57.0	59.1	63.0	64.6	64.0	61.6	54.8	46.2	40.0	53.5
शिमला	ऊचाई के	35.4	36.1	43.6	50.6	57.7	60.1	59.2	59.2	56.3	51.4	44.2	39.3	49.4
तटीय केन्द्र :	लिए देखो													
बम्बई	तालिका	66.7	67.4	71.9	76.1	79.6	78.6	76.7	76.1	75.7	75.6	72.5	68.8	73.8
मद्रास	न० 1	67.1	68.4	72.4	78.1	81.7	81.1	79.3	78.0	77.2	75.0	71.9	68.9	74.9
मैदानी केन्द्र·														
इलाहाबाद		47.1	50.9	61.0	71.4	79.9	82.9	79.8	78.5	76.6	67.1	54.3	47.1	66.4
कलकत्ता		54.6	59.4	68.8	75.5	77.5	78.6	78.6	78.3	78.0	73.8	63.7	55.0	70.2
कानपुर		45.7	51.0	60.1	70.6	80.4	83.0	79.9	78.7	76.2	66.0	53.9	46.5	66.0
कटक		59.8	64.8	71.8	77.5	79.9	79.6	78.3	78.1	77.8	74.4	65.8	58.7	72.2
नई दिल्ली		43.3	49.2	57.1	67.7	78.8	82.5	80.1	78.4	75.5	64.3	51.8	45.0	64.5
लखनऊ		47.1	51.4	60.6	70.8	78.3	81.7	79.5	78.6	76.5	66.5	54.1	47.3	66.0
पटना		51.1	54.8	64.3	73.5	78.1	79.9	79.9	79.7	78.9	72.8	61.0	52.3	68.9
पठारों के केन्द्र														
देहरादून		44.0	46.6	54.1	62.5	70.1	74.1	73.8	72.9	69.5	60.3	51.1	45.1	60.3
नागपुर		56.0	59.9	66.7	74.5	80.9	79.6	75.5	75.0	74.2	66.5	59.1	53.8	68.5

तलिका 3

मासिक तथा वार्षिक वर्षा (इंचों में)

केन्द्र	ऊंचाई फुटों में	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	वार्षिक
पार्वत्य केन्द्र:														
दार्जिलिंग		0·53	1·19	1·88	4·14	9·63	24·18	32·92	26·56	18·90	5·41	0·81	0·27	126·42
शिलांग		0·52	1·06	1·97	5·10	11·29	18·16	13·65	12·49	11·79	6·72	1·61	0·28	84·64
शिमला		2·61	2·92	2·36	1·81	2·53	6·04	16·30	16·85	6·68	1·18	0·52	1·24	61·04
तटीय केन्द्र:	देखो													
बम्बई	तालिका	0·14	0·08	0·05	0·03	0·65	19·06	24·27	13·39	10·39	2·54	0·53	0·08	71·21
मद्रास	नं० 1	1·41	0·41	0·29	0·61	1·03	1·86	3·60	4·58	4·68	12·04	13·96	5·45	49·92
मैदानी केन्द्र:														
इलाहबाद		0·85	0·63	0·56	0·17	0·63	5·04	12·56	10·03	8·36	2·34	0·31	0·34	41·82
कलकत्ता		0·37	1·17	1·36	1·75	5·49	11·69	12·81	12·92	9·95	4·48	0·81	0·18	62·98
कानपुर		0·56	0·66	0·29	0·22	0·32	3·19	10·75	11·20	5·79	1·30	0·35	0·28	35·91
कटक		0·32	0·78	1·04	1·07	3·57	9·95	12·89	13·40	9·76	5·34	1·62	0·23	59·97
नई दिल्ली		0·99	0·83	0·51	0·33	0·52	3·03	7·03	7·23	4·84	0·40	0·10	0·43	26·24
लखनऊ		0·76	0·72	0·34	0·25	0·77	4·46	12·00	11·50	7·40	1·28	0·22	0·32	40·02
पटना		0·59	0·74	0·42	0·27	1·40	7·14	11·58	13·09	8·60	2·30	0·34	0·22	46·69
पठारों के केन्द्र:														
देहरादून		2·32	2·47	1·26	0·65	1·45	8·55	26·30	28·79	10·62	1·26	0·35	1·02	85·04
नागपुर		0·37	0·65	0·60	0·60	0·76	8·82	14·60	11·42	8·01	2·17	0·77	0·47	49·24

प्राकृतिक साधन

खनिज पदार्थ

सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है, जिसे गोडवाना भी कहते है। इसके अन्तर्गत दक्षिण बिहार का भाग, दक्षिण-पश्चिमी बगाल और उत्तरी उडीसा आते है। देश को कोयले, लोहे, अभ्रक और ताबे का अधिकाश भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। झरिया और रानीगज की कोयला खानो से कोयले का प्रमुख भाग प्राप्त होता है। साथ ही लिग्नाइट के रूप मे कोयला दक्षिण-पूर्वी हैदराबाद, दक्षिणी मध्य-भारत और मद्रास के दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट के साथ साथ भी मिलता है। लोहा मैसूर मे और अभ्रक उत्तरी मद्रास तथा मध्य राजस्थान मे पाया जाता है। इल्मेनाइट और मोनाजाइट, जो सामरिक महत्व के खनिज पदार्थ है, तिरुवाकुर के समुद्री तट की बालू में पाये जाते है। मैंगनेमाइट मद्रास की चाक की पहाड़ियो के क्षेत्र मे निकाला जाता है और सोना मैसूर की कोलार स्वर्ण खानो से। बाक्साइट, जिप्सम, मकान बनाने के लिये पत्थर, नमक, अग्निजित मिट्टी (फायर क्ले) कोरडम, और फुलर की मिट्टी भी देश के विभिन्न क्षेत्रो मे विभिन्न परिमाण मे प्रचुरता के साथ पाई जाती है। भारत मे अभ्रक काफी मिलता है। वास्तव मे यहा ससार के कुल अभ्रक के 60 प्रतिशत का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त भारत मे पाये जाने वाले मेंगनीज, इल्मेनाइट, मोनाजाइट और लोहा तथा टिटेनियम की और किस्मे भी परिमाण की दृष्टि से ससार की सब से अधिक अच्छी किस्मो मे है। पर भारत के खनिज साधनो का लाभ अभी तक पूरी तरह नही उठाया जा सका है। देश मे पेट्रोलियम की कमी है। पेट्रोलियम का एकमात्र क्षेत्र आसाम मे है। आसाम के इन तेलक्षेत्रो का उत्पादन प्रायः नगण्य है। इसी प्रकार सीसा, गधक, चादी, निकेल, टिन, जस्ता, पारा, टगस्टेन, मोलिब्डेनम, प्लैटिनम, ग्रैफाइट, तारकोल, पोटाश, और फ्लोराइड्स का परिमाण देश की आवश्यकता के अनुपात से यथेष्ट नही है। नीचे दिए गए विवरण द्वारा इन महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की मात्रा और मूल्य का सकेत मिलता है, जिनका उत्पादन देश मे सन 1951 में हुआ :—

तालिका 4

सन् 1951 मे खनिज उत्पादन

खनिज	मात्रा	रुपयो मे मूल्य
अपाटाइट	416 टन	6,408
ऐस्बेस्टस	433 टन	2,32,555
बाक्साइट	67,047 टन	7,52,365
बरिटीज़	8,224 टन	2,89,631
चीनी मिट्टी	54,987 टन	15,86,298
क्रोमाइट	15,802 टन	8,67,287
कोयला	3,44,30,522 टन	50,47,62,162
कच्चा ताबा	3,69,057 टन	..
कोरन्डम	548 टन	2,27,745
हीरा	1,674 कैरेट	5,34,361

खनिज	मात्रा	रुपयों में मूल्य
फेल्सपर	3,145 टन	34 532
फुलर्स अर्थ	4,000 टन	63 000
सोना	2,26,357 औन्स	6,75,28,992
ग्रैफाइट	1,578 टन	2,01,188
जिप्सम	2,03,602 टन	12,63,128
कच्चा लोहा	36,56,661 टन	2,09,45,218
कायनाइट	42,301 टन	58,50,626
मैगनेसाइट	1,17,071 टन	17,78,134
कच्चा मैंगनीज	12,83,929 टन	17,71,82,202
अभ्रक	4,90,665 हड्रेडवेट	13,75,81,134
ओकर	8,409 हड्रेडवेट	1,14,965
स्टीटाइट	32,378 हड्रेडवेट	12,95,885

नदियां तथा जल-साधन

भारत के राष्ट्रीय जीवन पर सदा से नदियो का गहरा प्रभाव रहा है। यहा की प्राचीनतम सभ्यताओ का विकास सिन्धु, गगा और उनकी सहायक नदियो के तटीय प्रदेशो मे हुआ। दक्षिण मे भी देशवासियो की बडी सख्या, अपने अस्तित्व के लिए नदियो पर निर्भर रही है। नदियो के अतिरिक्त जमीन की सतह के नीचे का पानी भी घरेलू और कृषि कार्यो के लिए जल की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन रहा है। देश के अधिकाश भागो मे सिचाई की व्यवस्था के बिना सफलतापूर्वक खेती करना सम्भव नही है।

नदियो मे वर्ष पर्यन्त अनुमानत कुल 1,35,60,00,000 एकड फुट पानी बहता है, जिसमे से प्राय: 7,60,00,000 एकड़ फुट या 5 6 प्रतिशत ही इस समय सिचाई के काम मे आता है। नदियो मे बहने वाले कुल पानी का न तो पूरा इस्तेमाल किया ही जा सकता है और न सिचाई के लिए उतने पानी की जरूरत है। पर यह अनुमान लगाया गया है कि 1,35,60,00,000 एकड फुट पानी मे से एक तिहाई, अर्थात 45,00,00,000 एकड फुट पानी देश के उपयोग में लाया जा सकता है। महत्वपूर्ण नदी श्रृङ्खलाओं मे जलीय साधनो के उपयोग की स्थिति इस प्रकार है:—

तालिका 5

नदी शृङ्खला	अनुमानित वार्षिक बहाव एकड फुटो मे	वर्तमान उपयोग	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित उपयोग एकड फुटों में
1. सिन्ध	1,700 लाख सम्पूर्ण शृङ्खला के लिए (पाकिस्तान सहित)	लगभग 80 लाख एकड फुट	भाखडा नंगल कार्य	80 लाख

नदी शृङ्खला	अनुमानित वार्षिक बहाव एकड फुटो में	वर्तमान उपयोग	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित उपयोग एकड़ फुटों में
2. गगा	4,000 लाख	अल्प भाग का उपयोग मुख्यत. गगा यमुना और शारदा नदियो की नहरो द्वारा हो रहा है।	दामोदर घाटी कार्य	27 लाख
3 ब्रह्मपुत्र	3,000 लाख	नगण्य आम तौर पर आसाम मे भारी वर्षा होने के कारण सिचाई की जरूरत नही होती।	--	—
4. गोदावरी	840 लाख	लगभग 14 प्रतिशत	—	—
5 महानदी	740 लाख	डेल्टा क्षेत्रो के लिए अल्प मात्रा मे	हीराकुड कार्य	लगभग 110 लाख
6 कृष्णा	500 लाख	लगभग 18 प्रतिशत	तुंगभद्रा कार्य	60 लाख
7. कावेरी	120 लाख	60 प्रतिशत से अधिक	--	—
8 नर्मदा	320 लाख	—	—	—
9 ताप्ती	170 लाख	—	काकरापार कार्य	—

शक्ति—

भारत मे विद्युत प्राप्त करने के ये तीन प्रमुख स्रोत है—मिट्टी का तेल, कोयला, और पानी। पैट्रोलियम के ज्ञात स्रोत यहा बहुत कम है। पत्थर के कोयले की कुल अनुमानित मिकदार 20,00,00 लाख (20 अरब) टन है, जिसमें से 5,00,00 लाख (5 अरब) टन अच्छी किस्म का कोयला है। यह अच्छी किस्म का कोयला धाते बनाने आदि कार्यो के लिये सुरक्षित किया जाएगा। घटिया किस्म का (लिगनाइट आदि) कोयला काफी बडी मात्रा मे उपलब्ध होता है, और उससे प्राप्ति स्थानो के निकट, बिजली पैदा की जा सकती है। भारत के जल-विद्युत् के स्रोत बहुत विशाल है। नीचे की तालिका से 11 विभिन्न क्षेत्रो के अनुमानित स्रोतो का अन्दाज लगाया जा सकता है —

तालिका 6

(किलोवाट में)

क्षेत्र का नाम	मार्च 1951 मे प्राप्त	1954 के अन्त म अनुमानित शक्ति	1959 के अन्त में अनुमानित शक्ति
१. जम्मू और काश्मीर	6,000	12,000	15,000
२. पजाब, दिल्ली और राजस्थान का कुछ भाग	1,48,000	2,62,000	4,70,000

क्षेत्र का नाम	मार्च 1951 में प्राप्त	1954 के अन्त में अनुमानित शक्ति	1949 के अन्त में अनुमानित शक्ति
३. मध्य प्रदेश और राजस्थान क कुछ भाग	1,49,000	2,31,000	3,26,000
४. बम्बई और हैदराबाद का कुछ भाग	5,28,000	6,99,000	10,44,000
५. दक्षिण भारत (आन्ध्र के तटीयभाग को छोड कर)	3,17,000	5,78,000	7,57,000
६. आन्ध्र का तटीय भाग तथा हैदराबाद, उडीसा और मध्यप्रदेश के कुछ भाग	67,000	1,78,000	2,35,000
७. महानदी घाटी कार्य का क्षेत्र	13,000	66,000	1,41,000
८. रेहन्द कार्य का क्षेत्र तथा उत्तर-प्रदेश का कुछ भाग	1,75,000	1,96,000	2,96,000
९. उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िले	74 000	1,43,000	1,94,000
१०. कलकत्ता तथा दामोदर घाटी कार्य	9,48,000	12,15,000	15,34,000
११. आसाम	8,000	8,000	17,000
योग	24,33 000	35,88,000	50,92,000

जंगल—

भारत के जंगलों का क्षेत्रफल 14,77,00,000 वर्गमील है, और देश की अर्थ-व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। यहा 2,500 किस्म की लकडी उपलब्ध होती है, जिसमे से 450 किस्में व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान है। निर्माण के कार्य तथा जलाने के अतिरिक्त लकडी से यहा ये चीज़े भी निकाली जाती है : एसेटिक एसिड, एसेटोन, मेथिल अलकोहल, तेल, क्रेमोसोट तथा सल्फेनोमाइड और क्लोरोफार्म जैसी कीमती दवाइया। जगलो से प्राप्त होने वाली छोटी चीजों की विविधता और मात्रा बहुत बड़ी है। भारत में लगभग 3,000 किस्मो की वनस्पतिया उत्पन्न होती है, उनके साथ ही जन्तु जगत की भी कितनी ही वस्तुए जगलो से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए दवाई वाली तथा जहरीली वनस्पतिया, आवश्यक तेल, बरोजा, घने तेल और चरबी, मोम, मैदा, गोंद, रंग, बांस, बेंत, कपड़े के तन्तु, घटिया किस्म का रेशम, सब तरह की घासें, शहद, लाख तथा पैकिंग का सामान आदि। इनमे से बहुत सी चीजे छोटे और बड़े व्यवसायो का पोषण करती है। विभिन्न प्रदेशों में भारत के जंगलो का क्षेत्रफल इस तालिका से ज्ञात होगा :—

तालिका 7

प्रदेश	जगलो का क्षेत्रफल	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
पूर्वी प्रदेश	3,46,10,000	20 63
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश	2,98,74,000	10 70
केन्द्रीय प्रदेश	3,96,92,000	29 92
दक्षिणी प्रदेश	4,35,29,000	18 82
सम्पूर्ण भारत	14,77,05,000	18 22

कृषि—

भारत मे विविध प्रकार के खाद्यान्न तथा धन लाने वाली उपजे पैदा होती है । इन क्षेत्रो में चावल पैदा होता है—गगा की घाटिया, पजाब के पहाडी ज़िले, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगाल, आसाम, पश्चिमी घाट, उडीसा के तट क्षेत्र और मद्रास । गेहू के उत्पादन क्षेत्र है—पजाब, पैप्सू, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत । गन्ने के क्षेत्र है—गगा के निकटवर्ती मैदान, मद्रास, मैसूर, उडीसा, हैदराबाद और पजाब । मूगफली, तिल, एरण्ड, सरसों, बीन्स, अलसी आदि तेल देने वाली उपजें, उत्तरी मद्रास, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश आदि में तथा रुई दक्खन के दक्षिणी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और पजाब मे पैदा होती है। चाय दार्जिलिंग, आसाम की पहाडियो तथा नीलगिरी मे उत्पन्न होती है। पटसन मुख्यत: पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होता है। काफी, चाय, रबर, काली मिरच, मसाले आदि अन्नामलाई तथा कार्डमम पहाड़ियो में पैदा होते है । भारत के विस्तृत समुद्र तट के काफी बड़े भाग पर नारियल पैदा होता है, जिससे गिरी, तेल और मुञ्जी आदि उपलब्ध होते है । काजू मलाबार तट पर होता है । इन्ही तटो पर केला भी खूब होता है । भारतीय आम की लगभग 500 किस्मे होती है, जिनमे से बम्बई का अल-फन्मो आदि ससार भर मे प्रसिद्ध है । बम्बई, पूना, मद्रास के सलेम और तजौर जिलो के तथा माल्दा, दरभगा, सहारनपुर और लखनऊ आदि के आम देश भर मे प्रसिद्ध है ।

सन् 1953 की मुख्य उपजो के क्षेत्रफल का अन्दाज इस तालिका से मिलेगा :—

तालिका 8

फसल	क्षेत्रफल एकडो मे	उपज टनो मे
खाद्यान्न :—		
चावल . .	7,46,74,000	2,34,24,000
गेहू . .	2,40,41,000	67,62,000
अन्य अन्न . .	10,10,81,000	1,73,98,000
चना	1,72,67,c00	37,71,000
मूगफली . .	1,18,62,000	28,94,000
गन्ना . .	43,76,000	52,60,000
अन्य उपजें :—		
तिलहन . .	1,56 49,000	17,41,000
तम्बाकू . .	7,98,000	2,05 000
रबर (1952 में) .	1,73,000	44,000
रूई . .	1,56,78,000	3,00,50,000 (गांठ)
पटसन (1952 में) .	18,34,000	46,95,000 (गांठ)

पशुधन—

भारत मे 29,22,18,000 पालतू पशु है, जो रूस को छोड कर शेष ससार के कुल पशुधन का सातवा भाग है । इनमे से लगभग दो तिहाई दूध देने वाले पशु है । इनके द्वारा प्राप्त दूध, मक्खन, घी, मास. अण्डे आदि देश के आन्तरिक व्यवहार में आते है, और खाल, हड्डी ,ऊन, चगड़ा, सीग

आदि के कुछ भाग का निर्यात होता है। पशुधन की पिछली तीन पंचवर्षीय गणनाओं के आंकड़े इस प्रकार है :—

	1940	1945	1950
कुल पशु .	27,61,48,000	26,84,40,000	29,22,18,000
मुर्गिया आदि .	5,74,08,000	5,82,47,000	7,33,99,000

बन्दरगाह—

भारत के पूर्वी तट पर कलकत्ता, मद्रास और विशाखापत्तनम तथा पश्चिमी तट पर बम्बई और कोचीन महत्वपूर्ण बन्दरगाह है। करांची की क्षतिपूर्ति के लिये इन दिनों कांडला के बन्दरगाह का विकास किया जा रहा है। इन्हीं से भारत का अधिकांश सामुद्रिक आयात निर्यात होता है।

गर्मियों के लिये शीतल स्थान—

गर्मियों में भारत के ये पहाडी स्थान बहुत लोकप्रिय है— हिमालय पर शिमला, मसूरी, नैनीताल, गुलमर्ग, पहलगाव, श्रीनगर, कुल्लू, शिलांग और दार्जिलिंग तथा पश्चिमी घाट के माथेरान, महाबलेश्वर, ऊटकमंड और कोडाईकनाल।

तीर्थस्थल—

उत्तर प्रदेश मे काशी इलाहाबाद (प्रयाग), हरिद्वार, मथुरा और वृन्दावन; उड़ीसा में पुरी; सौराष्ट्र मे द्वारका; बम्बई मे नासिक; मद्रास मे काजीवरम, कुम्भकोणम और रामेश्वरम; आन्ध्र मे तिरुपति आदि प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ है। पजाब मे अमृतसर और फतेहगढ सिक्खो के तीर्थ है और अजमेर, दिल्ली तथा पेप्सू मे सरहिन्द मुसलमानो के तीर्थ स्थान है। मैसूर मे श्रवण बेलगोला तथा पालिताना के निकट शत्रुजय पहाडी जैनियों के तीर्थ है। दिल्ली का राजघाट, जहा महात्मा गाधी का दाह सस्कार किया गया था, भारत भर का तीर्थस्थान बन गया है।

अनुसन्धान के स्थान—

ऐतिहासिक अनुसन्धान के महत्वपूर्ण स्थान ये है :—हैदराबाद मे अजन्ता और एलोरा की गुफाए; बम्बई मे कार्ली और एलिफैण्टा की गुफाए; उत्तर प्रदेश मे सारनाथ के बौद्ध खडहर; भूपाल मे साची और विहार मे बुद्ध गया; मैसूर मे बेलूर; बम्बई मे माउण्ट आबू; मद्रास मे मदुरा; तजौर, कोणार्क और महाबलिपुरम तथा उडीसा में भुवनेश्वर। इनके अतिरिक्त आगरा मे ताजमहल, दिल्ली के मुगल काल और उससे पहले के निर्माण, फतहपुर सीकरी, दौलताबाद, अहमदाबाद, सिकन्दराबाद और गोलकुण्डा आदि भी दर्शनीय है।

निवासी—

आबादी की दृष्टि से चीन के बाद भारत ससार का सबसे बड़ा देश है। सन् 1881 से भारत में प्रति 10 वर्षों के बाद नियमित रूप से जनगणना होती रही है। 1951 में जम्म–काश्मीर तथा

आसाम के आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारत मे जनगणना हुई थी। निम्नलिखित तालिका से पिछले 60 वर्षों की जनवृद्धि का अन्दाजा मिलेगा :—

तालिका 9

वर्ष	आबादी	गत दस वर्ष में (+) वृद्धि या (—) घटौती
1891	23,59,00,000	..
1901	23,55,00,000	--4,00,000
1911	24,90,00,000	+1,35,00,000
1921	24,81,00,000	--9,00,000
1931	27,55,00,000	+2,74,00,000
1941	31,28,00,000	+3,73,00,000
1951	35,69,00,000	+4,41,00,000

सन् 1921 से लेकर 1951 के 30 वर्षों मे भारत की आबादी मे लगभग 11 करोड की वृद्धि हुई है। 1921 के बाद से आबादी की वृद्धि का ढाचा एकदम बदल गया है। 1921 से पहले अकाल, महामारी आदि के कारण आबादी की वृद्धि रुकी रही, और कृषि की उपज बढती चली गई। परन्तु 1921 के बाद से इस परिस्थिति मे परिवर्तन आ गया।

1951 की जनगणना—

तालिका स० 10 में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यो की जनसंख्या दी गई है। जम्मू-काश्मीर तथा आसाम के उपजातीय क्षेत्र को छोड कर भारत की कुल जनसख्या 35,68,29,485 है। इसमें 18,33,05,654 पुरुष है और 17,35,23,831 स्त्रियां। 1941 से 1951 तक 4,20,00,000 आबादी बढ़ी। सिर्फ पजाब और अण्डमान निकोबार मे क्रमश. 0·5 तथा 8 6 प्रतिशत आबादी घटी, बाकी सब राज्यो मे आबादी बढी। सबसे अधिक आबादी दिल्ली में बढ़ी जो 62·1 प्रतिशत है और दूसरे नम्बर पर कुर्ग मे (30.5 प्रतिशत)। अधिकाश राज्यो मे वृद्धि का हिसाब 10 से 22 प्रतिशत रहा। सिर्फ बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और पेप्सू मे वृद्धि 10 प्रतिशत से नीचे रही। पेप्सू की आबादी केवल 2 6 प्रतिशत बढी।

स्त्री और पुरुषों का अनुपात :—

भारत मे प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे 947 स्त्रिया है। केवल उडीसा, मणिपुर, मद्रास, तिरुवां-कुर-कोचीन और कच्छ (जहा प्रति 1,000 पुरुषो के पीछे स्त्रियो की संख्या क्रमश 1,022, 1,036, 1,006, 1,008 और 1,079 है) को छोड़ कर सब राज्यों मे पुरुषो की सख्या अधिक

तालिका 10

क्षेत्रों तथा राज्यों की जनसंख्या

क्षेत्र और राज्य	वर्गमीलो मे भूमि का क्षेत्रफल	आबादी 1951 व्यक्ति	आबादी 1951 पुरुष	आबादी 1951 स्त्री	1941 व्यक्ति	प्रति 1000 पुरुषो के पीछे स्त्रिया (1951)	1941–1951 में वृद्धि की रफ्तार
भारत . .	12,69,64	35,68,29,485	18,33,05,654	17,35,23,831	31,47,66,380	947	+12.5
1 उत्तर भारत .	1,13,409	6,32,15,742	3,30,98,866	3,01,16,876	5,65,31,848	910	+11.2
1. उत्तर प्रदेश .	1,13,409	6,32,15,742	3,30,98,866	3,01,16,876	6,65,31,848	910	+11.2
2. पूर्वी भारत .	2,61,657	9,00,80,297	4,63,15,658	4,37,64,639	8,08,73,038	945	+10.8
1. बिहार .	70,330	4,02,25,947	2,02,23,675	2,00,02,272	3,65,28,119	989	+ 9 6
2 उडीसा .	60,136	1,46,45,946	72,42,892	74,03,054	1,37,67,988	1,022	+ 6.2
3. पश्चिमी बगाल	30,775	2,48,10,308	1,33,45,441	1,14,64,867	2,18,37,295	859	+12.7
4 आसाम* .	85,012	90,43,707	48,12,166	42,31,541	7,5,93,037	879	+17.4
5. मणिपुर .	8,628	5,77,635	2,83 685	2,93,950	5,12,069	1,036	+12.0
6 त्रिपुरा .	4,032	6,39,029	3,35,589	3,03,440	5,13,010	904	+21.9
7. सिक्किम .	2,744	1,37,725	72,210	65,515	1,21,520	907	+12.5
3. दक्षिण भारत .	1,68,009	7,56,00,804	3,78,22,542	3,77,78,262	6,48,37,350	999	+15.3

1. मद्रास .	1,27,790	5,70,16,002	2,84,19,003	2,85,96,999	4,98,30,749	1,006	+13 4
2 मैसूर .	29,489	90,74,972	46,57,409	44,17,563	73,37,818	949	+21 2
3 तिरुवांकर कोचीन	9,144	92,80,425	46,20,803	46,59,622	75,00,057	1,008	+21 2
4 कुर्ग	1,586	2,29,405	1,25,327	1,04,078	1,68,726	830	+30 5
4 पश्चिमी भारत	1,49,609	4,06,61,115	2,09,82,281	1,96,78,834	3,32,49,726	938	+20 1
1 बम्बई	1,11,434	3,59,56,150	1,86,14,8C2	1,73,41,288	2,91,81,146	932	+20 8
2 सौराष्ट्र	21,451	41,37,359	20,94,442	20,42,917	35,60,700	975	+15.0
3 कच्छ .	16,724	5,67,606	2,72,977	2,94,629	5,07,880	1,079	+11 1
5 मध्य भारत	2,89 399	5,22,67,959	2,64,97,524	2,57,70,435	4,72,73,886	973	+10 0
1 मध्य प्रदेश	1,30,272	2,12,47,533	1,06,62,812	1,05,84,721	1,96,31,615	993	+ 7 9
2 मध्य भारत .	46,478	79,54,144	41,33,075	38,21,079	71,69,880	925	+10 4
3 हैदराबाद	82,168	1,86,55,108	94,31,062	92,24,046	1,63,27,119	978	+13 3
4 भोपाल	6,878	8,36,474	4,37,635	3,98,839	7,78,623	911	+ 7.2
5 विन्ध्य प्रदेश	23,603	35,74,690	18,32,940	17,41,750	33,66,649	950	+ 6 0
6. उत्तर-पश्चिमी भारत	2,84,342	3,49,72,597	1,85,69,728	1,64,02,869	3,19,66,764	883	+ 9.0
1 राजस्थान	1,30,207	1,52,90,797	79,61,673	73,29,124	1,33,06,232	921	+13.9
2 पंजाब .	37,378	1,26,41,205	67,86,934	58,54,271	1,26,98,603	863	— 0 5
3 पैप्सू	10,078	34,93,685	18,94,844	15,98,841	34,02,586	844	+ 2 6
*4 जम्मू और काश्मीर	92,780	—	—	—	—	—	—
5 अजमेर .	2,417	6,98,372	3,60,236	3,33,136	3,83,693	925	+17.2
6 दिल्ली .	578	17,44,072	9,86,538	7,57,534	9,17,939	768	+62.1
7 बिलासपुर .	453	1,26,099	64,738	61,361	1,10,336	948	+13.3
8 हिमाचल प्रदेश	10,451	9,83,367	5,14,765	4,68,602	9,47,375	910	+ 3.7
अन्दमान और निकोबार द्वीपपुंज	3,215	30,971	19,055	11 916	33,768	625	— 8.6

*जम्मू और काश्मीर तथा आसाम के आदिवासी क्षेत्रों के आंकड़े शामिल नहीं है ।

है। सबसे कम स्त्रियां अण्डमान निकोबार में हैं, जहां उनका अनुपात 1,000 पुरुषों के पीछे 625 है। दिल्ली में यह अनुपात 768 है। इन राज्यों में स्त्रियों का अनुपात 1,000 के पीछे 900 से कम है—पश्चिमी बंगाल, आसाम, कुर्ग, पंजाब और पेप्सू।

आबादी का विभाजन :—

क्षेत्रों की दृष्टि से आबादी का वर्गीकरण करने पर उत्तर भारत में केवल एक ही राज्य (उत्तर प्रदेश) की आबादी भारत की कुल आबादी का 18 प्रतिशत है। पूर्वी भारत (7 राज्य) की आबादी 25 प्रतिशत है, दक्षिणी भारत (4 राज्य) की 21 प्रतिशत, पश्चिमी भारत (3 राज्य) की आबादी 11 प्रतिशत, केन्द्रीय भारत (5 राज्य) की 15 प्रतिशत और उत्तर पश्चिमी भारत (7 राज्य) की आबादी 10 प्रतिशत है।

तालिका 11

आबादी का प्रादेशिक वर्गीकरण

संख्या	क्षेत्र	कुल आबादी	कुल आबादी का अनुपात
1.	हिमालय प्रदेश . .	1,70,42,697	4.8
2.	उत्तरी मैदान . .	13,93,98,043	39.1
3.	प्रायद्वीपी पहाडिया और पठार	10,85,58,645	30.4
.	पश्चिमी घाट तथा तटीय प्रदेश	3,99,26,793	11.2
5.	पूर्वी घाट तथा तटीय प्रदेश .	5,18,23,336	14.5
6.	अण्दमान निकोबार द्वीप समूह	30,971	
	सम्पूर्ण भारत	35,68,29,485	100 0

क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बडा राज्य मध्य प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 1,30,272 वर्गमील है। राजस्थान (क्षेत्रफल 1,30,207 वर्ग मील) का स्थान दूसरा है। सबसे छोटा राज्य दिल्ली है, जिसका क्षेत्रफल केवल 578 वर्गमील है।

आबादी के लिहाज से सबसे बडा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 6,30,00,000 है। मद्रास दूसरा है (5,70,00,000) और बिहार तीसरा (4,00,00,000)। विन्ध्य प्रदेश (आबादी 35,70,000) और दिल्ली (आबादी 17,40,000) को छोड कर और किसी भी "ग" या "घ" श्रेणी के राज्य की आबादी 10 लाख से अधिक नही। अण्दमान निकोबार की आबादी केवल 30,971 है।

आबादी की घनता:—

भारत में आबादी की औसत घनता प्रति वर्ग मील पीछे 312 व्यक्ति है। किसी राज्य मे आबादी अधिक घनी है, और किसी मे कम। दिल्ली मे आबादी का औसत प्रति वर्गमील पीछे 3,017 है और तिरुवांकुर कोचीन मे 1,015; कच्छ मे यह औसत 34 है और अण्दमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10। आबादी की सघनता या विरलता स्वभावतः भूतल की बनावट, मिट्टी और वर्षा पर निर्भर करते । विशेषकर इन्ही से यह निश्चित होता है कि कितनी जमीन खाद्य-उत्पादन के काम

में आ सकती है और वह किस हद तक खाद्य-उत्पादन के योग्य है। इसलिये आबादी की समस्या का अध्ययन देश के राजनीतिक विभागों के सहारे न करके भू-विज्ञान और मौसम के आधार पर किये गये प्राकृतिक विभागों की सहायता से किया जाये तो अधिक अच्छा होगा। इसी अभिप्राय से देश को 15 उप-प्रदेशों में बांटा गया है और उन्हें निम्न तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। अधिक सघन, कम सघन और मध्यम सघन। नीचे के विवरण में यह बताया गया है कि इन 15 उप-प्रदेशों में आबादी कितनी घनी है और प्रति व्यक्ति पीछे जमीन का औसत कितना है।

तालिका 12

उप-प्रदेश	आबादी (लाख)	घनता प्रति वर्ग मील	जमीन का क्षेत्रफल (लाख एकड़)	प्रति व्यक्ति जमीन का क्षेत्रफल (एकड़ों में)
अधिक सघन उपप्रदेश :—				
1 गंगा का निचला मैदान	700	832	538	77
2 गंगा का उपरला मैदान	389	681	366	·94
3. मलाबार कोंकण	238	638	239	1 00
4 दक्षिणी मद्रास . .	307	554	355	1 15
5. उत्तरी मद्रास और समुद्र तटवर्ती उड़ीसा	211	461	293	1 39
योग . .	1,845	660	1,791	97
कम सघन उपप्रदेश :—				
1. रेगिस्तान . .	46	61	482	10 47
2 पश्चिमी हिमालय .	90	68	852	9·44
3 उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश . .	104	163	409	3 94
4 पूर्वी हिमालय .	124	118	674	5·42
5. उत्तर-मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश और पठार	138	164	537	3 89
6. उत्तरी पूर्वी पठार .	290	192	967	3 33
योग . . .	792	129	3,921	4 95
मध्यम सघन उपप्रदेश :—				
1. गंगा पार का मैदान	259	332	499	1·93
2. दक्षिणी दक्कन का पठार	315	247	817	2·59
3. उत्तरी दक्कन का पठार	239	246	621	2·60
4. गुजरात काठियावाड़ .	161	226	456	2·83
योग . . .	974	266	2,393	2·46

नीचे की तालिका मे भारत तथा कुछ अन्य देशों मे जोती, बोई जाने वाली और जोतने बोने योग्य जमीन का प्रति व्यक्ति पीछे क्षत्रफल दिया गया है :—

तालिका 13

	भारत	ससार	अमेरिका	यूरोप (रूस कोछोडकर)	रूस
आबादी (करोड़ों मे) . . .	36·1	240	15·1	39·6	19·4
जमीन का क्षेत्रफल (करोड एकडो मे)	81·3	3,251	190·5	121·8	590·4
क्षत्रफल प्रति व्यक्ति (एकड़ो में):					
कुल जमीन (प्रति व्यक्ति) .	2·25	13·54	12 64	3·07	30 46
जोती बोई जाने वाली जमीन (प्रति व्यक्ति) (एकड़ो मे) . .	·97	3·51	7·41	1 53	4 48
जोतने बोने योग्य जमीन (प्रति व्यक्ति)"	·97	1 26	3·02	92	2·87

संसार मे सबसे अधिक घना बसा महाद्वीप यूरोप है, परन्तु वह भारत से कम घना बसा है। औसत भारतीय कुल जमीन के 43 प्रतिशत भाग मे खेती करता है, जबकि औसत यूरोपीय 30 प्रतिशत भाग मे ही खेती करता है। अमेरिका और रूस मे काम मे आने लायक जितनी जमीन है, उतनी यूरोप और भारत मे नही है।

शहरी और देहाती आबादी :—

भारत की कुल आबादी 35 करोड 70 लाख है। इसमे मे केवल 6 करोड 20 लाख आदमी शहरों और कस्बों में रहते है, शेष 29 करोड़ 50 लाख गावो मे रहते है। शहरी आबादी कुल आबादी का 17.3 प्रतिशत है और देहाती आबादी 82 7 प्रतिशत। नीचे की तालिका से पता चलता है कि गावो की आबादी धीरे धीरे शहरो की ओर खिच रही है।

तालिका 14

वर्ष	कुल आबादी का प्रतिशत	
	देहाती	शहरी
1921	88·7	11 2
1931	87·9	12·1
1941	86·1	13·9
1951	82 7	17·3

पिछली दशाब्दी मे शहरी आबादी 3·4 प्रतिशत बढी है, जबकि उससे पिछली दो दशाब्दियो में वह केवल 2·6 प्रतिशत ही बढ़ी थी।

देहली और अजमेर राज्य बहुत छोटे हैं। यहा शहरी आबादी क्रमशः 83 और 43 प्रतिशत है। बडे राज्यों में सबसे अधिक शहरी आबादी सौराष्ट्र और बम्बई में है। सौराष्ट्र में 34 प्रतिशत और बम्बई में 31 प्रतिशत लोग बड़े नगरों और शहरों में रहते हैं।

शहर, गांव और घर :—

देश में कुल 3,018 शहर और 5,58,089 गाव है। बसे हुए घरों की कुल संख्या 6 करोड़ 44 लाख है, जिनमें से 5 करोड़ 41 लाख गावों मे है और 1 करोड़ 3 लाख शहरों में। नीचे की तालिका में आबादी के अनुसार वर्गीकृत गावों, कस्बों, शहरों और बड़े नगरों की संख्या दी गई है :—

तालिका 15

गाव, कस्बे और शहर	संख्या
500 से कम आबादी वाले	3,80,020
500 से 1,000 तक आबादी वाले	1,04,268
1,000 से 2,000 तक आबादी वाले	51,769
2,000 से 5,000 तक आबादी वाले	20 508
5,000 से 10,000 तक आबादी वाले	3.101
10,000 से 20,000 तक आबादी वाले	856
20,000 से 50,000 तक आबादी वाले	401
50,000 से 1,00,000 तक आबादी वाले	111
1,00.000 से 10,00,000 तक आबादी वाले	69
10,00,000 से अधिक आबादी वाले	4
(दिल्ली और नई दिल्ली को एक मान कर 5)	
योग	5 61 107

१ लाख से अधिक आबादी वाले 73 शहरो मे "क" भाग के राज्यों मे से आसाम मे और "ख" भाग के राज्यो में से पेप्सु मे एक भी ऐसा शहर नही है। "ग" भाग के सात राज्यो मे इस तरह के चार शहर है, दिल्ली, नई दिल्ली, अजमेर और भोपाल। उपर्युक्त 73 शहरों में 24 ऐसे है, जिनकी आबादी दस साल पहले 1 लाख से कम थी। पिछले दस सालों में ये सब बढ़ते बढ़ते शहर बन

गए हैं। परन्तु उससे पिछले दस सालों में इस तरह के केवल 15 ही नए शहर बने थे। इन शहरों के नाम और 1942 तथा 1951 की जनगणना मे इनकी जनसंख्या नीचे दी जा रही है :—

तालिका 16

शहर	जनसंख्या (1951 में)	जनसंख्या (1941 मे)	दसवार्षिकी वृद्धि का मध्यमान (मीन रेट) 1941-51
"क" भाग के राज्य			
बिहार			
1. पटना . .	2,83,479	1,96,415	+ 36·3
2 जमशेदपुर . .	2,18,162	1,65,395	+ 27·5
3. गया . . .	1,33,700	1,05,223	+ 23·8
4. भागलपुर* . .	1,14,530	93,254	+ 20·5
5 रांची* . .	1,06,849	62,562	+ 52·3
बम्बई			
1 बम्बई . . .	28,39,270	16,95,168	+ 50·5
2 अहमदाबाद . .	7,88,333	5,91,267	+ 28·6
3. पूना . . .	4,80,982	2,78,165	+ 53·4
4 शोलापुर . .	2,66,050	2,03,691	+ 26·6
5. सूरत . . .	2,23,182	1,71,434	+ 26·2
6. बडौदा . . .	2,11,407	1,53,301	+ 31·9
7 कोल्हापुर* . .	1,36,835	93,032	+ 38·1
8 हुबली* .	1,29,609	95,512	+ 30·3
मध्यप्रदेश			
1. नागपुर . . .	4,49,099	3,01,957	+ 39·2
2 जबलपुर . .	2,56,998	1,78,339	+ 36·1
मद्रास			
1. मद्रास . . .	14,16,057	7,77,481	+ 58·5
2. मदुराई . . .	3,61,781	2,39,144	+ 40·8
3. तिरूचिरापल्ली .	2,18,921	1,59,566	+ 31·4
मद्रास क्रमशः			
4. सलेम . . .	2,02,335	1,29,702	+ 43·8
5. कोयम्बटूर .	1,97,755	1,30,348	+ 41·1
6. विजयवाडा* . .	1,61,198	86,184	+ 60·6
7. कोजीकोडे . .	1,58,724	1,26,352	+ 22·7
8. गुन्टूर* . . .	1,25,255	83,599	+ 39·9
9 मगलौर* . .	1,17,083	81,069	+ 36·3

नोटः—तारांकित शहर पहली बार बड़े शहर माने गए हैं।

शहर	जनसंख्या (1951 में)	जनसंख्या (1941 में)	दशवार्षिकी वृद्धि का मध्यमान (मीन रेट) 1141—51
10. विशाखपत्तनम्* .	1,08,042	70,243	+ 42.4
11 वेल्लोर* . .	1,06,024	71,502	+ 38 9
12. राजमुन्द्री* .	1,05,276	74,564	+ 34 2
13. तजौर* . .	1,00,680	68,702	+ 37 8
उड़ीसा			
1. कटक* . .	1,02,505	74,291	+ 31 9
पंजाब			
1 अमृतसर .	3,25,747	3,91,010	— 18 2
2. जालधर .	1,68,816	1,35,283	+ 22 1
3. लुधियाना .	1,53,795	1,11,639	+ 31 8
उत्तर प्रदेश			
1 कानपुर .	7,05,383	4,87,324	+ 36 6
2. लखनऊ .	4,96,861	3,87,177	+ 24 8
3 आगरा . .	3,75,665	2,84,149	+ 27 7
4 बनारस .	3,55,777	2,63,100	+ 30 0
5. इलाहाबाद .	3,32,295	2,60,630	+ 24 2
6 मेरठ . .	2,33,183	1,69,290	+ 31 8
7. बरेली .	2,08,083	1,92,688	+ 7 7
8 मुरादाबाद .	1,61,854	1,42,414	+ 12 8
9 सहारनपुर .	1,48,435	1,08,263	+ 31 3
10. देहरादून* .	1,44,216	78,228	+ 59 3
11. अलीगढ .	1,41,618	1,12,655	+ 22 8
12. रामपुर* .	1,34,277	89,322	+ 40 2
13. गोरखपुर*	1,32,436	98,977	+ 28 9
14 झासी .	1,27,365	1,03,254	+ 20.9
पश्चिमी बंगाल			
1 कलकत्ता .	25,48,677	21,08,891	+ 18.9
2 हावड़ा . .	4,33,630	3,79,292	+ 13.4
3 टौलीगज* .	1,49,317	58,594	+ 87.5
4 भाटपाडा .	1,34,916	1,17,044	+ 14.2
5. खडगपुर* .	1,29,636	87,185	+ 39.2
6. गार्डन रीच * .	1,09,160	85,188	+ 24.7
7. साउथ सबर्बन (बेहाला)*	1,04,055	63,479	+ 48.4
"ख" भाग के राज्य			
हैदराबाद			
1. हैदराबाद .	1,085,722	7,39,159	+ 38.0
2 वारंगल* .	1,33,130	92,808	+ 35.7

नोट—तारांकित शहर पहली बार बड़े शहर माने गये हैं।

शहर	जनसंख्या (1951 में)	जनसंख्या (1941 म)	दशवार्षिकी वृद्धि का मध्यमान (मीन रेट) 1941—51
मध्य-भारत			
1. इन्दौर . .	3,10,859	2,03,695	+ 41 7
2. ग्वालियर .	2,41,577	1,82,492	+ 27.9
3. उज्जैन* .	1.29,817	81,272	+ 46.0
मैसूर			
1. बंगलोर .	7,78 977	4,06,760	+ 62.8
2. मैसूर . .	2,44,323	1,50,540	+ 47.5
3 कोलार (सोने की खान).	1,59,084	1,33,859	+ 17.2
राजस्थान			
1. जयपुर . .	2,91,130	1,75,810	+ 49.4
2. जोधपुर .	1,80,717	1,26,842	+ 35.0
3. बीकानेर .	1,17,113	1,27,226	— 8.3
सौराष्ट्र			
1. भावनगर .	1,37,951	1,02,851	+ 29 2
2. राजकोट .	1,32 069	52,178	+ 86.7
3. जामनगर .	1,04 419	71,588	+ 37.3
तिरवांकूर-कोचीन			
1. त्रिवेन्द्रम .	1,86,931	1,28,365	+ 37.2
2. अलेप्पी * .	1,16,278	56,333	+ 69.5
"ग" भाग के राज्य			
1. अजमेर . .	1,96,633	1,47,258	+ 28.7
2. भोपाल * .	1,02,633	75,228	+ 30.5
3. दिल्ली . .	9,14,790	5,21,849	+ 54.7
4. नई दिल्ली* .	2,76,314	98,733	+ 98.7

नोट:—तारांकित शहर पहली बार बड़े शहर माने गये हैं।

आर्थिक वर्गीकरण

जीविका के साधनों की दृष्टि से यदि आबादी का वर्गीकरण किया जाए, तो ज्ञात होगा कि 70 प्रतिशत आदमी खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं और 30 प्रतिशत अन्य व्यवसायों पर। सौराष्ट्र, कच्छ, अजमेर, दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ कर शेष सब राज्यों में किसानों की संख्या गैरकिसानों की संख्या से अधिक है। सौराष्ट्र, कच्छ, अजमेर, दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में गैर किसानों की संख्या किसानों की संख्या से क्रमश: 3,8,5,90 और 86

प्रतिशत अधिक है। पश्चिमी बगाल और बम्बई राज्य उद्योगों मे सबसे आगे बढे हुए है, यद्यपि किसानों की सख्या यहा भी गैर किसानो की संख्या से अधिक है। इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आदि अधिकांश पहाड़ी राज्यों में तो किमानो की आबादी कुल आबादी के 90 प्रतिशत से भी अधिक है।

हर 100 भारतीयों मे जिनमे उनके आश्रित भी शामिल है, 47 मुख्य रूप से अपने खेतों के मालिक किसान है, 9 मुख्य रूप से किराये की जमीन बोने वाले किसान है, 13 खेतिहर मजदूर है, 1 जमीदार है, और 10 उद्योगो मे या दूसरे किसी गैर खेतीबाड़ी सम्बन्धी उत्पादन में लगे हुए हैं, 6 व्यापार में है, 2 परिवहन मे तथा 12 नौकरियो और विभिन्न फुटकर कार्यों मे लगे हुए है। नीचे की तालिका मे आजीविका की दृष्टि से खेतीबाडी और अन्य व्यवसायो के चार-चार उपवर्ग किये गये है, और यह दिखाया गया है कि इनमे कितने स्वावलम्बी है, और कितने उनके आश्रित है तथा आश्रितो मे कितने कमाते है और कितने नही कमाते।

तालिका 17 (लाखों मे)

वर्ग	उपवर्ग	स्वावलम्बी	न कमाने वाले आश्रित	कमाने वाले आश्रित	योग
(1) किसान	(1) ऐसे किसान, जो सर्वथा या अधिकाश मे अपनी जमीन के मालिक है	4,58	10,01	2,14	16,73
	(2) ऐसे किसान जो सर्वथा या अधिकाश मे अपनी जमीन के मालिक नही है	88	1,89	39	3,16
	(3) खेतो में काम करने वाले मजदूर	1,49	2,46	53	4,48
	(4) ऐसे जमीदार जो खेती करते है और लगान वसूल करते है	16	33	4	53
	किसानो की कुल सख्या	7,11	14,69	3,10	24,90
(2) गैर किसान	(1) ऐसा उत्पादन जो खेती से नही होता	1,22	2,24	31	3,77
	(2) व्यापार	59	1,45	9	2,13
	(3) परिवहन	17	36	3	56
	(4) अन्य सेवाए और व्यवसाय आदि	1,36	2,68	26	4,30
	गैर किसानो की कुल सख्या	3,34	6,73	69	10,76
	सर्व योग	10,45	21,42	3,79	35,66

जनगणना के समय जीविका के उपसाधनो के बारे मे जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसकी सहायता से अपनी ज़मीन जोतने वाले किसानो और दूसरो की जमीन जोतने वाले भूमिहीन किसानो की अलग गणना की गई है। इस गणना से पता चला है कि अपनी जमीन जोतने वाले किसानो और भूमिहीन किसानो मे परस्पर मे 1,000 और 402 का अनुपात है। एक हजार भूमिधर किसानों के पीछे भूमिहीन किसानो का अनुपात हर राज्य मे अलग अलग है। उत्तर प्रदेश मे यह सब से कम (161) है और तिरुवाकुर-कोचीन मे सब से अधिक (782)। दूसरे बड़े राज्यो मे ये आकडे इस प्रकार है—मैसूर (190), आसाम (235), उड़ीसा (271), बम्बई (383), मध्यभारत (397), मध्य-प्रदेश (413), हैदराबाद (507), बिहार (510), राजस्थान (544), पश्चिमी बगाल (609) और मद्रास (714)।

खेती करने वाले असली किसान 545 लाख है। इन मे 457 लाख मालिक-किसान है, और 88 लाख लगान देने वाले किसान। मालिक-किसानो की अधिकता भारत के कृषकवर्ग के ढाचे की विशेषता है। हमारे देश में इन की अधिकता बहुत महत्वपूर्ण है। ये रैयतवारी इलाको मे ही नहीं, इस्तमरारी बन्दोबस्त वाले और अस्थायी बन्दोबस्त वाले इलाको मे भी अधिक है।

334 लाख स्वावलम्बी गैर-किसानो को निम्नलिखित चार श्रेणियो मे विभाजित किया गया है:

तालिका 18

श्रेणिया	सख्या	स्वावलम्बी गैर किसानो का प्रतिशत	स्वावलम्बी व्यक्तियो का प्रतिशत
(1) मालिक	11,00,000	3 3	1 1
(2) मालिको के अलावा अन्य लोग जो अपना ही काम करते है	1,65,00,000	49.4	15 7
(3) नौकर	1,48,00,000	44.3	14 2
(4) ऐसे लोग किसी प्रकार के किराये पर निर्भर करते है, पेशन पाने वाले तथा अन्य किसी प्रकार की आय पर गुजर करने वाले	10,00,000	3.0	0.9
योग	3,34,00,000	100.0	31.9

इस विभाजन को देखने से पता चलता है कि गैर-किसानो मे नौकरो की सख्या का अनुपात किसानों मे नौकरों की संख्या के अनुपात से अधिक है। इस के विपरीत अपना काम करने वाले लोग (जो मालिक नही है) संख्या में इतने अधिक है कि मालिक और नौकर दोनों मिल कर भी उतने नहीं है।

खेतीबाड़ी को छोड़कर अन्य सेवाओं और उद्योगो मे लगे हुए 324 लाख स्वावलम्बी व्यक्ति अपनी जीविका किस प्रकार कमाते है, यह जानने के लिये उनको दस विभागों और 88 उप-विभागो मे बाटा गया है। नीचे जो आंकड़े दिये गये है, वे उसी ढग से तैयार किये गये है, जिस ढंग से दूसरे देशों मे युनैस्को द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार तैयार किये जाते है। भारत की 1931 की तथा उस से पहले की जन-गणनाओं के जो आंकड़े प्रकाशित होते रहे है, उन के ढग को भी ध्यान मे रखा गया है।

तालिका 19

उद्योग और नौकरियो के विभाग	सख्या	प्रतिशत
1. खेती, खान और पत्थर की खुदाई को छोड़ कर अन्य प्राथमिक उद्योग	24,00,000	7.4
2 खानो और पत्थर की खुदाई	5,70,000	1.8
3. खाद्य पदार्थ, कपडे, चमड़ा और उस की बनी चीजो की प्रक्रिया और निर्माणसम्बन्धी कार्य	55,10,000	17.0
4 धातु, रासायनिक पदार्थ और उन की बनी चीजो की प्रक्रिया और निर्माणसम्बन्धी कार्य	12,40,000	3.8
5. अन्यत्र अनिर्दिष्ट वस्तुओ की प्रक्रिया तथा निर्माण	24,30,000	7.5
6 निर्माण और उपयोग की चीजे	15,90,000	4.9
7. व्यापार	59,00,000	18.2
8. परिवहन, भडारीकरण और सचार	19,00,000	5.9
9. स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक प्रशासन	32,90,000	10.2
10 वे सेवाये जिन का अन्यत्र निर्देश नही है	75,40,000	23.3
योग	3,23,70,000	100.0

आयुओं का विवरण

21 नम्बर तालिका मे आयु के अनुसार आबादी का ब्यौरा दिया गया है। प्रत्येक आयु-वर्ग के साथ जो संख्या नीचे दिखाई गई है, वह कुल आबादी का प्रतिशत है :

तालिका 20

	आयुवर्ग (वर्षों मे)	प्रतिशत
दूध पीते और छोटे बच्चे	0 से 4	13.5
लडके और लडकिया	5 से 14	24.8
युवक और युवतिया	15 से 24	17.4
	25 से 34	15.6
अधेड़ पुरुष और अधेड स्त्रिया	35 से 44	11.9
	45 से 54	8.5
वृद्ध तथा वृद्धाएं	55 से 64	5.1
	65 से 74	2.2
	75 और उस से ऊपर	1.0
		100.0

तालिका 21

आयु और नागरिक स्थिति

आयु-वर्ग (वर्षो मे)	कुल (हजारो मे)		अविवाहित (हजारो मे)		विवाहित (हज़ारो मे)		विधुर, विधवा और विवाह विच्छेद प्राप्त (हज़ारो मे)	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
I से कम	5,821	5,668	5,821	5,668	—	—	—	—
I से 4	17,939	17,908	17,939	17,908	—	—	—	—
5 से 14	44,703	41,989	41,804	35,737	2,833	6,118	66	134
15 से 24	30,672	30,052	16,627	5,184	13,660	24,041	384	827
25 से 34	27,875	26,633	3,701	733	23,122	23,731	1,052	2,129
35 से 44	22,032	19,528	1,150	304	19,323	15,346	1,559	3,178
45 से 54	15,719	13,898	604	173	13,076	8,314	2,038	5,412
55 से 64	9,064	8,624	299	89	6,777	3,334	1,989	5,201
65 से 74	3,867	3,976	104	37	2,533	1,092	1,230	2,847
75 और उस से ऊपर	1,630	1,756	46	18	883	370	701	1,367
अज्ञात आयु	111	117	51	60	46	42	14	15
विस्थापितो के इलावा कुल आबादी	1,79,433	1,70,149	88,146	65,951	12,253	12,388	9,033	21,810

यह स्पष्ट है कि आबादी मे कम उम्र वालो का अनुपात बहुत अधिक है, और ऐसे लोगो की सख्या बहुत कम है, जो अधेड होने के बाद जीते है। नीचे की तालिका (संख्या २२) मे इस सम्बन्ध मे दूसरे देशों की परिस्थिति के साथ हमारे देश की परिस्थिति की तुलना की गई है।

तालिका 22

देश	कुल आबादी का प्रतिशत			
	छोटे बच्चे	छोटे बच्चे और लड़के लडकियां	15 से कम आयु वाले व्यक्ति	55 और उस से ऊपर आयु वाले व्यक्ति
भारत	3.3	13.5	38.3	8.3
यूरोप	2.0	9.8	26.9	17.2
जर्मनी	1.5	7.0	23.5	19.1
इग्लैंड	1.5	8.6	22.5	21.1
इटली	1.8	9.2	26.6	12.0
फ्रांस	1.6	7.2	21.8	21.4
उत्तरी अमेरिका	——	10.8	27.1	16.9
ओशेनिया	2.5	10.5	26.0	17.8
जापान	2.8	13.5	35.4	11.0
दक्षिण पूर्वी एशिया	3.3	15.1	40.9	7.3
दक्षिण पश्चिमी एशिया	3.1	16.7	40 6	9.5
दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका	3.1	14.6	40.1	7.4
अफ्रीका	2.9	13.7	13.1	8.5

विवाह सम्बन्धी स्थिति का नमूना

भारत मे प्रति 10 हजार व्यक्तियो मे (इनमे विस्थापितो का हिसाब शामिल नही है) 5,133 पुरुष और 4,867 स्त्रिया है । इन मे से 2,521 पुरुष और 1,886 स्त्रियां अविवाहित है । यदि पुरुषो और स्त्रियों का हिसाब एक साथ किया जाए, तो कुल आबादी के 44.1 प्रतिशत लोग अविवाहित है ।

विवाह सम्बन्धी परिस्थिति की एक बहुत बडी विशेषता यह है कि बाल-विवाह रोक सम्बन्धी कानून होते हुए भी बहुत अधिक बाल विवाह होते है । 1951 की जनगणना मे 5 से लेकर 14 साल की उम्र के लोगों मे 28,33,000 विवाहित पुरुष, 61,18,000 विवाहित स्त्रियां, 66,000 विधुर और 1,34,000 विधवाए दिखाई गई है । 14 साल उम्र की विवाहित स्त्रियों तथा 15, व 16 और 17 साल के विवाहित पुरुषो की सख्या क्या है, यह मालूम नही है । इस जन-गणना से यह मालूम हुआ है कि लगभग 92,00,000 विवाह ऐसे हुए है, जो कानून तोड़ कर ही किये गये थे । देश के विभिन्न इलाको मे कानून के विरुद्ध बाल-विवाह इस प्रकार हुए है :—

तालिका 23

इलाका	15 साल से कम आयु वाले विवाहित, विधुर तथा विधवाएं	
	संख्या	इलाके की कुल आबादी का प्रतिशत
उत्तरी भारत	25,70,000	4.1
पूर्वी भारत	27,60,000	3.2
दक्षिणी भारत	5,20,000	0.7
पश्चिमी भारत	6,80,000	1.7
मध्य भारत	19,20,000	3.7
उत्तर-पश्चिमी भारत	7,00,000	2.2
भारत	91,50,000	2.6

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बाल-विवाहों की संख्या करीब करीब सभी स्थानों पर स्पष्टतः घट रही है। 1941 में 15 साल से कम उम्र वाली विवाहिता स्त्रियों का अनुपात विवाहित पुरुषों के मुकाबले में 9.6 प्रतिशत था, और अब 1951 में यह प्रतिशत घट कर 7.4 रह गया है। इसी प्रकार यह अनुपात उत्तर भारत में 10.9 से 10.1, पूर्वी भारत मे 10.5 से 8.2, दक्षिण भारत में 5.2 से 2.6, पश्चिमी भारत में 9.5 से 6.0, मध्य भारत मे 12.8 से 10.6 और उत्तर-पश्चिमी भारत में 7.4 से 6.5 हो गया है।

जन्म और मृत्यु का अनुपात

नीचे की तालिका मे 1931 से 1946 तक की जन्म और मृत्यु संख्यायें दिखलाई गई है, जब भारत अविभक्त था। साथ ही 1947 से 1950 तक की जन्म और मृत्यु संख्यायें भी दिखलाई गई हे।

तालिका 24

वर्ष	प्रति हजार के पीछे		
	जन्म अनुपात	मृत्यु अनुपात	शिशु-मृत्यु
1931	35	25	179
1932	34	22	169
1933	36	23	171
1934	34	25	187
1935	35	24	164
1936	36	23	162
1937	35	22	162
1938	34	24	167
1939	34	24	156
1940	33	22	160
1941	32.1	21.9	158
1942	29.5	21.4	163
1943	26.1	23.9	165
1944	25.8	24.5	169
1945	28.0	22.1	151
1946	28.9	18.7	136
1947	26.6	19.7	146
1948	25.4	17.1	130
1949	26.7	16.0	123
1950	24.8	16.0	127

ऊपर जो आंकड़े दिये गये हैं, वे विभिन्न राज्यों द्वारा रखी हुई पंजीकरण सामग्री पर आधारित हैं। यहां यह बता देना चाहिये कि अधिकांश राज्यों में पंजीकरण की पद्धति न तो

सन्तोषजनक है और न वह कुशलता-पूर्वक रक्खी जाती है। इसी कारण जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में हमें रजिस्टरों में जो आकड़े मिलते हैं, उन में और दस-वर्षीय जन-गणना के आकड़ों में बहुत अन्तर हो जाता है।

पंजीकरण सम्बन्धी सामग्री, जनगणना के आकड़े तथा अन्य इस प्रकार की सूचनाओं की छानबीन और अध्ययन करने के बाद 1951 की जन-गणना की रिपोर्ट में ये परिणाम निकाले गये हैं :—

गत 10 वर्षों मे यानी 1941–50 में :—

(1) प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियो के पीछे 40 नए जन्म हुए।
(2) प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियो के पीछे 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
(3) इस तरह प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियो के पीछे 13 आदमियों की वृद्धि हुई।

धर्म :—

1951 की जनगणना में भी पहले की जन-गणनाओ की तरह धर्म सम्बन्धी आकड़े एकत्र किये गये थे। गणना सम्बन्धी लेखा पहलेपहल धार्मिक आधार पर तैयार किया जाता था, पर इस बार गणना जीविका के प्रधान साधनो के आधार पर की गई है। इसलिये इस जन-गणना मे आबादी के वर्गो के लिये जो सूचना एकत्र की गई है, वह केवल विभिन्न धर्मों के मानने वालो की सख्या की जानकारी तक ही सीमित है। नीचे जो आकड़े दिये गये है, उनमे पता चलेगा कि कितने लोग किस धर्म को मानने वाले हैं।

तालिका 25

धर्म	सख्या	प्रति 1,000 व्यक्तियो पर
हिन्दू	30,32,00,000	8,499
सिख	62,00,000	174
जैन	16,00,000	45
बौद्ध	2,00,000	6
पारसी	1,00,000	3
ईसाई	82,00,000	230
मुसलमान	3,54,00,000	993
यहूदी	...	...
दूसरे धर्म (कबायली).	17,00,000	47
दूसरे धर्म (गैर कबायली)	1,00,000	3
सर्व धर्म	35,67,00,000	10,000

विशेष वर्ग :—

1951 के पहले जब भी जन-गणना होती थी, तो प्रत्येक व्यक्ति से उसकी नस्ल, उपजाति या जाति के सम्बन्ध में पूछा जाता था। यह प्रथा भारत में पृथकता की भावना बढ़ाने वाली थी।

इस कारण 1951 की जन-गणना मे जातपातमूलक विभिन्नताओं का लेखा बन्द कर दिया गया। केवल उन्ही विशेष वर्गों के सम्बन्ध मे गणनाएं की गईं, जिन के सम्बन्ध में संविधान मे विशेष-रूप से उल्लेख है। एक व्यक्ति विशेष वर्ग का सदस्य केवल उसी हालत में माना गया है, जब कि वह "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित उपजाति", अन्य किसी पिछड़े हुए वर्ग का सदस्य हो या "ऐंग्लो इण्डियन" हो। नीचे की तालिका में विभिन्न राज्यों की इन विशेष वर्गों की आबादी दिखलाई गई है।

तालिका 26

विशेष वर्गों की आबादी

राज्य	एंग्लो इण्डियन	अनुसूचित जातिया	अनुसूचित जन-जातिया
अजमेर	298	80,974	9,816
आसाम	1,055	4,24,044	17,35,245
भोपाल	18	1,29,370	59,114
बिहार	4,596	50,57,812	40,49,183
बिलासपुर	4	27,135	..
बम्बई	7,327	30,03,024	33,59,305
चन्द्रनगर	89	..	..
कुर्ग	41	25,690	21,084
दिल्ली	812	2,08,612	..
[illegible]माचल प्रदेश	6	2,24,610	..
[illegible]दराबाद	3,919	28,00,184	3,54,933
कच्छ	..	7,450	17 002
मध्य भारत	186	13,23,881	10,60,812
मध्य प्रदेश	2,634	28,98,968	24,77,024
मद्रास	27,253	85,33,632	6,35,979*
मणिपुर	..	..	1,94,239
मैसूर	10,659	16,08,821	15,310
उड़ीसा	485	26,30,763	29,67,334
पैप्सू	239	6,76,302	..
पजाब	935	23,86,143	2,429
राजस्थान	740	16,09,074	3,16,348
सौराष्ट्र	58	1,19,338	38,849
सिक्किम	..	..	..
तिरुवांकुर-कोचीन	11,990	8,70,139	26,580
त्रिपुरा	94	46,371	1,92,293
उत्तर-प्रदेश	6,343	1,14,79,102	..
विन्ध्य-प्रदेश	240	4,76,234	4,18,282
पश्चिमी बंगाल	31,616	46,96,205	11,65,377
कुल	1,11,637	5,13,43,898	1,91,16,498*

*इन आंकडो मे मद्रास जिले के 5000 व्यक्ति भी शामिल है, जिन्होंने अपने को हरिजन लिखाया था पर उन्हें गलती से अनुसूचित उपजातियो में दिखला दिया गया था।

संविधान की धारा 314 और 342 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आज्ञापत्रो के अनुसार अन्दमान द्वीपपुज, चन्द्रनगर, और सिक्किम की कोई जाति या जनजाति अनुसूचित नही की गई। फिर भी 1951 की जन-गणना मे चन्द्रनगर और सिक्किम पर पश्चिम बगाल की अनुसूचित जनजातियो वाली सूची लागू कर दी गई है। इस आधार पर जो आकडे प्राप्त हुए, वे इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जातिया	अनुसूचित आदिजातियां
चन्द्रनगर	5,457	139
सिक्किम	112	29,429

भाषाएं

सविधान मे ये 14 भाषाए स्वीकृत की गई है —आसामी, बगला, गुजराती, हिन्दी, उर्दू, कन्नड, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पजाबी, सस्कृत, तमिल और तेलगू। देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी स्वीकार की गई है और यह धीरे धीरे अग्रेजी का स्थान ले लेगी। अग्रेजी इस देश मे 1965 तक चलेगी।

1951 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक भाषा के बोलने वालो की सख्या अभी तक प्राप्त नही है।

हिन्दी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, अजमेर, दिल्ली, बिहार, मध्यप्रदेश के अधिकाश भाग, पजाब पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद के कुछ भागो की बोलचाल की भाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप मे हिन्दी का देश भर मे विकास किया जाएगा और उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। पर साथ ही क्षेत्रीय भाषाओ को भी अपने अपने इलाके मे इसी प्रकार पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाएगा।

प्रवासी भारतीय

मोटे तौर पर प्रवासी भारतीयो की कुल सख्या लगभग 40 लाख है। जिन देशो मे उन की सख्या 1 लाख से ऊपर है, वे है सिहल, मलय, सिगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनिडाड, टोबागो, मारीशस, ब्रिटिश गयाना और फिजी द्वीपपुज। इन के अतिरिक्त डच गयाना, केनिया, यूगाडा, टागानिका तथा इडोनेशिया मे उनकी सख्या प्रत्येक स्थान पर 25 हजार से ऊपर है।

भारतीय मजदूरो के बाहर जाने का कार्यक्रम 19वी शताब्दी के प्रारम्भ मे तब से जारी हुआ था, जब उन्हे स्टेट्स सैटलमेन्ट बगानो मे काम करने के लिए ले जाया गया था। 1837 मे जब पहला 'एमीग्रेशन ऐक्ट' पास हुआ, तभी से भारतीय नियमित ढग से बाहर जाकर बसने लगे। उसके पहले यह सब बिल्कुल अनियमित था। 1922 मे इस कानून की जगह पर एक दूसरा भारतीय एमीग्रेशन ऐक्ट पास हुआ। 1938 मे उसमें सशोधन किया गया, और फिर 1940 मे सशोधन हुआ।

नीचे की तालिका मे ससार के विभिन्न देशो मे रहने वाले भारतीयो की सख्या दिखाई गई है :—

तालिका 27

प्रवासी भारतीय

देश का नाम	भारतीयों की संख्या	गणना का वर्ष
राष्ट्रमडलीय देश		
आस्ट्रेलिया	2,500	1947
कैनाडा	3,000	1950
न्यूज़ीलैन्ड	1,200	1952
दक्षिण अफ्रीका	3,65,524	1951
दक्षिण रोडेशिया	4,150	1951
सिंहल (क)	9,85,327	1953
ब्रिटिश मलाया (पाकिस्तानियो को मिला कर)	6,40,709	1952
सिगापुर (क)	83,624	1952
हागकाग	1,500	1952
मारीशस	3,22,972	1952
सेशेल्ज	285	1947
जिब्राल्टर	41	1946
नाइजीरिया	375	1947
केनिया	90,528	1948
यूगान्डा	33,767	1948
न्यासालैण्ड	4,000	1951
जन्जिबार और पेम्बा	15,812	1948
टैगानिका	56,499	1952
जमैका	25,000	1952
ट्रिनीडाड और टोबैगो	227,390	1950
ब्रिटिश गयाना	1,97,696	1951
फिजी द्वीप	1,48,802	1952
उत्तरी रोडेशिया	2,600	1951
ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो	1,298	1948
अदन	9,456	1946

(क) 1953 के 15 मार्च तक जिन भारतीयो तथा पाकिस्तानियों ने इंडियन मिशन में अपना पंजीकरण कराया, उनकी सख्या 18,500 थी ।

तालिका 27--क्रमशः

देशों के नाम	भारतीयों की संख्या	गणना का वर्ष
मारीशस	2,300	1940
ब्रनेई	436	1947
ब्रिटिश सोमालीलैण्ड	250	1946
माल्टा	37	1948
ग्रनाडा	9,000	1946
सेंट लूसिया	7,000	1952
ब्रिटिश हाण्डूरास	2,000	1946
सेरा लीओन	76	1948
ब्रिटेन	7,128	1932
लीवर्ड द्वीप	99	1946
गोल्ड कोस्ट	250	1948
सेंट विंसेन्ट	1,818	1950
बारबेडोस	100	1950
सेंट किट्स	97	1950
डोमिनिका	5	1950
राष्ट्रमण्डलीय देशों में भारतीयों की कुल संख्या	32,54,651	
अन्य विदेश		
बर्मा (1)	...	...
इण्डोनेशीय गणराज्य	40,000	1952
थाई देश	17,000	1952
हिन्दचीन	2,300	1950
जापान	474	1952
बेहरीन	1,135	1948
ईराक	650	1948
मस्कत	1,145	1947
पुर्तगीज पूर्वी अफ्रीका	5,000	1948
मदगास्कर	9,955	1950
रीयूनियन	2,200	1947
संयुक्त राज्य अमेरिका	2,405	1947
ब्राजील	40	1951
पनामा	908	1950
भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियां	3,23,295	1939

(1) बर्मा के सही अंक प्राप्य नहीं हैं। 1931 की जनगणना के अनुसार वहां भारतीयों की जनसंख्या करीब 11 लाख थी। रंगून स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार भारतीयों की जनसंख्या अब लगभग 7 लाख होने का अनुमान है।

तालिका 27 —क्रमशः

देशो के नाम	भारतीयो की संख्या	गणना का वर्ष
अफगानिस्तान (2)	264	1951
ईरान	752	1952
इथियोपिया	1,250 (3)	—
डच गयाना	60,000	1953
फिलिपीन	1,800	1951
लेबनान	49	1948
सीरिया	32	1948
कुवेत	1,250	1948
सऊदी अरब	2,400	1948
फिलिस्तीन	56	1947
जर्मनी	35	1953
आस्ट्रिया	39	1953
इटली	200	1952
बेल्जियन कांगो	1,227	1950
बेल्जियम	60	1952
अान्डा उरुन्डी	1,963	1950
इटालियन सोमालीलैण्ड	1,000	1947
नेपाल	10,441	1941
चेकोस्लोवाकिया	11	1953
बल्गारिया	3	1953
सोवियत रूस	15	1953
स्विट्जरलैण्ड	100	1953
फ्रास	23	1951
नीदरलैण्ड	—	1953
लक्समबर्ग	—	1952
पुर्तगाल	1	1952
युगोस्लाविया	—	1953
विदेशो मे कुल भारतीयो की सख्या (बर्मा को छोडकर)	4,89,478	
सब देशो मे कुल भारतीयो की सख्या (बर्मा को छोडकर)	37,44,129	

(2) ये आकडे केवल काबुल और कन्दहार के ही है। पूरे अफगानिस्तान के सम्बन्ध मे जानकारी अप्राप्य है ।

(3) इथियोपिया के ये आकडे गैर सरकारी है, वहा कभी जनगणना नही हुई ।

भारत
अफ़गानिस्तान
काश्मीर और जम्मू
श्रीनगर
पंजाब
हिमाचल प्रदेश
बिलासपुर
पश्चिमी पाकिस्तान
शिमला
चण्डीगढ़
पैप्सू
पटियाला
पंजाब
दिल्ली
तिब्बत
जयपुर
आगरा
अजमेर
लखनऊ
ग्वालियर
प० बंगाल
शिलांग
पटना
मणिपुर
विन्ध्य-प्रदेश
रीवा
बिहार
कच्छ
भुज
पूर्वी बंगाल
अगरतला
त्रिपुरा
पश्चिमी बंगाल
कलकत्ता
इन्दौर
भोपाल
राजकोट
सौराष्ट्र
नागपुर
कटक
बम्बई
हैदराबाद
करनूल
अरब समुद्र
बंगाल की खाड़ी
मैसोर
बंगलोर
मद्रास
कुर्ग
पोर्टब्लेयर
अन्दमान तथा
निकोबार द्वीपसमूह
ट्रावनकोर कोचीन
त्रिवेन्द्रम
लंका

दूसरा अध्याय

संविधान

भारत का संविधान 22 भागो मे विभक्त है, और उसमें 395 धाराये तथा 9 अनुसूचिया हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान का उद्देश्य अपने सब नागरिको के लिये निम्नलिखित बातो को सुरक्षित करना है :

(क) न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

(ख) विचारो की स्वाधीनता—अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना के सम्बन्ध मे,

(ग) समानता—संविधान की निगाह में सब एक समान है और सब को एक समान अवसर है,

(घ) भ्रातृभाव—व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित करना।

नागरिकता

संविधान की पाचवी धारा मे कहा गया है :

प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का निवासी बन गया है और

(क) जो भारत की सीमा मे जन्मा था, अथवा

(ख) जिस के माता पिता मे से कोई भारत की सीमा मे जन्मा था; अथवा

(ग) जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम पाच वर्ष तक भारत की सीमा मे सामान्यतया रहता आया है,

भारत का नागरिक होगा।

पाकिस्तान से भारत आये प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह भी व्यवस्था की गई है कि—

(क) यदि वह अथवा उस के माता पिता मे से कोई अथवा उस के दादा दादी और नाना नानी मे से कोई भारत-शासन-कानून 1935 (मूल कानून) मे परिभाषित भारत में उत्पन्न हुआ था,

(ख) (1) ऐसा व्यक्ति जो सन् 1948 की जुलाई के उन्नीसवे दिन से पूर्व भारत मे चला आया हो और तब से सामान्यत भारत की सीमा में ही रहता आया हो ; अथवा

(2) ऐसा व्यक्ति जो सन् 1948 की जुलाई के उन्नीसवे दिन या उस के पश्चात् भारत में आया हो, परन्तु संविधान प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत राज्य की सरकार द्वारा निश्चित रीति से आवेदनपत्र दे कर अधिकारप्राप्त भारतीय पदाधिकारी से भारत का नागरिक पंजीकृत कर लिया गया हो।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदनपत्र की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो, तो वह इस प्रकार पंजीकृत नही किया जायेगा।

भारतीय उद्भव के ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिकता का अधिकार दिया गया है, जो इस समय भारत के बाहर अन्यत्र निवास कर रहे हैं। इनमें वे व्यक्ति भी आ जाते है जो, स्वयं अथवा जिनके माता पिता में अथवा दादा दादी या नाना नानी मे से कोई भारत-शासन कानून 1935 मे परिभाषित भारत में जन्मे थे, तथा जो विदेश स्थित भारत के राजनीतिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधियो द्वारा अपने को भारत का नागरिक पजीकृत करा चुके है ।

जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वह फिर भारत का नागरिक नही रह जाता। किन्तु उपरोक्त नियम नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयो के बारे में भारतीय संसद को कानून बनाने से नही रोकते ।

आधारभूत अधिकार

भारतीय नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को इन सात श्रेणियों में विभाजित किया गया है: समता का अधिकार; स्वातन्त्र्य अधिकार; शोषण के विरुद्ध अधिकार; धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार; संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार; सम्पत्ति का अधिकार और सवैधानिक उपचारो का अधिकार ।

समता के अधिकार द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के कारण सभी प्रकार के भेदभावो का निषेध किया गया है । हा, राज्य को महिलाओं तथा बच्चो के लिये किसी विशेष कानून बनाने तथा सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े लोगो, अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो के लोगो के विकास की व्यवस्था करने का अधिकार अवश्य दिया गया है । संविधान के अन्तर्गत सरकारी नौकरियो के सम्बन्ध मे सभी लोगो को समान अवसर दिया जायेगा । अस्पृश्यता का किसी भी दशा मे आचरण करना निषिद्ध ठहराया गया है, और अस्पृश्यता के कारण किसी को किसी भी कार्य के लिये आयोग्य ठहराना कानून की दृष्टि में (धारा 17) दडनीय अपराध है। साथ ही सविधान द्वारा सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधियो को छोड़ अन्य उपाधियो की प्रथा का भी अन्त कर दिया गया है।

धारा 19 (1) द्वारा भारत के सभी नागरिको को बोलने और भाव प्रकट करने, सस्था या सघ बनाने, भारत राज्य-क्षेत्र मे सर्वत्र आ जा सकने, भारत के किसी भी भाग मे निवास करने या बस जाने, सम्पत्ति के कमाने और व्यय करने, कोई भी वृत्ति या उपजीविका अपनाने तथा कोई भी व्यापार या कारोबार करने के अधिकार की गारटी दी गई है। परन्तु इस से राज्य पर ऐसे कानून बनाने पर रुकावट नही डाली गई जिस के फलस्वरूप राज्य की सुरक्षा हो, विदेशो के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा सदाचार का हित हो। साथ ही न्यायालय-अवमान, मान-हानि अथवा उकसाहट पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये चाहे जैसे कानून बनाये जा सकते हैं । इस के अतिरिक्त इन अधिकारो का किसी भी वर्तमान कानून पर कोई प्रभाव नही पडता, और न सार्वजनिक हित और व्यवस्था के लिये कोई नया कानून बनाने में ही रुकावट आती है ।

सविधान की धारा 21 व 22 मे व्यक्ति की स्वाधीनता का संरक्षण किया गया है । इसी धारा के अनुसार नियमविरुद्ध गिरफ्तारी तथा अनियमित नजरबन्दी पर भी रोक लगाई गई है। अन्य अधिकारो द्वारा बेगार, बाल-श्रम तथा मनुष्यों के व्यापार का प्रतिषेध लगाया गया है,

धार्मिक मामलो मे अन्त करण की स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया गया है , अल्पसख्यको के सास्कृतिक और शिक्षासम्बन्धी हितो की रक्षा की गई है तथा यह कहा गया है कि पर्याप्त मुआवजा दिये बिना सरकार किसी की सम्पत्ति पर कब्जा न कर सकेगी ।

धारा 32 के अनुसार उपरोक्त अधिकारो के सम्बन्ध मे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है । यह निश्चय कराने के लिये कि इन अधिकारो का पूर्ण पालन किया जायेगा धारा 12 मे राज्य की परिभाषा करते समय कहा गया है "राज्य के अन्तर्गत भारत की सरकार और ससद तथा भा त य राज्यो में से प्रत्येक की सरकार और उन के विधानमडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य अधिकारी भी है ।" एक दूसरे उपबन्ध (धारा 13)द्वारा वे सभी कानून, जो इन अधिकारो के विरोधी है और जो इस सविधान के प्रारम्भ होने से पहले चालू थे, उस मात्रा तक अवैध घोषित कर दिये गये है, जहा तक उनका इन अधिकारों से विरोध है ।

निर्देशक सिद्धान्त

न्यायालयों द्वारा लागू न किये जा सकने पर भी निर्देशक तत्व देश के शासन मे मूलभूत माने जाते है । धारा 38 में कहा गया है : लोक कल्याण की भावना से राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बढाने का अधिकतम प्रयत्न करेगा, जिस मे सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सकेगा । धारा 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का ऐसा सचालन करेगा जिस से कि निश्चित रूप से

(क) सभी नागरिको को, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ;

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बटा हो, जिस से सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सम्पन्न हो ;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन के साधनो का ऐसा एकत्रीकरण न होता चला जाए, जो सार्वजनिक हित का विरोधी हो ;

(घ) पुरुषो और स्त्रियो दोनो को समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाए ,

(ङ) श्रमिक पुरुषो और स्त्रियो के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालको की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके । साथ ही आर्थिक आवश्यकता से विवश हो कर नागरिको को ऐसे रोजगार मे न जाना पडे, जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल न हो ;

(च) बच्चो और कम उम्र के लो ो का शोषण या चारित्रिक तथा भौतिक पतन न होने दिया जाए ।

स्वायत्त शासन की इकाइयो के रूप मे राज्य ग्राम-पचायतो का संगठन करेगा, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओ के भीतर राज्य सभी नागरिको की रोज़गारी, शिक्षा आदि का प्रबन्ध करेगा और बुढापा, बीमारी और अगहीनता आदि की दशाओ मे सार्वजनिक सहायता देने का प्रबन्ध करेगा । वह नागरिकों के भोजन तथा जीवनस्तर को भी ऊचा करने का प्रयत्न करेगा । स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक द्रव्यो के यथासभव प्रतिषेध करने तथा कृषि और पशु-पालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियो द्वारा सगठितकरने का प्रयत्न किया जाएगा । यह भी

निश्चय किया गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का तथा राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धो को बनाने और बढाने का प्रयास करेगा।

यूनियन कार्यकारी

भारतीय संविधान मे संसदीय पद्धति द्वारा देश के शासन की व्यवस्था है। केन्द्र की कार्यपालिका म एक राष्ट्रपति और एक मन्त्रिपरिषद् है।

राष्ट्रपति

भारत यूनियन का कार्यकारी मुखिया भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। सघ की कार्यकारी शक्ति, जिस मे सेनाओ का उच्चतम कमाड भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति मे निहित है और राष्ट्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचक मडल करता है, जिस मे संसद् के दोनो सदनो के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यो की विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य है। निर्वाचन सानुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार इकहरे सक्रमणशील मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु से अधिक तथा लोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये। राष्ट्रपति अपने पद पर पाच वर्ष तक रह सकता है, तथा वह दुबारा भी चुना जा सकता है। सविधान के अतिक्रमण की दशा मे राष्ट्रपति पर अभियोग चला कर उसे पदच्युत भी किया जा सकता है।

राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। वह ससद के दोनो सदनो की बैठक बुला सकता है, सत्र को समाप्त किये बिना बैठक स्थगित करवा सकता है, दोनो सदनो को सम्बोधित कर सकता है तथा उनको सन्देश भेज सकता है। वह अध्यादेश जारी कर सकता है तथा ससद द्वारा पास किये गये कानूनो पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। कुछ खास मामलो मे राष्ट्रपति दड क्षमा, उस का परिहार अथवा दडादेश को लघु भी कर सकता है।

उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति को चुनने वाला निर्वाचक मडल ही उपराष्ट्रपति को भी चुनता है। उस का कार्यकाल भी पाच वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यपरिषद् के सभापति का कार्य करता है। राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति मे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करता है। राष्ट्रपति का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रपति के रूप मे उस समय तक कार्य करेगा, जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार न सभाल ले।

मन्त्री-परिषद्

सविधान की धारा 74 मे एक मत्री-परिषद् की व्यवस्था की गई है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करती है। परिषद् का मुखिया प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य मत्री भी प्रधानमत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते है, यद्यपि मत्रीपरिषद् राष्ट्रपति की इच्छा की अवधि पर्यन्त रहती है, तो भी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

सविधान की 78 धारा मे ऐसी व्यवस्था है कि प्रधानमत्री मत्री-परिषद् के यूनियन के प्रशासन सम्बन्धी सभी निश्चयो को राष्ट्रपति तक पहुचाये तथा राष्ट्रपति के कहने पर उस विषय को, जिस पर किसी मत्री ने निश्चय कर दिया हो, किन्तु मत्रीपरिषद् ने विचार नही किया हो, परिषद् के सम्मख विचार के लिये पेश करे।

ससद्

यूनियन का व्यवस्था सम्बन्धी भाग राष्ट्रपति और दो सदनो — (1) राज्य सभा और (2) लोक सभा—से मिल कर बनता है ।

राज्यपरिषद्

राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है । इनमे से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा आदि के क्षेत्रो मे उनकी ख्याति के कारण नामजद किये जाते है । शेष सदस्य राज्यो के प्रतिनिधि होते है । स्थानो का बटवारा संविधान की चतुर्थ अनुसूची के उपबन्धो के अनुसार होता है ।

पूरी राज्य सभा कभी नही बदलती । इस के एक तिहाई सदस्यो का कार्यकाल प्रति दो वर्षो के बाद समाप्त हो जाता है, और उन स्थानो का नया चुनाव होता है । राज्य सभा के निर्वाचन परोक्ष होते है । प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित सदस्यो का निर्वाचन उसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यो द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सक्रमणशील मत पद्धति के अनुसार होना है ।

लोक सभा

लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 है, जो जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जाते है । निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बाटे जाते है कि प्रति 7,50,000 की जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति 5,00,000 की जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न रहे (धारा 81)।

कोई व्यक्ति ससद् मे न चुना जा सकेगा, जब तक कि वह

(क) भारत का नागरिक न हो,

(ख) राज्य सभा के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का तथा लोक सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का न हो, तथा

(ग) ऐसी अन्य योग्यताये न रखता हो जोकि इस बारे मे ससद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जाये ।

संविधान द्वारा ससद् के दोनो सदनो के सदस्यो को कई अधिकार और विशेषाधिकार दिये गये है । धारा 105(2) के अनुसार ससद् मे या उस की किसी समिति मे कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय मे ससद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय मे कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, ससद् के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मत या कार्यवाहियो के प्रकाशन के विषय मे इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी । ससद् के प्रत्येक सदन के सदस्य की शक्तिया, विशेषाधिकार और छूट ऐसी होगी, जैसी ससद् समय-समय पर नियत करे तथा इस सम्बन्ध मे जिन बातो पर ससद कोई नियम नही बनाती, उन के बारे मे जो कायदे कानून इग्लिस्तान की पार्लियामेट के हाउस आफ कामन्स के है, वे ही लागू होगे ।

न्याय

भारत के उच्चतम न्यायालय मे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये एक मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधीश, जो 7 से अधिक न हो, होते है । न्यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था तक पद पर बने

रहते है । यदि आवश्यक हो तो धारा 124 (1) के अन्तर्गत ससद् अधिक सख्या भी निर्दिष्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट मे एतदर्थ तथा पेन्शन प्राप्त जजो की नियुक्ति भी हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिये व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और वह (क) किसी एक या दो हाईकोर्टों का कम से कम पाच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा (ख) किसी एक या दो हाई कोर्टो मे दस वर्ष तक लगातार वकील रहा हो अथवा (ग) राष्ट्रपति की राय मे कानून का पडित हो। उच्चतम न्यायालय से अवसर-प्राप्त मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश भारत की किसी अदालत मे वकालत का काम नहीं कर सकता ।

राज्य सरकारे

राज्यपाल

सविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'क'[1] मे उल्लिखित राज्य का मुख्य-कार्यवाहक राज्य-पाल कहलाता है । राष्ट्रपति साधारणत पाच वर्ष की अवधि के लिये उस की नियुक्ति करते है, और वह उन के प्रसाद पर्यन्त उस पर रहता है। 35 वर्ष से अधिक अवस्था वाले भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्त किये जा सकते है। राज्यपाल केन्द्र अथवा राज्य के किसी विधान मडल के सदस्यत्व का अथवा कोई भी सरकारी लाभ का पद ग्रहण नही कर सकता।

राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल मे निहित है, और उस से प्रत्यक्षत अथवा अपने अधीन अधिकारियो द्वारा सविधान के अनुरूप इस शक्ति के प्रयोग की अपेक्षा की जाती है ।

मंत्रिपरिषद्

धारा 163 मे एक ऐसी मत्रिपरिषद् की व्यवस्था है, जो सिवाय उन मामलो मे, जहा सविधान के अन्तर्गत राज्यपाल से अपने निर्णय की अपेक्षा की जाती है, सभी कामो मे राज्यपाल को मत्रणा और सहायता देती है । इस का नेता मुख्यमत्री होता है। मुख्य मत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है । अन्य मत्री मुख्यमत्री की सलाह पर नियुक्त किये जाते है। मत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के सम्मुख उत्तरदायी है ।

विधान मडल

संविधान मे प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मडल की व्यवस्था है । बिहार, बम्बई, मद्रास, पजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मैसूर इन 7 राज्यो में दो सदनो के विधानमडल है। शेष राज्यो मे एक सदन के विधान मडल है । उच्च सदन विधान परिषद् कहलाता है और निचला सदन विधान सभा ।

विधान सभा

किसी विधान सभा के सदस्यों की कुल सख्या 500 से अधिक और 60 से कम न होगी । साधारण तौर से 75,000 जनसख्या के पीछे एक सदस्य लिया ै। विधान सभा का साधारण कार्य काल 5 ५५ है, यदि इस से पूर्व उसे भग न कर दिया जाए ।

---

1 भाग 'क' के 10 राज्य निम्नलिखित है—आसाम, आन्ध्र, बिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, ास, उडीसा, पजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ।

विधान परिषद्

किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक चौथाई से अधिक न होगी। कम से कम निर्दिष्ट संख्या 40 है। जब तक कि संसद् किसी विधि द्वारा अन्य व्यवस्था न कर दे, विधान परिषद् के आधे सदस्य स्थानीय प्रशासन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के स्नातकों और शिक्षकों के निर्वाचकमंडलों द्वारा निर्वाचित किये जायंगे। एक तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किये जायंगे, जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं और शेष राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायेंगे, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है। केन्द्र में अपने प्रतिरूप की तरह विधान परिषदें स्थायी हैं, प्रति दूसरे वर्ष के बाद उनके एक तिहाई सदस्य निवृत्त होते रहते हैं।

राज्य विधान मंडल में निर्वाचन के लिये ये बातें आवश्यक हैं—

(क) भारतीय नागरिक होना।

(ख) विधान सभा के स्थान के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और विधान परिषद् के लिए 30 वर्ष।

(ग) ऐसी योगताएं, जो इस सम्बन्ध में संसद् द्वारा बनाई किसी विधि अथवा उसके अन्तर्गत आवश्यक करार दी जाए।

प्रत्येक राज्य के विधान मंडल में भी भाषण की स्वतन्त्रता है, और इस सम्बन्ध में उन की स्थिति संसद् के समान है।

न्याय

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) का विधान है। इस में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। वे 60 वर्ष की अवस्था तक अपने पद का उपभोग कर सकते हैं।

भाग 'ख' के राज्य [1]

धारा 238 में निर्दिष्ट कुछ रूपभेदों और छूटों के अतिरिक्त भाग 'क' के राज्यों पर लागू होने वाले सभी उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' में उल्लिखित सभी राज्यों पर लागू होंगे। ये रूपभेद विशेष रूप से राज्य के मुख्य के पद के बारे में और भूतपूर्व नरेशों की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के कुछ विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में हैं।

इन राज्यों में राज्य का मुख्य (जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त) राजप्रमुख कहलाता है। जम्मू और काश्मीर में वह 'सदरे रियासत' कहलाता है। राज्य का राजप्रमुख राष्ट्रपति द्वारा इसी रूप में मान्यता प्राप्त करता है और वह उन सभी मतों और विशेषाधिकारों का हकदार है

1. भाग 'ख' के य 8 राज्य हैं : हैदराबाद, जम्मू और काश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पैप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, और तिरुवाकुर-कोचीन।

जो राष्ट्रपति सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निश्चित कर दे । राज्य के मुख्य कार्यपालक के रूप मे राजप्रमुख की भी स्थिति 'क' राज्यो के राज्यपाल के समान है ।

भाग 'ग' के राज्य [1]

सविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'ग' मे निर्दिष्ट राज्यो का प्रशासन राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त द्वारा करेगे। इन राज्यो का प्रशासन पडौसी राज्य की सरकार द्वारा भी किया जा सकता है। ससद् को अधिकार है कि इन राज्यो मे स्वायत्त शासन को बढाने के अभिप्राय से इन राज्यो के लिये स्थानीय विधान-मडल या मत्रणादाताओ या मत्रियो की परिषदो की स्थापना कर दे । इसी के अनुरूप भाग 'ग' के 6 राज्यो मे निर्वाचित विधान-मडल या इलैक्टोरल कालेज और मत्रिपरिषदे स्थापित की जा चुकी है ।

सघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध

वैधानिक सम्बन्ध

संसद समस्त भारत के बारे मे या उस के किसी भाग के बारे मे कानून बना सकती है और राज्य का विधानमडल समस्त राज्य या राज्य के किसी भाग के बारे मे कानून बना सकता है। संसद का बनाया कोई कानून कभी इस आधार पर अवैध नही होगा कि वह क्षेत्र के आधार पर अथवा क्षेत्रो का ख्याल किए बिना बनाया गया है ।

यूनियन सूची मे उल्लिखित विषयो के बारे मे पार्लियामेट को कानून बनाने के पूर्ण अधिकार है, और यूनियन की राज्यो की सूची मे उल्लिखित सभी विषयो पर राज्य विधान मडलो के साथ-साथ संसद् को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है ।

एक राज्य विधान-मडल को राज्य सूची मे उल्लिखित किसी भी विषय के बारे में कुल राज्य या उस के एक भाग के लिये विधि निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है। विधान निर्माण की अतिरिक्त (रेजिड्यूअरी) शक्तिया भारतीय ससद् मे निहित है (धारा 248) ।

शासन सम्बन्ध

प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस ढग से प्रयोग किया जाएगा कि ससद् द्वारा निर्मित कानूनो और राज्य मे प्रयुक्त होने वाले कानूनो मे परस्पर कोई टकराव न हो । सघ की कार्यकारी शक्ति उस सीमा तक राज्य को निर्देश देगी, जहा तक कि वह इस उद्देश्य के लिये आवश्यक समझे (धारा 256)। राज्य सरकारो से आशा की जाती है कि वे अपनी शक्तियो का इस ढंग से प्रयोग करेगी कि यूनियन की कार्यकारी शक्ति पर उस का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

यूनियन के कार्यकारी अधिकारियो को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे राज्य के राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व के घोषित सचार साधनो के निर्माण और स्थिति के बारे मे आदेश दे सके । संसद् को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह किसी राजमार्ग अथवा जल-मार्ग को राष्ट्रीय घोषित कर दे । यूनियन के कार्यकारी अधिकारी नौ-सैनिक, सैनिक और वायु शक्ति के सम्बन्ध मे जरूरी रास्तो का निर्माण कर सकते है और उन की रक्षा के लिये प्रबन्ध कर सकते है। वे राज्यो के भीतर रेलो की सुरक्षा के लिये भी आवश्यक उपाय कर सकते

---

[1] भाग 'ग' मे ये 9 राज्य है : अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मनिपुर, त्रिपुरा और विन्ध्यप्रदेश ।

है। इस के साथ ही धारा 258 मे इस बात की भी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से कुछ शर्तो पर अथवा बिना शर्त उस सरकार अथवा उस के अधिकारियो को ऐसे कार्यों की जिम्मेवारी सौप दे जिन पर यूनियन की कार्यकारी शक्ति का अधिकार है।

जन-हित की दृष्टि से एक अन्तर्राज्य परिषद् के निर्माण की भी व्यवस्था है ताकि—

(क) राज्यो के बीच उठने वाले झगडो की छान-बीन कर उन्हे परामर्श दिया जा सके,

(ख) ऐसे विषयो की चर्चा और अनुसन्धान किया जा सके, जिस मे कुछ अथवा सब राज्यो का अथवा यूनियन और एक अथवा अधिक राज्यो का साझा हित है ; या

(ग) राज्यो मे परस्पर ताल-मेल बढाने के उपायो पर विचार किया जा सके और उसके उपाय सुझाये जा सके ।

ऐसी किसी परिषद् की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से हो सकती है ।

यूनियन सूची

यूनियन सूची मे 97 विषय है और इन मे रक्षा, परमाणु शक्ति वैदेशिक मामले, नागरिकता और निष्कासन, रेले और राष्ट्रीय राजपथ, समुद्रपथ, नौवहन, व्यापारिक समुद्री यातायात और राष्ट्रीय जलमार्ग, विमान और वायुपथ, डाक और तार, नोट और सिक्के, महाजनी और बीमा, विदेशी मुद्रा-विनिमय, विदेशो के साथ व्यापार और वाणिज्य, व्यापार चिन्ह, पैटेण्ट, आविष्कार, नमूने और कापीराइट, सीमा-शुल्क, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, कारपोरेशन कर आदि विषय सम्मिलित है ।

राज्य सूची

राज्य सूची मे 66 विषय है और इन मे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय का प्रशासन, जेल और सुधारालय, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आरोग्य, शिक्षा, भूमि, वन और मछली व्यवसाय, चुगी-कर तथा कृषि-कर, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका, विलास की वस्तुओ पर कर, मनोरजन-कर, शर्त और जूए पर कर आदि विषय सम्मिलित है।

समाधिकार सूची

समाधिकार सूची मे 47 विषय है। इनमे दड-विधि और दण्ड प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शर्तनामे, खाद्यो मे अपमिश्रण, ट्रेडयूनियन, मजदूरो का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, आर्थिक और सामाजिक आयोजना, मूल्य नियन्त्रण, कारखाने, बिजली, समाचारपत्र, पुस्तके और मुद्रणालय आदि सम्मिलित है ।

यदि एक राज्य के विधान मडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ससद् द्वारा बनाये गये किसी कानून के विरुद्ध है, अथवा समाधिकार सूची मे उल्लिखित विषयो के सम्बन्ध मे दोनो पक्षो द्वारा बनाये गये कानूनो मे कोई विरोध है, तो ससद् निर्मित कानून ही मान्य होगा । फिर, यदि राज्य सभा (काउन्सिल आफ स्टेट) दो-तिहाई सख्या के बहुमत से यह निश्चय कर ले कि राज्य सूची मे उल्लिखित किसी विषय के बारे मे भी ससद कानून बनाये, तो उस विषय पर भी ससद् कानून बना सकती है ।

संकटकालीन निवेश

युद्ध अथवा भीतरी उपद्रवो के कारण उत्पन्न गभीर सकट के समय राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा (क) उस प्रदेश के राज्यो को निदेश दे सकते है कि वे अपने अधिकारो का प्रयोग किस रूप मे करे ; साथ ही वह (ख) सविधान की उन धाराओ को भी स्थगित कर सकते है जिन के अनुसार यूनियन राज्यो को कुछ आर्थिक सहायता देता है । इस विपत्तिकालीन अवधि में यूनियन की संसद् राज्य सूची मे उल्लिखित किसी भी विषय के बारे में कानून बना सकती है ।

चुनाव कमीशन

ससद् और राज्यो के विधान मडलो के सभी चुनावो तथा सघ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावो की देखरेख, निर्देशन और नियन्त्रण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक चुनाव कमीशन करेगा । मुख्य चुनाव कमीशनर को वही अधिकार और सुविधाए प्राप्त होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है ।

लेखा-परीक्षा

सविधान मे इस बात की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति भारत का एक नियत्रक (कण्ट्रोलर) और एक महालेखा परीक्षक नियुक्त करे, जो यूनियन और राज्यो के वित्तीय साधनो और हिसाब-किताब पर निगाह रखे । यह देखना उस का उत्तरदायित्व है कि संसद् अथवा किसी राज्य के विधान मडल द्वारा पास किये गये और विनियोग अधिनियम मे दिये गये व्यय से अधिक या अन्य मद मे तो व्यय नही होता ।

व्यापार और वाणिज्य

समस्त भारतीय प्रदेश मे व्यापार, वाणिज्य, आने जाने की स्वतन्त्रता के सामान्य सिद्धान्त सविधान मे विद्यमान है । तथापि संसद और राज्य विधान मडलो को यह अधिकार प्राप्त है कि जहां कही किसी विशेष वस्तु का अभाव हो तो राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक हित के विचार से उन पर बाधायें लगा सकें । परन्तु किसी भी विधान मंडल को, चाहे वह संसद् हो अथवा किसी राज्य का विधान मंडल, ऐसा कानून बनाने का अधिकार नही है जिस से सातवी अनुसूची मे उल्लिखित वस्तुओ के व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध मे एक राज्य को दूसरे राज्य की अपेक्षा अधिक सुविधाये दी जा सकें अथवा जिस मे विभिन्न राज्यो के प्रति भेदभाव प्रदर्शित हो । केवल भाग 'ख' के कुछ राज्य दस वर्ष की अवधि तक के लिये इस निवेश से मुक्त कर दिये गये है । यह विशेषाधिकार उन्हे इसलिये दिया गया है कि सविधान के लागू होने से पूर्व वे इस का उपभोग करते थे और भारत सरकार के साथ इस सम्बन्ध मे एक करार कर चुके थे ।

सरकारी भाषा

धारा 343 मे व्यवस्था है कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी और सरकारी उद्देश्यो के लिये भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूपो का प्रयोग होगा । तथापि संविधान जारी होने से 15 वर्षों तक अग्रेजी भाषा सरकारी भाषा के रूप मे जारी रहेगी । इस अवधि मे राष्ट्रपति को एक विशेष कमीशन बनाने का अधिकार होगा जो हिन्दी के विकास और उन्नति का निरीक्षण करे और सभी सभावित उद्देश्यो के लिये इस के प्रयोग का

उन्नतिशील विस्तार करे । उद्देश्य यह है कि निश्चित अवधि की समाप्ति पर हिन्दी पूर्ण रूप मे अंग्रेजी का स्थान ले ले ।

सविधान के अनुसार किसी राज्य का विधान मडल कानून बना कर राज्य मे प्रचलित एक या कई प्रादेशिक भाषाओ[1] को अथवा हिन्दी को सभी सरकारी उद्देश्यो अथवा विशेष कार्यों के लिये राज्य भाषा स्वीकार कर सकता है । राज्यो के बीच और राज्य तथा यूनियन के बीच उसी भाषा का प्रयोग होगा, जो यूनियन की भाषा है अर्थात् 15 वर्षो तक अंग्रेजी और बाद में हिन्दी । सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्टों की कार्रवाई तथा कानूनो के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई है और धारा 348 मे इस बात की व्यवस्था भी की गई है ।

सविधान मे सशोधन

धारा 368 मे व्यवस्था है कि सविधान मे सशोधन, ससद् के किसी भी सदन मे पेश किया जा सकता है और जब वह दोनो सदनो मे उपस्थित सदस्यो की दो-तिहाई सख्या के बहुमत से पास हो जाए, तो उसे राष्ट्रपति के सम्मुख उन की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जाएगा और उस अनुमति के प्राप्त हो जाने पर वह सविधान का भाग बन जाएगा । केवल निम्नलिखित सशोधनो के लिये राज्यो की कम से कम आधी सख्या का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है--सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, केन्द्र और राज्यो के बीच शक्तियो का वितरण, तीनो व्यवस्थापिका सूचिया पार्लियामैण्ट मे राज्यो का प्रतिनिधित्व तथा सविधान मे सशोधन की विधि ।

---

[1]. संविधान की आठवी अनुसूची मे भारत की निम्नलिखित 14 भाषाओ को प्रादेशिक भाषा स्वीकार किया गया है : असमिया, बगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पजाबी, सस्कृत, तमिल, तेलगु और उर्दू ।

तीसरा अध्याय

राष्ट्र के प्रतीक

राष्ट्रीय चिन्ह

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तम्भ के शीर्ष का प्रतिरूप है। इस में एक चौरस गोल पत्थर पर 3 सिंह खड़े हैं और चौकोर आधा पर बीच में उभरा हुआ "धर्मचक्र" है, दाईं ओर एक बैल है, बाईं ओर एक घोडा तथा दायें-बाये छोर पर धर्मचक्र की रूपरेखा अंकित हैं। चिन्ह के नीचे मुण्डक उपनिषद् से लिये गये "सत्यमेव जयते" (सत्य ही की विजय होती है) शब्द देवनागरी लिपि में अंकित हैं।

26 जनवरी, 1950 को भारत सरकार ने सिंह मस्तक को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। इस तथ्य से कि मूल सिंह मस्तक का यह चिन्ह 242–232 ई० पू० तैयार किया गया था, और यह सम्राट् अशोक द्वारा उस स्थान के प्रतिष्ठान के लिये बनाया गया था, जहा बुद्ध ने अपने शिष्यो को सर्वप्रथम अष्टांग मार्ग मे दीक्षित किया था, चिन्ह को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो गया है। एक बालुए पत्थर में से तराशी लाट के मस्तक पर यह चक्र था।

राष्ट्रीय झंडा

राष्ट्रीय झंडे मे 3 समानान्तर रंग हैं—सब से ऊपर केसरी, बीच मे श्वेत और नीचे गहरा हरा। सब पट्टिया बराबर चौडाई की हैं। झंडे की लम्बाई-चौडाई का अनुपात 3 और 2 है। झंडे का चिन्ह सारनाथ मे अशोक स्तम्भ के मस्तक के चक्र की हूबहू प्रतिलिपि है, और यह बीच की पट्टी पर बनाया जाता है। यह चक्र सफेद पट्टी जितना चौडा है। इस का रंग गहरा नीला है और चक्र मे 24 अरे हैं।

22 जुलाई, 1947 को भारत की संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था और 14 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रि सत्र मे भारत की नारियों द्वारा यह राष्ट्र को भेंट किया गया था।

झंडे का प्रयोग

झंडे के समुचित प्रयोग की गारंटी के लिये गृह मंत्रालय और सेना के सदर मुकामो ने नियम बना दिये हैं। यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सम्मान मे न झुकाया जाये जहा इस सम्मान की आवश्यकता हो, वहा रेजिमेंट का झंडा, राज्य का झंडा, संगठन या संस्था का झंडा यह काम देगा।

राष्ट्रीय झंडे के ऊपर या इस के दाहिनी ओर कोई भी अन्य झंडा अथवा चिन्ह न रखा जाये। यदि झंडे एक पंक्ति मे फहराने हो, तो सभी झंडे राष्ट्रीय झंडे के बाईं ओर रहेंगे, और यदि उन को ऊंचे फहराना हो तो राष्ट्रीय झंडा सब से ऊपर फहराया जाये।

यदि राष्ट्रीय झंडे के साथ अन्य झंडे भी एक ही ध्वजदंड पर फहराये जाने हों, तो राष्ट्रीय झंडा सब से ऊपर रहना चाहिये। झंडे को लिटाकर या गिरी हुई अवस्था मे कभी न ले जाया जाये, सदा ऊंचा और खुला हुआ ले जाया जाये। जब कभी किसी जुलूस में राष्ट्रीय झंडा ले जाया जाये, तो यह ध्वजावाहक के दाहिने कन्धे पर ऊंचा उठा रहे और जुलूस के आगे-आगे रहे।

जब झंडे को किसी खिड़की या छज्जे या भवन के आगे एक दंड पर क्षितिज समानान्तर अथवा किसी कोण पर झूलता हुआ दिखाया जाये, तो केसरिया भाग सब से ऊपर रहे।

भवनों पर प्रदर्शन

साधारणतया राष्ट्रीय झंडा केन्द्र और राज्यो मे उच्च न्यायालयो, सचिवालयो, कमिश्नरो और कलक्टरो के दफ्तरो, जेलो, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा म्युनिसिपैलिटियो के दफ्तरो जैसे सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनो पर फहराया जाना चाहिये। तथापि सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ विशेष स्थानो पर राष्ट्रीय झंडा लहरा सकता है। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति, राज्यपालो और राजप्रमुखो के अपने निजी झंडे है।

स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गाधी के जन्म-दिवस और राष्ट्रीय सप्ताह आदि विशेष अवसरों पर झडे के प्रयोग पर कोई रोक-टोक न होगी।

राष्ट्रीय गान

24 जनवरी, 1950 को "जनगणमन" भारत के राष्ट्रीय गान के रूप मे अंगीकृत हुआ। उस के साथ ही यह निर्णय भी किया गया कि "वन्दे मातरम्" को भी, जिस ने कि भारत के स्वाधीनता सग्राम मे ऐतिहासिक भाग अदा किया है, समान दर्जा प्राप्त रहेगा।

"जनगणमन"

27 दिसम्बर, 1911 को कलकत्ता काग्रेस अधिवेशन मे श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर का "जनगणमन" प्रथम बार गाया गया था। जनवरी 1912 मे यह गान "भारत विधाता" शीर्षक से "तत्वबोधिनी पत्रिका" मे, जिस के सम्पादक स्वय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे, सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। सन् 1911 मे "दि मार्निंग साग आव इण्डिया" शीर्षक से कवि ने स्वय इस का अग्रेजी मे अनुवाद किया था। पूरे गीत मे 5 पद है। प्रथम पद, जिसे सेनाओ ने अगीकार किया है, और जो साधारणतया समारोहो के अवसरो पर गाया जाता है, इस प्रकार है :

जनगणमन अधिनायक, जय हे भारत-भाग्य-विधाता।
पजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बग
विन्ध्य हिमाचल यमुना गगा उच्छल जलधि तरग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे,
गाहे तव जय गाथा।
जनगण मगलदायक, जय हे भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे!

इस का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :

जनता के हृदय सम्राट्, भारत के भाग्य-विधाता, तेरी जय हो। पजाब, सिन्ध, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड, उत्कल, वग, विन्ध्याचल, हिमाचल, गगा, यमुना और सागर की उच्छल तरंगे तेरी शुभ महिमा गाती है, तेरे शुभ आशीष की कामना करती है, तेरी जय गाथा गाती है।

जनता का कल्याण करने वाले, भारत-भाग्य-विधाता, तेरी जय हो, जय हो, जय हो! जय जय जय, जय हो।

वन्दे मातरम्

इस का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है —

वन्दे मातरम् ।	हे मा, मैं तेरी वन्दना करता हूं ।
सुजला सुफला मलयज शीतलाम्	शुभ जल मे आप्लावित, फलो से लदी, मलय पवन से शीतल,
शस्यश्यामला मातरम् ।	लहलहाती फसलो से हरी-भरी, मा !
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्,	तेरी राते शुभ्र चादनी से आनन्दमय है,
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,	तू फूलो से लदे वृक्षो से शोभायमान है,
सुहासिनी सुमधुर भाषिणीम्	सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी,
सुखदा वरदां मातरम् ।	सुखदायिनी, वरदायिनी, मा !
वन्दे मातरम ।	मैं तेरी वन्दना करता हूं ।

चौथा अध्याय

यूनियन सरकार और संसद्

1 जनवरी 1954

राष्ट्रपति	राजेन्द्रप्रसाद
उप-राष्ट्रपति	एस० राधाकृष्णन्

मंत्रिपरिषद्

मंत्री	नाम	पद लेने की तिथि
1. प्रधान मंत्री और वैदेशिक मामलों के तथा प्रतिरक्षा मंत्री	जवाहरलाल नेहरू	13 मई 1952
2. शिक्षा और प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक अन्वेषण	अबुल कलाम आज़ाद	"
3. संचार	जगजीवनराम	"
4. स्वास्थ्य	राजकुमारी अमृतकौर	"
5. वित्त	सी० डी० देशमुख	"
6. योजना, सिंचाई और बिजली	गुलज़ारीलाल नन्दा	"
7. गृह विभाग और राज्य	कैलासनाथ काटजू	"
8. खाद्य और कृषि	रफ़ी अहमद किदवई	"
9. वाणिज्य और उद्योग	टी० टी० कृष्णमाचारी	"
10. कानून और अल्पमतों के मामले	सी० सी० विश्वास	"
11. रेल और परिवहन	लालबहादुर शास्त्री	"
12. निर्माण, आवास और पूर्ति	स्वर्णसिंह	"
13. श्रम	वी० वी० गिरि**	"
14. उत्पादन	के० सी० रेड्डी	"
मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री (परन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)		
15. संसदीय मामले	सत्यनारायण सिन्हा	"
16. पुनर्वास	अजित प्रसाद जैन†	"
17. रक्षा संगठन	महावीर त्यागी*	13 मार्च, 1953
18. सूचना एवं प्रसार	बी० वी० केसकर	13 मई, 1952
19. वाणिज्य	डी० पी० करमारकर	12 अगस्त, 1952
20. कृषि	पंजाबराव एस० देशमुख	"
उपमंत्री		
21. संचार	राजबहादुर	4 जून, 1952

†अगस्त 1954 से मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए है।

*महावीर त्यागी 13 मई 1952 से लेकर 15 मार्च, 1953 तक आय और व्यय के राज्य मंत्री थे।

** वी० वी० गिरि द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर मध्यसितम्बर में श्रममन्त्री के पद पर खंडूभाई देसाई नियुक्त हुए।

उपमंत्री	नाम	पद लेने की तिथि
22. प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अन्वेषण	केशवदेव मालवीय	12 अगस्त, 1952
23. रक्षा	सुरजीतसिंह मजीठिया	"
24. घरेलू मामले	बी० एन० दातार	"
25. श्रम	आबिद अली	"
26. वित्त	एम० सी० शाह	"
27. पुनर्वास	जे० के० भोंसले	"
28. रेल और परिवहन	ओ० वी० अलगेशन	"
29. स्वास्थ्य	श्रीमती एम० चन्द्रशेखर	"
30. वैदेशिक मामले	ए० के० चन्दा	"
31. खाद्य और कृषि	एम० वी० कृष्णप्पा	"
32. सिंचाई और बिजली	जयसुखलाल हाथी	12 सितम्बर, 1952
33. प्रतिरक्षा	सतीशचन्द्र	27 नवबर, 1952
34. वित्त	ए० सी० गुह	18 मार्च, 1953
35. प्लैनिंग	श्यामनन्दन मिश्र	5 सितम्बर 1954

संसदीय सचिव

1. वैदेशिक मामले	श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन
2. रेल और परिवहन	शाहनवाज खान
3. वैदेशिक मामले	जे० एन० हज़ारिका
4. वित्त	बी० आर० भगत
5 उत्पादन	आर० जी० दुबे
6. शिक्षा	के० एल० श्रीमाली
7. शिक्षा	मनमोहन दास
8. सूचना एवं प्रसार	जी० राजागोपालन
9. वैदेशिक मामले	सआदत अली खान

2 सितम्बर, 1946 को जो अन्तरिम सरकार बनो थी, उसके सदस्य निम्नलिखित थे :

जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, बलदेवसिंह, जान मथाई, एम० आसफ अली, राजेन्द्र प्रसाद, जगजीवनराम, शफात अहमद खां, अली ज़हीर, सी० राजगोपालाचारी, शरतचन्द्र बोस और सी० एच० भाभा।

15 अगस्त, 1947 को स्वाधीन भारत की जो प्रथम सरकार बनी थी, उसके सदस्य निम्नलिखित थे :

जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जान मथाई, बलदेवसिंह, जगजीवनराम, सी० एच० भाभा, रफी अहमद किदवई, राजकुमारी अमृतकौर, बी० आर० अम्बेदकर, आर० के० षणमुखम् चेट्टी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी और एन० वी० गाडगिल ।

लोक-सभा

अध्यक्ष — जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष — एम० अनन्तशयनम् आय्यंगार

राजनीतिक दलों की शक्ति

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	361
प्रजा समाजवादी दल	25
भारतीय साम्यवादी दल	17
जनता का लोकतंत्री मोर्चा	7
गणतंत्र परिषद् (उड़ीसा)	5
तमिलनाड टायलर्स दल	4
हिन्दू महासभा	4
अकाली दल (पंजाब और पेप्सू)	4
अन्य दल	25
स्वतन्त्र तथा अन्य	43
रिक्त (उप-चुनाव होने बाकी)	4
	499

लोक सभा के सदस्य

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल (क)
		आंध्र—28	
1	अनन्तपुर	पैंडी लक्ष्मय्या	कांग्रेस
2	चित्तूर	टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी	"

(क) चुनाव के समय के दलीय सम्बन्ध दिखाये गये हैं। समाजवादी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी को, जो बाद में प्रजा समाजवादी दल के रूप में एक पार्टी बन गई, एक दल के रूप में दिखाया गया है।

संस्थाओ के संक्षिप्त नामो की सूची इस प्रकार है: कां० (कांग्रस) ; प्र० सो० पा० (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) ; छो० ना० स० प० ज० पा० (छोटा नागपुर और सथालपरगना जनता पार्टी) ; लो० से० सं० (लोक सेवक संघ) ; पी० व० पा० (पीज़ेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी); अनु० जा० सं० (अनुसूचित जाति संघ) ; फा० ब्ला० (मा०) (फार्वर्ड ब्लाक-मार्क्सवादी) ; त० टा० पा० (तमिलनाड टायलर्स पार्टी) ; का० वी० पा० (कामन वील पार्टी) ; मु० ली० (मुस्लिम लीग); ग० प० (गणतंत्र परिषद्) ; हि० म० (हिन्दू महासभा) ; रि० सो० पा० (रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी) ; ज० सं० (जनसंघ) पी० डि० एफ० (पीपुल्स डैमोक्रेटिक फ्रंट); कृ० लो० पा० (कृषिकार लोक पार्टी); रा० रा० प० (रामराज्य परिषद्) ; ति० त० कां० (तिरुवांकुर तमिलनाड कांग्रेस) ; अनु० आ० जा० सु० (अनसूचित आदिम जाति के लिये सुरक्षित) ; अनु० जा० सु० (अनसूचित जाति के लिये सुरक्षित)।

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
3	चित्तूर (अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित)	एम० वी० गंगाधर शिवा	कांग्रेस
4	कड़प्पा	वाई० ईश्वर रेड्डी	साम्यवादी
5	एलुरू	बी० एस० मूर्ति	प्र० सो० पा०
6	एलुरू (अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित)	कोंडू सुब्बा राव	साम्यवादी
7	गुडिवाडा	कादियाला गोपाल राव	साम्यवादी
8	गुण्टूर्	एस० वी० एल० नरसिंहम्	स्वतंत्र
9	काकिनाडा	चौ० बी० रामा राव	साम्यवादी
10	कुरनूल	वाई० गाडीलिगना गौड	प्र० सो० पा०
11	मसुलीपटनम	सनक बुचि कोटैय्या	साम्यवादी
12	नन्दलाल	राय सम शेषागिरि राव	स्वतंत्र
13	नरसरावपेट	सी० आर० चौधरी	"
14	नेल्लोर	बी० रामचन्द्र रेड्डी	"
15	ओंगोल (अनु० जा० सु०)	पशुपति वेकटा राघवैया	"
16	ओंगोल (अनु० जा० सु०)	मंगलगिरि नानादास	"
17	पार्वतीपुरम्	एन० रामशेषय्या	"
18	पथापटनम्	वी० वी० गिरि	कांग्रेस
19	पेनुकोंडा	के० एस० राघवाचारी	प्र० सो० पा०
20	राजामुन्द्री	नलारेड्डी नायडू	"
21	राजामन्द्री (अनु० जा० सु०)	कनेटी मोहन राव	साम्यवादी
22	श्रीकाकुलम्	वी० राजगोपाल राव	स्वतंत्र
23	तेनालि	कोथा रघुरामैया	कांग्रेस
24	तिरुपति	एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार	कांग्रेस
25	विजयवाड़ा	हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय	स्वतंत्र
26	विशाखापटनम्	लंका सुन्दरम्	"
27	विशाखापटनम् (अनु० आ० जा० सु०)	गाम मल्लूडोरा	स्वतंत्र
28	विजियानगरम्	कांडल सुब्रामण्यम्	प्र० सो० पा०
	आसाम—13*		
29	स्वायत्त ज़िले (अनु० आ० जा० सु०)	श्रीमती बी० खोगमेन	कांग्रेस

* आसाम के भाग 'ख' आदिम जाति क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिये राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये गये सदस्य सहित ।

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
30	बारपेटा	बेलीराम दास	कांग्रेस
31	कचार-लुशाई पहाड़ियां	एस० सी० देव	"
32	कचार-लुशाई पहाड़ियां (अनु० जा० सु०)	निवारणचन्द्र लश्कर	"
33	दरांग	कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी	"
34	डिब्रूगढ़	जोगेन्द्रनाथ हजारिका	"
35	ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां	अमजद अली	प्र० सो० पा०
36	ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां (अनु० आ० जा० सु०)	सीतानाथ ब्रह्म चौधरी	कांग्रेस
37	गोलाघाट-जोरहाट	देवेश्वर सर्मा	"
38	गौहाटी	रोहिणी कुमार चौधरी	"
39	नौगांव	देवकान्त बरुआ	"
40	शिवसागर-उत्तर लखीमपुर	बी० पी० चालिहा	"
41	निर्देशित (भाग 'ख' आदिम जाति क्षेत्र)	चौखामून गोहिन	"

बिहार—55

42	भागलपुर (मध्य)	बनारसीप्रसाद झुनझुनवाला	कांग्रेस
43	भागलपुर (दक्षिण)	श्रीमती सुषमा सेन	"
44	भागलपुर-पूर्निया	जे० बी० कृपालानी	प्र० सो० पा०
45	भागलपुर-पूर्निया (अनु० जा० सु०)	किराई मुसहर	प्र० सो० पा०
46	चाईबस्सा (अनु० आ० जा० सु०)	कान्हू राम देवगम	झारखण्ड
47	चम्पारन (उत्तर)	बी० बी० वर्मा	कांग्रेस
48	चम्पारन (पूर्व)	सैयद महमूद	"
49	दरभंगा (मध्य)	श्री नारायण दास	"
50	दरभंगा (पूर्व)	अनिरुद्ध सिंह	"
51	दरभंगा (उत्तर)	श्यामनन्दन मिश्र	"
52	दरभंगा-भागलपुर	ललित नारायण मिश्र	"
53	गया (पूर्व)	ब्रजेश्वर प्रसाद	"
54	गया (पूर्व) (अनु० जा० सु०)	रामधनी दास	"
55	गया (उत्तर)	विज्ञेश्वर मिश्र	प्र० सो० पा०

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
56	गया (पश्चिम)	सत्येन्द्र नारायण सिंह	कांग्रेस
57	हजारीबाग (पूर्व)	नागेश्वर प्रसाद सिन्हा	कांग्रेस
58	हज़ारीबाग (पश्चिम)	रामनारायण सिंह	(छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी)
59	मानभूम (उत्तर)	पी० सी० बोस	कांग्रेस
60	मानभूम (उत्तर) (अनु० जा० सु०)	हरिमोहन	कांग्रेस
61	मानभूम (दक्षिण-धालभूम)	भजहरि महाता	लोकसेवक संघ
62	मानभूम (दक्षिण-धालभूम) (अनु० आ० जा० सु०)	चैतन माझी	"
63	मुंगेर (उत्तर-पूर्व)	सुरेशचन्द्र मिश्र	प्र० सो० पा०
64	मुंगेर (उत्तर-पश्चिम)	मथुराप्रसाद मिश्र	कांग्रेस
65	मुंगेर सदर जमुई	बनारसीप्रसाद सिन्हा	"
66	मुंगेर सदर-जमुई (अनु० जा० सु०)	नयनतारा दास	"
67	मुज़फ्फरपुर (मध्य)	श्यामनन्दन सहाय	"
68	मुजफ्फरपुर (पूर्व)	अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा	"
69	मुज़फ्फरपुर (उत्तर पश्चिम)	युगल किशोर सिंह	प्र० सो० पा०
70	मुजफ्फरपुर (उत्तर पूर्व)	दिग्विजय नारायण सिंह	कांग्रेस
71	मुजफ्फरपुर-दरभगा	राजेश्वर पटेल	"
72	मुजफ्फरपुर-दरभगा (अनु० जा० सु०)	रामेश्वर साहू	"
73	पालामऊ-हज़ारीबाग-रांची	गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा	"
74	पालामऊ-हज़ारीबाग-रांची (अनु० आ० जा० सु०)	खेरवर जेठन	"
75	पाटलिपुत्र	एस० सिन्हा	"
76	पटना (मध्य)	कैलासपति सिन्हा	"
77	पटना (पूर्व)	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	"
78	पटना-शाहाबाद	बी० आर० भगत	"
79	पूर्निया (उत्तर पूर्व)	मुहम्मद इस्लामुद्दीन	"
80	पूर्निया (मध्य)	फणि गोपाल सेन	"
81	पूर्निया-सन्थाल परगना	भागवत झा आज़ाद	"
82	पूर्निया-सन्थाल परगना (अनु० आ० जा० सु०)	पाल जुझर सोरेन	झारखण्ड
83	रांची (उत्तर-पूर्व)	ए० इब्राहीम	कांग्रेस

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
84	रांची (पश्चिम) (अनु० आ० जा० सु०)	जयपाल सिंह	झारखण्ड
85	समस्तीपुर (पूर्व)	सत्यनारायण सिन्हा	कांग्रेस
86	सन्थाल परगना-हजारी बाग	रामराज जजवाड़े	"
87	सन्थाल परगना-हजारीबाग (अनु० आ० जा० सु०)	लाल हेमब्रोम	"
88	सारन (मध्य)	महेन्द्रनाथ सिंह	"
89	सारन (पूर्व)	सत्यनारायण सिन्हा	"
90	सारन (उत्तर)	झूलन सिन्हा	"
91	सारन (दक्षिण)	द्वारका नाथ तिवारी	"
92	सारन-चम्पारन	विभूति मिश्र	"
93	सारन-चम्पारन (अनु० जा० सु०)	भोला राउत	"
94	शाहाबाद (दक्षिण)	राम सुभग सिंह	"
95	शाहाबाद (दक्षिण) (अनु० जा० सु०)	जगजीवन राम	"
96	शाहाबाद (उत्तर पश्चिम)	कमलसिंह	स्वतंत्र
		बम्बई—45	
97	अहमदाबाद	जी० वी० मावलंकर	कांग्रेस
98	अहमदनगर (अनु० जा० सु०)	मूलदास भूधरदास वैश्य	"
99	अहमदनगर (उत्तर)	पी० आर० कानावाडे पाटिल	"
100	अहमदनगर (दक्षिण)	यू० आर० बोगावत	"
101	बनस्कंठा	अकबर चावदा	"
102	बड़ौदा (पश्चिम)	इन्दुभाई बी० अमीन	स्वतंत्र
103	बेलगांव (उत्तर)	बलवन्त नागेश दातार	कांग्रेस
104	बेलगांव (दक्षिण)	एस० बी० पाटिल	"
105	भुसावल	शिवराम रांगो राने	कांग्रेस
106	बीजापुर (उत्तर)	राजाराम गिरधरलाल दुबे	"
107	बीजापुर (दक्षिण)	रामप्प बालप्प बिदारी	"
108	बम्बई नगर (उत्तर)	वी० बी० गांधी	"
109	बम्बई नगर (उत्तर) (अनु० जा० सु०)	नारायण सादोबा कजरोल्कर	"
110	बम्बई नगर (दक्षिण)	एस० के० पाटिल	"
111	बम्बई (उपनगर)	श्रीमती जयश्री रायजी	"
112	भड़ौच	चन्द्रशंकर भट्ट	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
113	धारवाड़ (उत्तर)	डी० पी० करमरकर	कांग्रेस
114	धारवाड़ (दक्षिण)	टी० आर० नेसवी	"
115	जलगांव	हरी विनायक पाटस्कर	"
116	कैरा (उत्तर)	फूलसिंहजी बी० दाभी	"
117	कैरा (दक्षिण)	श्रीमती मणिबेन वी० पटेल	"
118	कनारा	जोकीम आल्वा	"
119	कोलाबा	चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख	"
120	कोल्हापुर-सतारा	बी० एच० खर्डेकर	स्वतंत्र
121	कोल्हापुर-सतारा (अनु० जा० सु०)	के० एल० मोरे	कांग्रेस
122	मेहसाना (पूर्व)	शान्तिलाल गिरधरलाल पारिख	"
123	मेहसाना (पश्चिम)	तुलसीदास किलाचन्द	स्वतंत्र
124	नासिक (मध्य)	गोविन्द हरि देशपांडे	कांग्रेस
125	उत्तर सतारा	गणेश सदाशिव आल्तेकर	"
126	पंचमहल-बड़ौदा (पूर्व)	माणिकलाल मगनलाल गांधी	"
127	पंचमहल-बड़ौदा (पूर्व) (अनु० आ० जा० सु०)	रूपाजी भावजी परमार	"
128	पूना (मध्य)	नरहर विष्णु गाडगिल	"
129	पूना (दक्षिण)	श्रीमती इन्दिरा ए० मायदेव	"
130	रत्नागिरि (उत्तर)	जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले	"
131	रत्नागिरी (दक्षिण)	मोरेश्वर दिनकर जोशी	"
132	सबरकंठा	गुलजारीलाल नन्दा	"
133	शोलापुर	शंकर शांताराम मोरे	पी० व० पा०
134	शोलापुर (अनु० जा० सु०)	पी० एन० राजभोज	अनु० जा० सं०
135	दक्षिण सतारा	वेंकटराव पिराजीराव पवार	कांग्रेस
136	सूरत	कन्हैयालाल नानाभाई देसाई	"
137	सूरत (अनु० आ० जा०सु०)	बहादुरभाई कुंठाभाई पटेल	"
138	थाना	चोइथराम प्रतापराय गिडवानी	प्र० सो० पा०
139	थाना (अनु० आ० जा० सु०)	यशवन्तराव मारतण्डराव मुकणे	कांग्रेस
140	पश्चिम खान्देश	शालिगराम रामचन्द्र भारतीय	"
141	पश्चिम खान्देश (अनु० आ० जा० सु०)	जयन्तराव गणपत नटवाडकर	"
		मध्य प्रदेश—२९	
142	अमरावती (पूर्व)	पंजाबराव एस० देशमुख	कांग्रेस
	अमरावती (पश्चिम)	के० जी० देशमख	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
144	बालाघाट	सी० डी० गौतम	कांग्रेस
145	बस्तर (अनु० आ० जा० सु०)	मुचाकी कोसा	स्वतंत्र
146	बैतूल	बी० एल० चांडक	कांग्रेस
147	भंडारा	अशोक मेहता	प्र० सो० पा०
148	भंडारा (अनु० जा० सु०)	अर्जुन बोरकर	कांग्रेस
149	बिलासपुर	अमरसिंह सहगल	"
150	बिलासपुर (अनु० आ० सु०)	रेशमलाल जांगड़े	"
151	बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर	भूपेन्द्रनाथ मिश्र	"
152	बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर (अनु० जा० सु०)	श्रीमती मिनीमाता	"
153	बुलडाना-अकोला	गोपालराव बाजीराव खेडकर	"
154	बुलडाना-अकोला (अनु० जा० सु०)	लक्ष्मण श्रवण भटकर	"
155	चान्दा	अब्दुल्लाभाई मुल्ला तेहरअली	"
156	छिंदवाड़ा	रायचन्द भाई एन० शाह	"
157	दुर्ग	वासुदेव श्रीधर किरोलिकर	"
158	दुर्ग-बस्तर	भगवती चरण शुक्ल	"
159	होशंगाबाद	सैयद अहमद	"
160	जबलपुर (उत्तर)	सुशीलकुमार पटेरिया	"
161	महासमुन्द	मगनलाल बागड़ी	प्र० सो० पा०
162	मण्डला-जबलपुर (दक्षिण)	सेठ गोविन्ददास	कांग्रेस
163	मण्डला-जबलपुर (दक्षिण) (अनु० आ० जा० सु०)	एम० जी० उइके	"
164	नागपुर	श्रीमती अनसूयाबाई काले	"
165	निमाड़	बी० एल० तिवारी	"
166	सागर	खूबचन्द सोधिया	"
167	सूरगुजा-रायगढ़	चन्डिकेश्वर शरणासिंह	स्वतंत्र
168	सरगुजा-रायगढ़ (अनु० आ० जा० सु०)	बाबूनाथ सिंह	कांग्रेस
169	वर्धा	श्रीमन्नारायण अग्रवाल	"
170	यवतमाल	गोस्वामी राजा सहदेव भारती	"
		मद्रास—46	
171	अरुपुक्कोटाई	एम० डी० रामस्वामी	फ़ार्वर्ड ब्लाक (मार्क्सिस्ट)
172	कन्नानूर	ए० के० गोपालन	साम्यवादी

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
173	चिंगलपट	ओ० वी० अलगेशन	कांग्रेस
174	कोयम्बटूर	एन० एम० लिंगम	”
175	कुडलूर	एन० डी० गोविन्दस्वामी काचि-रोयर	त० टा० पा०
176	कुडलूर (अनु० जा० सु०)	एल० इलयापेरुमल	कांग्रेस
177	धर्मपुरी	एन० सत्यनाथन	स्वतंत्र
178	डिंडिगल	श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन	कांग्रेस
179	इरोड	के० पेरियास्वामी गौंडर	”
180	इरोड (अनु० जा० सु०)	एस० सी० बालकृष्णन्	”
181	कांचीपुरम	ए० कृष्णस्वामी	का० वी० पा०
182	कोजिकोडे	के० ए० दामोदर मेनन	प्र० सो० पा०
183	कृष्णगिरि	सी० आर० नरसिंहन्	कांग्रेस
184	कुम्बकोणम्	सी० रामस्वामी मुदलियार	”
185	मद्रास	टी० टी० कृष्णमाचारी	”
186	मदुराई	एस० बालसुब्रह्मण्यम्	”
187	मदुराई (अनु० जा० सु०)	पी० कक्कन	”
188	मलप्पुरम	बी० पोकर	मुसलिम लीग
189	मयूरम्	के० आनन्द नम्बियार	साम्यवादी
190	मयूरम् (अनु० जा० ु०)	वी० वीरस्वामी	स्वतंत्र
191	पेराम्बेलूर	वी० बूवराघसामी	त० टा० पा०
192	पेरियाकुलम	के० शक्तिवाडिवेल गौंडर	कांग्रेस
193	पोल्लाची	जी० आर० दामोदरन	”
194	पोन्नानी	के० केलप्पन	प्र० सो० पा०
195	पोन्नानी (अनु० जा० सु०)	आई० ईयाचरण	कांग्रेस
196	पुदुकोटे	के० एम० वल्लाथरास	प्र० सो० पा०
197	रामनाथपुरम	वी० वी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा चेट्टियार	कांग्रेस
198	सलेम	एस० वी० रामस्वामी	”
199	शंकरनायिनार कोबिल	एम० शंकरपांडियन्	”
200	श्रीवैकुंठम	ए० वी० टामस	”
201	श्रीविल्लीपुत्तूर	के० कामराज	”
202	दक्षिण कनारा (उत्तर)	यू० श्रीनिवास मल्लय्या	”
203	दक्षिण कनारा (दक्षिण)	बी० शिवाराव	”
204	तंजोर	आर० वेंकटरमण	”
205	तेलिचेरी	नेत्तूर पी० दामोदरन्	प्र० सो० पा०

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
206	टिन्डीवनम	वी० मुनिस्वामी अ० ल० थिरुकुरलार	तामिलनाड टायलर्स पार्टी
207	टिन्डीवनम (अनु० जा० सु०)	ए० जयरमन	"
208	तिरुचनगोड	एस० के० बेबी कंडासामी	स्वतंत्र
209	तिरुचिरापल्ली	एडवर्ड पाल मथुरम	"
210	तिरुनलवेली	पी० टी० थानू पिल्ले	कांग्रेस
211	तिरुपुर	टी० एस० अविनाशिलिंगम चेट्टियार	"
212	तिरुवल्लूर	पी० नटेशन	"
213	तिरुवल्लूर (अनु० जा० सु०)	श्रीमती एम० चन्द्रशेखर	"
214	वेल्लोर	डी० रामचन्द्र	कामनवील पार्टी
215	वेल्लोर (अनु० जा० सु०)	एम० मुत्तुकृष्णन	कांग्रेस
216	वान्दिवाश	एन० आर० एम० स्वामी	का० वी० पा०
		उड़ीसा—20	
217	बालासोर	भागवत साहू	कांग्रेस
218	बालासोर (अनु० जा० सु०)	कान्हू चर जेना	"
219	बारगढ़	जी० डी० थिरानी	स्वतंत्र
220	कटक	हरेकृष्ण महताब	कांग्रेस
221	ढेंकानाल-पश्चिम कटक	सारंगधर दास	प्र० सो० पा०
222	ढेंकानाल-पश्चिम कटक (अनु० जा० सु०)	निरंजन जेना	कांग्रेस
223	गंजम (दक्षिण)	विजयचन्द्र दास	साम्यवादी
224	घूमसूर	उमाचरण पटनायक	स्वतंत्र
225	जाजपुर क्योंझर	बी० दास	कांग्रेस
226	जाजपुर क्योंझर (अनु० जा० सु०)	लक्ष्मीधर जेना	गणतंत्र परिषद्
227	कालाहांडी-बोलनगिर	राजेन्द्र नारायण सिंह	ग० प०
228	कालाहांडी-बोलनगिर (अनु० जा० सु०)	गिरधारी भोई	"
229	केन्द्रपाड़ा	नित्यानन्द कानूनगो	कांग्रेस
230	खुर्दा	लिंगराज मिश्र	"
231	मयूरभंज (अनु० आ० जा० सु०)	रामचन्द्र माझी	"
232	नौरंगपुर	पी० सुब्बा राव	ग० प०
233	पुरी	लोकनाथ मिश्र	कांग्रेस
234	रायगढ़ फुलबनी (अनु० आ० जा० सु०)	टी० संगण्णा	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
235	सम्बलपुर	नटवर पाण्डे	ग० प०
236	सुन्दरगढ़ (अनु०आ०जा०सु०)	किशन नारायण सिंह महापा	कांग्रेस
		पंजाब—18	
237	अम्बाला-शिमला	टेकचन्द	कांग्रेस
238	अमृतसर	गुरमुख सिंह मुसाफिर	"
239	फ़ाजिल्का सिरसा	इकबाल सिंह	"
240	फ़िरोज़पुर-लुधियाना	लाल सिंह	अकाली
241	फ़िरोज़पुर-लुधियाना (अनु० जा० सु०)	बहादुर सिंह	"
242	गुरदासपुर	तेजा सिंह अकरपुरी	कांग्रेस
243	गुड़गांव	ठाकुरदास भार्गव	"
244	हिसार	अचिन्त राम	"
245	होशियारपुर	दीवान चन्द शर्मा	"
246	होशियारपुर (अनु० जा०सु०)	रामदास	"
247	झज्जर-रिवाड़ी	घमण्डी लाल बन्सल	"
248	जालन्धर	अमरनाथ विद्यालंकार	"
249	कांगड़ा	हेमराज	"
250	करनाल	श्रीमती सुभद्रा जोशी	"
251	करनाल (अनु० जा० सु०)	वीरेन्द्र कुमार	"
252	नवांशहर	बलदेव सिंह	"
253	रोहतक	रणवीर सिंह	"
254	तरन तारन	सुरजीतसिंह मजीठिया	
		उत्तर प्रदेश—86	
255	आगरा ज़िला (पूर्व)	रघुवीरसिंह	कांग्रेस
256	आगरा ज़िला (पश्चिम)	अचलसिंह	"
257	अलीगढ़ ज़िला	श्रीचन्द सिंघल	"
258	अलीगढ़ (अनु० जा० सु०)	नरदेव स्नातक	"
259	इलाहाबाद ज़िला (पश्चिम)	पुरुषोत्तमदास टंडन	"
260	इलाहाबाद ज़िला (पूर्व)–जौनपुर ज़िला (पश्चिम)	जवाहरलाल नेहरू	"
261	इलाहाबाद ज़िला (पूर्व)–जौनपुर ज़िला (पश्चिम) (अनु० जा० सु०)	मसुरिया दीन	"
262	अल्मोड़ा ज़िला (उत्तर-पूर्व)	देवीदत्त पंत	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
263	आजमगढ़ जिला (पश्चिम)	सीताराम अस्थाना	"
264	आजमगढ़ जिला (पश्चिम) (अनु० जा० सु०)	विश्वनाथ प्रसाद	"
265	आजमगढ़ जिला (पूर्व)—बलिया जिला (पश्चिम)	अलगू राय शास्त्री	"
266	बहराइच जिला (पूर्व)	रफी अहमद किदवई	"
267	बहराइच जिला (पश्चिम)	जोगेन्द्र सिंह	"
268	बलिया जिला (पूर्व)	मुरली मनोहर	स्वतंत्र
269	बनारस जिला (मध्य)	रघुनाथ सिंह	कांग्रेस
270	बनारस जिला (पूर्व)	त्रिभवन नारायण सिंह	"
271	बांदा जिला-फतहपुर जिला	शिवदयाल उपाध्याय	"
272	बांदा जिला-फतहपुर जिला (अनु० जा० सु०)	प्यारेलाल कुरील	"
273	बरेली जिला (दक्षिण)	सतीश चन्द्र	"
274	बस्ती जिला (उत्तर)	उदय शकर दुबे	"
275	बस्ती जिला (मध्य पूर्व)—गोरखपुर जिला (पश्चिम)	रामशकर लाल	"
276	बस्ती जिला (मध्य पूर्व)—गोरखपुर जिला (पश्चिम) (अनु० जा० सु०)	सोहनलाल धूसिया	"
277	बिजनौर जिला (दक्षिण)	नेमी सरन जैन	"
278	बदायू जिला (पश्चिम)	बदन सिंह	"
279	बुलन्दशहर जिला	रघुवर दयाल मिश्र	"
280	बुलन्दशहर जिला (अनु० जा० सु०)	कन्हैयालाल वाल्मीकी	"
281	देहरादून जिला—बिजनौर जिला (उत्तर-पश्चिम)—सहारनपुर जिला (पश्चिम)	महावीर त्यागी	"
282	देवरिया जिला (पूर्व)	रामजी वर्मा	"
283	देवरिया जिला (पश्चिम)	विश्वनाथ राय	"
284	देवरिया जिला (दक्षिण)	सरयू प्रसाद मिश्र	"
285	एटा जिला (मध्य)	रोहनलाल चतुर्वेदी	"
286	एटा जिला (उत्तर पूर्व)—बदायू जिला (पूव)	रघुवीर सहाय	"
287	एटा जिला (पश्चिम)—मैनपुरी जिला (पश्चिम)—मथुरा जिला (पूर्व)	दिगम्बर सिंह	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
288	फैज़ाबाद ज़िला (उत्तर-पश्चिम)	लल्लन जी	कांग्रेस
289	फैजाबाद जिला (उत्तर-पश्चिम)	पन्नालाल	"
290	फर्रुखाबाद जिला (उत्तर)	मूलचन्द दुबे	"
291	गढवाल ज़िला (पश्चिम) –टिहरी गढवाल ज़िला –बिजनौर ज़िला (उत्तर)	श्रीमती कमलेन्दुमती शाह	स्वतंत्र
292	गढ़वाल ज़िला (पूर्व)— मुरादाबाद ज़िला (उत्तर-पूर्व)	भक्त दर्शन	कांग्रेस
293	गाज़ीपुर ज़िला (पश्चिम)	हरप्रसाद सिंह	कांग्रेस
294	गाज़ीपुर ज़िला (पूर्व)– बलिया जिला (दक्षिण पश्चिम)	आर० एन० सिंह	प्र० सो० पा०
295	गोंडा ज़िला (उत्तर)	हैदर हुसैन	कांग्रेस
296	गोंडा ज़िला (पश्चिम)	श्रीमती शकुन्तला नायर	हि० म०
297	गोंडा ज़िला (पूर्व)–बस्ती जिला (पश्चिम)	केशवदेव मालवीय	कांग्रेस
298	गोरखपुर ज़िला (उत्तर)	हरिशंकर प्रसाद	"
299	गोरखपुर ज़िला (मध्य)	दशरथप्रसाद द्विवेदी	"
300	गोरखपुर ज़िला (दक्षिण)	सिंहासन सिंह	"
301	हमीरपुर ज़िला	एम० एल० द्विवेदी	"
302	हरदोई ज़िला (उत्तर-पश्चिम) – फर्रुखाबाद ज़िला (पूर्व)–शाहजहान-पुर जिला–दक्षिण	बी० एच० ज़ैदी	"
303	हरदोई ज़िला (उत्तर-पश्चिम) – फर्रुखाबाद ज़िला (पूर्व)–शाहजहा-पुर ज़िला (दक्षिण) (अनु० जा० सु०)	बुलाकीराम वर्मा	"
304	जालौन ज़िला–इटावा ज़िला (पश्चिम)–झांसी ज़िला (उत्तर)	होतीलाल अग्रवाल	"
305	जालौन ज़िला–इटावा ज़िला (पश्चिम)–झांसी ज़िला (उत्तर) (अनु० जा० सु०)	लोटन राम	"
306	जौनपुर ज़िला (पूर्व)	बीरबल सिंह	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
307	जौनपुर ज़िला (पूर्व) (अनु० जा० सु०)	गणपति राम	कांग्रेस
308	झांसी ज़िला (दक्षिण)	आर० वी० धुलेकर	"
309	कानपुर ज़िला (मध्य)	(शिवनारायण टंडन)	
310	कानपुर ज़िला (दक्षिण)-इटावा ज़िला (पूर्व)	बालकृष्ण शर्मा	"
311	कानपुर ज़िला (उत्तर)—फर्रुखाबाद ज़िला (दक्षिण)	वेंकटेश नारायण तिवारी	"
312	लखनऊ ज़िला (मध्य)	श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित	"
313	लखनऊ ज़िला-बाराबांकी ज़िला	मोहनलाल सक्सेना	"
314	लखनऊ ज़िला—बाराबाकी ज़िला (अनु० जा० सु०)	श्रीमती गंगा देवी	"
315	मैनपुरी ज़िला (पूर्व)	बादशाह गुप्त	"
316	मथुरा ज़िला (पश्चिम)	कृष्ण चन्द्र	"
317	मेरठ ज़िला (पश्चिम)	खुशीराम शर्मा	"
318	मेरठ ज़िला (दक्षिण)	कृष्ण चन्द्र शर्मा	"
319	मेरठ ज़िला (उत्तर पूर्व)	शाहनवाज खा	"
320	मिर्ज़ापुर ज़िला-बनारस ज़िला (पश्चिम)	जे० एन० विलसन	"
321	मिर्ज़ापुर ज़िला—बनारस ज़िला (पश्चिम) (अनु० जा० सु०)	रूप नारायण	"
322	मुरादाबाद ज़िला (पश्चिम)	राम सरन	"
323	मुरादाबाद ज़िला (मध्य)	हिफ़ज़ुर रहमान	"
324	मुज़फ्फरनगर ज़िला (दक्षिण)	हीरा वल्लभ त्रिपाठी	"
325	नैनीताल ज़िला-अल्मोड़ा ज़िला (दक्षिण-पश्चिम) बरेली ज़िला (उत्तर)	सी० डी० पाडे	"
326	पीलीभीत ज़िला-बरेली ज़िला (पूर्व)	मुकुन्दलाल अग्रवाल	"
327	प्रतापगढ़ ज़िला (पश्चिम)	मुनीश्वर दत्त उपाध्याय	"
328	प्रतापगढ़ ज़िला (पश्चिम)—रायबरेली ज़िला (पूर्व)	फिरोज़ गान्धी	"
329	प्रतापगढ़ ज़िला (पश्चिम)-रायबरेली ज़िला (पूर्व) (अनु० जा० सु०)	बैजनाथ कुरील	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
330	रामपुर जिला—बरेली जिला (पश्चिम)	अबुल कलाम आजाद	कांग्रेस
331	सहारनपुर जिला (पश्चिम) —मुजफ्फरनगर जिला (उत्तर)	अजित प्रसाद जैन	"
332	सहारनपुर जिला (पश्चिम) —मुजफ्फरनगर जिला (उत्तर) (अनु जा० सु०)	सुन्दरलाल	"
333	शाहजहांपुर जिला (उत्तर) —खेरी (पूर्व)	आर० पी० नेवटिया	"
334	शाहजहापुर जिला (उत्तर) —खेरी (पूर्व) (अनु० जा० सु०)	गणेशी लाल चौधरी	"
335	सीतापुर जिला—खेरी जिला (पश्चिम)	श्रीमती उमा नेहरू	"
336	सीतापुर जिला—खेरी जिला (पश्चिम) (अनु० जा० सु०)	परागीलाल	"
337	सुल्तानपुर जिला (दक्षिण)	बी० वी० केसकर	"
338	सुल्तानपुर जिला (उत्तर) फजाबाद जिला (दक्षिण पश्चिम)	सैयद मुहम्मद अहमद काजमी	"
339	उन्नाव जिला—रायबरेली जिला (पश्चिम)—हरदोई जिला (दक्षिण-पूर्व)	विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी	"
340	उन्नाव जिला—रायबरेली जिला (पश्चिम)—हरदोई जिला (दक्षिण-पूर्व) (अनु० जा० सु०)	रामानन्द शास्त्री	"
	पश्चिम बंगाल—34		
341	बांकुरा	जगन्नाथ कोले	कांग्रेस
342	बांकुरा (अनु० जा० सु०)	पशुपति मण्डल	"
343	बैरकपुर	रामानन्द दास	"
344	बसीरहाट	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	साम्यवादी
345	बसीरहाट (अनु० जा० सु०)	पतिराम राय	कांग्रेस
346	बरहामपुर	त्रिदिव कुमार चौधरी	साम्यवादी
347	वीरभूम	अनिल कुमार चन्दा	कांग्रेस
348	वीरभूम (अनु० जा० सु०)	कमल कृष्ण दास	"
349	बर्दवान	अतुल्य घोष	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
350	बर्दवान (अनु० जा० सु०)	मन मोहन दास	काग्रेस
351	कलकत्ता (उत्तर पूर्व)	हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी	साम्यवादी
352	कलकत्ता (उत्तर पश्चिम)	मेघनाद साहा	स्वतंत्र
353	कलकत्ता (दक्षिण पूर्व)	साधन चन्द्र गुप्त	साम्यवादी
354	कलकत्ता (दक्षिण पश्चिम)	असीम कृष्ण दत्त	कांग्रेस
355	कोण्टाई	बसन्त कुमार दास	"
356	डायमण्ड हारबर	कमल कुमार बसु	साम्यवादी
357	डायमण्ड हारबर (अनु० जा० सु०)	पूर्णेन्दु शेखर नास्कर	काग्रेस
358	घाटल	निकुंज बिहारी चौधरी	साम्यवादी
359	हुगली	एन० सी० चैटर्जी	हिन्दू महासभा
360	हावडा	सन्तोषकुमार दत्त	काग्रेस
361	कलना-कटवा	अब्दुस्सत्तार	"
362	माल्दा	सुरेन्द्र मोहन घोष	"
363	मिदनापुर झाडग्राम	दुर्गा चरण बैनर्जी	ज० सं०
364	मिदनापुर झाड़ग्राम (अनु० आ० जा० सु०)	भरत लाल टुडू	काग्रेस
365	मुर्शिदाबाद	मुहम्मद खुदा बख्स	"
366	नवद्वीप	श्रीमती इला पाल चौधरी	"
367	उत्तर बंगाल	ए० के० बसु	"
368	उत्तर बगाल (अनु० जा० सु०)	उपेन्द्र नाथ बर्मन	"
369	उत्तर बगाल (अनु० आ० जा० सु०)	बीरेन्द्रनाथ कथम	"
370	शान्तिपुर	अरुण चन्द्र गुहा	"
371	श्रीरामपुर	तुषार चैटर्जी	साम्यवादी
372	तामलुक	सतीशचन्द्र सामन्त	काग्रेस
373	उलुबेरिया	सत्यवान राय	"
374	पश्चिम दीनाजपुर	सुशील रजन चैटर्जी	"
		हैदराबाद—25	
375	आदिलाबाद	सी० माधव रेड्डी	प्र० सो० पा०
376	अम्बड़	हनुमतराव गणेशराव वैष्णव	कांग्रेस
377	औरगाबाद	सुरेशचन्द्र	"
378	भीर	आर० जी० पराजपे	पी० डे० फ्रं०
379	बीदर	शौकतुल्ला शाह अन्सारी	कांग्रेस

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
380	गुलबर्गा	रामानन्द तीर्थ	कांग्रेस
381	हैदराबाद शहर	अहमद मुहीउद्दीन	"
382	इब्राहीमपटनम्	सादत अली खा	"
383	करीम नगर	बद्दम येत्ला रेड्डी	पी० डे० फ्रं०
384	करीम नगर (अनु० जा० सु०)	एम० आर० कृष्ण	अनु० जा० सं०
385	खम्मम	टी० बी० विट्ठल राव	पी० डे० फ्रं०
386	कुष्टगी	शिवमूर्ति स्वामी	स्वतंत्र
387	महबूबनगर	के० जनार्दन रेड्डी	कांग्रेस
388	महबूबनगर (अनु० जा० सु०)	पी० रामस्वामी	"
389	मेदक	एन० एम० जयसूर्य	पी० डे० फ्रं०
390	नलगोंडा	रवि नारायण रेड्डी	" " "
391	नलगोंडा (अनु० जा० सु०)	सुकम अचल	" " "
392	नान्देड	शंकर राव तेलकीकर	कांग्रेस
393	नान्देड (अनु० जा० सु०)	देवराव नामदेवराव पाथ्रीकर	"
394	निजामाबाद	एच० सी० हेडा	"
395	उस्मानाबाद	राघवेन्द्रराव, श्रीनिवासराव दीवान	"
396	परभणी	नारायणराव वाघमारे	पी० व० पा०
397	विकाराबाद	एस० ए० एबनजिर	कांग्रेस
398	वारंगल	पेंड्याल राघव राव	पी० डे० फ्रं०
399	यादगीर	कृष्णाचार्य जोशी	कांग्रेस

जम्मू और काश्मीर—6 (अ)

400	राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत	मुहम्मद सईद मसूदी	"
401	" " "	लक्ष्मणसिंह चरक	"
402	" " "	सूफी मुहम्मद अकबर	"
403	" " "	शिवनारायण फोतेदार	"
404	" " "	मुहम्मद शफी चौधरी	"
405	" " "	गुलाम कादिर	"

मध्य भारत—11

406	गूना	विष्णु घनश्याम देशपांडे	हिन्दू महासभा
407	ग्वालियर	एन० बी० खरे	"
408	इन्दौर	नन्दलाल जोशी	कांग्रेस

(अ) नेशनल कान्फ्रेन्स, काश्मीर के छः सदस्य लोक-सभा की कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये हैं।

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
409	झाबुआ (अनु० आ०जा० सु०)	अमरसिंह साबजी डामर	कांग्रेस
410	मन्दसौर	कैलास नाथ काटजू	"
411	मुरैना-भिंड	राधाचरण शर्मा	"
412	मुरैना-भिंड (अनु० जा० सु०)	सूर्यप्रसाद	"
413	निमाड़	बैजनाथ महोदय	"
414	शाजापुर-राजगढ़	लीलाधर जोशी	
415	शाजापुर-राजगढ़ (अनू० जा० सु०)	भगूनन्दु मालवीय	"
416	उज्जैन	राधेलाल व्यास	
		मैसूर—12	
417	बंगलौर–उत्तर	एन० केशवैयंगार	
418	बंगलौर–दक्षिण	टी० मादिय्य गौडा	
419	बेल्लारी	टेकूर सुब्रह्मण्यम्	"
420	चितलद्रुग	एस० निजलिंगप्पा	
421	हासन-चिकमगालूर	एच० सिद्धनजप्पा	"
422	कोलार	एम० वी० कृष्णप्पा	"
423	कोलार (अनु० जा० सु०)	डोडा तिमय्या	"
424	मण्डया	एम० के० शिवनजप्पा	"
425	मैसूर	एम० एस० गुरुपादस्वामी	प्र० सो० पा०
426	मैसूर (अनु० जा० सु०)	एन० राचय्या	कांग्रेस
427	शिमोगा	के० जी० वोडयार	"
428	टुमकुर	सी० आर० बासप्पा	"
		पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ—5	
429	कपूरथला-भटिंडा	हुकमसिंह	अकाली
430	कपूरथला-भटिण्डा (अनु० जा० सु०)	अजीतसिंह	"
431	महेन्द्रगढ़	हीरासिंह चिनारिया	कांग्रेस
432	पटियाला	रामप्रताप गर्ग	"
433	संगरूर	रणजीतसिंह	स्वतंत्र
		राजस्थान—20	
434	अलवर	शोभाराम	कांग्रेस
435	बांसवाड़ा-डूंगरपुर (अनु० आ० जा० सु०)	भीखाभाई	"

क्रम संख्या	चनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
436	बारमर-जालोर	भवानी सिह	स्वतंत्र
437	भरतपुर-सवाई माधोपुर	गिरिराजशरण सिह	"
438	भरतपुर-सवाई माधोपुर (अनु० जा० सु०)	मानिकचन्द जाटव-वीर	कृ० लो० पा०
439	भीलवाड़ा	हरिराम नथानी	रा० रा० प०
440	बीकानर-चुरू	कर्णीसिह जी	स्वतंत्र
441	चित्तौड़	उमाशंकर मूलजीभाई त्रिवेदी	जनसंघ
442	गगानगर-झुझुनू	राधेश्याम रामकुमार मुरारका	काग्रेस
443	गंगानगर-झुझुनू (अनु० जा० सु०)	पन्नालाल बारुपाल	"
444	जयपुर	दौलत मल भडारी	"
445	जयपुर-सवाई माधोपुर	राजबहादुर	"
446	जोधपुर	जसवन्तराज मेहता	स्वतंत्र
447	कोटा-बून्दी	राजचन्द्र सेन	रा० रा० प०
448	कोटा-झालावाड़	नेमीचन्द्र कासलीवाल	काग्रेस
449	नागौर-पाली	जी० डी० सोमानी	स्वतंत्र
450	सीकर	नन्दलाल शर्मा	रा० रा० प०
451	सिरोही-पाली	अजित सिंह	स्वतंत्र
452	टोंक	माणिक्यलाल वर्मा	काग्रेस
453	उदयपुर	बलवन्तसिह मेहता	"

सौराष्ट्र—6

454	गोहिलवाड़	बलवन्तराय गोपालजी मेहता	"
455	गोहिलवाड़-सोरठ	चिमनलाल चाकूभाई शाह	"
456	हालर	खडूभाई कासनजी देसाई	"
457	मध्य सौराष्ट्र	जेठालाल हरिकृष्ण जोशी	"
458	सोरठ	नरेन्द्र पी० नथवानी	
459	झालावाड	जयीन्तलाल नरभेराम पारिख	"

तिरुवांकुर-कोचीन—12

460	एल्लेपी	पी० टी० पुन्नूस	स्वतंत्र
461	चिरायिनकील	वी० पी० नायर	"
462	क्रेगान्नूर	के०टी० अच्युतन	काग्रेस
463	एरणाकुलम	ए० एम० टामस	"
464	कोट्टयाम	सी० पी० मैथ्यू	"
465	मीनाचिल	जार्ज टामस	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
466	नागरकोइल	ए० नेसामनी	तिरू त० कां०
467	क्विलोन-मावेलिक्करा	एन० श्रीकान्तन नायर	रि० सो० पा०
468	क्विलोन-मावेलिक्करा (अनु० जा० सु०)	आर० वेलायुधन	स्वतंत्र
469	तिरुवल्ला	सी० पी० मैथन	कांग्रेस
470	त्रिचूर	सी० आर० इय्युन्नी	"
471	त्रिवेन्द्रम	श्रीमती ऐन मैस्करीन	स्वतंत्र
		अजमेर—2	
472	अजमेर-उत्तर	ज्वालाप्रसाद	कांग्रेस
473	अजमेर-दक्षिण	मुकुट बिहारीलाल भार्गव	"
		भोपाल—2	
474	रायसेन	चतुरनारायण मालवीय	"
475	सिहोरे	सैयदउल्लाखां रज्मी	"
		बिलासपुर—1	
476	बिलासपुर	आनन्दचन्द	स्वतंत्र
		कुर्ग—1	
477	कुर्ग	एन० सोमना	कांग्रेस
		दिल्ली—4	
478	दिल्ली शहर	राधारमण	कांग्रेस
479	नई दिल्ली	श्रीमती सुचेता कृपलानी	प्र० सो० पा०
480	बाह्य दिल्ली	सी० कृष्णन नायर	कांग्रेस
481	बाह्य दिल्ली (अनु० जा० सु०)	नवल प्रभाकर	"
		हिमाचल प्रदेश—3	
482	मंडी-महासू	राजकुमारी अमृत कौर	कांग्रेस
483	मंडी-महासू (अनु० जा० सु०)	गोपीराम	"
484	सिरमूर-चम्बा	ए० आर० सेवल	स्वतंत्र
		कच्छ—2	
485	कच्छ-पूर्व	गुलाबशंकर अमृतलाल धोलकिया	कांग्रेस
486	कच्छ-पश्चिम	भवनजी ए० खीमजी	"

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
		मणिपुर—2	
487	आंतरिक मणिपुर	लेसराम जोगेश्वरसिंह	कांग्रेस
488	बाह्य मणिपुर (अनु० आ० जा० सु०)	रिशांग किशिंग	प्र० सो० पा०
		त्रिपुरा—2	
489	त्रिपुरा–पूर्व	दशरथ देव	साम्यवादी
490	त्रिपुरा–पश्चिम	बीरेन दत्त	"
		विन्ध्य प्रदेश—6	
491	छतरपुर-दतिया-टीकमगढ	रामसहाय तिवारी	कांग्रेस
492	छतरपुर-दतिया-टीकमगढ (अनु० जा० सु०)	मोतीलाल मालवीय	"
493	रीवा	राजभानु सिंह तिवारी	"
494	सतना	शिवदत्त उपाध्याय	"
495	शाहडोल-सिद्धी	भगवानदत्त शास्त्री	प्र० सो० पा०
496	शाहडोल-सिद्धी (अनु० आ० जा०सु०)	रणदमन सिंह	"
		अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह—1 (क)	
497	नामजद	जान रिचडसन	
		ऐंग्लो इंडियन (क)	
498	नामज़द	फ़्रैंक एन्थनी	
499	नामज़द	ए० ई० टी० बैरो	

(क) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।

लोक-सभा के लिये उपचुनाव

निर्वाचन क्षेत्र और मतदाताओ की सख्या	स्थान रिक्त होने का कारण	उम्मीदवारो के नाम	पार्टी	प्राप्त मत
आसाम : शिवसागर—उत्तरी लखीमपुर—3,42,934	एस० एन० बरगोहेन (काग्रेस) की मृत्यु	1. बी० पी० चालिया (निर्वाचित)	काग्रेस	61,127
		2. के० एन० बरबरुआ	रिवोल्यूशनरी साम्यवादी	39,816
		3. पी० एम० सारवान	स्वतंत्र	16,403
		4. पद्मेश्वर गोगोई	प्र० सो० पा०	7,632
बिहार : मुजफ्फरपुर (उत्तर-पश्चिम)—2,93,890	चन्द्रेश्वरनारायण प्रसाद सिह (काग्रेस) का चुनाव अवैध घोषित	1. जुगलकिशोर सिह (निर्वाचित)	प्र० सो० पा०	35,205
		2. चन्द्रेश्वरनारायण प्रसाद सिह	काग्रेस	23,785
		3. लक्ष्मण महतो	स्वतत्र	1,833
बिहार : भागलपुर-पूर्निया—6,40,994 (द्वि-सदस्यीय)	अनूपलाल मेहता (काग्रेस) और किराई मुसहर (सो०) के चुनाव अवैध घोषित।	1. जे० बी० कृपालानी (निर्वाचित)	प्र० सो० पा०	1,14,539
		2. किराई मुसहर (अनु० जा०) (निर्वाचित)	प्र० सो० पा०	92,616
		3. महाबीरदास (अनु० जा०)	काग्रेस	69,251
बम्बई : थाना—7,12,902 (द्वि-सदस्यीय)	ए० एस० नन्दकर (अनु० आ० जा०—काग्रेस) की मृत्यु	1. यशवन्तराव मार्तण्डराव मुक्णे (अनु० आ० जा०) (निर्वाचित)	काग्रेस	72,808
		2. लखम नवसू पाडू (अनु० आ० जा०)	प्र० सो० पा०	51,169
		3. चोइथराम प्रतावराय गिडवानी (निर्वाचित) (क)	प्र० सो० पा०	1,40,595ख

(क) चुनाव ट्रिब्यूनल द्वारा जी० डी० वर्तक (काग्रेस) के स्थान पर, जिसे आमचुनाव मे 1,40,604 मत मिले, निर्वाचित घोषित।

(ख) आम चुनाव मे प्राप्त मत।

नमर्वाचन क्षेत्र और मतदाताओं की संख्या	स्थान रिक्त होने का कारण	उम्मीदवारों के नाम	पार्टी	प्राप्त मत
मध्य प्रदेश : महासमुन्द–3,92,827	शिवदास लाल डागा (कांग्रेस) की मृत्यु	1. मगनलाल बागडी (निर्वाचित)	प्र० सो० पा०	49,938
		2. नेमीचन्द	कांग्रेस	41,770
मध्य प्रदेश : बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर–7,59,652 (द्वि-सदस्यीय)	आगमदास (अनु० जा०–कांग्रेस) की मृत्यु	1. श्रीमती मणिमाता (अनु०जा०) (निर्वाचित)	कांग्रेस	55,146
		2. मुक्तावनदास (अनु० जा०)	स्वतंत्र	23,661
मद्रास : अरुपुक्कोटाई–3,72,858	यू० मुथुरामालिगा थेवर (मार्क्सवादी) का त्यागपत्र	1. एम० डी० रामस्वामी (निर्वाचित)	फा० ब्ला० (मार्क्सवादी)	69,128
		2. राजाथी कुंचिथापत्थम	कांग्रेस	50,291
		3. नलाइअप्पा पिल्ले	स्वतत्र	3,190
		4 पिचुमणि अय्यर	स्वतत्र	2,679
मद्रास : कोयम्बटूर—3,46,405	टी० ए० रामलिंगम चेटियार (काग्रेस) की मृत्यु	1. एन० एम० लिंगम (निर्वाचित)	कांग्रेस	92,465
		2 पार्वती कृष्णन	साम्यवादी	51,138
		3. पी० एस० चिन्नादुराई	प्र० सो० पा०	4,680
		4. आर० वरदाप्पन	स्वतत्र	1,356
आंध्र : कुरनूल—3,54,495	एच० सीताराम रेड्डी (काग्रेस) का चुनाव अवैध घोषित	I वाई० गार्डिलिंगन गौड (निर्वाचित)	प्र० सो० पा०	90,192
		2. एच० सीताराम रेड्डी	काग्रेस	48,532
		3. नागप्पा	स्वतंत्र	8,218
उत्तर प्रदेश : इलाहाबाद जिला (पश्चिम)—3,76,100	श्रीप्रकाश (कांग्रेस) का त्यागपत्र	1. पुरुषोत्तमदास टंडन (निर्वाचित)	कांग्रेस	निर्विरोध
पश्चिमी बंगाल : कलकत्ता (दक्षिणपूर्व) 3,80,061	श्यामाप्रसाद मुखर्जी (जनसंघ) की मृत्यु	1. साधन चन्द्र गुप्त (निर्वाचित)	साम्यवादी	58,211
		2. राधा बिनोद पाल	कांग्रेस	36,319
		3. जे० पी० मित्र	जनसंघ	5,431
		4. भूपाल चन्द्र बोस	फा० ब्ला० (मार्क्सवादी)	5,415

पश्चिमी बंगाल : नवद्वीप–3,81,812	लक्ष्मीकान्त मैत्र (कांग्रेस) की मृत्यु	1. श्रीमती इलापाल चौधरी (निर्वाचित)	कांग्रेस . .	69,606
		2. सुशील कुमार चैटर्जी . .	साम्यवादी . .	27,455
		3. मिहिर लाल चैटर्जी . . .	प्र० सो० पा० .	19,802
		4. जतीन्द्रनाथ बिस्वास . . .	स्वतत्र . .	7,365
मध्य भारत : ग्वालियर—3,79,320	वी० जी० देशपांडे (हि० म०) का त्यागपत्र	1 एन० बी० खरे (निर्वाचित) .	हि० म० .	42,534
		2. गौतम शर्मा	कांग्रेस . .	38,846
राजस्थान : जयपुर-सवाई माधोपुर–3,86,270	रामकरण जोशी (कांग्रेस) का त्यागपत्र	1. राजबहादुर (निर्वाचित) . .	कांग्रेस . .	31,282
		2. शातिभाई जौहरी . . .	प्र० सो० पा० .	5,316
राजस्थान · जोधपुर—4,03,653 .	हनवन्त सिंह जी (स्वतत्र) की मृत्यु	1. जसवन्तराय मेहता (निर्वाचित)	स्वतत्र . .	58,527
		2 नूरी मुहम्मद यासीन . .	कांग्रेस . .	20,183
		3. रतन लाल	स्वतत्र . .	3,260
		4 हैदर बक्स	स्वतत्र . .	1,372
		5. सीताराम	स्वतत्र . .	702
राजस्थान . टोक 3,91,851 . .	पन्नालाल आर० कौशिक (कांग्रेस) की मृत्यु	1. माणिक्यलाल वर्मा (निर्वाचित) .	कांग्रेस . .	41,492
		2. श्रीनारायण तोतला . . .	स्वतत्र . .	7,073
		3 ग्यारसीलाल . . .	स्वतत्र . .	5,311
सौराष्ट्र : हलार 2,71,319 . .	हिम्मतसिंहजी (कांग्रेस) का त्यागपत्र	1. खडूभाई देसाई (निर्वाचित) .	कांग्रेस . .	53,573
		2 कृष्णशर्मा गुरुदयाल शर्मा .	हि० म० .	7,682
सौराष्ट्र · झालावाड 3,15,744 .	रसिकलाल उमेदचन्द पारिख (कांग्रेस) का त्यागपत्र	1. जयन्तिलाल नरभेराम पारिख (निर्वाचित)	कांग्रेस . .	निर्विरोध
तिरुवांकुर कोचीन : मीनाचल—3,55,237	पी० टी० चाको (कांग्रेस) का त्यागपत्र	1. जार्ज टामस कौतुकपल्ली (निर्वाचित) .	कांग्रेस . .	1,57,006
		2. अक्कम्मा	स्वतत्र . .	1,16,747

राज्यसभा

अध्यक्ष — एस० राधाकृष्णन्
उपाध्य — एस० वी० कृष्णमूर्ति राव

अजमेर और कुर्ग—1

के० सी० कसम्बाया

आंध्र—12

ए० वालारामी रेड्डी
अल्लूरी सत्यनारायण राजु
जी० रगा
शकगालिब
जे० वी० के० वल्लभराव
के० सूर्यनारायण
मक्किनेनी बासवपुन्नैया
एन० डी० एम० प्रसादराव
पुचलपल्ली सुन्दरैया
पाइदा वेकटनारायण
एस० शम्भू प्रसाद
वी० वेकटरमण

आसाम—6

(श्रीमती) वेदवर्त बरागोहाईं
मोहम्मद रफीक
एम० तय्यबुल्ला
(श्रीमती) पुष्पलता दास
आर० थन्हलिरा
फखरुद्दीन अली अहमद

भोपाल—1

भैरों प्रसाद

बिहार—21

अहमद हुसेन
थिप्रोडोर बोडरा
ब्रजकिशोर प्रसाद सिह
महेश सरन
जाफर इमाम
कैलाशबिहारी लाल
कामेश्वर सिंह
किशोरीराम
(श्रीमती) लक्ष्मी एन० मेनन
महेश्वरप्रसाद नारायण सिंह
मजहर इमाम
पूर्णचन्द्र मित्र
रामबहादुर सिह
रामधारी सिंह दिनकर
आर० जी० अग्रवाल
राजेन्द्रप्रताप सिंह
राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह
श्री नारायण महथा
तजम्मुल हुसैन
वी० जी० गोपाल
(कुँवरानी) विजया राजे

बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश—1

सी० एल० वर्मा

बम्बई—17

आबिद अली
भालचन्द्र महेश्वर गुप्ते
बी० आर० अम्बेदकर
चन्दूलाल पी० पारिख
देवकीनन्दन नारायण
धैर्यशीलराव यशवन्तराव पवार
लालचंद हीराचंद दोषी
(श्रीमती) लीलावती मुन्शी
मणिलाल चतुरभाई शाह
एम० डी० डी० गिल्डर
एन० एस० हार्डिकर
प्रेमजी ठोभनभाई लियबा
राजाराम बालकृष्ण राउत
श्रीयांस प्रसाद जैन
सोमनाथ पी० दवे
टी० आर० देवगिरिकर
(श्रीमती) वायलेट अल्वा

दिल्ली—1

ओंकार नाथ

हैदराबाद—11

दिनशा डी० इनालिया
अकबर अली खान
किशन चंद
राघवेन्द्र राव
नरसिंहराव बालभीमराव देशमुख
नारायणदास डागा
वी० प्रसादराव
राजबहादुर गौड़
स० चन्ना रेड्डी
वेंकट कृष्ण धगे
बी० वी० गुरुमूर्ति

जम्मू और काश्मीर—4

आगा सैयद मुहम्मद जलाली
रिक्त
बुधसिंह
पीर मोहम्मद खां

कच्छ—1

लावजी लाखमशी

मध्य भारत—6

गोपीकृष्ण विजयवर्गीय
कन्हैयालाल डी० वैद्य
कृष्णकान्त व्यास
रघुबीर सिंह
त्रिम्बक दामोदर पुस्तके
वी० एस० सरवते

मध्य प्रदेश—12

भानुप्रताप सिंह
करीमुद्दीन
गोपालदास बुलाकीदास मोहता
रामराव माधवराव देशमुख
आर० पी० दुबे
राजा भाऊ विट्ठलदास

एम० आर० मजुमदार
रघुवीर
रामेश्वर उमराव अग्निभोज
(श्रीमती) सीता परमानन्द
रतनलाल किशोरीलाल मालवीय
वामन शिवदास बार्लिंगे

मद्रास—18

ए० रामास्वामी मुदलियार
के० माधव मेनन
(श्रीमती) पार्वती कृष्णन
जी० राजगोपालन
एच० डी० राजा
के० एल० नरसिम्हम्
के० एस० हेग्डे
एम० मुहम्मद इस्माइल साहिब
(श्रीमती) मोना हेन्समैन
पी० एस० राजगोपाल नायडू
पी० सुब्बरायन
एस० वेंकटरामन्
टी० भास्कर राव
टी० एस० पट्टाभिरामन्
टी० वी० कमलास्वामी
वी० के० कृष्ण मेनन
वी० एम० ओबेदुल्ला साहिब
वी० एम० सुरेन्द्र राम

मैसूर—6

बी० पी० बासप्पा शेट्टी
एच० सी० दासप्पा
के० सी० रेड्डी
एम० गोविन्द रेड्डी
मुहम्मद वलीउल्ला
एस० वी० कृष्णमूर्ति राव

मणिपुर और त्रिपुरा—1

नंगोम तम्पोक सिंह

उड़ीसा—9

बोधराम दुबे
स्वप्नानन्द पाणिग्रही
जगन्नाथ दास
प्रफुल्लचन्द्र भञ्जदेव
राधाकृष्ण विस्वासराय
बिस्वनाथ दास
सुन्दर मोहन हेमराम
सुरेन्द्र महन्ती
सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी

पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यसंघ—3

जगन्नाथ कौशल
जोगेन्द्रसिंह मान
रघवीरसिंह जहजारी

पंजाब—8

अनूपसिंह
चमन लाल
दर्शनसिंह फेरूमन
गुरजसिंह ढिल्लन
रायजादा हंसराज
एम० एच० एस० निहालसिंह
स्वर्णसिंह
उधमसिंह नागोके

राजस्थान—9

बरकत उल्ला खा
हरिश्चन्द्र माथुर
केशवानन्द
के० एल० श्रीमाली
लक्ष्मण सिंह
आदित्येन्द्र
विजय सिंह
सरदार सिंह
(श्रीमती) शारदा भार्गव

सौराष्ट्र—4

भोगीलाल मगनलाल शाह
डी० एच० वरियावा
जैसुखलाल हाथी
नानाभाई भट्ट

तिरुवांकुर-कोचीन—6

ए० अब्दुल रज़ाक
सी० नारायण पिल्लई
(श्रीमती) के० पारती
के० पी० माधवन नायर
एन० सी० शेखर
एस० चट्टनाथ करयालर

उत्तर प्रदेश—31

ए० धरमदास
अहमद सईद खा
(बेगम) एज़ाज़ रसूल
अमरनाथ अग्रवाल
अख्तर हुसैन
अमोलख चन्द
बी० के० मुकर्जी
ब्रजबिहारी शर्मा
(श्रीमती) चन्द्रावती लखनपाल
गोपीनाथ सिंह
हरप्रसाद सक्सेना
हृदयनाथ कुंजरू
इन्द्र विद्यावाचस्पति
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जसौदसिंह बिष्ठ
जे० पी० श्रीवास्तव
जसपतराय कपूर
लालबहादुर शास्त्री
मोहम्मद फारूकी
मुरारीलाल
नरेन्द्र देव
नवाबसिंह चौहान
रामकृपाल सिंह
रामप्रसाद टम्टा
आर० सी० गुप्त
(श्रीमती) सावित्रीदेवी निगम
शाम सुन्दर नारायण तन्खा
श्यामधर मिश्र
सुमतप्रसाद
तारकेश्वर पाडे
ठाकुरदास

विन्ध्य प्रदेश—4

अवधेशप्रताप सिंह
(श्रीमती) कृष्ण कुमारी
बनारसीदास चतुर्वेदी
गुलशेर अहमद

पश्चिमी बंगाल—14

बेनी प्रसाद अग्रवाल	नलिनाक्ष दत्त
भूपेश गुप्त	नौशेर अली
विमल कुमार घोष	राजपतसिंह डूगर
सी० सी० बिस्वास	सत्यप्रिय बनर्जी
अब्दुर रेज्जाक खान	सत्येन्द्र नारायण मजुमदार
इन्द्र भूषण बीड	सत्येन्द्र प्रसाद राय
(श्रीमती) मायादेवी छेत्री	सुरेशचन्द्र मजूमदार

राष्ट्रपति द्वारा नामजद—12

ए० आर० वाडिया	पी० वी० काने
काका साहेब कालेलकर	राधाकुमुद मुकर्जी
एम० सत्यनारायण	(श्रीमती) रुक्मिणीदेवी अरुण्डेल
मैथिलीशरण गुप्त	साहिबसिंह सोखे
नारायणदास रतनमल मलकानी	सत्येन्द्रनाथ बोस
पृथ्वीराज कपूर	जाकिर हुसैन

पांचवा अध्याय
न्याय विभाग

26 जनवरी, 1950 को भारत में नया सविधान जारी हुआ था, परन्तु देश के न्याय विभाग में उससे कोई विशेष परिवर्तन नही आया । सविधान की धारा 372 मे यह कहा गया है कि यह संविधान जारी होने के दिन भारत मे जो कानून चल रहे है, उनमे से 'भारत सरकार कानून 1935' तथा 'भारतीय स्वाधीनता कानून 1947' के अतिरिक्त शेष सब कानून उसी तरह जारी रहेगे, जब तक कि अधिकारप्राप्त व्यवस्था द्वारा उनमे परिवर्तन या सुधार न कर दिया जाय । वर्तमान कानूनों को सविधान के अनुकूल बनाने के लिए उनमे आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है ।

इस तरह भारत मे न्याय सम्बन्धी कानून लगभग उसी तरह जारी है, जिस तरह वे स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर थे । दूसरे शब्दों मे विवाह, उत्तराधिकार, दत्तकाधिकार इत्यादि पर विभिन्न सम्प्रदायो के लिए विभिन्न कानून जारी है और अपराध, सौदा, सम्पत्ति के हस्तातरण करने व ट्रस्ट इत्यादि के सम्बन्ध मे देशभर मे एक से कानून है ।

भारत का उच्चतम न्यायालय

संविधान की धारा 124 में कहा गया है कि "देश मे एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमे एक उच्चतम न्यायाधिपति और 7 न्यायाधीश रहेगे । समद इस सख्या को बढा भी सकती है ।" इस समय उच्चतम न्यायालय के सदस्य इस प्रकार है :—

	मुख्य न्यायाधिपति :	**नियुक्ति की तिथि:**
	मेहरचन्द महाजन	4 जनवरी 1954
	न्यायाधीश :	
1.	विजनकुमार मुखर्जी	14 अक्तूबर 1948
2	सुधी रजन दास	20 जनवरी 1950
3.	विवियन बोस	3 मार्च 1951
4.	गुलाम हसन	8 सितम्बर 1952
5.	एन० एच० भगवति	8 सितम्बर 1952
6.	बी० जगन्नद्धादास	9 मार्च 1953
7.	टी० एल० वेंकटराम अय्यर	4 जनवरी 1954

इस से पहले हरिलाल जे० कानिया 26 जनवरी 1950 से 6 नवम्बर 1951 तक तथा एम० पातंजलि शास्त्री 7 नवम्बर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक मुख्य न्यायाधिपति रह चुके है ।

अधिकार क्षेत्र

उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे नये मुकदमे सुनना तथा अपीले सुनना दोनो है । यूनियन तथा राज्यों के बीच के झगड़े अथवा राज्यों के पारस्परिक झगडे उच्चतम न्यायालय के सामने आते है । कानून के अर्थ के सम्बन्ध में हाईकोर्टों द्वारा दिये गये सभी निर्णयों के सम्बन्ध

मे उच्चतम न्यायालय मे अपील की जा सकती है। दीवानी और फौजदारी के मामलो में उच्चतम न्यायालय को वही अधिकार प्राप्त है, जो 1947 तक प्रिवी कौंसिल को थे। इस के अतिरिक्त नागरिको के आधारभूत अधिकारों को अक्षुण्ण रखने के सम्बन्ध मे उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा निर्णयार्थ प्रेरित विषयों पर इस न्यायालय से सलाह भी मागी जा सकती है।

1935 के कानून के अनुसार, उस जमाने के प्रस्तावित फैडरल कोर्ट मे कानून सम्बधी केवल वे ही मामले पेश किये जा सकते थे, जिनके सम्बन्ध मे हाईकोर्ट अपना निर्णय दे चुका हो और हाईकोर्ट ने यह भी कहा हो कि उनका सम्बन्ध संविधान की व्याख्या से है। परन्तु नये सविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय मे वे मामले भी पेश किये जा सकते हैं, जिनके सम्बन्ध मे हाईकोर्ट इस तरह की कोई बात नही कह का। वे आर्थिक मामले उच्चतम न्यायालय मे पेश हो सकते हैं, जिनमे 20 हजार रुपयो से अधिक राशि का निर्णय होना हो। इस से पहले प्रीवी कौसिल के सामने कम से कम 10,000 रु० की धनराशि के सम्बन्ध मे अपील हो सकती थी।

फौजदारी के मुकदमो मे से वे मामले उच्चतम न्यायालय मे पेश हो सकते हैं, जिनके सम्बन्ध मे हाईकोर्ट ने (क) निचले न्यायालय मे अभियुक्त की रिहाई के निर्णय के प्रतिकूल मौत की सजा दे दी हो (ख) अपने से निम्न कोटि के किसी न्यायालय से किसी मुकदमे को अपने हाथ मे ले लिया हो, और उस मुकद्दमे मे अभियुक्त को मौत की सजा दी हो या (ग) यह प्रमाणित किया हो कि यह मामला उच्चतम न्यायलय में अपील के लिए उपयुक्त है (धारा 134)। ससद को यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और भी बढा कर उसे यह अधिकार दे दे कि वह भारत के किसी हाईकोर्ट द्वारा फौजदारी मामले में दिए हुए निर्णय, अन्तिम आज्ञा या सजा के सबध मे अर्जी प्राप्त करें तथा सुने।

अन्य शक्तियां

धारा 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को नागरिको के आधारभूत अधिकारो की रक्षा के लिए कई विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार हाईकोर्टों को भी हैं। सविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सम्पूर्ण भारत मे मान्य होगा। किसी एक मामले मे दिया गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश भर के उसी तरह के मामलों के लिए प्रत्येक न्यायालय को मान्य होगा। धारा 142(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को कहीं उपस्थित होने के लिए अथवा दस्तावेज़ों को पेश करने के लिए अथवा अपने अपमान के सिलसिले मे हाि र होने के लिए बाधित कर सकता है।

धारा 145 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने लिए कार्य पद्धति के नियमोपनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। संविधान सम्बन्धी मामलों में, जो उच्चतम न्यायालयों की डिवीजन बेंचों के सन्मुख पेश होंगे, कम से कम 5 जज अवश्य होंगे। अगर जजों में मतभेद होगा, तो बहुमत की राय मानी जायेगी, परन्तु अल्पमत को यह अधिकार होगा कि वह अपने मतभेद को अंकित कर दे।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय

गत वर्ष कई ऐसे महत्वपूर्ण मामले उच्चतम न्यायालय के सामने उपस्थित किये गये थे, जो कानून की व्यवस्था से सम्बद्ध थे। उनमे सबसे महत्वपूर्ण मामला सविधान का प्रथम सशोधन (सन् 1951) सम्बन्धी था। ससद ने यह कानून ज़मीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए न्याय-सम्बन्धी अनावश्यक और लम्बी छानबीन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया था ताकि अनावश्यक मुकदमेबाज़ी न हो। जमीदारो पर इस कानून का प्रतिकूल प्रभाव पडता था। इसलिये सविधान की धारा 32 के अनुसार उन्होने उच्चतम न्यायालय मे इस कानून के खिलाफ अपील की। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त कानून वैध है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि अस्थायी ससद को इस तरह का परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि उस मे उस समय केवल एक ही सदन था, जब कि संविधान मे दो सदनो की व्यवस्था है।

सार्वजनिक उद्देश्य

इसी सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्ण कानूनी मसला यह था कि जमीदारी हटाने मे 'सार्वजनिक उद्देश्य' कहा तक आता है। इस सम्बन्ध मे जजो की राय विभाजित थी। जस्टिस महाजन ने बहुमत की रिपोर्ट मे यह कहा कि "उच्चतम न्यायालय को इस सम्बन्ध मे विचार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।" उनका कथन था, "यह स्पष्ट है कि कुछ व्यक्तियो के पास भूमि के बडे बडे भाग होना भारतीय सविधान के आधारभूत सिद्धान्तो के विरुद्ध है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि वह भूमि कुछ व्यक्तियो के हाथ से निकल कर राष्ट्र के हाथ मे आ जाए और राष्ट्र उसे सार्वजनिक हित के कार्यों मे लगा सके।"

इस तरह विद्वान जजो ने जमीदारी को हटाने के सम्बन्ध मे राष्ट्र की नीति को उचित सिद्ध किया। ये सिद्धान्त कोई अदालत किसी राज्य पर थोप नही सकती, परन्तु सरकार का यह अपना कर्तव्य है कि कानून बनाते हुए इन सिद्धान्तो का ख्याल रखे। जस्टिस महाजन का कथन था कि सार्वजनिक हित का तात्पर्य क्या है, यह युग भावना की गति को देखते हुए सम ना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह विशेष कानून किस समय बनाया गया था। उन्होने यह भी कहा, इस सम्बन्ध में अदालतो की अपेक्षा राज्यो के विधानमडल अधिक प्रामाणिक है।

कानून के सन्मुख समानता

उच्चतम न्यायालय के सामने दूसरा महत्वपूर्ण मामला 'पश्चिमी बगाल सरकार बनाम अनवरअली सरकार' था। इस मामले मे कानून के सन्मुख समानता का प्रश्न विचारणीय था। पश्चिमी बगाल सरकार ने बंगाल स्पेशल कोर्ट कानून के नाम से एक कानून बनाया था, जिसका उद्देश्य कुछ मामलों मे मुकदमो की रफ्तार तेज करना था। राज्य की सरकार ने कुछ ऐसी विशेष अदालतें बनाई थी, जिन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सिद्धान्त के अतिरिक्त भी कुछ कार्य-पद्धति सम्बन्धी अ कार दिए गए थे। ऐसी ही किसी विशेष अदालत ने अनवरअली को फासी की सजा दी थी। अनवरअली ने इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की कि राज्य को कानून के सम्बन्ध मे समानता के सिद्धान्त को खंडित करने का

अधिकार नही है। इस सम्बन्ध मे उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से (6 और 1) अपील को स्वीकार कर लिया। यह निर्णय दिया गया कि स्पेशल कोर्टों की कार्य पद्धति मे कोई आधारभूत भेद नही होना चाहिए।

पेशों की स्वाधीनता

संविधान की धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को कोई भी पेशा अपनाने की पूरी स्वाधीनता है। केवल राज्यों की सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे व्यापार व्यवसाय आदि पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगा सकें। 'मोहम्मद यासीन बनाम टाउन एरिया कमेटी' के एक मामले मे यह प्रश्न उठाया गया कि व्यापार पर लायसस फी लगाना आधारभूत सिद्धान्त के विरुद्ध है या नही। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस तरह की फीस नही लगाई जा सकती।

'सतीशचन्द्र बनाम भारत यूनियन' मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या भारत सरकार सतीशचन्द्र की सेवाओ को बीच मे ही समाप्त कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य अस्थायी सेवा के लिए अनुबन्ध कर सकता है। सतीशचन्द्र की अपील स्वीकार नही हुई।

उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट)

राज्यों मे न्याय के लिए सब से उच्च अदालत उच्च-न्यायालय है।

वर्तमान समय मे 'क' और 'ख' सूचियों के राज्यो मे कुल 17 उच्च न्यायालय है। उन की सूची इस प्रकार है :—

	उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) का नाम	अधिकार क्षेत्र का प्रदेश	प्रतिस्थापन वर्ष
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1919
2.	आसाम	आसाम	1948
3.	बम्बई	बम्बई	1861
4.	कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल	1861
5.	हैदराबाद	हैदराबाद	1926
6.	जम्मू और काश्मीर	जम्मू और काश्मीर	1928
7.	मध्य भारत	मध्य भारत	1948
8.	मद्रास	मद्रास और आंध्र	1861
9.	मैसूर	मैसूर	1884
10.	नागपुर	मध्यप्रदेश	1936
11.	उड़ीसा	उडीसा	1948
12.	पटना	बिहार	1916
13.	पेप्सू	पेप्सू	1948
14.	पंजाब	पंजाब और दिल्ली	1947
15.	राजस्थान	राजस्थान	1949
16.	सौराष्ट्र	सौराष्ट्र	1948
17.	तिरुवांकुर-कोचीन	तिरुवांकुर-कोचीन	1949

लगभग 75 वर्षों तक इनमे से कुछ उच्च न्यायालय देश के सर्वोच्च न्यायालय बने रहे। प्रिवी कौंसिल इस देश से बहुत दूर थी, इसलिए उसका शासन सम्बन्धी नियत्रण उच्च न्यायालयों पर नही रह सकता था। नए संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अधिकार स्वभावतः अधिक है। उसके अपील सम्बन्धी अधिकार भी प्रिवी कौंसिल की अपेक्षा विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के व्यवस्था सम्बन्धी मामलो मे अब भी हस्तक्षेप नही कर सकता। यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, जो उच्च न्यायालय के जजो की नियुक्ति करते हुए भारत के उच्चतम न्यायाधिपति से भी राय लेता है।

उच्च न्यायालयो के जजो की सख्या का निर्णय राष्ट्रपति विभिन्न राज्यो की आवश्यकताओ को देखकर करता है। उक्त 17 उच्च न्यायालयो मे कुल मिलाकर 140 जज है, उनकी सूची नीचे दी गई है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

इलाहाबाद

मुख्य न्यायाधीश	नियुक्ति की तिथि	
बी० मल्लिक	14 दिसम्बर	1947
अन्य न्यायाधीश		
1. एम० एच० किदवई	13 जुलाई	1946
2 ओ० एच० मूथम	22 जुलाई	1946
3 आर० दयाल	22 जुलाई	1946
4 एच० चन्द्र	15 जनवरी	1947
5 सी० बी० अग्रवाल	14 मई	1948
6 एम० सी० देसाई	13 दिसम्बर	1948
7 वी० भार्गव	1 अगस्त	1949
8. बी० एम० लाल	फरवरी	1950
9. आर० एन० गुर्टू	1 जून	1951
10. एन० बेग	1 जून	1951
11. बी० मुकर्जी	8 अगस्त	1952
12. एम० एल० चतुर्वेदी	8 अगस्त	1952
13 एच० एम० चतुर्वेदी	14 नवम्बर	1952
14. ए० चरण	22 दिसम्बर	1952
15. आर० सिंह	6 अप्रैल	1953
16. एच० पी० अस्थाना	6 अप्रैल	1953
17. डी० एन० राय	14 दिसम्बर	1953

आसाम

मुख्य न्यायाधीश		
सरजू प्रसाद	25 जनवरी	1950

अन्य न्यायाधीश	नियुक्ति की तिथि
1. आर० लभाया	3 जनवरी 1949
2. एच० आर० डेगा	5 जून 1951

बम्बई

मुख्य न्यायाधीश	
एम० सी० चागला	4 जनवरी 1948
अन्य न्यायाधीश	
1 एन० एच० सी० कोयाजी	1 मार्च 1943
2 जी० एस० राजाध्यक्ष	14 जून 1943
3 आर० एस० बावडेकर	6 मार्च 1945
4. पी० बी० गजेन्द्रगडकर	6 मार्च 1945
5. वाई० वी० दीक्षित	16 फरवरी 1946
6 एस० आर० तन्दूलकर	2 जुलाई 1946
7 एच० के० चेनानी	27 अगस्त 1948
8 जे० सी० शाह	1 मार्च 1949
9. डी० वी० व्यास	6 मार्च 1950
10. एस० टी० देसाई	8 अक्तूबर 1952

कलकत्ता

मुख्य न्यायाधीश	
पी० बी० चक्रवर्ती	14 मई 1952
अन्य न्यायाधीश	
1. जी० एन० दास	12 फरवरी 1947
2. के० सी० चन्दर	10 मार्च 1948
3. के० सी० दासगुप्त	13 मई 1948
4. आर० पी० मुकर्जी	13 मई 1948
5. एस० आर० दासगुप्त	3 जनवरी 1949
6. एस० सी० लाहरी	3 जनवरी 1949
7. पी० बी० मुकर्जी	3 जनवरी 1949
8. ए० के० सरकार	25 जनवरी 1949
9. जे० पी० मित्र	11 फरवरी 1949
10. बी० के० गुहा	3 नवम्बर 1949
11. एच० के० बोस	8 दिसम्बर 1949
12 आर० एस० बचावट	23 जनवरी 1950
13. डी० एन० सिन्हा	3 जुलाई 1950
14. पी० एन० मुकर्जी	20 नवम्बर 1950
15. एस० एन० गुहा राय	23 मई 1951

16. आर० मुकर्जी	12 मई	1952
17. एस० के० सेन	12 मई	1952
18. जी० के० मित्र	24 नवम्बर	1952
19 डी० मुकर्जी	24 नवम्बर	1952

हैदराबाद

मुख्य न्यायाधीश

एल० एस० मिश्र	13 नवम्बर	1952

अन्य न्यायाधीश

1 एम० आर० पालनिटकर	24 फरवरी	1943
2 क्यू० हसन	24 फरवरी	1943
3 एम० प्रसाद	20 नवम्बर	1946
4 एम० ए० अन्सारी	20 नवम्बर	1946
5 एम० ए० खान	1 जनवरी	1947
6 ए० श्रीनिवासाचारी	26 मार्च	1947
7 वी० आर० देशपांडे	10 सितम्बर	1949
8 पी० जे० रेड्डी	16 फरवरी	1952

जम्मु और काश्मीर

मुख्य न्यायाधीश

जे० एन० वजीर	मार्च	1948

अन्य न्यायाधीश

1 जे० एल० किलम	अप्रैल	1948
2 एम० ए० शाहमीरी	अगस्त	1948

मध्य भारत

मुख्य न्यायाधीश

जी० के० शिण्डे	26 जनवरी	1952

अन्य न्यायाधीश

1 पी० वी० दीक्षित	29 जुलाई	1948
2. ए० एच० खान	21 मार्च	1951
3. बी० के० चतुर्वेदी	21 मार्च	1951
4. वी० आर० नेवासकर	14 जुलाई	1952
5. एम० एम० सम्वतसर	29 जुलाई	1953

मद्रास

मुख्य न्यायाधीश

पी० वी० राजमन्नार	17 जनवरी	1948

अन्य न्यायाधीश

1. पी० एस० राव	28 जुलाई	1947
2. पी० जी० मेनन	28 जुलाई	1947

अन्य न्यायाधीश	नियुक्ति की तिथि
3. के० एस० राव	22 मार्च 1948
4. ई० ई० मैक	3 अप्रैल 1948
5. पी० राजगोपालन	5 अप्रैल 1948
6. ए० एस० पी० अय्यर	7 सितम्बर 1948
7. एन० सोमसुन्दरम्	27 सितम्बर 1948
8. पी० वी० बी० अय्यर	19 जनवरी 1949
9. पी० सी० रेड्डी	16 जुलाई 1949
10. बी० अहमद	16 जुलाई 1949
11. डब्ल्यू० एस० के० नायडू	16 जुलाई 1949
12. पी० एन० रामास्वामी	7 जुलाई 1951
13. के० आर० गुन्दर	7 जुलाई 1951
14. एन० आर० आयंगार	23 नवम्बर 1953
15. के० उमामहेश्वरम्	26 नवम्बर 1953

मैसुर

मुख्य न्यायाधीश	
पी० मेदप्पा	20 नवम्बर 1948
अन्य न्यायाधीश	
1. पी० वेंकटरामैय्य	25 फरवरी 1946
2. एन० बालकृष्णैय्य	14 जून 1948
3. टी० एन० मल्लप्प	24 नवम्बर 1948
4. बी० वी० मूर्ति	10 अगस्त 1950

नागपुर

मुख्य न्यायाधीश	
बी० पी० सिनहा	24 फरवरी 1951
अन्य न्यायाधीश	
1. एम० हिदायतउल्ला	24 जून 1944
2. के० टी० मंगलमूर्ति	21 जून 1948
3. के० राव	2 मार्च 1949
4. जे० आर० मुधोलकर	11 नवम्बर 1948
5. वी० आर० सैन	26 जनवरी 1949
6. पी० पी० देव	29 अक्तूबर 1949
7 बी० के० चौधरी	9 नवम्बर 1951
8 जी० पी० भट्ट	14 फरवरी 1953
9 वाई० एस० ताम्बे	8 फरवरी 1954

उड़ीसा

मुख्य न्यायाधीश

एल० पाणिग्रही	4 मार्च	1953

अन्य न्यायाधीश

1.	आर० एल० नरसिंहम्	26 जुलाई	1948
2	एस० पी० महापात्र	2 मई	1952
3.	जे० महन्ती	23 अप्रैल	1953

पटना

मुख्य न्यायाधीश

एस० जे० इमाम	3 सितम्बर	1953

अन्य न्यायाधीश

1	एस० के० दास	4 नवम्बर	1944
2.	वी० रामास्वामी	1 नवम्बर	1947
3.	जे० के० नारायण	22 जनवरी	1948
4.	वी० पी० जमौर	18 जुलाई	1949
5.	वी० एन० राय	25 जनवरी	1950
6.	सी० पी० सिन्हा	16 जून	1950
7.	के० अहमद	23 अप्रैल	1951
8.	एस० सी० मिश्र	11 दिसम्बर	1952
9.	के० के० बैनर्जी	12 दिसम्बर	1952
10.	आर० के० चौधरी	4 अप्रैल	1953
11.	के० सहाय	13 जुलाई	1953

पेप्सु

मुख्य न्यायाधीश

के० आर० पास्सी	19 नवम्बर	1953

अन्य न्यायाधीश

1.	जी० एल० चौपड़ा	28 अक्तूबर	1948
2.	जी० सिंह	21 जुलाई	1950
3.	मेहरसिंह	24 दिसम्बर	1953

पंजाब

मुख्य न्यायाधीश

ए० एन० भंडारी	8 दिसम्बर	1952

अन्य न्यायाधीश

1.	जी० डी० खोसला	1 नवम्बर	1944
2.	डी० फालशा	2 दिसम्बर	1946

3. एच० सिंह	8	नवम्बर	1948
4. जे० एल० कपूर	6	जून	1949
5. एस० एस० दूलत	13	मार्च	1953

राजस्थान

मुख्य न्यायाधीश			
के० एन० वाचू	2	जनवरी	1951
अन्य न्यायाधीश			
1. के० एल० बापना	29	अगस्त	1949
2. जे० एस० राणावट	29	अगस्त	1949
3. के० के० शर्मा	15	जून	1951
4. डी० एस० दवे	12	जुलाई	1952
5. आई० एन० मोदी	29	जनवरी	1953

सौराष्ट्र

मुख्य न्यायाधीश			
एम० सी० शाह	1	अप्रैल	1951
अन्य न्यायाधीश			
1. एस० जे० चटपर	5	अप्रैल	1950
2. जे० ए० बक्सी	22	सितम्बर	1951

तिरुवाकुर-कोचीन

मुख्य न्यायाधीश			
के० टी० कोशी	26	जनवरी	1952
अन्य न्यायाधीश			
1. के० शंकरन	7	जुलाई	1949
2. के० एस० गोविन्द पिल्लई	7	जुलाई	1949
3 पी० के० सुब्रमण्य अय्यर	9	अगस्त	1950
4 वी० आई० जोसेफ	25	मई	1951
5 जी० के० पिल्लई	24	नवम्बर	1952
6. एम० एस० मेनन	29	जनवरी	1953
7. टी० के० जोसेफ	31	जुलाई	1953

उच्च न्यायालयों की स्वाधीनता

साधारणत. उच्च न्यायालय का अधिकारक्षेत्र अपने राज्यो तक ही सीमित है । राज्य के विधान मण्डलों को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वे उच्च न्यायालय के विधान या सगठन मे कोई परिवर्तन कर सकें । यह अधिकार संसद् को है । इसी तरह उच्च न्यायालय के किसी जज को हटाने का अधिकार भी संसद् को ही है । उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाने के सम्बन्ध में जो कानून हैं, उसी ढंग से उच्च न्यायालय के जजो को हटाया जा सकता है ।

शक्ति तथा कार्य

नए सविधान में उच्च न्यायालयों के कार्य तथा शक्ति मे विशेष परिवर्तन नही किया गया। भारत मे ये उच्च न्यायालय रायल लैटर्स पेटेण्ट के अनुसार जारी किये गये थे। 1861 मे तीन प्रेसीडेसी हाई-कोर्ट बने थे, जिन्हे सीधे मुकदमे सुनने तथा अपीले सुनने का विशेष अधिकार दिया गया था। उसके बाद जो हाई-कोर्ट बने, उन्हे केवल अपीले सुनने का अधिकार था। हां, कुछ विशेष मामले सीधे तौर पर भी उनके पास जा सकते थे।

उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी अदालतो और न्याय मडलो के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। वह इन न्यायालयों के सभी कार्यों, गतिविधि, हिसाब किताब तथा कार्य पद्धति के सम्बन्ध में नियम बना सकता है तथा देखरेख रख सकता है। (धारा 225)

धारा 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सीमा के भीतर किसी व्यक्ति, अधिकारी या सरकार को पेशी के लिए बुला सके या किसी काम को करने से रोक सके और या सविधान के भाग ३ के अधिकारो का प्रयोग कर सके।

अधीनस्थ अदालते

जिले के न्यायाधीशो की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय की राय से करता है। ये न्यायाधीश दीवानी मामलो के सम्बन्ध मे पेश होने वाले मुकदमे सुनते है। जिले के शेष न्यायाधिकारी उनके अधीन होते है। इन शेष न्यायाधिकारियो की नियुक्ति राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से राज्यपाल करता है, और उस की मजूरी उच्च न्यायालय से ली जाती है। इन न्यायाधिकारियो के सम्बन्ध मे सभी कानून, उन के स्थान का निश्चय पदोन्नति, छुट्टी आदि के कार्य उच्च न्यायालय के अधीन होते है।

बनावट और कार्य

देश भर मे छोटे न्यायालयो का ढाचा लगभग एक समान है। प्रत्येक राज्य कुछ जिलो मे बंटा हुआ है और प्रत्येक जिले मे एक जिला न्यायाधीश होता है। उस के नीचे विभिन्न ओहदों के न्यायाधिकारी होते है। इन मे से कुछ को नए मामले सुनने का अधिकार होता है, और कुछ को अपीले सुनने का भी। छोटे दीवानी मामलो के लिए सबजजी अदालते होती है। जमीदार और किसानो के झगडो के लिए लगान सम्बन्धी अदालते है, जिन के निर्णय की अपील ऊपर की अदालतो मे की जा सकती है।

दीवानी अदालते जायदाद या रुपये पैसे सम्बन्धी मुकदमो के अतिरिक्त सरक्षकता, विवाह, तलाक, जायदाद का प्रबन्ध और अधिकार क्षेत्र के निश्चय आदि के सम्बध मे पेश होने वाले मामले भी सुनती है। भूमि अधिगति कानून (लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट) तथा जगलात कानून के दीवानी मामले विशेष अफसर सुनते है, परन्तु उन की अपील दीवानी अदालतो में हो सकती है। नागरिकता के अधिकार सम्बन्धी मामलो को सुनने के लिए तीसरी तरह की अदालते भी होती है, जो प्राय. इसी काम के लिए अस्थायी रूप से बनाई जाती है। इन मामलों में अपील सम्बन्धी अधिकारों के बारे मे कोई स्पष्ट व्यवस्था नही है, इसलिए ऐसे मामलों मे वादी और प्रतिवादी प्राय: उच्च न्यायालयो के हस्तक्षेप का अनुरोध किया करते हैं।

फौजदारी न्याय

भारत का फौजदारी कानून समय समय पर सशोधित किया जाता रहा है और उस के अनुसार फौजदारी अदालते काम करती है। प्रत्येक जिले मे इन अदालतो का मुखिया एक सैशन जज होता है। आवश्यकता के अनुसार उस की सहायता के लिए सहकारी सैशन जज भी नियुक्त किया जाता है। ये न्यायाधिकारी सीधे उच्च न्यायालय के नीचे होते है, और प्राय जिले का शासक उन के कार्य मे हस्तक्षेप नही कर सकता। उन के सन्मुख गभीर मामले भी पेश किये जाते है, जिन के बारे मे कोई मजिस्ट्रेट पहले छानबीन कर चुका होता है। इन अदालतो मे जूरी या असेसर भी नियुक्त किये जाते है। जिला मजिस्ट्रेट इस बात पर निगरानी रखता है कि उस के जिले मे विभिन्न न्यायाधीश क्या काम कर रहे है। जिला कलक्टर के रूप मे वह जिले की कार्यव्यवस्था का भी मुखिया होता है। इसी सम्बन्ध मे यह प्रश्न पैदा होता है कि न्याय को शासन व्यवस्था से कहा तक पृथक रखा जा सकता है। इस सम्बन्ध मे एक अभीष्ट बात यह है कि न्याय सम्बन्धी सभी मामले उच्चन्यायालय के अधीन होते है, और उसी की देखरेख मे चलाये जाते है। बहुत छोटे मामले आनरेरी मजिस्ट्रेटो के सामने भी पेश किये जाते है।

पंचायती अदालतें

सविधान की धारा 40 के अनुसार राज्यो को यह हिदायत दी गई है कि वे गावो की पंचायतों को क्रमश ऐसे अधिकार दे कि वे धीरे धीरे स्वायत्त शासन करने योग्य सस्थाओं का रूप धारण कर ले। इस निर्देश के अनुसार कई राज्यो ने पचायत सम्बन्धी कानून पास कर दिये है, और वहा पचायतो ने कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है।

इन पचायतो के कानूनी विभाग को पचायती अदालत कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश मे प्रत्येक गाव मे एक गाव सभा होती है, जिसका सदस्य प्रत्येक ग्रामवासी होता है। यह गाव सभा 5 प्रतिनिधियो को चुनती है। इसी तरह से कई गाव मिल कर 25–30 आदमियो की एक अदालत सी बना लेते है। ये पचायती अदालते अपने मे से फिर 5 पचो को चुन लेती है। गाव के छोटे छोटे मामले इन पचायतो के सामने पेश होते है। ये पच मौके पर जाकर अपने विचाराधीन मामलो के सम्बन्ध मे निर्णय देते है। उनके निर्णय के खिलाफ अपील नही की जा सकती। अगर किसी मामले मे दीवानी जज यह समझे कि कोई भारी अन्याय हुआ है, तो वह किसी नए ट्रिब्यूनल के सामने उस मामले को पेश कर सकता है। परन्तु पचायती अदालत के निर्णय को वह स्वय नही बदल सकता।

न्याय और शासन का पृथकत्व

संविधान की धारा 50 के अनुसार सभी राज्य अब यह प्रयत्न कर रहे है कि न्याय को शासन से पृथक कर दिया जाये। इस सम्बन्ध मे सब से अधिक उन्नति मद्रास मे हुई है। वहा फौजदारी कानून के अधीन निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है। मजिस्ट्रेट के कार्यों को इन दो भागों में बाटा गया है—(1) न्याय सम्बन्धी तथा (2) अन्य। जो अधिकारी न्याय सम्बन्धी कार्य कर रहे है, उन्हे हाईकोर्ट के अधीन कर दिया गया है। जो शासन अधिकारी कानून और व्यवस्था की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, उनके अधिकारों

में कोई कमी नहीं की गई। यह भी नियम बना दिया गया है कि न्याय सम्बन्धी अधिकारी केवल वही लोग बनाये जाये, जिन्हे कानून का ज्ञान हो। अन्य राज्यों में भी इसी तरह के प्रयत्न किए जा रहे है।

न्यायपद्धति मे सुधार

22 दिसम्बर 1953 को भारत सरकार ने एक नया बिल प्रकाशित किया था, जिस का उद्देश्य देश की न्याय व्यवस्था मे बड़े बड़े सुधार करना है। इस बिल पर आजकल ससद विचार कर रही है। जब यह बिल कानून बन जायगा, तब देश की न्याय-व्यवस्था अब की अपेक्षा अधिक सरल, कम समय लेने वाली और प्रभावशाली बन जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन

गत वर्ष की एक बड़ी घटना दिल्ली मे एक अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन का होना है, जो 28 दिसम्बर 1953 से 2 जनवरी 1954 तक हुआ था। यह सम्मेलन एशिया भर मे अपने ढग का प्रथम सम्मेलन था, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून सघ की भारतीय शाखा ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन मे 25 देशो के प्रतिनिधि और प्रेक्षको ने भाग लिया था। सम्मेलन ने कोई प्रस्ताव तो पास नही किया, परन्तु कानून सम्बन्धी कितनी ही बातो पर 6 दिन तक विचार-विनिमय होता रहा। प्रतिनिधियो ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। जिन प्रश्नो पर विचार हुआ था, उन मे से कुछ निम्नलिखित है :—

सयुक्त राष्ट्र सघ का अधिकारपत्र; मानवीय अधिकार, राज्य के व्यक्तित्व भग का कानूनी परिणाम, विदेशियो के व्यक्तिगत अधिकार, न्याय सम्बन्धी कानून और कानूनी पेशा। ससार की वर्तमान राजनीतिक अवस्था को देखते हुए सम्मेलन ने यह अनुभव किया कि केवल बहुमत के बल पर सयुक्त राष्ट्र सघ के अधिकारपत्र मे कोई परिवर्तन नही करना चाहिए।

मानवीय अधिकार

सम्मेलन को यह जान कर सन्तोष हुआ कि मानवीय अधिकारो की आधारभूत बाते बहुत से देशो के सविधानो मे सम्मिलित कर ली गई है। परन्तु यह उचित समझा गया कि इस सम्बन्ध के कानून सब देशो मे लगभग एक समान बनाये जाये। प्रतिनिधियो की यह भी राय थी कि सयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशो के लिए यह आवश्यक है कि वे मानवीय अधिकारो के अधिकारपत्र का आदेश स्वीकार करे।

न्यायविभाग तथा कानूनी पेशा

सम्मेलन की यह भी राय थी कि जज कैसे व्यक्ति बनाये जाते है, इस बात का किसी भी देश की न्याय व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उचित ढग के लोगों को न्याय विभाग मे लगाना चाहिए। सब की यह भी राय थी कि न्यायाधिकारियो का चुनाव करते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण कभी नही होना चाहिए, केवल कानूनी गुण और योग्यता को ही इस सम्बन्ध मे परख मानना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि न्यायाधिकारियों का वेतन इतना अवश्य रखना चाहिए कि यह कार्य ऊचे दर्जे के लोगो को अपनी ओर आकृष्ट कर सके।

सलाहकारी समिति

सम्मेलन के अन्तिम दिन बर्मा के प्रतिनिधि ने यह सुझाव पेश किया कि एशियाई देशों की सरकारें कानून विशेषज्ञो की एक सलाहकार समिति का निर्माण करें, जो अन्तर्राष्ट्रीय

कानून तथा अन्य कानूनी बातों के सम्बन्ध में राय दिया करे । ईराक, सीरिया, इण्डोनेशिया, जापान, नेपाल, लंका और भारत के प्रतिनिधियों ने इस सुझाव का समर्थन किया ।

भारत का एटर्नी-जनरल

संविधान की धारा 76 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को भारत का एटर्नी-जनरल नियुक्त करें, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय का जज बनने की योग्यता विद्यमान हो । यह एटर्नी-जनरल भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा । एटर्नी-जनरल भारत की सब अदालतों में उपस्थित हो सकता है । इस के साथ एक सोलीसिटर-जनरल होता है । आजकल ये पद इन लोगों के पास हैं —

(1) भारत के एटर्नी-जनरल : एम० सी० सीतलवाड

(2) भारत के सोलीसिटर-जनरल . सी० के० दफ्तरी

प्रत्येक राज्य में एक एडवोकेट जनरल होता है । उस की नियुक्ति राज्यपाल करता है । इस एडवोकेट जनरल में उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए । भारत में जो कार्य और अधिकार एटर्नी-जनरल को हैं, वही कार्य और अधिकार राज्यों में एडवोकेट जनरल को हैं ।

वकील

1926 के बार कौंसिल कानून के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य भर के एडवोकेटों की एक सूची रखनी पड़ती है । इस कानून का उद्देश्य यह था कि देश में वकालत का काम करने वाले विभिन्न पदवी प्राप्त लोगों, यथा वकील, एटर्नी, बार-एट-ला, मुख्तार प्लीडर, एडवोकेट आदि को एक ही सूची में लाया जा सके ।

वर्तमान प्रथा के अनुसार उच्चतम न्यायालय में सब वकील अपना नाम दर्ज कराते हैं, और किसी मामले में बिना छोटे वकील को साथ लिए कोई बड़ा वकील पेश नहीं हो सकता । उच्च न्यायालयों में वकालत करने वाले वकीलों की पृथक सूची है, और उस के सम्बन्ध में विशेष नियम हैं । छोटी अदालतों में वकालत करने वाले वकीलों के सम्बन्ध में राज्य का उच्च न्यायालय कानून बनाता है ।

अखिल भारतीय विधान-जीवी-वर्ग (बार)

उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बाद देश में इस बात का विशेष अनुभव किया गया कि एक अखिल भारतीय विधान-जीवी-वर्ग (बार) को स्थापित करना आवश्यक है । दिसम्बर 1951 में जस्टिस एम० आर० दास की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक बार-कमेटी का निर्माण किया था । इस कमेटी को यह कार्य दिया गया था कि वह अखिल भारतीय बार की आवश्यकताओं और संभावनाओं के सम्बन्ध में विचार करे ।

मई 1953 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । इस कमेटी ने सिफारिश की कि (1) एक अखिल भारतीय बार कौंसिल की स्थापना की जाये, (2) कलकत्ता और बम्बई के उच्च न्यायालयों में कौंसिल और सोलीसिटर की दोहरी प्रथा जारी रहे, (3) उच्चतम न्यायालय में यह दोहरी प्रथा न डाली जाय और (4) देश भर में वकालत के पेशे के लिए अपना नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध में कम से कम योग्यता का एक समान माप नियत कर दिया जाये ।

इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इस प्रस्तावित अ० भा० बार कौंसिल में ये लोग रहेंगे :—

(1) उच्चतम न्यायालय के दो ऐसे जज, जो कभी वकील रह चुके हों। उन का चुनाव भारत का मुख्य न्यायाधिपति करेगा। (2) भारत का एटर्नी-जनरल तथा सोलीसिटर-जनरल। (3) राज्यों की बार कौंसिलों का एक-एक प्रतिनिधि। (4) उच्चतम न्यायालय की बार कौंसिल के ३ प्रतिनिधि।

यह अखिल भारतीय विधानजीवी कौन्सिल देश भर के वकीलों के लिए न्यूनतम योग्यता तथा सूची में अपना नाम लिखाने के लिए फीस की दर निश्चित करेगी। यह उन बातों का भी निश्चय करेगी, जिन के आधार पर आवेदनपत्र को अस्वीकार किया जा सकता है और यही कौन्सिल वकालत के नियमों तथा शिष्टाचारों का निश्चय करेगी, तथा उन प्रणालों का निर्णय करेगी, जिनसे राज्यों की विधानजीवी कौन्सिल अपने सदस्यों के व्यवहार के सम्बन्ध में जांच करेगी। देश में कानूनी शिक्षा का माप भी यही कौंसिल निश्चित करेगी।

छटा अध्याय

सार्वजनिक सेवा

सविधान के अनुसार भारतीय यूनियन मे तथा भारत के प्रत्येक राज्य मे एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का विधान है। दो या अधिक राज्य चाहे तो वे मिलकर अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते है। राष्ट्रपति की अनुज्ञा से कोई राज्य यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी यह अनुरोध कर सकता है कि उस राज्य की सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करे।

सविधान की धारा 316 मे इन कमीशनो का उल्लेख है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष तथा सदस्यो की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यो मे ये नियुक्तिया राज्यपाल करता है। इस कमीशन के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए, जो कम से कम 10 वर्षों तक यूनियन की अथवा किसी एक राज्य की सेवा कर चुके हो।

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यो की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए होती है और वे 65 वर्ष की अवस्था मे अवसर प्राप्त कर लेते हैं। राज्यो के कमीशनो के लिए अधिकतम आयु की सीमा 60 वर्ष है। पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य को उस के किसी गभीर विपरीत आचरण के लिए उच्चतम न्यायालय की राय से केवल राष्ट्रपति ही पदच्युत कर सकता है।

धारा 319 के अनुसार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष अवसर प्राप्त कर लेने के बाद भारत सरकार मे अथवा राज्यो की किसी सरकार मे पद ग्रहण नही कर सकता। राज्यो के पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष किसी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते है अथवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मे लिए जा सकते हैं। इस तरह के नियम यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के सदस्यो तथा राज्यो के पब्लिक सर्विस कमीशनो के सदस्यो के लिए भी है।

ये कमीशन अपने क्षेत्र मे राज्य की सेवाओ के लिए परीक्षा द्वारा अथवा भेट द्वारा राज्याधिकारियो को चुनते है। पदोन्नति के लिए भी ये कमीशन उम्मीदवारो को मुलाकात के लिए बुला सकते है। ये कमीशन अपनी अपनी सरकारो को सरकारी सेवाओ के सम्बन्ध के सभी मामलों पर सलाह देते है। इनमे सरकारी कार्यकर्ताओ के अनुशासन भग का मसला भी है। सरकारी नौकरी सम्बन्धी प्रत्येक बात के लिए यह आवश्यक है कि यूनियन सरकार और राज्यो की सरकारे अपने पब्लिक सर्विस कमीशनों से राय ले। इस सम्बन्ध मे राष्ट्रपति या राज्यपाल भी यदि हस्तक्षेप करना चाहे तो उन्हे संसद या राज्य के सविधान मडलो से स्वीकृति लेनी होगी।

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है। अगर किसी मामले मे राष्ट्रपति कमीशन से असहमत हो, तो वह मामला तथा उक्त रिपोर्ट ससद के सामने पेश की जाती है। राज्यो मे भी इसी तरह की कार्य पद्धति का विधान है।

सेवाओं का पुनर्गठन

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से एक ओर तो सरकारो का काम बढ़ गया, और दूसरी ओर उन का कार्य-क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया। जनता की हित की दृष्टि से जो नये

काम प्रारम्भ किये गये तथा नये राजनीतिक सम्बन्धो के कारण नये दूतावास स्थापित होने से राज्य कर्मचारियो की सख्या पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ानी आवश्यक हो गई। दूसरी ओर स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बहुत से अग्रेज उच्च राज्याधिकारी वापस चले गए, तथा अधिकाश मुसलमान राज्याधिकारी पाकिस्तान चले गए। इस तरह भारतीय सिविल सर्विस के लगभग 1,000 उच्च पदाधिकारियो में से लगभग 600 देश छोड कर चले गए, और 400 ही बाकी बच रहे। भारतीय पुलिस सेवाओ का भी यही हाल हुआ।

देश विभाजन से भारतीय सेवाओ के सम्बन्ध मे 3 नई समस्याए उत्पन्न हुई : (1) रिक्त स्थानो की तत्काल पूर्ति, (2) भारतीय सिविल सर्विस तथा भारतीय पुलिस सर्विस के लिए चुनाव करने की नई विधि बनाना, (3) देश की आवश्यकताओ के अनुसार केन्द्रीय सरकार की शासन सम्बन्धी मशीन का पुनर्गठन करना, ताकि देश की शासन सम्बन्धी सेवाए भारत की उन्नति के लिए बरती जाने वाली नई नीति को भली प्रकार व्यवहार मे ला सके।

आपत्कालीन भरती

भारतीय गृह-मत्रालय ने इस कार्य के लिए सेवाओ की तत्कालीन भरती आरम्भ की। 1948 के मध्य मे एक विशेष भरती बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड ने स्थायी सेवाओ के अतिरिक्त अन्य लोगो मे से भी योग्य व्यक्तियो का चुनाव किया। ऊचे पदो पर वे लोग चुने गये, जिन मे इन पदो के लिए आवश्यक सभी गुण विद्यमान थे।

अखिल भारतीय सेवाएं

भारतीय सिविल सर्विस तथा भारतीय पुलिस सर्विस के पुनर्गठन तथा पूरी तरह भारतीय-करण की ओर सरदार वल्लभभाई पटेल का ध्यान उसी समय आकर्षित हुआ, जब वे पहले पहल अन्तरिम सरकार के गृहमत्री बने। अक्तूबर 1946 मे ही उन्होने भारतीय सिविल सर्विस की जगह भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रारम्भ किया, और पुलिस सम्बन्धी सेवाओ की भरती तथा शिक्षा के लिए भी आवश्यक परिवर्तन किये।

3 वर्षों के बाद जब भारत की प्राय सब रियासते भाग 'ख' के रूप मे भारत मे शामिल हो गई, तब उन्हे भी (जम्मू और काश्मीर को छोडकर), इन सेवाओ के अन्तर्गत ले आया गया। वर्तमान भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारत की केन्द्रीय सरकार तथा राज्यो की सरकारो को उच्च शासनाधिकारी देती है और उस का वर्गीकरण विभिन्न राज्यो के आधार पर किया जाता है।

एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ट्रेनिंग स्कूल

दूसरे महायुद्ध तक आई० सी० एस० के सभी चुने हुए उम्मीदवारो को इग्लैड मे जा कर 1 या 2 वर्षों के लिए शिक्षा लेनी पडती थी। महायुद्ध के दिनो मे यह प्रथा बन्द कर दी गई और देहरादून मे एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया गया और 1947 मे दिल्ली मे एक भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस स्कूल खोल दिया गया। इस स्कूल के पाठ्यक्रम मे, फौजदारी कानून, प्रारम्भिक दीवानी कानून, भारतीय भाषाए, सेवा सम्बन्धी व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा, भारत की सामाजिक, सास्कृतिक और व्यवस्था सम्बन्धी विकास का इतिहास और देश की आर्थिक समस्याओ से सम्बद्ध अर्थ-अस्त्र के आधारभूत सिद्धान्तो की शिक्षा दी जाती है।

भारतीय पुलिस सेवाए

स्वाधीनता से पहले भारतीय पुलिस सर्विस का सगठन भी भारतीय सिविल सर्विस के ढग पर था, और इस सेवा मे भी कुछ लोग इग्लैंड में और कुछ लोग भारत मे प्रादेशिक आधार पर लिए जाते थे। प्रान्तों की पुलिस सेवाओ के व्यक्ति भी अच्छा काम करने की दशा मे भारतीय पुलिस सर्विस मे ले लिए जाते थे। द्वितीय विश्व महायुद्ध तथा भारतीय स्वाधीनता के कारण इन सेवाओ मे जब स्थान रिक्त हुए, तो उन की पूर्ति मुख्यत: प्रान्तो की पुलिस सर्विस के योग्य व्यक्तियो को लेकर की गई।

राज्यो के मुख्य मत्रियो के जिस सम्मेलन मे भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सम्बन्ध मे नया ढग स्वीकार किया गया, उसी सम्मेलन मे भारतीय पुलिस सर्विस के लिए भी यह ढग स्वीकार किया गया। यह निश्चय हुआ कि पुलिस सर्विस के व्यक्ति भी राज्यों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा चुने जायेंगे। इन सेवाओ के वेतन वर्तमान स्थितियो के दृष्टिकोण मे विभिन्न राज्यो की सलाह से नियत किये जायेंगे। शुरू शुरू मे एक विशेष भरती बोर्ड रिक्त स्थानों की पूर्ति बाहर से योग्य व्यक्तियो के चुनाव द्वारा करेगा।

सेवाओं के सम्बन्ध के नियम

सविधान की धारा 312 के अनुसार भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा भारतीय पुलिस सर्विस ये दोनो अखिल भारतीय सेवाए हैं। इन के सम्बन्ध मे सभी तरह के नियमन करना संसद का काम है। उसी के अनुसार अक्तूबर 1951 मे ससद ने अखिल भारतीय सेवा कानून (आल इडिया सर्विस ऐक्ट) पास किया था। सविधान के अनुसार सेवाओ के सदस्यो को उनके सदस्यत्व काल के लिए उचित सुरक्षा भी दी गई है। धारा 311 के अनुसार किसी अखिल भारतीय सेवा का कोई व्यक्ति केवल अपने नियुक्त करने वाली सस्था द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है और साथ ही यदि कभी उसे पदच्युत करने की स्थिति उत्पन्न भी हो जाये, तो पदाधिकारी को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जायेगा। परन्तु वह अधिकार तीन अवस्थाओ मे नही मिलेगा—(1) जिन अधिकारियो पर फौजदारी अधिरोप हो, या (2) जिन्हे पदच्युत करने वाला अधिकृत अधिकारी यह समझे कि अपराधकर्ता को अपनी सफाई दे सकने की सुविधा देने का कोई व्यवहारिक उपाय नही है और (3) जहा राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस बात का विश्वास हो कि इस तरह की सफाई से राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

भरती

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से राज्य की सेवाओ की भरती के लिए निम्नलिखित अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं :

भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा, भारतीय विदेशी सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा सेवा, भारतीय सेना-लेखा सेवा, भारतीय रेलवे-लेखा सेवा, भारतीय तटकर तथा आन्तरिक कर सेवा, आयकर अफसर श्रेणी 1 और 2, रेलवे-व्यापारिक सेवा, भारतीय रेलवे का प्रवन्ध विभाग, भारतीय डाक सेवा, भारतीय प्रमापन सेवा, भारतीय जंगल सेवा, केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय

रेल की इजीनियरिग सेवा, तार इजीनियरिग मेवा, डाक और तार विभाग की बेतार शाखा की सेवा ।

आयु सीमा

प्रतियोगिता से जिन परीक्षाओ मे चुनाव किया जाता है, उनमे उम्मीदवारो की आयु 21 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। कुछ सेवाओ के लिए परिगणित जातियो के उम्मीदवारो की आयु 27 वर्ष तक हो सकती है ।

केंद्रीय सचिवालय की सेवाए

केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओ मे सहकारी (असिस्टेट) से लेकर अडर-सेक्रटरी तक की सेवाए सम्मिलित है । गृह-मत्रालय चाहे तो इस मे कुछ अपवाद कर सकता है । उन के अतिरिक्त वे सेवाए भी इन्ही मे सम्मिलित है, जिन के बारे मे विभिन्न मत्रालय, अर्थ सचिवालय तथा गृह सचिवालय की सहमति से यह निश्चय करे कि उनकी गणना उक्त सेवाओ मे की जाए ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा सम्बन्धी नई योजना 22 अक्टूबर 1948 को मन्त्रि-मडल ने स्वीकार की थी । इस योजना के अनुसार इन सेवाओ को चार भागो मे बाटा गया है —

(1) अडर सेक्रटरी, (2) सुपरिन्टेण्डेंट, (3) असिस्टेट सुपरिन्टेण्डेट, (4) असिस्टेट । पिछले दो दर्जों के लिए सीधा चुनाव किया जायेगा । 25 प्रतिशत असिस्टेट साधारण क्लार्कों मे से चुने जायेंगे। बाकी स्थानो की पूर्त्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा करेगा । असिस्टेट सुपरिन्टेण्डेट के लिए 50 प्रतिशत स्थान पदोन्नति द्वारा पूरे किये जायेंगे और शेष की पूर्ति प्रतियोगिता-परीक्षाओ द्वारा की जायेगी, जिन परीक्षाओ का नियत्रण एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा सेन्ट्रल श्रेणी I की परीक्षाओ के ढग पर किया जायेगा । सुपरिन्टेण्डेट तथा अडर सेक्रेटरी की सेवाए पदोन्नति के द्वारा की जायेगी ।

सातवां अध्याय

प्रतिरक्षा

अगस्त 1947 म भारतीय सेनाओ को बहुत सी गुथीली समस्याओ का सामना एक साथ करना पड़ा। उन्ही दिनों सेना के बहुत से अंग्रेज अफसर इग्लेंड वापस चले गये थे, और अनेक मुसलमान अफसर पाकिस्तान चले गये थे। इस से भारतीय सेनाओ को अनुभूतपूर्व कठिनाइयो का सामना करना पडा। साथ ही उन्ही दिनो पाकिस्तान से लाखो व्यक्तियो को भारत में लाना था और भारत से लाखो व्यक्तियो को पाकिस्तान ले जाना था। यह सब काम भी भारतीय सेना ने किया। यह कठिन काम समाप्त हुआ ही था कि भारतीय सेनाओ को जम्मू और काश्मीर मे आततायियो को खदेडने के काम पर जाना पडा। उस के कुछ दिन बाद हैदराबाद मे भारतीय सेना को पुलिस कार्यवाही करनी पडी। जिस शीघ्रता और श्रेष्ठता से भारतीय सेनाओ ने यह कार्य किया, उस से उस की ख्याति और प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ गई है।

संगठन

भारतीय सेना जिन दिनो इन उपर्युक्त महत्वपूर्ण कामो मे लगी हुई थी, उन्ही दिनो उन के सगठन मे नए और महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे थे। सब से पहले सेना का नियन्त्रण एक मत्री के सुपुर्द किया गया। स्थल-सेना, जल सेना तथा वायु सेना के लिए पृथक-पृथक तीन कमाडर-इन-चीफ नियुक्त किये गये।

नये सविधान के अनुसार सेनाओ की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के अधीन है तथा उक्त तीनो सेनाओ का नियन्त्रण प्रतिरक्षा सचिवालय करता है। नीति सम्बन्धी सभी बातो का निश्चय मत्रिमडल की प्रतिरक्षा समिति करती है। इस प्रतिरक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान मत्री है, और प्रतिरक्षा, गृह विभाग, अर्थ तथा यातायात के मत्री इस समिति के सदस्य हैं। तीनो कमानो के अध्यक्ष, प्रतिरक्षा सचिव तथा प्रतिरक्षा के आर्थिक सलाहकार भी इस समिति की बैठको मे सम्मिलित होते हैं।

स्थल-सेना का मुख्य केन्द्र सीधे तौर पर आर्मी स्टाफ के मुखिया तथा कमाडर-इन-चीफ के अधीन काम करता है। इस की मुख्य शाखाये निम्नलिखित है (1) जनरल स्टाफ शाखा, (2) एडज्युटेंट जनरल की शाखा, (3) क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा, (4) आर्डिनेंस के मास्टर-जनरल की शाखा, (5) मुख्य इजीनियर की शाखा और, (6) सेना सचिव की शाखा। ये छहो शाखाए कितनी ही उपशाखाओ मे विभक्त की गई है, जिन को डायरेक्टरेट कहा जाता है।

सेना की विभिन्न कमाने पृथक-पृथक जनरल आफिसर कमाडिग-इन-चीफो के अधीन है, जिन्हे लेफ्टीनेंट-जनरल का ओहदा प्राप्त है। ये कमाने क्षेत्रो के अनुसार विभाजित है और प्रत्येक क्षेत्र का मुखिया जनरल आफिसर कमाडिग (जी० ओ० सी०) कहलाता है और उसे मेजर जनरल का ओहदा प्राप्त है। ये क्षेत्र उप-क्षेत्रो म विभक्त है, जिन का मुखिया एक एक ब्रिगेडियर होता है।

जल सेना की कमान नवल स्टाफ के मुखिया तथा कमाडर-इन-चीफ के अधीन है। इस का कार्य चार हिस्सो मे बटा हुआ है। एक सामुद्रिक जहाजो से सम्बन्ध रखने वाला और शेष 3 के कार्यालय स्थल भाग पर है। इसी तरह वायु सेना की कमान 'चीफ आफ एयर स्टाफ' तथा

कमाडर-इन-चीफ के अधीन है। 1949 से सेना के सब फ्रण्टलाइन यूनिट ओपरेशनल कमान के अधीन कर दिये गये है, और सैनिक शिक्षा देने वाली सस्थाए ट्रेनिग कमान के नीचे ले आई गई हैं।

विभिन्न सेनाओं में पारस्परिक समन्वय

तीनो सेनाओ में पारस्परिक रूप से तालमेल रखने के लिए विभिन्न स्तरो पर अनेक कमेटिया बनाई गई है। इन मे सब से ऊची प्रतिरक्षा मत्री की कमेटी है, जो विभिन्न सेनाओ की मुख्य समस्याओ पर विचार करती है। भारत के प्रतिरक्षा मंत्री, तीनो सेनाओ के मुखिया, प्रतिरक्षा सचिव तथा सेना के आर्थिक सलाहकार इस कमेटी के सदस्य है। इस कमेटी का निश्चय देश भर मे लागू होता है। अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी बाते यह कमेटी मत्रिमडल की प्रतिरक्षा कमेटी को विचारार्थ भेजती है।

उक्त तीनो सेनाओ मे परस्पर में अच्छे सम्बन्ध और तालमेल रखने की दृष्टि से सेना, जल सेना तथा वायु सेना के केडेट अफसरो को खडकवासला की नेशनल डिफेन्स एकेडेमी मे एक साल प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी तरह देहरादून की नेशनल डिफेन्स एकेडेमी मे भी तीनो सेनाओ का एक सम्मिलित भाग जारी कर दिया गया है। इसी तरह विलिंग्टन मे शिक्षण प्राप्त सैनिक अफसरो को सैनिक विज्ञान तथा रणनीति आदि का स्नातकोत्तर शिक्षण देने के लिए एक स्टाफ कालेज खोला गया है।

राष्ट्रीयकरण

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय सेनाओ का राष्ट्रीयकरण बहुत शीघ्रता मे हुआ। आज भारतीय सेना मे केवल 49 अग्रेज अफसर है और उन में से भी अधिकाश विशेज्ञ सलाहकार का काम ही कर रहे है।

भारतीय जल सेना तथा वायु सेना मे राष्ट्रीयकरण की यह प्रक्रिया बडी तेजी मे जारी है। जल सेना के बहुत से बडे-बडे अफसर भारतीय है और कैप्टेन आर० डी० कटारी भारतीय जल सेना के डिप्टी कमाडर-इन-चीफ है। कैप्टेन ए० चक्रवर्ती बम्बई के कोमोडोर-इचार्ज है। दोनो को कमाडर का पद प्राप्त है। इन दोनो से ऊपर केवल दो जल सेना अफसर है, एक तो जल सेना के कमाडर-इन-चीफ और दूसरे भारतीय जल सेना के फ्लैग अफसर।

इसी तरह वायु सेना मे भी बडी शीघ्रता से राष्ट्रीयकरण हो रहा है। अप्रैल 1954 से एयर मार्शल मुखर्जी भारतीय वायु सेना के चीफ आफ स्टाफ और कमाडर-इन-चीफ नियुक्त हुए है। एक अन्य भारतीय एयर मार्शल है।

प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी सगठन

1948 मे एक वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन प्रतिरक्षा विज्ञान सगठन बनाया गया था जिस का उद्देश्य प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी आवश्यक बातो के सम्बन्ध मे अन्वेषण करना है। यथा–शक्तिक्षेपण, युद्ध कार्य सम्बन्धी अनुसन्धान, युद्ध सम्बन्धी यातायात, बारूद सम्बन्धी अन्वेषण, सैनिक भोजन तथा सैनिक शिक्षा आदि।

प्रतिरक्षा मंत्रालय को राय देने के लिए वैज्ञानिको की एक समिति बनाई गई है। प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा नाम से प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिको की एक नई सेवा जारी की गई है, जिस मे नागरिक वैज्ञानिक भी लिए जाते है।

1922 मे किरकी मे शस्त्रास्त्रो के अध्ययन के लिए एक सस्था जारी की गई थी। अक्तूबर 1953 से इस सस्था ने सेना के टैकनिकल स्टाफ को नियमित रूप से शिक्षा देना आरम्भ किया। इस सस्था का कोर्स 18 महीनो का है। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयो से भी यह सस्था सम्बद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान के कार्य मे सहायता लेती है।

वीरता के पुरस्कार

26 जनवरी, 1950 को, जिस दिन भारत एक प्रजातन्त्र राज्य बना, राष्ट्रपति ने वीरता के लिए 3 सैनिक पुरस्कार जारी किये . परमवीर चक्र, महावीर चक्र, और वीर चक्र । सेना सम्बन्धी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पद पर क्यो न हो, वीरता के ये पुरस्कार मिल सकते है।

अभी तक परमवीर चक्र, जो वीरता का सब से बडा पुरस्कार है, केवल 5 व्यक्तियो को मिला है। कुछ व्यक्तियो को महावीर चक्र और वीर चक्र भी दिये गये है, जो मख्यत काश्मीर के युद्ध मे दिखाई गई वीरता के सम्बन्ध मे है। इस के अतिरिक्त सैनिको की वीरता के कार्य का वर्णन सेना के खरीतो मे भी किया जाता है।

युद्ध के अतिरिक्त अन्य सेना सम्बन्धी प्रशसनीय या वीरतापूर्ण कार्य के लिए अशोक चक्र नाम का एक पदक दिया जाता है, जो तीन श्रेणियो मे बाटा गया है। भारत का कोई भी नागरिक यह पदक प्राप्त कर सकता है। कुछ व्यक्तियो को यह पदक दिया भी गया है।

सेना

देश की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए भारतीय सेना को आधुनिक ढग का श्रेष्ठतम शिक्षण देने का प्रयत्न किया जा रहा है। सैनिक शिक्षण के डायरेक्टर की अध्यक्षता मे एक शिक्षण पखवाडा भी मनाया गया था। इस के अतिरिक्त बहुत बडे पैमाने पर सैनिक व्यायामो का प्रदर्शन किया गया। गत वर्ष सैनिक शिक्षण का कार्य बहुत सन्तोषप्रद रहा। सेनाओ को युद्ध के नये से नये साधनों और उपायों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया। बर्मा, इण्डोनेशिया, नेपाल, अफगानिस्तान और लंका के सैनिक भी ऊची शिक्षा के लिए भारतीय सेना शिक्षण केन्द्र मे आये। भारतीय सेना के एक मिशन ने नेपाल की सेना का पुनर्गठन किया।

उपकरण

सेना सम्बन्धी उपयोगी और महत्वपूर्ण औजार बनाने के लिए अम्बरनाथ मे एक मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी खोली गई है। नये ढग की इस फैक्टरी से देश की सेना सम्बन्धी औजारो की आवश्यकताओ की बहुत अश तक पूर्त्ति होगी। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हमे बाहर से कम से कम सामान मगवाना पडे। भारत सरकार ने एक फ्रासीसी सस्था से यह समझौता भी किया है कि वह देश मे एक बेतार के तार का कारखाना खोलेगी। इस कारखाने मे तीनो सेनाओं के लिए बहुत सा उपयोगी सामान बनाया जायेगा। आशा है कि सन् 1956 तक यह कारखाना सामान बनाने लगेगा।

एम्बूलेंस यूनिट

1953 मे भारतीय फील्ड एम्बूलेंस यूनिट ने कोरिया म बहुत प्रशसनीय कार्य किया

एक महान कार्य

18 अगस्त 1953 को भारतीय सेना के जिम्मे एक बहुत ही कठिन परन्तु निराला कार्य सौंपा गया। यह कार्य था कोरियाई सन्धि के अनुसार सयुक्त राष्ट्र सघ, उत्तरी कोरियाई, तथा चीनी कमानो को सहायता देने के लिए एक भारतीय कस्टोडियन सेना को कोरिया मे भेजना। सम्भवतः मानवीय इतिहास मे यह पहला उदाहरण था, जब किसी देश की सेना किसी दूसरे देश मे शान्ति तथा जन-कल्याण के उद्देश्य से भेजी गई हो।

हमारी सेना ने कोरिया मे जिस समझदारी, धैर्य और निष्पक्षता से काम किया, उस से सब जगह उन के प्रति सम्मान का भाव बहुत बढ गया और ससार भर मे उस की प्रशसा हुई। भारत मे अपनी इस सेना के लिए जो स्नेह तथा आत्मीयता का भाव विद्यमान था, उस का उदाहरण इस तथ्य मे मिला कि भारतीय नागरिकों ने लाखो रुपये की वस्तुये अपने इन साहसी जवानो के लिए भेजी। अपना काम पूरा कर जब ये सेनाये भारत मे वापस आई, तो सब जगह उन का शानदार स्वागत किया गया।

जल सेना

1953 मे भारतीय जल सेना ने असाधारण उन्नति की। जल सेना को नवीनतम साधनो की शिक्षा देने तथा सैनिक सेवाओ मे तालमेल बढ़ाने के अतिरिक्त गत वर्ष भारतीय जल सेना का पहला हवाई स्टेशन गरुड के रूप मे स्थापित किया गया। इस के अतिरिक्त एक फ्लीट रिक्वायरमेंट यूनिट भी जारी किया गया। गत वर्ष अंग्रेजी जल सेना से हण्ट श्रेणी के 3 डिस्ट्रॉयर उधार रूप मे लिए गये। इन के नाम है गोदावरी, गोमती और गगा। साथ ही 'आई० एन० एस० तीर' पर सैनिक शिक्षण देने का एक केन्द्र खोला गया है।

शुभेच्छा का दूत

भारतीय जल सेना हमारे देश के लिए शुभेच्छा के दूत के रूप मे भी कार्य कर रही है। उसके जहाज इसी भावना से मध्य तथा पूर्वीय भूमध्यसागर के देशो और बर्मा मे भेजे गये। ये जहाज जहा भी गये, वहा इन का हार्दिक स्वागत किया गया। मिश्र के राष्ट्रपति जनरल नजीब ने 8 अगस्त 1953 को अलक्जेंड्रिया मे भारतीय जल सेना के इन जहाजो का निरीक्षण किया।

जून 1953 मे भारतीय जल सेना के 3 पताका जहाज, जिन में दिल्ली भी था, महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के अवसर पर इग्लेंड मे होने वाली जल सेना परेड मे सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हमारी जल सेना के इन जहाजो का निरीक्षण अमेरिका, ब्राजील कैनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशो के जल सेना अधिकारियो ने भी किया।

जल सेना दिवस

सन् 1953 का जल सेना दिवस बहुत महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि उस दिन पहली बार राष्ट्रपति ने उस का निरीक्षण किया। भारतीय जल सेना के कमाडर-इन-चीफ सर पिज़े के शब्दो मे यह दिन भारतीय जल सेना के इतिहास मे एक स्मरणीय दिन था।

जल सेना का वीरता सम्बन्धी पुरस्कार पहली बार 15 अगस्त को लक्ष्मणन टोपास को दिया गया। 26 जनवरी 1953 को लक्ष्मणन ने अपनी जान पर खेल कर हुगली मे से 9 आदमियों की जान बचाई थी, जिन मे स्त्रिया और बच्चे भी सम्मिलित थे।

वायु सेना

1953 में भारतीय वायु सेना के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा संगठन मे लगातार उन्नति हुई है। भारतीय वायु सेना की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे देश मे कितने हवाई जहाज बनाये जाते है। इस वर्ष हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड ने एच० टी० 2 नाम के कुछ जहाज बनाए। आशा की जाती है निर्माण की इस रफ्तार मे शीघ्र ही बहुत वृद्धि होगी और भारतीय वायु सेना को अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए आवश्यक जहाज इसी कम्पनी से मिल सकेंगे। भारतीय वायु सेना के कुछ जहाजों ने आसाम के जंगलो मे चिकित्सा सम्बन्धी सहायता भी पहुंचाई। इस कार्य के लिए एक चिकित्सा सम्बन्धी उडान यूनिट भी बनाई गई है।

प्रशिक्षण

पिछले दो वर्षों मे भारतीय वायु सेना ने उडान की तथा उड़ान सम्बन्धी टेक्निकल बातो की शिक्षा देने का विशेष प्रबन्ध कर लिया है। अब एशिया के कुछ देशो से भी शिक्षार्थी इस बात क शिक्षण के लिए यहां आ रहे है। भारतीय वायु सेना के विमान देश भर मे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे है और राष्ट्रपति तथा प्रधान मत्री को हवाई मार्ग से ले जाने और ले आने का कार्य भारतीय वायु सेना के जिम्मे है। इस के अतिरिक्त भारतीय वायु सेना सर्वे सम्बन्धी उड़ाने भी करती रहती है। गत वर्ष कुछ संकटापन्न व्यक्तियो को भारतीय वायु सेना के विमानो ने उक्त परिस्थितियों से बचाया था।

जेट फाइटर्स

भारतीय वायु सेना ने फ्रांस से बहुत से ओरागन या तूफानी जेट फाइटर्स भी खरीदे है, जो बहुत शक्तिशाली है। मार्च 1954 मे वायु सेना की छठी वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के निकट वायु सेना का एक बहुत बडा प्रदर्शन किया गया, जिस मे राजधानी के लगभग 3 लाख नागरिक दर्शक रूप से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर प्रधान मंत्री एक हेलीकोप्टर मे सवार हो कर गये थे।

पुरस्कार

1953 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास को भारत के सब से बडे पुरस्कारो मे से अशोक चक्र प्रथम श्रेणी भेंट किया गया।

प्रादेशिक सेना

अक्तूबर 1949 से प्रादेशिक सेना में भरती शुरू की गई। इस नागरिक सेना में ऐसा प्रत्येक भारतीय शामिल हो सकता है, जिस की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो। परन्तु फौजियो तथा टेक्निकल योग्यता के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु की सीमा 35 तक ही सीमित नही है।

वायुयान से होने वाले आक्रमणों से रक्षा तथा तटीय रक्षा के लिए यह प्रादेशिक सेना उत्तरदायी है। अन्य सैनिक कार्यों मे भी इस से सहायता ली जा सकती है। इस का मुख्य उद्देश्य यह ह कि नागरिक अपना कुछ समय निकाल कर सैनिक शिक्षण ले और अपने को देश की रक्षा के योग्य बनाये। इस प्रादेशिक सेना म भरती करने के लिए भारत को 8 भागों मे बांटा गया है। सब तरह के सैनिक कार्यों का शिक्षण इस सेना को दिया जाता है तथा शहरों और नगरो मे इस की भरती की जाती है।

प्रान्तीय यूनिटों को 30 दिन का शिक्षण दिया जाता है और नागरिक यूनिटों को कुल मिला कर 120 घंटे का। उस के बाद प्रान्तीय यूनिटो को प्रति वर्ष 2 महीनों की शिक्षा लेनी होती है और शहरी यूनिटो को प्रति वर्ष 120 घंटे की। इन सब के लिए वर्ष में कम से कम 4 दिन फौजी कैम्प में रहना आवश्यक है। प्रादेशिक सेना के सब सदस्यो को 7 वर्षों के लिए कलर्स मे अपना नाम लिखाना होता है और 8 वर्ष तक वे रिजर्व में रखे जाते है। पहले ढंग के सेवा काल को 2 वर्ष के लिए बढाया भी जा सकता है।

प्रादेशिक सेना का कार्य आशिक समय का कार्य गिना जाता है और उस के लिए भत्ता और वेतन केवल इन तीन स्थितियों में मिलता है: (1) शिक्षण काल, (2) व्यवहारिक शिक्षण काल और (3) सेना मे काम करने के दिन।

सहकारी प्रादेशिक सेना

इस सहकारी सेना का उद्देश्य भारत के सभी नागरिको को सैनिक ढग का शिक्षण देना है, ताकि उन में अच्छा नागरिक बनने के लिए उचित नियत्रण आ सके। 18 से ले कर 40 वर्ष तक के सभी भारतीय नागरिक इस सेना मे सम्मिलित हो सकते है। इस के कैम्प भी शहरी तथा देहाती इन दो भागो मे बाटे जाते है। देहाती कैम्पो मे 7 दिन का शिक्षण दिया जाता है और शहरी कैम्पो मे 14 दिन तक 3 घटे प्रतिदिन। इस सेना के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नही होता कि वे आवश्यकता पडने पर सेना मे सम्मिलित हो। सन् 1953 में इस सेना के 3 कैम्प लगाये गये वे और 1954 के पहले 3 महीनो मे लगभग 36।

राष्ट्रीय केडेट कोर

राष्ट्रीय केडेट कोर का उद्देश्य स्कूलो और कालेजो के लडके लडकियो को सैनिक शिक्षण देना है ताकि उनमे नियत्रण, नेतृत्व की शक्ति और कष्ट सहन आदि गुणो का सचार हो सके।

राष्ट्रीय केडेट कोर के 3 भाग है: उच्च विभाग, निम्न विभाग तथा लडकियो का विभाग। इन मे से पहले दोनों विभागो मे सब तरह का सैनिक शिक्षण दिया जाता है। तथा उन्हे सेना, जल सेना और वायु सेना के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जल सेना की शिक्षा का प्रबन्ध केवल उन नगरो मे है, जो समुद्र के किनारे है। जो विद्यार्थी वायु-सेना की शिक्षा लेना चाहते ह, उन्हे हवाई जहाज चलाना भी सिखाया जाता है। लडकियों के विभाग का उद्देश्य उन मे आत्मनिर्भरता की भावना भरना है। इस से उनकी शारीरिक दशा भी सुधारती है। वे इस लायक बन पाती है कि आवश्यकता पडने पर देश के लिए कठिन से कठिन काम भी कर सके।

राष्ट्रीय केडेट कोर का प्रारम्भ सन् 1948 मे किया गया था और प्रारम्भ से ही वह बहुत लोकप्रिय हो गया था। परन्तु आर्थिक सीमाओ के कारण उस का विकास यथेष्ट रूप से नही हो पाया। आजकल पचवर्षीय योजना की प्रगति के लिए भी राष्ट्रीय केडेट कोर बहुत उपयोगी कार्य कर रहे है। जहा-जहा इस कोर के विद्यार्थी गये है, वहा वहां उन्होने अपने सगठन के लिए आदर का भाव पैदा किया है। समय समय पर विभिन्न विषयो का शिक्षण देने के लिए इस कोर के कैम्प संगठित किए जाते है। इन कैम्पो मे शिक्षण के साथ साथ सदस्यों से व्यावहारिक काम भी करवाया जाता है और वे सडकें, मकान, नहरें आदि बनाने मे नागरिको की सहायता करते है।

सहायक केडेट कोर

26 अगस्त 1953 को दिल्ली राज्य के लगभग 30,500 विद्यार्थियो ने सहायक केडेट कोर नाम के एक नये आन्दोलन मे भाग लिया । इस मे 121 लडको के और 79 लड़कियो के स्कूलो के विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे । इस कोर का उद्देश्य विद्यार्थियो को नियन्त्रण तथा देश-सेवा की शिक्षा देना है । इस का सचालन प्रतिरक्षा मत्रालय के नेशनल केडेट कोर के डायरैक्टर द्वारा होता है । इस के व्यय मे विद्यार्थी भी हिस्सा बटाते हैं ।

नया पैन्शन कानून

गत वर्ष पैन्शन कानून मे कुछ सुधार किये गये, और अवसर-प्राप्त सैनिको की पैन्शने बढा दी गई । नई दरो के अनुसार एक सैनिक कैप्टेन को 350 रु० पैन्शन मिलेगी, और एक जनरल को 1,000 रु० । एक सूबेदार मेजर को 153 रु०, चीफ आर्टिफिसर को 116 रु० और मास्टर वारन्ट आफिसर को 165 । एक साधारण सिपाही को, जो 15 वर्ष सेना मे काम कर चुका हो, 15 रु० प्रति मास पैन्शन मिलेगी । यह भी निश्चय किया गया कि कल्याणवाला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सैनिको के प्रोविडेट फण्ड मे सरकारी देन $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ाकर $8\frac{1}{8}$ प्रतिशत कर दी जाये ।

भूतपूर्व सैनिक

गत वर्ष भूतपूर्व सैनिको के पुनर्वास के लिए भी सन्तोषजनक प्रयत्न किये गये । इस उद्देश्य पे भारत के विभिन्न भागो मे 9 कृषि उपनिवेश बसाने का निश्चय किया गया, जिस मे से भोपाल का कृषि उपनिवेश पूर्ण रूप से बन चुका है तथा मनुनगर (उत्तर प्रदेश) मे काम जारी है ।

आठवां अध्याय

सार्वजनिक वित्त

सविधान के अनुसार सरकार की आमदनी जमा करने का अधिकार केवल किसी एक ही सस्था या अधिकारी को नही है। यह अधिकार केन्द्रीय सरकार तथा राज्यो की सरकारो में बटा हुआ है, और उन की आय के स्रोत अलग-अलग है। इस तरह देश भर के लिए राष्ट्रीय आय का केवल एक बजट नही होता। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न स्रोतो से आय होती है और उस का व्यय एक ही व्यक्ति या अधिकारी के हाथ मे नही होता। इस तरह सरकारी परिव्यय एक बहुत गुथीली मशीन के समान है।

सविधान के अनुसार लेखा-परीक्षक सभी सरकारी व्ययो का निरीक्षण करता है, और उस पर कार्यकारी अधिकारी मडल का अधिकार नही होता। सभी राज्यो के व्यय का लेखा तथा उस की जाच पडताल की रिपोर्ट व्यवस्थापक मडल के सामने पेश की जाती है।

ससद मे तथा राज्यो की व्यवस्थापिका सभाओ मे क्रमश. भारत सरकार और राज्यो की सरकारो का बजट प्रति वर्ष अप्रैल के महीने मे पेश किया जाता है। इन सस्थाओं की अनुमति के बिना कोई व्यय नही किया जा सकता। व्यय के कुछ बधे हुए मद ऐसे हैं, जिन की स्वीकृति लिए बिना ही सरकार उन्हे व्यय कर सकती है। परन्तु पूर्व स्वीकृति के बिना इन मदो पर पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक खर्च किसी भी सूरत मे नही किया जा सकता।

राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय कमेटी ने जो जाच पडताल की थी, उस के अनुसार सन् 1950–51 में भारत की राष्ट्रीय आय 9,530 करोड रुपये थी। इस से पूर्व 1949-50 मे यह आय 9,010 करोड थी और इस से भी एक वर्ष पूर्व अर्थात् 1948–49 मे 8,650 करोड़ रही। इस तरह इन 3 वर्षों की प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार है. 1950–51 मे 265.2 रु०, 1949–50 मे 253.9 रुपये और 1948-49 मे 246.9 रुपये।

केन्द्रीय सरकार की आय और व्यय

पहले 4 वर्षों में केन्द्रीय सरकार की आय और व्यय इस प्रकार थे ·

तालिका 28

आय लेखा (क)

(करोड रुपयो मे)

	आय	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1951–52 (लेखे) . .	515.36	387.27	+128.09
1952–53 (संशोधित) .	418.64	422 43	—3.79
1953–54 (बजट) . .	437.76	438 81	+0.45

(क) ताजे से ताजे आकडो के लिए देखिए तालिका 35.

पूंजी लेखा (क)

(करोड़ रुपयों में)

	प्राप्ति	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1951-52 (लेखे) . .	169.04	293.43	—124.39
1952-53 (संशोधित) .	130.01	208.50	—78.49
1953-54 (बजट) . .	317.51	348.08	—30.57

देश विभाजन के बाद से केन्द्रीय सरकार के आय और व्यय की विस्तृत रूपरेखा तालिका संख्या 34 और 36 मे दी गई है।

राज्य सरकारों की आय और व्यय

पिछले तीन वर्षों में राज्यों की सरकारों की आय और व्यय इस प्रकार रहा :

तालिका 29

भाग 'क' के राज्य—राजस्व लेखा

(करोड रुपयो मे)

	आय	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1951-52 (लेख) . .	315.60	309.11	+6.49
1952-53 (संशोधित) .	336.96	340.06	—3.10
1953-54 (बजट) . .	350.51	362.93	—12.42

भाग 'क' के राज्य—पूंजी लेखा

(करोड रुपयों मे)

	प्राप्ति	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1951-52 (लेखे) . .	133	147	—14
1952-53 (संशोधित) .	154	157	—3
1953-54 (बजट) . .	151	161	—10

भाग 'ख' के राज्य—राजस्व लेखा

(करोड रुपयों मे)

	प्राप्ति	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1951-52 (लेखे) . .	106·70	100·53	+6·17
1952-53 (संशोधित) .	110·91	111·18	—0·27
1953-54 (बजट) .	115·29	118·62	—3·33

(क) ताज से ताजे आंकडों के लिए देखिए तालिका 35.

भाग 'ख' के राज्य—पूंजी लेखा

(करोड़ रुपयों में)

	प्राप्ति	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1951–52 (लेखे) .	32.00	43.00	—11.00
1952–53 (संशोधित) .	36.80	39.25	—3.15
1953–54 (बजट) . .	42.60	46.00	—3.40

सन 1952-53 से भाग 'ग' के राज्यों (अजमेर, भूपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश) का पृथक बजट बनने लगा, जो इस प्रकार हैं—

(हजार रुपयों में)

	आय	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1952–53 (संशोधित) .	1,35,353	1,33,241	+ 2,112
1953–54 (बजट) . .	1,55,386	1,55,243	+ 143

राज्यों की सरकारों के आय और व्यय का विस्तृत ब्यौरा तालिका संख्या 41 से तालिका संख्या 43 तक दिया गया है।

आय के स्रोतों का विभाजन

केन्द्र की आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं :

तट कर, आन्तरिक कर, कारपोरेशन कर तथा आय कर (जिस में कृषि से होने वाली आय सम्मिलित नहीं है), जायदादों तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क, टकसाल की आय। इन के अतिरिक्त रेल तथा डाक और तार विभागों से भी कुछ आय केन्द्र के सामान्य बजट में होती है। केन्द्रीय सरकार की आय का लगभग 90 प्रतिशत तट कर, आन्तरिक कर, कारपोरेशन कर तथा आय कर से आता है। जायदाद तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क 15 अक्तूबर 1953 से जारी किया गया है।

राज्यों की आय का एक स्रोत जंगल, मछली व्यवसाय, राज्यों द्वारा प्रारम्भ किये गये अपने व्यवसाय तथा केन्द्र द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता है। आय कर से केन्द्रीय सरकार को जो धन प्राप्त होता है, उसका आधे से अधिक भाग राज्यों को दे दिया जाता है। कृषि पर लगाये गये सब करों की आय पूर्णरूप से राज्यों को प्राप्त होती है। राज्यों की आय के अन्य स्रोत ये हैं : कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क, मकानों और जमीनों पर कर, खनिज कर, शराब, भंग, धतूरा आदि पर कर, बिक्री कर, बिजली से प्राप्त होने वाली आय, विज्ञापनों पर (अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों के अतिरिक्त) कर, यात्री कर, कुछ सवारियों पर कर, चुंगी, विभिन्न पेशों पर कर, व्यापार, टिकटों का शुल्क, भोग की वस्तुओं तथा मनोविनोद पर कर।

संविधान की धारा 280 के अनुसार नवम्बर 1953 मे जो वित्त आयोग (फाइनान्स कमीशन) नियुक्त हुआ था, उस की सिफारिश इस प्रकार थी : (1) आयकर मे राज्यों का हिस्सा 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 55 प्रतिशत कर दिया जाये। इस का 4/5वां भाग आबादी के आधार पर तथा शेष भाग आय कर सग्रह करने के आधार पर दिया जाये, (2) आबादी के आधार पर निम्न करों का 40 प्रतिशत राज्यो को मिले : तम्बाकू, दियासलाई, वनस्पति पदार्थ आदि पर आन्तरिक कर, (3) आसाम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बगाल के पटसन के निर्यात पर लगाये गये कर से प्राप्त होने वाली आय मे से राज्यो को अब की अपेक्षा अधिक हिस्सा दिया जाये तथा (4) जिन राज्यो को सहायता की अधिक आवश्यकता है, विशेषतः शिक्षा तथा विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को, उन्हे अब की अपेक्षा अधिक सहायता दी जाये ।

इस के अतिरिक्त भाग 'क' तथा 'ख' के राज्यो के विकास के लिए यथेष्ट पूजी केन्द्रीय सरकार कर के रूप मे देती है। भाग 'ग' के राज्यो मे पूजी का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के बजट से किया जाता है ।

करों की जांच

अप्रैल 1953 मे भारतीय करो की जाच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिस के अध्यक्ष डा० जान मथाई हे, तथा श्री बी० एल० मेहता, प्रोफेसर वी० के० आर० वी० राव, श्री के० आर० के० मेनन, श्री बी० वेंकटपैया तथा डाक्टर बी० के० मदान सदस्य हे। यह कमीशन इन बातो के सम्बन्ध मे जाच पड़ताल कर रहा है :

(1) विभिन्न राज्यो के विभिन्न व्यक्तियो पर केन्द्रीय तथा राज्यो के करो का बोझ किस तरह पडता है ?

(2) देश के विकास कार्यक्रम को ध्यान मे रख कर तथा आय और सम्पत्ति की विषमता को कम करने की दृष्टि से वर्तमान कर प्रथा कहा तक उपयुक्त है ?

(3) वर्तमान आय कर के विभिन्न दर्जों से देश की पूंजी-सग्राहकता तथा उत्पादक व्यवसायो के विकास पर कहा तक प्रभाव पडता है ?

(4) मुद्रा सकोच (डिफ्लेशन) तथा मुद्रा विस्तार (इन्फ्लेशन) की दशा मे सुधार करने के लिए करो का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है ?

(5) वर्तमान कर प्रथा की पूरी छानबीन करना और नये करो के स्रोत तलाश करना ।

केन्द्रीय व्यय

केन्द्रीय बजट मे पिछले कुछ वर्षों से घाटा इस कारण हो रहा है कि देश को अपने विकास के कार्यक्रम के लिए बहुत अधिक नई पूजी लगाने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमो का उद्देश्य न सिर्फ युद्ध और विभाजन के आर्थिक दुष्परिणामो को दूर करना है, अपितु इन का सब से बडा उद्देश्य यह है कि देश के सम्पूर्ण प्राप्त और सम्भव साधनो मे इस हद तक देश की आर्थिक उन्नति कर ली जाये कि भारत भर मे कही बेकारी न रहे। 1953-54 के पूजी बजट मे 317·51 करोड रुपये की आय थी तथा 348·08 करोड़ रुपये का व्यय। इस से पहले वर्षों मे यह मद बहुत कम हुआ करती थी। विकास सम्बन्धी इन व्ययो की विस्तृत तालिकाएं अन्यत्र दी गई हं। विकास सम्बन्धी कुछ कार्यों के लिए नये ऋण जारी कर के धन सग्रह किया जा रहा हे। अप्रैल 1954 के अन्त मे राष्ट्रीय विकास ऋण नाम से एक नया ऋण जारी किया गया,

जिसमे जून 54' के अन्त तक 120 करोड रुपये से ऊपर रुपये एकत्र हो चुके है । इस उद्देश्य से कुछ विदेशी सरकारो से भी भारत को रुपया प्राप्त हो रहा है । भारत अपने पौण्ड पावने का रुपया भी इमी काम मे लगा रहा है ।

राज्यों का व्यय

राज्यो की आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग विकास के कार्यों पर व्यय किया जा रहा है ।

आय कर तथा जायदाद शुल्क

तालिका सख्या 39 और 40 मे आय कर तथा जायदाद शुल्क की दरे दी गई है । इन मे बहुत सी छूटे भी दी जाती है । उदाहरण के लिए कृषि से प्राप्त होने वाली आय, ट्रस्टो तथा धार्मिक और दान सम्बन्धी संस्थाओ की आय, वह आय जो धार्मिक संस्थाओ को चन्दे द्वारा प्राप्त होती है, पूजी की आय, इनाम तथा वर्ग पहेली प्रतियोगिताओ मे प्राप्त होने वाली आय नौकरी छूट जाने की दशा मे प्राप्त होने वाली इकट्ठी राशि, कतिपय आय-कर मुक्त सरकारी ऋणो के सूद से प्राप्त होने वाली आय इत्यादि ।

जायदाद शुल्क के सम्बन्ध मे और भी अधिक छूटे दी गई है । यह कर केवल उसी दशा मे लगेगा, जब कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उस की जायदाद उस के उत्तराधिकारियो को मिलेगी । इस के अतिरिक्त ६ श्रेणियो की सम्पत्ति पर यह शुल्क नही लगेगा । इन के सम्बन्ध मे यह माना गया है कि यह मृत्यु के बाद हस्तान्तरित नही होती ।

राष्ट्रीय ऋण

अविभक्त भारत मे 1938-39 मे केन्द्रीय सरकार का कुल ऐसा राष्ट्रीय ऋण जिस पर सरकार सूद देती थी, 1,205·76 करोड रुपये था, जो 1945-46 मे बढ कर 2,308·48 करोड रुपये हो गया । यह वृद्धि महायुद्ध के कारण हुई, तथापि यह वृद्धि तत्कालीन सरकार की उम्मीदो तथा समय की आवश्यकताओ के अनुसार नही थी । यही कारण है कि जहा इग्लैड और अमेरिका मे युद्ध का व्यय मुख्यत आन्तरिक ऋणों से पूरा किया गया, वहा भारत मे उसका व्यय बहुत अधिक नोट छाप कर पूरा किया गया । इसी तथ्य से यह ज्ञात हो जाता है कि भारत मे जो मुद्रा विस्तार हुआ, वह इग्लैड या अमेरिका के मुद्रा विस्तार की अपेक्षा अधिक आशकाए पैदा करने वाला क्यो था ? स्वाधीन भारत मे भारतीय जनता ऋणो के सम्बन्ध मे सरकार का साथ दे रही है, और मार्च 1953 तक ऋणो से प्राप्त राशि 2,646 करोड तक पहुच गई, जब कि 1947-48 मे यह केवल 2,181 89 करोड रुपये थी । 1952-53 में छोटी बचतों से प्राप्त आय मे 45 करोड की वृद्धि हुई तथा आन्तरिक सूदवाले दातव्यों में 28 करोड रुपये की वृद्धि हुई, उधर प्लवमान (फ्लोटिंग) कर्जों में 16 करोड़ की कमी हुई । हाल ही मे राष्ट्रीय विकास ऋण नाम से जो बडा ऋण जारी किया गया है, उस का देश मे हार्दिक स्वागत किया जा रहा है । इस ऋण का जिक्र पहले भी किया जा चुका है । तालिका सख्या 44 और 45 मे इन ऋणों की सख्या दी गई है ।

अगस्त 1952 मे बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बगाल की सरकारो ने क्रमश: रु० 3½ करोड़, 50 करोड, 2 करोड़ और 2 करोड रुपयो के ऋण जारी किए । ये सब ऋण 1964 मे अदा किये जायेंगे और इन पर 4 प्रतिशत सूद मिलेगा । बम्बई और पश्चिमी बगाल

के ऋण पूरी कीमत पर जारी किये गये, जब कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रारम्भिक मूल्य 99-8-0 रु० और मद्रास मे 99-12-0 रु० था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 करोड़ का एक और ऋण भी जारी किया। ये सब ऋण बहुत शीघ्र खरीद लिये गये।

दिसम्बर 1947 के समझौते के अनुसार अविभाजित भारत के ऋणों मे भारत और पाकिस्तान के हिस्सों का भी निश्चय किया गया था। उस के अनुसार यह निश्चित हुआ था कि अविभक्त भारत के राष्ट्रीय ऋणो का पूरा जिम्मा भारत सरकार अपने पर ले ले, और पाकिस्तान सरकार अपने हिस्से का 300 करोड रुपया, 3 प्रतिशत सूद सहित, 50 वार्षिक किश्तो मे भारत को अदा करे। परन्तु अब तक पाकिस्तान सरकार ने एक भी किश्त भारत को नही दी है। इस सम्बन्ध मे बातचीत जारी है।

मुद्रा तथा बैंकिंग

युद्ध की असाधारण परिस्थितियो मे भारतीय मुद्रा का विस्तार बहुत अधिक हो गया। उस का परिणाम यह हुआ कि वस्तुओ की कीमते बहुत शीघ्रता से बढने लगी। अगस्त 1939 मे वस्तुओ के जो दाम थे, उन्हे यदि 100 माना जाय, तो 1942–43 मे वे 171 तक जा पहुचे और 1946–47 मे 275·4 तक। इस तरह जीवन व्यय बहुत बढ गया। अगस्त 1939 को आधार मान कर यह माप 1942–43 में 166 तक पहुच गया, और 1946–47 मे 252 तक।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस मुद्रा विस्तार को नियत्रण मे लाने के गम्भीर प्रयत्न किये गये। 1952–53 में बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार देश की मूल्य नियत्रण सम्बन्धी नीति मे आवश्यक परिवर्तन किये। कुछ चीजो पर से, जैसे कपडा, चीनी, अनाज आदि, यह नियत्रण या तो हटा लिया गया या ढीला कर दिया गया। दूसरी ओर अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने कच्चा लोहा, इस्पात और रबड की कीमतो को कुछ हद तक बढ जाने दिया। प्रयत्न किया गया कि चीनी, गन्ना और खाद्य पदार्थों की कीमते कम हो जाये। वर्ष के प्रथम आधे भाग मे कीमते कुछ ऊपर की ओर गईं, परन्तु पिछले आधे भाग मे कीमते गिरी।

वर्ष के पहले आधे भाग मे खाद्य पदार्थों की कीमते बढने का एक कारण यह भी था कि मार्च 1952 से भारत सरकार ने खाद्यान्नो के सम्बन्ध मे दी जाने वाली सहायता रोक दी। दूसरी ओर उन की पूर्त्ति बढाने का प्रयत्न किया गया। परिणाम यह हुआ कि कीमतो पर नियत्रण रहा काम करने वाली जमातो के जीवन व्यय का माप भारत मे 1944 को आधार मान कर, मार्च 1952 मे 135 हो गया, अक्तूबर 1952 मे वह 144 तक पहुच गया, परन्तु जनवरी 1953 मे वह 139 तक उतर आया।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के वर्षों मे मुद्रा विस्तार को रोकने के सब प्रयत्न किये गये। इस सम्बन्ध मे रिजर्व बैंक ने ये प्रयत्न किए . बैंको के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो को खुले बाजार मे साख पर रुपये देना, तथा बाजार मे विद्यमान रुपये के चलन पर नियत्रण रखना। 1949–50 म 12,52,96,00,000 रुपये बाजार मे थे और 1950-51 में 13,42,69,00,000 रुपये। 1951–52 मे यह घट कर 12,23,39,00,000 रुपये हो गये और 1952–53 मे 12,09,66,00,000 रुपये।

भारत का रिजर्व बैंक

भारत का रिजर्व बैंक केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारो का बेंकर है, और इस तरह वह देश का केन्द्रीय बैंक है, । वह राष्ट्रीय ऋणों की व्यवस्था करता है, तथा सरकारो की आय और व्यय का सचालन करता है। जहा इस बैंक की शाखाए नही है, वहा इस के एजेण्ट के रूप में भारत का इम्पीरियल बैंक, और जिलो तथा सब-डिवीजनो के खजाने यह काम करते है। रिजर्व बैंक ही भारत भर के बैंकों पर निगरानी रखता है तथा देश की मुद्रा का प्रबन्ध करता है। इस बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 मे हुई थी और 1949 मे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।

बीमा

भारत मे बीमे की क्रमश सन्तोषजनक उन्नति हो रही है। पिछले 10 वर्षों मे बीमा कम्पनियो ने जो काम किया, उस की सूची निम्नलिखित है :—

तालिका 30

(करोड रुपयों मे)

वर्ष	भारतीय बीमा कम्पनियो मे बीमा की गई राशि	अभारतीय बीमा कम्पनियो मे बीमा की गई राशि	योग
1942	36.5	6.4	42.9
1943	62.9	9.2	72.1
1944	95.2	11.0	106.2
1945	122.8	12.6	135.4
1946	131.4	12.9	144.3
1947	114.1	12.3	126.4
1948	107.7	12.0	119.7
1949	123.1	12.2	135.3
1950	118.4	13.7	132.1
1951	116.5	16.4	132.9

31 दिसम्बर 1951 को भारतीय बीमा कम्पनियो के पास 2,49,82,00 000 रुपये थे। ये रुपये निम्नलिखित प्रकार से काम मे लाये गये थे :

तालिका 31

(लाख रुपयो मे)

ब्यौरा	राशि
भारत सरकार की सिक्युरिटियां	12,160
भाग 'ख' राज्यों की सिक्युरिटिया	161
ब्रिटिश, औपनिवेशिक तथा विदेशी सरकारो की सिक्युरिटिया ..	414

ब्यौरा	राशि
म्युनिसिपल, पोर्ट ट्रस्ट तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्टो की सिक्यूरिटिया . .	1,374
रहन रखी गई सम्पत्ति	998
पालिसियों पर ऋण	1,478
स्टाक और शेयरो पर ऋण	23
अन्य ऋण	173
भारतीय कम्पनियो, सहकारी संस्थाओ आदि मे हिस्सा . . .	3,468
भूमि और मकान सम्पत्ति	1,248
एजेन्टो की बाकी, चालू प्रीमियम, ब्याज आदि	1,244
जमा, नकद और स्टाम्प	1,581
विविध	660

तालिका 32

भारतीय संघ की राष्ट्रीय आय

(अरब रुपयों में)

मद	1950-51	1949-50	1948-49
	कुल प्राप्ति	कुल प्राप्ति	कुल प्राप्ति
कृषि			
1. कृषि, पशुपालन तथा सम्बन्धित कार्य	47.8	43.8	41.6
2. जगल उद्योग	0.7	0.7	0.6
3. मछली उद्योग	0.4	0 4	0.3
योग	48.9	44.9	42.4
खनिजकार्य, कारखाने और छोटे व्यापार			
4. खनिजकार्य	0.7	0.6	0.6
5. कारखाने	5.5	5.4	5.5
6. छोटे व्यवसाय	9.1	9.0	8.7
योग	15.3	15.0	14.8
वाणिज्य, यातायात तथा संवाद परिवहन			
7. सवाद परिवहन (डाक और तार) . .	0 4	0.3	0.3
8. रेलवे	1.8	1.8	1.7
9. बैंकिग और बीमा कम्पनी	0.7	0.6	0.5
10 अन्य वाणिज्य और यातायात .	14.0	13.9	13.5
योग	16.9	16.6	16.0
अन्य कार्य			
11 व्यवसाय तथा कलात्मक कार्य . .	4.7	4.5	4.3
12. सरकारी नौकरिया (प्रशासन) .	4.3	4.1	4.0
13. घरेलू नौकरिया	1.3	1.2	1.2
14. गृह सम्पत्ति	4.1	4.0	3.9
योग	14.4	13.8	13.4
15. देश का शुद्ध उत्पादन	95 5	90.3	86.7
16. विदेशों से अर्जित शुद्ध आय	—0.2	--0.2	—0.2
17. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय आय	95 3	90.1	86.5

तालिका 33

चुने हुए देशों के थोक मूल्यो और जीवन निर्वाह के सूचक अंक

वर्ष	भारत		आस्ट्रेलिया		कनाडा		फ्रास		द० अफ्रीका मघ		ब्रिटेन		अमेरिका	
	थो	जी (ब)	थो*	जी	थो	जी	थो (पे)	जी	थो**	जी	थो	जी	थो	जी
1948 .	100	100	100	100	100	100	100	100सि	●100	100	100	100	100	100
1949 .	104	101	112	109	103	104	112	118	106	104	105	103	95	99
1950 .	109	103	132	120	109	107	121	131	113	108	120	106	99	100
1951 .	120	109	163	146	124	118	155	154	129	116	146	116	110	108
1952 .	105	111	184	170	117	121	163	171	148	126	149	126	107	110

थो—थोक मूल्य • **—खपत हुआ माल सि—सितम्बर

जी—जीवन निर्वाह

*—मेलबोर्न मे खपत हुआ माल जी—जीवन निर्वाह व्यय

(पे)—पेरिस मे खपत हुआ माल (ब)—बम्बई के मजदूरों का जीवन निर्वाह अक

तालिका 34

भारत सरकार के आय और व्यय के मुख्य मद

(करोड रुपयो में)

	1948–49-क	1949–50	1950–51-क	1951–52-क	1952–53 (संशोधित)	1953–54 (बजट)
आय						
सीमाकर	126 16	124 71	157 15	231 69	177 00	170.00
युनियन आन्तरिक कर	50 63	67 85	67 54	85.78	80 00	94 00
कारपोरेशन टैक्स	62 26	39 53	40 49	41 41	39.83	36.62
(अतिरिक्त लाभ कर)	(14 38)	(3 98)	(3 81)	(1 03)	(0.72)	(0 85)
कारपोरेशन टैक्स के अलावा आय पर कर (ख)	119 50	121 59	132 73	146.19	130 17	123 38
(अतिरिक्त लाभ कर)	(8 11)	(3 46)	(2.49)	(2 44)	(1.81)	(1.40)
						(–0.82) (ग)
मुद्रा तथा टकसाल	12 63	11 22	12 27	11.30	10.77	15 69
रिजर्व बैंक का लाभ	( )	( )	(.)	(.)	(7.50)	(12 50)
सामान्य आय को प्राप्त भाग :—						
रेल	7 34	7.00	6 50	6.93	7 68	7.65
डाक और तार	2 36	2 38	3 98	3 43	1.40	0 40
						(+1.90) (ग)
सम्पूर्ण संग्रहीत आय (ख)	361.73	357 28	404 52	512.85	429 11	425.34 (ङ)
आयकर, सम्पूर्ण करो मे होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत है (घ)	50.2	45.1	42 8	36.6	39.6	६7.6
सम्पूर्ण आय	371.70	350 39	410 66	515 36	418 64	437.76 (च) (+1.50) (ग)

व्यय						
अ.य पर मीधी माग	8 62	13 90	12 50	16 23	31 05	32 49
मिचाई	0 06	0 08	0 22	0 17	0 17	0 19
ऋण मेवाये (छ)	42 53	39 43	37 36	39 00	35 03	37 17
नागरिक प्रशासन	35 56	39 30	48.80	53 67	56.23	71 27
मुद्रा और टकमाल	2 13	2 08	2 55	2 51	3.05	2 57
नागरिक कार्य आदि	6 61	6 53	10 38	11 36	14 82	15.06
विविध	56 89	52 44	52 88	65 14	53 11	29 37
प्रतिरक्षा सेवाए (शुद्ध)	146 05	148 86	164.13	170.96	192.73	199 84
सघीय तथा राज्य सरकारो के बीच अशदान और विविध समायोजन (ज)	2 96	2 96	15 59	17 31	23 04	26.37
असाधारण मदे	19 45	11 54	7 03	10 91	13.21	24.48(झ)
आय मे मे किया गया कुल व्यय—	320 86	317 12	351.44	387.27	422 43	438 81
बचत (—) अथवा घाटा (–)	+50 84	+33 27	+59 22	+128 09	—3 79	+0.45

(क) लेखे अस्थायी है ।

(ख) इन मे राज्यो का भी भाग मम्मिलित है—1951–52 मे 52 86 करोड रुपये, 1952–53 (बजट) मे 50 84 करोड रुपये, 1952–53 (सशोधित) मे 56 82 करोड रुपये तथा 1953–54 (बजट) मे 54 90 करोड रुपये (राज्यो के अश सम्बन्धी बजट प्रस्तावो के फलस्वरूप 42 लाख रुपये) ।

(ग) बजट प्रस्ताव के फल।

(घ) कारपोरेशन टैक्स सहित ।

(ङ) बजट प्रस्ताव के परिणाम को ध्यान मे रखते हुए ।

(च) पाकिस्तान मे 1952–53 (बजट) मे 9 करोड और 1953–54 (बजट) मे 18 करोड रुपयो की प्राप्ति के लिये बजट मे की गई जमा भी इस मे मम्मिलित है ।

(छ) ऋण की कमी या बचाव के लिये निर्धारित राशि सम्मिलित है ।

(ज) राज्यो को दिये गये सहायता अनुदान मम्मिलित हैं ।

(झ) राज्यो को (1) अधिक अन्न उपजाओ योजना, (2) दैवी प्रकोपो के दिनो मे सहायता, (3) सामूहिक विकास योजनाओ, (4) औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओ तथा (5) विकास योजनाओं के लिये भाग "ख" के राज्यो को अनुदान देने की व्यवस्था सम्मिलित है ।

तालिका 35

आय लेखा

(अन्तिम अनुमान जो 27 फरवरी 1954 को ससद मे प्रस्तुत किये गये)

(करोड रुपयों में)

	आय	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1953-54 (सशोधित) . . .	413 69	430 65	—16 96
1954-55 (बजट)	452.88	467.09	—14.21

पूजी लेखा

(अन्तिम अनुमान जो 27 फरवरी 1954 को ससद मे रखे गये)

(करोड रुपयो में)

	प्राप्ति	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1953-54 (संशोधित)	285.28	318.10	—32 82
1954-55 (बजट)	433.06	406.62	+26.46

तालिका 36

भारत सरकार के आय और व्यय के मुख्य मद (1953-54 और 1954-55)

(अन्तिम प्राक्कलन जो 27 फरवरी 1954 को संसद मे रखे गये)

(लाख रुपयो में)

	सशोधित 1953-54	बजट 1954-55
आय		
सीमाकर	16,000	17,500
यूनियन आन्तरिक कर	9,355	9,260 +1,185(क)

(क) बजट प्रस्तावों का परिणाम ।

(लाख रुपयों में)

	संशोधित 1953-54	बजट 1954-55
कारपोरेशन टैक्स	3,840	3,835
कारपोरेशन टैक्स के अलावा आय पर कर .	6,931	7,067
भू सम्पत्ति कर	..	25
अफीम	207	185
ब्याज	278	278
नागरिक प्रशासन	1,034	1,048
मुद्रा और टकसाल	1,541	2,042
नागरिक कार्य	162	163
आय के अन्य स्रोत	1,069	792
डाक और तार—से प्राप्त आय . .	202	150
रेल—से प्राप्त आय	750	737
असाधारण मदें	..	1,021
सम्पूर्ण आय	41,369	44,103(क) 1,185(क)
व्यय		
आय पर सीधी माग	3,092	3,219
सिंचाई	19	16
ऋण सेवाएं	3,885	4,000
नागरिक प्रशासन	6,857	8,608
मुद्रा और टकसाल	256	263
नागरिक कार्य और विविध सार्वजनिक सुधार	1,475	1,554
पेन्शन	859	845
विविध		
शरणार्थियों पर व्यय	1,267	1,023
खाद्य सम्बन्धी सहायता	177	..
अन्य व्यय	998	974
राज्यों को अनुदान आदि	2,636	3,248
असाधारण मदें	1,576	2,397
प्रतिरक्षा सेवाएं (शुद्ध)	19,968	20,562
सम्पूर्ण व्यय	43,065	46,709
बचत (+) / घाटा (—)	—1,696	—1,421

(क) बजट प्रस्तावों के परिणाम

तालिका 37

1943 के बाद से करों से प्राप्त होने वाली आय का विश्लेषण

(लाख रुपयो मे)

वर्ष	तट कर से आय	यूनियन आन्तरिक कर से आय	संग्रह व्यय	कार्पोरेशन टैक्स सहित आय पर लगे करो से होने वाली आय	संग्रह व्यय	नमक से प्राप्ति आय	संग्रह व्यय	अन्य करो से प्राप्त आय	संग्रह व्यय	सम्पूर्ण करो से प्राप्त आय का योग	केन्द्रीय सडक कोष को हस्तातरण	बाटे जाने योग्य आन्तरिक कर मे राज्यों का भाग	सघीय सरकार द्वारा प्राप्त कर आय	संग्रह व्यय का योग	शुद्ध कर आय का योग
1943-44	2,657	2,494	219	10,964	98	834	129	166	69	17,115	92	—	17,023	515	16,508
1944-45	3,976	3,814	397	16,474	109	929	124	196	75	25,389	102	—	25,287	705	24,582
1945-46	7,361	4,637	438	14,980	128	1,020	136	216	85	28,214	60	—	28,154	787	27,367
1946-47	8,922	4,303	440	13,072	152	897	201	252	98	27,446	142	—	27,304	891	26,413
1947-48	7,274	2,438	144	7,811	95	80	104	147	52	17,750	87	—	17,663	395	17,268
1948-49	12,616	5,063	407	13,998	182	—	—	319	148	31,996	268	—	31,728	737	30,991
1949-50	12,471	6,785	815	11,537	201	—	—	360	155	31,153	220	—	30,933	1,171	29,762
1950-51	15,715	6,754	591	12,571	244	—	—	661	190	35,701	340	—	35,361	1,025	34,336
1951-52	23,169	8,578	835	13,474	270	—	—	778	183	45,999	340	—	45,659	1,288	44,371
1952-53 (संशोधित)	17,700	8,000	739	11,318	315	—	—	211	141	37,229	520	1,642	35,067	1,195	33,872
1953-54 (बजट)	17,000	9,400	704	10.470	341	—	—	216	145	37,086	460	1,649	34,977	1,190	33,787

तालिका 38

भारत सरकार का पूंजी बजट

(करोड़ रुपयो मे)

	1950–51 (क)	1951–52 (क)	1952–53 संशोधित	1953-54 बजट
प्राप्तियां				
नये ऋण	38.09	111.30	35 79	100.79
ट्रेजरी बिल (ख) . .	16 10	—43 69	4 69	110 00
ट्रेजरी डिपोजिट से प्राप्ति (ख)	—7.13	11.47	—18 03	—0.15
ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टीफिकेट (ख) . .	5 47	13 10	8 00	9.00
छोटी बचतें (ख) . .	28.05	25 38	35.98	35 93
अन्य ऋण जिन के लिए कोई निधि न हो (ख) .	8.30	10.16	10 37	10.74
रेल कोष (ख) .	17 55	20.04	—11 78	—10.09
अन्य सुरक्षित कोष (ख) .	0 16	0 26	—0.45	—0.71
ऋण की कमी या बचत के लिए व्यवस्था (ख) .	5.00	5 00	5 00	5.00
अतिरिक्त लाभकर तथा आय-कर सम्बन्धी जमा (ख)	—33.21	—39.27	—32·94	—10 92
राज्यो द्वारा ऋणो का भुगतान दिया जाना	8 08	12 22	16.55	17 57
विशेष विकास कोष (ग) .	——	51 02	40 22	29.72
आकस्मिकता कोष .	15 00	——	——	——
अन्य मदे . . .	19.09	—7.95	36 61	20 63
सम्पूर्ण प्राप्तियां .	120 55	169 04	130 01	317 51

(शेष पृष्ठ 120 पर)

(क) लेखे अस्थायी है

(ख) आंकडे शुद्ध है

(ग) (1) अमेरिकी (ऋण) गेहूं और (2) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं की बिक्री के रूप मे तथा—(1) कोलम्बो योजना और (2) भारत-अमेरिकी टेकनिकल कोआपरेशन एग्रीमेंट के अन्तर्गत सहायता के रूप मे विशेष विकास कोष मे प्राप्ति ।

(करोड़ रुपयो में)

	1950-51 (क)	1951-52 (क)	1952-53 सशोधित	1953-54 बजट
व्यय				
पूजीगत व्यय—				
रेल	25.41	23.21	14.12	18.97
नागरिक कार्य . . .	7 72	10 15	15 93	17.81
प्रतिरक्षा पूजीगत व्यय .	4.19	10.17	8.71	15.00
डाक और तार . . .	7.07	4 96	5.39	7 60
औद्योगिक विकास .	8 90	8 34	1.95	6.75
बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाए	2 50	3 77	4 15	3.80
सरकारी व्यापार की योजनाए	—2 26	12 63	—0 20	3.52
नागरिक उड्डयन . . .	1 82	1.51	1.77	2.32
बन्दरगाह	0 70	0 90	2.13	3.25
पौण्ड पशेन . . .	—7 37	—7.31	—7.26	—7.16
विशेष विकास कोष (ख)	——	46 97	26 57	——
अन्य मदे . .	22 35	2 88	2.60	4.78
सम्पूर्ण पूजी व्यय .	71 03	118 18	75.86	76.64
स्थायी ऋण का चुकता किया जाना . . .	45 85	87.94	6 19	119.62
राज्यो को पेशगी . .	61.46	60.77	90 00	93.75
विशेष विकास कोष मे से राज्यो को पेशगी . . .	——	14.94	27.12	37.45
अन्य ऋण और पेशगी (ग).	4 25	11.60	9.33	20.62
सम्पूर्ण व्यय . . .	182.59	293.43	208.50	348 08
पूजी लेखा मे घाटा.	62 04	124.39	78.49	30 57

तालिका 39

आयकर और सुपरटैक्स की दरे

व्यक्तियो, फर्मों, हिन्दू सयुक्त परिवारों तथा अन्य जनसस्थाओ के सम्बन्ध मे

आयकर	दरे	सर्चार्ज
(1) सम्पूर्ण आय के प्रथम 1,500 रुपयो पर	कुछ नही	कुछ नही
(2) ” ” ” अगले 3,500 ” ”	9 पाई प्रति रुपया	पिछले खाने मे निर्दिष्ट दर का $\frac{1}{20}$
(3) ” ” ” 5,000 ” ”	एक आना 9 पाई	”
(4) ” ” ” 5,000 ” ”	तीन आना प्रति रुपया	”
(5) शेष आय पर	चार आना प्रति रुपया	”

नोट :— 7,200 रुपये या इस से कम की सम्पूर्ण आय पर सर्चार्ज नही लगता।

(क) लेखे अस्थायी है। (ख) अमेरिकी (ऋण) गेहूं की बिक्री से प्राप्त धन का हस्तांतरण।
(ग) आंकड़े शुद्ध है।

सुपरटैक्स	दरें	सर्चार्ज
(1) सम्पूर्ण आय के प्रथम 25,000 रुपयो पर	कुछ नही	कुछ नही
(2) " " अगले 15,000 " "	तीन आना प्रति रुपया	पिछले खाने मे निर्दिष्ट दर का $\frac{1}{20}$
(3) " " " 15,000 " "	चार आना " "	" " "
(4) " " " 15,000 " "	छः आना " "	" " "
(5) " " " 15,000 " "	सात आना " "	" " "
(6) " " " 15,000 " "	साढे सात आना" "	" " "
(7) " " " 50,000 " "	आठ आना " "	" " "
(8) शेष सम्पूर्ण आय अर्थात् डेढ लाख रुपये से ऊपर	साढे आठ आना " "	" " "

तालिका 40

भूसम्पत्ति कर की दरे

भाग 1

ऐसी सम्पत्ति जिस पर मिताक्षरा, मरुमक्कत्तायम अथवा अलियासन्तान कानून द्वारा प्रशासित सम्मिलित हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पत्ति सम्मिलित है :

कर की दर :

(1) भूसम्पत्ति के मूल्य के प्रथम	50,000 रुपयो पर	कुछ नही
(2) " " " अगले	50,000 " " . . .	5 प्रतिशत
(3) " " " "	50,000 " " . . .	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(4) " " " "	50,000 " " . .	10 प्रतिशत
(5) " " " "	1,00,000 " " . . .	$12\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(6) " " " "	2,00,000 " " . .	15 प्रतिशत
(7) " " " "	5,00,000 " " . . .	20 प्रतिशत
(8) " " " "	10,00,000 " " . . .	25 "
(9) " " " "	10,00,000 " " . . .	30 "
(10) " " " "	20,00,000 " " . . .	35 "
(11) " " " "	शेष भाग पर . . .	40 "

भाग 2

अन्य किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कर की दर:

(1) भूसम्पत्ति के मूल्य के प्रथम	1,00,000 रुपयों पर . .	कुछ नही
(2) " " " अगले	50,000 " " . .	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(3) " " " "	50,000 " " . . .	10 प्रतिशत
(4) " " " "	1,00,000 " " . . .	$12\frac{1}{2}$ प्रतिशत

(5)	भूसम्पत्ति के मूल्य के अगले	2,00,000 रुपयों पर . .	15	प्रतिशत
(6)	,, ,, ,, ,,	5,00,000 ,, ,, . .	20	,,
(7)	,, ,, ,, ,,	10,00,000 ,, ,, . .	25	,,
(8)	,, ,, ,, ,,	10,00,000 ,, ,, . .	30	,,
(9)	,, ,, ,, ,,	20,00,000 ,, ,, . .	35	,,
(10)	,, ,, ,, ,,	शेष भाग पर . .	40	,,

भाग 3

ऐसी कम्पनी के किसी मृत सदस्य के हिस्सो के सम्बन्ध में जिस की स्थापना भारत से बाहर हुई हो और जो उस क्षेत्र मे कारोबार करती हो, जिस मे कानून लागू होता हो :

		कर की दर :
(1)	यदि हिस्से 5,000 रुपये के मूल्य से अधिक के नही हों . . .	कुछ नहीं
(2)	यदि हिस्से 5,000 रुपये से अधिक के हो	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत

तालिका 41

भाग "क" के राज्यों की बजट सम्बन्धी स्थिति

(लाख रुपयो मे)

राज्य	आय: आयकर	आय: लगान	आय: विक्रय कर	आय: प्रान्तरिक कर	आय: स्टाम्प	आय: करों मे होने वाली अन्य आय	आय: करो मे प्राप्त कुल आय	आय: करो के अलावा (क) अन्य आय	आय: सम्पूर्ण आय	व्यय: आय पर सीधी मागे	व्यय: ऋण सेवाए (ख)	व्यय: नागरिक प्रशासन (ग)	व्यय: नागरिक कार्य	व्यय: नागरिक कार्यों के (घ) अलावा विकास व्यय	व्यय: सम्पूर्ण व्यय	बचत (+) घाटा (—)
आसाम																
1951–52 (लेखे)	248	181	76	121	29	76	731	398	1,129	97	9	232	204	358	1.093	+36
1952–53 (सशोधित)	235	172	81	148	27	72	735	537	1,272	103	8	206	349	408	1,268	+4
1953–54 (बजट)	190	166	71	158	28	72	685	616	1,301	121	12	224	385	544	1,497	—196
बिहार																
1951–52 (लेखे)	710	145	409	519	224	142	2,149	1,281	3,430	176	—9	894	650	1,284	3,282	+148
1952–53 (संशोधित)	636	350	321	653	197	156	2,313	1,264	3,577	283	23	815	530	1,242	1,136	+441
1953–54 (बजट)	608	331	270	655	207	173	2,244	1,056	3,300	337	27	820	574	1,329	3,334	—34

(जारी)

(क) अनुदान, असाधारण मदें, सुपरएनुएशन, रेविन्यु रिजर्व से प्राप्त राशि सहित ।
(ख) ऋण की बचत या कमी की व्यवस्था सहित ।
(ग) सामान्य प्रशासन, न्याय का प्रशासन, जेल और कैदियो की बस्तिया तथा विविध विभाग (विकास सबधी शीर्षकों को छोड कर) सहित।
(घ) वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, चिकित्सा सबधी और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग, ग्राम विकास, श्रम कल्याण, उडडयन, प्रसार, विद्युत योजनाये तथा सामूहिक विकास योजनाओ सहित ।

राज्य	आयकर	लगान	विक्रय कर	आन्तरिक कर	स्टाम्प	करों से होने वाली अन्य आय	करों से प्राप्त कुल आय	करों के अलावा (क) अन्य आय	सम्पूर्ण आय	आय पर सीधी मांगें	ऋण सेवाएं (ख)	नागरिक प्रशासन (ग)	नागरिक कार्य	नागरिक कार्यों के (घ) अलावा विकास व्यय	सम्पूर्ण व्यय	बचत (+) घाटा (—)
बम्बई																
1951-52 (लेखे)	1,099	614	1,188	92	414	1,048	4,455	1,815	6,270	543	188	2,007	300	2,578	6,258	+ 12
1952-53 (सशोधित)	1,067	626	1,060	279	412	1,087	4,531	1,903	6,434	659	209	2,025	412	2,860	6,824	—390
1953-54 (बजट)	1,031	667	1,400	295	420	1,107	4,920	1,864	6,784	711	238	1,967	525	2,753	6,776	+8
मध्यप्रदेश																
951-52 (लेखे)	314	439	232	256	107	147	1,495	865	2,360	247	41	508	244	600	1,822	+538
952-53 (सशोधित)	319	504	225	339	103	149	1,639	751	2,390	264	87	513	311	741	2,120	+270
1953-54 (बजट)	308	544	212	339	103	151	1,657	849	2,506	299	79	592	331	922	2,453	+ 53
मद्रास																
1951-52 (लेखे)	915	657	1,559	41	454	863	4,489	1,454	5,943	594	—86	1,793	763	2,934	6,444	—501
1952-53 (सशोधित)	926	739	1,400	327	498	920	4,810	1,526	6,336	595	—53	1,717	890	3,351	6,875	—539
1953-54 (बजट)	895	736	1,400	332	548	1,008	4,919	1,656	6,575	614	—88	1,703	602	3,349	6,575	—
उड़ीसा																
1951-52 (लेखे)	170	103	111	200	69	44	697	499	1,196	85	34	303	174	433	1,086	+110
1952-53 (सशोधित)	222	114	100	256	76	46	814	546	1,360	109	23	319	189	522	1,240	+120
1953-54 (बजट)	215	119	100	232	78	46	790	567	1,357	128	35	338	260	588	1,446	--89
पंजाब																
1951-52 (लेखे)	288	198	168	278	59	106	1,097	720	1,817	147	58	511	139	545	1,645	+ 172
1952-53 (सशोधित)	195	202	167	298	58	121	1,041	815	1,856	172	—11	528	147	576	1,689	+167
1953-54 (बजट)	189	232	178	295	58	154	1,106	868	1,974	218	12	531	220	722	2,005	—31
उत्तर प्रदेश																
1951-52 (लेखे)	1,042	758	480	632	234	527	3,673	1,883ङ	5,556ङ	547	142	1,495	321	1,949	5,550ङ	+6
1952-53 (सशोधित)	1,026	1,373	475	889	238	477	4,478	2,163ङ	6,641ङ	592	196	1,652	395	2,237	6,641ङ	—
1953-54 (बजट)	972	1,852	524	871	255	613	5,087	2,351ङ	7,438ङ	661	690	1,680	438	2,420	7,880ङ	—442
पश्चिम बंगाल																
1951-52 (लेखे)	770	210	562	672	293	528	3,035	824	3,859	189	18	1,044	402	1,251	3,731	+128
1952-53 (सशोधित)	747	210	558	699	287	560	3,061	769	3,830	189	34	1,086	455	1,512	4,213	—383
1953-54 (बजट)	727	210	558	687	287	560	3,029	787	3,816	202	52	1,094	511	1,548	4,327	—511
योग																
1951-52 (लेखे)	5,556	3,305	4,785	2,811	1,883	3,481	21,821	9,739	31,560	2,623	395	8,787	3,197	11,932	30,911	+649
1952-53 (सशोधित)	5,373	4,290	4,387	3,888	1,896	3,588	23,422	10,274	33,696	2,966	516	8,861	3,677	13,449	34,006	—310
1953-54 (बजट)	5,135	4,857	4,713	3,864	1,984	3,884	24,437	10,614	35,051	3,291	1,057	8,949	3,846	14,175	36,293	-1,242

(क) अनुदान, असाधारण मदे, सुपरएनुएशन, रेविन्यु रिजर्व से प्राप्त राशि सहित ।

(ख) ऋण की बचत या कमी की व्यवस्था सहित ।

(ग) सामान्य प्रशासन, न्याय का प्रशासन, जेल और कैदियो की बस्तियां तथा विविध विभाग (विकास सम्बन्धी शीर्षकों को छोड कर) सहित ।

(घ) वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, चिकित्सा सम्बन्धी और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग, ग्राम विकास, श्रम कल्याण, उड्डयन, प्रसार, विद्युत योजनाये तथा सामूहिक विकास योजनाओं सहित ।

(ङ) आय और व्यय में राज्य की यातायात सम्बन्धी सेवाओं की सब प्राप्तियां तथा व्यय सम्मिलित हैं ।

तालिका 42

भाग 'ख' के राज्यो की बजट सम्बन्धी स्थिति

(लाख रुपयो मे)

राज्य	आय: अन्तर्राज्यीय पारगमन कर	आय: आय कर	आय: लागत	आय: विक्रय कर	आय: प्रान्तीय कर	आय: स्टाम्प	आय: करो मे अन्य आय	आय: करो से सम्पूर्ण आय	आय: अन्य स्रोतों मे आय (क)	आय: सम्पूर्ण आय	व्यय: आय पर सीधी मागे	व्यय: ऋण सेवाये (ख)	व्यय: नागरिक प्रशासन (ग)	व्यय: नागरिक कार्य	व्यय: नागरिक कार्यों के अलावा विकास, व्यय (घ)	व्यय: सम्पूर्ण व्यय	बचत (+) घाटा (—)
हैदराबाद																	
1951-52 (लेखे)	403	10	482	106	1,016	51	22	2,090	897	2,987	306	215	901	152	836	2,819	+168
1952-53 (सशोधित)	223	254	492	193	1,036	51	36	2,285	506	2,791	332	271	654	178	818	2,682	+109
1953-54 (बजट)	171	245	502	197	1,038	51	54	2,258	544	2,802	322	322	554	203	892	2,822	—20
मध्य भारत																	
1951-52 (लेखे)	127	6	253	91	185	41	17	720	429	1,149	102	-	366	102	407	1,131	+18
1952-53 (सशोधित)	100	96	341	108	199	39	17	900	401	1,301	109	5	316	136	467	1,273	+28
1953-54 (बजट)	85	93	346	138	220	40	18	940	490	1,430	116	3	300	164	570	1,449	—19
मैसूर																	
1951-52 (लेखे)	-	-	131	137	207	46	109	630	1,201	1,831	91	128	212	213	1,040	1,835	—4
1952-53 (सशोधित)	-	-	134	121	177	47	113	592	1,375	1,967	93	132	241	246	1,177	2,021	—54
1953-54 (बजट)	-	-	121	98	172	48	115	554	1,508	2,062	100	129	242	237	1,379	2,220	—158
पेप्सू																	
1951-52 (लेखे)	-	15	90	46	235	19	40	445	164	609	48	-	164	67	126	466	+143
1952-53 (सशोधित)	-	40	100	45	186	19	37	427	198	625	73	1	172	72	184	579	+46
1953-54 (बजट)	-	40	131	45	176	20	36	448	187	635	83	41	174	114	239	704	—69
राजस्थान																	
1951-52 (लेखे)	419	13	315	—	299	47	30	1,123	428	1,551	203	20	517	88	522	1,576	—25
1952-53 (सशोधित)	351	192	380	—	323	53	34	1,333	417	1,750	238	7	524	125	645	1,714	+36
1953-54 (बजट)	349	200	425	—	348	54	39	1,415	529	1,944	263	25	552	169	767	1,944	—
सौराष्ट्र																	
1951-52 (लेखे)	40	—	152	16	17	23	43	291	461	752	57	2	259	91	329	863	—111
1952-53 (सशोधित)	14	—	280	16	10	21	36	377	607	984	142	13	247	130	520	1,166	—182
1953-54 (बजट)	11	—	279	58	9	22	38	417	525	942	127	10	209	147	419	995	—53
तिरुवांकुर-कोचीन																	
1951-52 (लेखे)	--	99	71	244	240	89	127	870	921	1,791	125	88	180	182	523	1,363	+428
1952 53 (सशोधित)	--	85	72	227	260	90	106	840	833	1,673	136	53	196	220	669	1,683	—10
1953-54 (बजट)	--	75	87	212	240	90	107	811	903	1,714	142	5	221	244	778	1,728	—14
योग																	
1951-52 (लेखे)	989	143	1,494	640	2,199	316	388	6,169	4,501	10,670	932	453	2,599	895	3,783	10,053	+617
1952-53 (सशोधित)	688	667	1,799	710	2,191	320	379	6,754	4,337	11,091	1,123	482	2,350	1,107	4,480	11,118	—27
1953-54 (बजट)	616	653	1,891	748	2,203	325	407	6,843	4,686	11,529	1,153	535	2,252	1,278	5,044	11,862	—333

(क) अनुदान, असाधारण मदे, सुपरएनुएशन, रविन्यू रिज़र्व से प्राप्त राशि समेत ।

(ख) ऋण की वचन या कमी की व्यवस्था सहित ।

(ग) सामान्य प्रशासन, न्याय का प्रशासन, जेल और कैदियो की बस्तियां, पुलिस तथा विविध विभाग सहित ।

(घ) वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग धधे, ग्राम विकास, श्रम कल्याण उड्डयन, प्रसार, विद्युत योजनाए तथा सामूहिक विकास योजनाए सहित ।

तालिका 43

भाग 'ग' के राज्यों की बजट सम्बन्धी स्थिति (क)

(हजार रुपयों में)

राज्य	आय: लगान	आय: राज्यीय प्रान्तरिक कर	आय: स्टाम्प	आय: बिक्रय कर	आय: करों से अन्य आय	आय: करों से सम्पूर्ण आय	आय: अन्य स्रोतों से आय	आय: सम्पूर्ण आय	व्यय: आय पर सीधी माग	व्यय: नागरिक प्रशासन (ख)	व्यय: नागरिक कार्य	व्यय: नागरिक कार्यों को छोड़ कर विकास व्यय (ग)	व्यय: सम्पूर्ण व्यय	बचत (+) घाटा (—)
अजमेर														
1952-53 (संशोधित)	299	3,272	412	—	70	4,053	18,576	22,629	971	4,299	860	16,068	22,269	+360
1953-54 (बजट)	335	2,777	433	1,000	395	4,940	13,936	18,876	1,191	4,385	1,651	11,451	18,876	—
भोपाल														
1952-53 (संशोधित)	4,179	1,500	264	—	418	6,361	14,311	20,672	1,565	4,883	3,681	9,047	20,232	+440
1953-54 (बजट)	4,328	1,561	274	—	441	6,604	16,700	23,30	1,690	4,526	4,384	11,938	23,259	+45
दिल्ली														
1952-53 (संशोधित)	622	6,892	4,030	10,500	4,735	26,769	9,484	36,253	2,455	4,819	2,056	26,793	36,253	0
1953-54 (बजट)	648	7,562	4,030	12,500	5,453	30,193	12,370	42,563	2,668	5,142	2,860	31,394	42,563	0
हिमाचल प्रदेश														
1952-53 (संशोधित)	1,941	1,499	349	—	219	4,008	19,961	23,969	4,371	4,206	3,717	10,306	23,694	+275
1953-54 (बजट)	1,916	1,653	440	—	209	4,218	22,465	26,683	3,768	4,606	4,766	12,414	26,596	+87
विन्ध्य प्रदेश														
1952-53 (संशोधित)	8,147	3,360	530	1,600	550	14,187	17,643	31,830	4,034	8,367	4,800	12,184	30,793	+1,037
1953-54 (बजट)	8,251	3,000	530	1,796	1,033	14,610	29,350	43,960	5,591	10,399	7,221	19,165	43,949	+11
योग														
1952-53 (संशोधित)	15,188	16,523	5,585	12,100	5,982	55,378	79,975	1,35,353	13,396	26,774	15,114	74,398	1,33,241	+2,112
1953-54 (बजट)	15,478	16,553	5,707	15,296	7,531	60,565	94,821	1,55,386	14,908	29,058	20,882	86,362	1,55,243	+143

(क) कुर्ग को छोड़ कर। (ख) सामान्य प्रशासन, न्यायप्रशासन, जेल और कैदियों की बस्तियां तथा विविध विभागों के समेत। (ग) शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि पशु-चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग और पूर्ति सहित।

13 M of I & B.

तालिका 144

भारत सरकार के ऋण (जिन पर ब्याज देना होगा) और सम्पत्तियां (जिन पर ब्याज मिलेगा)

(लाख रुपयों में)

	1938-39	1946-47 संशोधित	1947-48 संशोधित	1948-49 संशोधित	1949-50 संशोधित	1950-51 संशोधित	1951-52 संशोधित	1952-53 संशोधित	1953-54 बजट
I ऋण जिन पर ब्याज देना होगा									
भारत मे :									
1 ऋण .	43,787	1,52,975	1,51,709	1,47,839	1,45,215	1,43,846	1,40,210	1,40,558	1,38,958
2 ट्रेजरी बिल, पेशगी तथा ट्रेजरी डिपाजिट की प्राप्तिया .	4,630	7,920	8,684	37,333	36,148	37,320	33,501	31,919	42,904
3 छोटी बचत .	14,145	27,320	23,310	27,173	29,380	32,625	37,257	41,764	46,257
4 मूल्य ह्रास और सरक्षित कोष	2,734	14,397	11,215	11,677	12,615	15,556	17,147	17,018	15,940
5 अन्य .	8,368	29,703	18,341	17,274	22,275	20,726	19,302	18,914	19,413
योग	73,664	2,32,315	2,13 259	2,41,296	2,45,633	2,50,073	2,47,417	2,50,173	2,63,462
इंग्लैण्ड में									
6 ऋण	39,650	1 222	580	339	273	135	124	120	115
7 अन्य	7,262	4 652	4,360	3,945	3,710	3,482	3,224	2,903	2,784
योग .	46,912	5,874	4 940	4,284	3,983	3,617	3,348	3,023	2,899
8 डालर ऋण .	—	—	—	—	1,677	2,460	11,204	11,374	11,276
ऋणो का योग (जिन पर ब्याज देना होगा)	1 20,576	2 38,189	2 18,199	2,45,580	2,51,293	2,56,150	2,61,969	2,64,570	2,77,637
II ब्याज देने वाली सम्पत्ति (एसेट)									
9 रेल को दी गई पूजी	72,524	80,816	67,587	69,247	72,380	81,413	83,363	86,423	88,320
10 अन्य वाणिज्य विभागो को दी गई पूजी	2,742	4,863	4,386	4,885	6,897	9,011	11,295	8,125	9,034
11 राज्यो को पेशगी दी गई पूजी और अन्य ऋण जिन पर ब्याज मिलेगा	14,399	7,378	7,315	11,044	15,892	21,697	28,432	37,747	47,379
12 बर्मा और पाकिस्तान से प्राप्तव्य ऋण	4,973	4 815	34,815	34,815	34,815	34,815	34,815	34,815	34,815
13 रेल एन्यूटी के लिये ब्रिटिश सरकार के पास जमा	—	2,244	1,965	1,553	1,329	1,096	853	544	433
14 स्टर्लिंग पेंशनो के लिए एन्यूटियो की खरीद . . .	—	—	—	21,568	20,826	20,089	19,358	18,632	17,916
15 कुल सम्पत्तियो का योग जिन पर ब्याज मिलेगा .	94,638	1,00,116	1,16 068	1,43,112	1,52,139	1,68,121	1,78,116	1,86,286	1,97,897
16 नकद और ट्रेजरी एकाउन्ट् मे जमा सिक्युरिटिया . . .	3,030	51 376	24 612	23,581	17,299	14,197	19,870	13,618	10,653
17 ब्याज देने वाले ऐसे अन्य बाकी ऋण, जो ऊपर नही आये	22,908	86,697	77,519	78,887	81,855	73,832	63,983	64,466	68,887

तालिका 45

(रुपया ऋण) भारत सरकार की ऋण सम्बन्धी स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

मार्च के अन्त में	बिना तारीख	कुल का प्रतिशत	10 वर्षों के ऊपर	कुल का प्रतिशत	5 से 10 वर्षों तक के	कुल का प्रतिशत	5 वर्ष से कम के	कुल का प्रतिशत	ट्रेजरी बिल	कुल का प्रतिशत	छोटी बचतें (क)	कुल का प्रतिशत	अन्य ऋण (ख)	कुल का प्रतिशत	कुल	प्रतिशत वृद्धि (+) घटी (−)	विदेशी ऋण (ग)
1939	128.46	18.1	113.80	16.0	124.71	17.6	70.89	9.9	46.30	6.5	141.45	19.8	84.34	11.8	709.96	+2.4	469.10
1945	284.03	18.1	396.17	25.2	282.44	18.0	249.50	15.9	86.71	5.5	159.18	10.1	113.39	7.2	1,571.42	+17.0	38.13
1946	284.04	14.7	663.80	34.3	222.75	11.5	321.59	16.6	83.33	4.3	221.52	11.4	139.92	7.2	1,936.95	+23.3	37.69
1947	257.47	12.1	752.62	35.5	171.09	8.1	343.18	16.2	77.59	3.6	263.30	12.6	251.68	11.9	2,121.93	+9.6	36.52
1948(घ)	257.74	12.1	682.42	31.9	[illegible]	13.3	287.23	13.4	98.68	4.6	283.90(च)	13.3	244.42	11.4	2,140.01	+0.9	29.83
1949(घ)	257.85	10.8	711.59	29.9	196.90	8.3	309.80	13.0	354.36(ङ)	14.9	313.27(च)	13.2	234.34	9.9	2,378.11	+11.1	27.36
1950(घ)	257.86	10.5	597.93	24.3	303.08	12.3	291.08	11.8	355.70(ङ)	14.4	339.15(च)	13.8	317.91	12.9	2,462.71	+3.6	43.38(छ)
1951(घ)	257.85	10.4	519.33	21.0	342.51	13.9	318.77	12.9	364.72(ङ)	14.8	326.25	13.2	342.81	13.9	2,472.24	+2.3	49.81(छ)
1952(घ)	257.85	10.5	463.47	18.8	450.14	18.3	232.05	9.4	332.51(ङ)	13.5	372.57	15.2	351.24	14.3	2,459.83	−0.9	136.99(छ)
1953(घ)	257.85	10.3	387.60	15.6	411.67	16.5	346.46	13.9	315.44(ङ)	12.7	411.78	16.5	361.82	14.5	2,492.62	+0.6	138.53(छ)

(क) 1950–51 से दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट सहित ।

(ख) इसमें सम्मिलित है—(1) पुराने बाकी ऋण जिन्हें मांगा नहीं गया और जिन पर अब ब्याज नहीं दिया जाता, (2) विशेष ऋणों का बाकी, (3) स्टेट प्राविडेंट फंड, पेंशन फंड और अन्य फंडों का शेष, जैसे जनरल फैमिली पेंशन फंड, हिन्दू फैमिली एन्युटी फंड, पोस्टल इंश्योरेंस और लाइफ एन्युटी फंड आदि तथा (4) तीन वर्षीय ब्याज मुक्त बोंड और पंचवर्षीय ब्याज मुक्त इनाम बौण्ड ।

(ग) इसमें मार्च 1949 के अन्त तक केवल स्टर्लिंग ऋण था, 1942–43 से रेल एन्युटी शामिल नहीं थी पर उस के बाद से डालर ऋण शामिल थे ।

(घ) प्रारम्भिक ।

(ङ) ट्रेजरी डिपाजिट की रसीदों समेत ।

(च) 14 अगस्त, 1947 के दिन तक का पाकिस्तान का ऋण भी सम्मिलित है ।

(छ) मार्च 1950, 1951, 1952 तथा 1953 के अन्त में के क्रमश: 16.77 करोड़, 24.60 करोड़, 112.04 करोड़ और 113.74 करोड़ डालर ऋण भी सम्मिलित हैं ।

तालिका 46

मुद्रा परिचलन

(लाख रुपयों में)

	परिचलन (क)			परिचलन में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) (ख)			
	नोट (ग)	रुपया के सिक्के (घ)	दोनों का योग	नोट (ङ)	रुपयों के सिक्के	छोटे सिक्के	वृद्धि का योग
अविभक्त भारत							
1938–39	17,836	—	—	+7	—1,339	+7	—1,325
1945–46	1,21,877	16,573	1,38,450	+13,389	+1,835	+998	+16,222
1946–47	1,24,203	16,767	1,40,970	+2,326	+194	+591	+3,111
1947–48	1,30,436	15,533	1,45,969	+6,233	—1,234	+398	+5,397
भारतीय यूनियन							
1948–49	—	—	—	—784	—431	+24	—1,191
1949–50	1,12,035	13,261	1,25,296	—584	+178	—216	—622
1950–51	1,20,424	13,845	1,34,269	+8,389	+584	—320	+8,653
1951–52	1,09,794	12,545	1,22,339	—10,021	—1,300	—305	—11,626
1952–53	1,08,995	11,971	1,20,966	—799	—574	—409	—1,782

(क) समय के अन्त में ।

(ख) आकड़ों को तैयार करते समय बाहर से आई और बाहर गई मुद्रा का समायोजन नही किया गया। उदाहरण के लिये, यह विदित है कि 1951–52 मे और 1952–53 मे मध्यपूर्वीय देशों से भारतीय मुद्रा काफी मात्रा मे वापस आई। 27 जनवरी, 1950 से हैदराबाद में भारतीय मुद्रा के जारी किये जाने के सम्बन्ध में कोई समायोजन यहा नही किया गया।

(ग) मार्च 1950 से परिचलन मे रहे नोट सम्बन्धी आकड़े संशोधित किये जा चुके हैं और इन आकड़ो में 43 करोड़ के वे नोट शामिल नही हैं, जो पाकिस्तान से वापस आए और यहा चालू नही किए गए।

(घ) ऐसा मान लिया गया हैं कि मार्च 1948 के अन्त मे (जब से पाकिस्तान मे परिचलित भारतीय रुपये के सिक्कों की वापसी आरम्भ हुई) भारतीय सघ के मुद्रा परिचलन में रुपये के सिक्के 135.14 करोड़ थे और यह सख्या नोटों की भांति मार्च 1948 के अन्त मे अखडित भारत में परिचलित कुल रुपयों (सिक्कों) को 87 प्रतिशत थी। ऐसा इसलिए मान लेना पड़ा कि पाकिस्तान में परिचलन के सभी भारतीय सिक्के पाकिस्तान (मुद्रा प्रणाली और रिजर्व बैंक) के आदेश 1947 (सशोधित) के भाग 4 की धारा 3 के अनुसार, भारत को वापस लौटाये जाने वाले नहीं थे।

(ङ) अक्तूबर 1951 से फरवरी 1952 तक के आकड़ों को तैयार किये जाते समय अदन से वापस आये भारतीय नोटों का समायोजन कर लिया गया था।

तालिका 47

शेड्यूल्ड बैंकों की कुल मिलाकर स्थिति (बरमा को छोड़ कर)

(लाख रुपयों में)

शुक्रवार के आंकड़ों की औसत	अवधि के अन्त में बैंकों की संख्या	ऐसे ऋण जो मांग पर चुकाये जाने चाहिये	(6) के साथ (2) का प्रतिशत	निश्चित समय के ऋण	सेविंग्स डिपाजिट (क)	कुल ऋण (2) और (4) का योग	बैंको के बीच ऋणों का लेन देन (ग): मांग वाले ऋण	समय वाले ऋण	योग	कुल ऋण	रिजर्व बैंक से लिये गये ऋण	नकद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								अखंडित भारत				
1938-39	51	12,381	54.5	10,330	—	22,711	—	—	—	—	—	638
1945-46	91	65,453	71.6	25,952	12,156	91,405	—	—	—	—	—	3,480
1946-47	96	72,554	69.2	32,311	13,304	1,04,865	—	—	—	—	—	4,111
1947-48	101	70,665	67.3	34,389	14,971	1,05,054	—	—	—	—	—	3,992
								भारतीय यूनियन				
1948-49	94	67,456	68.9	30,388	14,039	97,844	2,659 (ख)	49 (ख)	2,708 (ख)	95,136	333	3,751
1949-50	94	59,779	68.7	27,259	13,395	87,038	2,606	48	2,654	84,384	743	3,447
1950-51	93	59,913	68.3	27,845	13,785	87,759	2,075	101	2,176	85,583	446	3,468
1951-52	94	59,373	67.1	29,082	13,566	88,455	2,320	61	2,381	86,074	1,382	3,733
1952-53	91	54,623	63.8	30,926	13,805	85,549	1,304	343	1,646	83,903	1,120	3,333

(क) सेविंग्स डिपाजिट के आकडे मार्च के अन्तिम शुक्रवार के और मासिक आकडे महीने के अन्तिम शुक्रवार के हैं। रिज़र्व बैंक कानून की धारा 42 के अनुसार सेविंग डिपोजिट को 'टाइम लाएबिलिटी' (समय का ऋण) माना गया है।

(ख) मार्च 1949 तक समाप्त होने वाले 9 महीनों के लिये।

(ग) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये ऋणों को छोड कर और इम्पीरियल बैंक (भारत) से लिये गये ऋण 18 अप्रैल, 1952 के बाद से।

(जारी)

तालिका 47—जारी

शेड्यूल्ड बैंकों की कुल मिलाकर स्थिति (बर्मा को छोड़कर)—जारी

(लाख रुपयों में)

शुक्रवार के आंकड़ों का औसत	रिजर्व बैंक में बाकी 13	रिजर्व बैंक में स्थायी न्यूनतम से अधिक 14	रिजर्व बैंक में कुल नकदी और बाकी 15	(6) के साथ (15) का प्रतिशत 16	अन्य बैंकों के [illegible] एकाउन्ट में बाकी 17	सरकारी सिक्योरिटियों में लगाई गई राशि (घ) 18	(6) के साथ (18) का प्रतिशत 19	जो धन छोटे नोटिस पर वापस लिया जा सकता है (ङ) 20	डिस्काउन्टेड अन्तर्देशीय बिल (ङ) 21	अगाऊ (ङ) 22	शेड्यूल्ड बैंकों का कुल ऋण (20 + 21 + 22) 23	(6) के साथ (23) का प्रतिशत 24
						अविभक्त भारत						
1938-39	1,588	762	2,226	9 80	—	—	—	—	460	11,134	11,594	51 05
1945-46	8,991	5,199	12,471	13.64	—	—	—	—	1,605	28,507	30,112	32 94
1946-47	8,125	3,851	12,236	11 67	—	—	—	—	2,132	40,639	42,771	40.79
1947-48	10,081	5,860	14,073	13 40	—	—	—	—	1,682	42,754	44,436	42 30
						भारतीय यूनियन						
1948-49	7,663	3,682	11,414	11 67	—	—	—	—	1,644	42,485	44,129	45.10
1949-50	6,585	3,051	10,032	11 53	—	—	—	—	1,535	42,674	44,209	50.79
1950-51	6,078	2,525	9,546	10 88	—	—	—	—	1,187	44,703	45,890	52.29
1951-52	5,729	2,179	9,462	10.70	1.191 (च)	30,348 (च)	34 31	1,140 (च)	2,281	52,359	55,120	62.32
1952-53	5,182	1,832	8,515	9.95	1,157	30,634	35 81	1,726	3,847	46,164	51,737	60.48

(घ) किताबी कीमत के अनुसार; इसमें ट्रेजरी बिल और ट्रेजरी डिपाजिट रसीदें भी शामिल हैं।

(ङ) नवम्बर 1951 के "अगाऊ" में छोटे नोटिस पर वापस लिया जा सकने वाला रुपया तथा खरीदे हुए अन्तर्देशीय बिल शामिल नहीं है। तब से उनकी गणना डिस्काउन्टेड अन्तर्देशीय बिलों (सख्या 21) में की गई है।

(च) नवम्बर 1951 से सप्ताह की औसत।

भारतीय शेड्यूल्ड ज्वाइन्ट स्टाक बैंक, 1951

संख्या	बैंक का नाम	स्थापन तिथि
1	अयोध्या बैंक, फैजाबाद	11-9-1894
2.	इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता	17-4-1865
3	आंध्र बैंक, मछिलीपत्तनम	20-11-1923
4	बैंक औव् आसाम, शिलांग	29-4-1936
5.	बैंक औव् बड़ोदा, बड़ौदा	20-7-1908
6.	बैंक औव् बिहार, पटना	1-4-1911
7	बैंक औव् बीकानेर, बीकानेर	30-12-1944
8	बैंक औव् इण्डिया, बम्बई	7-9-1906
9	बैंक औव् इन्दौर, इन्दौर	23-3-1920
10	बैंक औव् जयपुर, जयपुर	8-2-1943
11	बैंक औव् महाराष्ट्र, पूना	16-9-1935
12	बैंक औव् मैसूर, बंगलौर	19-5-1913
13.	बैंक औव् नागपुर, वर्धा	13-11-1937
14	बैंक औव पूना, पूना	19-7-1945
15	बैंक औव् राजस्थान, उदयपुर	7-5-1943
16	बरेली कार्पोरेशन (बैंक), बरेली	19-7-1928
17.	बेलगांव बैंक, बेलगांव	11-1-1930
18	बनारस स्टेट बैंक, रामनगर	12-9-1946
19	भाग्य लक्ष्मी बैंक, मछिलीपत्तनम	22-4-1929
20	कलकत्ता नेशनल बैंक, कलकत्ता	9-5-1935
21	कनारा बैंक, मंगलौर	1-7-1906
22	कनारा बैंकिंग कारपोरेशन, उदीपी	28-5-1906
23	कनारा इंडस्ट्रियल एण्ड बैंकिंग सिण्डीकेट उदीपी	20-10-1925
24.	सेण्ट्रल बैंक औव् इण्डिया, बम्बई	21-12-1911
25.	देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी, बम्बई	26-5-1938
26.	दिनाजपुर बैंक, कलकत्ता	28-3-1914
27.	गाडोदिया बैंक, बम्बई	11-8-1943
28.	हिन्द बैंक, कलकत्ता	2-2-1943
29	हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक, कानपुर	14-5-1943
30.	हिन्दुस्तान मर्कैन्टाइल बैंक, कलकत्ता	5-2-1944
31.	हैदराबाद स्टेट बैंक, हैदराबाद (दक्षिण)	25-8-1941
32.	इम्पीरियल बैंक औव् इण्डिया, कलकत्ता	27-1-1921

संख्या	बैंक का नाम	स्थापन तिथि
33.	इण्डियन बैंक, मद्रास	5-3-1907
34.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, मद्रास	20-11-1936
35.	इण्डो-कर्मशियल बैंक, मयूरम्	20-11-1932
36.	इण्डो-मर्केन्टाइल बैंक, कोचीन	2-9-1937
37.	जोधपुर कर्मशियल बैंक, जोधपुर	16-6-1944
38.	करनानी इंडस्ट्रियल बैंक, कलकत्ता	26-9-1919
39.	कुम्भकोणम बैंक, कुम्भकोणम	31-10-1904
40.	लक्ष्मी कर्मशियल बैंक, दिल्ली	3-4-1939
41.	लक्ष्मी बैंक, अकोला	26-2-1938
42.	महालक्ष्मी बैंक, कलकत्ता	22-11-1910
43.	मर्केन्टाइल बैंक ऑव् हैदराबाद, हैदराबाद (दक्षिण)	6-2-1947
44.	मेट्रोपोलिटन बैंक, कलकत्ता	16-9-1936
45.	मीराज स्टेट बैंक, मिराज	30-4-1929
46.	नादर बैंक, तूतीकोरिन	11-5-1921
47.	नारंग बैंक ऑव् इण्डिया, अमृतसर	24-12-1942
48.	नेशनल बैंक ऑव् लाहौर, दिल्ली	28-8-1942
49.	नेशनल सेविंग्स बैंक, बम्बई	28-5-1941
50.	नेदुगडी बैंक, कोज़ीकोड	29-5-1913
51.	न्यू बैंक ऑव् इण्डिया, अमृतसर	21-12-1936
52.	न्यू सिटिज़न बैंक ऑव् इण्डिया, बम्बई	31-7-1937
53.	ओरियंटल बैंक ऑव् कामर्स, दिल्ली	19-2-1943
54.	अवध कर्मशियल बैंक, फैज़ाबाद	3-5-1881
55.	पलाई सैन्ट्रल बैंक, पलाई	10-1-1927
56.	पाण्ड्यन बैंक, तिरुमंगलम	11-12-1946
57.	प्रभात बैंक, दिल्ली	1-2-1943
58.	प्रताप बैंक, दिल्ली	17-12-1943
59.	प्रेजिडेंसी इण्डस्ट्रियल बैंक, पूना	19-11-1936
60.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, अमृतसर	4-6-1908
61.	पंजाब कोआपरेटिव बैंक, अमृतसर	31-10-1904
62	पजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली	19-5-1894
63.	सांगली बैंक, सागली	5-10-1916
64.	सदर्न बैंक, कलकत्ता	10-10-1934
65.	साउथ इण्डिया बैंक, तिरुनेलवेली	12-1-1903

संख्या	बैंक का नाम	स्थापन तिथि
66.	साउथ इण्डियन, बैंक, त्रिचूर . . .	25-1-1929
67.	तँजोर परमानेन्ट बैंक, तँजोर . . .	6-7-1901
68.	ट्रेडर्स बैंक, दिल्ली . . .	28-7-1933
69.	तिरुवांकुर बैंक, त्रिवेन्द्रम . . .	12-9-1945
70.	तिरुवांकुर फारवर्ड बैंक, कोट्टयम . .	7-2-1929
71.	यूनियन बैंक ग्रौव् इण्डिया, बम्बई . .	11-11-1919
72.	यूनाइटेड बैंक ग्रौव् इण्डिया, कलकत्ता . .	12-10-1950
73.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, दिल्ली . .	6-1-1943
74.	यूनाइटेड इण्डस्ट्रियल बैंक, कलकत्ता . .	21-2-1940
75.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, सतारा सिटी . .	17-10-1936
76.	यूनिवर्सल बैंक ग्रौव् इण्डिया, दालमियानगर . .	4-1-1937
77.	वीस्या बैंक, बंगलौर सिटी . . .	29-3-1930

विदेशी शेड्यूल्ड बैंक

संख्या	बैंक का नाम
1.	ग्रमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी इन्कारपोरेटिड
2.	बैंक ग्रौव् चाइना
3.	चार्टर्ड बैंक ग्रौव् इण्डिया, ग्रास्ट्रेलिया एण्ड चीन
4.	कोंत्वार नाश्यनाल देस्कोंतद पारि
5.	ईस्टर्न बैंक
6.	फरीदपुर बैंकिंग कार्पोरेशन
7.	ग्रिन्डलेज़ बैंक
8.	हबीब बैंक
9.	हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
10.	लायड्स बैंक
11.	मर्केन्टाइल बैंक ग्रौव् इण्डिया
12.	नेशनल बैंक ग्रौव् इण्डिया
13.	नेशनल बैंक ग्रौव् पाकिस्तान
14.	नेशनल सिटी बैंक ग्रौव् न्यूयार्क
15.	नेशनल हैण्डेल्स बैंक एन० वी०
16.	नीडरलैण्ड्स ट्रेडिंग सोसाइटी

भारतीय इन्श्योरेन्स कम्पनियां

जी=जीवन, अ=अग्नि, स=समुद्री और वि=विविध

---

1. आदर्श बीमा कम्पनी (1935) जी, इलाहाबाद
2. एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी (1942) जी, अ स, वि, बम्बई
3. अजय म्युचुअल बीमा कार्पोरेशन (1945) जी, आगरा
4. अल्को इन्श्योरेंस कम्पनी (1944) अ, वि, बम्बई
5. आल इण्डिया कोआपरेटिव फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस सोसायटी (1949) अ, वि, बम्बई
6. आल इण्डिया जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी (1944) जी, अ स. वि, बम्बई
7. आल इण्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट म्युचुअल इन्श्योरेंस कम्पनी (1946) वि, पूना
8. आनन्द इंश्योरेंस कम्पनी (1942) जी, अ, स, वि, बम्बई
9. आंध्र इंश्योरेंस कम्पनी (1925) जी, अ, स, वि, मछलीपट्टम
10. आर्गस इन्श्योरेंस कम्पनी (1919) जी, अहमदाबाद
11. अरुणोदय मैरीन इन्श्योरेंस कम्पनी (1949) स कन्ट्रीक्राफ्ट, बम्बई
12. आर्यन चेम्पियन इन्श्योरेंस कम्पनी (1934) जी बम्बई
13. आर्यस्थान इन्श्योरेंस कम्पनी (1933) जी, कलकत्ता
14. आर्य इन्श्योरेंस कम्पनी (1910) जी कलकत्ता
15. एशियन एन्श्योरेन्स कम्पनी (1910) जी, अ, वि, बम्बई
16. एशियाटिक गवर्नमेंट सिक्युरिटी लाइफ एण्ड जनरल एन्श्योरेंस कम्पनी (1913) जी, अ, स, वि, बंगलौर सिटी
17. एसोशिआकाओ गोआना डि म्युचुओ प्रौविडेन्सियो (1885) जी, बम्बई
18. एसोशिएटेड इन्श्योरेंस (1931)[1] जी, नागपुर
19. औंध म्युचुअल लाइफ एश्योरेन्स सोसायटी (1941) जी पूना
20. बंगलक्ष्मी इन्श्योरेंस (1931) जी, कलकत्ता
21. बिहार यूनाइटेड इन्श्योरेंस (1933) जी, पटना
22. बंगाल क्रिश्चियन फैमिली पेन्शन फंड (1859) जी, कलकत्ता
23. बंगाल इंश्योरेंस एण्ड रिअल प्रापर्टी कम्पनी (1920) जी, कलकत्ता
24. बंगाल सेक्रेटरिएट कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी (1929) जी, कलकत्ता
25. भाभा मेरीन इंश्योरेंस कम्पनी (1951) स (कन्ट्रीक्राफ्ट) पोरबन्दर, सौराष्ट्र राज्य
26. भाग्यलक्ष्मी इंश्योरेंस (1931) जी, कलकत्ता
27. भारत फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस (1942) अ, स, वि, नई दिल्ली
28. भारत इंश्योरेंस कम्पनी (1896) जी, वि, दिल्ली
29. भास्कर इन्श्योरेंस कम्पनी (1936) जी, गौहाटी (आसाम)

---

[1] विधि की धारा 3(4) (जी) के अनुसार रजिस्टरी रद्द कर दिया गया।

30 बी० बी० एण्ड सी० आई रेलवे जोरोस्ट्रियन कोआपरेटिव डेथ बेनिफिट एसोसिएशन (1888)[1] जी बम्बई

31 बौम्बे एलाइन्स एश्योरेन्स कम्पनी (1937) जी बम्बई

32 बौम्बे कोआपरेटिव इन्श्योरेंस सोसायटी (1930) जी बम्बई

33 बौम्बे फेमिली पेंशन फंड ऑव् गवर्नमेंट सर्वेन्टस (1848) जी, बम्बई

34 बौम्बे फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी (1935) अ स, वि, बम्बई

35 बौम्बे लाइफ एश्योरेंस कम्पनी (1908) जी बम्बई

36 बौम्बे म्युचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसायटी (1871) जी, बम्बई

37 बौम्बे पोस्टल एम्प्लाइज कोआपरेटिव इन्श्योरेंस फंड (1935) जी बम्बई

38. बौम्बे जोरोस्ट्रियन कोआपरेटिव लाइफ एश्योरेंस सोसायटी (1889)[2] जी, बम्बई

39 ब्रिटिश इण्डिया जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी (1919) जी, अ, स, वि बम्बई

40 कलकत्ता कस्टम्स कोआपरेटिव बेनिफिट सोसायटी (1931) जी कलकत्ता

41 कलकत्ता हास्पिटल एण्ड नर्सिंग होम बेनिफिट्स एसोसिएशन (1948) वि, कलकत्ता

42 कलकत्ता इन्श्योरेंस (1924) जी, अ, स वि कलकत्ता

43 कलकत्ता पोस्टल एण्ड आर० एम० एस० कोआपरेटिव म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी (1930) जी, कलकत्ता

44 कनारा मोटर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी (1945) वि कोडियालबेल (द० कनारा)

45 कनारा म्युचुअल एश्योरेंस कम्पनी (1935) जी उडीपि (द० भारत)

46 सेन्ट्रल इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी[3] (1946) जी स, वि इंदौर सिटी

47 सेन्ट्रल मर्केन्टाइल एश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, बम्बई

48 सेन्ट्रल म्युचुअल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी (1943) जी बम्बई

49 सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लाईज एश्योरेंस फंड[4] (1916) जी बम्बई

50 चन्द्रगुप्त म्युचुअल लाइफ एश्योरेंस कम्पनी[5] (1944) जी, बम्बई

51 सिटिजन्स ऑव् इण्डिया म्युचुअल इन्श्योरेंस कम्पनी (1945) जी, भरतपुर

52 क्लाइव इन्श्योरेंस कम्पनी (1917) अ, स वि कलकत्ता

53 कमर्शियल इन्श्योरेंस कम्पनी (193[illegible]) स, जी बम्बई

54 कामनवेल्थ एश्योरेंस कम्पनी (1928) जी, अ, वि, पूना सिटी

55 कन्कोर्ड ऑव् इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी (1931) अ स, वि, कलकत्ता

---

[1] पहले का बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे जोरोस्ट्रियन एसोसिएशन डेथ बेनिफिट फंड

[2] पहले का बाम्बे जोरोस्ट्रियन म्युचुअल डेथ बेनिफिट फंड

[3]. पहले ग्लोरी इंश्योरेंस कम्पनी

[4]. पहले जी० आई० पी० रेलवे एम्प्लाईज एश्योरेंस फंड

[5]. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द । कम्पनी बन्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल

56. कौन्टिनेन्टल म्युचुअल एश्योरेंस कम्पनी (1946) जी, पूना
57. कोआपरेटिव एश्योरेंस कम्पनी (1906) जी, अ, स, वि, अमृतसर
58 कोआपरेटिव फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस सोसायटी (1941) अ, वि, मद्रास
59 कोआपरेटिव जनरल इंश्योरेंस सोसायटी अ, वि, हैदराबाद (दक्षिण)
60. कौर्पोरेशन कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी (1931) जी, कलकत्ता
61 क्रेसन्ट इंश्योरेंस कम्पनी (1919) जी, बम्बई
62. दीपक जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1943) जी, अ, स, वि, बम्बई
63. दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स इंश्योरेंस कम्पनी (1945) जी, दिल्ली
64. डिपौजिटर्स बेनिफिट इंश्योरेंस कम्पनी (1932) जी, बम्बई
65 देवकरण नानजी इंश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, अ, वि, बम्बई
66. धर्मशी मोरारजी पैरौन इंश्योरेंस कम्पनी (1951) स, (कन्ट्री क्राफ्ट) पोरबन्दर
67. दिग्विजय इंश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, बम्बई
68. डोमिनियन इंश्योरेंस कम्पनी (1930) जी, कलकत्ता
69. ईस्ट एण्ड वेस्ट इंश्योरेंस कम्पनी (1913) जी, अ, स, वि, बम्बई
70. ईस्ट इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी (1929) जी, कलकत्ता
71. ईस्टर्न लाइफ़ एश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, बम्बई
72. ईस्टर्न म्यूचुअल इंश्योरेंस कम्पनी (1943) जी, कलकत्ता
73 एम्पायर आव इण्डिया लाइफ एश्योरेंस कम्पनी[1] (1897) जी, बम्बई
74. फ़ेमस लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी[2] (1942) जी, बम्बई
75. फ़ायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1942) अ, स, वि, कलकत्ता
76 फ्री इण्डिया जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1934) जी, अ, स, वि, कानपुर
77 जनरल एश्योरेंस सोसायटी (1908) जी, अ, स, वि, अजमेर
78. जनरल फेमिली पेंशन फंड (1870) जी, कलकत्ता
79 गुडविल एश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, बम्बई
80. गोर्धनदास मगनलाल भाभा (1936)[3] स (कन्ट्री क्राफ्ट), बम्बई
81 ग्रेट पिरामिड इंश्योरेंस कम्पनी (1945) अ, स वि, कलकत्ता
82 ग्रेट सोशल लाइफ एण्ड जनरल एश्योरेंस (1933) जी, स, बम्बई
83 गुजरात पारसी म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसायटी (1891) जी, सूरत
84 हैपी इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, कलकत्ता
85 हरिलाल जेठाभाई बीमावाला (1946)[4] स (कन्ट्री क्राफ्ट), बम्बई
85क. हरिलाल जेठाभाई बीमावाला लि० (1951) स (कन्ट्री क्राफ्ट), बम्बई

---

[1] कानून की धारा 52 (क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त

[2] कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द और धारा 52 (क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त

[3] 25-7-51 से रजिस्ट्री रद्द

[4] नवकरण न करवाने के कारण रजिस्ट्री रद्द

86. हरकुलीज इंश्योरेंस कम्पनी (1935) अ, स, वि, कलकत्ता।
87 हिन्दू फैमिली एन्युटी फंड (1872) जी, वि, कलकत्ता
88. हिन्दू म्युचुअल लाइफ़ एश्योरेंस (1891) जी, कलकत्ता
89 हिन्दुस्तान म्युचुअल एश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, आगरा
90 हिन्दुस्तान कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी (1907) जी, वि, कलकत्ता
91 हिन्दुस्तान जनरल इंश्योरेंस सोसायटी (1944) अ, स, वि, कलकत्ता
92 हिन्दुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, अ, वि, मछ्लीपल्यम
93 होम सिक्युरिटी एश्योरेन्स कम्पनी (1944) जी, बम्बई
94 हावड़ा इंश्योरेंस कम्पनी (1942) जी, अ, स, वि कलकत्ता
95 हुकुमचन्द इंश्योरेंस कम्पनी (1929) अ, वि कलकत्ता
96. हैदराबाद कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी (1935) जी, हैदराबाद (दक्षिण)
97 हैदराबाद यूनाइटेड इंश्योरेंस कम्पनी (1947) अ, स, वि, हैदराबाद (दक्षिण)
98. आइडियल म्युचुअल इंश्योरेंस कम्पनी (1941) जी कलकत्ता
99. इण्डिया इक्विटेबल इंश्योरेंस कम्पनी (1908) जी, कलकत्ता
100 इण्डिया लाइफ़ एण्ड जनरल एश्योरेंस सोसायटी [1] (1927) जी, वि, कोयम्बटूर
101 इण्डिया ओरियोल एश्योरेंस कम्पनी (1931) जी, अमृतसर
102 इण्डियन सरकार इंश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, मद्रास
103 इण्डियन एकोनोमिक इंश्योरेंस कम्पनी (1934) जी, कलकत्ता
104 इण्डियन ग्लोब इंश्योरेंस कम्पनी (1929) जी, अ, स, वि, बम्बई
105 इण्डियन गारटी एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1922) अ, वि, बम्बई
106 इण्डियन इंश्योरेंस (1934) [2] जी, दिल्ली
107. इण्डियन मर्केन्टाइल इंश्योरेंस कम्पनी (1907) जी अ, स वि, बम्बई
108 ण्डियन मर्चेन्ट्स मैरीन इंश्योरेंस (1941) स. (कन्ट्री क्राफ्ट) बम्बई
109 इण्डियन म्युचुअल जनरल इंश्योरेंस सोसायटी (1946) अ, वि, मद्रास
110 इण्डियन म्युचुअल इंश्योरेंस कम्पनी (1928) जी दिल्ली
111 इण्डियन म्युचुअल लाइफ एसोसियेशन (1926) जी मद्रास
112 इण्डियन ओशन इंश्योरेंस कम्पनी (1944) स (कन्ट्री क्राफ्ट), बम्बई
113 इण्डियन पोस्ट्स एण्ड टेलिग्राफ कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी (1921) [3] जी, मद्रास
114 इण्डियन प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, पूना
115 ण्डिया ट्रेड एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1944) अ, स, वि कलकत्ता
116. इडस्ट्रियल एण्ड प्रूडेन्शियल इंश्योरेंस कम्पनी (1913) जी, बम्बई
117 इंश्योरेंस आव इण्डिया (1936) जी, कलकत्ता

1. पहले इण्डिया लाइफ बेनिफिट एश्योरेंस सोसायटी
2. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द
3 पहले पोस्टल एण्ड आर० एम० एस० कोआपरेटिव बेनिफिट फंड

118 न्वेस्टमेंट ट्रस्टी एण्ड इंश्योरेंस कारपोरेशन (1936) वि, बेलगाव
119 जय भारत इंश्योरेंस कम्पनी (1943) जी, अ, स, वि, बम्बई
120 जुपीटर जनरल इंश्योरेंस कम्पनी[1] (1919) जी, अ, स, वि, बम्बई
121 केसर-ए-हिन्द इंश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, अ, स, वि, बम्बई
122 कल्याण मैरीन इंश्योरेंस कम्पनी (1951) स (कन्ट्री क्राफ्ट) पोरबन्दर
123. लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी (1924) जी, दिल्ली
124 लिबर्टी इंश्योरेंस कम्पनी[2] (1947) अ, स, वि, नई दिल्ली
125 लीग लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी (1933) जी, पूना
126. मध्यप्रदेश म्युचुअल इंश्योरेंस (1927)[3] जी, नागपुर
127 मद्रास लाइफ एश्योरेंस कम्पनी (1934) जी, कांचीपुरम
128 मद्रास मोटर इंश्योरेंस कम्पनी (1950 वि, मद्रास
129 मदुरा इंश्योरेंस कम्पनी (1943) अ, वि, मदुराई
130 महागुजरात कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी (1938) जी, बड़ौदा
131 महावीर इंश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, कलकत्ता
132 मंगलोर रोमन कैथोलिक पायोनियर फंड (1888) जी, मंगलोर
133 मैरीन एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1944) अ, स, वि, बम्बई
134 मर्चेन्टस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1944) स (कन्ट्री क्राफ्ट) बम्बई
135 मेथोडिस्ट एन्युइटेंट सोसायटी फोर इण्डिया, बर्मा एण्ड सीलोन (1911) जी, म [illegible]
136 मेट्रोपोलिटन इंश्योरेंस कम्पनी (1930) जी, कलकत्ता
137 मिडलैण्ड इंश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, वि, मद्रास
138 मिलओनर्स म्युचुअल इंश्योरेंस एसोसियेशन (1924) वि, बम्बई
139 मॉडर्न म्युचुअल लाइफ एश्योरेंस कम्पनी (1945)[4] जी कलकत्ता
140. मदर इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1943) अ, स, वि, मदुराई
141. मदर इण्डिया लाइफ एश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, मदुराई
142. मोटर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1947) वि, कलकत्ता
143. मोटर ओनर्स म्युचुअल इंश्योरेंस कम्पनी (1940) वि, बेलगाम
144 म्युचुअल हैल्प एसोसियेशन, शिमला (1899) जी, नई दिल्ली
145 मैसूर इंश्योरेंस कम्पनी (1933) जी, बंगलौर
146 नागपुर पायोनियर इंश्योरेंस कम्पनी (1921) जी, बम्बई
147 नारणजी भानाभाई एण्ड कम्पनी लि० (1951) स (कन्ट्री क्राफ्ट), भावनगर
148. नरहरि मैरीन इंश्योरेंस कम्पनी लि० (1952) स (कन्ट्री क्राफ्ट), बम्बई
149. नेशनल सिटी इंश्योरेंस (1940) जी, कलकत्ता

---

1. कानून की धारा 52 (क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त
2. पहले खाण्डेलवाल इंश्योरेंस कम्पनी
3. पहले सी० पी० एण्ड बरार टीचर्स म्युचुअल बेनिफिट फंड
4. कानून की धारा 3 (4) (क) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द

150. नेशनल फायर एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1931) अ, स, वि, कलकत्ता
151. नेशनल इण्डियन लाइफ इश्योरेंस कम्पनी (1906) जी, कलकत्ता
152. नेशनल इश्योरेंस कम्पनी (1906) जी, अ, म, वि, कलकत्ता
153. नेशनल मर्केन्टाइल इश्योरेंस कम्पनी (इण्डिया)[1] (1933) जी, कलकत्ता
154. नेशनल सिक्युरिटी एश्योरेंस कम्पनी (1940) अ, स, वि, शिमला
155. नेशनल स्टार एश्योरेंस कम्पनी (1928) जी, मद्रास
156. नेपच्यून एश्योरेंस कम्पनी (1930) जी, अ, वि, बम्बई
157. न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस कम्पनी (1933) जी, अ, स, वि, नई दिल्ली
158. न्यू ग्रेट इश्योरेंस कम्पनी औव इण्डिया (1943) जी, अ, स, वि, बडौदा
159. न्यू गार्जियन औव् इण्डिया लाइफ इश्योरेंस कम्पनी (1934) जी, मद्रास
160. न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी (1919) जी, अ, स, वि, बम्बई
161. न्यू इश्योरेंस (1933) जी, बनारस
162. न्यू मर्चेन्टस इश्योरेंस कम्पनी (1936) स (कन्ट्री क्राफट), पोरबन्दर
163. न्यू मेट्रो इश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, बम्बई
164. न्यू स्वस्तिक लाइफ एश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, बम्बई
165. नार्दर्न इण्डिया मोटर ओनर्स म्यूचुअल इश्योरेंस कम्पनी (194[illegible]) वि, जालंधर सिटी
166. नार्दर्न इण्डिया ट्रासपोर्टर्स इश्योरेंस कम्पनी (1948) वि, जालधर सिटी
167. ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1947) अ, स, वि, बम्बई
168. ओरियण्टल गवर्नमेंट सिक्युरिटी लाइफ एश्योरेंस कम्पनी (1874) जी, बम्बई
169. उड़ीसा कोआपरेटिव इश्योरेंस सोसायटी (1946) अ, वि, कटक
170. पैलेडियम एश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, कलकत्ता
171. पाण्ड्यन इश्योरेंस कम्पनी (1933) अ, स, वि, मदुराई
172. पीयरलैस लाइफ एश्योरेंस कम्पनी[2] (1942) जी, कलकत्ता
173. पीपुल्स इश्योरेंस कम्पनी (1926) जी, दिल्ली
174. पायोनियर फायर एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1942) जी, अ, म, वि, कोयम्बटूर
175. पौलिस कोआपरेटिव लाइफ इश्योरेंस सोसायटी (1926) जी, कलकत्ता
176. पौलिसी-होल्डर्स एश्योरेंस (1939) जी, दिल्ली
177. पौपुलर इंश्योरेंस कम्पनी (1929) जी, मगलौर (द० भारत)
178. पोरबन्दर इश्योरेंस कम्पनी (1951) स (कन्ट्री क्राफट), पोरबन्दर
179. प्रवर्तक इश्योरेंस कम्पनी (1931) जी, कलकत्ता
180. प्राची इश्योरस कम्पनी (1947) अ, वि, कटक
181. प्रीमियर लाइफ एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1934) जी, अ, स, वि, मद्रास
182. प्रेसीडेन्सी लाइफ इश्योरेंस कम्पनी (1930) जी, बम्बई

---

1. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द और धारा 52-क के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त

2. कानून की धारा 3 (4) (क) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द

183. पृथ्वी इंश्योरस कम्पनी (1943) जी, अ, स, वि, बम्बई
184. पंजाब नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, दिल्ली
185. रैडिकल इंश्योरस कम्पनी (1931) जी, कलकत्ता
186. रेलवे एम्प्लाईज कोआपरेटिव इश्योरेंस सोसायटी[1] (1931) जी, कलकत्ता
187. राजस्थान एग्रीकल्चर लिवस्टाक एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1948) जयपुर
188. राजस्थान इश्योरेंस कम्पनी (1937) जी, कलकत्ता
189. रिलायन्स एश्योरेंस सोसायटी (1931) जी, बडौदा
190. रूबी जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, अ, स, वि, दिल्ली
191. सह्याद्रि इंश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, नासिक सिटी
192. सरस्वती इंश्योरेस कम्पनी (1934) जी, अ, वि, दिल्ली
193. सैन्टिनेल एश्योरेंस कम्पनी (1934) जी, अ, स, वि, बम्बई
194. सर्वेन्ट्स आव् इंडिया इश्योरेस कम्पनी (1932) जी, नई दिल्ली
195. शाह नरोत्तमदास हरजीवनदास एण्ड कम्पनी[2] (1933) स (कन्ट्री क्राफ्ट), बम्बई
196. श्री महासागर बीमा कम्पनी (1951) म (कन्ट्री क्राफ्ट), पोरबन्दर
197. श्री विजय सागर इश्योरेस कम्पनी लि० (1951) स (कन्ट्री क्राफ्ट), वेरावल
198. साउथ इण्डिया कोआपरेटिव इंश्योरेस सोसायटी (1932) जी, मद्रास
199. साउथ इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी[3] (1934) अ, म, वि, बम्बई
200. साउथ इण्डियन टीचर्स यूनियन प्रोटेक्शन फंड (1928) जी, मद्रास
201. स्टैण्डर्ड जनरल एश्योरेस कम्पनी (1943) अ, स, वि, कलकत्ता
202. स्टर्लिंग जनरल इश्योरेस कम्पनी (1944) जी, अ, स, वि, नई दिल्ली
203. सनलाइट ऑव् इण्डिया इश्योरेस कम्पनी (1932) जी, नई दिल्ली
204 सनशाइन इश्योरेस कम्पनी (1933) जी, बम्बई
205. सुप्रीम म्युचुअल एश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, पूना
206 सुशील लाइफ एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी[4] (1939) जी, नई दिल्ली
207. स्वदेशी बीमा कम्पनी[5] (1931) जी, वि, आगरा
208. स्वराज लाइफ़ इश्योरस कम्पनी (1933) जी, धारवाड
209. सिलवन स्टार इश्योरेंस ट्रस्ट (1936) जी, दिल्ली
210 तरुण एश्योरेंस कम्पनी (1931) जी, बम्बई।
211. तिलक इंश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, नई दिल्ली

---

1. पहले बी० एण्ड ए० रेलवे एम्प्लाईज़ कोआपरेटिव बेनिफिट सोसायटी
2. नवकरण न कराये जाने के कारण रजिस्ट्री रद्द
3. पहले साउथ इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेस कम्पनी
4. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द और कम्पनी को बन्द करन का प्राथना पत्र दाखिल

कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द

212. तिन्नेवेली डायोसेशन म्युचुअल इंश्योरेंस कम्पनी[1] (1849) जी, पलमकोटा (दक्षिण भारत)

213. ट्रिनिटी म्युचुअल एश्योरेंस कम्पनी[2] (1942) जी, बम्बई
214. ट्रिटोन इंश्योरेंस कम्पनी (1850) अ, स, वि, कलकत्ता
215. ट्रोपिकल इंश्योरेंस कम्पनी[3] (1927) जी, स, वि, नई दिल्ली
216. ट्रस्ट आव् इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, पूना
217. यूनियन लाइफ एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी[4] (1939) जी, बम्बई
218. यूनीक मोटर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1940) स, वि, बम्बई
219. युनाइटेड जनरल एश्योरेंस ट्रस्ट (इण्डिया) (1928) अ, स, वि, बम्बई
220. युनाइटेड इण्डिया फ़ायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1938) अ, स, वि, मद्रास
221. युनाइटेड इण्डिया लाइफ़ एश्योरेंस कम्पनी (1906) जी, मद्रास
222 ुनाइटेड कर्नाटिक इंश्योरेंस कम्पनी[5] (1929) जी, धारवाड
223 युनीवर्सल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1919) जी अ, स, वि, बम्बई
224. वेनगार्ड फ़ायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1944) अ, स वि मद्रास
225. वेनगार्ड इंश्योरेंस कम्पनी (1937) जी, वि, मद्रास
226. वसत इंश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, बम्बई
227 विक्रम जनरल एश्योरेंस (1937) जी, बम्बई
228 विशालभारत बीमा कम्पनी[6] (1934) जी, आगरा
229. विश्व भारती इंश्योरेंस कम्पनी (1942) जी, अ, स, वि, बम्बई
230. वल्कन इंश्योरेंस कम्पनी (1919) जी, अ, स, वि, बम्बई
231. वार्डन इंश्योरेंस कम्पनी (1933) जी, अ, वि, बम्बई
232. वैस्टर्न इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी (1913) जी, सतारा सिटी
233. वैस्टर्न रेलवे कोआपरेटिव लाइफ एश्योरेन्स सोसायटी[7] (1932) जी, बम्बई सैन्ट्रल
234. ह्वाइट स्टार म्युचुअल इंश्योरेंस कम्पनी (1944) जी, कलकत्ता
235. यशवन्त म्युचुअल इंश्योरेंस कम्पनी (1943) जी, पूना
236. जैनिथ एश्योरेंस कम्पनी (1916) जी, अ, स, वि बम्बई

---

1. पहले तिन्नेवेली डायोसेशन काउन्सिल विडोज़ फंड
2. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द, बम्बई हाई कोर्ट द्वारा कम्पनी का काम बन्द करने का आदेश
3. कानून की धारा 52 (क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त
4. अग्नि, समुद्री तथा विविध बीमा सम्बन्धी काम की रजिस्ट्री रद्द, कानून की धारा 52-(क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त
5. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द
6. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द
पहले बी० बी० एण्ड सी आई० रेलवे कोआपरेटिव लाइफ एश्योरेंस सोसायटी

विदेशी बीमा कम्पनियों की सूची

अफ्रीका में संस्थापित

जुबिली इंश्योरेस कम्पनी (1937) जी, अ, बम्बई
सोसिएटे नौर्ड अफ्रीकने डि ग्एिश्योरेंसेज (1941) अ, बम्बई

आस्ट्रेलिया में संस्थापित

बेकर्स एण्ड ट्रेडर्स इंश्योरेंस कम्पनी (1921) अ स, वि, कलकत्ता
इंश्योरेस आफ़िस औव् आस्ट्रेलिया (1910) अ, कलकत्ता
नेशनल इंश्योरेस कम्पनी औव् न्यूजीलैण्ड (1873) अ, स वि, कलकत्ता
न्यूजीलैण्ड इश्योरेस कम्पनी (1859) अ, स, वि, कलकत्ता
क्वीन्सलैण्ड इश्योरेस कम्पनी (1886) अ, स, वि, कलकत्ता
साउथ ब्रिटिश इश्योरेंस कम्पनी (1872) अ, स, वि, कलकत्ता

कैनाडा में संस्थापित

क्राउन लाइफ इश्योरेस कम्पनी (1900) जी, बम्बई
मर्केन्टाइल इश्योरेंस कम्पनी (1927) अ, कलकत्ता
सन लाइफ एश्योरेंस कम्पनी औव् कैनाडा, (1865) जी, वि, बम्बई
वेस्टर्न एश्योरेस कम्पनी (1851) अ स, वि, कलकत्ता

फ्रांस में संस्थापित

यूनियन फायर, एक्सिडेंट एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी[1] अ, स बम्बई

हांगकांग में संस्थापित

ब्रिटिश ट्रेडर्स इश्योरेस कम्पनी (1865) अ, स, कलकत्ता
केन्टन इश्योरेस आफ़िस (1836) स, कलकत्ता
चाइना फायर इंश्योरेंस कम्पनी[2] (1870) अ, कलकत्ता
हागकांग फायर इश्योरेस कम्पनी (1868) अ, कलकत्ता
नार्थ चाइना इंश्योरेंस कम्पनी (1863) स, कलकत्ता
यूनियन इश्योरेंस सोसायटी औव केन्टन (1835) अ, स, वि, कलकत्ता

इण्डोनीशिया में संस्थापित

जावा सी एण्ड फायर इंश्योरेस कम्पनी (1861) अ, स, कलकत्ता

---

[1] प्रतिस्थापन—वर्ष अप्राप्य

[2] नवकरण न कराये जाने के कारण रजिस्ट्री रद्द, स्वेच्छा समामान सम्बन्धी प्रस्ताव 1-10-51 को पास

इटली में संस्थापित

एड्रियाटिक इंश्योरेंस कम्पनी (1838) अ, स, बम्बई

पाकिस्तान में संस्थापित

क्रिश्चियन म्युचुअल इंश्योरेंस कम्पनी (1847) जी, वि गुन्टूर
ईस्टर्न फेडरल यूनियन इंश्योरेंस कम्पनी (1932) जी, अ स, वि, कलकत्ता
इण्डियन लाइफ एश्योरेंस कम्पनी (1892) जी, बम्बई
कराची म्युचुअल एश्योरेंस कम्पनी (1946)[2] जी, अजमेर

स्ट्रेट सैटलमेन्ट्स में संस्थापित

ईस्टर्न यूनाइटेड एश्योरेंस कार्पोरेशन (1913) अ, स. वि, कलकत्ता
ओवरसीज एश्योरेंस कार्पोरेशन (1920) अ, कलकत्ता

स्विट्जरलैण्ड में संस्थापित

बलौजे फायर इंश्योरेंस कम्पनी (1863) अ, बम्बई
हलवेशिया स्विस फायर इंश्योरेंस कम्पनी (1861) अ, बम्बई
विन्टरथुर स्विस लाइफ एश्योरेंस कम्पनी (1923) जी. बम्बई

ब्रिटेन में संस्थापित

एलायन्स एश्योरेन्स कम्पनी (1824) अ, स, वि, कलकत्ता
एटलस एश्योरेंस कम्पनी (1808) जी, अ, स, वि, कलकत्ता
एविएशन एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1935) वि, कलकत्ता
ब्रिटिश एण्ड फारेन मैरीन इंश्योरेंस कम्पनी (1863) स, कलकत्ता
ब्रिटिश एविएशन इंश्योरेंस कम्पनी (1930) वि, कलकत्ता
ब्रिटिश कामनवेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी (1946) अ, बम्बई
ब्रिटिश क्राउन एश्योरेंस कार्पोरेशन (1919) अ, स, बम्बई
ब्रिटिश इक्विटेबल एश्योरेंस कम्पनी (1854) अ, कलकत्ता
ब्रिटिश फायर इंश्योरेंस कम्पनी (1908) अ, वि, कलकत्ता
ब्रिटिश जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1904) अ, कलकत्ता
केलेडोनियन इंश्योरेंस कम्पनी (1805) अ, स, वि, कलकत्ता
सेन्ट्रल इंश्योरेंस कम्पनी (1907) अ, वि, कलकत्ता
सेन्चुरी इंश्योरेंस कम्पनी (1885) अ, स, वि, कलकत्ता
कमर्शियल यूनियन एश्योरेंस कम्पनी (1861) जी, अ, स, वि, कलकत्ता

---

1. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द
2. कानून की धारा 3 (4) (क) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द

क्रूसेडर इंश्योरेंस कम्पनी (1899) अ, स, बम्बई
ईगल स्टार इश्योरेंस कम्पनी (1904) अ, स, वि, बम्बई
एम्प्लायर्स लायबिलिटी एश्योरेंस कार्पोरेशन (1880) अ, स, वि, कलकत्ता
इंग्लिश एण्ड अमेरिकन इश्योरेंस कम्पनी (1929) अ, स, बम्बई
एसेक्स एण्ड सफ़ोक एक्विटेबल इश्योरेंस सोसायटी (1802) अ, वि, कलकत्ता
फाइन आर्ट एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1890) वि, कलकत्ता
जनरल एक्सिडेंट, फ़ायर एण्ड लाइफ़ एश्योरेंस कारपोरेशन (1885) अ, स, वि, बम्बई
ग्रेशम फ़ायर एण्ड एक्सिडेंट इश्योरेंस सोसायटी (1910) अ, स, बम्बई
ग्रेशम लाइफ़ एश्योरेंस सोसायटी (1848) जी, बम्बई
गार्जियन एश्योरेंस कम्पनी (1821) अ, स, वि, कलकत्ता
इंडेम्निटी मैरीन एश्योरेंस कम्पनी (1824) स, बम्बई
लॉ यूनियन एण्ड रौक इश्योरेंस कम्पनी (1806) अ, स वि, कलकत्ता
लीगल एण्ड जनरल एश्योरेंस सोसायटी (1836) अ, स, वि, बम्बई
लाइसेन्सेज़ एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (1890) अ, स, बम्बई
लिवरपूल एण्ड लन्दन एण्ड ग्लोब इश्योरेंस कम्पनी (1836) अ, स, वि, कलकत्ता
लन्दन एश्योरेन्स (1720) अ, स, कलकत्ता
लन्दन गारण्टी एण्ड एक्सीडेंट कम्पनी (1869) अ, कलकत्ता
लन्दन एण्ड लकाशायर इंश्योरेंस कम्पनी (1862) अ स, वि, कलकत्ता
लन्दन एण्ड प्राविन्सियल मैरीन एण्ड जनरल इंश्योरेंस कं० (1898) स, बम्बई
लन्दन एण्ड स्कौटिश एश्योरेंस कार्पोरेशन (1862) अ, कलकत्ता
मेरिटाइम इश्योरेंस कम्पनी (1864) स, बम्बई
मोटर यूनियन इंश्योरेंस कम्पनी (1906) अ, स, वि, कलकत्ता
नेशनल एम्प्लायर्स म्युचुअल जनरल इश्योरेंस एसोसियेशन (1914) अ, वि, बम्बई
नेशनल गारण्टी एण्ड श्योरिटीशिप एसोसिएशन (1863) वि, कलकत्ता
नेशनल इश्योरेंस कम्पनी औव् ग्रेट ब्रिटेन (1897) अ, वि, कलकत्ता
नार्थ ब्रिटिश एण्ड मर्केन्टाइल इश्योरेंस क० (1809) जी, अ, वि, कलकत्ता
नार्दर्न ऐश्योरेन्स कम्पनी (1836) अ, स, वि, कलकत्ता
नार्विच यूनियन फ़ायर इश्योरेंस सोसायटी (1797) अ, स, वि, कलकत्ता
नार्विच यूनियन लाइफ इश्योरेंस सोसायटी (1808) जी, वि, बम्बई
ओशन एक्सीडेंट एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन (1871) वि, कलकत्ता
ओशन मेरिन इश्योरेंस कम्पनी (1888) स, कलकत्ता
पेलैटाइन इश्योरेंस कम्पनी (1886) अ, कलकत्ता
पर्ल एश्योरेंस कम्पनी (1864) जी, अ, वि, कलकत्ता
फिनिक्स एश्योरेंस कम्पनी (1782) जी, अ, स, वि, कलकत्ता
प्राविन्शियल इश्योरेंस कम्पनी (1903) अ, स, बम्बई
प्रूडेंशियल एश्योरेंस क० (1848) जी, अ, स, वि, कलकत्ता

रेलवे पैसेन्जर्स एश्योरेंस कम्पनी (1849) वि, कलकत्ता
रिलायन्स मैरीन इश्योरेंस कम्पनी (1881) अ, म, कलकत्ता
रायल एक्सचेंज एश्योरेंस (1720) अ, स, वि, कलकत्ता
रायल इश्योरेंस कम्पनी (1845) जी, अ, स, वि, कलकत्ता
स्कौटिश यूनियन एण्ड नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी[1] (1824) जी, अ, वि, कलकत्ता
सी इंश्योरेंस कम्पनी औव् लिवरपूल (1875) अ, स, वि, बम्बई
स्टेट एश्योरेंस क० (1891) अ, म, वि, कलकत्ता
सन इश्योरेंस आफिस (1710) अ, स, वि, कलकत्ता
टेम्स एण्ड मर्सी मरीन इश्योरेंस क० (1860) स, कलकत्ता
यूनियन एश्योरेंस सोसायटी (1907) अ, वि, कलकत्ता
यूनियन मैरीन एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1863) म, कलकत्ता
यूनाइटेड स्काटिश इश्योरेन्स क० (1992) अ, स, वि, कलकत्ता
वेस्ट आव स्काटलैण्ड इश्योरेंस आफिस (1886) अ, कलकत्ता
वर्ल्ड मरीन एण्ड जनरल इंश्योरेंस क० (1894) म, कलकत्ता
यार्कशायर इश्योरेंस क० (1824) जी, अ, स, वि, बम्बई

लायड्स के साथ स्थायी सम्पर्क रखने वाली बीमा कम्पनी

ब्लडस्टौक सेल्स एण्ड सर्विसेज (1948) वि, बम्बई

अमेरिका में संस्थापित

अमेरिकन इश्योरेंस क० (1846) अ, कलकत्ता
ग्रेट अमेरिकन इश्योरेंस कम्पनी (1872) अ, स, कलकत्ता
हेनोवर फायर इंश्योरेंस कम्पनी (1852) अ, स, बम्बई
हार्टफ़ोर्ड फ़ायर इश्योरेंस क० (1810) अ, कलकत्ता
होम इश्योरेंस क० (1853) अ, स, कलकत्ता
इश्योरेंस कम्पनी औव् नार्थ अमेरिका (1946) स, बम्बई
न्यू हेम्शायर फ़ायर इश्योरेंस कम्पनी (1869) अ, स, बम्बई
ओरियन्ट इश्योरेंस क० (1867) अ, कलकत्ता
क्वीन इश्योरेंस कम्पनी औव् अमेरिका (1891) अ, कलकत्ता

---

1. नवकरण न कराये जाने पर मेरीन इश्योरेंस की रजिस्ट्री रद्द

नवा अध्याय

पंच वर्षीय आयोजना

मार्च 1950 मे भारत सरकार ने भारत के साधनों का अधिकतम प्रभावशाली और संतुलित उपयोग करने के उद्देश्य से एक आयोजना कमीशन की स्थापना की थी। जुलाई 1950 मे इस कमीशन से अनुरोध किया गया था कि वह कामनवैल्थ सलाहकार समिति के सन्मुख पेश करने के लिए एक षष्ट वर्षीय आर्थिक विकास की आयोजना प्रस्तुत करे। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के सहयोगी आर्थिक विकास के लिए जो कोलम्बो आयोजना बनी थी, उसमे उक्त आयोजना सम्मिलित की गई थी।

जुलाई 1951 मे आयोजना कमीशन ने अपनी प्रथम पचवर्षीय आयोजना की रूप रेखा सार्वजनिक जनता की अधिकतम आलोचना प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकाशित की थी। यह रूपरेखा दो भागों मे विभक्त थी और इसके अनुसार 1951 से 1956 तक, मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्रो मे 1793 करोड़ रुपये लगाए जाने थे। आयोजना के प्रथम भाग पर जो 1,493 करोड़ रुपये लगाए जाने थे, उसके अधिकाश भाग को आन्तरिक साधनो से ही पूरा करन का निश्चय हुआ था। दूसरे भाग पर जो 300 करोड़ रुपया व्यय होना था, उसका अधिकाश भाग इस आशा पर आश्रित था कि विदेशों से आर्थिक सहायता मिलेगी। उसके बाद दिसम्बर 1952 मे प्रथम पंचवर्षीय आयोजना भारतीय ससद् के सन्मुख पेश की गई। पहली रूपरेखा के समान वतमान पचवर्षीय आयोजना दो भागों मे विभक्त नही की गई। वह एक पूरी आयोजना है तथा उसकी पूर्ति के लिए बाह्य सहायता शर्त रूप मे नही रखी गई। इस आयोजना के अनुसार 1951 से 1956 तक 2,069 करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय हुआ। अक्तूबर 1953 मे यह राशि 150 से लेकर 175 करोड रुपये तक इस उद्देश्य से बढाई गई कि उसके द्वारा देश मे बढती हुई बेकारी को नियन्त्रित किया जा सके। व्यय मे पूरी आयोजना की वृद्धि इस कारण की गई कि उस मे कुछ नए कार्य बढ़ा दिए गए और कुछ कार्यों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम पर किये जानेवाले व्यय का परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा :—

तालिका 84 (करोड रुपयों मे)

	1951–56 का व्यय	कल का प्रतिशत
कृषि और सामूहिक विकास	361	17.5
सिचाई	168	8.1
बहुद्देशीय सिचाई और विद्युत् कार्य	266	12.9
विद्यत्	127	6.1
यातायात और डाक-तार	497	24.0
उद्योग	173	8.4
समाज सेवाएं	340	16.4
पुनर्वास	85	4.1
विविध	52	2.5
योग	2,069	100.0

आयोजना मे देश के कृषि सम्बन्धी विकास, सिंचाई की व्यवस्था तथा बिजली के उत्पादन पर सबसे अधिक बल दिया गया है । भारत में यातायात तथा सवादवहन के साधनों के विकास को भी बहुत ऊचा स्थान दिया गया है । स्वभावत: इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यवसायों के विकास को सीमित करना पड़ा है । स्पष्टत: इसका अभिप्राय यह है कि पचवर्षीय आयोजना के कायकाल मे देश का व्यावसायिक विकास मुख्यत: व्यक्तिगत क्षेत्रो के साधनो तथा प्रेरणा शक्ति पर निर्भर करेगा ।

निम्नलिखित तालिका मे यह दिखाया गया है कि आयोजना द्वारा सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति बढाने के लिए कितनी राशि व्यय की जाएगी ।

तालिका 49

(करोड रुपयो मे)

(1) व्यय जिससे केन्द्रीय और राज्य सरकारो की उत्पादक पूजी बढ़ेगी	1,199
(2) व्यय जो निजी क्षेत्र में उत्पादक पूजी के निर्माण मे योग देगा—	
1. कृषि और ग्राम विकास पर व्यय (सामूहिक विकास योजनाओ और अभावग्रस्त क्षेत्रों के प्रबन्ध-व्यय को छोड कर)	244
2. परिवहन और उद्योग के लिये ऋण . .	47
3. स्थानीय विकास कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये व्यय (सामूहिक योजनाए और स्थानीय कार्य) . .	105
(3) सामाजिक पूजी पर व्यय . . .	425
(4) अवर्गीकृत मदों पर व्यय (अभावग्रस्त क्षेत्रो के व्यय की व्यवस्था सहित)	49
योग ..	2,069

केन्द्र मे तथा राज्यो मे (जम्मू और काश्मीर को छोड कर) विकास का यह व्यय किस तरह बाटा जाएगा, इसका परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा :—

तालिका 50

(करोड़ रुपयों में)

	केन्द्र	भाग 'क' के राज्य	भाग 'ख' के राज्य	भाग 'ग' के राज्य
कृषि और सामूहिक विकास . .	186.3	127.3	37.6	8.7
सिंचाई और बिजली . .	265.9	206.1	81.5	3.5
परिवहन और संचार . .	409.5	56.5	17.4	8.8
उद्योग . . .	146.7	17.9	7.1	0.5
समाज सेवाएं (पुनर्वास सहित) .	191.4	192.3	28.9	10.4
विविध . . .	40.7	10.0	0.7	—
योग .	1,240.5	610.1	173.2	31.9

तालिका 51

(करोड़ रुपयो में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य (जम्मू और काश्मीर सहित)	योग
विकास सम्बन्धी आयोजित व्यय .	1,241	828	2,069
बजट सम्बन्धी स्रोत :—			
(1) चालू आय में से बचत .	330	408	738
(2) पूंजीगत प्राप्तियां (संरक्षित कोष मे से निकाली गई राशियों के अतिरिक्त) .	396	124	520
(3) आयोजना के सम्बन्ध में आन्तरिक अन्तः सरकारी हस्तान्तरण (यथा केन्द्रीय सहायता) . .	(–)229(क)	229(क)	—
	497	761	1,258
बाहरी स्रोतों से प्राप्त . .	156	—	156
योग .	653	761	1,414

शेष 655 करोड रुपए बाह्य सहायता द्वारा, आन्तरिक करों द्वारा, नए ऋणों द्वारा तथा हीनार्थ प्रबन्धन (deficit financing) द्वारा पूरे किए जाएंगे।

पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्य निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए है —

तालिका 52

	1950–51	1955–56
1. कृषि		
खाद्यान्न (ख) (लाख टन) .	52.7	61 6
रूई (लाख गाठें) . .	29.7	42.2
पटसन (लाख गांठें) . .	33.0	53.9
गन्ना (लाख टन) .	5.6	6.3
तिलहन (लाख टन) . . .	5.1	5.5

(क) अनसूचित आदिम जातियों के लिये 4 करोड़ रु० के सरकारी अनुदान सहित, जो आसाम राज्य की अनुसूचित आदिम जाति के लोगो के विकास पर व्यय किया जायेगा।

(ख) इनमें दाल और चना सम्मिलित है। 1949–50 मे उत्पादन (जिसके आधार पर 1955–56 का लक्ष्य निर्धारित किया गया) 540 लाख टन रहा।

2. **सिंचाई और बिजली**

बड़े पैमाने की सिंचाई के साधान (लाख एकड)	50.0	69.7
छोटे पैमाने की सिंचाई के साधान (लाख एकड़)		
बिजली शक्ति (स्थापित सामर्थ्य लाख किलोवाटों में)	2.3	3.5

3. **उद्योग**

लोहा और इस्पात ।		
ढलाई के कारखानो के लिये कच्चा लोहा (लाख टन)	3.5	6.6
तैयार इस्पात (लाख टन)	9.8	13.7
सीमेंट	26.9	48.0
अल्यूमिनियम (हज़ार टन)	3.7	12 0
खादें :		
एमोनियम सल्फेट (हजार टन)	46.3	450.0
सुपरफ़ासफ़ेट	55.1	180.0
ऐंजिन (सख्या)	--	150.0
मशीनो के औज़ार (संख्या हजारो में)	1.1	4 6
पैट्रोल शुद्ध करने का काम		
द्रव पैट्रोल (लाख गैलन)	--	403.0
बिटुमेन (हजार टन)	—	37.5
रुई की बनी हुई वस्तुएं:		
सूत (लाख पौंड):	11,790	16,400
मिल का कपडा (लाख गज)	37,180	47,000
करघे का कपडा (लाख गज)	8,100	17,000
पटसन की वस्तुएं (हज़ार टन)	892	1,200
कृषि सम्बन्धी मशीनें :		
बिजली से चलने वाले पम्प (हजार)	34.3	85.0
डीज़ेल इंजिन (हजार)	5 5	50.0
बाइसिकिल (हजार)	101.0	530 0
पावर अलकोहल (लाख गैलन)	4.7	18.0

4. **परिवहन**

जहाज़रानी (टन) :		
समुद्रतटीय (जी० आर० टी० हजार)	211.0	315.0

समुद्र पार की (जी० आर० टी० हजार) .	173.5	283.0
सड़कें :		
राष्ट्रीय सडके (हजार मील) . .	11.9	12.5
राज्यों की सडके (हजार मील) . .	17 6	20.6
5. शिक्षा (क)		
विद्यार्थी :		
प्राइमरी स्कूल (लाख) . .	151.1	187.9
जुनियर बेसिक स्कूल (लाख) . .	29.0	52.8
सेकेन्डरी स्कूल (लाख) . .	43.9	57.8
औद्योगिक स्कूल (हजार) . .	14.8	21 8
टैकनिकल तथा काम धंधों का शिक्षण देने वाले अन्य स्कूल (हजार) . . .	26.7	43.6
6. स्वास्थ्य		
चिकित्सालय (रोगियो के लिये स्थान की सख्या हजारो मे) .	106.5	117.2
औषधालय (सख्या) :		
शहरी . . .	1,358	1,615
देहाती . . .	5,229	5,840
7. विकास संस्थाएं		
पचायत (हजार) . . .	55 1	69.1
सहकारी सस्थाए (ख) :		
ऋण देने वाली (हजार) . .	87.8	112.5
बिक्री और बाजार व्यवस्था करने वाली (हजार) .	14.7	20.7
बहुद्देशीय (हजार) . . .	31.5	40.5
लिफ्ट सिंचाई (सख्या) . .	192.0	514.0
सहकारी कृषि (सख्या) . .	352.0	975.0
अन्य (हजार) . . .	27.3	35.8
योग (हजार) . . .	161.9	211.1

(क) इन आंकड़ों मे (औद्योगिक स्कूलो को छोड़कर) हैदराबाद, राजस्थान, अजमेर, और विंध्य प्रदेश के आकडे नही है। कुछ मामलों मे कुछ राज्यो के आकडे (जैसे प्राइमरी स्कूलो के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और जूनियर बेसिक और सेकेण्डरी स्कूलो के सम्बन्ध मे मध्य देश) भी इनमे नही है।

(ख) इनमें पंजाब, उडीसा हैदराबाद, पेप्सू तथा भाग 'ग' के अधिकाश राज्यो के आंकड़े सम्मिलित नही है।

1951–52 से लेकर 1953–54 तक आयोजना के लिए वित्त का प्रबन्ध जिस ढंग पर किया गया, उसका परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा—

तालिका 53

आयोजना की वित्त व्यवस्था : 1951–52 से 1953–54

(करोड़ रुपयो मे)

	केन्द्र				राज्य			
	1951–52 (लेखे)	1952–53 संशोधित	1953–54 बजट	1951–56 पचवर्षीय आयोजना	1951–52 (लेखे)	1952–53 संशोधित	1953–54 (बजट)	1951–56 पचवर्षीय आयोजना
आयोजना का व्यय	133 5	165.4	236 9	2,240 5	128 0	157.2	176 1	828.2
बजट सम्बन्धी स्रोत	127.1	56.5	71.3	497 2	79 6	99.5	128.3	760 3
सरकारी आय के स्रोतों से बचत :—								
(क) चालू आय से	121.1	4.2	29.5	160 0	68.8	57.1	63.0	411.7
(ख) रेल से	37 7	20.7	20.4	170 0	—	—	—	—
निजी बचत :—								
(क) जनता मे ऋण	–34 2	—1.2	–16.7	36.0	11 5	15.1	14.1	79 0
(ख) छोटी बचत और अन्य ऋण जिनके लिए कोष न हों (चल ऋणों को छोड़ कर)	48 6	54.4	55.7	270 0	—	—	—	—
(ग) जमा, कोष और अन्य विविध स्रोत (क)	-14 8	25 8	30.8	90 0	–34.0	–17.5	– 2 3	40 8

(क) इस शीर्षक की प्राप्तियो मे परिवर्तन आशिक रूप से राज्य के व्यापारिक लेन देनो के फलस्वरूप है। केन्द्र तथा राज्यो में राजकीय व्यापार पर शुद्ध पूजी विनियोग प्रति वर्ष इस प्रकार है —

		केन्द्र (करोड़ रु०)	राज्य (करोड रु०)
1951–52	(लेखे)	11.3	29 5
1952–53	(संशोधित)	—3 2	—7 1
1953–54	(बजट)	3.2	—7.8

(करोड़ रुपयों में)

	केन्द्र				राज्य			
	1951–52 (लेखे)	1952–53 संशोधित	1953–54 बजट	1951–56 पंचवर्षीय अयोजना	1951–52 (लेखे)	1952–53 संशोधित	1953–54 (बजट)	1951–56 पंचवर्षीय आयोजना
आयोजना सम्बन्धी आन्तरिक अन्त सरकारी हस्तान्तरण (जैसे केन्द्रीय सहायता) (ख)	-31 4	-46 8	-48.4	-228.8	33.3	44 8	53.5	228.8
स्रोतों में कमी	6.4	108.9	165 6	743.3	48 5	57 7	47.8	67.9
बाहरी सहायता	61.7	44 4	27.6	—	—	—	—	—
अनुदान	4.1	13 6	29.7	—	—	—	—	—
ऋण (शुद्ध) (ग)	57 6	30.8	- 2.1	—	—	—	—	—
घाटा—	-55.3	64 5	138.0	—	48.5	57.7	47.8	67.9
पूर्ति के साधन—								
(क) अल्पकालीन ऋणों मे वृद्धि (घ)	-32.2	-13 3	109.9	—	-0.3	20.8	20 8	—
(ख) संरक्षित सिक्युरिटियों की बिक्री (शुद्ध)	-22.2	-5 0	—	—	34.2	32.0	22.0	67.9
(ग) संरक्षित धन में से वापसी	--0.9	82.9	28.1	—	14.6	4.9	5.0	

(ख) केन्द्रीय बजट के आधार पर आगणित "केन्द्रीय सहायता" राज्य-बजटो के आधार पर आगणित "के० स०" से कुछ भिन्न है । 1951–52 और 1952–53 दोनो के आंकड़ो का साथ-साथ लेने पर जो अन्तर है, वह उपेक्षणीय है । भाग "ग" के सभी राज्यो के मामले मे यह मान लिया गया है कि उनके विकास-व्यय की व्यवस्था केन्द्र से मिलने वाले ऋण और अनुदानो मे से की गयी है । भाग "ग" के उन राज्यो के सम्बन्ध मे ऐसा मान लेना ठीक नही जो 1952–53 से अपने राजस्व-बजट अलग तैयार करते है ।

(ग) प्रस्तुत आकड़े पुराने ऋणों के भुगतान के बाद के हैं ।

(घ) राज्यों के मामले में ये ऋण विशेषकर कर्मशियल बैंको से ही मिलते है ।

केन्द्रीय सरकार को 5 वर्षों में यह 726 करोड रुपया इन साधनो से पूरा करना था : आय मे से बचत, रेल मे अधिक आय, राष्ट्रीय ऋण, सार्वजनिक छोटी बचते तथा इसी तरह के अन्य साधन । 1951–53 तक के दो वर्षों मे इन साधनो द्वारा 262 करोड रुपया एकत्र हुआ । राज्यो की सरकारो को 5 वर्षों में 532 करोड रुपया एकत्र करना था, परन्तु 1951–53 के दो वर्षों मे वे केवल 101 करोड रुपया एकत्र कर पाए । इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारो की स्थिति का परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा —

तालिका 54

आयोजना के अन्तर्गत विकास व्यय की प्रगति – केन्द्र तथा राज्य

(लाख रुपयों मे)

विकास शीर्षक	केन्द्रीय सरकार				राज्य			
	व्यय की प्रगति				व्यय की प्रगति			
	1951–52 (वास्तविक)	1952–53 (सशोधित)	1953–54 (बजट)	पाच वर्षों का योग 1951–56	1951–52 (वास्तविक)	1952–53 (सशोधित)	1953–54 (बजट)	पाच वर्षों का योग 1951–56
	1	2	3	4	5	6	7	8
I कृषि और सामूहिक विकास:								
कृषि	171.0	439.0	1,458.0	5,922 0	2,059 5	2,232.0	2 203.4	12,490.0
पशु पालन (दुग्ध व्यवसाय	--	—	1 0	412.0	248 3	217.9	286 0	1,816.5
सहित) जगल	—	—	—	200 0	81 2	114 3	164.5	969 4
सहकारिता	—	—	15 0	50 0	82.0	93.6	106.3	660.2
मछली उद्योग	—	4.0	8 0	51 0	48 9	48 4	69 1	412.6
ग्राम-विकास	—	—	—	—	115 4	156.7	197 1	1,047 1
सामूहिक योजनाए (क)	—	475.0	1,733.0	9 000 0	—	—	—	—
स्थानीय निर्माण कार्य	—	—	300.0	1,500 0	—	—	—	—

(क) सामूहिक योजनाओ पर का व्यय केन्द्र के अन्तर्गत दिखाया गया है । 1952–53 (सशोधित) और 1953–54 (बजट) के व्यय के आकड़ो में राज्यो का वह व्यय सम्मिलित नही है, जिसकी व्यवस्था उन्होने राज्यो के स्रोतो मे से ही की । **विस्तृत आकड़ो की अभी पड़ताल की जा रही है ।**

(लाख रुपयों में)

विकास शीर्षक	केन्द्रीय सरकार — व्यय की प्रगति 1951-52 (वास्तविक) 1	1952-53 (संशोधित) 2	1953-54 (बजट) 3	पांच वर्षों का योग 1951-56 4	राज्य — व्यय की प्रगति 1951-52 (वास्तविक) 5	1952-53 (संशोधित) 6	1953-54 (बजट) 7	पांच वर्षों का योग 1951-56 8
अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम	—	—	400 0	1 500 0	—	—	—	—
योग	171 0	918 0	39,15 0	18,635 0	2,635 3	2,862.0	3,026 4	17,395.8
2 सिंचाई और बिजली :								
बहुद्देशीय कार्य	3,544 0	4,578 0	5,038 0	26,590 0	--	—	--	—
सिंचाई कार्य	—	—	—	--	2,605 1	3,481 7	3,699 6	16,769 7
बिजली कार्य	--	—	--	—	2,148 4	2,560 1	3,022 3	12,754 0
योग	3,544 0	4,578 0	5,038 0	26,590 0	4,753 5	6,041 8	6,721 9	29,523 7
3 परिवहन और सचार—								
रेल (क)	4,085 0	4,670 0	4,961 0	25,000 0	—	—	--	—
सडकें	310 0	702 0	805 0	3,124.0	1,135 7	1,620 4	1,948 8	7,763 6
सडक परिवहन (ख)	20 0	35 0	45 0	—	78 0	262 2	121 1	896 9
जहाजरानी	158 0	124 0	441 0	1,806.0	--	—	—	—
असैनिक उड्डयन	209 0	247 0	400 0	2,287 0	—	--	--	—
बन्दरगाह	113 0	230 0	875 0	3,206.0	6 2	12 1	27 0	102 4
आन्तरिक जल परिवहन	2 0	2 0	4 0	10 0	—	—	—	—
डाक-तार	553 0	602 0	1 017 0	5,000 0	—	—	--	—
प्रसारण	39 0	43 0	71 0	352 0	--	—	—	--
समुद्र पार के सचार	7 0	20 0	34 0	100 0	—	—	—	—
अन्तरिक्षविज्ञान विभाग	—	7 0	7 0	62 0	—	—	—	—
योग	5 496 0	6,682 0	8,660 0	40,947 0	—	—	—	—
4 उद्योग —								
बडे उद्योग	695 0	674 0	1 041 0	12 604 0	249 3	414 7	448 9	1 434 6
कुटीर एव छोटे उद्योग	13 0	18.0	100 0	1,500 0	118 7	142 8	218 3	1,181 5
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान	85 0	108 0	78 0	461 0	—	—	—	—
खनिज विकास	1 0	8 0	23 0	106 0	—	—	--	—
योग	794 0	808 0	1,242 0	14,671 0	368 0	557 5	667 2	2,616 1
5 समाज सेवाए—								
शिक्षा	150 0	333 0	486 0	3,902 0	1,892 7	2,052 3	2,386 1	11,637 7
स्वास्थ्य	9.0	75.0	334 0	1,787.0	1,182.0	1,235.6	1,484.1	8,224.3
गृह निर्माण	168 0	200 0	984 0	3,850 0	111 6	348 4	274 0	1,031 6
श्रम और श्रम कल्याण	46 0	80 0	78 0	397 0	30 2	38 8	35 8	294 3

(क) इनमें वर्तमान सम्पत्तियों के मूल्य ह्रास सम्बन्धी व्यय सम्मिलित नहीं है।

(ख) दिल्ली राज्य के सडक परिवहन का व्यय केन्द्रीय परिवहन मन्त्रालय के अन्तर्गत दिखाया गया है। आयोजना के अनुसार यह 2 16 करोड रुपये है।

तालिका 54--(जारी)

(लाख रुपयों में)

विकास शीर्षक	केन्द्रीय सरकार				राज्य			
	व्यय की प्रगति				व्यय की प्रगति			
	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (संशोधित)	1953-54 (बजट)	पांच वर्षों का योग 1951-56	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (संशोधित)	1953-54 (बजट)	पांच वर्षों का योग 1951-56
	1	2	3	4	5	6	7	8
पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का कल्याण (क) .	—	—	170.0	700 0	339 0	434.4	518 0	2,186 5
योग	373 0	688 0	2,052 0	10,636 0	3,555 5	4,109 5	4698.0	23,374.4
6 पुनर्वास . .	2,866.0	2,638 0	2,270 0	8,500 0	—	—	—	--
7 कार्य और इमारतें .	22 0	106.0	203 0	1,102 0	—	--	—	—
8 वित्तमंत्रालय की योजनाएं	76 0	103 0	174 0	490 0	—	—	—	—
9 उत्तर पूर्वी सीमान्त प्रदेश (ख) .	10 0	18 0	40 0	300 0	—	—	--	—
10. अन्दमान .	—	—	94 0	383 0	—	—	—	—
11. कारपोरेशनों को ऋण	—	—	—	1,200 0	—	—	—	—
12. विविध . . .	—	—	—	600 0	267 9	258.4	402 9	1,148.3
सर्वयोग	13,352 0	16,539 0	23,688 0	1,24,054 0	12,800 1	15,724.8	17,613.3	82 821 2

(क) यह उन अनुदानों से अलग है, जो संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत 1951-56 के लिये 9 करोड़ रुपये के रखे गये हैं, और जो आयोजना के अंश के रूप में दिखाये नहीं गये हैं।

(ख) उत्तर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश में सड़कों पर हुआ व्यय सड़कों के अन्तर्गत दिखाया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों मे कार्य संवृद्धि के लिए राज्यों मे जो विकास व्यय किया जा रहा है, उस उन्नति का परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा :—

तालिका 55

(लाख रुपयों मे)

विकास शीर्षक	व्यय की प्रगति 1951–52 (वास्तविक)	1952–53 (संशोधित)	1953–54 (बजट)	पाच वर्षों का योग 1951-56
कृषि	2,059 5	2,232 0	2,203 4	12,490 0
पशु पालन .	124.8	144 1	180 7	1,035 5
दुग्ध व्यवसाय और दुग्ध व्यवस्था	123 5	73 8	105 3	781 0
जगलात .	81 2	114 3	164 5	969 4
सहकारिता .	82 0	93.6	106 3	660 2
मछली उद्योग .	48 9	48 4	69 1	412.6
ग्राम विकास . .	115 4	156 7	197 1	1,047 1
योग .	2,635 3	2,862 9	3,026 4	17,395 8
सिंचाई योजनाएं	2,605 1	3,481 7	3,699 6	16,769 7
बिजली योजनाए	2,148 4	2,560 1	3,022 3	12,754 0
योग .	4,753 5	6,041 8	6,721 9	29,523 7
कुटीर उद्योग . .	118 7	142 8	218 3	1,181 5
अन्य उद्योग .	249 3	414 7	448 9	1,434 6
योग .	368 0	557.5	667 2	2,616 1
सड़के . .	1,135 7	1,620 4	1,948 8	7,763.6
सड़क परिवहन .	78 0	262 2	121 1	896 9
बन्दरगाह . .	6 2	12 1	27 0	102 4
योग .	1,219 9	1,894 7	2,096 9	8,762.9
शिक्षा . .	1,892.7	2,052 3	2,386 1	11,637 7
चिकित्सा सम्बन्धी .	688 4	649 9	803 4	4,274 7
सार्वजनिक स्वास्थ्य .	493 6	585 7	680 7	3,949 6
गृह निर्माण . .	111 6	348 4	274.0	1,031 6
श्रम और श्रम कल्याण .	30 2	38 8	35 8	294 3
पिछडी जातियों का कल्याण .	339 0	434 4	518 0	2,186 5
योग .	3,555 5	4,109 5	4,698 0	23,374 4
विविध . .	267 9	258.4	402 9	1,148 3
सर्वयोग .	12,800 1	15,724 8	17,613 3	82,821 2

राज्यों के अनुसार विकास व्यय की उन्नति निम्नलिखित तालिका में देखियें :--

तालिका 56

(लाख रुपयों में)

राज्य	व्यय की प्रगति			पाच वर्षों का योग
	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (सशोधित)	1953-54 (बजट)	1951-56
भाग 'क' के राज्य :				
आसाम . .	118 4	234 2	378 0	1,749.2
बिहार	1,372 2	1,197 4	1,356 4	5,729 1
बम्बई .	2,304 7	2,905 9	3,085 9	14,643 3
मध्य प्रदेश .	705.7	849 1	1,038.6	4,308 2
मद्रास . .	2,699.5	2,826 8	2,431 5	14,084.1
उडीसा .	279 1	325 0	427.3	1,784 2
पजाब .	275 3	502 8	628.3	2,020 7
उत्तर प्रदेश . .	1,599 3	2,152 4	2,426 1	9,782 3
पश्चिमी बगाल .	1,015 6	1,407 8	1,473.5	6,909 7
योग .	10,369 8	12,401 4	13 245 6	61,010 8
भाग 'ख' के राज्य :				
हैदराबाद . .	658 9	748.4	781.8	4,155 0
मध्य भारत . .	163.2	267.0	404.0	2,240 0
मैसूर . .	527 1	611 3	580.9	3,660 2
पेप्सू .	59 1	104 8	252.6	814 6
राजस्थान .	213 2	239.8	357.7	1,681 4
सौराष्ट्र	192 5	337 8	446 9	2 040 9
तिरुवाकुर-कोचीन .	407 5	525 1	554 8	2,731 9
योग .	2,221.5	2,834 2	3,378 7	17,324 0
जम्मू और काश्मीर	75.9	128 9	270 2	1,300.0
भाग 'ग' के राज्य :				
अजमेर	10 5	14 8	30 7	157 2
भोपाल .	32 2	66 8	128.6	389 9
बिलासपुर .	2 1	10 8	25.2	57 1

राज्य	व्यय की प्रगति			पाच वर्षों का योग
	1951–52 (वास्तविक)	1952–53 (सशोधित)	1953–54 (बजट)	1951–56
कुर्ग . .	6 2	4 3	20 8	73 0
दिल्ली .	32 2	48 3	62 1	748 0
हिमाचल प्रदेश .	10 0	42 5	149 5	454 6
कच्छ . .	10 6	61 4	89 6	305 3
मणिपुर . .	—	16 8	43 3	154 8
त्रिपुरा . .	5 0	14.7	50 3	207.3
विन्ध्य प्रदेश . .	24 1	79 9	118 7	639 2
योग .	132 9	360 3	718 8	3,186 4
सर्व योग .	12,800 1	15,724 8	17,613.3	82,821.2

भाग 'क' और 'ख' के राज्यो को आयोजना के सम्बन्ध मे जो आर्थिक सहायता केन्द्र की ओर से दी जानी थी, वह इस तालिका मे देखिए —

तालिका 57

(करोड रुपयो मे)

	1951–53	1951–56 पच वर्षीय आयोजना
भाग 'क' के राज्य :		
आसाम	0.8	15.0
बिहार	5.7	15.0
बम्बई	7.0	16 0
मध्यप्रदेश	5.8	12 0
मद्रास	16.4	20 0
उडीसा	3.5	10 0
पजाब	1 8	11.
उत्तर प्रदेश . .	7.4	15
पश्चिमी बंगाल . .	7.3	26.5
योग .	55 7	140.5

	1951–53	1951–56 पच वर्षीय आयोजना
भाग 'ख' के राज्य .		
हैदराबाद	5 9	10·0
मध्यभारत. . . .	1·0	4·0
मैसूर . . .	4·8	8 0
पेप्सू . . .	1·2	2·5
राजस्थान . .	1·2	9·0
सौराष्ट्र	1·8	6 0
त्रिवांकुर-कोचीन . .	0·1	7 0
योग	16 0	46 5
सर्वयोग	71 7	187 0

पचवर्षीय आयोजना की पूर्ति के लिए 1951 से 1953 तक कुल 189 करोड रुपया विभिन्न ढगो की विदेशी सहायता के रूप मे प्राप्त हुआ, जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका मे दिया गया है —

तालिका 58

(करोड रुपये)

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक	
आयोजना से पूर्व काल के ऋणो का बकाया, जो लिया नही गया .	9 0
इस्पात कार्य ऋण (दिसम्बर 1952) . .	15·2
दामोदर घाटी कार्य के लिए ऋण (जनवरी 1953) . .	9 5
अमेरिकी खाद्य ऋण	90·4
कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत अनुदान	
कैनाडा से	13·3
आस्ट्रेलिया से	6·1
न्यूजीलैण्ड से	0·9
अमेरिकी टेक्निकल सहकारिता सहायता	
टैक्निकल सहकारिता करार (जनवरी 1952) . .	23·8
पूरक टैक्निकल सहकारिता करार (नवम्बर 1952) . .	18·0
अन्य सहायता (क)	2·8
योग . .	189·0

(क) इसमे नार्वे और फोर्ड प्रतिष्ठान से मिली सहायता सम्मिलित है ।

दसवां अध्याय

कृषि

कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। इस देश के 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषिजन्य आय पर निर्भर करते हैं, और भारत की राष्ट्रीय आय का 48 प्रतिशत भाग कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है। कुछ कृषिजन्य पदार्थ हमारे यहा के बड़े व्यवसायों के लिए कच्चे माल का काम देते हैं जैसे गन्ना और रूई, और कुछ का निर्यात होता है। लाख (लाक्षा) केवल भारत मे ही पैदा होता है, तथा मूगफली और चाय की दृष्टि से भारत ससार का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी तरह चावल, पटसन, तम्बाकू और रूई के उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान ससार में दूसरा है।

क्षेत्रफल तथा मिट्टी

भारत भर मे कुल मिला कर 26,60,00,000 एकड मे खेती बाडी होती है, उसमे से 3,60,00,000 एकड भूमि, अर्थात् कृषित भूभाग का 13 प्रतिशत, पर वर्ष मे एक से अधिक फसले होती है। इसके अतिरिक्त 1,16,00,000 एकड भूमि ऐसी है, जिस पर खेती-बाडी की जा सकती है, तथा 5,80,00,000 एकड ऐसी भूमि है, जिसे प्रयत्नपूर्वक कृषिसाध्य बनाया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भारत मे खेती बाडी को गुण तथा मात्रा की दृष्टि से बढाने की अभी बहुत गुजाइश है। तालिका सख्या 60 मे कुछ वर्षों की कृषित भूमि की गणनाए दी गई है।

भारत मे प्राप्त होने वाली मिट्टी चार भागो मे बाटी जा सकती है (1) रेत मिली मटियाली, (2) काली, (3) लाल और (4) भूरी। इनमे से पहली तीन किस्म की मिट्टी मे पोटाश और चूना काफी मात्रा में है, परन्तु उसमे फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी है। चौथे किस्म की मिट्टी मे कतिपय रासायनिक पदार्थों की कमी है। इनमे से रेत मिली मटियाली मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, और गगा के मैदानो मे वह बहुतायत से पाई जाती है। दक्षिणी पठार की ओर जो काली मिट्टी पाई जाती है, वह अपने अन्दर नमी को बहुत समय तक सुरक्षित रख सकती है। लाल मिट्टी भारत के पूर्वी भाग मे पाई जाती है। चौथे किस्म की मिट्टी मध्य भारत, आसाम तथा पूर्वी तथा पश्चिमी घाटो मे पाई जाती है।

वर्षा और सिंचाई

भारत की कुल कृषित भूमि के केवल 19 प्रतिशत भाग की ही सिचाई हो पाती है, शेष 81 प्रतिशत भाग केवल वर्षा पर निर्भर करता है। इसी कारण यदि कभी वर्षा समय पर न हो, या कम अधिक हो जाये तो कृषि को बहुत हानि पहुचती है। इसके साथ ही भारतीय कृषि की अन्य दो मुख्य समस्याए ये है: (1) सैकडो वर्षों से लगातार कृषि किए जाने के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है; तथा (2) उत्तराधिकार मे लगातार भूमि का बंटवारा होने के कारण धरती

बहुत छोटे छोटे टुकडों मे बंट गई है। इन दोनों बातो का प्रभाव यह हुआ है कि भारत के किसान काफी गरीब है, तथा इनमे से कुछ लोग ऋणों के बोझ से दबे हुए है।

सिंचाई के सम्बन्ध मे 1947 से 1950 तक क्या स्थिति थी, इसका परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा--

तालिका 59

(हजार एकड)

वर्ष	नहरों से			तालाबों से	कुओ से	अन्य स्रोतो मे	योग
	राज्य	निजी	योग				
1947-48 .	15,304	4,448	19,752	7,991	12,550	6,342	46,635
1948-49 .	15,929	4,524	20,453	7,658	12,643	6,133	46,887
1949-50 .	16,961	2,856	19,817	8,174	12,881	7,780	48,652

जिस भूमि की सिंचाई होती है, उसकी उपज प्राय. असिंचित भूमि की अपेक्षा दुगुनी से चौगुनी तक होती है। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में सिंचाई के विस्तार पर बहुत अधिक बल दिया गया है। आजकल 4,90,00,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, इस संख्या में योजना के अनुसार 1955-56 तक 1,97,00,000 एकड़ भूमि की वृद्धि हो जाएगी।

सिंचाई के जिन बड़े कार्यों पर आजकल काम हो रहा है, आशा है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक उनके द्वारा 85,00,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगेगी, और जब उक्त योजनाओं का पूर्ण विकास हो जाएगा, तब यह संख्या 1,69,00,000 एकड़ तक जा पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई के छोटे साधनों तथा राज्यो की सरकारो और व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा किए गए कार्यों से 1,12,00,000 एकड़ और अधिक भूमि भी सींची जा सकेगी।

भूमि स्वामित्व

भारत मे भूमि स्वामित्व की तीन प्रथाएं प्रचलित है: ज़मीदारी, महलवारी तथा रैयतवारी। ज़मीदारी प्रथा के अनुसार एक या अधिक व्यक्ति भूमि का स्वामी होता है और वह सरकार को लगान देता है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम, उडीसा, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में यह प्रथा प्रचलित है। महलवारी प्रथा के अनुसार गाव के कुछ लोगों या गाव की कुछ जमातो के पास अपने गांव की भूमि का स्वामित्व होता है, जिसमें सब लोग मिल कर और अलग-अलग रूप से लगान

(देखिय पृष्ठ 170)

तालिका 60

भूमि के उपयोग का विवरण

(हजार एकड)

वर्ष	कुल क्षेत्र	क्षेत्र का वर्गीकरण					गाव के कागजो के अनुसार जिन क्षेत्रों के विवरण मौजूद है	एक बार से अधिक बोया जोता गया क्षेत्र	बोया गया कुल क्षेत्र	खेती योग्य भूमि जो ऊसर को छोड कर ऐसी भूमि मे सम्मिलित हो, जो जोती बोयी न गई हो
		जंगलात	खेती के लिये अप्राप्य	ऊसर को छोड कर अन्य भूमि जिसे जोता बोया नहीं गया	ऊसर	बोया जोता गया क्षेत्र				
1939-40	8,10,809	81,835	93,936	19,106	51,093	2,37,159	5,55,204 (क)	30,548	2,67,707	10,610
1948-49 (ख)	8,10,809	86,787	94,897	93,364	62,891	2,43,963	5,82,888 (ग)	33,347	2,77,310	7,521
1949-50 (घ)	8,10,809	93,143	96,024	48,400	58,171	2,66,372	6,14,610 (ङ)	35,514	3,01,886	11,554

(क) इनमे वे 75,000 एकड सम्मिलित है, जिनके बारे मे वर्गीकरण का विवरण अप्राप्य है।

(ख) इनमे वे 9,86,000 एकड सम्मिलित है, जिनके बारे मे वर्गीकरण का विवरण अप्राप्य है।

(ग) इनमे वे 25,00,000 एकड सम्मिलित है, जिनके बारे में वर्गीकरण का विवरण अप्राप्य है।

(घ) अस्थायी।

(ङ) पहले सालो में सीमा विस्तार के कारण 1948-49 और 1949-50 के आंकडों की 1939-40 के आकडो मे तुलना नहीं की जा सकती।

देने के जिम्मेवार होते है । यह प्रथा मध्य प्रदेश, पजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागो मे जारी है । रैयतवारी प्रथा के अनुसार किसान भूमि का स्वामी होता है, और वही लगान देता है । यह प्रथा बम्बई और मद्रास मे है ।

इस तरह राज्य तथा खेती करने वाले किसानो के बीच अन्य मध्यरथों की उपस्थिति से खेती बाड़ी के काम को बाधा पहुचती है । इस कारण राज्यो की सरकारो ने जमीदारी प्रथा को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है । पश्चिमी बगाल को छोड़ कर, भाग 'क' के सभी राज्यो मे जमीदारी प्रथा नष्ट कर देने का कानून बन चुका है । जम्मू और काश्मीर मे भी जमीदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है । हैदराबाद, मध्यभारत, राजस्थान तथा सौराष्ट्र मे इसी उद्देश्य से आजकल कानून बनाए जा रहे है । 1952-53 मे 'ग' भाग के राज्यो मे से भी जमीदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयत्न आरम्भ हो गया है ।

भूदान यज्ञ

अपने आश्रितो का मिला कर भूमिरहित किसानो की सख्या भारत मे $4\frac{1}{2}$ करोड़ है । जमीदारी प्रथा समाप्त हो जाने से, खेती बाडी के इन मजदूरो को कोई लाभ नही हुआ, क्योकि उन्हे भूमि का कोई भाग प्राप्त नही हुआ । इन लोगो के कल्याण के लिए, 3, 4 वर्ष हुए, आचार्य विनोबा भावे ने भारत मे भूदान यज्ञ का प्रारम्भ किया था । इस आन्दोलन को देश के अधिकाश राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दलो का समर्थन प्राप्त है और यह कहा जा सकता है कि गैरसरकारी कार्यो मे आचार्य विनोबा भावे का यह आन्दोलन सबसे बडा आन्दोलन है । इस आन्दोलन द्वारा भारत की सामाजिक कार्यशक्ति तथा त्याग की भावना को एक नया क्षेत्र और स्रोत प्राप्त हो गया है । इस आन्दोलन को पूर्णत सफल और क्रियात्मक बनाने के लिए राज्यो की सरकारो ने आवश्यक कानून पास कर दिए है, ताकि कोई कानूनी अडचन इस आन्दोलन के मार्ग मे खड़ी न हो सके । आचार्य विनोबा भावे ने यह अपील की थी कि अप्रैल 1954 तक उन्हे 25 लाख एकड भूमि इस यज्ञ के लिए प्राप्त हो जाये, परन्तु भारत मे आचार्य विनोबा भावे की यह पुकार इतनी बलवती सिद्ध हुई कि उन्हे इसी अवधि तक $27\frac{1}{2}$ लाख एकड भूमि प्राप्त हो गई । अप्रैल 1954 मे सर्वोदयपुरी मे आचार्य विनोबा भावे ने एक सर्वोदय सम्मेलन बुलाया था, जिसमे उनके 550 कार्यकर्त्ताओ के अतिरिक्त भारत के प्रधान मत्री भी सम्मिलित हुए थे । सितम्बर 1953 तक विभिन्न राज्यो मे भूदान यज्ञ मे प्राप्त होने वाली भूमि की सख्याए इस प्रकार थी :— बिहार 10,75,217 एकड, उत्तर प्रदेश 5,11,417 एकड, राजस्थान 2,17,886 एकड; और हैदराबाद 63,982 एकड । अब तक न सिर्फ उक्त राज्यो मे इस भूमि की मात्रा मे वृद्धि हुई है, बल्कि अन्य राज्यो मे भी भूदान यज्ञ मे भारतीय जनता उत्साह दिखाने लगी है ।

भूदान यज्ञ मे प्राप्त इस भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा गरीब किसानो को आवश्यक साधन जुटाने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने अब कूपदान तथा सम्पत्ति दान यज्ञ भी प्रारम्भ किये है ।

भूमि कर

अग्रेजी राज्य के जमाने मे पश्चिमी बगाल, बिहार, आसाम, मद्रास, उडीसा और उत्तर प्रदेश मे स्थाई बन्दोबस्त की प्रथा विद्यमान थी । जमीदारी प्रथा की समाप्ति के साथ इसे भी समाप्त कर दिया गया । शेष भारत मे अस्थाई बन्दोबस्त की प्रथा थी । विभिन्न राज्यो मे विभिन्न ढगो से

भूमि कर निश्चित किया जाता है। अर्थात् समय समय पर लगान की दरों में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और बिहार में पहले अनुभव के आधार पर लगान निश्चित किया जाता है और महलवारी, रैयतवारी अथवा जमींदारी प्रथा वाले प्रदेशों में लगान की दर निश्चित है। पंजाब में यह 25 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत तथा मद्रास में 50 प्रतिशत है।

भूस्वामित्व के आकार

भारत में औसतन एक भूमिहर किसान के पास 5 एकड़ भूमि है। बम्बई में यह अनुपात 11.7 एकड़, पंजाब में 10 एकड़, उत्तर प्रदेश में 6 एकड़, बंगाल में 4.5 एकड़, मद्रास में 4.4 एकड़ तथा हैदराबाद में 12 एकड़ है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अधिकांश किसानों के पास औसत से बहुत कम भूमि है। मद्रास, बिहार और पश्चिमी बंगाल में 1949–50 में एक कृषि श्रम सम्बन्धी जांच-पड़ताल की गई थी। उसके अनुसार इन राज्यों में अधिकांश किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भूमि इतने छोटे छोटे भागों में बंट गई है कि इस पर अच्छी तरह खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। यहां तक कि पशु तथा खेती बाड़ी का सामान भी बहुत अल्प मात्रा में बंट जाता है और उनसे यथेष्ट लाभ नहीं उठाया जा सकता।

1912 में भारत में इस तरह के प्रयत्न आरम्भ किए गए कि भूमि का यह विभाजन अब और अधिक न बढ़ने पावे। इस कार्य के लिए सहकारी समितियों से सहायता ली गई। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक कार्य पंजाब में हुआ। वहां 1950-51 में 361 सहकारी समितियां थीं और उनकी सदस्य संख्या 1,86,057 थी। इन सहकारी समितियों के पास कुल मिला कर 7,07,000 एकड़ भूमि थी और एकीकरण विभाग की ओर से 3,50,000 एकड़ भूमि एकत्र की गई। सहकारिता आन्दोलन की उन्नति की रफ्तार इस कारण बहुत अधिक नहीं है कि सरकार इस सम्बन्ध में जबर-दस्ती नहीं करना चाहती। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि लोगों को समझा बुझा कर इस कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। कुछ राज्यों में कानून बना कर सहकारी प्रथा जारी की जा रही है। इस सम्बन्ध में सबसे पहला कानून 1928 में मध्य प्रदेश सरकार ने पास किया, उसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी इस सम्बन्ध में कानून पास किए गए: उत्तर प्रदेश (1939), बम्बई (1947), पंजाब (1936 और 1948), दिल्ली (1936 और 1948), जम्मू और काश्मीर (1996 विक्रमी), तथा पेप्सू (2007 विक्रमी)।

सहकारी खेती को भी संगठित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आर्थिक तथा टेक्निकल सहायता देती है। नए विकसित होने वाले प्रदेशों में वह कुछ भूमि भी देती है। लगान में भी कुछ रियायत दी जाती है। आसाम, बम्बई, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में इस आशय के कानून बना दिए गए हैं कि एक निश्चित परिमाण से कम भूमि वाले कुछ निर्दिष्ट किसानों को सहकारी समितियों द्वारा खेती बाड़ी करनी होगी। इस समय बम्बई में 326 सहकारी कृषि समितियां हैं तथा उत्तर प्रदेश में 52। 1951–52 में पंजाब में इस तरह की समितियों की संख्या 194 थी और मद्रास में 41।

पिछले वर्षों में सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति का संचालन ये दो उद्देश्य ध्यान में रख कर किया गया है: (1) भूमि और अधिक हिस्सों में न बटने पाए, साथ ही (2) भूमि कुछ ही व्यक्तियों के पास जमा न हो जाये। बहुत से राज्यों में, उदाहरण के लिए आसाम, उत्तर प्रदेश,

मध्यभारत, जम्मू और काश्मीर, बम्बई, पजाब और पेप्सू मे, कम से कम भूमि और अधिक से अधिक भूमि की मात्रा निश्चित कर दी गई है या की जा रही है ।

कृषि के साधन तथा संगठन

भारत मे किसानो तथा उन पर आश्रित व्यक्तियो की सख्या 24,90,00,000 है । इसमे से दो तिहाई किसान स्वय भूमि के मालिक है, 13 प्रतिशत काश्तकार है और 18 प्रतिशत भूमि-रहित किसान मजदूर । खेतीबाडी का काम न करने वाले मज़दूरो की सख्या लगभग 2 प्रतिशत है । ये लोग या तो अपनी भूमि काश्तकारो को दे देते है और या काश्तकारो को बंटाई पर देते है । कुछ ज़मींदार मज़दूरो द्वारा खेती कराते है । काश्तकारो और भूमिरहित किसान मजदूरो की दशा सुधारने के लिए विभिन्न राज्यों मे समय समय पर कुछ न कुछ नियम बनाए जाते रहे है, परन्तु अभी तक उन्हे बहुत लाभ नही पहुचा । इस तरह का एक कानून बम्बई का 1948 का टैनेन्सी तथा कृषि भूमि कानून था । इस ढग का कानून हैदराबाद, मैसूर और सौराष्ट्र मे भी बनाया गया है । उत्तर प्रदेश मे जमीदारी प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया गया है । भूमिरहित किसान मजदूरो को कम से कम क्या वेतन दिया जाये, इस सम्बन्ध मे भी जाच पडताल की गई, और पजाब, दिल्ली, कच्छ, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, अजमेर तथा बिहार के पटना जिले मे उनके लिए कम से कम वेतन नियत कर दिया गया ।

1949-50 मे भारत मे 26,60,00,000 एकड भूमि पर कृषि की गई थी । इस हिसाब से प्रत्येक कृषिजीवी भारतीय के पीछे एक एकड से कुछ ही अधिक भूमि आती है । इन परिस्थितियों में गहरी खेती से लाभ हो सकता है, परन्तु उसके लिए जितना पानी और खाद आदि चाहिए, वह यथेष्ट मात्रा मे उपलब्ध नही है । इसीलिए पचवर्षीय आयोजना के अनुसार सिंचाई के साधन बढाए जा रहे है । हाल ही मे सिन्द्री मे वैज्ञानिक खादो का जो कारखाना खोला गया है, उससे खाद की कमी दूर होने मे बहुत सहायता मिल रही है ।

भारत के किसान पुराने ढग के और स्थानीय कारीगरो द्वारा बनाए गए औज़ारो से खेती बाडी का काम लेते है । हाल ही मे बहुत अच्छे ढग के हल और सुहागा, चारा काटने की मशीनें, गन्ने से रस निकालने की मशीने पानी खीचने वाले नल आदि बनाने का प्रयत्न शुरू किया गया है । कुछ राज्यो मे ट्रैक्टरो से भी खेतीबाडी करने की कोशिश हो रही है ।

उपज

भारतीय कृषि उत्पादन के दो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहा बहुत तरह की चीजे उत्पन्न होती है तथा उपज मे खाने की वस्तुओं का प्राधान्य रहता है । गरम, समशीतोष्ण अथवा तराई वाले क्षेत्रो की शायद ही कोई ऐसी उपज हो, जो इस देश मे पैदा न होती हो । कुल कृषित भूमि के 85 प्रतिशत भाग पर खाने-पीने की वस्तुए बोई जाती है ।

देश की मुख्य उपजों को दो मुख्य भागो मे बाटा जा सकता है: (1) खरीफ (2) रबी । खरीफ की उपजो मे मुख्यत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्की, रूई, गन्ना तथा मूगफली आदि होती है, और रबी की फसलो मे मुख्यतः गेहू, जौ, चना, तिलहन, सरसो आदि ।

उपज की दृष्टि से भारत का औसत प्रतिवर्ग एकड काफी कम है । इसके मुख्य कारण है, सिंचाई के साधनो की कमी, वर्षा की कमी, बाढे तथा कृषि नाशक बीमारिया ।

तालिका 61

जोता बोया गया क्षेत्र

(हज़ार एकड़ो मे)

वर्ष	अन्न की मुख्य फसले								अन्य मुख्य फसले				
	चावल	गेहू	अन्य अन्न	चना	मूगफली	गन्ना	चाय	कहवा	रूई	पटसन	अन्य तिलहन	तमाखू	रबर
1947	64,692	25,007	89,159	16,971	10,267	3,528	765	212	11.671	652	12,652	845	159
1948	64,415	20,843	86,943	19,336	10,079	4,056	768	215	10,655	841	13,986	827	162
1949	72 485	22,342	91,976	20,497	9,165	3,752	712	218	11,293	1,163	14.421	803	168
1950	75.414	24,114	95.969	20.497	9,832	3,624	777	223	12,173	1,454	15,053	860	171
1951	75,975	24,134	92,930	18,709	11,130	4 214	—	224	14,556	1,951	15.551	902	171
1952	73 665	23,450	95 124	16,857	11,798	4,792	—	—	16,198	1,834	16.590	712	173
1953	74,674	24,041	1.01.081	17,267	11,862	4,376	—	—	15.678	--	15.649	798	—

तालिका 62

मुख्य फसलों का उत्पादन

वर्ष	अन्न की फसलें								अन्य फसलें				
	चावल (हजार टन)	गेहू (हजार टन)	अन्य अन्न (हजार टन)	चना (हजार टन)	मूगफली (हजार टन)	गन्ना, कच्ची खाड, गुड (हजार टन)	चाय (लाख पौड)	कहवा (लाख पौड)	रूई (हजार गाठे)	पटसन (400 पौड की हजार गाठे)	तिलहन (हजार टन)	तमाबू (हजार टन)	रबर (लाख पौड)
1947	21,669	4.971	15.904	3.599	3.588	4 913	5,620	410	2,168	1,658	1,560	270	370
1948	21,247	5,570	16,924	4,503	3.411	5.817	5,760	350	2 188	2,055	1.706	234	350
1949	22.597	5,650	15,067	4.535	2,901	4.869	5.850	350	1 767	3 089	1 601	255	350
1950	23,170	6,290	16,558	3,667	3.379	4 938	6,070	480	2 628	3,301	1,763	264	350
1951	20,295	6.374	15,117	3,593	3.437	5,616	—	540	2 971	4,678	1,666	263	380
1952	20,741	6,039	15,650	3,293	3,045	6 068	—	—	3,133	4,695	1,775	205	440
1953	23.424	6,762	17,398	3.771	2,894	5,260	—	—	3,050	—	1,741	205	—

1951-52 में बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र तथा आंध्र के रायलसीमा जिले मे खाद्यान्नो की न्यूनता की परिस्थिति के कारण उपज अधिक नही बढाई जा सकी। परन्तु 1952-53 में खरीफ की उपज मे 60 लाख एकड (कुल भूमि का 5 5 प्रतिशत) भूमि की वृद्धि की गई। उपज मे वृद्धि स्वभावत. इस अनुपात से तो नही हुई, परन्तु कुछ न कुछ अवश्य हुई । ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की उपज जिस हिसाब से बढी, उसका परिचय निम्नलिखित तालिका मे मिलेगा ।

तालिका 63

फसल	उत्पादन (लाख टन) 1951-52	1952-53	वे राज्य जिन के आकड़े इस मे सम्मिलित नही
चावल . . .	155	163	बिहार, उडीसा, जम्मू और काश्मीर और तिरुवाकुर-कोचीन
ज्वार . .	34	36	बम्बई, पंजाब, मद्रास और राजस्थान
बाजरा . . .	17	18	बम्बई, पजाब और पेप्सू
मक्का . . .	15	17	पजाब, पेप्सू, राजस्थान और जम्मू और काश्मीर

1951-52 मे गन्ना पहले की अपेक्षा अधिक भूमि मे बोया गया, और उस की उपज मे 3 लाख टन की वृद्धि हुई। 1952-53 में उस मे कुछ कमी आई। इस वर्ष तिलहन की उपज, आबोहवा की कुछ प्रतिकूल परिस्थितियो के कारण गत वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हुई ।

परन्तु रूई और पटसन की उपज में काफी वृद्धि हुई। इसका परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा। रूई की उपज मे 1952-53 मे थोडी सी कमी आई। उसका कारण आबोहवा सम्बन्धी विपरीत परिस्थितियो का होना था ।

तालिका 64

वर्ष	रूई (लाख गाठे– प्रति गाठ 392 पौड)	पटसन (प्रति गाठ 400 पौड) (लाख गाठे)
1948-49 . .	17·7	20·6
1949-50 . .	26·3	30·9
1950-51 . .	29·7	33·0
1951-52 . .	31·3	46·8
1952-53 . .	30·5	46·9

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

भारत मुख्यतः कृषिप्रधान देश हे, फिर भी पिछले कुछ वर्षों से वह अपनी आबादी के लिये पर्याप्त अन्न पैदा नही कर पा रहा था। इस सदी की चौथी दशाब्दी के मध्य में अन्नों की उपज से आबादी की वृद्धि की रफ्तार अधिक बढ़ गई। 1937 में बर्मा भारत से पृथक हो गया। बर्मा से बहुत सा चावल भारत आया करता था। अन्न की यह कमी इतनी बढ़ती गई कि 1943 में बंगाल में अत्यन्त भयंकर अकाल पडा। उस के 4 वर्षों के बाद देश का विभाजन हुआ और पंजाब तथा सिध के उपजाऊ इलाके, जहा नहरो से खेती बाड़ी की सिचाई होती थी, तथा पूर्वी बगाल की उपजाऊ नीची भूमिया पाकिस्तान को मिली। इस का परिणाम यह हुआ कि भारत मे न सिर्फ खाद्यान्नो की कमी हो गई, अपितु पटसन और रूई की भी असाधारण कमी हो गई ।

बगाल के अकाल के दिनों में, अर्थात् 1943 में, "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन का प्रारम्भ किया गया था। पिछले 4 वर्षों मे इस कार्य के लिये केन्द्र तथा राज्यों की सरकारे किसानो को आर्थिक सहायता तथा कर्ज देती रही। आजकल केन्द्रीय सरकार केवल कुछ विशेष कार्यक्रमों के लिये ही आर्थिक सहायता दे रही है। इस आन्दोलन के अधीन दो तरह की योजनाये चल रही हैं : (1) नए कार्य तथा (2) आवश्यक पूर्ति के कार्य। पहली योजना के अन्तर्गत, कुएं, तालाब, छोटे बाध, नालिया, ट्यूबवैल और पानी के नलके इत्यादि का निर्माण और मरम्मत हो रही हैं। इसी योजना के अन्तर्गत बेकार पडी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। दूसरी योजना के अन्तर्गत किसानो को अच्छे बीज तथा खाद आदि बाटे जाते हैं। 1951-52 मे इस सम्बन्ध मे यह निश्चय किया गया कि कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की अपेक्षा उत्तम वैज्ञानिक ढग से काम करना अधिक अच्छा रहेगा।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त 1950-51 मे एक सयुक्त उत्पादन कार्यक्रम भी बनाया गया, जिसका उद्देश्य अन्न, रूई, पटसन और चीनी के उत्पादन मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। बाद में यह कार्यक्रम पंचवर्षीय कार्यक्रम मे सम्मिलित कर लिया गया और अब भूमि-सुधार के सम्बन्ध मे एक दस-वर्षीय योजना भी बन चुकी है। इस सम्बन्ध मे राज्यों को जो सहायता दी जा रही है, वह "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत है। "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन का संचालन अब निम्नलिखित नीति के अनुसार हो रहा है

(1) उत्पादन की ऐसी योजनाओ पर अधिक बल दिया जाये, जो स्थायी महत्व की हो, जैसे सिचाई तथा भूमि विकास कार्य आदि ;

(2) ट्यूबवैलो के निर्माण पर विशेष बल दिया जाये ;

(3) अच्छे बीज, खाद, रासायनिक खाद, आदि विशेषत: ऐसे भागो मे दिए जाये जहा सिचाई की निश्चित व्यवस्था हो अथवा यथेष्ट वर्षा की संभावना हो ;

(4) पशु-पालन, मछली उद्योग तथा बागबानी की योजनाओ को विशेष सहायता दी जाये ; और

(5) यह सिद्धान्त बरता जाये कि केन्द्र की सहायता जहा तक सम्भव हो, कर्ज के रूप मे दी जाये ।

कृषि विकास के लिये विभिन्न राज्यो मे 1951-52 में 20,60,00,000 रुपये खर्च किये गये तथा 1952-53 मे 22,30,00,000 रुपये। इस राशि मे से केन्द्रीय सरकार ने 1951-52 मे 17,40,00,000 रुपये दिये (जिसमे से 10,40,00,000 रुपये कर्ज के रूप मे और 7 करोड अनुदान के रूप मे दिये गये) तथा 1952-53 मे 21 करोड रुपये (जिस मे से 14,50,00,000 कर्ज के रूप मे थे और 6,50,00,000 रुपये अनुदान के रूप में) दिए। केन्द्रीय सहायता जिस रूप मे प्राप्त हुई, उसे इस तालिका में देखिये —

तालिका 65

(करोड रुपयो मे)

योजना	1951-52		1952-53	
	राशि रु०	प्रतिशत	राशि रु०	प्रतिशत
सिचाई . . .	10·9	62	13·7	65
भूमि सुधार . . .	1·5	9	1·6	8
बीज, खाद और उर्वरक .	2·7	16	3·3	16
अन्य योजनाए (पौधा-सरक्षण आदि) . .	2·3	13	2·4	11
योग . .	17·4	100	21·0	100

सिंचाई के छोटे कार्यक्रम

1951-52 तथा 1952-53 मे केन्द्र ने राज्यो को जो सहायता दी, उसका 60 प्रतिशत सिचाई के छोटे कार्यक्रमो के लिये था, यथा कुआं और तालाबो की मरम्मत और निर्माण, नलके, बाध तथा नालियो का निर्माण और सुधार आदि। परिणाम यह हुआ कि 1951-52 मे 20,50,000 एकड नई भूमि की सिचाई होने लगी।

तालिका 66

(लाख एकड)

योजना	पाच वर्षो के लिये लक्ष्य	1951-52 मे सीची गई अतिरिक्त भूमि
1. कुआ बनाना और उनकी मरम्मत .	16 .5	3 .6
2 ट्यूब वेल्स . .	6 .6	1 .4
3. पम्प लगाना, जिन मे रहट भी सम्मिलित है .	7 .5	3·4
4 बाध, नालियां आदि .	52·2	12·1
योग . .	82·8	20·5

1951-52 मे उत्तर प्रदेश में 8,687, मद्रास मे 7,288, मध्य भारत में 3,297 और पंजाब में 2,001 नए कुए खोदे गये या उनकी मरम्मत की गई।

शक्ति और तेल से चलने वाले नलके बहुत लोकप्रिय होते जा रहे है। 1951-52 में उनकी संख्या में जो वृद्धि हुई है, वह निम्न तालिका से पता चलेगी :

तालिका 67

राज्य	किसानों को दिये गये एंजिन और पम्प
मद्रास	
(क) तेल से चलने वाले एंजिन . . .	833
(ख) बिजली से चलने वाले एंजिन .	156
मध्य प्रदेश	138
पश्चिमी बगाल	310
पंजाब	76
हैदराबाद	842
मध्य भारत	286
योग . . .	2,641

इसके अतिरिक्त मद्रास तथा उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने क्रमशः 200 और 739 पम्पिग सेट लगाए, जिन से निजी खेतो को पानी दिया जाता है। बम्बई मे यह काम सहकारी समितियों द्वारा हो रहा है और वहा इस उद्देश्य के लिये 250 के लगभग समितियां बनी हुई है।

भारत अमेरिका टैक्निकल सहायता कार्यक्रम के अनुसार जो 2,650 नए ट्यूबवैल लगाने की योजना बनाई गई है, उस के लिये पचवर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किये जाने वाले 30 करोड़ रुपये की राशि मे से काफी बड़ी मात्रा लगाई जा रही है। ये ट्यूबवैल बिहार, उत्तरप्रदेश, पजाब और पेप्सू में लगाए जा रहे है।

नए ट्यूबवैल लगाने के सम्बन्ध मे कुछ राज्यो की योजना निम्नलिखित तालिका मे दिखाई गई है—

तालिका 68

राज्य	लगाये जाने वाले ट्यूबवैलो की सख्या	लगाये गये ट्यूबवैलो की संख्या
उत्तर प्रदेश	440	221
पजाब	225	138
बिहार	300	96
बम्बई	400	26
योग . . .	1,365	481

पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में तालाबों की मरम्मत तथा नालियों का निर्माण आदि कार्य ज़ोरशोर से जारी है। 1951-52 में पश्चिमी बंगाल में इस तरह के 975 कार्य किए गए और उन पर 27,42,000 रुपये खर्च किये गये। इसके अतिरिक्त 22,50,000 रुपये तालाबों की

मरम्मत पर व्यय हुए । आसाम मे 36,51,000 रुपये व्यय कर के इस तरह के 650 कार्य किये गये । उत्तर प्रदेश मे नालियो पर 12 लाख रुपये खर्च हुए और उससे 9,700 एकड भूमि को लाभ पहुचा । मद्रास मे 1,62,00,000 रुपये तालाबो पर खर्च किए गए और 1,34,00,000 रुपये सिचाई के अन्य छोटे कार्यक्रमो पर ।

भूमि का उद्धार तथा विकास

1947 मे अमेरिकन सेना द्वारा छोडे गये 200 ट्रैक्टरो के साथ भारत मे केन्द्रीय ट्रैक्टर सगठन का प्रारम्भ किया गया था । तब से अब तक इस सगठन ने इस देश मे एशिया के कुछ सब से बडे भूमिसुधार कार्य किये है । इस सगठन ने कास तथा गहरी व घनी झाडियो से भरे हुए जगलो को साफ किया है, तथा वृक्षो को गिरा कर कृषि के लिये भूमि प्राप्त की है । 1951 मे इस सगठन के लिये 250 नए ट्रैक्टर खरीदे गये थे और इस कार्य के लिये भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से कर्ज मिला था । 1952 तक निम्नलिखित भूमि का कृषि के लिये उद्धार किया गया--

वर्ष	एकड प्राप्त भूमि
1948-49	71,497
1949-50	79,346
1950-51	2,81,962
1951-52	1,55,367

उक्त सगठन के अतिरिक्त कतिपय राज्यो की सरकारो ने भी इसी तरह के सगठन बना रखे है । ये सगठन निजी कृषिको को भूमि की सिचाई तथा जुताई आदि मे सहायता देते है । इस सम्बन्ध की विस्तृत सख्याये निम्नलिखित तालिका मे देखिये--

तालिका 69

राज्य	ट्रैक्टर सख्या
मद्रास	299
बम्बई	256
उत्तर प्रदेश	492
पजाब	89
मध्य प्रदेश	100
आसाम	40
हैदराबाद	51
मध्य भारत	27

भूमि की सुरक्षा

पचवर्षीय योजना मे 2 करोड रुपये भूमि की सुरक्षा के लिये रखे गये है । जोधपुर मे राजस्थान के रेगिस्तान की वृद्धि को रोकने के लिये एक अनुसन्धान संस्था भी खोली गई है । देहरा-

दून मे जगल अनुसन्धान सस्था (फौरेस्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट) के अधीन भूमि सुरक्षा अनुसन्धान सम्बन्धी शाखा भी खोली गई है ।

इसी उद्देश्य से भूमि के किनारे बनाने का कार्य भी जोरशोर से जारी है । बम्बई मे 1951-52 मे 30 लाख रुपये के व्यय से 50 हजार एकड के किनारे बनाये गये थे, ताकि वह भूमि बिखरने न पाये । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश मे क्रमश 6,67,000 तथा 10,00,000 रुपये के व्यय से 6,300 तथा 10,000 एकड भूमि सीमा-निर्माण तथा बाधो द्वारा सुरक्षित की गई ।

पशु पालन

1951 की गणना के अनुसार भारत मे 15,50,00,000 गाय, बैल आदि, 4,30,00,000 भैसे और 3,90,00,000 भेडे थी । भारत मे कृषि का सब से बडा और महत्वपूर्ण साधन बैल है, तथा देश की अधिकाश जनता के भोजन मे दूध और उस से उत्पन्न होने वाले पदार्थो का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । 3,90,00,000 भेडो मे भारत को यथेष्ट ऊन प्राप्त होती है । (भारत मे बकरियो की सख्या भी 4,70,00,000 है) । भारत की पशु सख्या के लिये निम्नलिखित तालिका देखिये —

तालिका 70 (क)

(हजारो मे)

पशु	1940	1945	1951
गाय बैल	1,37,929	1,36,739	1,55,099 (ख)
भैस	40,125	40,732	43.351
भेड	41,506	37,728	38,829
बकरिया .	50,253	46,302	47,077
घोडे और टट्टू	1,780	1,398	1,514
खच्चर .	50	45	60
गधे	1,186	1,131	1,239
ऊट .	617	656	629
सुअर .	2,702	3,709	4,420
योग . .	2,76,148	2,68,440	2,92,218
मुर्गीपालन			
चिडिया . . .	55,062	54,666	67,135
बत्तखे . . .	2,346	3,581	6,264

(क) 1940 और 1945 के आकडे भिन्न है, क्योकि दोनो जनगणनाओ मे भाग लेने वाले राज्यो की सख्या एक समान नही थी ।

(ख) इनमे 1,000 ऐसे पशु भी सम्मिलित है, जिन का विवरण अप्राप्य है ।

भारत मे सब से अच्छी गाय पजाब के साहीवाल और सौराष्ट्र के गीर मे होती है। सब से अच्छे बैल पजाब के हिसार (हरियाना) और हासी मे, मद्रास के नैलोर और कगायम मे मैसूर के अमृतमहल मे, गुजरात के कगरेज मे, उत्तर प्रदेश के खेरीगढ मे तथा बम्बई के डागी और नीमार मे होते है। दूध के लिये कगरेज और गीर प्रसिद्ध है। सब मे अच्छी भैसो के लिये पजाब का मुर्रा, सौराष्ट्र के जफराबाद और बम्बई के मेहसाना, सूरत और पढरपुर प्रसिद्ध है।

भारत के पशु बहुत अच्छे किस्म के नही होते, क्योकि उनकी नस्ल तथा भोजन पर विशेष ध्यान नही दिया जाता। इस देश मे एक गाय एक वर्ष मे औसतन 413 पौड दूध देती है, जोकि ससार मे सब से न्यून मात्रा है। अधिकाश देशो मे यह मात्रा 2,000 मे 7,000 पौड तक है।

सुधार की योजनाएं

पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत पशुओ के सुधार के सम्बन्ध मे कुछ योजनाए बनाई गई है जो निम्नलिखित है—

1. केन्द्र ग्राम योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारत भर मे ऐसे गाव चुन लिये जायेगे, जिनमे पशुओ की नस्ल सुधारने के लिये कुछ साड रखे जा सके। यथेष्ट मात्रा मे साड नही मिल पाते, इसलिये गायो के वैज्ञानिक गर्भाधान का प्रबन्ध भी किया जा रहा है। 1951-52 मे यह योजना प्रारम्भ की गई थी और एक ही वर्ष मे इस तरह के 96 केन्द्र खोले गये। पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत इस तरह के 600 केन्द्र ग्राम तथा 150 वैज्ञानिक गर्भाधान केन्द्र खोलने का इरादा है।

2. गो-सदन

जहा मुख्य ग्राम योजनाओ का उद्देश्य पशुओ की नस्ल मे सुधार करना है, वहा गो-सदन का उद्देश्य वर्तमान पशुओ, विशेषत गायो की देखभाल करना तथा बेकार के पशुओ का पथकीकरण करना है। योजना के अन्तर्गत 160 गो-सदन बनाए जायेगे।

गउओ की नस्ल सुधारने के लिये 1952 मे केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय गौसवर्धन समिति भी बनाई थी।

दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने अच्छा दूध देने की एक प्रारम्भिक योजना जारी की हुई है, जिसके अनुसार वैज्ञानिक रीति से दूध को शुद्ध कर के 40 केन्द्रो द्वारा नई और पुरानी दिल्ली मे बाटा जाता है।

3. पशुओं का बीमारी से बचाव

भारत मे पशुओ की मृत्यु जिन रोगो से होती है, उनमे रिडरपैस्ट सब से बुरी और भयानक बीमारी है। इस बीमारी को दूर करने के लिये आइजटनगर मे टीके का एक बडा कारखाना खोला गया है। इस के लिये यथेष्ट साधन वहा एकत्र कर लिये गये है।

जंगलात

देश के आर्थिक जीवन मे जगल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । उनसे जलाने की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के अतिरिक्त बास, घास, लाख, गोद, बरोजा, रग आदि उपयोगी और लाभदायक चीजे प्राप्त होती है । पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को सुरक्षित रखने और उसे फटाव से रोकने मे जंगल बडा महत्वपूर्ण भाग लेते है । जगल पशुओ के लिये चरागाह का काम भी देते है । 1894 मे भारतीय जगलो के सम्बन्ध मे तत्कालीन सरकार ने एक अस्पष्ट सी नीति का सूत्रपात किया था । 1951 मे स्वतंत्र भारत मे जगलो के सम्बन्ध मे एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया ।

जंगलों का क्षेत्रफल

भारतीय जगलो का कुल क्षेत्रफल 2,65,932 वर्गमील है, जो देश की कुल भूमि का 21 प्रतिशत भाग है । ससार के अन्य अधिकाश देशो की तुलना मे यह अनुपात कम है । इस कारण 12 मई 1952 के जगल नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार यह निश्चय किया गया कि देश के एक तिहाई भाग पर जगल लगाये जाये । हिमालय, दक्कन तथा अन्य पहाडी क्षेत्रो मे यह अनुपात 60 प्रतिशत रहेगा, तथा मैदानो में 20 प्रतिशत । पचवर्षीय योजना मे 4 करोड एकड़ जमीदारी जगलो को विकसित करने का कार्यक्रम सम्मिलित है । यह कार्य राज्यो की सरकारो के अधीन है । जगल के विकास के लिये निम्नलिखित साधन बरते जायेगे :—

(1) युद्ध के दिनो मे जो जगल काटे गये थे, उनका पुनरुद्धार ;
(2) जिन भूमियो मे बडे-बड़े दरार पड गये है, उन मे जगल बोना ,
(3) जगल की सडको का विकास ;
(4) इंधन की कमी दूर करने के लिये गावो के नजदीक छोटे जगलो का विकास; तथा
(5) देश मे नए-नए और उपयोगी किस्म के वृक्ष लगाने का प्रयत्न करना ।

1949-50 मे देश मे जगल के क्षेत्र इस प्रकार थे :—

	(वर्ग मीलो मे)
(1) भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल	12,66,890
(2) देश मे जगलो का क्षेत्रफल	2,65,932
(क) स्वामित्व	
(1) सरकारी जगल विभाग के अधीन	2,05,272
(2) सहकारी संस्थाओ के अधीन	850
(3) व्यक्तिगत सम्पत्ति	59,810
(ख) जंगलों की किस्में	
(1) व्यापारोपयोगी	1,55,136
(2) अशक्य प्रवेश	54,353
(3) जिसके बारे मे सूचना प्राप्त नहीं	2,56,443

(ग) कानूनी स्थिति

(1) सुरक्षित (रिजर्व)	1,23,665
(2) रक्षित (प्रोटेक्टेड)	37,944
(3) जिसका वर्गीकरण नहीं हुआ	87,371
(4) जिसके बारे में सूचना प्राप्त नही	16,952

(घ) रचना

(1) देवदार वर्ग के	13,983
(2) साल	40,932
(3) सागौन (टीक)	16,874
(4) विविध	1,47,898
(5) जिसके बारे में सूचना प्राप्त नही है	46,245

जंगलों की उपज

युद्ध के दिनो में जंगलों का उपयोग काफी निर्दयता के साथ किया गया था। परिणाम यह हुआ कि बहुत से जंगल नष्ट हो गये। अब जंगलों के पुनर्निर्माण की दृष्टि से प्रति वर्ष 18 लाख टन लकड़ी कम काटी जा रही है।

उत्तरी अदमान के जंगलों से 7,500 टन लकड़ी भारत में लाई गई। यह भी ज्ञात हुआ है कि नीकोबार द्वीपसमूह से भारत को 30 हजार टन लकडी प्रति वर्ष प्राप्त हो सकती है। निचली तालिका में 1949-50 की जंगल की उपज दिखाई गई है—

तालिका 71

जंगलों में पैदा होने वाली वस्तुएं	मात्रा (हजार घनफुट)	मूल्य (रुपयों में)
1. इमारती लकडी	85,208	11,10,45,000
2. लट्ठे	22,822	1,00,38,000
3. लुगदी वाली लकडी	95	'क'
4 जलाने की लकडी	3,72,048	3,21,45,000
5. कोयला	28,571	13,98,000
	5,34,52 'ख'	17,16,48,000 'ग'

'क' इमारती लकडी के अन्तर्गत सम्मिलित

'ख' इस में 25,784 हजार घनफुट सम्मिलित है, जिस के बारे में विवरण अप्राप्य है।

'ग' इस में 1,70,22,000 रुपये सम्मिलित है, जिन के बारे में विवरण अप्राप्य है।

इस वर्ष जगल से होने वाली उपजो की सूची निम्न तालिका में देखिये :—

तालिका 72

जगल मे पैदा होने वाली छोटी वस्तुए	मूल्य (रुपयों में)
पशुजन्य वस्तुए	1,29,000
बास और बेत	1,00,37,000
औषधियां	5,02,000
मसाले	37,000
रेशे और तन्तु	45,000
चारा और चरागाह	1,50,94,000
चारे के अलावा अन्य घास	28,82,000
गोंद और राल	32,72,000
लाख	56,00,000
रबर और पौधो का दूध	5,67,000
सुगन्धित लकडी	6,50,000
चमडा रगने के द्रव्य	19,16,000
वनस्पतिजन्य तेल और तिलहन	1,20,000
अन्य छोटी वस्तुए	1,59,41,000

मछली उद्योग

द्वितीय महायुद्ध के दिनों में जब देश में खाद्यान्नो की कमी हो गई थी, तब मछली उद्योग के महत्व का अनुभव किया गया था। तब से मछली व्यवसाय के विकास का कार्यक्रम भी 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन का भाग बना दिया गया। इस व्यवसाय की उन्नति के लिय अब ये दो काम करने की योजना है—जिन जलाशयों मे मछलियों का विकास किया जा सकता है, उन का परिमापन ; समुद्र के उथले किनारो तथा गहरे समुद्र में से मछली पकडने के लिये नए ढग के छोटे जहाज़ तैयार करना।

मछलियो को बर्फ में सुरक्षित रखने के लिये कालीकट और बगलौर में दो शीत भडार बनाय गये हे। इस कार्य के लिये जापान से कुछ वैज्ञानिक सामान मगाया गया है, तथा 4 विशेषज्ञ भी बुलाये गये है। कुछ विशेषज्ञ इंग्लैंड से भी बुलाये गये है। तिरुवाकुर-कोचीन मे मछली व्यवसाय का विकास करने के लिये नार्वेजियन सहायता कार्यक्रम के अनुसार 38 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

खाद्य के रूप में मछलियों को सुरक्षित रखने का कार्य एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इस के लिये दो साधन बरते जाते है : मछलियो को धूप में सुखाना और उन्हें नमक में रखना। भारत

में अब सारडीन और शार्क मछलियो के लिवर का तेल भी बडे पैमाने पर निकाला जाने लगा है। 1949 मे मछलियो की प्राप्ति इस तरह हुई —

(1) **उत्पत्ति :**

समुद्र की मछली	1,00,80,000 मन
मीठे पानी की मछली	41,30,000 मन
योग . . .	1,42,10,000 मन

(2) **उपयोग :**

जो ताज़ा रूप मे खाई गई	60,76,000 मन
धूप मे सुखाई गई	36,78,000 मन
नमक मे सुरक्षित	35,22,000 मन
मछली के खाद के रूप मे व्यवहृत . . .	9,36,000 मन

बाजार

उत्पन्न वस्तुओ की बिक्री की देखभाल के लिये भारत सरकार का बाजार तथा निरीक्षण डायरेक्टर नियुक्त है। इस तरह के सगठन कुछ राज्यो की सरकारो ने भी बनाये है। 1937 मे कृषि उपज का वर्गीकरण और बाजार का कानून बनाया गया था। यह कानून फल, फलो से बनने वाला सामान, वनस्पति, अडा, दूध, दूध मे बनने वाला सामान, तमाखू, कहवा, चावल, बूरा, आटा, गेहू, गुड, तिलहन, तिल, रूई, लाख, सन, चमडा, खाल, ऊन और बकरियो के बालो, पर लागू होता है। हाल ही मे इस सूची मे लकडी, सख्त बाल, बरोज़ा, तार्पिन, सुपारी आदि बढा दिये गये है। 1948 से ले कर 1952 तक वर्गीकृत पदार्थों की उत्पत्ति इस तरह हुई—

वर्ष	(करोड रुपयो मे)
1948	11.9
1949	12.3
1950	14.0
1951 . . .	13.0
1952	18.0

भारतीय प्लैनिंग कमीशन ने यह निश्चय किया है कि कृषि से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थो का वर्गीकरण अवश्य किया जाए। यह वर्गीकरण का कार्य वर्तमान पचवर्षीय आयोजना मे सम्मिलित है। निम्नलिखित राज्यों में से उपज की बाजार बिक्री के सम्बन्ध मे कानून बनाए गए है : बम्बई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, मद्रास मैसूर, पंजाब तथा पेप्सू तथा मध्य भारत के कुछ भाग।

कृषि अनुसन्धान

भारत के केन्द्रीय कृषि विभाग की स्थापना 1894 मे हुई थी। क्रमशः विकास होते होते 1905 मे पूसा की कृषि अनुसन्धान सस्था खोली गई, तथा 1929 मे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्। इस परिषद् की सलाहकार समिति मे विभिन्न राज्यो, विश्वविद्यालयो और वैज्ञानिक सस्थाओं के प्रतिनिधि है तथा इस की शासन समिति मे सभी भारतीय राज्यो के कृषि मत्री और संसद् मे व्यापारी हितो के प्रतिनिधि सदस्य रूप से सम्मिलित है। शासन समिति को सहायता देने के लिये एक अनसन्धान बोर्ड बनाया गया है, तथा एक विस्तार बोर्ड। देश के विभिन्न क्षेत्रो मे कृषि सम्बन्धी जो अनुसन्धान कार्य हो रहा है, उन सब मे परस्पर समन्वय रखना, उन के कार्यों का बटवारा करना, उन्हे आर्थिक सहायता देना—इस भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कार्य है।

1951 मे इस परिषद् का पूरी तरह पुनर्गठन किया गया। अनुसन्धान विभाग के कार्य-कर्ताओ तथा किसानों मे परस्पर किसी तरह की खाई न रहे, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय पैमाने पर एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओ तथा रूई, गन्ना, तिलहन, तमाखू, नारियल, आदि के उत्पादन मे सुधार करने तथा उनके बाजार को सुगम बनाने के लिय कुछ केन्द्रीय समितियों का निर्माण किया गया है।

अन्न तथा कृषि मंत्रालय विभिन्न अनुसन्धान सस्थाओ मे तालमेल रखने के अतिरिक्त कुछ अनुसन्धान सस्थाओं का संचालन भी करता है। यह कार्य भारतीय कृषि अनसन्धान परिषद्, केन्द्रीय अनुसन्धान सस्था तथा केन्द्रीय पदार्थ कमेटियो द्वारा किया जाता है। 1952-53 मे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने विभिन्न सस्थाओ तथा विश्वविद्यालयो की सहायता से 300 नई स्कीमो का प्रारम्भ किया। इन नई स्कीमो तथा विस्तार सेवाओ पर लगभग 40 लाख रुपये व्यय किये गये। इस वर्ष उक्त योजना के अधीन बम्बई राज्य मे चावल बोने का जापानी तरीका बरता गया, जिस से चावल की उपज मे बहुत वृद्धि हुई। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि चावल बोने का जापानी तरीका देश के अन्य राज्यों मे भी बरता जाए।

केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाएं

दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान शाला कृषि सम्बन्धी ऐसी महत्वपूर्ण समस्याओ पर अनुसन्धान किया करती है, जिनका सम्बन्ध सारे भारत से है; यथा भूमि की उपजाऊ शक्ति की वृद्धि, अच्छे किस्म के बीज जो पानी की कमी, बीमारी, कीटाणुओं आदि को सह सके तथा विभिन्न भूमियो और जलवायुओ मे पनप सके। 1952-53 मे इस सस्था के कार्यों मे वृद्धि की गई तथा भारत-अमेरिकन टेक्निकल सहयोग समझौते के अनुसार कुछ नए कार्य हाथ मे लिये गये। इसी समझौते के अन्तर्गत एक केन्द्रीय अनुसन्धान शाला खोलने का विचार है, जहां पर किसान अपनी भूमियों की मिट्टी की परीक्षा करवा सके। विभिन्न भूमियों मे उपजाऊ शक्ति तथा विभिन्न खाद के उपयोगों के सम्बन्ध मे भी देश मे 6 प्रादेशिक केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है। यह सस्था स्नातकोत्तर शिक्षा देने का काम भी करेगी।

कटक मे जो केन्द्रीय चावल अनुसन्धान सस्था खोली गई है, वह चावल की बनावट, गुण, उपज, विकास, कृषि आदि के सम्बन्ध मे सब तरह की वैज्ञानिक परीक्षा करती है । चावल की उपज किस तरह बढाई जा सकती है तथा उसकी किस्में किस तरह अच्छी की जा सकती है, हरे खाद से क्या लाभ है, इत्यादि के सम्बन्ध मे भी वहा परीक्षण होते है । दक्षिण पूर्व एशिया मे अन्तर्राष्ट्रीय चावल कमीशन द्वारा दिये गये धन से भारतीय किस्म के चावल की परीक्षा के लिए एक पचवर्षीय योजना बनाई गई है । इस मे यह देखा जायेगा कि विभिन्न किस्म के चावलो को एक दूसरे के साथ मिला कर उनकी उपज किस तरह बढाई जा सकती है ।

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान सस्था आलू की किस्म अच्छी बनाने तथा उनकी उपज बढाने के सम्बन्ध मे अनुसन्धान कर रही है । पचवर्षीय योजना के अनुसार आलू का ऐसा बीज तलाश करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिस पर बीमारियो का प्रभाव न पड़े तथा उन्हे चाहे तो पहाड पर और चाहे मैदान मे बोया जा सके । इस तरह के 30 लाख मन आलुओ के बीज पैदा करने का लक्ष्य है । इस योजना पर 14,50,000 रुपया खर्च आयेगा, परन्तु बाद मे यह योजना आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन जायेगी ।

कुल्लू का केन्द्रीय सब्जी उपज केन्द्र ऐसे बीजो की उत्पत्ति का प्रयत्न कर रहा है, जिन में उत्पादन की शक्ति तथा उपज साधारण बीजो की अपेक्षा बहुत अधिक हो ।

1914 मे देहरादून मे जगल अनुसन्धान सस्था की स्थापना की गई थी । यह सस्था कृषि, लकड़ी की रचना, लकड़ी की सुरक्षा, सैल्युलोस और कागज व्यवसाय तथा जगल के अन्य उत्पादनो के सम्बन्ध म अनुसन्धान कार्य करती है । जगलात के अफसरो को भी इस संस्था मे शिक्षा दी जाती है । इन वर्षों मे यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यह सस्था जगल की उपज के अधिकतम और श्रेष्ठ उपयोगों की ओर अपना ध्यान दे ।

आइजटनगर की भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान सस्था की स्थापना 1890 में की गई थी । अब इस संस्था के 6 अनुसन्धान भाग तथा 4 सेना सम्बन्धी भाग है । पशुओ के लिये टीके की दवाइया बनाने के अतिरिक्त यह सस्था विद्यार्थियो को शिक्षा भी देती है । अमेरिका के विशेषज्ञो की सहायता से इस सस्था द्वारा तैयार हुई दवाओ मे उन्नति की गई है । सयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एव कृषि सगठन ने इस सस्था को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र स्वीकार किया है।

बगलोर की भारतीय दुग्ध अनुसन्धान सस्था दुग्धालयो की समस्याओ के सम्बन्ध मे अनुसन्धान करने के अतिरिक्त विद्यार्थियो को शिक्षा भी देती है । इस सस्था मे अच्छे दर्जे की गाय और बैल उत्पन्न करने का प्रयत्न भी किया जाता है । करनाल और कोयम्बटूर मे भी दो पशु केन्द्र खोले गए है, तथा आनन्द मे एक विशेष दुग्धालय का प्रबन्ध किया गया है ।

नामकुम मे भारतीय लाख अनुसन्धान सस्था लाख सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य कर रही है ।

पदार्थ समितिया

भारत मे विभिन्न स्थानो पर रूई, पटसन, तिलहन, गन्ना, नारियल, सुपारी और तमाखू के सम्बन्ध मे अनुसन्धान करने के लिये भारतीय केन्द्रीय समितिया बनाई गई है ।

रूई समिति

भारत में लम्बे रेशे की रूई की कमी को पूरा करने के लिये भारतीय केन्द्रीय रूई समिति की स्थापना की गई है। इसका मुख्य केन्द्र इन्दौर में है। मध्य प्रदेश की सरकार से भी इस संस्था को सहायता मिलती है। यह संस्था रूई सम्बन्धी प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही है।

पटसन समिति

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति अनुसन्धान तथा विस्तार के सम्बन्ध में यह कार्य कर रही है :

(1) पटसन कृषि अनुसन्धान संस्था का संचालन,

(2) टैक्नोलौजिकल अनुसन्धान परीक्षण संस्था का संचालन,

(3) आर्थिक अनुसन्धान विभाग, तथा

(4) प्रकाशन विभाग का संचालन।

यह समिति कलकत्ता विश्वविद्यालय, बोस अनुसन्धान संस्था तथा कलकत्ता के प्रेजिडैन्सी कालेज के सहयोग से काम कर रही है।

तिलहन समिति

आइजटनगर में तेल सम्बन्धी अनुसन्धान जारी है, जहां घानी का तेल, खली आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान होता है।

गन्ना समिति

1936 में कानपुर में गन्ना अनुसन्धान के बारे में एक संस्था की स्थापना हुई थी। आजकल भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति इस संस्था का संचालन कर रही है। गन्ना सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं और प्रश्नों पर अनुसन्धान करने के अतिरिक्त यह संस्था चीनी के कारखानों के लिये दक्ष कार्यकर्ता भी तैयार करती है। पिछले वर्षों में इस संस्था ने इस बात का अध्ययन किया है कि चीनी बनाने के काम में गन्धक का प्रयोग आवश्यक है या नहीं।

नारियल समिति

कासरागोड और कायागुलम में भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के दो अनुसन्धान केन्द्र हैं। इस के अतिरिक्त तिरुवांकुर कोचीन में 3 तथा उडीसा में 1 क्षेत्रीय केन्द्र भी हैं। इन में से कासरागोड की संस्था ही प्रति वर्ष 10,000 पौधे तैयार करती है।

सुपारी समिति

सुपारी समिति के अधीन सुपारी की उपज की वृद्धि के लिए मैसूर, तिरुवानकुर-कोचीन और दक्षिण कनारा आदि में भी केन्द्र खोले गये हैं। सुपारी सम्बन्धी अनुसन्धानों में यह समिति सहायता देती है।

इसी तरह की महत्वपूर्ण अनुसन्धान सस्थाओ मे दिल्ली की फल अनुसन्धान सस्था तथा बैरकपुर, मडप्पम, और बम्बई की मछली अनुसन्धान सस्थाये भी है ।

उपर्युक्त सब संस्थाओ के अतिरिक्त भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयो के साथ 22 कृषि महाविद्यालय भी जारी है । इन मे से कितने ही महाविद्यालयो मे अनुसन्धान का बहुत अच्छा प्रबन्ध है ।

विस्तार

1952 मे अनुसन्धान के कार्यकर्ताओ तथा किसानो मे पारस्परिक दूरी को मिटाने के लिये विस्तार सगठन का प्रारम्भ किया गया था । इस विषय का अध्ययन करने के लिये कुछ व्यक्ति अमेरिका और जापान भेजे गये थे । जनवरी 1952 मे फोर्ड फाउडेशन के साथ भारत सरकार का यह समझौता हुआ कि भारत के विभिन्न राज्यो मे 5 विस्तार योजना के शिक्षा केन्द्र तथा 15 गहरे विकास केन्द्र खोले जायें। प्रत्येक केन्द्र मे 50 कार्यकर्ताओ को शिक्षा देने का निश्चय हुआ और यह भी निश्चय हुआ कि वे आसपास के 100 गावो मे उपयोगी कार्य करेगे । पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत सामूहिक योजना के अनसार इसी तरह के 25 और नए केन्द्र भी खोलने का निश्चय हुआ, जहा गावो के दर्जे के कार्यकर्ताओ को तैयार किया जाएगा ।

तालिका 73

फसलो का प्रारम्भ

फसल	समय
खरीफ फसल . .	I नवम्बर
रबी "	I मई
चावल	I नवम्बर
गेहू . .	I मई
गन्ना	I नवम्बर
रूई .	I सितम्बर
पटसन . .	I जुलाई
खरीफ तिलहन . . .	I नवम्बर
रबी तिलहन . . .	I अप्रैल
चाय	I जनवरी
कहवा	I जुलाई

नोट—समय के प्रारम्भ से अभिप्राय है, जब फसल बाजार मे आने लगती है ।

तालिका 74

फसल समय-कलैण्डर

मुख्य फसलें, ऋतु और समय

फसल	ऋतु	समय (क)	
चावल (ख) . .	जाडा . . .	5 ½–6	महीने
	पतझड़ .	4–4½	"
	गर्मी . . .	2– 3	"
गेहू . . .	रबी . .	5–5½	"
ज्वार . . .	खरीफ . .	4 ½–5½	"
	रबी . . .	4 ½ - 5	"
	जाइद खरीफ . .	2 ½	"
बाजर . . .	खरीफ .	4 ½	"
मक्का . . .	खरीफ . .	4–4½	"
रागी . . .	खरीफ . .	3½	"
जौ . . .	रबी . . .	5–5 ½	"
चना . . .	रबी . . .	6	"
गन्ना . . .	सालभर . .	12–15	"
तिल . . .	खरीफ . .	3 ½–4	"
	रबी . . .	5	"
मूगफली . .	खरीफ . .	पहले की 4–4½	"
		बाद की 4 ½–5	"
सरसो और राई . .	रबी . . .	4–5	"
	जाइद रबी . .	4	"
अलसी . . .	रबी . . .	5–5½	"
अरण्डी . . .	खरीफ . .	पहले की 6	"
		बाद की 8	"
रूई . . .	खरीफ	पहले की 6–7	"
		बाद की 7–8	"
पटसन . . .	खरीफ . .	6–7	"

(क) इस से उन महीनो से तात्पर्य है जिन दिनो फसल ज़मीन पर रहती है।

(ख) चावल की ऋतुए विभिन्न राज्यो मे विभिन्न नामो से प्रचलित है

आसाम . .	पतझड़ अथवा 'आहू' अथवा 'औस'	बम्बई	पहले की
	जाडा अथवा 'साली' अथवा 'बाओ'		बीच की
	बसन्त अथवा 'बोरो'		बाद की
प० बगाल .	पतझड़ अथवा 'भदोई' अथवा 'औस'	मध्यप्रदेश .	पहले की
	जाडा अथवा 'अमन'		बाद की
	गर्मी अथवा 'बारो'		
बिहार . .	पतझड अथवा 'भदोई' . .	मद्रास .	पहली फसल
	जाडा अथवा 'अगहनी'		दूसरी "
उडीसा .	पतझड अथवा 'भदोई' . .	उत्तरप्रदेश	पहले की
	जाडा		बाद की

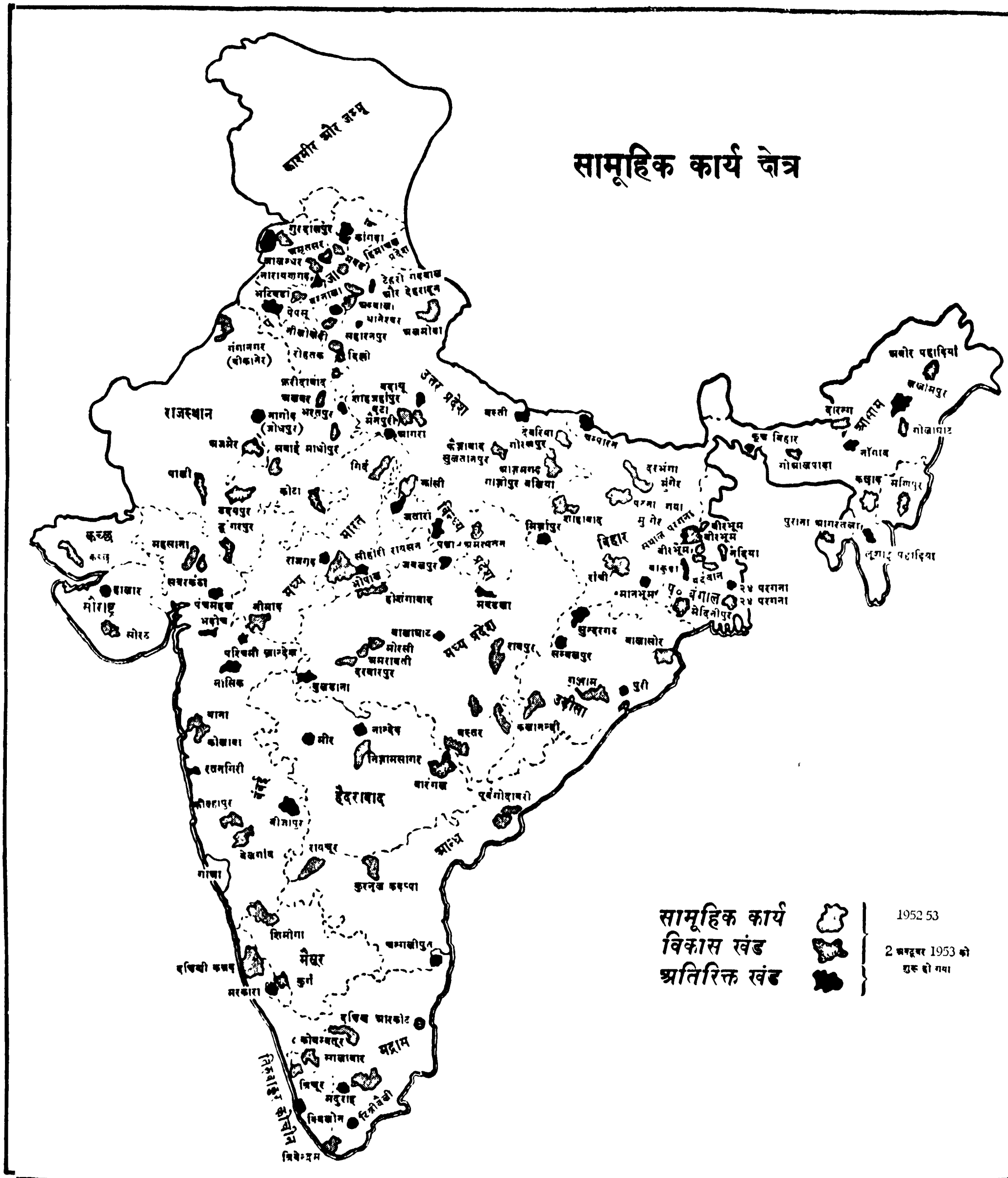
सामूहिक कार्य क्षेत्र
काश्मीर और जम्मू
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
मध्य भारत
मध्य प्रदेश
बिहार
उड़ीसा
हैदराबाद
आन्ध्र
मैसूर
मद्रास
कच्छ
सौराष्ट्र
सामूहिक कार्य
विकास खंड
अतिरिक्त खंड
1952 53
2 अक्टूबर 1953 को शुरु हो गया

ग्यारहवां अध्याय

सामूहिक विकास

1946 से भारत के कुछ राज्यों में ग्राम विकास सम्बन्धी परीक्षण किये जा रहे थे। उदाहरण के लिये मध्यप्रदेश के सेवाग्राम में, बम्बई के सर्वोदय केन्द्रों मे, मद्रास की फिरका विकास योजना के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर जिलो में। इन कार्यो की सफलता से उत्साहित होकर ही आयोजना कमीशन ने ग्राम विकास योजनाओ के कार्यक्रम को अपन पंचवर्षीय कार्यक्रम का आन्तरिक अग बना लिया। तदनुसार, आयोजना कमीशन ने सामुदायिक योजनाओं के लिये तथा आगामी 10 वर्षों मे देश भर मे विस्तार योजनाओ का जाल बिछा देने के लिये 90 करोड रुपया रखा है। गहरे विकास के लिये केवल वही स्थान चुने गये है, जहा यथेष्ट वर्षा होती है तथा जहा की भूमि बहुत उपजाऊ है।

२ अक्तूबर 1952 को भारत के विभिन्न राज्यो में इस तरह के 55 कार्य प्रारम्भ किये गये। इन मे से प्रत्येक कार्य का क्षेत्र 300 गावो तक विस्तृत है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल औसतन 450 से 500 वर्ग मील है; आबादी लगभग 2 लाख है तथा कृषित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1,50,000 एकड। प्रत्येक कार्य का क्षेत्र 3 विकास खंडो मे विभाजित किया गया है। प्रति 5 गावो के पीछे एक ग्राम सेवक रखा गया है। सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रम में दो तरह के कार्य सम्मिलित किये गये हैं। कुछ कार्य केवल ग्राम विस्तार सम्बन्धी है, और कुछ कार्य मिले-जुले। इन दूसरे किस्म के कामो मे छोटे और बीच के व्यवसायो का विकास तथा कस्बो का निर्माण भी सम्मिलित है।

उद्देश्य

सामूहिक विकास कार्यों के आधारभूत उद्देश्य निम्नलिखित है—(1) प्रत्येक सभव उपाय से कृषि की उपज बढाना, (2) ग्रामीण इलाको मे बेकारी की समस्या को हल करना, (3) गाव के संचार साधनो को सुधारना, (4) गाव मे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरजन के केन्द्रो का प्रबन्ध करना, तथा (5) मकानो मे सुधार तथा देशी कारीगरी और छोटे व्यवसायो को उन्नति देना। सामूहिक विकास कार्यक्रमो की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रामवासी उन में कितनी और कैसी दिलचस्पी लेते है। सरकार तो उन्हे इस सम्बन्ध मे मार्ग ही दिखा सकती है और उन के कार्यों में यत्किंचित सहायता दे सकती है।

आर्थिक प्रबन्ध

प्रत्येक कार्य के क्षेत्र मे यह बात आधारभूत बातो मे से मानी गई है कि ग्रामवासी यथेष्ट आर्थिक सहायता देंगे तथा स्वय कार्य भी करेगे। इन कार्यों के लिये सरकार जो सहायता देगी, उस में केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों द्वारा दी गई अनावर्तक (नौन रिकरिंग) सहायता का अनुपात 3 और 1 रहेगा। व्यय सम्बन्धी आवर्तक (रिकरिंग) सहायता केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें बराबर बराबर देंगी। यह आशा की जाती है कि 3 वर्षों के बाद इन कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार को सहायता देनें की जरूरत नहीं रहेगी। गाव में किये जाने वाले सामूहिक

कार्यों पर 3 वर्षों मे लगभग 65 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे, जिन मे से 6,53,000 रुपये डालर व्यय के रूप मे होगे। सामूहिक विकास के प्रत्येक शहरी कार्यक्रम पर 3 वर्षो मे 1,11,00,000 रुपये व्यय किये जायेगे, जिसमे से 45,00,000 रुपये डालर व्यय के रूप मे होगे।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

2 अक्तूबर 1953 को, अर्थात् महात्मा गाधी के चौरासीवे जन्म दिन, भारत मे मुख्यतः ग्रामो की उन्नति के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना का प्रारम्भ किया गया। पचवर्षीय योजना के कार्यकाल मे, आशा है कि, भारत का एक चौथाई काम इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा तथा 10 वर्षों में भारत भर के गावो मे इस योजना के अनुसार कार्य होने लगेगा। सामूहिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओ का आधारभूत उद्देश्य एक ही है, इसलिये अब केन्द्र में तथा राज्यो मे इन मे परस्पर समन्वय कर दिया गया है। इन विस्तार सेवाओ का उद्देश्य यह है कि गावो के किसान वर्तमान वैज्ञानिक ढग से खेती करने लगे तथा सब क्षेत्रो (मानसिक, सामाजिक, आर्थिक आदि) मे उनका दृष्टि- कोण विशाल बन जाये।

विस्तार कार्यक्रम तथा सामूहिक विकास कार्यक्रम अब एक साथ चलाये जायेगे, केवल इस अन्तर के साथ कि सामूहिक कार्यक्रमो का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होगा तथा उन पर अधिक रुपये व्यय किये जायेगे। 1956 तक देश मे 1,200 विकास खड बन जायेगे, जिनमे से प्रत्येक मे 100 गाव होंगे, जिन की औसतन आबादी लगभग 66,000 होगी। इस तरह देश के ग्रामीण भाग का एक चौथाई भाग इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा। इन 1,200 खडो मे से 300 खडों मे सामूहिक विकास कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। शेष 900 मे राष्ट्रीय विस्तार सेवाए इस प्रकार प्रारम्भ की जायेगी . 1953-54 मे लगभग 180, 1954-55 मे 270 तथा 1955-56 मे 450। इनमे से 500 खडो मे सामूहिक योजनाओ के ढग पर गहरे विकास का कार्य किया जायेगा। इस तरह देश की लगभग 4,62,00,000 आबादी सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत आ जायेगी। राष्ट्रीय विस्तार सेवाओ के लिये क्षेत्रो का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि किस स्थान पर कितने आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत उपलब्ध हो सकते है तथा वहा के लोगो मे योजना के लिये कितना उत्साह है। व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के लिये प्रत्येक खड मे एक सब-डिवीजनल अफसर या सब-कलक्टर रखा जायेगा।

वित्तीय प्रबन्ध

पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार इस कार्य पर कुल मिला कर 101 करोड रुपया व्यय किया जायेगा। इसमे से अनावर्तक व्यय का 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी तथा आवर्तक व्यय का 50 प्रतिशत। शेष व्यय राज्यो की सरकारे करेगी। इस योजना के कार्यकर्ताओ पर जो व्यय आयगा, उसका 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी। योजना पूरी हो जाने के बाद भी यह कार्यकर्ता काम करते रहेगे। इस तरह इस कार्य द्वारा 85,000 व्यक्तियो को रोजगार मिल सकेगा, जिनमे अधिकाश टेक्निशियन तथा शिक्षित कार्यकर्त्ता होगे।

कार्यकर्ताओं को शिक्षा

विस्तार योजना के कार्यक्रम की सफलता काफी अशों तक योजना के कार्यकर्ताओ की योग्यता पर निर्भर करती है। इस कारण ग्रामसेवकों को शिक्षा देने के लिये देश के विभिन्न भागो में 35 शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। इनके अतिरिक्त अगस्त 1953 मे अलाहाबाद, गांधीधाम, हैदराबाद, नीलोखेडी तथा शान्तिनिकेतन में सामाजिक सेवा के कार्यकर्ताओ के लिये 5 शिक्षा-केन्द्र खोले गये है। राज्यो की सरकारो द्वारा चुने हुए व्यक्ति इन शिक्षा केन्द्रो मे शिक्षा के लिये भेजे जाते है। शिक्षा की समाप्ति के बाद ये कार्यकर्ता अपने राज्यों मे कार्य करते है। केन्द्रीय सरकार का शिक्षा मत्रालय भी इस सम्बन्ध मे कार्यकर्ताओ को शिक्षा देने का यथासम्भव प्रबन्ध करता रहता है। इस योजना का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि लोग इन कार्यों मे स्वय मेहनत करे और व्यावसायिक कार्यों के लिये आवश्यक रुपये भी स्वय दे। यह काम तभी सभव है, जबकि लोग मिलजुल कर मेहनत करे और मिलजुल कर सामूहिक हितकर कार्यो के लिये रुपये लगाये। इसके लिये जनता का दृष्टिकोण बदलने की भी आवश्यकता होगी। सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार योजना द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता का दृष्टिकोण बदलना तथा उन्हे ग्रामो के सर्वतोमुखी विकास मे अधिकतम सहायता देना है।

संगठन

इन विकास कार्यक्रमों के सचालन का उत्तरदायित्व मुख्यत राज्यों की सरकारो पर है। प्राय प्रत्येक राज्य मे इन कार्यो के लिये एक प्रमुख अधिकारी सस्था नियुक्त की गई है। इस सस्था को राज्य विकास समिति कहते है। इसमे राज्य के मुख्य मत्री, विकास मत्री तथा कुछ गैर-सरकारी सदस्य होते है। यह समिति नीति सम्बन्धी बातो का निर्णय करती है। राज्य का विकास कमिश्नर इस समिति का मत्री होता है, वही राज्य के विकास विभाग तथा इस योजना के कार्यो मे तालमेल पैदा करता है। यह कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि विकास कमिश्नर को राज्य के सचिव का ओहदा दिया गया है, तथा उसे यथेष्ट अधिकार प्राप्त है।

जिले की विकास समिति का अध्यक्ष कलक्टर होता है, और जिला विकास अफसर इस समिति का मत्री होता है। जिले मे विकास सम्बन्धी कार्य करने वाले सभी विभागो के मुखिया और जिला बोर्ड का चैयरमैन तथा वाइस चैयरमेन इस समिति के सदस्य होते है।

सब-डिवीजन मे यह कार्य करने के लिये एक विस्तार अधिकारी नियुक्त किया गया है। आवश्यकतानुसार इस ढाचे मे यथेष्ट परिवर्तन करने का अधिकार भी राज्य के अधिकारियो को प्राप्त है।

योजना मे ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये भारत सेवक समाज नामक एक राजनीति रहित स्वयसेवक सगठन कार्य कर रहा है।

तालिका 75

सामूहिक योजनाएं

गांव, जनसंख्या और क्षेत्र

राज्य	कार्य का नाम	गावों की सख्या	जनसख्या (हजारों मे)	क्षेत्र (वर्ग-मील)
भाग 'क' के राज्य				
1 आसाम .	1. कछाड (सोनई-गिलचर) आदि	508	313	513
	2 दराग (मौजा डकुवा) . .	413	101	424
	3. गारो पहाडिया (ग्वालपाडा क्षेत्र)	72	20	50
	4 गोलाघाट-मिकिर पहाडी क्षेत्र	95	36	.
2 बिहार .	1. पूसा-समस्तीपुर-बेगुसराय क्षेत्र	612	516 5	450
	2 देहरी-भबुआ-मोहनिया क्षेत्र	538	196	450
	3 ओरमाझी-राची मडी क्षेत्र	343	207	450
	4. जहानाबाद-एकगरसराय बिहार-बडबीघा क्षेत्र . .	600	460	500
	5. सथाल परगना रानेश्वर खड	160	37	100
3. बम्बई .	1. महसाना जिला (बीजापुर-कलोल-तहसीले) .	204	442	627
	2 कोल्हापुर जिला (करवीर पनहाला तहसीले) . . .	209	363	477
	3 थाना कोलाबा जिला (कल्याण करजट खालापुर तहसीले)	520	468	550
	4 बेलगाव जिला (हुक्करी-गोकक तहसीले) . . .	209	377	965
	5. साबरकन्ठा जिला . .	120	69.4	.
4. मध्य प्रदेश .	1. चावल क्षेत्र (रायपुर धामतरी)	302	106.9	500
	2. गेहू क्षेत्र (होशगाबाद सोहागपुर)	293	175	600
	3 ज्वार क्षेत्र (अमरावती-मोरसी-दरियापुर) . . .	270	221	525
	4. बस्तर जिला	..	..	..
5. मद्रास .	1. करनूल-कुड्डपाह नहर क्षेत्र .	179	595.8	851
	2. कोयम्बटूर (गोबी ऐरोद-भवानी धारपुरम तहसील) . .	188	551	323
	3. मालाबार (पालघाट) .	123	586	496
	4. पूर्वी गोदावरी (काकिनाडा-पेड्डु-पुरम)	242	758	561
	5 दक्षिण कनारा (कराईकाल-मंगलोर)	442	622	745
	6. मदुराई (नीलकोट्टाई-मैलूर- मदुराई) . . .	279	327.8	943

राज्य	कार्य का नाम	गावों की सख्या	जनसख्या (हजारो मे)	क्षेत्र (वर्ग-मील)
6. उडीसा .	1. भद्रक . .	553	173.6	460
	2. कलहन्दी जिला (धर्मगढ सबडिवीजन)	338	171.6	637
	3. गजाम जिला (धुमसर तहसील)	307	140	493
7. पंजाब .	1. गुरदासपुर ज़िला (बटाला तहसील)	495	339	472
	2. अम्बाला जिला (जगाधरी तहसील)	384	208	488
	3 जालधर जिला(नवानशहर तहसील)	292	222.3	299
	4. सोनीपत तहसील . .	241	253.5	..
	5. फरीदाबाद . .	..	23 15	..
	6. नीलोखेड़ी . .	123	..	..
8. उत्तर प्रदेश	1. गोरखपुर ज़िला (महाराजगज सदर तहसील)	257	166	155
	2. आजमगढ़ जिला (घोसी-मुहम्मदाबाद गोहाना तहसील)	386	206.9	178
	3. फैजाबाद ज़िला (बीकापुर तहसील)	177	126	177
	4. मैनपुरी तहसील . .	177	159	180
	5 झासी जिला (गरौठा-मौरानीपुर तहसील)	339	200	1,000
	6. अल्मोड़ा तहसील . .	756	107	700
9. पश्चिम बंगाल	1. झाडग्राम जिला . .	295	30.7	50
	2. शक्तिगर . .	127	66	101
	3. गुस्कारा . .	110	74	50
	4. नलहटी . .	82	61.6	50
	5. मुहम्मद बाज़ार . .	125	33.8	50
	6. अहमदपुर . .	104	32	50
	7. फूलिया . .	96	49.3	82
	8. बरुईपुर . .	100	78.6	50
भाग 'ख' के राज्य				
10. हैदराबाद	1. निजामसागर . .	..		
	2. रायचूर ज़िला (कोप्पाल-गंगावती सिधनूर) . .	63	80	460
	3. वारंगल जिला . .	..	..	..
11. मध्य भारत	1. गिर्द ज़िला (घाटीगांव-पिछौर तहसील)	247	97.2	453
	2. निमाड़ ज़िला (राजपुर कसरावर्द तहसील) . .	307	153	690
12 मैसूर .	1. शिमोगा ज़िला (शिकारीपुर-सोराब क्षेत्र) . . .	480	130	795

राज्य	योजना का नाम	गांवों की संख्या	जनसंख्या (हजा ों में)	क्षेत्र (वर्ग-मील)
13. पेप्सू .	1. धुरी तहसील . .	107	111	276
14. राजस्थान	1. बीकानेर (गगानगर जिला राय-सिंह नगर और अनूपगढ तह-सील) . . .	58	83	340
	2. सवाई माधोपुर जिला (हिंन्दुआ तह-सील) . . .	103	79.8	176
	3. अलवर (अलवर जिला) .	100	..	
	4. कोटा (कोटा जिला बारन तहसील)	103	62.5	239
	5. जोधपुर-पाली जिला (जोधपुर)	..	..	
	6. उदयपुर । उदयपुर जिला (राज-समन्द और रेलमगडा तहसील) .	100	68.6	190
	7. भील क्षेत्र डूंगरपुर जिला (अनु-सूचित आदिमजातिया)	..	..	..
15. सौराष्ट्र .	1. सोरठ जिला (मानवदार-वनथली तहसील) . .	106	144	378
16. तिरूवाकुर-कोचीन	1. कुन्नतनाड चलाकुदी-क्षेत्र (त्रिचूर जिला)	229	..	458
	2. कैयाटिनकरा-विलावनकोड-क्षेत्र (त्रिवेन्द्रम जिला) . .	334	656	399
भाग 'ग' के राज्य				
17. अजमेर .	1. अजमेर सबडिवीजन .	106	116 8	441
18 बिलासपुर	1. सदर तहसील . .	342	40	154
19. भापाल .	1. सिहोरे और रायसेन जिले (गोहर-गज हुसूर-सिहोरे-इच्छवार तह-सील) . .	354	247	671
20. कुर्ग	1. शनिवारसन्थे हुबली-सोमवारपेट नाड फ्रेजर पेट, हुबली नोटिफाइड क्षेत्र . . .	105	229	..
21. दिल्ली .	1. अलिपुर क्षेत्र .	100	360	574
22 हिमाचल प्रदेश	1 सिरमूर-पौण्टा तहसीलें .	121	30	68
	2. मडी-सदर-सर्वाघाट-चचिओट-सुन्दरनगर . .	626	69	168
	3. महाशिव जिला (कुनिहार)	108	14	..
23 कच्छ .	1 नखतराना-भुज तहसील .	118	85	540
24. मणिपुर .	1. थौबल तहसील .	127	77	200
25. त्रिपुरा .	1. नूतनहवेली और पुराना अगरताला	270	48	166
26 विन्ध्य प्रदेश	1. अमरपाटन तहसील . .	108	..	216
27. उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश	1. अबोर जिला पासीघाट .	37	13.5	..

तालिका 76

विकास व्यय

(करोड रुपयों मे)

	व्यय	केन्द्र का अश	राज्यो का अश	अल्पकालीन ऋण
1 900 राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास क्षेत्रो का व्यय	38 3	16 6	6.4	15 3
2 शिक्षण योजनाओ आदि के लिए व्यवस्था				
3 टेकनिकल कोआपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम स० 8 (डालर व्यय सहित) के अन्तर्गत	(क)	5	(क)	..
55 वर्तमान सामूहिक विकास योजनाओ और 55 अतिरिक्त विकास क्षेत्रो का व्यय	46 7	37 9	8.8	..
4 सामूहिक विकास कार्यक्रम के अनुसार 400 गहरे विकास क्षेत्रो का व्यय .	16 6	13 8	2 8	..
योजना के समय मे कुल व्यय	101 6	73 3	18 0	15 3
योजना के समय के बाद का व्यय (29 2+25 4) .	54 6	33 9	9 0	11 7
कार्यक्रम का कुल व्यय	156 2	107 2	27 0	27 0

(क) व्यय बाटने का प्रश्न विचाराधीन है, पर यह मान लिया गया है कि केन्द्र का अश 5 करोड रुपये होगा ।

तालिका 77

वे साधन जो 1951–56 में प्राप्त हो सकेंगे

(करोड रुपयो मे)

1 आयोजना मे सामूहिक विकास योजनाओ के लिये निर्धारित	90
2 कृषि के लिय मध्यम और दीर्घकालीन ऋण (आयोजना मे 'कृषि' के अन्तर्गत निर्धारित 10 करोड रुपये का आधा)	5
3 शिक्षा . (सामाजिक और बुनियादी शिक्षा के लिये निर्धारित कुल 20 करोड रुपये का 1/3)	7
4. आयोजना मे राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिये निर्धारित .	3
5 पशुपालन और आदर्श ग्राम योजनाएं (आयोजना म निर्धारित 4.1 करोड रुपये का 1/4 .	1
योग	106

नोट:—ये साधन उन साधनो के अलावा होगे जो राज्य सरकारो को अधिक अन्न उपजाओ योजना छोटी सिचाई योजनाओ; शिक्षा, स्वास्थ्य, सचार आदि सम्बन्धी योजनाओ के अन्तर्गत प्राप्त होगे और जो राज्य सरकारो की पचवर्षीय आयोजना मे सम्मिलित है ।

बारहवां अध्याय

विद्युत शक्ति तथा सिंचाई

शक्ति

भारत मे पानी से निकलने वाली बिजली का पहला कारखाना 1897-98 मे दार्जिलिंग मे लगाया गया था। 1925 तक पानी से निकलने वाली बिजली कुल मिला कर 1,62,341 किलोवाट थी। 10 वर्षों के बाद अर्थात 1935 में यह मात्रा 9,00,402 किलोवाट हो गई। 1945 से ले कर 1951 तक पानी से निकलने वाली बिजली का जो विकास हुआ, वह निम्नलिखित तालिका मे दिखाया गया है। इस तालिका मे 1939 को आधार वर्ष मान कर 100 के बराबर दिखाया गया है।

तालिका 78

बिजली की प्रगति के सूचक अंक

मद	1939	1945	1951
स्थापित विद्युत क्षमता			
स्टीम प्लान्ट (भाफ का कारखाना) .	100	126 2	203.0
आयल प्लान्ट (तेल का कारखाना) .	100	106 9	187.4
हाइड्रो प्लान्ट (जल विद्युत ,,)	100	107 3	130 1
योग . .	100	116.8	171 6
विद्युत उत्पादन			
स्टीम प्लान्ट . . .	100	170.1	267.8
आयल प्लान्ट . . .	100	126 9	226.4
हाइड्रो प्लान्ट . . .	100	160 9	218.7
योग . .	100	163.5	239 9
कोयले की खपत . . .	100	164.4	262.7
जलाने के तेल की खपत .	100	121.1	201.1
औसतन अधिक से अधिक मांग .	100	146.2	209.3
जिन कार्यों को बिजली बेची गई			
घरेलू अथवा निवास सम्बन्धी .	100	159.2	363.5
कमर्शियल और छोटे इजिन . .	100	212.4	378.0
औद्योगिक . . .	100	174.0	225.5
ट्रैक्शन . . .	100	125 2	153 4
सिंचाई . . .	100	145.2	315 5
सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानो की रोशनी	100	71.1	145 7
वाटर वर्क्स . .	100	152 6	236.2
योग . .	100	164.4	265.6

किलोवाट से 6,12,00,00,000 किलोवाट हो गई । अर्थात् 5 वर्ष पहले की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक । इसी समय म भाप का शक्त का क्षमता 54 5 प्रतिशत बढ गई । इस वृद्धि का परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा .—

तालिका 79

बिजली की प्रगति 1939–51

वर्ष	बिजली के यत्रो की स्थापित विद्युत क्षमता				वर्ष भर की अधिकतम माग की औसत	उत्पादित बिजली (किलोवाट)	उत्पादित बिजली औसत क्षमता का प्रति किलोवाट	बेची गई बिजली (किलोवाट)		
	स्टीम	डीज़ल	हाइड्रो	योग						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	किलोवाट	किलोवाट	किलोवाट	किलोवाट	किलोवाट	लाख	किलोवाट	लाख	प्रतिशत	प्रतिशत
1939	5,40,760	86,790	4,42,169	10,69,719	5,75,810	24 424 15	2,283	20,346 36	48 42	53 8
1940	5,71,250	89,691	4,59,369	11,20,310	6 28 630	27,020 56	2,412	22,499 71	49 07	56.1
1941	5,97,900	90,845	4,59,369	11,48,114	6,64,270	31,208 17	2,718	26,634.15	53.63	57 8
1942	5,82,028	89,542	4 59,369	11,30,939	6,95,802	31,601 87	2,794	26,626 28	51 85	61 5
1943	6,34,580	89,337	4,58,129	11,82,046	7,12,525	34,451 95	2,933	28,997 16	55.66	60 3
1944	6,51,235	90,171	4,69,419	12,10,825	7,87,848	37,198 41	3,072	31,314 15	53 90	65.1
1945	6,82,220	92,815	4,74,419	12,49,454	8,41,682	39,928 43	3,196	33,448 03	54 15	67.4
1946	7,25,185	91,920	4,84,419	13,01,524	8,19,182	38,922 76	2,991	32,578 02	52 24	62.9
1947	7,57,457	97,679	5,08,129	13,63,265	8,82,853	40,733 18	2,988	33,567 94	52 67	64.8
1948	7,88,393	1,07,019	5,15,554	14,10 966	9,65,780	45,754 66	3,243	37,214 64	51 08	68.4
1949	8,52,639	1,25,468	5,59,079	15,37,186	10,08 000	49,092 89	3,194	40,047 16	55.60	65 6
1950	10,04,434	1,48,796	5,59,285	17,12,515	10 98,014	51,067 00	2,981	41,566.57	53 08	64.1
1951	10,97,567	1,62,680	5,75,179	18,35,426	12,05,194	58,584 03	3,192	47,933.44	55.49	65.7

तालिका 80

सार्वजनिक उपयोग के बिजली उत्पादक केन्द्र

	केन्द्रसंख्या		स्थापित विद्युत क्षमता		अधिकतम माँग		उत्पादित बिजली		बेची गई कुल बिजली		औद्योगिक रेलवे मशीनों की क्षमता	मशीनों की क्षमता
			(किलोवाट)		(किलोवाट)		(लाख किलोवाट)		(लाख किलोवाट)		(किलोवाट)	(किलोवाट)
	1947 (क)	1953 (ख)	1947 (क)	1953 (ख)	1946	1952	1946	1952	1946	1952	1952	1952
आसाम	8	9	2 708	3 525	1,678	2 690	43 80	73 50	33 64	62 54	2 096	2 154
बिहार	17	22	31 822	48 542	19 193	27 529	818 31	1,233 85	736 89	1 333 76	3,09,213	10 596
बम्बई	95	124	3 40 445	4 96 506	2 60 395	3 75 253	13 218 27	17 936 17	11 214 51	15,475 37	81 478	5 516
मद्रास	26	30	1 53 067	2,11 913	1,00 500	1 84 271	4,041.10	7 988 87	3 244 35	6,185 94	13 115	1 396
मध्य प्रदेश	27	34	24,393	58 108	11 607	30 029	403 63	1 192 61	336 89	783 40	26 604	128
उडीसा	6	20	1 570	8 180	851	5 144	24 56	82 63	19 83	60 26	13 933	36
पंजाब	23	29	55 989	72 006	33 545	44 630	1 581 52	1 952 23	1 296 37	1 025 92	6 586	568
उत्तर प्रदेश	28	46	1 68,130	2 11 823	90 064	1 25,373	4 290 36	6 037 95	3 514 70	4 849 08	27 648	9 175
प० बंगाल	15	26	3 55,115	5 46 378	1 88 820	2 84 974	8 377 43	12 896 11	7,275 18	11 460 24	1,56,150	13 110
जम्मू और काश्मीर	3	6	4 270	6 479	3,961	4 228	229 67	267 15	157 18	171 64	—	—
हैदराबाद	7	10	20 551	26 800	7 916	11 771	315 79	555 47	280 70	408 86	28 669	—
मध्य भारत	16	29	8 474	14,995	4 840	8,100	207 27	315 74	150 88	258 05	12 702	15
पेप्सू	6	10	3,313	6 896	1 396	2,244	49 71	67 60	35 68	131 35	9 235	85
राजस्थान	16	30	12 543	30 897	7 182	14,628	318 02	631 45	232 65	475 91	15,943	198
सौराष्ट्र	17	33	8 883	25 550	4 583	12 667	185 25	438 52	157 80	361 91	3 324	82
त्रावनकोर-कोचीन	6	7	19 866	42,186	12 132	33 423	797 40	1 855 81	726 98	1 504 69	1 014	—
मैसूर	2	3	59,200	1 79 200	56 500	1 09,200	3 047 79	5 989 59	2 387 65	4 138 60	2 980	—
दिल्ली	3	5	29 285	62 613	19 681	30,030	902 41	1 516 07	768 41	1 232 35	10,804	—
अन्य	15	22	4,267	9,158	2,453	4,521	95 19	172 15	74 19	136 95	5 067	2 150

(क) जैसी स्थिति 1 जनवरी को थी।

तालिका 81

बिजली का विकास (1952)

राज्य	स्थापित विद्युत क्षमता (किलोवाट)			उत्पादित बिजली (किलोवाट घटे)			
	योग	प्रति 1,000 की जनसख्या के पीछे	प्रति वर्ग मील	योग (लाख)	प्रति 1,000 की जनसंख्या के पीछे	प्रति वर्ग मील	प्रति व्यक्ति के पीछे बिजली की वार्षिक खपत (किलोवाट घटे)
आसाम	3,525	0·367	0 041	73 50	765	86	0·65
पश्चिमी बगाल	5,46,378	22·022	17·752	12,896 11	51,980	41,899	46·10
बिहार	48,542	1 207	0·690	1,233 86	3,068	1,754	3·31
केन्द्र द्वारा प्रशासितक्षेत्र	4,96,506	13·809	4·456	17,936·17	49,884	16,096	43·04
(क) दिल्ली	62,613	35·902	108·327	1,516·07	86,931	2,62,296	70·66
(ख) अन्य	9,158	1·091	0·113	172 15	2.050	213	1·63
हदराबाद	26,800	1·437	0·326	555·47	2,978	676	2·19
जम्मू और कश्मीर	6,479	1·469	0 070	267 15	6,058	288	3·89
मध्य भारत	14,995	1·885	0 323	315 74	3,970	679	3·24
मध्य प्रदेश	58,108	2·735	0·446	1,192 61	5,613	915	3·69
मद्रास	2,11,913	3 717	1·658	7 988 87	14,012	6,252	10·85
मैसूर	1,79,200	19·747	6 077	5 989 59	66,001	20,311	45·60
उड़ीसा	8,180	0·559	0·136	82 63	564	137	0·41
पेप्सू	6,896	2·884	0·684	67 60	1,935	671	3·76
पजाब	72,006	5·696	1 926	1,952·23	15,444	5,223	8·12
राजस्थान	30,897	2·021	0·237	631 45	4.130	485	3·11
सौराष्ट्र	25,550	6·176	1·191	438 52	10,600	2,044	8·75
त्रावनकोर-कोचीन	42,186	4·546	4·614	1,855 81	19,998	20,295	16·21
उत्तर प्रदेश	2,11,823	3·351	1·868	6,037 95	9,551	5,324	7 67
योग	20,61,755	5·699	1·624	61,203 47	16,916	औसत 4,821	13·83

राज्यों के हिसाब से विभाजन

प्रारम्भ में बिजली का प्रयोग केवल भारतीय नगरों को प्रकाश देने के कार्य मे किया जाता था । तब व्यवसाय और कृषि म बिजली का प्रयोग नही किया गया था । धीरे धीरे व्यवसाय में बिजली का प्रयोग प्रारम्भ हुआ और क्रमश· स्थिति यहा तक पहुच गई कि देश में कुल उत्पादित बिजली का 64 प्रतिशत भाग व्यवसाय पर व्यय होने लगा । इस सम्बन्ध मे विभिन्न राज्यों म बहुत बडा भेद पाया जाता है । राज्यों के हिसाब से प्रति व्यक्ति सब से ज्यादा बिजली का व्यय दिल्ली मे होता है । इसके बाद पश्चिमी बगाल में और तदनन्तर मैसूर और बम्बई मे । भारत मे 1952 में बिजली का औसतन प्रति व्यक्ति व्यय 13 83 किलोवाट था, जबकि 1940 मे यह औसत 7·1 किलोवाट था ।

स्वामित्व

1925 तक बिजली कम्पनिया प्राय· व्यक्तिगत सगठनो के हाथ मे थी । इन कम्पनियो को बिजली का लायसेंस दिया जाता था । उसके बाद कुछ राज्यो ने बिजली विकास सम्बन्धी कार्य अपने हाथों मे ले लिया । 1952 तक व्यक्तिगत कम्पनिया 52 प्रतिशत बिजली निकाल रही थी । विस्तृत सख्याए निम्नलिखित तालिका मे देखिए —

तालिका 82

स्वामित्व	सस्थाओ की सख्या	स्थापित विद्युत क्षमता (किलोवाट)
सरकारी . .	190	8,57,545
म्युनिसिपलिटिया . .	14	25,191
प्राइवेट कम्पनिया . .	220	11,79,019
योग .	424	20,61,755

1952 मे विभिन्न व्यवसायो, रेलवे, विभिन्न सरकारी सस्थाओ तथा व्यक्तिगत कम्पनियो के अधीन बिजली उत्पन्न करने वाले कारखानो की सख्या निम्नलिखित तालिका मे दी गई है —

तालिका 83

उद्योग	चालू बिजली केन्द्रो की सख्या	स्थापित विद्युत क्षमता (किलोवाट)
लोहा तथा इस्पात (रोलिंग मिल्स सहित) .	7	1,79,665
वस्त्र :		
(क) सूती . . .	144	91,102
(ख) ऊनी . .	5	3,833

उद्योग	चालू बिजली केन्द्रों की संख्या	स्थापित विद्युत क्षमता (किलोवाट)
सीमेंट		
(क) प्राइमरी .	19	1,05,855
(ख) सेकन्डरी . .	19	1,910
रासायनिक पदार्थ . .	8	19,000
कोयला (खान) .	48	70,296
खाद . .	1	80,000
पटसन .	38	44.646
रेलवे .	84	45.209
कागज . .	15	46,300
चीनी	103	35 770
अल्युमीनियम (प्राइमरी) .	3	16,482
तांबा (प्राइमरी) .	1	9,875
अन्य . .	25	21,827
योग . .	520	7,71,770

व्यय

बिजली का व्यय विभिन्न श्रेणियों मे किस तरह होता है, उसके लिए निम्नलिखित तालिका देखिए—

तालिका 84

उपयोग के प्रकार	उपभोक्ताओं की संख्या		सम्बन्धित भार		बिजली की बिक्री	
	योग	योग का प्रतिशत	योग	योग का प्रतिशत	लाख किलोवाट घंटे	योग का प्रतिशत
1 **घरेलू** निवास स्थानों की रोशनी और छोटी मशीनें .	14,35,661	78	9,42,258	27	6,288.82	12 6
2. **व्यापारिक** हलकी और छोटी मशीनें	3,02,393	16	3,29,036	9	3,363 28	6 7
3. औद्योगिक बिजली (बिजली, ट्राम व ट्रेन तथा वाटर वर्क्स सहित)	74,063	4	19,95,830	28	37,510.38	74.9
4. सार्वजनिक स्थानों का प्रकाश .	2,645	..	24,688	1	739 42	1.5
5. सिंचाई .	28,710	2	1,61,389	5	2,151 92	4 3
योग .	18,43,472	100	34,53,201	100	50,056.82	100 0

गांवों का विद्युतीकरण

अब तक बिजली मुख्यतः नगरों को ही प्राप्त है। कुछ कारखाने गावों की आवश्यकताओं के लिए भी बिजली देते हैं। मद्रास, मैसूर, ट्रावनकोर कोचीन, उत्तर प्रदेश और पजाब के गावो मे बिजली की माग क्रमशः बढ रही है। इस सम्बन्ध मे 1952 की गणनाए इस प्रकार है। देखिए तालिका 85—

तालिका 85

	जनसख्या (1951 की जनगणना के अनुसार)	इस ग्रुप के कस्बे और गाव (स०)	कस्बे और गाव जहा बिजली पहुचती है	कुल गाव और नगरों का प्रतिशत
1	1 00 000 से अधिक	73	73	100 00
2	50 000 से 1,00,000	111	109	98 20
3	20 000 से 50,000	401	308	76 81
4	10,000 से 20,000	856		
5	5 000 से 10,000	3,101	4 028	0 72
6	5,000 से कम	5,56,565		
	योग	5,61,107	4,518	0 81

इन सख्याओं से यह स्पष्ट है कि अधिकाश बिजली शहरो के उपयोग मे ही आती है। भारत मे कुल मिला कर जितनी बिजली पैदा होती है, उसका 38 प्रतिशत भाग केवल बम्बई और कलकत्ता मे ही व्यय हो जाता है। शेष बिजली का 13 प्रतिशत भाग अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास और दिल्ली मे व्यय होता है। इस तरह ये 6 नगर ही भारत मे उत्पन्न होने वाली कुल बिजली की पूर्ण उत्पादन क्षमता की दृष्टि से प्रतिशत 51 तथा उत्पन्न बिजली का 54 प्रतिशत व्यय करते है।

सरकारी नीति

शासन

कुछ समय पहले तक बिजली के उत्पादन तथा वितरण के सम्बन्ध मे भारत सरकार की नीति भारतीय बिजली कानून 1910 के अनुसार बरती जाती थी। इस कानून का उद्देश्य बिजली सम्बन्धी सभी बातो को मर्यादा मे रखना था। बिजली शक्ति के विकास को प्रोत्साहित करने वाली कोई बात इस कानून मे नही थी। स्वाधीनता से पहले तत्कालीन सरकार ने भारत मे बिजली की उन्नति की ओर कभी कोई विशेष ध्यान नही दिया था। केवल 1921 मे एक कमीशन द्वारा इस बात की जाच-पडताल की गई थी कि पानी द्वारा बिजली कहा कहा से निकाली जा सकती है। द्वितीय महायुद्ध के दिनो मे युद्ध सम्बन्धी उत्पादन का प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने 1941 मे एक बिजली कमीशन की नियुक्ति की थी। 1945 मे इसी काम के लिए एक केन्द्रीय टेक्निकल पावर बोर्ड बनाया गया, जिसे 1948 मे इलैक्ट्रिकल कमीशन मे मिला दिया गया। मितव्ययता तथा कार्य सचालन मे श्रेष्ठता लाने के उद्देश्य से हाल ही मे केन्द्रीय बिजली कमीशन, केन्द्रीय जल शक्ति, सिंचाई और जहाजरानी कमीशन मिला कर एक कर दिये गये है और उनका

सम्मिलित नाम 'केन्द्रीय विद्युत तथा शक्ति कमीशन' रख दिया गया है। इस कमीशन के अधीन ये कार्य है—बिजली सम्बन्धी सब तरह की छानबीन, परिमाप, अनुसधान, परीक्षण और प्रचार मे समन्वय तथा सहयोग उत्पन्न करना, और केन्द्रीय तथा राज्यो की सरकारो के विद्युत विकास तथा जल विद्युत निर्माण के कार्यों मे सहायता तथा सलाह देना।

बिजली बनाने के कार्यो मे शीघ्रता लाने के उद्देश्य से पार्लियामेट ने भी 1948 मे विद्युत कानून पास किया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय बिजली बोर्ड नाम से एक केन्द्रीय बिजली शासन सस्था की स्थापना की गई है। यह शासन सस्था 1950 मे बना दी गई, इसमे 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य है। मध्यप्रदेश और दिल्ली मे भी 'राज्य बिजली बोर्डो' की स्थापना हो चुकी है।

केन्द्रीय बिजली शासन सस्था के ये कार्य है —

(1) भारत के लिए एक समान राष्ट्रीय बिजली नीति बनाना और इस सम्बन्ध मे जो आयोजना सम्बन्धी सस्थाए काम कर रही है, उनके कार्यो मे सहयोग और समन्वय उत्पन्न करना,

(2) यदि कभी राज्यो की सरकारो या राज्यो के बिजली बोर्डो मे अथवा लायसेंसदारो मे कोई झगडा हो जाय, तो उनमे मध्यस्थता का काम करना;

(3) बिजली की उत्पत्ति, विभाजन तथा व्यय और शक्ति के विकास के लिए सब तरह की जानकारी एकत्र करना और आवश्यक सूचनाए प्रकाशित करना,

(4) जनता को इस सम्बन्ध मे आवश्यक सूचनाए देते रहना।

राज्यो के बिजली बोर्डों के ये कार्य है --

(1) अपने क्षेत्र मे बिजली की उत्पत्ति तथा वितरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाना और बिजली के कारखानो को सब तरह की आवश्यक सहायता देना;

(2) जहा आवश्यक हो वहा वर्तमान लायसेंस प्राप्त सस्थाओ को बिजली देना;

(3) जहा आवश्यकता हो वहा वर्तमान बिजली उत्पादक कारखानो को नियत्रित कारखाने घोषित करना; और

(4) लायसेंस प्राप्त सस्थाओ को कम से कम व्यय पर अधिकाधिक बिजली उत्पन्न करने के कार्य मे नियुक्त और तत्पर रखना।

1948 के इस कानून द्वारा पुराने लायसेंस प्राप्त सस्थाओ के कार्य मे विशेष परिवर्तन करने का प्रयत्न नही किया जाएगा। यह प्रयत्न किया जाएगा कि राज्यो के बिजली बोर्डों को उन सस्थाओ की सेवाए अधिकतम रूप मे प्राप्त हो सके। राज्यो के यह बोर्ड गावों मे बिजली पहुचाने की ओर विशेष ध्यान देगे।

स्रोत तथा सीमाएं

भारत के विस्तृत क्षेत्रफल और बड़ी आबादी की दृष्टि से इस देश में बिजली बहुत कम उत्पादन की जा रही है। इस सम्बन्ध में संसार के अन्य

देशो मे स्थिति और उनके साथ भारत की तुलना तालिका 86 मे देखिए —

तालिका 86

बिजली सम्बन्धी आंकड़े (क)

(एक तुलनात्मक अध्ययन)

देश	क्षेत्र (हजार वर्ग मील)	जनसख्या (लाख)	बिजली का उत्पादन (लाख किलोवाट घटे)	प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन (किलोवाट घटे)	जनसख्या (प्रति वर्ग मील)
नार्वे . .	126	33.27	1,83,960	5,529	27
कनाडा	3,700	144 30	6,17,860	4,282	4
स्वीडन	173	71 26	2,06,930	2,904	41
अमेरिका	3,738	1,569 81	39,89,230	2,541	42
स्विटजरलैण्ड	16	48 15	1,08,420	2,252	301
न्यूजीलैण्ड .	104	19 95	30,300	1,519	19
ब्रिटेन .	95	504 29	6,19,880	1,229	531
बेल्जियम	12	87 05	94,700	1,088	725
नीदरलैण्ड्स .	13	103 77	63,100	608	798
डेनमार्क	17	43 34	23,330	538	255
जापान .	148	855 00	4,31,990	505	578
भारत .	1,270	3,720 00	61,930	17	293

भारत मे मुख्यत. खनिज तेल, कोयला और पानी से बिजली प्राप्त की जाती है । इनमे से खनिज तेल भारत मे अपनी आवश्यकता का केवल 6 प्रतिशत पैदा होता है, इसलिए बिजली उत्पन्न करने के कार्य मे उसका उपयोग अनुपयुक्त है । व्यवहार मे बिजली के केवल उन्ही छोटे कारखानो मे खनिज तेलो का उपयोग किया जाएगा, जहा बिजली निकालने का कोई अन्य साधन उपलब्ध नही है ।

भारत मे कोयला काफी मात्रा मे उपलब्ध होता है । कोयले के स्रोतो से हमे कम से कम 16,47,40,00,000 टन कोयला प्राप्त हो सकता है । बल्कि अनुमान तो यह है कि भारत की खानो मे 60,00,00,00,000 टन कोयला विद्यमान है । व्यावसायिक दृष्टि से ससार के अन्य उन्नत देशो की तुलना मे यह कोयला अधिक नही है । हमारे देश मे धातुओ के काम मे आने वाला कोयला 70 करोड से 75 करोड़ टन के बीच मे है । जिस रफ्तार से आज उसका व्यय हो रहा है, उस रफ्तार से वह 65 और 70 वर्षों के बीच मे समाप्त हो जाएगा । इसलिए भारतीय कोल क्षेत्र कमेटी की यह सिफारिश है कि ऊचे दर्जे के कोयले का कम इस्तेमाल किया जाय । इसी कराण बिजली के कारखानो तथा रेलवे इजन आदि चलाने के लिए घटिया दर्जे का कोयला बरता जाता है । साथ ही कोयला कुछ ही राज्यो (बिहार, पश्चिमी बगाल, उडीसा, मध्यप्रदेश,

(क) जनसख्या और बिजली उत्पादन सम्बन्धी आकडे सयुक्त राष्ट्र सघ की आकड़ा सम्बन्धी मासिक पत्रिका के अगस्त 1953 के अक से तथा क्षेत्र सम्बन्धी आकड़े कॉलिन्स के 'एसेन्शियल वर्ल्ड एटलस' से लिये गये है ।

हैदराबाद) मे ही प्राप्त होता है । इसलिए इसका मितव्ययतापूर्ण प्रयोग इन्ही राज्यो मे हो सकता है । उसे पजाब या दक्षिणी भारत मे ले जाने मे काफी व्यय आता है, इसलिए वहा कोयले से बिजली निकालना बहुत महगा पडेगा ।

जल विद्युत शक्ति

केन्द्रीय जल और शक्ति कमीशन ने हाल ही मे भारत मे प्राप्त होने वाली जल विद्युत शक्ति के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक ढंग से जाच पडताल की है । अनुमान है कि यह आजकल 3 करोड किलोवाट है ।

जल से विद्युत् निकालने की सम्भावना केवल इसी बात पर निर्भर नही करती कि पानी मे कितना प्रवाह है, अपितु उसके लिए यह देखना भी आवश्यक होता है कि प्रवाह या प्रपात के पास बिजली निकालने के बडे बडे कारखाने लगाए भी जा सकते है या नही; और जहा बिजली की खपत होती है, वहा से वह स्थान कितनी दूर है । भारत की नदिया विभिन्न ऋतुओ मे एकदम विभिन्न आकार धारण कर लेती है । बाध बना कर उनका पानी एकत्र कर लेने का कार्य बहुत व्ययसाध्य है । साथ ही हमे अपनी नदियो का पानी सिचाई के कामो पर व्यय करना है । इस कारण यह देखना आवश्यक हो जाता है कि बिजली निकालने का कोई काम सिचाई की कीमत पर न किया जाय । यह सब होते हुए भी पानी से निकाली गई बिजली हमारे देश मे सबसे सस्ती सिद्ध होती है ।

भारत मे शक्ति विकास की स्थिति इस प्रकार है --

दक्षिण भारत--मुख्यत जल विद्युत्, बम्बई--मुख्यत जल विद्युत्, परन्तु कुछ क्षेत्रो मे कोयले द्वारा भी विद्युत् प्राप्त की जा सकती है, बिहार और बगाल के कोल क्षेत्र--मुख्यत कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली, केन्द्रीय भारत--(हैदराबाद, उडीसा तथा मध्य प्रदेश)--मुख्यत कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली, तथा पजाब और उत्तर प्रदेश--मुख्यत जल विद्युत्, आशिक रूप मे कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली ।

आयोजना के अन्तर्गत शक्ति कार्यो का विकास

राज्यो की प्रेरणा शक्ति का फल यह हुआ है कि देश मे बिजली का विकास जोरशोर से हो रहा है । स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से इसमे और भी उन्नति हुई है । पश्चिमी बगाल, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश और उडीसा उक्त श्रेणी के राज्य है । पिछले वर्षो मे यद्यपि कोई नई बडी विद्युत् उत्पादक कम्पनी नही बनाई गई, तथापि पुरानी व्यक्तिगत कम्पनियो मे पहले की अपेक्षा अधिक बिजली बन रही है । इससे यह स्पष्ट है कि राज्यो की सरकारे स्वय बिजली उत्पन्न करने लगी है । इस कार्य मे कुछ व्यावहारिक बाधाए अवश्य आई । बिजली सम्बन्धी कार्य करने वाले शिक्षित कार्यकर्त्ताओ की कमी इसमे सबसे बडी बाधा थी । साथ ही विदेशी विनिमय की न्यूनता, कच्चा सामान, यथा लोहा, और सीमेण्ट की कमी और बडी बडी मशीने लगाने की कठिनाइया भी इसमे बाधक सिद्ध हुई ।

इस समय भारत के 24 राज्यो मे 115 विद्युत् निर्माण कार्य जारी है या जारी किए जाने वाले है । उनमे से कुछ बहुमुखी नदी योजनाओ से सम्बद्ध है, जिनका जिक्र आगे चल कर किया गया है । तालिका 87 मे राज्यो की शक्ति, केन्द्र का सामर्थ्य, और उनके विकास का परिचय दिया गया है और तालिका 88 मे बताया गया है कि 1959 तक इस सम्बन्ध मे क्या स्थिति हो जाएगी ।

तालिका 87

स्थापित क्षमता की अपेक्षित वृद्धि
(आयोजना काल में)

क्रम सख्या	राज्य	अप्रैल 1951 मे कुल स्थापित विद्युत क्षमता (दस लाख वाट)	मार्च 1951 तक कुल अपेक्षित क्षमता (दस लाख वाट)
1.	आसाम	3 36	4.05
2.	पश्चिमी बंगाल	522.29	560.29
3.	बिहार	44.98	258.98
4.	बम्बई	416.19	672.49
5.	केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र		
	(क) दिल्ली	37.54	68.54
	(ख) अन्य	6.88	13 68
6.	हैदराबाद	21.07	74.57
7.	जम्मू और काश्मीर	6.30	12.30
8	मध्य भारत	13.69	31.19
9.	मध्य प्रदेश	27.84	101.34
10.	मद्रास	168.03	362.03
11.	मैसूर	107.20	179.20
12.	पेप्सू	6.74	6 74
13.	उड़ीसा	4.61	58.61
14.	पंजाब	61.38	160.38
15.	राजस्थान	24.12	39.12
16.	सौराष्ट्र	21.89	31.89
17.	त्रावनकोर-कोचीन	34.59	115.59
18.	उत्तर प्रदेश	183.84	306.14
	योग	1,712.54	3,057.13

तालिका 88

	1956 तक क्षमता (दस लाख वाट)	1959 तक योजनाओं के पूरा होने पर क्षमता (दस लाख वाट)
हाइड्रो	1,176	2,147
थरमल	1,881	2,090
योग	3,057	4,237

सिंचाई

सिंचाई का विकास

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, सिंचाई के साधनों का क्या महत्व है तथा उनका कितना विकास हुआ है, इस सम्बन्ध में कृषि के अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। जब से भारत का इतिहास प्रारम्भ होता है, तब से इस देश में सिंचाई के साधनो की विद्यमानता सिद्ध होती है। दक्षिण में बड़े बड़े तालाबो मे वर्षा का पानी एकत्र कर लिया जाता था और उत्तर मे कुओ द्वारा तथा नदियों द्वारा खेती बाड़ी को पानी दिया जाता था। भारत मे नहरो का निर्माण बहुत प्राचीन काल ही मे प्रारम्भ हो गया था। अंग्रेजी शासन काल में नहरो के विकास पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि भारत में सीची जाने वाली भूमि ससार के किसी भी अन्य देश से अधिक है, तथापि वह भारत की कुल कृषियोग्य भूमि का केवल पाचवा भाग ही है।

भारत की नदियो मे प्रतिवर्ष लगभग 1,35,60,00,000 एकड फुट पानी बहता है। जिसका लगभग 49 प्रतिशत वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। इसमे से केवल 7,60,00,000 एकड फुट (अर्थात् कुल जल का 5 6 प्रतिशत) ही सिचाई अथवा बिजली बनाने के काम मे प्रयुक्त होता है और शेष 94.4 प्रतिशत पानी व्यर्थ बह जाता है, बल्कि इस पानी से बाढ आदि के रूप मे कभी कभी बहुत हानि भी पहुचती है। वर्तमान बड़े कार्यो की पूर्ति हो जाने पर भारत अपने कुल पानी का 13.6 प्रतिशत प्रयोग मे लाने लगेगा।

भारतीय नदियो से सिचाई के कार्य के लिए जितनी नहरे निकाली जा सकती थी, वे लगभग पूरी मात्रा मे निकाल ली गई है। इस कारण अब यही सम्भव था कि वर्षा के दिनो का पानी बाध बना कर वर्ष के बाकी दिनो के लिए एकत्र कर लिया जाय। इस उद्देश्य से आजकल उचित स्थानो पर बाध बनाए जा रहे हैं। कुछ स्थानो पर सिचाई के लिए पानी को वैज्ञानिक साधनों से ऊपर उठाना पड़ता है। यह तरीका महगा तो अवश्य सिद्ध होता है, परन्तु वहा सिचाई के लिए यह अकेला सम्भव साधन होता है। इसलिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। कुछ प्रदेशो मे सिंचाई का काम ट्यूबवेल द्वारा ही किया जा रहा है। इस विशाल देश मे सिचाई के छोटे साधनो यथा कुओ, तालाबो आदि का भी बहुत अधिक महत्व है और सिचाई के लिए जो योजनाएं गई है, उनमे उन्हे यथेष्ट स्थान दिया गया है।

बनाई शासन

1902 से पहले सिचाई का काम, विशेष रूप मे उसका आर्थिक पहलू एक केन्द्रीय विषय था। यद्यपि उसकी व्यवस्था प्रान्तीय सरकारो के सुपुर्द थी, तथापि सिचाई के साधन बनाने पर पूरा व्यय भारत सरकार ही करती थी। मौण्टफोर्ड सुधारो के अनुसार सिचाई एक प्रान्तीय विषय बन गया। परन्तु तो भी सिचाई के कार्य के लिए भारत सरकार राज्यो को काफी रुपया उधार देती रही और 1926 मे इस कार्य के लिए एक केन्द्रीय सिचाई बोर्ड बनाया गया, जिसने भारत मे जल विद्युत की सम्भावनाओ के बारे मे अपनी रिपोर्ट उपस्थित की। सिचाई तथा बाढ़ आदि के नियत्रण के सम्बन्ध मे यह बोर्ड प्रान्तीय सरकारो को सलाह दिया करता था और सब तरह के अनुसधान तथा तालमेल आदि के कार्य भी इसी बोर्ड के सुपुर्द थे। अप्रैल 1937 मे भारत मे प्रान्तीय स्वाधीनता की स्थापना के बाद सिचाई पूर्ण रूप से एक प्रान्तीय विषय बन गया।

1945 में एक केन्द्रीय जल मार्ग, सिंचाई और जहाजरानी कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुख्यतः उक्त बातो के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एकत्र करना था। इन विषयों के सगठन तथा निर्माण के कार्य भी इसी कमीशन के सुपुर्द थे। हाल ही मे यह कमीशन केन्द्रीय जल और विद्युत कमीशन मे मिला दिया गया है।

सिंचाई सम्बन्धी अनुसन्धान

पूना का केन्द्रीय जल शक्ति, सिंचाई तथा जहाजरानी अनुसधान स्टेशन भारत की सबसे पुरानी सिचाई अनुसंधान सस्था है। इसकी स्थापना 1916 मे की गई थी। 1920 मे वहा हाईड्रोडाइनामिक अनुसधान स्टेशन भी खोला गया। 1934 मे वहा हाईड्रोलिक अनुसधान का कार्य भी जारी कर दिया गया। 1937 मे यह स्टेशन भारत सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया। आजकल यह स्टेशन 8 भागो मे विभक्त है (1) नहर हाईड्रोलिक्स, (2) जहाजरानी, (3) नहर बनाने का सामान, सीमेण्ट ककरीट आदि। (4) भूमि तथा भूमि की रचना, (5) एतदविषयक गणित, (6) एतदविषयक गणनाए और (7-8) एतदविषयक भौतिकी और रसायन।

कुछ राज्यो की अपनी अनुसधानशालाए भी है। उदाहरण के लिए बम्बई, उत्तर प्रदेश, बगाल, मैसूर और हैदराबाद आदि। सिचाई का केन्द्रीय बोर्ड इन सब स्टेशनो के अनुसधान कार्य मे तालमेल और सहयोग उत्पन्न का कार्य करता है।

नदी घाटी योजना

भारत का आर्थिक विकास तथा खाद्य की कमी की समस्या का हल मुख्यत इस बात मे है कि उसकी बहुमुखी नदी घाटी योजनाए जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। इन योजनाओ को बहुमुखी इसलिए कहा जाता है कि उनसे एक साथ बहुत से लाभ होगे। उनके द्वारा सिचाई होगी, इससे कृषि की उपज तो बढेगी ही, साथ ही उनके द्वारा बाढो पर नियंत्रण भी किया जा सकेगा तथा बडे परिमाण मे जल विद्युत निकाली जा सकेगी। इसके साथ ही बडी नहरो मे आन्तरिक यातायात का काम भी हो सकेगा। इन मुख्य लाभो के अतिरिक्त इन योजनाओ की पूर्ति से जगल उत्पादन का कार्य, मछली उत्पादन कार्य, पीने के जल की प्राप्ति तथा जनता के मनोरजन के साधनो का विकास भी किया जा सकेगा। इन महान कार्यों का इसी महत्ता के कारण पचवर्षीय आयोजना के कार्यक्रम मे उन्हे सबसे ऊची प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यो पर आयोजना के कुल बजट का एक तिहाई भाग खर्च किया जा रहा है। इन में से कुछ कार्य इतने बडे होगे कि उनकी गणना ससार के सबसे बडी नदी-घाटी कार्यो मे की जाएगी।

भारत के जलमार्ग लगभग सम्पूर्ण देश में एक समान बटे हुए है। यह पता लगाया गया है कि 15 से 20 वर्षों के बीच मे देश की सिचाई वाले क्षेत्र दुगने किए जा सकते है। इससे न केवल अन्न की वर्तमान कमी दूर हो जाएगी, बल्कि देश की आबादी बढ जाने पर भी अन्न की कमी नही होगी। इन योजनाओ द्वारा भारत को सैकडो मील के जलमार्ग प्राप्त हो जायेगे तथा 3 करोड से 4 करोड किलोवाट बिजली मिलने लगेगी।

इस समय देश के विभिन्न भागो मे 153 कार्यो का निर्माण जारी है। इनमे से केवल 6 ही बहुमुखी है; 104 सिचाई के उद्देश्य से बनाए जा रहे है और 43 जल विद्युत प्राप्त करने के उद्देश्य से। इनमे से 12 को बडे कार्य कहा जा सकता है। इन 12 मे से 6 बहुमुखी है, 3 जल विद्युत सम्बन्धी है और 3 सिचाई सम्बन्धी। इन 12 बडे कार्यों पर 4 39,00,00,000 रुपये और

शेष 141 कार्यों पर 1,51,00,00,000 रुपये व्यय आएंगे कुल मिला कर इन सब कार्यों पर 6,80,00,00,000 रुपये व्यय होंगे। इनके अतिरिक्त 122 अन्य कार्यों के सम्बन्ध मे प्रारम्भिक जाच पडताल की जा चुकी है या की जा रही है। परन्तु धन की कमी के कारण उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इन 122 कार्यों पर 13,10,00,00,000 रुपये के व्यय का अनुमान है।

पचवर्षीय आयोजना के अनुसार सिचाई के 173 कार्य किये जा रहे हैं, जिनसे 85,30,000 एकड नई भूमि की सिचाई की जा सकेगी और 10 लाख किलोवाट नई जल विद्युत प्राप्त होगी। क्रमश. इन कार्यों मे 1,69,40,000 एकड़ नई भूमि की सिचाई होने लगेगी और 15 लाख किलोवाट नई जल विद्युत मिलेगी। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित तालिका 89 देखिए—

तालिका 89

पचवर्षीय आयोजना मे विद्युत एवं सिचाई कार्य

(व्यय और लाभ)

कार्य	1951–56 मे कुल व्यय (लाख रुपये)	सिचाई से लाभ (हजार एकड)		विद्युत से लाभ (हजार किलोवाट)	
		1955-56 तक	पूरा होने पर	1955–56 तक	पूरा होने पर
बहुद्देशीय कार्य					
भाखडा नगल .	7,750	1,361	3,604	96	144
हारीके .	1,062	—	—	—	—
दामोदर घाटी योजना	4,170	595	1,141	194	274
हिराकुड . .	4,400	261	1,785	48	123
उपरोक्त कार्यों के लिए अतिरिक्त निधिया .	5,000	—	—	—	—
नई योजनाए (क) .	4,000	—	—	—	—
योग .	26,382	2,217	6,530	338	541
भाग 'क' के राज्य :					
आसाम .	283	218	218	5	7
बिहार .	1,682	675	777	11	11
बम्बई . .	3,312	474	893	83	84
मध्य प्रदेश	908	114	184	73	73
मद्रास .	8,432	435	608	196	307
उडीसा .	691	480	480	8	8
पंजाब . .	364	666	774	—	—
उत्तर प्रदेश .	3,321	1,361	3,181	109	124
पश्चिमी बगाल .	1,613	917	917	4	4
योग .	20,607	5,340	-8,032	489	618

(क) नई योजनाओ मे कोसी (खड I), कोयना (खड I), कृष्णा, चम्बल (खड I और रिहद शामिल है।

	1951-56 मे कुल व्यय	सिचाई के लाभ (हजार एकड़)		विद्युत से लाभ (हजार किलोवाट)	
कार्य	(लाख रुपये)	1955-56 तक	पूरा होने पर	1955-56 तक	पूरा होने पर
भाग 'ख' के राज्य .					
हैदराबाद .	2,800	306	731	53	53
जम्मू और कश्मीर .	360	76	169	7	7
मध्य भारत .	556	83	152	15	18
मैसूर . .	1,984	30	250	72	120
पेप्सू . .	65	—	129	—	—
राजस्थान. .	545	243	523	11	11
सौराष्ट्र .	688	108	120	12	12
त्रावनकोर-कोचीन	1,513	17	168	81	81
योग	8,510	863	2,242	251	302
भाग 'ग' के राज्य					
अजमेर . .	11	—	—	—	—
भोपाल . .	28	—	—	—	—
कुर्ग . .	25	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	93	75	100	1	1
कच्छ .	114	38	38	—	—
त्रिपुरा	7	—	—	—	—
मणिपुर	12	—	—	—	—
विन्ध्य प्रदेश	51	—	—	3	3
योग	341	113	138	4	4
सर्वयोग	55,841	8,533	16,942	1,082	1,46

सिंचाई और शक्ति के कार्यों की उन्नति

बडे बडे कार्य वर्तमान पचवर्षीय आयोजना के निर्माण से पहले ही प्रारम्भ कर दिए गए थे और बाद मे उन्हे पचवर्षीय आयोजना का अग बना लिया गया। इन सिचाई सम्बन्धी और विद्युत सम्बन्धी योजनाओ पर कुल 7,65,00,00,000 रुपये व्यय होगे जिसमे से आधे से अधिक रुपया अब तक खर्च हो चुका है।

पिछले 3 वर्षों मे ही इन कार्यों से देश को लाभ पहुचना शुरू हो गया है। 1952-53 मे 3,15,000 किलोवाट जल विद्युत की मशीने लगा दी गई और आजकल उनसे बिजली प्राप्त हो रही है। इसी तरह 14,20,000 नई भूमि की सिचाई प्रारम्भ हो गई है। इस सम्बन्ध मे पजाब और उत्तर प्रदेश मे आशा से अधिक उन्नति हुई और बिहार, मद्रास, राजस्थान तथा दामोदर वैली समय से कुछ पीछे रह गए है। तथापि यह स्पष्ट है कि इन कार्यों से पूरा लाभ आयोजना की पूर्ति के बाद ही प्राप्त हो सकेगा।

अगली तीन तालिकाओं में बहुमुखी कार्यों, राज्यों में सिंचाई के कार्यों तथा राज्यों की विद्युत शक्ति के कार्यों के सम्बन्ध में सूचनाए [illegible] 1953-54 में जो व्यय किया जा रहा है, उसका निर्देश भी इन तालिकाओं में है।

तालिका 90

पचवर्षीय आयोजना की प्रगति

राज्यों के सिंचाई कार्य

(1951-53)

राज्य	आयोजना में कार्यों का कुल व्यय	मार्च 1951 तक का व्यय	आयोजना में व्यवस्था	व्यय की प्रगति 1951-52 संशोधित	1951-52 वास्तविक	1952-53 बजट	1952-53 संशोधित	1953-54 बजट	सींचा गया क्षेत्र (अतिरिक्त) 1951-52 आयोजनानुसार	1951-52 वास्तविक	1952-53 आयोजनानुसार	1952-53 वास्तविक
			(लाख रुपये)						(हजार एकड़)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भाग 'क' के राज्य												
आसाम	200	—	200	1	12	4	42	76	—	19	30	68
बिहार	1 414	125	973	238	168	234	233	233	77	—	180	146
बम्बई	2 565	270	2 269	232	233	274	227	469	2	1	16	2
मध्य प्रदेश	369	14	308	10	10	50	13	45	5	5	10	10
मद्रास	4 968	1 561	3 408	809	869	936	963	613	—	—	42	7
उड़ीसा	402	102	300	49	72	91	70	60	124	126	263	182
पंजाब	432	106	326	121	69	113	119	108	97	223	176	238
उत्तर प्रदेश	4 944	532	1,911	256	217	390	444	464	123	285	528	585
पश्चिमी बंगाल	1 941	403	1 538	315	190	412	399	417	173	100	360	—
योग	17,235	3,117	11,223	2,031	1,840	2,500	2,510	2 485	601	759	1,605	1,238
भाग 'ख' के राज्य												
हैदराबाद	3,246	876	2 479	452	400	482	440	477	—	—	31	21
जम्मू और कश्मीर	311	19	340	25	49	30	57	85	2	—	8	—
मध्य भारत	339	11	328	32	29	37	31	50	4	2	19	2
मैसूर	2,709	245	716	61	88	72	119	140	5	5	7	8
पेप्सू	36	2	34	3	—	15	6	15	—	—	—	—
राजस्थान	1 071	163	504	68	56	75	63	140	11	2	73	5
सौराष्ट्र	1,102	92	475	60	54	91	132	153	4	2	20	11
त्रावनकोर-कोचीन	610	132	478	100	86	84	92	90	—	10	—	20
योग	9 604	1 540	5,354	801	762	886	940	1,150	26	21	158	67
भाग 'ग' के राज्य												
अजमेर	11	—	11	—	—	—	1	1	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	80	—	80	—	—	13	5	33	—	—	—	5
कच्छ	91	—	91	5	4	32	26	33	—	—	—	—
योग	182	—	182	5	4	45	32	67	—	—	—	5
संयोग	27,021	4,657	16,769	2,837	2,606	3,431	3,482	3,702	627	780	1 763	1,310

तालिका 91

पचवर्षीय योजना की प्रगति
राज्यों के विद्युत कार्य

राज्य	आयोजना मे कार्यों का कुल व्यय	मार्च 1951 तक का व्यय	आयोजना में व्यवस्था	व्यय की प्रगति: 1951-52 संशोधित	1951-52 वास्तविक	1952-53 बजट	1952-53 संशोधित	1953-54 बजट	स्थापित क्षमता—वर्तमान यंत्रों में वृद्धि और/या नये यंत्र: 1951-52 योजनानुसार	1951-52 वास्तविक	1952-53 योजनानुसार	1952-53 वास्तविक
				(लाख रुपये)					(हजार किलोवाट)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भाग 'क' के राज्य :												
आसाम	85	2	83	—	—	19	19	55	—	—	—	—
बिहार	1,120	64	709	95	82	141	130	158	1	1	4	2
बम्बई	1 412	396	1,043	256	253	415	310	342	2	2	21	21
मध्य प्रदेश	1,384	763	600	186	148	185	110	140	24	20	51	51
मद्रास	7 773	1 805	5,024	725	807	999	800	927	7	7	58	58
उड़ीसा	874	133	391	65	59	80	74	124	4	4	7	4
पंजाब	59	21	38	18	6	20	12	10	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	2 930	699	1,410	269	228	358	319	444	7	7	26	16
पश्चिमी बंगाल	133	57	76	25	25	33	32	12	—	—	—	—
योग	15,770	3,940	9,364	1 639	1,608	2,250	1 806	2,212	45	41	167	152
भाग 'ख' के राज्य :												
हैदराबाद	581	260	321	58	50	79	83	96	—	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	186	12	75	18	6	25	9	24	—	—	—	—
मध्य भारत	[illegible]	46	228	48	44	111	99	66	1	—	4	4
मैसूर	2,027	690	1,268	191	191	230	215	150	—	—	36	72
पैप्सू	200	—	30	5	5	—	8	13	—	—	—	—
राजस्थान	53	—	41	30	40	11	12	15	4	—	11	9
सौराष्ट्र	262	—	213	—	—	30	20	50	—	—	—	—
त्रावनकोर-कोचीन	1,770	735	1 035	237	206	277	284	268	7	—	21	21
योग	5 353	1,743	3 211	587	542	763	730	682	12	—	72	106
भाग 'ग' के राज्य :												
भोपाल	28	—	28	—	—	5	4	12	—	—	—	3
कुर्ग	35	—	35	—	—	—	—	12	—	—	—	—
कच्छ	23	—	23	—	—	11	11	9	—	—	—	—
त्रिपुरा	7	—	7	—	—	6	—	4	—	—	—	—
विन्ध्य प्रदेश	51	—	51	—	—	8	7	15	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	13	—	13	—	—	2	2	4	—	—	—	—
मणिपुर	12	—	12	—	—	2	2	1	—	—	—	—
योग	169	—	169	—	—	34	26	37	—	—	—	3
सर्वयोग	21 292	5,683	12,754	2,226	2,150	3,047	2,562	2,951	57	41	239	261

तालिका 92

पचवर्षीय योजना की प्रगति

बहुद्देशीय कार्य

(1951-53)

योजना	आयोजना में कार्यों का कुल व्यय	मार्च 1951 तक का व्यय	आयोजना में व्यवस्था	व्यय की प्रगति					सींचा गया क्षेत्र (अतिरिक्त)				स्थापित विद्युत			
				1951-52		1952-53	1953-54		1951-52		1952-53		1951-52		1952-53	
				संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट	आयोजनानुसार	वास्तविक	आयोजनानुसार	वास्तविक	आयोजनानुसार	वास्तविक	आयोजनानुसार	वास्तविक
				लाख रुपये					हजार एकड़				किलोवाट			
बहुद्देशीय कार्य—																
भाखड़ा नागल	13,290	2,356	7,750	1,226	1,214	1,700	1,900	2,215	19	19	101	101	—	—	—	—
हारीके .	1,380	318	1,062	260	108	250	250	150	—	—	—	—	—	—	—	—
दामोदर घाटी योजना .	7,498	1 687	4,170	1,350	1,350	1,200	1,572	1,463	—	—	26	5	—	—	—	54,000
हिराकुड बाध .	6,259	628	4,400	800	858	850	950	1,172	—	—	—	—	—	—	—	—
उपरोक्त योजनाओ के लिए अतिरिक्त **व्यवस्था**	—	—	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	28,427	4 989	22,382	3,636	3,530	4,000	4,672	5,000	19	19	127	106	-	—	—	54,000

तेरहवा अध्याय

वैज्ञानिक शोध

यह आश्चर्य की बात नही है कि हमारे यहा विदेशी सरकार ने वैज्ञानिक शोध मे यथेष्ट हाथ नही बटाया । सच तो यह है कि ब्रिटिश युग मे बहुत बाद को चल कर ही वैज्ञानिक शोध संस्थाओं को सरकारी सहायता प्राप्त होने लगी । फिर भी हमारे यहा एक से एक बड़े वैज्ञानिक उत्पन्न हुए सो भी ऐसे वैज्ञानिक जिन पर भारत उचित रूप से गर्व कर सकता है । इनमे से कुछ प्रमुख वैज्ञानिको के नाम सुपरिचित हैं जैसे श्रीनिवास रामानुजम, जगदीशचन्द्र बोस, प्रफुल्लचन्द्र राय, बीरबल साहनी, सी० वी० रमन, मेघनाद साहा, एच० जे० भाभा, एस० एस० भटनागर, के० एस० कृष्णन्, चन्द्रशेखरन, टी० एस० वेकटरमन और एस० कोठारी ।

शोध सम्बन्धी संस्थाएं

यद्यपि सरकारी सहायता बाद को आई, पर 1784 में ही हम यह देखते है कि रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना हुई । इस सस्था की स्थापना हमारे इतिहास की एक प्रमुख घटना है । थोड़े दिनो मे और भी संस्थाये स्थापित हुईं । 1800 ई० मे भारत का परिमापन विभाग, 1851 मे भूगर्भ वैज्ञानिक परिमापन, 1889 मे वनस्पति वैज्ञानिक परिमापन तथा 1916 मे पशु वैज्ञानिक परिमापन का सूत्रपात हुआ । 1876 मे विज्ञान के परिशीलन के लिये इडियन एसोसियेशन नाम से एक और सस्था खुली । ये संस्थाये अपने-अपने क्षेत्र मे शोध करती रही । जो शोध होता था, वह वैज्ञानिक पत्रो तथा अन्य प्रकाशनो के जरिये प्रचारित किया जाता था । समय समय पर वैज्ञानिको के सम्मेलन भी होते रहे, जिन में वैज्ञानिक मिल कर अपनी समस्याओ पर विचार करते थे ।

अब तक विज्ञान के अलग अलग विभागो के लिये अलग अलग सस्थायें काम कर रही थी, पर विज्ञान अन्ततोगत्वा एक ओर अविभाज्य है, इसलिये इस बात की भी आवश्यकता थी कि लोग सुविधा के लिये एक शाखा मे काम करे, पर साथ ही सब तरह के वैज्ञानिको को एक मच पर एकत्र हो कर विचार विनिमय करने का मौका मिले । इस उद्देश्य से 1914 मे भारतीय विज्ञान काग्रेस एसोसियेशन की स्थापना हुई । गत 40 सालो से यह सस्था काम कर रही है, और भारतीय वैज्ञानिको मे पारस्परिक विचार विनिमय के अतिरिक्त विदेश के वैज्ञानिक भी इस के सम्मेलनो मे आ कर सामान्य समस्याओ पर बातचीत तथा विचार विनिमय करते है ।

यह आवश्यक था कि एक केन्द्रीय सस्था होती जिसे सरकार सब से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सस्था के रूप मे स्वीकार करती और जो वैज्ञानिक परिषदो, सस्थाओ, सभाओ तथा सरकार के वैज्ञानिक विभागो और सेवाओ की बीच की कडी के रूप मे काम करती । इस उद्देश्य से नेशनल इस्टीट्यूट आफ साइसेज (1935) सब से उपयुक्त पाई गई । इस सस्था को वही मर्यादा प्राप्त है जो लन्दन की रायल सोसाइटी या वाशिगटन के राष्ट्रीय एकेडेमी को प्राप्त ह । ऊपर जो काम बताये गये, उनके अतिरिक्त नेशनल इस्टीट्यूट आफ साइसेज विज्ञान की उन्नति के लिये कोष तथा वृत्तियो को प्राप्त करती है, और साथ ही साथ किस प्रकार से उन का उपयोग किया जाये इस सम्बन्ध मे निर्णय देती है ।

इस शताब्दी के प्रारम्भ मे परिस्थिति यह थी कि सरकारी सूत्रो के द्वारा भी जो वैज्ञानिक कार्य होते थे, उनमे कोई सम्पर्क या सयोग नही था। 1902 मे इसी उद्देश्य से बोर्ड आफ साइंटिफिक एडवाइस यानी वैज्ञानिक परामर्श बोर्ड की स्थापना हुई। 1934 मे इस सस्था के स्थान पर इडस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो की स्थापना हुई।

द्वितीय महायुद्ध का युग भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य के लिये एक बहुत खतरनाक युग था। युद्ध चलते समय यह आवश्यक हो गया कि भारत मे प्राप्त साधनो का अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपयोग हो क्योकि बाहर से बहुत सी आवश्यक चीजो का आना असम्भव नही तो कठिन हो गया था। युद्ध की आवश्यकताओ को देखते हुए भारत सरकार ने 1940 मे बोर्ड आफ साइटिफिक इडस्ट्रियल रिसर्च और 1941 मे कौसिल आफ साइटिफिक एण्ड इडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की। यह द्रष्टव्य है कि युद्ध के बहुत खतरनाक युग मे ही इन सस्थाओ की स्थापना हुई। यह स्पष्ट है कि इन सस्थाओ की स्थापना विज्ञान के प्रति प्रेम के कारण नही, बल्कि साम्राज्य के स्वार्थ की दृष्टि से हुई।

शेषोक्त सस्था एक स्वायत्त सस्था के रूप मे स्थापित हुई। इसके जिम्मे यह काम डाला गया कि वह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध सम्बन्धी सस्थाओ पर देखरेख रक्खे और उन्हे चलावे, छात्रो को शोध के लिये वृत्तिया तथा फैलोशिप दे, औद्योगिक विकास के लिये शोध कार्य का उपयोग करे। कहना न होगा कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे। स्वाभाविक रूप से सस्थाये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक मामलो पर पत्र तथा अनुसन्धान प्रकाशित करती है।

इस सस्था को स्वतत्र भारत मे कितना महत्व दिया गया है यह इससे मालूम हो सकता है कि इसकी कार्य समिति के सभापति स्वय प्रधान मत्री है और प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक शोध के मत्री इसके उपसभापति है। इन महानुभावो के अतिरिक्त इस समिति मे विज्ञान, व्यापारी वर्ग तथा उद्योग धन्धे के गैर सरकारी प्रतिनिधि, और साथ ही वित्त मत्रालय के प्रतिनिधि भी है। यह समिति प्रौद्योगिक मामलो मे 19 सदस्यो के बोर्ड आफ साइटिफिक एण्ड इडस्ट्रियल रिसर्च से परामर्श लेती है। इन मे 9 व्यक्ति प्रमुख वैज्ञानिक है, जो मुख्यतः गैर सरकारी व्यक्ति है। जिन सरकारी विभागो का सम्बन्ध औद्योगिक शोध से है उसके भी प्रतिनिधि इस मे आ जाते है। बोर्ड कार्य-समिति को किन मामलो मे परामर्श देती है यह भी देख लिया जाये—(1) किसी विशेष समस्या पर शोध प्रारम्भ करने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव, (2) वैज्ञानिक सस्थाओ (जिन मे विशेष विज्ञानो तथा उद्योग धन्धो की समस्याओ पर अध्ययन करने के लिये विश्व-विद्यालय भी आ जाते है) द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव (3) ढग से शोध करने की आवश्यक तैयारी के रूप मे देश मे मौजूद साधनो के अध्ययन तथा परिमापन के सम्बन्ध मे प्रस्ताव।

बोर्ड को देश की निम्नलिखित मुख्य शोध सस्थाओ का सहयोग प्राप्त होता है :

(1) भौतिक विज्ञान शोध समिति, (2) रेडियो शोध समिति, (3) वातावरण शोध समिति, (4) उच्च तुंगत्व (आलटीच्यूड) शोध समिति, (5) भारत मे भूगर्भ वैज्ञानिक समय परिमापन समिति, (6) आकडा शास्त्र, स्टन्डर्ड तथा गुण नियत्रण समिति, (7) भवन निर्माण शोध समिति, (8) आन्तरिक कम्बश्चन इंजन शोध समिति, (9) रासायनिक शोध समिति, (10) फर्मासीजात द्रव्य और औषध शोध समिति, (11) मलेरिया कैमोथिरापी समिति, (12) बायोकैमिकल शोध समिति, (13) खान शोध समिति

(14) ईंधन शोध समिति, (15) कोयला मिश्रण और कोक शोध उपसमिति, (16) शीशा और परावर्तक द्रव्य शोध समिति, (17) लवण शोध समिति, (18) आवश्यक तैल शोध समिति, (19) उद्भिज्ज तैल शोध समिति, (20) वनस्पति शोध परामर्श समिति, (21) धातु शोध समिति, (22) प्लास्टिक शोध समिति, (23) चर्म शोध समिति, (24) सैल्यूलोज समिति और (25) सडक शोध समिति ।

स्वतत्रता की प्राप्ति के साथ सरकार ने वैज्ञानिक शोध के महत्व को देखते हुए 1948 के जून मे वैज्ञानिक शोध विभाग नाम से एक विभाग खोल दिया जिस पर यह काम सौंपा गया कि वह राज्यो मे और निजी सस्थाओ मे इस सम्बन्ध मे जो शोध हो रहे हैं, उन पर देखरेख रक्खे और उन्हे सयुक्त करे । जब 1952 मे केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक साधनो और वैज्ञानिक शोध के लिये एक मंत्रालय कायम किया तो वह विभाग इस के अन्तर्गत कर दिया गया ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाए

हमारी स्वतत्र सरकार विज्ञान को जल्दी से जल्दी आगे बढाना चाहती थी, इसलिये देश भर मे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई । ये सस्थाये मौलिक शोध करने के अतिरिक्त व्यवहारिक शोध भी करती है —

तालिका 93

अनुक्रम	प्रयोगशाला का नाम	स्थिति	उदघाटन तिथि	डायरेक्टर,
1	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ।	पूना .	3 जनवरी, 1950	जी० आई० फिच, एफ० आर० एस०
2	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	नई दिल्ली	21 जनवरी, 1950	के० एस० कृष्णन, एफ० आर० एस०
3	केन्द्रीय ईंधन शोध सस्था	धनबाद .	22 अप्रैल, 1950	जे० डब्ल्यू० व्हिटकर ।
4	केन्द्रीय शीशा और उन्नत मिट्टी शोध सस्था	जादवपुर .	25 अगस्त, 1950	आत्मा राम
5	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक सस्था ।	मैसूर .	21 अक्तूबर, 1950	वी० सुब्रह्मण्यम
6	राष्ट्रीय धातु शोध प्रयोगशाला ।	जमशेदपुर .	26 नवबर, 1950	ई० एच० बकनाल
7	केन्द्रीय औषध शोध सस्था	लखनऊ .	17 फरवरी, 1951	बी० मुकर्जी
8	केन्द्रीय सडक शोध सस्था .	नई दिल्ली .	16 जुलाई, 1952	ई० जीपेक्स
9	केन्द्रीय वैद्युत-रासायनिक . शोध सस्था	कराइकुडी	15 जनवरी, 1953	बी० बी० डे
10	केन्द्रीय चर्म शोध संस्था	मद्रास	16 जनवरी, 1953	बी० एम० दास
11	केन्द्रीय भवन निर्माण शोध सस्था	रुडकी .	13 अप्रैल, 1953	के० बिल्लिग
12	केन्द्रीय इलैक्ट्रौनिक इंजीनियरिग सस्था	पिलानी .	21 सितम्बर, 1953 को शिलान्यास हुआ ।	—
13	राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान .	लखनऊ .	अप्रैल, 1953 .	के० एन० कौल

इन तेरह संस्थाओं के अतिरिक्त भावनगर मे एक केन्द्रीय लवण शोध केन्द्र खुल रहा है, जिसके डायरेक्टर डा० माता प्रसाद होंगे। कौंसिल ने लखनऊ में सिकन्दरा उद्यान को अपने कब्जे में ले लिया है, और यह प्रस्ताव है कि अध्यापक के० एन० कौल के सचालकत्व मे इसे एक राष्ट्रीय उद्भिद वैज्ञानिक उद्यान के रूप में विकसित किया जाये। पचवर्षीय योजना मे एक यांत्रिक इजीनियरिग प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की व्यवस्था है।

यहा यह बता दिया जाये कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ का उद्देश्य किसी भी प्रकार देश की अन्य शोध सस्थाओ के कार्य को दबाना या उन मे रोडे अटकाना नही है, बल्कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ को बनाने मे सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि वे उन सस्थाओ के सहायक के रूप में काम करे। यह बडी खुशी की बात है कि हमारे देश मे ऊपर गिनाई हुई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण शोध सस्थाए है। यह शोध सस्थाए भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञानो से सम्बन्ध रखती है। ये सस्थाए विशुद्ध शोध तक ही अपने कार्यक्षेत्र को सीमित रखती है और सरकार से स्वतत्र रूप से कार्य करती है —

1.—प्राचीन उद्भिद विद्या सम्बन्धी बीरबल साहनी सस्था, 53 युनिवर्सिटी रोड लखनऊ।

2—बोस शोध सस्था, 93 अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता।

3.—इडियन एसोसियेशन फार दी कल्टीवेशन आफ साइंस, बौ बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता।

4—इडियन इस्टीच्यूट आफ साइस, बगलौर।

5.—इडियन एकेडैमी आफ साइस (रमन इन्स्टीच्यूट) की प्रयोग शालाए, मल्लेश्वरम बगलौर।

6 टाटा इन्स्टीच्यूट आफ फडामैटल रिसर्च, बम्बई।

पहले ही बताया गया है कि कौसिल आफ साइटिफिक एण्ड इडस्ट्रियल रिसर्च एक बहुत बडा काम कर रही है। इसका एक मुख्य काम यह भी है कि औद्योगिक शोध सस्थाओं के निर्माण मे सहायता दे। यह खुशी की बात है कि अहमदाबाद कपडा मिल उद्योग बम्बई की असली तथा नकली रेशम की मिले, कलकत्ते की जूट मिले तथा दिल्ली स्थित औद्योगिक शोध सम्बन्धी श्रीराम इस्टीट्यूट उल्लिखित प्रकार की सस्थाए है। इन सस्थाओं को सरकार कुछ सहायता देती है, पर जिस उद्योग से सस्था का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, वही इसका अधिकाश खर्च उठाता है। कौसिल इस प्रकार की शोध सस्थाओ को स्वीकृति देती है।

सहायता प्राप्त शोध

विश्वविद्यालयो तथा दूसरी शोध सस्थाओ मे जो मौलिक तथा व्यावहारिक शोध कार्य चालू है, उन्हे प्रोत्साहन देने के लिये कौसिल धन की सहायता देती है। कौसिल की देखरेख मे चालू तथा जल्दी ही चालू होने वाली शोध योजनाओ की सख्या 117 है। ये शोध योजनायें या तो वैज्ञानिक सस्थाओ के जरिये चालू हो रही है या विश्वविद्यालयो के जरिये।

1952–53 में बोर्ड आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च के महत्वपूर्ण कार्य

हमारा देश एक महादेश है इसलिये इसमे आश्चर्य नही कि यहा पर 30 विभिन्न सम्वत्सर पद्धति एक साथ चालू है। यदि उनमे से प्रत्येक पद्धति का इतिहास देखा जाये, तो ज्ञात होगा कि

भूतकाल की किसी न किसी राजनीतिक तथा सास्कृतिक घटना या परम्परा के कारण वह चालू हुई है तथा जारी रही। कहना न होगा कि निजी तौर पर कोई कुछ भी माने सरकार अपने सारे कामो के लिये केवल एक सम्वत्सर पद्धति को ही स्वीकार कर सकती थी। इस काम के लिये भारत सरकार ने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० मेघनाद साहा के सचालकत्व मे सम्वत्सर सुधार समिति नाम से एक सस्था स्थापित की। यह सस्था भी कौसिल आफ साइटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च की देखरेख मे काम कर रही है। अभी इस समिति का कार्य चालू है, पर ज्ञात हुआ है कि वैज्ञानिक आधार पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सौर सम्वत्सर पद्धति तैयार करने की योजना है। यह न समझा जाये कि चाद्र सम्वत्सर पद्धतिया इससे समाप्त हो जायेगी, धार्मिक कार्यों के लिये कई क्षेत्रो मे चाद्र वर्ष का होना जरूरी है। पर यह आशा की जाती है कि चांद्र सम्वत्सर पद्धतियो को सौर पद्धति से निकट कर दिया जायेगा। प्राचीन काल मे हमारी गणनाओं मे उज्जैन को विशेष महत्व प्राप्त था, तद्नुसार यह तय हुआ है कि उज्जैन जिस अक्षाश पर स्थित है, यानी ग्रीनविच 82.5° से पूर्व मे किसी स्थान पर एक केन्द्रीय स्थान चुना जाये जहा से भारत की सारी गणना की जाये। यो तो हमारे यहा कई वेधशालाये है, पर आधुनिक सूक्ष्म यत्रों से समन्वित एक केन्द्रीय वेधशाला की जरूरत थी। इसी बात को देखते हुए इस समिति ने इसकी भी सिफारिश की है। इस बीच मे और भी जो काम हुआ है, उसका व्यौरा यो है कि आगामी 5 साल के लिये एक प्रयोगात्मक चाद्र-सौर सम्वत्सर पद्धति कायम की जाये। श्री जे० आर० डी० टाटा के सभापतित्व मे एक गैस टरबाइन और जैट प्रौपल्शन इजन कमेटी भी कायम हुई है। इस कमेटी का काम यह होगा कि वह गैस टरबाइन और जैट प्रौपलशन इजनो के सम्बन्ध मे शोध करे और भारत मे उनका निर्माण करे।

रेडियो शोध कार्य

हमारे देश मे अब रेडियो को कितना महत्व प्राप्त हुआ है यह सभी को मालूम है, तद्नुसार एक रेडियो शोध समिति कायम की गई है जो रेडियो के वल्बो, रेडियो तरगो के वितरण तथा ध्रुवीकरण और लघु तरगो के अन्तर्निधान के सम्बन्ध मे शोध करेगी। इसके अलावा यह समिति वातावरण तथा आयनोस्फीयर के सम्बन्ध मे खोज कर रही है। अपने शोध के परिणामो को यह समिति बुलेटिनो के रूप मे प्रकाशित करती है। दुनिया के और हिस्सो मे इस सम्वन्ध मे जो शोध कार्य हो रहे है उनके परिणाम भी बुलेटिनो मे प्रकाशित होते है। इन बुलेटिनो के पारस्परिक विनिमय से दोनो पक्षो को लाभ होता है।

फर्मासी में उत्पन्न द्रव्य तथा दवाएं

पहले ही लखनऊ के ड्रग रिसर्च इस्टीच्यूट का उल्लेख किया जा चुका है। इस सस्था की ओर से जम्मू और काश्मीर मे जडी बूटियो के शोध के सम्बन्ध मे एक दीर्घकालीन कार्यक्रम चालू है। इसके साथ ही देश मे जिन विभिन्न जडी बूटियो का इस्तेमाल होता है, उन पर भी शोध किये जा रहे है, जिससे मालूम हो सके कि कहा तक लोगों का विश्वास सही है। दूसरे देशो की जडी बूटिया यहा आ कर किस हद तक उत्पन्न हो सकती है या नही, इस सम्बन्ध मे भी खोज की जा रही है।

गुलाब के पौधों पर खोज

गुलाब की कदर सारी दुनिया मे है इसलिये इसमें आश्चर्य नही कि विशेष रूप से गुलाब के पौधो पर खोज की गई। भूमि और जलवायु के साथ गुलाब की खेती का क्या सम्बन्ध है, गुलाब की कौन सी किस्मे खेती के लिये सब से उपयोगी है तथा विभिन्न गुलाब मे से कौन से गुलाब तथा उन की उपजो मे अधिक सुगन्ध होती है उन पर शोध कार्य किया जा चुका है और परिणाम जल्दी ही प्रकाशित होगा ।

प्लास्टिक

देखते देखते प्लास्टिक का धन्धा कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, यह सभी को मालूम है । इसलिये यह उचित ही है कि प्लास्टिक रिसर्च कमेटी की देखरेख मे शोधयोग्य समस्याओं की सूची तैयार हो चकी है और वह जल्दी ही प्रकाशित होगी ।

आंकड़ेगत गुण नियंत्रण का प्रशिक्षण और शोध

कौसिल आफ साइटिफिक एण्ड इडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से बम्बई के इडियन स्टैटिस्टिकल इस्टीच्यूट से आकडेगत गुण नियत्रण के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण देने की एक योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस सम्बन्ध मे सयुक्त राष्ट्र संघ के भारत मे मौजूद विशेषज्ञो से सलाह ली गई । 1952 के अक्तूबर मे आकडेगत गुण नियत्रण समिति की सभा मे विशेषज्ञ समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विचार किया गया। इसके बाद अध्यापक महलानबिस ने एक उन्नततर शिक्षण तथा शोध सम्बन्धी कार्यक्रम दिया जिस पर विचार हो रहा है।

भारतीय चट्टानों का वय-निर्णय

भूगर्भ विज्ञान मे चट्टानो का वय-निर्णय एक प्रमुख विषय है। इस सम्बन्ध मे भूगर्भ वैज्ञानिक समय प्रमापन समिति कार्य कर रही है। इस कार्य के लिये भौतिक, रासायनिक तथा प्राचीन उद्भिद विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम काम मे लाया जा रहा है । आंध्र विश्वविद्यालय मे समुद्र परिमापन शोध के सम्बन्ध मे भी एक नया तरीका काम मे लाया जा रहा है। यह कार्य अमेरिका के अध्यापक ई० एस० ला फौन्ड की देखरेख मे चल रहा है, जो समुद्र परिमापन सम्बन्धी स्क्रिप्स सस्था के सदस्य है । अभी परिमापन का काम बहुत प्रारम्भिक अवस्था मे है, फिर भी भारत के पूर्वी तट के सरसरी परिमापन से समुद्रगर्भ की गहराई, भूगर्भवैज्ञानिक विशेषताओ, चट्टानों की तेजोद्गर अन्तर्गत वस्तु तथा समुद्र के गर्भ के प्राणियो और उद्भिदो के सम्बन्ध मे बहुत उपयोगी सूचनाये प्राप्त हुई है । कहना न होगा कि यह काम अभी उस हद तक नही हुआ है जितना कि होना चाहिये । आशा की जाती है कि जल्दी ही इस कार्य का विस्तार होगा ।

भारत के वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के लिये एक अभाव यह भी रहा कि उन्हे आवश्यकतानुसार दुष्प्राप्य रासायनिक पदार्थ प्राप्त नही होते थे । इसलिये पूना की राष्ट्रीय रासायनि प्रयोगशाला इस सम्बन्ध मे कार्य कर रही है, और यह आशा की जा रही है कि उनके द्वारा बनाई हुई योजना के अनुसार कुछ दुष्प्राप्य रासायनिक पदार्थ शोध कार्य करने वालों को उचित मूल्य पर प्राप्त होगे ।

भौतिक विज्ञान पर शोध

दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला मे आर० एफ० अम्मीटरस शोध योजना के फलस्वरूप तैयार हुए और उनके डिजाइन बने। ये परीक्षण मे सन्तोषजनक पाये गये। अब नागरिक उड्डयन तथा प्रतिरक्षा सेवाओ मे उनका परीक्षण हो रहा है।

विज्ञान मंदिर

विज्ञान को गाव वालो तक ले जाना एक महान् उद्देश्य है। तदनुसार दिल्ली राज्य के गाव मे एक विज्ञान मन्दिर की स्थापना की गई है। इस मन्दिर का उद्देश्य गाव वालो को खेती तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे उठने वाली दैनिक समस्याओ पर सलाह देना है। विज्ञान मन्दिर नई समस्याओ पर भी विचार करेगा। इसमे भूमि और जल का विश्लेषण किया जायेगा और बीमारियो के सम्बन्ध मे भी अध्ययन होगे। इस मन्दिर से गाव वालो मे वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार किया जायेगा और आसान साहित्य का वितरण होगा। केवल सलाह देने से ही काम नही चल सकता, इसलिये पौधो की बीमारियो को दूर करने के लिये आवश्यक चीजे भी मन्दिर मे मिल सकेगी। दिल्ली का यह प्रयोग सफल रहा तो भारत भर मे विज्ञान मन्दिर खोले जायेगे।

इंजीनियरिंग शोध

1950 में इजीनियरिग सम्बन्धी शोध कार्य को आगे बढाने के लिये बोर्ड आफ इजीनियरिग रिसर्च की स्थापना हुई। इसकी सहायक समितियो के रूप मे 5 विशेषज्ञ समितिया काम करती हैं, जैसे (1) असैनिक इजीनियरिग समिति, (2) यत्रसम्बन्धी इजीनियरिग समिति, (3) बिजली और रेडियो इंजीनियरिग समिति, (4) हाइड्रोलिक समिति और (5) वायुयान विज्ञान सम्बन्धी इजीनियरिग समिति। इस बोर्ड के सामने विशेषरूप से दो कार्य है, एक तो देश मे इजी-नियरिग शोध से प्राप्त सुविधाओ का परिमापन तथा दूसरे उन समस्याओ का पता लगाना जो अभी तक हल नही की जा सकी।

प्रकाशन

कौसिल जो काम कर रही है, उसके सम्बन्ध मे लोगो को जानकारी देने के लिये कई पत्र–पत्रिकाये निकलती रहती है। अग्रेजी मे **'जरनल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च'** और हिन्दी मे **विज्ञान प्रगति** मासिक साहित्य के रूप में प्रकाशित हुई है। इनका उद्देश्य जनता में विज्ञान का प्रचार करना है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाये अपनी बुलेटिन प्रकाशित करती है।

भारत मे कौन कौन से कच्चे माल प्राप्त है उस के सम्बन्ध मे 11 जिल्दो मे एक ग्रन्थ प्रका-शित हो रहा है, जिन मे से चार जिल्दे प्रकाशित हो चुकी है। समय-समय पर और भी छोटी मोटी पुस्तिकाये तथा परिमापन रिपोर्टे प्रकाशित हुई है। इस सस्था की ओर से जो सबसे ताजी रचनाये प्रकाशित हुई है उनके नाम इस प्रकार है (1) वनस्पति की बनावट तथा पौष्टिक मूल्य पर शोध, (2) भारतीय फर्मासी ग्रन्थ।

यहा के विभिन्न द्रव्यो के परिमापन के साथ साथ कौसिल यहा की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक जनशक्ति के सम्बन्ध मे भी एक विस्तृत पूजी तैयार कर रही है। इस पुस्तक के लिखे जाने के समय तक 40,000 से ऊपर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विशेषज्ञो के सम्बन्ध मे सूचना एकत्र की जा चुकी है।

वैज्ञानिक सम्पर्क

भारत मे विज्ञान की उन्नति के लिये इतना ही यथेष्ट नही है कि भारत के वैज्ञानिक परस्पर विचार विनिमय ही करते रहे, बल्कि इस के साथ यह भी जरूरी है कि हमारे वैज्ञानिको का सम्पर्क संसार के अन्य वैज्ञानिको के साथ बना रहे। इसी उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार की ओर से एक वैज्ञानिक कर्मचारी इंग्लैड मे नियुक्त है, जो कामनवैल्थ के देशो के अन्दर वैज्ञानिको के आने जाने मे सहायता देता है। ससार के वैज्ञानिक निरन्तर जो नये आविष्कार कर रहे है, यह कर्मचारी सरकार को उन से परिचित कराता रहता है, और साथ ही भारतीय छात्रो के लिये विदेशो मे विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध करता रहता है।

राष्ट्रीय शोध विकास कारपोरेशन

हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशाला मे निरन्तर नई-नई प्रक्रियाये तथा पद्धतियो का आविष्कार होता है। यदि केवल इन बातो को विज्ञान की पुस्तको तक ही सीमित रखा जाये, तो कोई विशेष लाभ नही है। निजी व्यापारियो से यह आशा नही की जा सकती कि वे उन आविष्कारो को फौरन ही काम में लायेगे, तथा उस के लिये आवश्यक विपत्ति उठायेगे। इस खतरे से बचने के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोध विकास कारपोरेशन नाम से एक सस्था की स्थापना की है। यह सस्था आविष्कृत तरीकों का प्रयोग कर नये यत्रो तथा आविष्कारो का परीक्षण करेगी। जब परीक्षण मे आविष्कार खरे उतर जायेगे, तब तो निजी व्यापारी स्वय ही उस ओर बढेगे।

आणविक शक्ति आयोग

सारे ससार मे आणविक शक्ति के सम्बन्ध मे जो क्रियाशीलता चालू थी, उसे देखते हुए भारत सरकार इस ओर से उदासीन नही रह सकती थी। इसलिये 1948 के आणविक शक्ति ऐक्ट के अनुसार अगस्त 1948 मे आणविक शक्ति आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का काम यह है कि आणविक शक्ति के विकास और उपयोग सम्बन्धी सारे विषयो पर काम करे।

आणविक शक्ति शोध बोर्ड तथा कास्मिक रश्मि समिति आयोग के काम मे हाथ बटाती है। हमारे यहा गणित, रसायनशास्त्र, भौतिक विज्ञान पर अध्ययन का मान-दण्ड उतना ऊचा नही था जितना कि उच्च वैज्ञानिक अध्ययन के लिये आवश्यक है। इस उद्देश्य से आयोग ने देश की कई शिक्षा सस्थाओ को काफी अनुदान दिया है। आयोग ने शोध सम्बन्धी जो कार्यक्रम बनाया है, उसके अनुसार विश्वविद्यालय, टाटा इस्टीट्यूट तथा दूसरी सस्थाओ मे शोध कार्य हो रहा है।

कास्मिक रश्मि सम्बन्धी शोध करने के लिये आयोग की ओर से कलकत्ता के इस्टीट्यूट आफ न्यूक्लेयर फिजिक्स तथा बोस रिसर्च इस्टीट्यूट को तथा अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी को सहायता दी जाती है। इस मद मे प्रतिवर्ष कई लाख रुपये खर्च होते है।

आयोग ने तिरुवाकुर-कोचीन के अल्वाए नामक स्थान मे भारतीय दुष्प्राप्य मिट्टिया लि० स्थापित की है। इस कारखाने पर भारत सरकार और तिरुवाकुर-कोचीन की सम्मिलित मिल्कियत है। 1952 के अप्रैल मे यह कारखाना स्थापित हुआ था,

और इस में मोनाजाइट का प्रोसेसिंग होता है । इसी कारखाने मे बहुत लाभ हो रहा है, और साथ ही भारत को युद्धोपयोगी माल भी मिल रहा है। अब तक इस कारखाने मे यूरेनियम और थोरेनियम निकालने का कोई उपाय नही था, और इस के लिये वही एक दूसरा कारखाना खुल रहा है । इस कारखाने मे जो दुष्प्राप्य मिट्टियो वाला नमक प्राप्त होता है, उसमें से कुछ गैस मैन्टल धन्धे मे लगा दिया जायेगा और बाकी भविष्य के लिये रख दिया जायेगा ।

न्यूक्लेयर शोध

भारत मे अभी कई मामलो मे जैसे न्यूक्लेयर शोध मे तो अभी हाल ही मे शुरुआत हुई है। इस सम्बन्ध मे 1945 मे स्थापित टाटा इस्टीट्यूट अग्रगामी रहा है । यह सस्था वित्तीय सहायता के लिये भारत सरकार पर निर्भर करती है और शोध करने के अतिरिक्त छात्रो को प्रशिक्षण भी देती है। 1950 में कलकत्ता मे मदाम जोलियो कूरी ने इस्टीट्यूट आफ न्यूक्लेयर फिजिक्स की स्थापना की ।

चौदहवां अध्याय
उद्योग धन्धे

हमारे देश के लिये सब से बडी समस्या यह रही है कि जमीन पर बोझ घटाया जाये। यह सौभाग्य की बात है कि इधर हमारे देश मे औद्योगिक प्रगति तेजी से हुई है। 1952 में प्रगति काफी रही। नीचे की तालिका से ज्ञात होगा कि 1952 मे औद्योगिक उत्पादन का देशनाक 128 9 तक पहुंचा हुआ था जो युद्ध के बाद के वर्षो के लिये सर्वोच्च है :

तालिका 94
(आधार : 1946=100)

वर्ष	औद्योगिक जनसख्या का देशनाक	औद्योगिक जनसख्या का त्रैमासिक देशनाक		
		तिमाही	1951-52	1952-53
1947 . .	97·2	I	117·3	126·7
1948 .	108·4	II	117·7	128·2
1949 .	106·1	III	121·3	133·5
1950 .	105·0	IV	126·0	132·4
1951 .	117·2			
1952 .	128·9			

कुछ उद्योगो मे विशेष तरक्की रही, जैसे सूती कपड़े, पटसन का माल, चीनी, नमक, दियासलाई, कागज, कागज का गत्ता, बिजली की बत्तिया, कृत्रिम रेशमी सूत तथा सिलाई की मशीने। यदि यह विचार किया जाये कि यह बढती क्यो हुई तो यह ज्ञात होगा कि दो बाते मुख्यत. इस के लिये जिम्मेदार है। एक तो मालिक और मजदूरो का झगडा कम हो गया, और दूसरे कच्चे माल की पूर्ति अधिक हुई। पर इन बातो के होते हुए भी कुछ धन्धे ऐसे है जिन मे उत्पादन कम हुआ। इन धन्धो मे मुख्य ये है .—

अल्यूमीनियम, पम्प, डीजल इजन, यान्त्रिक औजार, करघे, हरिकेन लालटैन, सूखी और स्टोरेज बैटरी, सूपर फास्फेट, सलफ्यूरिक ऐसिड, सोडा ऐश, रग वाले पेन्ट, एनामेल, चमडा, शीशा तथा ऊन की चीजे। इन धन्धो मे अवनति इस कारण हुई कि सारी दुनिया मे बेचनेवालो के बाजार से खरीदने वालो के बाजार के रूप मे परिवर्तन हुआ।

1948 मे 13,120 स्थायी और 2,786 मौसमी कारखाने थे। कुल मिलाकर इन से राष्ट्रीय आय 6.6 प्रतिशत प्राप्त हुई थी। उत्पादन की मर्दुमशमारी के अनुसार उद्योगधन्धो के 29 वर्गो मे कुल उत्पादक पूजी का परिमाण 483 करोड रुपये, निर्दिष्ट पूजी का परिमाण 196 करोड रुपये और चालू पूजी 287 करोड रुपये की थी। इस के साथ यदि यह बात रक्खी जाये कि कई धन्धे इस गणना मे नही आये, तो भारतीय उद्योग धन्धो मे लगी हुई उत्पादक पूजी का परिमाण 650 करोड रुपये था। सब कारखानो मे कुल मिला कर पच्चीस लाख व्यक्ति काम कर रहे थे। इन सब बातो को देखते हुए 1948 मे ही ससार की औद्योगिक जातियो मे भारत को आठवा स्थान प्राप्त हुआ।

भारत मे पहली सूती मिल 1818 मे स्थापित हुई, पर यह केवल इतिहास के लिये है। असल मे 1854 मे बम्बई मे इस धन्धे का श्रीगणेश हुआ। सूती कपडे का धन्धा और पटसन का धन्धा यही दोनो भारत के मुख्य धन्धे है। जहा सूती कपडे का सूत्रपात बम्बई मे हुआ वहा पटसन के धन्धे का सूत्रपात कलकत्ते मे 1855 मे हुआ। स्थापना के स्थान के अतिरिक्त इन दोनो धन्धो मे एक फर्क और भी रहा। सूती कपडे के धन्धे के पीछे मुख्यत भारतीय पू जी और उद्योग था, पर पटसन के धन्धे के पीछे विदेशी पूजी और विदेशी उद्योग था। नीचे की तालिकाओ मे गत पचास वर्षो मे इन धन्धो मे जो प्रगति हुई है, दिखाई जा रही है :

तालिका 95

सूती कपड़ा उद्योग का विकास

वर्ष	मिलो की सख्या	तकुवो की सख्या (हजारो मे)	करघों की सख्या (हजारो मे)	उत्पादन	
				सूत (दस लाख पौडो मे)	पीस गुड्स
1901 .	178	4,841	40.5	573	120
1911 .	233	6,095	85.8	625	267
1921 .	249	7,278	133.5	694	403
1931 .	314	9,078	175.2	966	672
1941 .	396	10,026	200.2	1,577	1,093
1951 .	445	11,241	201.5	1,304	4,076 (दस लाख गज)

तालिका 96

पटसन उद्योग का विकास

वर्ष	मिलो की सख्या	अधिकृत पू जी (करोड रुपयो मे)	करघो की सख्या (हजारो मे)	तकुवो की सख्या (हजारो मे)
1879-80 से ले कर 1883-84 तक (औसत) .	21	2·71	5·5	88
1899-1900 से ले कर 1903-04 तक (औसत)	36	6·80	16·2	335
1909-10 से ले कर 1913-14 तक (औसत).	60	12·09	33·5	692
1925-26 . .	90	21·35	50·5	1,064
1930-31 . .	100	23·61	61·8	1,225
1937-38 . .	105	24·89	52·4	1,108
1951. . .	106			

1855 के लगभग इन दोनो धन्धो का आरम्भ हुआ, और प्रथम महायुद्ध छिडने तक ये ही दोनो धन्धे भारत के मुख्य धन्धे बने रहे। युद्ध के कारण भारतीय धन्धो को प्रोत्साहन मिला। उस युग की भारत सरकार समझ गई कि भारतीय धन्धो को प्रोत्साहन देना चाहिये, पर इस बीच में बहुत कुछ होते हुए भी 1922 मे ही भारतीय फिस्कल कमीशन की सिफारिश पर भारतीय धन्धो को सरक्षण दिया गया। इस से भारतीय धन्धो को बहुत फायदा रहा। 1922 और 1939 के बीच सूती पीसगुड का उत्पादन दुगुने से अधिक हो गया। इस्पात के इनगाट का उत्पादन आठ गुना हुआ, और कागज का उत्पादन ढाई गुना पहुचा। सब से मार्के की प्रगति चीनी के धन्धे मे हुई। सरक्षण मिलने के कारण 1932 से 36 के अन्दर देश चीनी के सम्बन्ध मे आत्मनिर्भर हो गया। यह एक बहुत बडी बात थी। सीमेन्ट का धन्धा भी जोरो पर हो गया, और 1935–36 तक यह धन्धा इतना बढ गया कि देश की सीमेन्ट सम्बन्धी जरूरत का 95 प्रतिशत भारत मे ही पूरा होने लगा। इसी प्रकार से दियासलाई, शीशा, वनस्पति, साबुन और इजीनियरिंग के कई धन्धो मे इस युग मे बहुत काफी प्रगति हुई। देश मे अब बिजली का सामान भी उत्पन्न होने लगा।

इस प्रकार प्रथम महायुद्ध से भारत के उद्योगधन्धो को बहुत फायदा रहा, पर दूसरे महायुद्ध में और भी अधिक फायदा रहा क्योंकि अब यह नारा लगाया गया कि जहा तक हो सके देश की जरूरत देश मे ही पूरी की जाये। इस कारण कई नये धन्धे चालू हो गये।

(देखिये पृष्ठ 231 पर तालिका 97)

नये धन्धो से लौह धातु मिश्रण, लौह धातु, डीजल इजन, पम्प, बाईसिकल, सिलाई की मशीने, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, क्लोरिन और सुपर फास्फेट का उत्पादन उल्लेखनीय है। इसी युग मे यंत्रसम्बन्धी औजार, सरल यन्त्र, चाकू, छुरी आदि तथा फर्मासी वाले द्रव्य उत्पन्न होने लगे। यह तो लडाई के जमाने की बात हुई। जब लडाई बन्द हो गई तो कई और नये धन्धे चल निकले। अब तो बाल और रोलर बेयरिंग, धुनाई इजन, रिंगफ्रेम और रेल इजन उत्पन्न होने लगे। यद्यपि इसके पहले से ही रासायनिक खाद, सीमेन्ट, शीशे की चादरे, कास्टिक सोडा, सल्फ्युरिक एसिड के धन्धे चालू हो चुके थे, फिर भी अब उन मे बहुत जोरो की वृद्धि हुई।

कोई भी देश केवल उपभोग द्रव्यों के उत्पादन से बडा नही हो सकता। यह सही है कि जनता के प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक उपभोग द्रव्य पहुचाना ही जनकल्याणकारी राष्ट्र का उद्देश्य है, पर जो देश केवल उपभोग के द्रव्य उत्पन्न करता है, वह आधारभूत पूजीवाले द्रव्यो के मामले मे दूसरे देशो पर निर्भर रहता है, इसलिये दूसरे देश जब चाहे तब उस की समृद्धि समाप्त कर सकते है। दुर्भाग्य से अब तक हमारे यहा उपभोग द्रव्यों के उत्पादन पर ही जोर रहा। विदेशी शासन से और क्या आशा की जा सकती थी। उपभोग द्रव्यो के मामले मे तो हम इतने आगे बढ गये थे कि सूती कपडा, चीनी, साबुन, दियासलाई और नमक मे हम बहुत कुछ आत्मनिर्भर हो चुके थे। बाकी द्रव्यो के मामले मे विशेषकर पूजी वाले द्रव्य तथा बीचकी उपजो को उत्पन्न करने वाले धन्धो मे हम अपनी वर्तमान आवश्यकता को भी पूर्ण करने मे असमर्थ रहे। लोहा और इस्पात के धन्धे मे तो हम देश की ५० प्रतिशत मौजूदा माग को भी पूरा नही कर सके। अल्यूमिनियम, लौह धातुमिश्रण, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, रासायनिक खाद तथा पट्रोल द्रव्यो मे हम बहुत ही पीछे है। बड यन्त्र, सिन्थिटिक दवाइया, एन्टीबायोटिक द्रव्य

तालिका 97

कुछ चुने हुए उद्योगों के उत्पादन आंकड़े

उद्योग	इकाई	1938	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952
तैयार इस्पात (क)	(000 टन)	702	954	890	893	857	930	1,004	1,076	1,103
सूत	(10 लाख पौंड)	1,289	1,644	1,367	1,296	1,447	1,360	1,175	1,304	1,450
सूती पीसगुड (ख)	(10 लाख गज)	4,306	4,711	3,908	3,762	4,319	3,905	3,665	4,076	4,598
पटसन से बना माल	(000 टन)	1,266	1,086	1,088	1,051	1,088	946(ख)	835(ख)	875(ख)	952(ख)
कागज और गत्ता	(000 हंडरवेट)	1,164	1,964	2,120	1,862	1,958	2,064	2,178	2,638	2,750
गन्धक का तेजाब	(000 हंडरवेट)	485	734	1,200	1,200	1,600	1,989	2,050	2,139	1,921
अमोनियम सल्फेट	(000 टन)	14·5	22·0	22·5	21·3	35·2	45·9	47·3	52·7	220·3
रंगवाला पेंट	(000 हंडरवेट)	572	1,030	768	772	714	618	559	670	643
दियासलाई	(10 लाख ग्रुस)	21·6	22·8	20·6	23·3	26·6	26·3	26·2	28·9	30·4
चीनी (ग)	(000 टन)	994	967	923	901	1,075	1,001	9,777	1,115	1,494
सीमेंट	(000 टन)	1,404	2,209	1,542	1,447	1,553	2,102	2,612	3,196	3,538
नमक (घ)	(000 मन)	43,968	54,602	47,868	51,600	63,528	55,620	71,316	74,376	76,860
कोयला	(000 टन)	28,344	28,716	28,884	30,000	29,820	31,452	31,992	34,308	36,228

द्रष्टव्य.—अगस्त, 1947 के बाद के आंकडे भारतीय यूनियन के लिये है।

(क) आकड़े भारतीय यूनियन के लिये हैं।

(ख) अगस्त, 1949 के बाद के आकडे उन मिलों के उत्पादन के लिये है, जो भारतीय जूट मिल एसोसियेशन की सदस्य हैं और एक ऐसी मिल के लिये भी है जो सदस्य नही है।

(ग) 1946 के बाद के आंकड़ों का सम्बन्ध नवम्बर से लेकर अक्तूबर तक के फसल-वर्ष के लिये है, और ये केवल गन्ने की शक्कर के लिये है।

(घ) 1946 तक के आंकड़े अप्रैल से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये है।

रंग का सामान, भारी रासायनिक पदार्थ का उत्पादन अभी अभी हम ने आर किया है। तालिका 97 में 1945 के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण धन्धों में व प्रगति हुई है, यह दिखाया गया है। इसी के साथ—साथ 1938 आंकड़े भी दिये गये हैं जिससे तुलना सम्भव है। छ मुख्य धन्धों के ब्यौरे इस प्रकार है:

तालिका 98

सूती कपड़ा

वर्ष	मिलों की संख्या	करघे (हजार)	तकुए (हजार)	उत्पादित सूत (दस लाख पौंड)	उत्पादित कपड़ा (दस लाख गज)	निय (ला गज
1947-48	408	197	10,266	1,330	3,770	19
1948-49	416	198	10,534	1,475	4,381	34
1949-50	425	200	10,849	1,290	3,779	69
1950-51	445	201	11,241	1,162	3,676	1,21
1951-52	453	204	11,427	1,325	4,297	42
1952-53	453	204	11,427	1,500 (लगभग)	4,800 (लगभग)	65 (लगभ

पटसन का माल

वर्ष (जून-जुलाई)	मिलों की संख्या	उत्पादन (हजार टनों में)	निर्यात (हजार टनों में)	प्रति दिन नियोजित व्यक्तियों क संख्या (औसत
1947-48	104	1,035	896	3,15,00
1948-49	104	1,040	872	3,03,00
1949-50	104	825	754	2,78,30
1950-51	104	858	547	2,84,00
1951-52	104	945	797	2,76,00
1952-53	104	920	739	2,70,00

चीनी

वर्ष	मिलों की संख्या	उत्पादन (हजार टनों में)	चीनी की औसत प्राप्ति (प्रतिशत
1948-49	136	1,007	9.97
1949-50	139	978	9.89
1950-51	138	1,100	9.99
1951-52	139	1,483 (क)	9.57
1952-53	136	1,250 (लगभग)	9.95

(क) अब तक का अधिकतम उत्पादन

लोहा व इस्पात

वर्ष	कुल उत्पादन (हजार टनो मे)
1948-49	3,620 1
1949-50	3,973 4
1950-51	4,007 6
1951-52	4,309 3
1952-53	4,100 0

सीमेंट

वर्ष	उत्पादन (लाख टनो मे)	आयात (हजार टनो मे)
1948-49	16 2	147
1949-50	22 9	340
1950-51	26 9	19
1951-52	33 0	13
1952-53	36 0	13

कोयला व पत्थर का कोयला

वर्ष	उत्पादन (लाख टनो मे)	निर्यात (लाख टनो मे)
1948-49	280 1	11.2
1949-50	323 4	9 7
1950-51	361 8	36.9
1951-52	350 0	24 0 (लगभग)
1952-53		

साइकिल

वर्ष	बनायी गयी साइकिलो की संख्या	आयात की गई (सम्पूर्ण) साइकिलों की संख्या
1948-49	46,000	2,64,392
1949-50	67,000	2,68,148
1950-51	1,01,136	1,65,461
1951-52	1,20,288	2,83,100
1952-53	1,92,000	2,56,491

अल्युमिनियम

वर्ष	वार्षिक क्षमता	इन्गाट का उत्पादन (टनो मे)	धातु का आयात सभी रूप मे (टनो में)
1948		3,362	
1949		3 490	
1950		3,596	
1951	अलुमिना 16,000 इन्गाट 4,000 (क) चादरे और छल्ले 3,500	3 489	8,000 (औसत)
1952		3,941	

मशीनी औजार

वर्ष	फैक्ट्रियो की सख्या	कूती गयी वार्षिक क्षमता	उत्पादन
1950-51	14	3,000	1,101
1955-56 (लक्ष्य)	15	4,600	4,600

बागान वाले धन्धे

हमारे देश मे चाय, कहवा और रबड़ के धन्धे खेती वाले भाग के कुल 0 4 प्रतिशत भाग मे फैले हुए है। भारत के उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिण-पश्चिमी हिस्सो मे इनका बोलबाला है। पर विदेश से धन लाने की दृष्टि से ये धन्धे बहुत महत्वपूर्ण है, और इन से भारत को 80 करोड़ रुपये के मूल्य का विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। केवल चाय से ही 78 करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। इस तथ्य के अतिरिक्त यह भी तथ्य कम महत्वपूर्ण नही है कि इन धन्धो से हमारे देश के 10 लाख से अधिक परिवार पलते ह। पहले कहवा और रबड़ बाहर भेजा जाता था, पर अब मुख्यत. देश मे ही उनकी खपत है। 1950-51 मे लगभग 1 करोड़ 20 लाख पौण्ड रबड बाहर भेजी गयी। यह अनुभव किया गया कि हमारे यहा रबड़ की खेती बढाई जा सकती है। तदनुसार रबड बनाने की विकास समिति ने एक पन्द्रह साल की योजना बनाई है। बागान वाले 3 धन्धो मे हाल मे कैसी प्रगति हुई है, यह तालिका 99 मे दिखलाया गया है।

(क) इडियन अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड 2,500; अल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑव् इडिया लिमिटेड, 1,500।

तालिका 99

बागान उद्योग

चाय

वर्ष	जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार एकडो मे)	उत्पादन (दस लाख पौण्डों मे)
1947 .	842	600
1948 (क)	773	567
1949 .	773	586
1950 .	777	606

कहवा

वर्ष	जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार एकडो मे)	उत्पादन (हजार टनो में)
1946-47 .	216.9	45·4
1947-48 .	218.8	15.8
1948-49 .	221.0	21.6
1949-50 .	224 6	20.1
1950-51 .	224.6	18.3

रबर

वर्ष	जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार एकडो में)	उत्पादन (हजार टनो में)
1947 .	129	16.4
1948 .	119	15·4
1949 .	124	15.6
1950 .	138	15.6
1951 .	149	17.1

(क) केवल भारतीय यनियन के लिए ।

औद्योगिक नोति

हमारे देश की औद्योगिक नीति क्या होनी चाहिये यह एक एसा विषय है जिस पर कई तरह के विचार प्रचलित थे। इसलिये 1948 की 7 अप्रैल को भारतीय ससद मे उद्योग नीति के सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव पास किया गया जिस मे यह कहा गया कि (1) कुछ धन्धे जैसे अस्त्रशस्त्र, आणविक शक्ति का धन्धा और नियत्रण, रेल मार्ग की मिल्कियत तथा व्यवस्था सम्पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन होगे, (2) दूसरे कुछ धन्धो मे जैसे कोयला, लोहा और इस्पात का उत्पादन, हवाई जहाज और जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ और बेतार के सामान का उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन, इन धन्धो मे और उन्नति करना राज्यो की जिम्मेदारी होगी। हा, जितनी हद तक निजी धन्धो के सहयोग की आवश्यकता है उतनी ली जाएगी और (3) औद्योगिक क्षेत्रो का बाकी हिस्सा निजी धन्धे, वैयक्तिक उद्योग तथा सहकारी सस्था पर निर्भर होगा। हा, इन पर केन्द्रीय नियत्रण रहेगा, तथा कुछ ऐसे धन्धो पर जो लागत तथा प्रौद्योगिक कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नियत्रण भी रहेगा। योजना आयोग ने ससद की नीति का समर्थन किया। बात यह है कि हमारे यहा यह मान लिया जा चुका है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था मिश्र पद्धति की होगी। योजना आयोग ने यह भी माना है कि इसी आधार पर हमारे औद्योगिक धन्धो की अट्टालिका खडी हो सकेगी। दूसरे शब्दो मे यह कहा जा सकता है कि हमारे यहा सरकारी धन्धे और निजी धन्धे साथ साथ चलेगे। निजी धन्धो को हर हालत मे हमारी प्रगति सम्बन्धी योजना के अनुसार चलना पडेगा, और उन्हे राष्ट्र के नियत्रण मे काम करना पडेगा। योजनात्मक उन्नति के लिये यह व्यवस्था जरूरी है।

1951 मे एक औद्योगिक विकास और नियत्रण विधि पारित हुई, जो 1952 की 8 मई से लागू हो गई। इस विधि का उद्देश्य यह है कि हमारी औद्योगिक उन्नति द्रुत हो। इसलिये इस विधि से उद्योग धन्धो के लिये केन्द्रीय परामर्श परिषद् की स्थापना हुई है। जो कारखाने इस समय चालू है, उन्हे अपने को पजीकृत कराना पडेगा और नये कारखानो को लाइसेन्स लेना पडेगा। यदि केन्द्रीय सरकार को किसी कारखाने के सम्बन्ध मे ज्ञात हो कि इसमे कुछ ऐसी त्रुटिया है जिसके कारण उत्पादन नही बढ रहा है, तो केन्द्रीय सरकार उस हालत मे जाच कर सकेगी और कुछ निर्देश देगी। इस प्रकार ये त्रुटिया दूर कर दी जायेगी। यदि सरकार द्वारा दिये हुए निर्देश काम मे न लाये जाये, तो सरकार को इस विधि के अनुसार अधिकार होगा कि उन धन्धो को अपनी देखरेख मे चलाये। इस विधि के अनुसार केवल 37 धन्धे या धन्धो के वर्ग के नियंत्रण के लिये व्यवस्था थी, और इस मे से प्रत्येक धन्धा या धन्धो के वर्ग के लिये एक विकास परिषद् की स्थापना की व्यवस्था थी। पर 1953 मे एक सशोधन के द्वारा इस सूची मे रेशम, कृत्रिम रेशम, रंग का सामान, साबुन, प्लाइवुड, फेरोमैंगनीज जोड दिये गये। पहले इस विधि के अनुसार कारखाने ऐसा देखरेख से बरी थे जिन मे 1 लाख रुपये से कम पूजी लगी हुई थी, पर अब यह रोक भी हटा दी गयी। पहले के मुकाबले मे अब सरकार को व्यवस्था और नियंत्रण के सम्बन्ध मे विस्तृत अधिकार मिले है। उक्त सशोधन के अनुसार अब आवश्यकता पड़ने पर किसी कारखाने पर संसद की स्वीकृति से 5 साल से अधिक समय तक भी नियंत्रण रक्खा जा सकता है।

1952 में विधि के अनुसार उद्योग धन्धो की जो केन्द्रीय परामर्श परिषद् बनी, उस में उद्योगधन्धे, श्रमिकवर्ग, उपभोक्ताओं तथा प्राथमिक उत्पादको के 27 प्रतिनिधि थे। 1952 के नवम्बर तक 3,562 कारखानो ने पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र दिये, और 2,209 इस विधि के अनुसार पंजीकृत हुए। इस बीच मे जो नये कारखाने खुले है, तथा मौजूदा कारखानो का

बिस्तार हुआ है, उस का ब्यौरा यह है कि सूती, तथा ऊनी कपड़े के धन्धे मे नौ इकाइयो, बिजली का सामान, इंजीनियरिंग, सीमेट और चीनी के धन्धो मे से प्रत्येक मे पाच इकाइयो, भारी रासायनिक पदार्थों मे तीन इकाइयो और तिलहन से उत्पन्न तेल के धन्धे मे चौदह इकाइयो को लाइसेस मिला। लाइसेस वाली समिति व्यापार और उद्योग मत्रालय, वित्त मत्रालय, रेल मत्रालय, उत्पादन मत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियो के द्वारा बनी है। सरकार इस सस्था के द्वारा इस सम्बन्ध मे अपना मत लोगो पर लागू कर सकती है कि कौन से धन्धे विशेष रूप से बढाये जाये। (1) भारी रासायनिक पदार्थ (ऐसिड) तथा रासायनिक खाद, और (2) आन्तरिक कम्बश्चन इजन के लिये दो विकास परिषदे स्थापित हुई है।

इन बातो के अतिरिक्त इस बात पर भी समय समय पर विचार करने की आवश्यकता है कि किन धन्धो को सरक्षण दिया जाये। यदि दिया जाये तो किस हद तक दिया जाये। इसके लिये अवनुविहित टैरिफ बोर्ड की जगह पर 1952 की जनवरी मे स्थापित अनुविहित टैरिफ कमीशन सामने आया। 1952–53 मे सब से पहली बार जिन धन्धो को सरक्षण मिला उन मे हाइड्रोक्वीनाइन, लोहा और इस्पात, मशीन स्क्रू, बिजली बत्तियो के पीतल के होल्डर, जीप फासनर और बाल बेयरिंग उल्लेखनीय है।

लागत और वित्त

यह देखा गया कि बहुत से नये धन्धो को स्थापित करने की आवश्यकता है पर इस प्रकार के धन्धो को चालू करने के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तदनुसार 1948 की जुलाई मे एक औद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना की गयी, जिस का उद्देश्य भारतीय उद्योग धन्धो को माध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देना है। 1950–51 मे कारपोरेशन ने 5·21 करोड़ रुपये और 1951–52 मे 6·55 करोड रुपये का ऋण दिया। 1951 मे राज्य वित्तीय कारपोरेशन ऐक्ट पारित हुआ, उसके अनुसार राज्य मे औद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना की व्यवस्था है। यह कारपोरेशन मझले और छोटे पैमाने के ऐसे धन्धो को आर्थिक सहायता देगा जो अखिल भारतीय औद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन के दायरे मे नही आते। तदनुसार 1953 की फरवरी मे पजाब वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना हुई। बम्बई, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर और तिरुवाकुर-कोचीन मे इस प्रकार की सस्थाओ की स्थापना की बात चल रही है।

केवल देश के अन्दर वित्त द्वारा सहायता यथेष्ट नही समझी गयी, बल्कि यह समझा गया कि विदेशो मे भी जहा तक हो सके खुलकर पूजी आनी चाहिये। इस से लाभ यह है कि पूजी वाले द्रव्यो तथा प्रौद्योगिक ज्ञान के रूप मे पूजी आती है। कही इस सम्बन्ध मे कोई गलतफहमी न हो, इसलिये 1948 की अप्रैल मे औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव मे विदेशी पूजी पर नीति स्पष्ट कर दी गयी। फिर 1949 की अप्रैल मे प्रधान मत्री ने भारत की सविधान सभा मे एक वक्तव्य दिया, उसमे भी इस का अधिकतर स्पष्टीकरण किया गया। इस सम्बन्ध मे भारत की नीति इस प्रकार है :—

(1) विदेशी पूजी और उद्योग को राष्ट्रीय हित मे नियमित करना आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप इस के साथ-साथ यह बात तो होनी ही चाहिए कि जहा तक हो सके मिल्कियत तथा नियत्रण, अपवादात्मक क्षेत्रो की

बात और है, हमेशा भारतीयो के ही हाथ मे हो, साथ ही भारतीयों को इस उद्देश्य से उपयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाये कि अन्ततोगत्वा वे विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ले ले ।

(2) सामान्य औद्योगिक नीति के बरतने मे विदेशी तथा भारतीय कम्पनी मे कोई भेदबुद्धिमूलक व्यवहार नही किया जायेगा ।

(3) देश की वैदेशिक विनिमय सम्बन्धी परिस्थिति से तालमेल रख कर मुनाफा बाहर भेजने तथा पूजी जहा से आयी है वहा भेजने के लिये उचित सुविधाएं दी जायेगी ।

(4) राष्ट्रीयकरण होने पर उचित और न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति दी जायेगी ।

सरकारी हिस्सा

यह पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे यहा यह मान लिया गया है कि निजी धन्धों के साथ-साथ सरकारी धन्धे भी रहेगे । पचवर्षीय योजना मे एक तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन औद्योगिक कार्यों के लिये 94 करोड रुपये की रकम नियत की गयी है, दूसरे आधारभूत धन्धो के लिये जिन मे परिवहन सम्बन्धी सहायक सुविधाए आ जाती है 50 करोड रुपया लगाने की व्यवस्था है । यह तो सरकारी धन्धो की बात हुई, निजी धन्धो के क्षेत्र मे औद्योगिक विस्तार के लिये यह अन्दाजा किया जाता है कि 233 करोड पये लगाये जायेगे । इसमे पुराने यन्त्रों आदि को बदलने तथा आधुनिकीकरण मे जो 150 करोड रुपये खर्च होगे, उस रकम को नही दिखाया गया है ।

पहले ही यह इगित किया जा चुका है कि लोहा और इस्पात के उत्पादन के मामले मे हमारा देश यथेष्ट पिछडा हुआ है । इसलिये पचवर्षीय योजना मे यह व्यवस्था की गयी है कि 80 करोड रुपये की लागत पर एक बहुत बडा औद्योगिक कारखाना खोला जाये जिस मे लोहा और इस्पात का उत्पादन किया जाये । यह न समझा जाये कि यह सारी रकम तुरन्त ही लगा दी जायेगी । सच तो यह है कि 1955–56 तक कुल 30 करोड पये ही लगाये जायेंगे । इस रकम में से सरकार केवल 15 करोड रुपये देगी, और बाकी रकम देशी और विदेशी सूत्रो से आयेगी । यह आशा की जाती है कि इस कारखाने की उत्पादन सामर्थ्य आठ लाख टन लोहा और कम से कम साढे तीन लाख टन इस्पात की होगी। इस कार्य को अच्छे से अच्छे ढग से चलाने के लिये अभी हाल ही मे भारत सरकार ने प्रसिद्ध जर्मन कम्बाइन क्रुप्स डेमाग के साथ एक समझौता किया है, जिस के अनुसार यह कम्पनी प्रौद्योगिक सहायता देने के अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिक कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षण भी ेगी ।

यह एक बहुत ही मार्के की बात है कि उपभोग द्रव्यो का उत्पादन निजी धन्धों पर ही छोड दिया गया है । सरकारी धन्धो मे केवल वे ही धन्धे रक्खे गये है, जैसे पूजी वाले द्रव्य और अत्यन्त आवश्यक बीच की उपजे । वर्तमान तथा भविष्य मे हमारे आर्थिक विकास के लिये जो बाते जरूरी है और होगी, उन्ही पर सरकार अपना ध्यान केन्द्रित करेगी । तालिका 100 में खर्च तथा सार्वजनिक क्षेत्रो के कारखानो आदि के सम्बन्ध मे ब्यौरे दिये गये है ।

निजी धन्धे

पहले हम यह बता चुके है कि निजी धन्धो के लिये उपभोग वाले द्रव्यो का उत्पादन छोड दिया गया है, पर इस का मतलब यह हरगिज नहीं कि निजी धन्धो के क्षेत्र मे केवल उपभोग द्रव्यो का ही उत्पादन होगा। तथ्य तो यह है कि निजी क्षेत्र मे 80 प्रतिशत पूजी वाले द्रव्य तो उत्पादक द्रव्यो के साथ-साथ विशेषकर लोहा और इस्पात (43 करोड रुपये), पेट्रोल शोधन (64 करोड रुपये), सीमेन्ट (13 करोड रुपये), अल्यूमिनियम (9 करोड रुपये) रासायनिक खाद, भारी रासायनिक पदार्थ और शक्ति सुरासार का उत्पादन होगा।

तालिका 100

सार्वजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक कार्य

कार्य	पूजी विनियोग (लाख रुपयो मे)				कार्य पूर्ण होने का वर्ष	1955-56 तक हो जाने वाली नयी अथवा अतिरिक्त वार्षिक क्षमता
	1951-52	1952-53	1953-54 बजट	1951-56 पाच सालो का योग		
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय सरकार						
1 लोहे व इस्पात का कार्य	—	10 00	10 00	3,000 0	1957-58	3,50,000 टन कच्चा लोहा
2 जहाज निर्माण (हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड)	232 05	328 56	232 00	1 408 0	1956-57	50,000 डी० डब्ल्यू० टी०
3 मशीनी औजार कारखाना जलहाली .	2 28	119 00	143.50	963.8	1953-54	1,600 इकाइया
4. सिंद्री खाद कारखाना .	274 62	—	—	903 0	अक्तूबर 1951	3,50,000 टन अमोनियम सल्फेट
5. चित्तरजन रेल इजन कारखाना	236.00	110 00	9 00	355.0	उत्पादन प्रारम्भ हो गया	100 रेल के इंजन

तालिका 100 (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7
6 रेल के डिब्बे बनाने वाला कारखाना (पेराम्बुर)	4 00	74.00	130 00	468 0	1955	50 इकाइया
7 पेनिसिलीन कारखाना, पिम्परी	2 08	22 50	64 00	206 6(क)	1954	48 लाख मेगा इकाइया
8 राष्ट्रीय औजार कारखाना, कलकत्ता	6 66	10 00	39 00	182 0	उत्पादन प्रारम्भ हो गया	64.4 लाख रुपये के औजार
9 भारतीय टेलीफोन उद्योग	65.00	33 00	82 00	130.0	विभिन्न भागो को जोडने का कार्य प्रारम्भ हो गया	200 लाख रुपये के टेलीफोन आदि
10 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (रूपनारायणपुर)	1.30	33 00	70 00	129 7	1953-54	100 लाख रुपये के केबुल्स
11 मंडी नमक कारखाना	—	2 25	1.00	100 0	1954	61,000 टन
12. वर्तमान नमक बनाने वाले कारखानो का विकास	4 42	5.00	8 00	50 0	1955-56	लगभग 3,68,000 टन
13 दुष्प्राप्य मिट्टी कारखाना, अलवाए	30.00	10 00	—	40 0	जून 1952	800 टन दुष्प्राप्य मिट्टी और 202 टन थोरियम कम्पाउण्ड
14 डी डी टी कारखाना, दिल्ली	—	10 00	7.45	39 1(ग)	1954	
15 हाउसिंग कारखाना, दिल्ली	12 91	4 55	2 00	19 5	1952-53	
16 अन्य कार्य (ख)	—	—	—	202.1	1955-56	700 टन
						—
योग	899 01	801.37	838 65	8,889 5		—

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्तराष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट कोष से प्राप्त 57 लाख रुपये के सहित —

(ख) नासिक छापाखाना, नयी टकसाल (अलीपुर), चादी शोधन कारखाना (अलीपुर), फोटोग्रैव्यूर प्रोजैक्ट, और स्टाम्प को रद्द करने वाली छापे की स्याही के सहित ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्तराष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट कोष से 3,50,000 अमेरिकी डालर सहित ।

I	2	3	4	5	6	7
राज्य सरकारें						
1 मैसूर लोहा व इस्पात कारखाना	40 08	80 00	100.00	283.0	1954–55	60,000 टन तैयार इस्पात
2 उत्तर प्रदेश सरकार का सीमेंट कारखाना . .	43 14	73 68	125.00	230 5	1953–54	2,00,000 टन
3 अखबारी कागज (नैपा मिल्ज)	50 33	47 00	130 00	200 0	1954	30,000 टन अखबारी कागज़ (300 कार्य के दिन)
4 सिरसिल्क लिमिटेड. .	65 57	51 43	—	200 0	1953–54	165 लाख गज नकली सिल्क (330 कार्य के दिन)
5 सिरपुर पेपर मिल्ज़. .	---	—	—	60 0	1953–54	8,000 टन
6 **उत्तर प्रदेश सूक्ष्म औजारों का कारखाना**	10 13	6 29	7.49	50 2	विस्तार कार्य	12,000 पानी के मीटर व 300 खुर्दबीन
7. बिहार सरकार का सुपरफोस्फेट कारखाना . .	40 00	23 09	26 15	41 1	1953–54	16,500 टन सुपरफोस्फेट (330 कार्य के दिन)
8. अन्य कार्य (क) . .	138 4	25 00	32 00	30 0	1955–56	
योग .	263.09	306 49	420 64	1,094 8		
सर्व योग .	1,162 10	1,107 86	1,259 29	9984 3		

(क) जिनमे मैसूर राज्य के कार्य व निरुवाकुर कोचीन की मिट्टी व चीनी मिट्टी की चीजें बनाने वाली फैक्ट्री भी शामिल है।

उपभोग द्रव्यो के धन्धो के क्षेत्र मे नये कारखाने खोलने पर उतना जोर नही है जितना कि इस बात पर कि जो कारखाने मौजूद है, वे अपनी सामर्थ्य का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। कुछ नये क्षेत्रो मे जैसे रेयन ,कागज, दवा तथा फर्मासी वाले द्रव्यो पर यथेष्ट खर्च होगा। सूत और ऊनी सूत के धन्धे मे भी थोडा बहुत विस्तार होगा।

कही किसी सम्बन्ध मे कोई अस्पष्टता न रह जाये इसलिये योजना आयोग ने प्रत्येक धन्धे के प्रतिनिधियो के साथ घनिष्ट रूप से मिलकर 42 सगठित धन्धो के सम्बन्ध मे ब्यौरेवार कार्य-क्रम बनाया है। कुछ खास बडे धन्धो के सम्बन्ध मे भी विस्तार का कार्यक्रम बनाया गया है, जो नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायेगा :

तालिका 101

निजी क्षेत्र में कुछ मुख्य दिशाओं में विस्तार का कार्यक्रम

	इकाई	1950-51		1955-56	
		कूती गई क्षमता	उत्पादन	कूती गई क्षमता	उत्पादन
1	2	3	4	5	6
(1) कृषि यत्र					
(क) शक्ति चालित पम्प	अक	33,460	34,310	64,400	80,000 से 85,000 तक
(ख) डीजेल इजन	अक	6,320	5,540	39,725	50,000
(2) अल्युमिनियम	टन	4,000	3,677	20,000	12,000
(3) मोटर गाडिया (केवल तैयार करना)	अक	30,000	4,077	30,000	30,000
(4) साइकिले	हजार	120	99	530	530
(5) सीमेंट	हजार टन	3,194	2,692	5,016	4,550
(6) विद्युत ट्रासफौरमर	हजार के वी ए	370	179	485	450
(7) खाद					
(क) अमोनियम सल्फेट	टन	78,670	46,528	1,31,270	1,20,000
(ख) सुपरफास्फेट	टन	1 23,460	55,089	1,92,855	1,64,000
(8) काच उद्योग शीशे की चादरे	टन	11,700	5,850	52,200	26,000
(9) भारी रासायनिक					
(क) कास्टिक सोडा	हजार टन	19	11	37	33
(ख) सोडा ऐश	,, ,,	54	45	86	78
(ग) गधक का तेजाब	,, ,,	150	99	213	192
(10) लोहा और इस्पात					
(क) कच्चा लोहा	,, ,,	1,850	1,572	2,700	1,950
(ख) इस्पात (प्रमुख उत्पादक)	,, ,,	975	976	1,550	1,280
(11) कागज व गत्ता	,, ,,	137	114	198	188

1	2	3	4	5	6
(12) पेट्रोलियम शोध					
(क) तरल पेट्रोलियम पदार्थ	दस लाख गैलन	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	403
(ख) बिटुमेन	टन	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	37,500
(13) शक्ति सुरासार	दस लाख गैलन	13	5	21	18
(14) रेल के इजन	अंक	---	---	50	50
(15) रेयन :					
(क) रेयन के तार	दस लाख पौंड	4	--	18	18
(ख) मुख्य रेशा	हजार गाठ	---	--	28	28

कुल मिलाकर निजी तथा सरकारी धन्धो के विकास के लिए 707 करोड रुपये की आवश्यकता है। इसमे चालू पूजी तथा मूल्यह्रास भी आ जाता है। विस्तार योजना का वित्त किस प्रकार जुटाया जायेगा उस का विवरण नीचे की तालिका में दिखलाया गया है:

तालिका 102

1951–56 में उद्योगों की अनुमानित आवश्यकताएं और उन के लिए वित्त-प्राप्ति के स्रोत

(करोड रुपयो मे)

अनुमानित आवश्यकताएं		
(1) सार्वजनिक क्षेत्र मे लगी हुई पूजी		94
(2) निजी क्षेत्र मे विस्तार, आधुनिकीकरण, तथा बदल के लिए लगाई गई पूजी		383
(3) चालू पूजी मे विनियोग		150
(4) चालू मूल्यह्रास व्यय जो सामान्य आय-कर की छूटों मे शामिल नही है		80
योग		707
वित्त प्राप्ति के स्रोत		
(1) सार्वजनिक-क्षेत्र के साधन जो सीधे लगाये गये है		74
(2) विदेशी पूजी		100
(3) घरेलू निजी उद्योग के साधन		533
(क) औद्योगिक क्षेत्र मे सम्मिलित प्रयत्नो की बचतें	200(क)	
(ख) नये निर्गमन	90	
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र से सहायता	5	
(घ) औद्योगिक वित्त कारपोरेशन	20	
(ङ) अतिरिक्त मुनाफा-कर की जमा से वापसी	60	
(च) अल्पकालीन वित्त के साधन, बैक आदि	158	
योग		707

(क) इस में सामान्य आय-कर छूटों के अंतर्गत आने वाले चालू मूल्यह्रास -व्यय के लिए की गयी व्यवस्था शामिल नही है।

प्रगति का लेखा

पचवर्षीय योजना को चालू हुए दो वर्ष हो गये । इस बीच में क्या प्रगति हुई यह एक महत्व-पूर्ण बात है । कुछ धन्धो मे जैसे सूती कपडे के क्षेत्र में 1955-56 के उत्पादन के लिये जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा हो चुका है । यदि उपभोग द्रव्य वाले सब धन्धो को एकत्र करके देखा जाये तो संक्षेप मे यह कह सकते है कि इन दो वर्षों मे सभी धन्धे 1955-56 वाले अपने लक्ष्य को 56 प्रतिशत तक पूरा कर चुके है । इसी प्रकार उत्पादक तथा पूजी वाले द्रव्यो मे लक्ष्य क्रमश 50 और 31 प्रतिशत पूरा हो चुका है ।

पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक सामर्थ्य को बढाने के सम्बन्ध मे भी कुछ लक्ष्य रखा गया है । इस क्षेत्र मे भी बहुत सतोषजनक प्रगति हुई है । उपभोग वाले द्रव्यो के क्षेत्र में औसत रूप मे लक्ष्य का 81 प्रतिशत तक उत्पादक द्रव्यो और पूजी वाले द्रव्यो मे क्रमशः लक्ष्य का 75 और 51 प्रतिशत प्राप्त किया जा चुका है । कई क्षेत्रो मे तो इतनी प्रगति हुई कि वह बहुत ही आशा-वर्धक है । 1952 के दिसम्बर तक 12 उत्पादक द्रव्यो के धन्धे तथा 6 उपभोग द्रव्यो के धन्धे 1955-56 वाले अपने लक्ष्य को 90 प्रतिशत तक पूरा कर चुके थे । कहना न होगा कि यह बहुत बड़ी बात है ।

जिन धन्धो मे विशेष मार्के की उन्नति हुई है, उन मे सूती कपडे और पटसन के कपडे, चीनी, लोहा और इस्पात, सीमेंट और कागज मुख्य है । इस्को, स्काब और टिस्को कम्पनियो की लोहा और इस्पात उत्पादन क्षमता को बढाने के साथ साथ पेट्रोल शोधनागार के सम्बन्ध में भी कार्य तेजी से चल रहा है । योजना मे जिन थोडे से नये उपभोग वाले द्रव्यो का प्रस्ताव रक्खा गया है, विशेषकर फर्मासी वाले धन्धे या तो उत्पादन करने लग गये है या करने ही वाले है । दूसरे नये धन्धो के यन्त्र और कारखाने लगभग तैयार है ।

1951-53 के युग मे केन्द्रीय सरकार के जिन 6 कारखानो मे काम शुरू हुआ वे इस प्रकार है (1) चित्तरजन इजन कारखाना, (2) भारतीय टेलीफोन उद्योग (3) अम्बरनाथ का यान्त्रिक औजार प्रोटोटाइप कारखाना, (4) सिद्री का रासायनिक खाद कारखाना, (5) दुष्प्राप्य मिट्टियों का कारखाना और (6) अलीपुर (कलकत्ता) की नई टकसाल ।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकारो के कार्य भी उल्लेखनीय है । राज्य सरकारो के कई कारखाने इस बीच मे चालू हो चुके है, और उन मे काफी प्रगति हुई है । उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश की सरकार का शुद्ध औजार कारखाना बहुत आगे बढ चुका है और अब उस मे अणुवीक्षण यन्त्र तथा जलमीटरो का उत्पादन हो रहा है । मैसूर मे लोहा और इस्पात का एक कारखाना था, उस का विस्तार हुआ है । और अब वह काम शुरू कर चुका है । 1952 से ही वहा एक बिजली की लोहे वाली भट्टी चालू थी और एक दूसरी भट्टी लगाई जा चुकी है । मध्यप्रदेश

सरकार का न्यूजप्रिंट कारखाना जल्दी ही काम शुरू करेगा, और ड्राइ कोर केबल कारखाना 1953-54 तक पूरा बन जाने की आशा है।

जहाज तैयार करने का कार्यक्रम भी बहुत आगे बढ़ चुका है और 1952 में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ने तीन जहाज तैयार किये। और भी दो जहाज तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिला कर 10 जहाज तैयार हो चुके हैं। पर इतने से ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, इसलिये इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है और यह भी आशा की जाती है कि बहुत अधिक संख्या में जहाज जल्दी ही तैयार हो सकेंगे।

सरकार मेसर्स बैसाखासिंह वालनबर्ग लि० के साथ साझेदारी मे वर्तमान मकान निर्माण सम्बन्धी कारखाने में फोम-कंकरीट रूफिंग पैनल तथा प्रीस्ट्रेस्ड ककरीट कम्पोनेन्ट इत्यादि का उत्पादन करेगी।

सरकार को प्रतिरक्षा विभाग की आवश्यकता का भी ख्याल है। रैडर और बेतार सम्बन्धी सामान के बिना कोई सरकार चल नही सकती। इसलिये एक फ्रैंच कम्पनी के साथ मिल कर सात करोड रुपये की लागत पर इन चीजो के निर्माण के लिए एक कारखाना खोलना निश्चित हुआ है।

शोध और प्रमापण

जैसा कि पहले अध्याय मे बताया जा चुका है, देश भर मे औद्योगिक और प्रौद्योगिक समस्याओ के समाधान के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाए स्थापित हुई है। यह बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसके बिना इस युग मे औद्योगिक धन्धे आगे नही बढ सकते। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रमापण का कार्य भी प्रामाणिक ढग से हो।

1947 मे इडियन स्टैंडर्ड इन्स्टीट्यूट नाम से एक सस्था स्थापित हुई थी जिसका उद्देश्य औद्योगिक तथा व्यापारिक उपजो का प्रमापण करना था। यह एक अर्ध सरकारी सस्था के रूप मे थी। 1952 तक इस सस्था की ओर से केवल 346 स्टैंडर्ड प्रमाणीकृत किये गये और 200 अतिरिक्त स्टैंडर्ड परीक्षार्थ घुमाये जा रहे थे, यानी विकास के अन्तिम सोपानो मे थे। 1952 मे इस सस्था के 777 ग्राहक तथा 3,602 समिति सदस्य थे। पेटेन्ट परामर्श समिति केन्द्रीय सरकार की शोध तथा प्रौद्योगिक सस्थाओ के आविष्कारो के लिये पेटेन्ट देती है। 1951 मे इसके पास अठारह पेटेन्ट विचारार्थ आये और 1952 मे 24 आविष्कार पेटेन्ट के लिये पेश हुए।

डायरेक्टरेट आफ इडस्ट्रियल स्टेटिस्टिकल प्रति मास एक बुलेटिन निकालता है, जिसमे उन्नीस वर्गों मे विभक्त 92 चुने हुए धन्धो के उत्पादन सम्बन्धी आकडे दिये जाते है। डायरेक्टरेट का शोध डिवीजन औद्योगिक आकडो पर अध्ययन परिचालित करता है।

कुटीर शिल्प

इस मे सन्देह नही कि हमारे देश मे औद्योगिक धन्धो की बहुत काफी उन्नति हो चुकी है, फिर भी अभी हमारे देश मे उत्पादन मुख्यतः छोटे पैमाने पर ही होता है

तालिका 103

औद्योगिक विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की प्रगति

अनुक्रम	उद्योग	इकाई	1951–56 अतिरिक्त क्षमता	1951–56 अतिरिक्त उत्पादन	1951–52 में हुई प्रगति अतिरिक्त क्षमता	1951–52 में हुई प्रगति अतिरिक्त उत्पादन	अप्रैल से दिसम्बर तक का वास्तविक उत्पादन 1951	अप्रैल से दिसम्बर तक का वास्तविक उत्पादन 1952	1952 की पूर्ण क्षमता	लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	धातु सम्बन्धी—									
1	लोहा व इस्पात									
	(1) कच्चा लोहा	000टन	1,757	1,261	—	166	1,350(क)	1,377(क)	1,950	1,685 (1957–58 तक होनी चाहिये)
	(2) तैयार इस्पात (केवल प्रमुख उत्पादक)	000टन	635	394	—	55	807	835(क)	1,050	500 (1957–58 तक होनी चाहिए)
2	अल्युमिनियम	टन	16,000	8,323	—	228	2,886	2,523	4,000	16,000
	यांत्रिक- इंजीनियरिंग									
3	कृषि यंत्र :									
	(1) शक्ति चालित सेन्ट्रीफ्युगल पम्प	हजार	36	46 से 51	9	14	29	18	43	27
	(2) डीज़ल इंजन	हज़ार	33	44	4	2	5	2	10	29
4	मोटर गाड़ियां (केवल तैयार करना)	अंक	—	25,923	—	2,561	—	1,396	3,000	—
5	रेलवे रोलिंग स्टाक									
	(1) रेल इंजन	अंक	150	438(ख)	—	14(क)	—	42 (क)	150	—
	(2) सवारी के डिब्बे	अंक	430	4,380(ख)	—	194(क)	—	550 (क)	850	430
	(3) माल के डिब्बे	अंक	—	30,000(ख)	—	1,001(क)	—	4 120	6,000	—
6	मशीनी औज़ार (ग्रेडेड)	अंक	1,600	3,499	—	2,164	3,600(क)	3,447	3,000	1,600
7	कपड़ा मिल मशीनें									
	(1) धुनाई करने वाले इंजन	अंक	—	600	—	158	—	57	600	—
	(2) कताई करने वाले यंत्र	अंक	404	440	—	31	207	206	396	404
	(3) करघे, सादे और अर्द्ध व पूर्ण स्वचालित	अंक	4,400	4,106	3,000	683	1,710	1,220	6,500	1,400
8	बाल व रोलर बेयरिंग	हज़ार	600	1,113	—	163	176	356	600	600
9	साइकिल	हज़ार	410	429	50	19	98	167	417	113
10	सिलाई मशीनें	हज़ार	54	59	—	15	33	37	41	50
11	हरीकेन लालटेन	हज़ार	250	2,800	—	768	2,982	2,595	4,410	90
12	चक्की	टन	480	519 से 569	40	121	236	286	500	340
	विद्युत इंजीनियरिंग									
13	सूखी बैट्रियां	दस लाख	25	183	—	9	108	93	297	13
14	स्टोरेज बैट्रियां	हज़ार	93	200	93	13	157	105	538	—
15	बिजली के तार और केबल ए सी एस आर केबल	टन	2,500	3,326	—	40	1,290 (क)	2,009	2,500	2,500
16	बिजली के पंखे	हज़ार	72	126 से 156	—	20	160	145	294	66

(क) अनुमानित ।
(ख) ये आंकड़े 1951 से 1956 तक के पांच सालों के सम्पूर्ण अनुमानित उत्पादन के हैं ।

	1	2	3	+	5	6	7	8	9	10
17	बिजली के लैम्प—जी एस एल	दस लाख	9	15	—	1	12	15	26	6
18	बिजली की मोटर	हजार एच पी.	150	221	3	54	107	120	200	100
19	बिजली के ट्रांसफार्मर	हजार के वी ए	115	271	15	26	146	165	304	181
20	रेडियो सेट	हजार	303	301	10	44	51	58	153	227
	रासायनिक और उनसे सम्बद्ध									
21	उर्वरक—									
	(1) अमोनियम सल्फेट	हजार टन	403	404	350	28	40	185	432	49
	(2) सुपर फोस्फेट .	हजार टन	86	125	50	4	46	31	198	11
22	भारी रासायनिक									
	(1) गधक का तेजाब	हजार टन	70	101	3	3	80	74	192	29
	(2) सोडा ऐश .	हजार टन	32	33	—	2	36	33	54	32
	(3) कास्टिक सोडा	हजार टन	18	22	4	4	11	13	35	2
23	औषध व फार्मेसी जात द्रव्य									
	(1) बैनजीन हैक्सा-क्लोराइड	टन	500	500	500	70	—	70	500	—
	(2) सलफा ड्रगस	हजार पौंड	400	400	—	—	—	80	350	50
	(3) पैरा–एमीनो सेलीसिलिक एसिड .	टन	48	48	—	7	7	—	—	—
24	पेंट और वार्निश									
	(1) रेडीमेड पेंट, वार्निश आदि,	हजार टन	5	31	—	4	25	24	65	5
	(2) रंग (टिटेनियम डाई ओक्साईड)	हजार टन	1,800	1,800	1,800	198(क)	153(क)	178(क)	1,800	
	(3) नाइट्रो-सेल्यूलोज प्रलाक्ष	हजार गैलन	500(ख)	450(ख)	194	—	69	82	403(ग)	—
	(4) अल्युमिनियम पेस्ट व चर्ण	टन	750	750	500	87(क)	13	228(क)	500(क)	250
25.	साबुन . .	हजार टन	15	94	7	11	63	63	272	—
26.	जूते .	10 लाख जोडे	—	6 0	—	0 56	4 3	3 7	—	8
27	कागज व गत्ता									
	(1) कागज व कागज का गत्ता .	हजार टन	74	86	6	21	101	104	148	63
	(2) स्ट्रा व अन्य चीजो के गत्ते	हजार टन	10	31	—	3	—	—	—	-
28	सीमेंट	हजार टन	2,026	2,108	442	596	2,386	2,714	3,845	1,461
29.	काच और उसकी चीजें									
	(1) काच की चादर	टन	40,500	20,150	-1,500	380	4,158	2,450	10,200	15,800
	(2) फुलाया और दबाया हुआ काच	टन	36,250	51,400 से 56,400	9,500	23,600	—	—	—	—
	तरल ईंधन पदार्थ									
30.	पावर एलकोहल	10 लाख गैलन	8	13	—	2	4	5	13	8
	वस्त्र									
31	सूती									
	(1) सूत . .	दस लाख पौंड	53	461	17	154	978	1,111	1,697	25

(क) अनुमानित
(ख) हाल में जो कुछ प्रगति हुई उसके प्रकाश में लक्ष्यो पर पुनर्विचार कर लिया गया है।
(ग) दो नई इकाइयो की अतिरिक्त क्षमता लगभग 97,000 गैलन प्रतिवर्ष है।

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(2) मिल का कपड़ा	10 लाख गज	35	982	19	416	3,057	3,576	4,778	1
	(3) हाथकरघे का कपड़ा	10 लाख गज	—	890	—	32	600 (क)	750 (क)	—	—
32	जूट का सामान	हजार टन	—	308	—	88	681	733	1,200	—
33.	रेयन का तार	10 लाख पौंड	14	17	6	4	4	6	10	8
34	ऊनी माल .	हजार पौंड	—	7,000	—	—1,138	13,275	12,616	20	—
	ईमारती लकड़ी									
35	माचिस . .	हजार ग्रुस बक्से	3,000	6,200	—	—	—	—	—	—
36	प्लाईवुड के चाय के डब्बे	10 लाख वर्ग फुट	41 से 51	55	21	32	45	56	171	9 से 19
	खाद्य पदार्थ									
37.	नमक . .	हजार टन	—	426	—	150	2,066	2,327	—	—
38.	चीनी . .	हजार टन	10	384	—	602	836	531	1,540	10
39.	वनस्पति तेल .	हजार टन	—	181	—	—	—	—	—	—
40	वनस्पति .	हजार टन	56	147	6	23	129	142 (क)	339	50

(क) अनुमानित

हमारे किसानो के लिए यह समस्या है कि जिस समय खेती न की जा सकती हो, उस समय का वे क्या उपयोग करे । कुटीरशिल्प से इस समस्या का बहुत कुछ समाधान हो जाता है । हिसाब लगा कर देखा गया है कि भारत मे लगभग दो करोड़ व्यक्ति कुटीरशिल्प मे लगे हुए है । कुटीर शिल्पों मे सबसे प्रधान हाथ करघा उद्योग है। इसमे 50 लाख लोग लगे हुए है । यह एक बहुत ही मार्के की बात है और जिसे अक्सर कई लोग भुला कर हवाई बाते करते है कि अकेले हाथ करघा उद्योग मे ही उतने लोग काम करते है, जितने कि सारे सगठित धधो मे, जिनमे खानो तथा बागानो के बडे पैमाने के धधे आ जाते है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हाथ करघा उद्योग की रक्षा के लिये इतना प्रयत्न क्यो किया जाता है ।

कुटीर शिल्प तथा छोटे पैमाने के धधो को ढग से सगठित करने तथा उनकी अधिक से अधिक उन्नति करने के लिये 1952 के नवम्बर और 1953 की फरवरी मे क्रमश. अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड और अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई । इन बोर्डों का कार्य यह है कि वे अपने क्षेत्रो के विषय मे सरकार को परामर्श देते रहे । हाथ करघा उद्योग तथा खद्दर के धधे को आगे बढाने और कायम रखने के लिये मिल के प्रत्येक गज कपडे पर तीन पाई अतिरिक्त कर लगाया गया है । इस प्रकार जो धन आयेगा, उससे इस उद्योग के विकास के लिये वित्त जुटाया जायेगा । हाथ करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सूती कपडे की मिलो मे धोतियो का उत्पादन भी सीमित कर दिया गया है ।

विदेशो के बाजार मे पहले नारियल की जटा की खपत बहुत अधिक थी, पर अब नारियल की जटा की खपत बहुत घट गयी है। इसका नतीजा यह हुआ कि इस उद्योग मे बहुत अधिक बेकारी और परेशानी हो गयी है । इसको दूर करना जरूरी है । यह समझ कर नारियल की जटा के धधे के सम्बन्ध मे एक अनुविहित बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है । इस बोर्ड का काम यह होगा कि वह स्थानीय माग उत्पन्न करने के साथ-साथ विदेशो मे नारियल की जटा की खपत बढाये । विदेशो मे इस चीज की खपत कदाचित इसलिये घट गयी कि अब इस क्षेत्र मे उत्पादन आधुनिक ढग से नही होता । इसलिए बोर्ड का काम यह भी होगा कि लोगो मे आधुनिक शिल्प प्रणाली और प्रक्रिया का प्रचार करे और साथ ही साथ शोध कार्य भी करे ।

राज्य सरकारे भी इस बात की बराबर चेष्टा कर रही है कि उनके इलाको मे कुटीर शिल्प से उत्पन्न द्रव्यों का अधिक प्रचार हो । उत्तर प्रदेश मे फलो को सुरक्षित रखने के उपायो के सम्बन्ध मे जानकारी न होने के कारण बहुत से फल नष्ट हो जाते थे । अब सहकारी आधार पर फल सुरक्षित रखने के लिये लखनऊ तथा रामगढ मे कारखाने खोल दिये गये है ।

गार्बो और टोकूबो श्रेणी की छोटे पैमाने की कताई इकाइयो और श्री काले द्वारा विकसित छोटे पैमाने की कताई इकाइया बम्बई तथा सौराष्ट्र के उन इलाको मे स्थापित हुई है जहा कपास उत्पन्न होती है । राज्य सरकार को इस सम्बन्ध मे सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की योजनाओ के लिये अनुदान दे रही है, जैसे लकडी का कारखाना, ऊन धुनने और तैयार करने का कारखाना, साइकिल के हिस्सो के परीक्षण तथा सही करने के कारखाने । केन्द्रीय सरकार ने केवल राज्य सरकारो को ही अनुदान नही दिये बल्कि मशीन खरीदने के लिये गैर सरकारी सस्थाओ को भी राज्य सरकारो के जरिये या सीधे सहायता देती रही। अखिल भारतीय चरखा सघ को 1951–53 मे ग्यारह लाख रुपये दिये गये ।

हमारे गाव वाले भाइयों की बेकारी अथवा अर्धबेकारी दूर करने के लिए पचवर्षीय योजना में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। कुटीर शिल्प तथा छोटे पैमाने के धधो के लिये योजना में 27 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है। नीचे देहाती धधों के विकास का लेखा दिया जा रहा है :—

तालिका 104

चुनी हुई ग्रामोद्योग योजनाओं के उत्पादन, व्यय और नियोजन के विवरण

अनुक्रम	उद्योग	कुल उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन	व्यय (लाख रुपयों मे)	मोटे तौर से अनुमानित नियोजन
1.	ग्रामीण तेल उद्योग	—	3 16 लाख टन तेल (2.6 लाख टन 5 टन प्रति सुधरी घानी और 0.56 लाख टन 0.85 टन प्रति घानी)	233.1	1,00,000 सगठनकर्ता, मिस्त्री तेल पेरने वाले।
2	नीम के तेल से साबुन बनाना	3,448 टन साबुन	3,448 टन साबुन	18.1	300 व्यक्ति और इसके अतिरिक्त बीज जमा करने मे अन्य लोगो को अशकालीन धधा।
3.	धान साफ करना	2 लाख टन	—	10.0	40,000 धान कूटने वाले।
4.	ताड-गुड	2,53,252 टन ताड गुड	81,852 टन ताड गुड (4 साल के बाद आवर्तक अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन 40,943 टन हो जायेगा)।	100.0	60,000 कृषक रस जमा करने वाले आदि।
5.	गुड और खाडसारी	(क) 450 लाख मन अच्छी किस्म का साधारण गुड (ख) 5 1 लाख मन	शुद्ध लाभ (रुपयो मे) (1) बढिया ढग से रस निकालने द्वारा 4 करोड (2) अच्छा माल तैयार करने से	100.4	1,200 पूर्णकालीन मजदूर 3,800 अशकालीन मजदूर 4,600 स्थानीय अवैतनिक मज़दूर,

अनुक्रम	उद्योग	कुल उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन	व्यय (लाख रुपयों म	नियोजना मोटे तौर से अनु-मानित
		शुद्ध साफ गुड़ (ग) 1 लाख मन मलाई के रंग का सीरा (घ) 13.6 लाख मन खांडसारी	2.60 करोड़ (3) विक्रय के सुधरे ढंग द्वारा 1.60 करोड़। योग 8.20 करोड़		6,00,000 गन्ना उत्पादक, जो 30,000 गांवों में हैं और जिन्हें वर्ष के एक अंश में धंधा मिलता है।
6.	चमड़ा उद्योग	खालें, हड्डियां चर्बी, तथा देशी जूते	मृत पशुओं से अधिक माल प्राप्त करने के कारण खाल, हड्डी व चर्बी का उत्पादन बढ़ा। अच्छी किस्म के जूते बनाये गये।	160.4	1,200 व्यक्ति जिनमे लगभग 900 खाल उधेड़ने वाले आदि भी हैं, इसके अतिरिक्त लगभग 8 लाख चमार जो 72,000 गांवों में फैले हैं।
7.	ऊन उद्योग	10 लाख कम्बल	10 लाख कम्बल	47.5	200 व्यक्ति, 4,000 कातने वाले 200, बुनकर।
8.	हाथ कागज़ उद्योग	1,400 टन बढ़िया किस्म का हाथ-कागज़ जिसका मूल्य 54 लाख रुपया कूता गया है	1,400 टन बढ़िया किस्म का हाथ-कागज़।	18.9	1,000 कागज़ बनाने वाले
9.	मधु मक्खी पालन	—	—	16.3	150 बड़े पैमाने पर मधु मक्खी पालने वाले; मधु मक्खी पालों ने सह-कारी संस्थाएं बनायी हैं।
10.	दियासलाई बनाने का कुटीर उद्योग	—	18 लाख ग्रुस	20.6	3,000 छात्र-कार्यकर्त्ता, 6,000 मज़दूर
			योग .	725.3	

पन्द्रहवां अध्याय
वाणिज्य

जब से कोरिया का युद्ध समाप्त हुआ और महायुद्ध छिडने की परिस्थितिया दूर हुई, तब से भारत की व्यापार सम्बन्धी नीति मे निर्यात पर अधिक जोर दिया जा रहा है। गैर-डालर के क्षेत्रो से आयात बहुत उदारता के साथ करने दिया जा रहा है, पर डालर क्षेत्रो से केवल अत्यावश्यक चीजो का ही आयात करने दिया जा रहा है।

निर्यात

यह तो स्पष्ट ही है कि निर्यात के बिना हमारा देश आगे नही बढ सकता। इसीलिये इस सम्बन्ध मे तीन तरह के उपाय किये गये। इसमे सबसे मुख्य उपाय तो यह था कि पटसन के माल, कपास तथा सूती कपडे पर निर्यात-कर कम कर दिया गया। दूसरे निर्यात का कोटा या निर्धारित भाग बढा दिया गया। सूती कपडे और पटसन के माल को मुक्त लाइसेस की सूची मे रखा गया है। हमारे यहा जो चीजे तैयार होती है, जैसे छत मे लगने वाले बिजली के पखे आदि बिल्कुल मुक्त रूप से बाहर भेजे जा सकते है। कपास, रेडी, मूगफली के तेलो के निर्यात सम्बन्धी निर्धारित भाग बढा दिये गये। चीनी तथा अन्य कई चीजो के निर्यात के सम्बन्ध मे भी निर्धारित भाग निर्दिष्ट कर दिये गये। इस सम्बन्ध मे यह बता देना उचित है कि अब तक इन चीजो का बाहर भेजा जाना निषिद्ध था। तीसरी बात यह है कि अब तक बहुत से कारखाने निर्यात की कमी के कारण काम नही कर पा रहे थे। इस सम्बन्ध मे सरकार ने यह नीति अपनाई कि जो लोग चीजो को समुद्र पार भेजने का प्रबन्ध कर सकते है, उन्हे इस्पात का अतिरिक्त निर्धारित भाग दिया जाये। सरकार ने भारतीय जूट मिल एसोसियेशन को भी इसीलिये सहायता दी कि वह अमेरिका मे पटसन के माल की खपत के लिये प्रचार कार्य करे। सबसे बडी बात इस सम्बन्ध मे यह हुई कि लाइसेस देने का तरीका सरल कर दिया गया।

आयात

1952 की जुलाई–दिसम्बर वाली छमाही मे आयात कुछ हद तक रुका रहा। इसका कारण यह था कि माल इकट्ठा हो गया था, और देश मे ही उन चीजो के उत्पादन के कारण बाहर से माल मगाने की आवश्यकता नही रह गयी थी। आयात के सम्बन्ध मे एक नयी बात यह भी की गयी कि पहले जहा कुछ चीजो के लिये लाइसेस एक साल के लिये होता था, अब छः माह के लिये लाइसेस दिये जाने लगे।

1953 की जनवरी–जून वाली छमाही मे आयात सम्बन्धी नीति यह रही कि पहली छमाही मे जिस आधार पर आयात हुआ, उसी आधार पर वह कायम रहा। हा, एक परिवर्तन यह करना पडा कि मशीन के आयात के सम्बन्ध मे उदारता की नीति रक्खी गयी, और उपभोग वाले ऐसे द्रव्यो के सम्बन्ध मे भी उदारता बरती गयी जिन्हे 1952 की जुलाई-दिसम्बर वाली छमाही मे या तो कतई रोक दिया गया था या आशिक रूप से रोक दिया गया था। उपभोगवाले द्रव्यो का आयात एक दम निषिद्ध करना उचित नही समझा गया क्योकि इससे यहा के कारखानो मे भारी गफलत पैदा हो सकती थी। स्वस्थ प्रतियोगिता जीवित रखना आवश्यक था। तालिका 105, 106 और 107 मे 1948 से 1953 तक के भारत के विदेशी व्यापार की परिस्थिति दिखलाई गई है।

तालिका 105

कुल व्यापार–सतुलन

(स्थल, जल व वायु मार्गों द्वारा)

(लाख रुपयो मे)

पण्य द्रव्य का व्यापार	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53
क. भारतीय पण्य-द्रव्य का निर्यात					
जल और वायु मार्गो द्वारा	42,104	47,207	57,898	70,175 (ख)	55,383 (ख)
स्थल मार्गों द्वारा .	3,039 (क)	2,788	1,781	2,714 (ख)	1,884 (ख)
योग .	45,143	49,995	59,679	72,889 (ख)	57,267 (ख)
ख. भारतीय पण्य-द्रव्य का निर्यात : (केवल जल और वायु मार्गों द्वारा)					
भोजन, पेय और तम्बाकू	9,230	11,588	13,581	15,816	14,216
कच्चा माल और उत्पादित वस्तुए और मुख्यत तैयार नही ऐसी वस्तुए	9,787	10,426	12,577	13,968	14,503
पूर्ण या मुख्य रूप से बनी हुई वस्तुए	22,906	24,974	31,478	40,031	25,977
योग (जीवित पशुओ और डाक की वस्तुओ को मिला कर) . .	42,104	47,207	57,898	70,180	55,104
ग. पुनः निर्यात (मार्गस्थ व्यापार को छोड कर) . .	729	607	456	392	504
घ. कुल निर्यात .	45,872	50,602	60,135	73,281	57,771

द्रष्टव्य : "अनाज, दाल और आटा के अन्य आयातों" का मूल्य सम्मिलित नहीं ।

(क) केवल पाकिस्तान के लिए ।

(ख) आधुनिकतम संशोधित आंकड़े ।

(लाख रुपयों में)

पण्य द्रव्य का व्यापार	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53
ङ. आयात :					
जल और वायु मार्गों द्वारा . .	55,717	59,434	58,117	87,308 (ख)	63,528 (ख)
स्थल मार्ग द्वारा .	8,500 (क)	3,371	4,279	8,045	2,516 (ख)
योग .	64,217	62,805	62,396	95,353 (ख)	66,044 (ख)
वहन व्यापार को घटा कर .	—	314	60	80	19
च. विशुद्ध आयात .	64,217	62,491	62,336	95,273	66,025
छ. आयात (केवल जल और वायु मार्गों द्वारा) भोजन, पेय पदार्थ और तम्बाकू .	12,712	15,664	11,061	26,205	17,564
कच्चा माल और उससे उत्पादित वस्तुएं और मुख्यत: तैयार नहीं ऐसी वस्तुए.	12,757	14,427	19,881	25,406	17,901
पूर्ण अथवा मुख्य रूप से तैयार वस्तुएं . .	29,790	28,863	26,954	34,138	27,400
योग (जीवित जन्तुओं और डाक की वस्तुओं को मिला कर) . .	55,717	59,434	58,117	86,284	63,295
ज. पण्य द्रव्य के व्यापार का संतुलन .	-18,345	-11,889	-2,201	-21,992	-8,254

अनाज, दाल और आटा के अन्य आयातों के मूल्य के सिवा :—

(क) केवल पाकिस्तान के लिये ।

(ख) सबसे ताजे सुधारे हुए अंक ।

तालिका 106

निर्यात की मुख्य वस्तुएं

(जल, वायु और स्थल मार्गों द्वारा)

(प—परिमाण और मू—लाख रुपयों में मूल्य के लिये प्रयुक्त हुए हैं)

भोजन, पेय पदार्थ और तम्बाकू

वर्ष		मछली (हजार हंड्रवेटों में)	प्याज (क) (हजार हंड्रवेटों में)	काजू की गिरी (हजार टनों में)	इलायची (हजार हंड्रवेटों में)	कालीमिर्च (हजार हंड्रवेटों में)	चाय (दस लाख पौंडों में)	बिना तैयार तम्बाकू (दस लाख पौंडों में)	तैयार तम्बाकू (हजार पौंडों में)
1948-49	प	235	309	18	18	141	443 (ग)	69	4 976 (क)
	मू	147	50	493	73	267	6 924 (ग)	649	567
1949-50	प	321	735	19	16	313	445	92	4 267 (क)
	मू	191	126	561	125	1 450	7,291	1,164	410
1950-51	प	387	1 156	25	12	308	442	103	11.828
	मू	246	115	855	148	2.040	8,042	1 411	435
1951-52	प	435	925	21	14	298	429	112	12.359
	मू	328	107	903	164	2 322	9,386	1,614	639
1952-53	प	475	659	27	19	246	428	79	15.084 (ख)
	मू	378	112	1 276	164	1.596	8,098	1 266	252

(क) केवल जल और वायुमार्गों द्वारा (ख) अपूर्ण (ग) स्थल मार्गों द्वारा अफगानिस्तान और ईरान के लिये निर्यात के आंकड़ों को छोड़ कर,

निर्यात की मुख्य वस्तुए (क्रमशः)

कच्चा माल और उत्पादित वस्तुएं तथा मुख्यतः तैयार नही ऐसी वस्तुएं

वर्ष	मूंगफली का तेल (हजार गैलन मे)	रेंडी का तेल (हजार गैलन मे)	अलसी का तेल (हजार गैलन मे)	मूंगफली (हजार टनो मे)	रेंडी (हजार टनो मे)	अलसी (हजार टनो मे)	कच्ची रूई (हजार टनों मे)	रद्दी रूई (हजार हण्डरवेटो मे)	कच्चा पटुआ (हजार हण्डरवेटों मे)	कच्चा ऊन (हजार पौंडो मे)
1948-49 प	8,951 (क)	3 009	2 281	38	--	25	76	1,017	665	8,658
मू	670	218	148	313	--	139	1,401	515	339	109
1949-50 प	7,049 (क)	1,138	1 773	126	5	72	58	1,513	342	27,363
मू	544	69	128	904	28	456	1,061	822	175	371
1950-51 प	19,991	5,898	1 359	38	79	68	15	1,307	271	25,371
मू	1,674	435	110	357	592	567	494	1 241	128	787
1951-52 प	5,119	5,522	6,077	20	1	7	23	623	417	18 295
मू	432	657	566	235	16	70	1,368	735	248	490
1952-53 प	16,181	8,925 (ख)	6,800 (क)	13	4	—	71	1,257	336	37,979
मू	1 046	772	481	140	38	52	1 932	962	144	842

(क) केवल जल मार्गों द्वारा। (ख) अपूर्ण।

निर्यात की मुख्य वस्तुएं (क्रमशः)

कच्चा माल और उत्पादित वस्तुएं तथा मुख्य रूप से तैयार नही ऐसी वस्तुएं

वर्ष		कोयला (हजार टनों मे)	अबरक (हजार हडरवेटो में)	लाख (हजार हडरवेटो मे)	कच्चा चमडा (हजार हडरवेटो मे)	कच्ची खाल (हजार हडरवेटो मे)	पुराना लोहा और इस्पात फिर तैयार होने के लिए (हजार टनो मे)	खनिज लोहा (हजार टनो मे)	मेंगनीज (हजार टनो मे)	हरें (हजार हडरवेटो मे)	वस्तुए तैयार करने की हड्डियां (हजार टनों में)
1948 49	प	1 332	340	491	42	204	—	—	309	612	31
	मू	458	594	869	49	498	—	—	181	55	57
1949-50	प	2,323	298	456	16	258	0 2	4	739	845	37
	मू	763	685	809	21	659	0 31	1	585	90	66
1950-51	प	994	407	662	38	248	2	85	821	821	45
	मू	344	1,000	1,189	69	874	4	22	801	103	116
1951-52	प	2,801	408	714	24	220	43	280	1,125	897	46
	मू	955	1,321	1 487	62	762	70	100	1 569	113	228
1952-53	प	2,187	284	688	1	228	481	812	1,365	515	71
	मू	1,011	899	761	2	554	1,026	371	2,077	41	221

निर्यात की मुख्य वस्तुएं (क्रमशः)

पूर्ण रूप से अथवा मुख्यतः तैयार वस्तुएं

वर्ष		तैयार चमड़ा (हजार हंडरवेटों में)	तैयार खाल (हजार हंडरवेटों में)	सूती ट्विस्ट व सूत (हजार पौंडों में)	सूती मोजे व बनियान आदि	हाथ से बने सूती पीस गुड्स (१० लाख गजों में)	मिल में बने सूती पीस गुड्स (१० लाख गजों में)	बिसातखाने का सामान (मुख्यतः तैयार सूती सामान)	टाट के बोरे (हजार टनों में)	टाट (हजार टनों में)	नकली सिल्क के पीस गुड्स (हजार गजों में)	ऊनी कालीन और कम्बल (हजार पौंडों में)	नारियल की जटा से बनी चीजें (हजार हंडरवेटों में)
1948-49	प	186	104	7,408	--	--	361(ग)	--	457	435	24 480	8,334	869
	मू	496	720	129	95	--	39,540(ग)	51	6 147	8,072	519	261	447
1949-50	प	315	162 (ख)	67,835(क)	--	--	709	--	434	309	12 230	10 465	1,424
	मू	853	1,183	1 240	79	--	5 965	81	6,382	5,725	149	331	721
1950-51	प	351	148 (ख)	75 091	--	60	1 224	--	345	266	6,990	14 091	1,560
	मू	1 202	1 333	1 728	86	1 088	11 217	171	5,539	5 291	97	556	1,081
1951-52	प	335	124 (क)	6 182(क)	--	40(क)	388	--	473	287	8,414	11,591	1,219
	मू	1 361	1 141	1,97 180	--	920	4 295	246	13 529	12,458	117	588	1,019
1952-53	प	313	162	17,453	--	54(क)	565	--	371(क)	1 304	3 621(क)	7,121	1,279
	मू	922	1 089 (क)	428	100	874	5 319	253	6 139	6,321	51	279	715

(क) अपूर्ण (ख) केवल जल और वायु मार्गों द्वारा। (ग) स्थल मार्गों द्वारा अफगानिस्तान और ईरान के निर्यात के आंकड़ों को छोड़ कर

निर्यात की मुख्य वस्तुएं (क्रमशः)

पूर्णतः अथवा मुख्यतः तैयार वस्तुएं :

वर्ष		पैराफिन मोम (हजार टनों में)	वस्त्र, कपड़े आदि (मोजे व बनियान व जूतों को छोड़ कर)	प्लीत-रीन (हजार हंडरवेटों में)	सन ईसबगोल (ख) (हजार हंडरवेटों में) (क)	लोहे का माल (हजार टनों में)	धातु का सामान	यंत्र (पूर्ण या उनके भाग)	कांच और मिट्टी के सामान	मशीनें (जिनमें सिलाई की मशीनें भी शामिल हैं)	कागज, लुगदी, गत्ता और स्टेशनरी	रबर का सामान	लोहे और इस्पात को छोड़ कर अन्य धातुएं तथा उनसे बना सामान
1948-49	प	10	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—
	मू	113	74	—	—	63	54	94	232	29	49	167	98
1949-50	प	16	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	—
	मू	158	51	—	—	99	61	74	32	69	31	99	59
1950-51	प	20	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—
	मू	226	115	—	—	86	78	96	29	47	33	165	124
1951-52	प	32	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
	मू	282	82	—	—	41	121	147	43	95	119	108	141
1952-53	प	19	—	61	—	11	—	—	—	—	—	—	—
	मू	133	165	90	—	41	110	151	34	127	87	143	268

(क) अप्रैल १९५२ से व्यापार के खाते में अलग से दिया गया।

(ख) अप्रैल १९५३ से व्यापार के खाते में अलग से दिया हुआ।

तालिका 107

आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं

(जल, वायु और स्थल मार्गों द्वारा)

(मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	मशीनों के लिए पट्ट	रासायनिक	कोलतार से तैयार होने वाले रंग	फल और सब्जियां	अनाज, दाल व आटा	लोहे का माल	यंत्र आदि	हर प्रकार का मशीनी सामान जिसमें मशीनों के पट्ट भी शामिल है	लोहा और इस्पात तथा उनसे बनने वाला सामान	लोहे और इस्पात के अतिरिक्त अन्य धातुए तथा उनसे बना सामान
1948–49.	212	2,057	1,234	825(क)	10,170	596	1,881	8,156	1,231	2,233
1949–50.	101	776	796	1,058	13,388	614	2,075	10,551	1,370	1,818
1950–51.	119	922	1,198	1,366	8,075	457	1,779	9,300	1,900	2,784
1951–52.	207	1,920	1,427	1,390	23,030	614	2,043	10,431	2,197	2,066
1952–53.	161	1,268	751	1,374	15,673	404	2,221	8,787	2,371	1,930

(क) अफगानिस्तान व ईरान से स्थल मार्गों द्वारा हुए आयात के आंकड़ों को छोड़ कर।

आयात को जाने वाली मुख्य वस्तुएं (क्रमशः)

(जल, वायु और स्थल मार्गों द्वारा)

(मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	कागज	रूई	कच्चा ऊन	नकली रेशम का धागा	मोटरों का ढांचा	मोटर कार	औषधियां	सूती पीस गुड	बटा हुआ और साधारण सूत	ऊनी और वरस्टेड पीस गुड	परचून का सामान और तेल आदि	पटसन
1948–49 .	1,337	6,448	318	1,283	892	764	812(क)	930	450	310	708	7,124
1949–50 .	774	6,379	303	1,046	538	318	804	1,070	577	164	730	2,117
1950–51 .	950	10,077	562	1,471	266	324	1,052	131	30	13	602	2,757
1951–52 .	1,316	13,718	260	1,729	287	479	1,560	237	182	45	1,084	6,707
1952–53 .	1,121	7,667	71	785	288	296	1,145	125	209	92	571	1,648

(क) ईरान व अफगानिस्तान से स्थल मार्गों द्वारा किये गये आयात के आंकड़ों को छोड कर ।

सोलहवां अध्याय

परिवहन

रेल मार्ग

भारत मे रेल मार्ग ही परिवहन का मुख्य साधन है। माल का 80 प्रतिशत तथा सवारियो का 70 प्रतिशत रेल पर ही आता जाता है। हमारे यहा रेल पद्धति का प्रारम्भ सन 1853 मे हुआ था और अभी हाल ही मे रेल मार्ग की शताब्दी जयन्ती मनाई गई। रेल मार्ग की हमारे यहां किस प्रकार उन्नति हुई यह नीचे दिया जा रहा है :

तालिका 108

रेल मार्ग की प्रगति 1853-1952

(लाख रुपयो मे)

व	पटरियोकी कुल लम्बाई (मीलो मे)	लगी हुई पूजी	कुल आय	व्यय	विशुद्ध आय
1853	20	38	0.90	0.41	0.49
1863	2,507	5,300	220	133	87
1873	5,697	9,173	723	378	345
1883	10,447	14,831	1,639	797	842
1893	18,459	23,318	2,408	1,135	1,273
1903	26,956	34,111	3,601	1,711	1,890
1913-14	34,656	49,509	6,359	3,293	3,066
1923-24	38,039	71,793	10,780	6,845	3,935
1933-34	42,953	88,441	9,958	6,954	3,004
1943-44 (क)	40,512	85,854	19,932	11,411	8,521
1947-48 (ख)	33,985	74,220	18,369	16,394	1,975
1948-49	33,861	77,588	23,412	18,406	5,006
1949-50	34,022	81,307	25,832	20,723	5,109
1950-51	34,079	83,818	26,462	21,439	5,023
1951-52	34,119	86,155	29,414	22,759	6,655

(क) 1937 मे बर्मा रेल अलग हो गयी।

(ख) 15 अगस्त 1947 विभाजन के बाद।

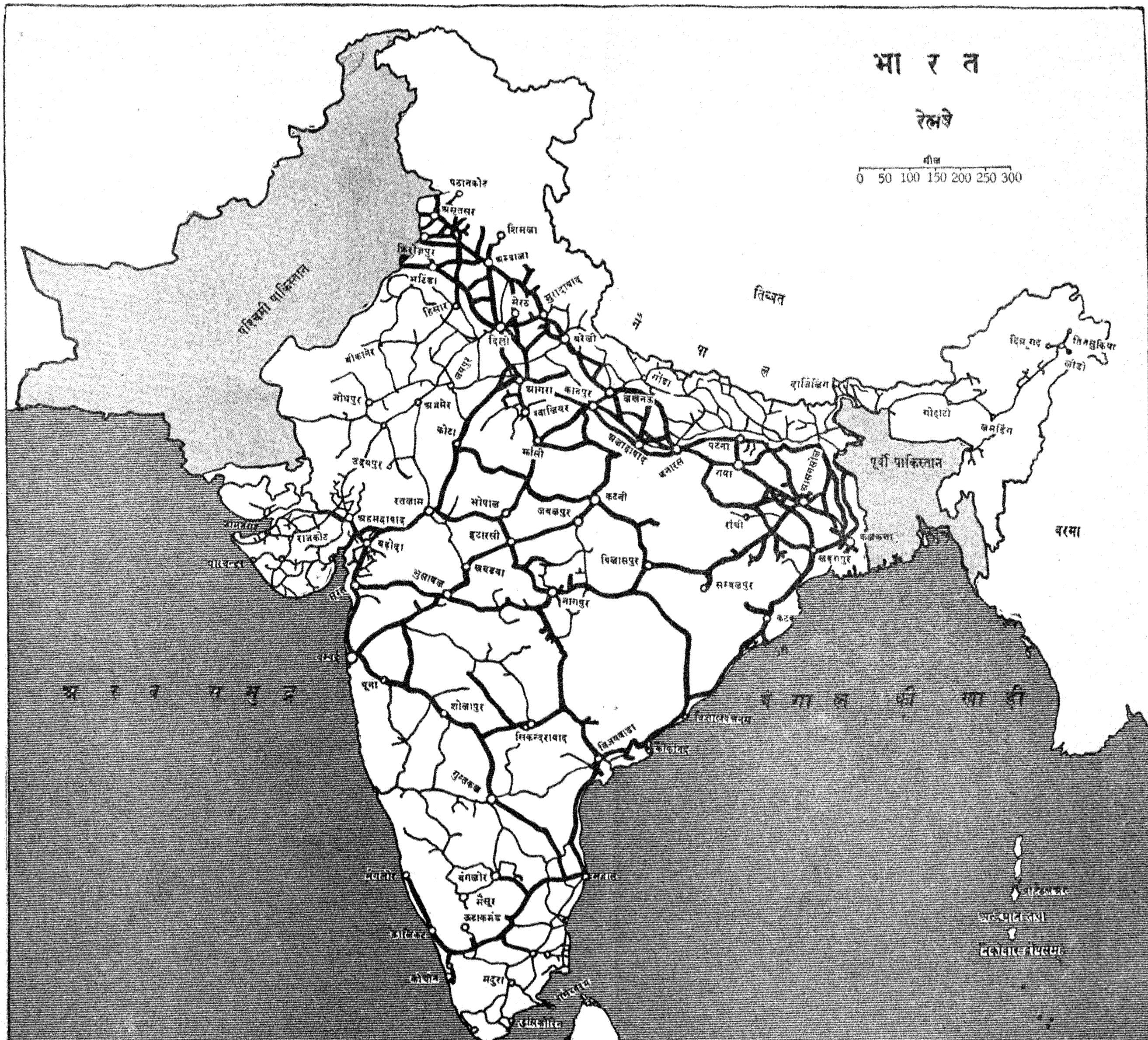
भारत
रेलवे
मील
0 50 100 150 200 250 300
पठानकोट
अमृतसर
शिमला
फिरोज़पुर
अम्बाला
भटिंडा
हिसार
मेरठ
मुरादाबाद
दिल्ली
बरेली
बीकानेर
जयपुर
जोधपुर
अजमेर
आगरा
कानपुर
लखनऊ
ग्वालियर
कोटा
झाँसी
इलाहाबाद
बनारस
पटना
गया
उदयपुर
रतलाम
भोपाल
जबलपुर
कटनी
अहमदाबाद
राजकोट
बड़ोदा
इटारसी
बिलासपुर
भुसावल
खंडवा
नागपुर
सम्बलपुर
कटक
राँची
कलकत्ता
खड़गपुर
पूना
शोलापुर
सिकन्दराबाद
विजयवाडा
विशाखापत्तनम
काकीनाड़ा
गुन्तकल
बंगलोर
मैसूर
उटाकमंड
मद्रास
मदुरा
तूतीकोरिन
तिब्बत
नेपाल
दार्जिलिंग
गोहाटी
पूर्वी पाकिस्तान
बरमा
पश्चिमी पाकिस्तान
अरब समुद्र
बंगाल की खाड़ी
पोरबन्दर
बम्बई
अण्डमान तथा
निकोबार द्वीपसमूह
गोंडा
लमडिंग
तिनसुकिया
डिब्रूगढ़

तालिका 109

यातायात (1871–1951)

वर्ष	यात्रियो की सख्या (हजार मे)	यात्रियो से प्राप्त भाडा (लाख रुपयो मे)	ढोया गया माल (हजार टनो मे)	माल की ढुलाई से प्राप्त भाडा (लाख रुपयो मे)
1871 . .	19,283	202	3,542	420
1881 . .	54,764	379	13,214	956
1891 . .	1,22,855	686	26,159	1,561
1901 . .	1,94,749	1,007	43,392	2,124
1911 . .	3,89,863	1,849	71,268	3,293
1921–22 . .	5,69,684	3,429	90,142	4,952
1931–32 . .	5,05,836	3,135	74,575	5,873
1941–42 (क) .	6,23,072	3,969	96,997	8,963
1951–52 (ख) .	12,32,073	11,142	98,025	15,395

विभाजन के अवसर पर अविभक्त भारत में 40,524 मील रेल थी, जिसमे से 6,958 मील पाकिस्तान मे चली गई, और भारतीय यूनियन के लिये 33,566 मील रेल बच रही। इस प्रकार जो कमी हुई सो तो हुई, सबमे बडी हानि यह हुई कि आसाम की रेल भारत की रेल से अलग हो गई। इसलिये सबसे पहले यह प्रश्न सामने आया कि किस प्रकार इसे दूर किया जाये। तदनुसार भारत और आसाम को जोडता हुआ जो पतला सा भूभाग था उसमे 142 मील लम्बी मीटरगेज लाईन बनाई गई। इस लाइन का उद्घाटन 1949 के दिसम्बर मे हुआ। इस प्रकार आसाम फिर एक बार भारत से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया :

काण्डला (गाधी धाम)—170 मील लम्बे दीसा रेल मार्ग का उद्घाटन दो अक्तूबर 1952 को हुआ। यह बता दिया जाये कि इस लाइन को इतना महत्व क्यों दिया गया। कराची के हम से पृथक् हो जाने से हमारे उस इलाके के लिये एक बन्दरगाह की आवश्यकता थी। काण्डला इसी के लिये विकसित किया गया, पर इसे रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सो के साथ जोडना था। इसलिये यह रेल मार्ग बना। इस कारण से एक नवम्बर 1949 से अप्रैल 1952 के बीच 3.77 करोड रु० की लागत पर सत्ताइस मील लम्बी मुकेरियां—पठानकोट रेल लाइन बनी। पहले पठानकोट को घूम कर जाना पडता था, अब इस रेल के बनने से दिल्ली से पठानकोट की दूरी 44 मील कम हो गई।

1944 मे ही भारत सरकार ने सब रेलो को अपने अधीन कर लिया था। इसमे पूर्व रेल की मिल्कियत और नियत्रण की पद्धति बडी जटिल थी। कई तरह की पद्धतिया एक साथ चालू थी।

(क) 1937 मे बर्मा रेल अलग हो गयी।
(ख) 15 अगस्त 1947 विभाजन के बाद।

कुछ रेलवे लाइनो की मालिक भी सरकार थी और सरकार ही व्यवस्थापक भी थी। कुछ रेलवे लाइनों की मालिक सरकार थी पर उनकी व्यवस्था कम्पनियों के हाथ में थी। ऐसी कई रेल लाइनें थी जो कम्पनियों की थी और कम्पनिया ही उनकी व्यवस्था करती थी। इसके अतिरिक्त रजवाडों की अपनी लाइने थी। कहना न होगा कि इस प्रकार की बातो से न तो कार्यकुशलता बढती थी और न काम ढग से हो पाता था। खर्च भी अधिक होता था। 1948 मे भारत मे 42 प्रकार की रेले थी। इनमे से तेरह अव्वल दर्जे की रेले थी जिनकी कुल सालाना आमदनी 50 लाख रुपये या उससे अधिक थी। दूसरे दर्जे की 10 रेले थी, जिनकी कल सालाना आमदनी 10 से 50 लाख रुपये के अन्दर थी। तीसरे दर्जे की 19 रेलें थी, जिनकी कुल सालाना आमदनी 10 लाख रु० या उससे कम थी। 42 रेलों मे से 32 (इसमे सांगली राज्य की पाच मील लम्बी रेल भी थी, ये लाइने कुल मिला कर 7,559 मील लम्बी थी) रजवाड़ों की थी। 1950 की पहली अप्रैल से रजवाडों की निजी रेले भारत सरकार की मिल्कियत और नियंत्रण मे आ गयी। बात यह है कि इस बीच मे रजवाडे भारतीय यूनियन में विलीन हो चुके थे। यह समझा गया कि खर्च घटाने तथा प्रशासन मे कार्य कुशलता बढाने के लिये, सिर्फ रेलो के नये वर्गीकरण की जरूरत है। तदनुसार रेल बोर्ड ने 1950 मे एक योजना बनाई, और 1951–52 मे इसे अलग कर दिया गया। कुछ निजी लाइट रेले इस कार्यक्रम से बरी रही। नये वर्गीकरण के पहले भारत मे 35 प्रकार की रेले थी, इनमे 22 पर सरकारी मिल्कियत थी। सरकारी रेलों के नाम ये थे : आसाम, बगाल—नागपुर, बम्बई—बडौदा और मध्य भारत (बी० बी० एण्ड सी० आई०), बेजवाडा—धौनकुरनूल, दार्जिलिंग—हिमालयन, ईस्ट इण्डियन, ईस्टर्न पजाब, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला (जी० आई० पी०), मद्रास और दक्षिणी मरहठा, अवध और तिरहुत, साऊथ इंडियन, बीकानेर राज्य, कच्छ राज्य, धौलपुर राज्य, जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य, मैसूर राज्य, निजाम शाही, राजस्थान, सौराष्ट्र और सिंधिया राज्य रेल। नये वर्गीकरण के फलस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्रीय विभाग हुए।

तालिका 110

क्षेत्र	किस तारीख को बनायी गयी	जिसके अन्तर्गत है	मुख्यकार्यालय	पटरियों की कुल लम्बाई (मीलों मे)
दक्षिण	14 अप्रैल 1951	मद्रास एवं दक्षिण-मरहठा, दक्षिण भारत और मैसूर रेल . .	मद्रास	6,016.97 बी० जी० 1,754.05 एम० जी० 4,160.12 एन० जी० 702.20

क्षेत्र	किस तारीख को बनायी गयी	जिस के अन्तर्गत है	मुख्य कार्यालय	पटरियो की कल लम्बाई (मीलो में)
मध्य	5 नव० 1951	ग्रेट इंडिया पनिनसुला, निजाम की स्टेट, सिंधिया और धौलपुर रेल .	बम्बई	5,427.70 बी० जी० 4,091.23 एम० जी० 772.49 एन० जी० 563.98
पश्चिम	5 नव० 1951	बम्बई बड़ौदा एव मध्य-भारत, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान और जयपुर रेलवे . .	बम्बई	5,461.03 बी० जी० 1,266.34 एम० जी० 3,402.18 एन० जी० 792.51
उत्तर	14 अप्रैल, 1952	पूर्वी पजाब, जोधपुर, और बीकानेर रेलवे और ईस्ट इण्डियन रेलवे के तीन अपर डिवीज़न .	दिल्ली	6,007.3 बी० जी० 3,881.68 एम० जी० 1,997.68 एन० जी० 127.97
उत्तर-पूर्व	14 अप्रैल 1952	अवध एवं तिरहुत और आसाम रेलवे .	गोरखपुर	4,766.87 बी० जी० 2.15 एम० जी० 4,712.75 एन० जी० 51.97
पूर्वी	14 अप्रैल 1952	ईस्ट इण्डियन रेलवे (तीन अपर डिवीज़नों को छोड़ कर) और बंगाल-नागपुर रेलवे .	कलकत्ता	5,667.24 बी० जी० 4,725.27 एम० जी० — एन० जी० 941.97

बी० जी० —ब्राड गेज

एम० जी० —मीटर गेज

एन० जी० —नैरो गेज

तालिका 111

रेल प्रशासन व्यवस्था जैसी कि वह 16 अप्रैल 1953 को थी

रेलवे	गेज	पटरियों की लम्बाई (मीलों में)	अधिकारी	प्रबन्धक
प्रथम श्रेणी की रेल				
(1) मध्य				
(क) मध्य . .	5′ 6″	4,091	भारत सरकार	भारत सरकार
	3′ 3⅜″	773	,,	,,
	2′ 6″	117	,,	,,
	2′ 0″	307	,,	,,
(ख) इलिचपुर यवतमाल	2′ 6″	118	ब्रांच लाइन क.	,,
(ग) पुलगाव-आर्वी	2′ 6″	22	,, 'क'	,,
(2) पूर्वी				
पूर्वी .	5′ 6″	7,733	भारत सरकार	,,
	2′ 6″	942		
(3) उत्तर-पूर्वी .			,,	,,
(क) उत्तर-पूर्वी .	5′ 6″	2'ख'	,,	,,
	3′ 3⅜″	4,655	,,	,,
	2′ 0″	72	,,	,,
(ख) चपरमुख सिलघाट	3′ 3⅜″	51	ब्राच लाइन क. 'ग'	,,
(ग) कटाखल-लाला बाजार	3′ 3⅜″	23	,,	,,
(4) उत्तर :				
(क) उत्तर	5′ 6″	3,870	भारत सरकार	,,
	3′ 3⅜″	1,997	,,	,,
	2′ 6″	128	,,	,,
(ख) पर नंगल बाघ 'घ' .	5′ 6″	34	,,	,,
(5) दक्षिण				
(क) दक्षिण .	5′ 6″	1,729	,,	,,
	2′ 3⅜″	4,006	,,	,,
	2′ 6″	102	,,	,,
(ख) तेनाली रेपल्ली .	5′ 6″	22	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गुंटूर	,,
(ग) कोचीन बन्दरगाह विस्तार .	5′ 6″	4	कोचीन बन्दरगाह प्रशासन	,,

'क' छूट की शर्तों पर ।

'ख' यह लाइन हलदीबारी और पाकिस्तान की सीमा के बीच में पाकिस्तान से सीधा सम्बन्ध जोड़ने के लिए है ।

'ग' इस लाइन को भारत सरकार द्वारा गारण्टी प्राप्त है, और इसे आसाम सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है ।

'घ' भारत सरकार और पंजाब सरकार का सम्मिलित स्वामित्व ।

रेल	गेज	पटरियों की लम्बाई (मीलों में)	अधिकारी	प्रबन्धक
(घ) अलनावार दादेली (प्रान्तीय)	3′ 3⅜″	19	बम्बई राज्य सरकार	भारत सरकार
(ङ) पश्चिमी भारत पुर्तगाली	3′ 3⅜″	51	पश्चिमी भारत पुर्तगीज़ रेल कम्पनी	,,
(च) पेरालाम–कराईकल	3′ 3⅜″	15	फ्रांसीसी सरकार	,,
(छ) पाडिचेरी	3′ 3⅜″	8	पाडिचेरी रेल कम्पनी	,,
(ज) तिन्नेवेल्ली तिरुचेन्दूर	3′ 3⅜″	38	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तिन्नेवेल्ली	,,
(झ) नन्जनगुड टाउन चमराजनगर	3′ 3⅜″	22	मैसूर व माण्ड्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड	,,
(6) पश्चिम पश्चिम	5′ 6″	1 266	भारत सरकार	,,
	3′ 3⅜″	3 573	,,	,,
	2′ 6″	792	,,	,,
प्रथम श्रेणी की कुल रेलें		33 582		
द्वितीय श्रेणी की रेल				
1 बार्सी लाइट	2′ 6″	203	अप्राप्त सहायता कम्पनी	बार्सी लाइट रेल कम्पनी
2 शाहदरा (दिल्ली) सहारनपुर लाइट	2′ 6″	93	प्राप्त सहायता कम्पनी 'क'	शाहदरा, दिल्ली सहारनपुर लाइट रेलवे कम्पनी
द्वितीय श्रेणी की कुल रेलें		296		
तृतीय श्रेणी की रेलवे				
1 अहमदपुर कटवा	2′ 6″	32	ब्रांच लाइन कम्पनी 'ख'	अहमदपुर कटवा रेलवे
2 आरा-ससाराम लाइट	2′ 6″	65	प्राप्त सहायता कम्पनी 'ग'	आरा-ससाराम लाइट रेलवे कम्पनी

'क' सरकार द्वारा केवल भूमि प्राप्त ।
'ख' भारत सरकार द्वारा गारण्टी प्राप्त ।
'ग' जिला बोर्ड द्वारा

रेलवे	गेज	पटरियों की लम्बाई (मीलों में)	अधिकारी	प्रबन्धक
3. बाकुरा-दामोदर .	2′ 6″	60	ब्रांच लाइन कम्पनी (ख)	बाकुरा-दामोद रिवर रेलवे कम्पनी
4. बरसेत-बसीरहाट लाइट	2′ 6″	52	प्राप्त सहायता कम्पनी (ग)	बरसेत-बसीरहाट लाइट रेल कम्पनी
5. बंगाल प्रोविंशियल—				
(I) बगाल प्रोविंशियल	2′ 6″	33	अप्राप्त सहायता कम्पनी	बगाल प्रोविंशियल रेल कम्पनी
(II) दसघरा जमालपुरगंज . .	2′ 6″	9	ब्राच लाइन कम्पनी (ख)	”
6. बख्तियारपुर-बिहार लाइट	2′ 6″	33	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पटना	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पटना
7. बर्दवान-कटवा .	2′ 6″	33	ब्राच लाइन कम्पनी (ख)	बर्दवान-कटवा रेल कम्पनी
8. देहरी-रोहतास लाइट .	2′ 6″	24	सहायता प्राप्त कम्पनी (क)	देहरी-रोहतास लाइट रेल कं०
9. फतवा इसलामपुर .	2′ 6″	27	ब्राच लाइन कम्पनी (ख)	फतवा इसलामपुर लाइट रेल कम्पनी
10. हावडा आम्टा लाइट .	2′ 0″	44	सहायता प्राप्त कम्पनी (क)	हावडा आम्टा रेल कम्पनी
11. हावडा शियाखाला लाइट	2′ 0″	20	सहायता प्राप्त कम्पनी (क)	हावडा शियाखाला लाइट रेल कम्पनी
12. जगाधारी लाइट .	2′ 0″	3	अप्राप्त सहायता कम्पनी	जगाधारी लाइट रेलवे कम्पनी
13. कालीघाट फाल्टा .	2′ 6″	26	ब्राच रेलवे कम्पनी (ख)	कालीघाट-फाल्टा रेल कम्पनी
तृतीय श्रेणी की कुल रेलें		461		

(क) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा गारंटी।
(ख) भारत सरकार द्वारा गारंटी
(ग) सरकार से केवल भूमि प्राप्त

द्रष्टव्य : प्रथम श्रेणी में वे रेल आती है जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपया या उससे अधिक हो। द्वितीय श्रेणी में वे रेल आती है जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये से कम हो पर 10 लाख रुपये से अधिक हो। तृतीय श्रेणी में वे रेल आती हैं जिनकी कुल वार्षिक आय 10 लाख रुपया या उससे कम हो।

1951-52 के रेल मार्ग के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यों है:—

कुल मार्ग की लम्बाई	34,119
ब्राड गेज (साढ़े 5 फुट)	15,702
मीटर गेज (3 फुट 3-3 18 इंच)	15,060
नैरोगेज (2 फुट 6 इंच और 2 फुट)	3,356
अव्वल दर्जे की रेलें	33,343
दूसरे और तीसरे दज की रेल	776
पूजी	861.55 करोड रुपये
कुल आमदनी	294.14 करोड रुपये
चालू खर्च	227.59 करोड रुपये
शुद्ध आमदनी	66 55 करोड रुपये
यात्रा कितनी मीले की गई . . .	18 करोड 80 लाख
ले जाई गई सवारियो की सख्या . . .	123.21 करोड़
ऐयर कडीशन्ड दर्जा	0 0017 करोड
प्रथम और दूसरी श्रेणी . . .	1 91 करोड़
ड्यौढ़ा दर्जा . .	2 14 करोड़
तीसरा दर्जा	119.16 करोड
सवारियो से आमदनी. . .	109.88 करोड रु०
ले जाया गया माल	980.3 लाख टन
माल से आमदनी	156.79 करोड रुपये

1951–52 मे रेल विभाग ने एक करोड आठ लाख टन कोयला इस्तेमाल किया, जिसका मूल्य 34 करोड 40 लाख रुपये है। बात यह है कि अभी हमारे देश मे बिजली वाली रेल बम्बई तथा मद्रास के पास की कुछ लाइनो तक ही सीमित है। बिजली की रेल पहले पहले 1925 मे शुरू की गयी थी, पर इस सम्बन्ध मे अधिक प्रगति नही हुई है। जिस प्रकार से बम्बई और मद्रास के आस पास की कुछ लाइनों मे बिजली वाली रेलें चालू है, उसी प्रकार कलकत्ते के इर्द गिर्द की कुछ लाइनो मे बिजली इस्तेमाल करने की योजना विचाराधीन है।

1925 में रेल विभाग का वित्त सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया। उस समय यह निश्चय किया गया कि रेल विभाग सामान्य राजस्व विभाग मे एक निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार राजस्व दिया करे। 1949 के दिसम्बर मे यह तय हुआ कि 1950-51 से जिस पंचवर्ष का प्रारम्भ हुआ है, उससे रेल विभाग प्रत्येक चतुर्थ वर्ष के अन्त में चार प्रतिशत का प्रत्याभावित लाभांश दे।

रेल विभाग के गत छः वर्षों के वित्त का लेखा नीचे की तालिका मे प्रस्तुत किया जाता है :

तालिका 112

(करोड रुपयो मे)

	1949–50	1950–51	1951–52	1952–53 (वास्तविक)	1953–54 (सशोधित)	1954–55 (बजट)
भाड़े से कुल आय	236.35	263 01	290.82	270 56	272.00	273.25
साधारण कार्य व्यय .	181.53	180.23	194.04	187 96	197 63	194 31
मूल्यह्रास सचित निधि के लिए सविनियोग .	11.58	30 00	30.00	30.00	30 00	30 00
जिन लाइनो पर कार्य हो रहा है उनके लिए भुगतान .	1.80	0 25	0.31	0 21	0 24	0.22
कुल कार्य व्यय	194.91	210 48	224.35	218 17	227.87	224.53
भाडे से विशुद्ध आय .	41.44	52 53	66 47	52 39	44 13	48 72
विशुद्ध फुटकर व्यय	3.67	4 97	4 72	5.21	6 49	8 08
रेल द्वारा विशुद्ध आय .	37 77	47 56	61 75	47.18	37 64	40 64
साधारण आय को लाभाश .	23 18	32.51	33.41	33 99	34 46	35 50
विशुद्ध लाभ और बचत	14 59	15 05	28.34	13.19	3.18	5.14

बहुत दिनो मे हमारे रेल विभाग के सामने यह प्रश्न रहा है कि किस प्रकार से पुराने इजनो, पटरियो आदि को बदल कर पहले वाली समृद्धावस्था मे पहुचा जाये। रेल विभाग पर पहली चोट तो 1930–39 की आर्थिक मन्दी से पडी। यह मन्दी बहुत दिनो तक कायम रही, और उसी सिलसिले मे द्वितीय महायुद्ध छिड़ा जिसके कारण बहुत बडे पैमाने पर युद्ध सामग्री इधर से उधर भेजी गई। साथ ही पटरिया, इजन और डिब्बो को बदलने की ओर ध्यान नही दिया जा सका। युद्ध की समाप्ति के बाद अभी परिस्थिति सम्भल नही पायी थी कि देश का विभाजन हुआ, जिससे फिर एक बार रेल विभाग पर आपत्ति आयी। फिर भी स्वतत्रता प्राप्ति के कारण जिस प्रकार से देश की समस्याओ पर ध्यान दिया गया उससे 1948 मे यह परिस्थिति हो गयी कि रेल विभाग के बुरे दिन समाप्त हो गये, और तब से हमारी रेले बराबर उन्नति कर रही हैं। 1949–50 के बजट मे पूजीगत खर्च के लिये जहा 64 करोड रुपये की व्यवस्था थी, वहा 1952-53 मे इस रकम को बढा कर 80 करोड रुपये कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना मे स्वाभाविक रूप से रेलो पर और भी अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि रेलों की उन्नति के बिना उत्पादन मे वृद्धि एक तो सम्भव न थी और जितनी सम्भव थी उससे कोई फायदा नही था। इसलिये रेलों के पुनरुद्धार और विस्तार के लिये पचवर्षीय योजना मे 400 करोड रुपये की व्यवस्था है। रेल मे रिजर्व फड की परिस्थिति भी काफी सतोषजनक रही। 1952–53 के अन्त मे रिजर्व 163 करोड रु० का था, ऐसा अनुमान किया जाता है।

1930 से लेकर रेल विभाग पर जिस तरह की आपत्तियां आती गई थी, उससे कितनी हानि हुई इसका अन्दाजा इस बात से लग सकता है कि 1949 की 31 मार्च को यह परिस्थिति हो गई

कि सरकारी रेलों के 30 प्रतिशत इजन अपनी निर्धारित उम्र पार कर चुके थे । इसके कई नतीजे दिखाई पडते थे, एक तो यह कि मरम्मत और कायम रखने का खर्च बहुत अधिक था । 1951 की 31 मार्च को परिस्थिति इतनी खराब थी कि 1,050 रेल इजन, 5,514 सवारी के डिब्बे तथा 21,418 माल के डिब्बे ऐसे हो गये थे जिन्हे फौरन बदलना जरूरी था । प्रति वर्ष 190 रेल इंजन, 650 सवारी वाले डिब्बे और 5,000 माल के डिब्बे बदले जाने चाहिये । इस समस्या को फौरन हल करना आवश्यक था । इसलिये एक तो देश मे जो कुछ भी उत्पन्न हो सकता था उसे अधिक से अधिक कर दिया गया और रोलिग स्टाक के लिये देश के बाहर आर्डर भेजे गये । किस प्रकार से हमें नया सामान मिलता गया, यह निम्न तालिका मे देखा जा सकता है :

तालिका 113

	1949-50	1950-51	1951-52
	प्राप्त (सख्या)	प्राप्त (सख्या)	काम मे आ रहे (सख्या)
रेल-इजन .	435	225	103
सवारी गाडियो के डिब्बे .	346	479	771
माल गाडियो के डिब्बे . .	1,443	3,157	—

निम्न रोलिंग स्टाक की प्राप्ति के लिये 1953-54 के बजट मे 39·30 करोड़ रुपयो की व्यवस्था की गयी है :

तालिका 114

(करोड रुपयो मे)

	कार्यक्रमानुसार पहुच	नयी उपलब्धि
रेल इजन .	6 02	2 07
बायलर्स	1 89	0 16
सवारी गाडी के डिब्बे .	11 28	4 71
माल गाडी के डिब्बे . .	4 71	7 81
फेरीज (नौकाए) . .	0 68	0 03
योग .	24 58	14.78

हमारे कार्यक्रम के अनुसार हमे ये चीजे मिलनी चाहिये—245 रेल इजन, 179 बायलर, 1,384 सवारी वाले डिब्बे, 10,663 माल वाले डिब्बे, 19 क्रेन और 7 फेरिया । इसमे से 150 रेल इजन, 63 बायलर 1,121 सवारी वाले डिब्बे और 6,834 माल वाले डिब्बे देश मे तैयार होंगे, ऐसी आशा है । बाकी माल बाहर से मगाया जा रहा है ।

यह बडे सौभाग्य की बात है कि अब हमारे देश मे रेल सामग्री का उत्पादन इतना आगे बढ गया है कि प्रतिवर्ष साधारण रूप से जितनी पटरियों, माल के डिब्बों तथा सवारी वाले डिब्बों की

आवश्यकता पड़ती है, उतने देश मे उत्पन्न हो रहे हैं । इस बात को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि इन चीजो का बाहर से मगाना रोक दिया जाये । हां, जिन चीजो के आर्डर दिये जा चुके है, वे तो आते ही रहेगे । चित्तरजन रेल इजन कारखाना, टाटा रेल इजन तथा इजीनियरिंग कम्पनी लि० रेल-सामग्री के उत्पादन मे लगी हुई है । जिस समय ये कारखाने अपने पूरे जोर पर होगे, उस समय यह आशा की जाती है कि भारत रेल-सामग्री के मामले में विशेष कर रेल इंजन के मामले मे आत्मनिर्भर हो जायेगा । यह स्मरण रहे कि चित्तरजन रेल इजन कारखाने ने अभी अभी 1950 मे उत्पादन आरम्भ किया है । इसमे अब तक 100 रेल इजन बने हैं । साथ ही देश मे 70 प्रतिशत पुर्जे भी बन रहे हैं । ऐसा अनुमान है कि 1954 तक कुछ विशेष तथा सर्वाधिकार युक्त पुर्जों के अतिरिक्त देश मे सारी रेल-सामग्री उत्पन्न होने लगेगी । चित्तरजन कारखाना प्रतिवर्ष 120 रेल इजन और 50 फालतू बायलर उत्पन्न करने लगेगा । टाटा रेल इजन कम्पनी मीटरगेज के रेल इजन उत्पन्न करती है, और 1953 की जनवरी तक 35 रेल इजन उत्पन्न कर चुकी थी । ऐसी आशा की जाती है कि 1951–56 के बीच यह कम्पनी 200 रेल इजन दे सकेगी ।

यह तो रेल-इजनो की बात हुई, अब रेल के डिब्बो के उत्पादन की बात लीजिए । जनवरी 1952 मे मद्रास के पैराम्बूर नामक स्थान मे सवारी वाले डिब्बो के बनाने का एक कारखाना खोला गया । यह आशा की जाती है कि यह कारखाना दिन मे केवल एक शिफ्ट काम करे, तो भी 300 हल्के अवयवगत किस्म के सर्वइस्पात-डिब्बे सालाना बनने लगेगे । बगलोर की सरकारी हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० कम्पनी 1950–51 मे 63 सर्वइस्पात तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बे और फिर 1951–52 मे 100 और तैयार कर चुकी है । 1953–54 के बजट मे देश मे 7,000 माल के डिब्बे बनने की तथा बाहर मे 4,000 माल के डिब्बे मगाने की व्यवस्था है ।

देश के अन्दर रेल के डिब्बो के उत्पादन का लेखा इस प्रकार है

तालिका 115

	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52	योजना की अवधि (1951-56) मे अनुमानित उत्पादन
सवारी गाडी के डिब्बे	238	337	479	673	4,380
माल गाडी के डिब्बे	2,520	1,095	2,924	3,707	30,000

हाल के वर्षो मे रेल विभाग पहले से अधिक कार्यकुशलता के साथ काम करने लगा है । यह निम्नलिखित आकडो से ज्ञात हो जायेगा

तालिका 116

सचालन कुशलता के देशनांक

	1950-51	1951-52
ब्राड गेज	100·7	102·8
मीटर गेज . . .	92·4	93·6

तालिका 117

सवारी गाड़ियों की समयनिष्ठता का अनुपात

	1947-48	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52
ब्राड गेज . . .	67·6	71·3	81·4	79·8	78·8
मीटर गेज . . .	69·7	68·4	76·7	71·4	77·7

नयी लाइनें

पहले ही यह बताया जा चुका है कि दीमा-गाधीधाम (काण्डला) को मिलाने के लिये एक रेल लाइन बनाई गई। इस के अलावा 1952-53 मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य या तो पूरे हो गये या शुरू किये गये—

(1) उत्तर रेलवे मे बन्द की हुई बाइस मील लम्बी बिजनौर-चादपुर-स्याऊ वाली लाइन का फिर से उद्धार, (2) पश्चिमी रेलवे मे बसदकठाना रेल लाइन का पुनरुद्धार, (3) तिरुवाकुर-कोचीन राज्य को रेल सम्बन्धी सुविधा देने के लिये दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत क्वीलोन-एर्नाकुलम मीटरगेज लाइनो का निर्माण। इस रेल का उद्देश्य कोचीन बन्दरगाह को दक्षिण की मीटरगेज लाइन के साथ मिलाना भी है। (4) मध्य रेलवे मे कल्याण बिजलीघर का तीन करोड रुपये की लागत पर विस्तार।

मुकामाघाट के पास गगा नदी पर एक पुल बनाना बहुत जरूरी था। यह काम आरम्भ हो चुका है। यह पुल उत्तरी और दक्षिणी बिहार को मिलाता है, तथा उन मे आवागमन आसान कर देता है। इस मे 13 करोड रुपये खर्च होंगे। 1950 मे केन्द्रीय परिवहन बोर्ड ने यह निश्चय किया था कि जो बारह लाइने बन्द कर दी गई थी, उन्हे फिर से चालू किया जाये। उन मे से दो लाइने चालू कर दी गई, और नौ लाइनो का काम पूरा होने का है। यह तय हुआ है कि देश की सर्वांगीण प्रगति के लिये प्रतिवर्ष कम से कम 200 मील लम्बी लाइने बढाई जाये।

रेल के किराये और भाड़े

1948 मे रेल के किराये और भाडो की दरे ठीक की गई थी। वे क्रमश: 46 और 13 प्रतिशत बढ गई। यह देखा गया कि एक तो चीजो का मूल्य सामान्यत बहुत बढ चुका था, दूसरे रेल का खर्च विशेष कर मरम्मत सम्बन्धी खर्च बहुत अधिक था, इसलिये 1951 की पहली अप्रैल को किराया बढा दिया गया। सवारियो के किराये का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	प्रति मील
एयर कन्डीशन्ड दर्जा	30 पाई
अव्वल दर्जा	27 पाई

	प्रति मील
दूसरा दर्जा	16 पाई
ड्यौढा (मेल या एक्सप्रेस) दर्जा	10½ पाई
ड्यौढा (मामूली) दर्जा	9 पाई
तीसरा दर्जा (मेल या एक्सप्रेस)	6 पाई
तीसरा दर्जा मामूली	5 पाई

भाडे की सुधारी गयी प्रणाली मे 15 दरे है। इसी प्रकार माल गाड़ियो के द्वारा माल ले जाने मे भी इतनी ही दरे हैं। दूरी बढने के साथ साथ भाडा घट जाता है। छोटे से छोटे रास्ते पर सस्ती से सस्ती दर पर अब माल ले जाया जाता है। निर्यात और आयात के माल भी देशीय माल के साथ एक श्रेणी मे गिने जाते हैं। पहले यह नियम था कि आयात वाले माल को कुछ प्रधानता दी जाती थी। वह अब समाप्त कर दी गई है।

पहले रेल की दरो के सम्बन्ध मे एक अनुविहित दर परामर्श समिति थी। अब उस की जगह पर 1949 मे अनुविहित दर ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी गई है। दरो के सम्बन्ध में जो भी झगडा उठ खडा होता है, उस के लिये यह ट्रिब्यूनल एक कानून ट्रिब्यूनल के रूप मे काम करती है।

स्वराज्य के पहले आम जनता की सुविधाओ पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, पर हमारे लोक कल्याणकारी राष्ट्र मे जनता के प्रति अब यह उदासीनता सम्भव नही है। इस कारण रेल विभाग मे तीसरे दर्जे के यात्रियो की सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। 1949 मे इस उद्देश्य से जो वित्तीय सम्मेलन बुलाया गया था, उस मे इस उद्देश्य से आगामी पाच वर्षो के लिये प्रति वर्ष तीन करोड रुपये के हिसाब से खर्च करना निश्चित हुआ। जिन सुविधाओ के सम्बन्ध मे ध्यान दिया गया, उन में से कुछ ये है : नई माडल गाडिया या आदर्श गाडिया जारी की गई, डिब्बो मे रोशनी की व्यवस्था पहले से अच्छी की गई, नये स्टेशन खोले गये, प्रतीक्षालय तथा हालो की व्यवस्था की गई, टिकट बाटने के नये दफतर और आऊट एजेन्सीज जारी की गई, स्टेशनो पर बिजली की व्यवस्था की गई, प्लेटफार्मो की व्यवस्था की गई, खाना पीना पहुचाने की उन्नत व्यवस्था की गई, स्टेशनो तथा डिब्बो मे और अधिक सफाई की व्यवस्था की गई।

रेलो के सम्बन्ध मे एक शिकायत यह भी थी कि भीड बहुत होती है। तदनुसार 1952 की पहली अप्रैल से 1953 की पहली जुलाई के बीच 109 नई गाडिया जारी की गई और 108 गाडियो के मार्ग का विस्तार किया गया। इस प्रकार प्रतिदिन 9,850 मील सवारी गाडिया बढ़ गई। जनता एक्सप्रेसो का जारी करना एक बहुत बडा काम रहा, क्योकि इन गाडियो मे केवल तीसरे दर्जे के डिब्बे होते हैं। दिल्ली और पठानकोट, दिल्ली और हावडा, लखनऊ और कटिहार, मद्रास (सैंट्रल) और मगलोर, मद्रास (एग्मोर) और तिरुचिरापल्ली, बम्बई और पूना तथा बम्बई और मद्रास के बीच जनता एक्सप्रेस गाडियां जारी की गई।

यह अनुभव किया गया कि हमारी रेले उतनी कार्यकुशल नही है, जितनी होनी चाहियें। इसलिये कार्यकुशलता अधिक कायम रखने के लिये यह प्रस्ताव किया गया कि केन्द्र मे एक छोटा सा कार्यकुशलता ब्यूरो या दफतर हो। 1952 की जनवरी मे बड़ौदा मे रेल के अफसरो के लिये एक प्रशिक्षण कालेज खोला गया। इसके अलावा 1952-53 मे लखनऊ मे प्रधान

दफतर बना कर एक रेल-शोध और परीक्षण केन्द्र तथा चित्तरजन तथा लोनावला मे उपकेन्द्र खोले गये ।

इन बातो के साथ साथ यह भी अनुभव किया गया कि रेल मजदूरो की भलाई का अधिकाधिक ध्यान रखना जरूरी है । 1947 के अगस्त से इस सम्बन्ध मे बहुत काम किया गया है । रेल व्यवस्था विभाग तथा मजदूरो मे मोटे तौर पर सम्बन्ध अच्छे ही रहे । 1952 की जनवरी मे रेल के सम्बन्ध मे मजदूरी की सारी शिकायतो और झगडो को तय करने के लिये तीन सदस्य वाली एक स्थायी सस्था की व्यवस्था कर दी गई । यह द्रष्टव्य है कि 1952-53 मे रेल मजदूरो के कल्याण पर सात करोड रुपये खर्च किये गये ।

1905 मे रेल बोर्ड नाम से एक सस्था तैयार हुई थी, जिस पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि वह रेलो का नियत्रण तथा प्रशासन करे । अब इस बोर्ड को 1951 के अप्रैल मे पुनःसगठित किया गया । अब बोर्ड मे एक वित्तीय आयुक्त और तीन सदस्य है । इन तीन सदस्यो मे से एक व्यक्ति बोर्ड का सभापति होता है, और वह केन्द्रीय रेल-मत्रालय का पदेन सचिव होता है । जनता और रेल प्रशासन के बीच घनिष्ट सम्बन्ध बनाये रखने के लिये अभी हाल ही मे निम्नलिखित समितिया बनाई गई--(1) रेल उपयोग करने वालो की क्षेत्रीय परामर्श-दात्री समिति, (2) रेल उपयोग करने वालो की उपक्षेत्रीय परामर्श-दात्री समिति, जो रेल के प्रत्येक उपक्षेत्र मे प्रधान स्थान पर होती है, (3) रेल उपयोग करने वालो की राष्ट्रीय परामर्श-दात्री परिषद् । यह केन्द्र मे होती है ।

परिवहन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड

1947 के नवम्बर मे परिवहन का केन्द्रीय बोर्ड स्थापित हुआ । इस का काम यह था कि यह परिवहन सम्बन्धी मुख्य समस्याओ, नई नीतियो पर विचार करे । इस का काम यह भी है कि परिवहन के सभी तरीको को अधिकाधिक सयुक्त करे और यह देखे कि देश के सामने इस समय खेती तथा उद्योग धधो की योजना मे सहायता पहुचाये । जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हमारी योजना तभी सफल हो सकती है जब परिवहन विभाग पूर्ण सहयोग करे ।

उक्त बोर्ड का सभापति परिवहन मत्री होता है । सचार--मत्री तथा व्यापार और उद्योग मंत्री इस के उपसभापति होते है और वित्त, प्रतिरक्षा, व्यापार, उद्योगधंधे, राज्य, रेल तथा परिवहन विभाग के उच्च कर्मचारी इस के सदस्य होते है ।

सड़के

1919 के शासन सुधार के अनुसार सडके प्रान्तीय विषय के अन्तर्गत मानी गई । बाद को चल कर 1929 मे पेट्रोल टैक्स की आय से एक केन्द्रीय सडक कोष स्थापित किया गया । इस कोष से प्रान्तो को सडक निर्माण के लिये एकबारगी अनुदान दिया गया । 1947 मे केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सडको के निर्माण और कायम रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली । बात यह है कि इस बीच मे हमारा जो सविधान बना, उस के अनसार राष्ट्रीय सड़के केन्द्रीय सरकार का विषय हो गई । बाकी सड़के यानी जिलो की सडके तथा गाव की सड़के राज्य सरकारो की जिम्मेदारी पर डाल दी गई ।

1948 की 31 मार्च को परिस्थिति यह थी कि देश की नगरपालिकाओं के बाहर 2,48,914 मील सडके थी, जिन मे से लगभग 90,000 मील सडके ऐसी थी जिन पर धरातल था, इस मे भी 13,400 मील सडके राजपथ के रूप मे थी ।

तालिका 118

31 मार्च, 1948 को नगरपालिकाओं के अधिकार के बाहर की सड़कें

(मीलो में)

क्षेत्र	पक्की सडके				कच्ची (जो तैयार नही है) सडके	कुल योग
	बिटुमिन्स	ककरीट	वाटर बाऊड मैकेडम	कुल सपाट सडके		
भूतपूर्व देशी रियासतो के अतिरिक्त भारत .	9,036	652	54,436	64,124	1,14,659	1,78,783(क)
भूतपूर्व देशी रियासते (31 मार्च 1944) .	1,675	111	24,198	25,984	44,147	70,131
योग .	10,711	763	78,634	90,108	1,58,806	2,48,914

विकास योजनाएं

शहरों मे जो सडके है, वे तो है ही, उन के अलावा देश भर मे 1,18,000 मील ऐसी सडके थी जो सभी मौसमो मे जारी रहती थी । भारत की आवश्यकताओ को देखते हुए इतनी सडके काफी नही है। प्रति सौ वर्गमील मे केवल 9·7 मील सर्वऋतु सडके भारत मे है। यह तो स्पष्ट है कि इतनी कम सडकों से हमारी उन्नति नही हो सकती, इसलिये यह उचित है कि पचवर्षीय योजना मे इस के लिये सौ करोड रुपये की व्यवस्था है । इस रकम मे से सताइस करोड रुपये राष्ट्रीय सडको पर तथा बाकी राज्य की सडको पर खर्च की जायेगी । पचवर्षीय योजना में इस सबध मे जो लक्ष्य रक्खा गया है, उसके अनुसार 3,000 मील नई सडके बनेगी और सामूहिक प्रयासो से 16,000 ले कर 17,000 मील सडके बनेगी। गाव वालो को सडक निर्माण कार्य मे उत्साह दिलाने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे सडक बनने के खर्च की दो तिहाई उठायेगी। 1951-53 मे केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सडक के विकास पर 7·4 करोड़ रुपये व्यय किये है। 240 मील नई सडकें और 17 बडे पुल बनाये जा

(क) 53,296 मील पब्लिक वर्कस विभाग तथा सैनिक इजीनियरिग सर्विस द्वारा तथा 1,25,487 मील स्थानीय सस्थाओं द्वारा रक्षित ।

चुके। पहले से मौजूद 1,050 मील सड़क उन्नत की गई, और 150 मील नई सडक, 20 बड़े पुल और 1,500 मील मौजूदा सडको पर काम चल रहा है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सडको के अलावा जिन चुनी हुई सडको के विकास का भार अपने ऊपर लिया है, उनमें त्रिपुरा और आसाम को मिलाने वाली सडक, पठानकोट--जम्मू सडक और सिक्किम की सडक पर 1951-52 तक 117 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस विभाग में 140 मील नई सड़के बनाई जा चुकी थी और 120 मील सडको तथा दो बड़े पुलो का काम जारी था। इसी ज़माने में 7,200 मील राज्य सडके, जिला सडके तथा गाव की सडके बनाई या सुधारी गई।

1951-53 मे "क" भाग के राज्यो ने 22·87 करोड रुपया खर्च किया जब कि योजना के सारेयोग मे कुल मिला कर 50·59 करोड रुपये खर्च करने है। "ख" भाग के राज्यो के लिये (जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त) ये ही आकडे क्रमश. 3.95 करोड रुपये और 15.83 करोड रुपये और "ग" भाग के राज्यो के लिये क्रमश. 1.19 करोड और 627 करोड रुपये थे।

सड़क परिवहन

भारत के गावो को मिलाने के लिये अब भी बैलगाडिया कितनी महत्वपूर्ण है, यह इस बात से जाना जा सकता है कि महायद्ध के पहले 87 लाख बैलगाडिया थी और इन मे 261 करोड रुपये लगे हुए थे। लगभग एक करोड व्यक्ति और दो करोड जानवर बैलगाडी के धन्ध मे लगे हुए थे।

भारत मे 1950-51 की अन्तिम तिमाही मे जिन मोटर गाडियो से टैक्स लिया गया, उन की सख्या 3,10,145 थी। उन मे से 2,906 डीजल इजन से चलाई जाती थी।

मोटर साइकिल	27,105
निजी मोटर गाडिया . . .	1,47,953
सार्वजनिक सेवा की गाडिया . . .	45,753
माल ढोने वाली मोटर गाडिया . . .	85,509
विविध	3,825
योग . .	3,10,145

हमारे सविधान मे मोटर गाडियो के टैक्स के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार को टैक्सो के सिद्धातो पर कानून बनाने का अधिकार है, जब कि टैक्स वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार मे ही निहित है। 1950-51 मे मोटर गाडियो पर टैक्स के रूप मे 7·77 करोड रुपये तथा मोटर गाडियो की लाइसेन्स फीस के रूप मे 84 लाख 90 हजार रुपये प्राप्त किये गये।

भारत मे कुल 1,59,000 मोटर कारे और टैक्सिया, तथा 1,23,000 ट्रक और परिवहन की दूसरी मोटर गाडिया है। घिसाई पिटाई को देखते हुए मोटर गाडियों की वर्तमान सख्या कायम रखने तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये भी प्रति वर्ष लगभग बीस हजार मोटर कारे और बत्तीस हजार परिवहन की दूसरी गाडिया चाहियें।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि मोटर यातायात संचालन करने वालों की सख्या 47,575 है जिन में 46,000 छोटे सचालक हैं और उन मे से प्रत्येक के पास पांच या उससे कम गाड़िया हैं। कार्यकुशलता बढ़ाने तथा खर्च घटाने के लिये इन सचालको को जहा भी सम्भव

हो बड़ी कम्पनियां बनाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 1950 की सड़क परिवहन कारपोरेशन विधि के अनुसार अनुविहित परिवहन कारपोरेशन, त्रिदलीय आधार पर यानी राज्य सरकार, रेल विभाग और निजी आपरेटरो को ले कर बनाया जा रहा है। भारत के 28 राज्यों में से 20 में राज्य सरकारो की परिवहन सेवाये चल रही है। सरकार और निजी कम्पनियो ने सडक परिवहन सेवाओ मे कुल 19 करोड 85 लाख रुपये की रकम लगा रक्खी है। पचवर्षीय योजना के अनुसार राज्य सरकारे और भी 8.97 करोड रुपये लगायेगी, ऐसी आशा है। परिवहन सम्बन्धी 2,000 गाडियो की खरीद के लिये यह रकम खर्च की जायेगी। इस के अलावा इस मे से राज्य सरकार की मोटर गाडियो को कायम रखने, उन की मरम्मत तथा नवकरण के लिये खर्च होगा। मोटर चलाने वालो के प्रशिक्षण के लिये भी सुविधाये दी जायेगी।

आभ्यंतरिक जलमार्ग

नया सविधान लागू होने के पहले आभ्यन्तरिक जलमार्ग राज्यो की जिम्मेदारी समझी जाती थी, पर हमारे सविधान मे आभ्यन्तरिक जलमार्ग जहा तक यत्र—चालित यानो का सम्बन्ध है, समाधिकार सूची मे रख दिया गया है। 1947 मे आभ्यन्तरिक वाष्पजलयान विधि मे कुछ त्रटिया थी, इसलिये 1951 मे उस मे इस प्रकार से सुधार किया गया जिस से आभ्यन्तरिक वाष्पजलयानो को अनिवार्य रूप से पजीकरण करना पडा।

ऐसा समझा जाता है कि भारत मे जल मार्ग के लिये बहुत बडी गुजाइश है। इस समय कुल नाव्य जलमार्ग 5,500 मील है। देश के विभाजन के परिणामस्वरुप उत्तर—पूर्व की नदिया भारत और पाकिस्तान के विभक्त नियत्रण मे आ गई है। फिर भी उत्तर मे गगा और ब्रह्मपुत्र तथा उस की सहायक नदिया जलमार्ग के रूप मे बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये 1952 मे गगा और ब्रह्मपुत्र जल-यातायात बोर्ड के नाम से एक सस्था की स्थापना की गई।

जहाजरानी

1952 के अन्त मे हमारी जहाजरानी सम्बन्धी परिस्थिति यह थी कि 150 जी० आर० टी० के ऊपर वाले भारतीय जहाजो का कुल टनेज 4,52,274 जी० आर० टी० था, पर इतना टनेज बहुत कम था और हमारे व्यापार का एक बहुत बडा हिस्सा यूरोप के जहाजो के सहारे चलता था। इसलिये 1947 की जहाजरानी नीति समिति ने बीस लाख टन का लक्ष्य रक्खा जिस से कि एक तो तमाम भारत के तट का सारा व्यापार अपने जहाजो के द्वारा हो, दूसरे बर्मा, लका और दूसरे पडोसी देशों के साथ भारत के व्यापार का 75 प्रतिशत भारत के हाथ मे आवे; तीसरे समुद्र पार भारत के वाणिज्य का 50 प्रतिशत हमारे जहाजों के ज़रिये हो तथा चौथे पूर्वी देशो मे होने वाला व्यापार जो पहले जापानी, जर्मन और इटैलियन जहाजो के द्वारा हुआ करता था उस का 30 प्रतिशत हमारे जहाजों के द्वारा हो। 1952 के अन्त तक यह परिस्थिति थी कि भारत के तटीय जहाजरानी का आंकडा 2,54,000 टन तक पहुच गया था और तट के व्यापार का 96 प्रतिशत भारतीय जहाजो के द्वारा होता था। सच तो यह है कि अब तट का सारा का सारा व्यापार भारतीय जहाजो के द्वारा होता है। 1951-52 मे भारतीय कम्पनियों को तटवर्ती व्यापार से कुल मिला कर भाड़ मे दस करोड रुपया मिला।

यह बडे सौभाग्य की बात है कि भारतीय जहाजरानी कम्पनियो के माल वाले जहाज नियमित रूप से इग्लैंड, यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया जाते हैं। इस मद मे भारतीय जहाजो को 1951-52 मे कुल नौ करोड रुपये मिले। 1952 के अन्त मे समुद्रपार वाणिज्य में लगे हुए भारतीय जहाजो का कुल टनेज 1,73,000 जी० आर० टी० था।

1947 की जहाजरानी नियन्त्रण विधि के अनुसार अब तट के व्यापार मे नियुक्त सब जहाजों को लाइसेन्स प्राप्त करना पडता है। सरकार ने 1950 मे ईस्टर्न शिपिग कारपोरेशन लि० नाम से एक कम्पनी का सूत्रपात किया। यह कम्पनी आस्ट्रेलिया, सुदूरपूर्व तथा निकटपूर्व के साथ भारत के व्यापार मे लगी हुई है। इस कम्पनी की अधिकृत पूजी दस करोड रुपये है। अब कारपोरेशन भारत-आस्ट्रेलिया, मद्रास-मलाया के मार्गों के यातायात को चलाता है।

जहाजरानी के क्षेत्र मे हमारा देश पिछडा हुआ था, इस बात को देख कर पचवर्षीय योजना मे यह व्यवस्था की गई है कि 14 करोड 94 लाख रुपये जहाजरानी कम्पनियो को रियायती सूद पर दिये जाये जिस से कि वह अतिरिक्त टनेज प्राप्त करे। इस ऋण का ब्यौरा नीचे तालिका 119 मे दिया जा रहा है :

तालिका 119

जहाजरानी का क्षेत्र	ऋण दिया गया धन (करोड रुपयो मे)	टन-सामर्थ्य जिस का अर्जन करना होगा (जी० आर० टी०)
तटीय व्यापार .	4·0	65,000
समुद्रपार का व्यापार . .	6·5	70,000
ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन . .	4·44(क)	40,000

पचवर्षीय योजना के अनुसार 1955-56 तक हमारे देश के जहाजो का कुल टनेज 3,62,150 से बढ कर छ. लाख जी० आर० टी० तक पहुच जायेगा। जहाजो के मूल्य मे तथा भाडे की दरो मे बराबर अत्यधिक उतार चढाव होने के कारण जहाजरानी कम्पनिया 1951-53 मे समुद्रपार वाणिज्य के लिये अतिरिक्त जहाज प्राप्त न कर सकी।

इन बातो को देखते हुए यह जरूरी था कि हमारे देश मे जहाज भी बने। इसी के अनुसार पंचवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम के जहाज वाले कारखाने को लेने तथा उस के विकास के लिये बारह करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। ये कारखाने सिन्धिया कम्पनी से खरीद कर हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सौंप दिये गये हैं, पर नियन्त्रण सरकार ने अपने हाथ मे रक्खा हैं। 1951-53 में 1,07,000 कुल टनेज के 31 जहाज भारतीय जहाज कम्पनियो को प्राप्त हुए थे, इन में से छ: विशाखापत्तनम के जहाज वाले कारखाने मे बने थे।

(क) कारपोरेशन को आवश्यक टन-सामर्थ्य अर्जन करने योग्य बनाने के लिये यह धन सरकार द्वारा लगाया जायेगा।

यद्यपि हमारे यहां जहाजरानी इतनी तरक्की पर है, तो भी यह आवश्यक है कि जहाजरानी विद्या के प्रशिक्षण के लिये कुछ व्यवस्था हो, तदनुसार प्रशिक्षण-जहाज डफरिन मे तथा डायरेक्टरेट आफ मेरीन इजीनियरिग ट्रेनिग मे व्यापारी जहाज के लिये क्रमश. प्रबन्धाधिकारी तथा सामुद्रिक इजीनियरिग का प्रशिक्षण होता है। बम्बई मे नाटिकल तथा इजीनियरिग कालेज मे इस सम्बन्ध मे और उच्च शिक्षा दी जा रही है। कलकत्ता तथा विशाखापत्तनम मे दो प्रशिक्षण जहाजो मे प्रतिवर्ष 1,000 नाविको को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस सख्या को 2,000 तक बढाने के लिये तट पर प्रशिक्षण की और भी व्यवस्था की जायेगी। मुख्य मुख्य बन्दरगाहो पर नाविको की डाक्टरी परीक्षा करने के लिये सुविधाये मौजूद है। 1944 से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय बन्दरगाहो मे नाविको के क्लबो तथा होस्टलो के निर्माण के लिये बराबर बहुत काफी धन दिया है। मख्य भारतीय बन्दरगाहो तथा कुछ विदेशी बन्दरगाहो मे भी कल्याण सेवा करने वाले दफतर मौजूद है।

बन्दरगाह

भारत की तट रेखा 3,500 मील लम्बी है। इस मे पांच मुख्य बन्दरगाह है यानी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम्। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का प्रशासन परिवहन मंत्रालय के द्वारा होता है। यह प्रशासन 1908 की भारतीय बन्दरगाह विधि के अनुसार पोर्ट ट्रस्टों के द्वारा किया जाता है। विशाखापत्तनम पर रेल बोर्ड का प्रशासन है, और कोचीन पर परिवहन मत्रालय द्वारा नियुक्त एक अधिकारी प्रशासन करता है। मुख्य बन्दरगाहो के सम्बन्ध में लेखा इस प्रकार है :

तालिका 120

बन्दरगाह	उन जहाजो की सख्या जिन्होने प्रवेश किया	आयात (लाख टनो में)	निर्यात (लाख टनो मे)	बचत (+) घाटा (—) (लाख रु० मे)
कलकत्ता . .	1,460	40·93	54·90	—0·28
बम्बई . . .	2,767	58·06	16·73	+186·30
मद्रास . . .	1,091	18·55	3·00	+48·89
कोचीन . . .	1,158	10·98	2·49	+4·62

पाकिस्तान के बनने से हमारा एक मुख्य बन्दरगाह कराची भारत से निकल गया। इसलिये भारत सरकार ने 12 करोड 95 लाख रुपये की लागत पर कच्छ मे काण्डला नामक स्थान को एक मुख्य बन्दरगाह के रूप मे विकसित करने का निर्णय किया। 1956 के प्रारम्भ तक इस बन्दरगाह का निर्माण पूरा हो जायेगा। कच्छ मे पांच छोटे बन्दरगाहों के विकास के सम्बन्ध में भी काम जारी है। हमारे यहा जो मुख्य बन्दरगाह है, उन मे भी कई त्रुटियां हैं। इसलिये उन के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये 29 करोड़ 27 लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था रखी गई है। बन्दरगाहो के सम्बन्ध मे हमारी एक समस्या यह भी रही है कि किसी बन्दरगाह में कुछ नियम हैं तो किसी में कुछ। इसलिये प्रशासन की एकरूपता कायम करने के लिये तथा अधिकतर केन्द्रीय नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के मुख्य बन्दर-

गाहो के अधिकारो को विकेन्द्रित करने के लिये 1951 मे पोर्ट ट्रस्ट्स एण्ड पोर्ट्स सशोधन विधि पारित की गई। 1950 मे एक राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड बनाया गया, जो भारत सरकार के सामुद्रिक राज्यो तथा मुख्य बन्दरगाह अधिकारियो के प्रतिनिधियो को ले कर सगठित किया गया। यह बोर्ड बन्दरगाहो के विकास विशेषकर छोटे बन्दरगाहो के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार को सलाह देता रहता है।

नागरिक उड्डयन

1952 मे भारत मे नौ ऐसी कम्पनिया थी जिन के हवाई जहाज नियमपूर्वक देश के अन्दर तथा बाहर उडते थे। 1947 से यह परिस्थिति किस प्रकार रही है यह नीचे देखा जा सकता है—

तालिका 121

वर्ष	उडान के घटे (हजारो मे)	कितने मील उडान की गई (हजार मीलो मे)	यात्रियो की सख्या (हजारो मे)	ढोया हुआ माल (हजार पौडो म)	ढोयी गई डाक (हजार पौडो मे)	टन-मील क्षमता (दस लाख मीलो मे)	प्रति टन भार आय (दस लाख मीलो मे)
1947 .	59	9,362	255	5,648	1,405	18·60	14·36
1948 .	79	12,649	341	11,975	1,583	26·32	19·30
1949 .	94	15,098	357	22,500	5,032	36·54	23·25
1950 .	117	18,896	453	80,007	8,356	52·25	34·41
1951	119	19,498	449	87,665	7,182	57·40	39·02
1952 (क) .	117	19,078	430	75,096	8,244	55·04	35·62

सोलह ऐसी कम्पनिया थी जिन के हवाई जहाज अनुसूचित ढग से नही उडते थे। इन में नौ कम्पनिया अनुसूचित हवाई लाइन चलाती थी। 1952 मे अनुसूचित सेवाओ ने लगभग 37 हजार घटे और 58,96,000 मील उडान की। इन के द्वारा लगभग 83,790 सवारिया ले जाई गई और ये 1,377 लाख पौड माल भी ले गये। तीन भारतीय कम्पनिया ऐसी थी जिन की अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन सेवाये थी और उन के जहाज इग्लैड, पूर्वी अफ्रीका, सिगापुर और अफगानिस्तान जाते थे। भारत के मुख्य शहरो के बीच जो रात्रि एयरमेल सेवाये जारी थीं, उन के द्वारा 1952 मे लगभग 26,783 सवारिया यानी प्रतिदिन औसतन 73 सवारिया, 28·8 लाख पौंड डाक और 10.7 लाख पौड माल ले जाया जाता रहा। जून 1951 के अन्त मे भारत मे 738 पंजीकृत हवाई जहाज थे और 200 हवाई जहाजो को वायुमार्ग के यातायात के सम्बन्ध मे प्रमाणपत्र मिले हुए थे। 1952-53 के अन्त मे हमारे यहां का नागरिक उड्डयन

(क) प्रारम्भ के आठ मासों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित

विभाग 77 एयरोड्रमो को कायम रखता तथा चलाता रहा। 1952-53 मे इस सम्बन्ध मे कुछ प्रगति हुई। तीन नये एयरोड्रम बने जिन मे से एक मगलौर में बना और दो नये संचार केन्द्र खोले गयें । भारतीय वायुयान कम्पनिया नियमित रूप से देश के बाहर काहिरा, रोम, पेरिस, जेनिवा, लन्दन, अदन, नैरोबी, बैंकोक, सिगापुर, लका, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मे हवाई लाइने चलाती रही। इन्हीं दिनों थाईलैंड, ईरान. और मिस्र के साथ वायुयान द्वारा परिवहन के सम्बन्ध मे द्विदलीय समझौते हुए ।

पहली अगस्त 1953 को भारत में एक बहुत क्रान्तिकारी कदम उठाया गया। उस दिन भारत मे वायुयान परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया, और देश के भीतर की तथा बाहर की वायुयान परिवहन सेवाओ को चलाने के लिये दो अनुविहित कारपोरेशन यानी ंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इडिया इंटरनेशनल की स्थापना हुई। इस राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को आग वढाने तथा कार्यान्वित करने के लिये साढ़े 9 करोड़ रुपये पचवर्षीय योजना मे निर्दिष्ट है ।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सगठन का एक सदस्य है। वायुमार्ग परिवहन मे इस देश मे अब लोगों को जो सुविधायें दी जा रही हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार हैं। 1952-53 के अन्त मे नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा परिचालित वैमानिक सचार केन्द्रो की कुल सख्या अट्ठावन थी ।

1948 मे इलाहाबाद मे एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। इस मे वायुयान चालको, इजीनियरिग, एयरोड्रम नियत्रण कर्मचारियो, रेडियो आपरेटरो तथा प्रौद्योगिक लोगो को प्रशिक्षित किया जाता है। भारत मे 1952-53 की जून मे दस सहायता-प्राप्त उड्डयन क्लब तथा दो ग्लाइडिग क्लब ऐसी थी, जहा विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स तथा प्रमाणपत्र के लिये 198 पाइलट प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। शोध तथा विकास के क्षेत्र मे महत्व-पूर्ण कार्य प्रोटोटाइप एच० टी०-2 ट्रेनर एयरक्रैफट का टाइप सर्टिफिकेशन किया जा रहा है। इसे हिन्दुस्तान एयरक्रैफट लि० ने बनाया था। प्रौद्योगिक केन्द्र मे एक मझोला किस्म का ग्लाइडर भी बना। कर्मचारियो को प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा गया और विदेशी विशेषज्ञो की सेवायें अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सगठन के जरिये से प्राप्त की गईं।

पचवर्षीय योजना मे नागरिक उड्डयन के विकास पर 22.8 करोड रुपये खर्च की व्यवस्था है। इस मे से 2.56 करोड़ रुपये 1951-53 मे खर्च हुए।

यात्री व्यवसाय

यूरोप मे तथा अन्य महादेशो मे यात्री व्यवसाय पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। अब तक इस पर सरकार का ध्यान नही था पर स्वतत्र भारत इस ओर से विमुख नही रह सकता था। इसलिये 1948 से सरकार देश मे यात्री व्यवसाय को प्रोत्साहन दे रही है। बात यह है कि एक तो इस से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना बढती है, और दूसरे यह विदेशी विनिमय उपार्जन का एक अच्छा साधन है। 1949 मे परिवहन मत्रालय के अधीन एक यात्री व्यवसाय शाखा खोली गई और तब से महत्वपूर्ण नगरो मे जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास मे क्षेत्रीय यात्री सुबिधा कार्यालय खोले गये हैं। कुछ और स्थानो मे ये दफ्तर छोटे रूप मे मौजूद हैं। यह दफतर राज्य-

सरकारों के यात्रा एजेन्टो तथा होटल के प्रशासन के साथ घनिष्ट सहयोग मे काम करती है। न्यूयार्क मे भी एक यात्री कार्यालय खोला गया है। इन कार्यालयो का काम यह है कि वे विदेशी यात्रियों के लिये युक्तिसंगत सुविधाओ की व्यवस्था करे और यात्रियो को आकृष्ट करने के लिये विदेशों मे प्रचार कार्य करे। 1952 के प्रथम 10 महीनो मे क्षेत्रीय यात्री कार्यालय ने कुल मिला कर 7,328 पूछताछ का उत्तर दिया। इस दृष्टि से गाइड पुस्तके, पुस्तिकाए, पोस्टर तथा फोल्डर निकाले जाते हैं। विदेशो मे वितरण तथा प्रदर्शन के लिये यात्री फिल्मे भी बनाई जा रही हैं। कहना न होगा कि इन कार्यों का परिणाम अच्छा हुआ है। 1951 मे लगभग 20 हजार और 1952 मे 25,448 यात्री भारत आये।

भारत सरकारी यात्रा सगठनो के अन्तर्राष्ट्रीय सघ का सदस्य हो गया है। इस सगठन की ओर से एशिया और दूरपूर्व के लिये भी क्षेत्रीय यात्री आयोग की स्थापना हुई है, और ऐसा करने से यूरोप और अफ़्रीका मे चालू प्रकार के आयोगो का अनकरण किया गया है।

सत्रहवां अध्याय

डाक और तार

रेल विभाग के बाद ही भारत सरकार के कार्यों मे डाक और तार विभाग सब से महत्वपूर्ण है। यह विभाग सचार मत्रालय के अधीन है और इस पर एक डायरेक्टर जनरल का नियत्रण होता है। डायरेक्टर जनरल की सहायता के लिये एक डाक और तार बोर्ड है, जिस के वे सभापति होते हैं। इस बोर्ड के सदस्य मुख्य इजीनियर, वरिष्ठ डिप्टी डायरेक्टर जनरल और सयुक्त सचिव वित्त मत्रालय (सचार डिवीजन) होते है। मुख्य इजीनियर डाक तार के सम्बन्ध मे प्रौद्योगिक परामर्श देता है, और वरिष्ट डिप्टी डायरेक्टर जनरल डाक तथा आर० एम० एस० के सबध मे परामर्श देता है।

इस विभाग का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि यही विभाग डाक तार, टेलीफोन और बेतार के लिये जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त डाकखानों का बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, डाक विभागीय जीवन बीमा और रेडियो सैटो के लिये लाइसेन्स की फीस के सग्रह का काम भी यही विभाग करता है।

प्रशासन की दृष्टि से सारे देश को तेरह भागो मे बाटा गया है जिन मे से ग्यारह डाकतार की इकाइया है, एक डाक वाला वृत्त है जो दिल्ली मे स्थित है। तेरहवी इकाई हैदराबाद वाला डाक-उपवृत्त है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली मे चार टेलीफोन के जिले कायम किये गये है।

नालिका 122

प्रदेशीय इकाइयां

जिला अथवा सर्किल अधिकारी का पद-नाम	अधिकार-क्षेत्र
1. पोस्ट मास्टर-जनरल, पश्चिमी बगाल	पश्चिमी बगाल, अडमान और निकोबार द्वीप-समूह, सिक्किम, और मध्य तिब्बत स्थित तीन डाकखाने।
2 पोस्टमास्टर-जनरल, बिहार	बिहार
3 पोस्टमास्टर-जनरल, उत्तर प्रदेश सर्किल	उत्तर प्रदेश
4. पोस्टमास्टर-जनरल, पजाब सर्किल	पजाब, हिमाचल प्रदेश, पेप्सू, बिलासपुर, जम्मू और काश्मीर, दिल्ली (केवल तार-विभाग)।
5 पोस्टमास्टर-जनरल, बम्बई सर्किल	बम्बई, सौराष्ट्र और कच्छ।
6. पोस्टमास्टर-जनरल, मद्रास सर्किल	मद्रास, मैसूर, तिरुवाकुर-कोचीन, कुर्ग हैदराबाद (यह एक डायरेक्टर के आधीन उप-सर्किल है)।
7. पोस्ट मास्टर जनरल, सैट्रल सर्किल	मध्य-प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश।
8 डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, राजस्थान सर्किल	राजस्थान, मध्य-भारत, भोपाल, और अजमेर

जिला अथवा सर्किल अधिकारी का पद -नाम	अधिकार क्षेत्र
9. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, आंध्र सर्किल	आंध्र
10 डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, उडीसा	उडीसा
11. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, आसाम	आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा
12 डायरेक्टर आफ पोस्टल सर्विसेज, दिल्ली	दिल्ली (केवल डाक)
13 डायरेक्टर आफ पोस्टल सर्विसेज, हैदराबाद	हैदराबाद राज्य (उप-सर्किल)
14 जनरल मैनेजर, कलकत्ता टेलीफोन जिला	कलकत्ता नगर
15 जनरल मैनेजर, बम्बई टेलीफोन जिला	बम्बई नगर
16 जिला मैनेजर, दिल्ली टेलीफोन जिला	दिल्ली व नई दिल्ली के क्षेत्र
17 जिला मैनेजर, मद्रास टेलीफोन जिला	मद्रास नगर
कार्यकारी इकाइया	
एडीशनल चीफ इंजीनियर, पोस्ट एव टेलिग्राफ, जबलपुर	टेली-सचार (डिजाइन और अनुसन्धान) विकास-कार्य के अधिष्ठाता
जनरल मैनेजर, वर्कशाप्स	जबलपुर और बम्बई स्थित पोस्ट एव टेलिग्राफ वर्कशाप्स के अधिष्ठाता
चीफ कंट्रोलर आफ टेलिग्राफ स्टोर्स	टेलिग्राफ व टेलीफोन स्टोर्स के अधिष्ठाता

इस विभाग मे 1952 की 31 मार्च को कुल मिला कर 2,19,710 व्यक्ति काम करते थे, जिन मे से 1,70,184 स्थायी थे, और 49,526 अस्थायी। इस मे 991 अधिकारी है, और 52,896 एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेन्ट है।

डाक और तार विभाग व्यवसायी ढग पर काम करता है। पर रेल विभाग का वित्त जिस प्रकार से सामान्य वित्त से अलग है, इस का वित्त उस प्रकार से अलग नही रखा गया है। चालू खर्च और लगाई हुई पूजी पर सूद स्थूल आमदनी से घटा दिया जाता है, और जो रकम बचती है, वह सामान्य राजस्व विभाग मे दी जाती है। इस प्रकार जो फालतू धन बच रहता है, उस मे से राजस्व विभाग मे एक रकम दे दी जाती है, और बाकी विभाग के नाम पर रोकड के रूप मे दिखलाया जाता है। उस प्रकार जो फालतू धन राशि जमा होती है, उस पर विभाग को कुछ छूट मिलती है।

1953-54 के बजट सम्बन्धी अनुमानो मे इस विभाग की स्थूल आमदनी 42 करोड 22 लाख रुपये तथा चालू खर्च और सूद 41 करोड 82 लाख रुपये कूता गया था। इस प्रकार से 40 लाख रुपये की बचत थी, जबकि 1952-53 के बजट सम्बन्धी अनुमानो मे यह रकम 1 करोड 16 लाख रुपये थी। इस प्रकार बचत घटने का कारण अतिरिक्त कर्मचारियो की नियुक्ति बतलाई जाती है। एकत्रित फालतू धन तथा लगाई हुई कुल पूजी क्रमश 14 करोड 37 लाख रुपये और 57 करोड रुपये है।

भारतीय डाक पद्धति 1,60,000 मील तक फैली हुई है। इस मे से यह 24 प्रतिशत डाक रेल द्वारा, 17 प्रतिशत मोटर गाडियो के द्वारा और 5 प्रतिशत परिवहन के दूसरे साधनो के

द्वारा जैसे स्टीमरो, डाक ले जाने वाली बैलगाडियो, घोडो, खच्चरों और ऊटो के द्वारा ले जाई जाती है। बाकी यानी कुल का 54 प्रतिशत हरकारो तथा छोटी नावो के द्वारा ले जाई जाती है।

रात के चलते फिरते डाकघर

रात के चलते फिरते डाकघरो का कार्यक्रम प्रयोगात्मक ढग से पहले पहल नागपुर में चालू किया गया। बाद को यह योजना मद्रास, दिल्ली, और कानपुर मे लागू कर दी गई। शहर के मामूली डाकघरो के बन्द हो जाने के बाद चलते फिरते डाकघर शहर के महत्वपूर्ण केन्द्रो मे निर्दिष्ट समय पर पहुचते है। यह डाकघर सभी दिनो यानी रविवारो तथा डाकघरो की अन्य छुट्टी के दिन भी चालू रहते है। चलते फिरते डाकघरो मे मनीआर्डर नही लिये जाते और न सेविंगस बैंक का ही काम किया जाता है।

हवाई डाक और सर्व-हवाई डाक की योजनाएं

1948 मे भारत के मुख्य नगरो यानी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और नागपुर को जोडती हुई एक आभ्यन्तरिक रात्रि हवाई डाक सेवा का प्रवर्तन किया गया। 1949 से हवाई डाक योजना के अनुसार सारे पत्र, पोस्टकार्ड इत्यादि मामूली तौर पर हवाई डाक से भेजे जाते हैं, और इस के लिये कोई अतिरिक्त महसूल नही देना पडता। 1951 की पहली मई से यह योजना आभ्यन्तरिक मनीआर्डर पर भी लागू कर दी गई। इसके अलावा सारी आभ्यन्तरिक इश्योरेस शुदा डाक भी जहा तक सम्भव और सुविधाजनक है हवाई जहाज से भेजी जानी है। विदेशो मे जाने वाला या विदेशो से आने वाला सामान देश के अन्दर हवाई डाक से नही भेजा जाता। 1951-52 तक यह परिस्थिति पहुच गई थी कि 55 लाख पौड डाक यानी सारी डाक का 27 प्रतिशत आभ्यन्तरिक हवाई डाक मार्ग से ले जाया गया। त्रिपुरा राज्य मे अगरतला को जाने या वहा से आने वाली सब तरह की डाक जिस मे पैकेट और पारसल भी है, बिना किसी अतिरिक्त महसूल के हवाई मार्ग मे ले जायी जाती है। 1951 मे एक पद्धति यह जारी की गई थी कि जम्मू और काश्मीर तथा भारत के बीच मे जो पारसल और पजीकृत समाचारपत्र रियायती हवाई महसूल पर हवाईडाक से भेजे जाते थे, उनका भेजा जाना अब भी जारी रक्खा जा रहा है। भारत से आस्ट्रेलिया, मिस्र, फ्रास, स्विट्जरलैंड, इग्लैड और अमेरिका के लिये एक हवाई पारसल सेवा 1953 की 2 जनवरी को जारी की गई। उसी तारीख से लंका के लिये हवाई डाक के पत्र सामान्य पजीकरण फीस के देने पर पजीकृत किये जा सकते है।

नीचे की तालिका मे डाक तार विभाग द्वारा किये हुए काम का लेखा प्रस्तुत किया जाता है

तालिका 123

(सख्याए दस लाखो मे)

	1938-39	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (वास्तविक)
I डाक जो लाई तथा ले जाई गई (इस मे सरकारी और रजिस्टर्ड-डाक भी शामिल है)	1,241 (क)	2,365·8	2,703

(क) दो सप्ताहो के औसत पर आधारित।

	1938-39	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (वास्तविक)
2. रजिस्टर्ड सामान जो लाया ले जाया गया (इस में वी० पी० और बीमा किया सामान भी शामिल है)	42	85·4	91·3
3. मनीआर्डर जो पहुंचाये गये (अन्तर्देशीय और विदेशी दोनों)	43	56·3	57·1
4. पहुंचाये गये मनीआर्डरों का मूल्य (अंतर्देशीय और विदेशी दोनों)	820	2,150	1,980·7
5. सेविंग्स बैंक का लेन-देन . .	12.48	12·99	14·4(ख)
6. नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट (लेन-देन आदि)	1.21	1·7	1·3 (ख)
7. तार	16.37	29·2(घ)	29·7(ग)
8. टेलीफोन सम्बन्ध (संख्या) .	83,378	1,84,506	2,00,800(ङ)
9. ट्रंककाल . . .	2.25	8·9	10·8
10. कितने मील तार कायम रखे गये	5,13,924	7,21,243(च)	7,77,566(ङ)

डाक और तार की वृद्धि डाकखानो तथा उन मे नियुक्त कर्मचारियो की सख्या बढ़ जाने के कारण ढग से देखरेख करने का प्रश्न भी सामने आया। इस कारण डाकघरो की देखरेख तथा नियत्रण तथा देहाती इलाको मे डाक पहुचाने पर क्या व्यवस्था हो सकती है, इस सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये पोस्टमास्टर जनरल की मर्यादा का एक उच्च कर्मचारी नियुक्त किया गया। उन स्थानो पर बीस अतिरिक्त डाक डिवीज़न बनाये गये जहा उन की बहुत ही आवश्यकता थी ।

तालिका 124

अतिरिक्त डाकखाने

सर्किल	1-4-1952 से 31-12-1952 तक		1-1-1953 से 31-8-1953 तक	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
आसाम . .	34	1	120	6
बिहार . . .	55	3	566	4
बम्बई . . .	11	–	82	1
सेंट्रल . . .	18	4	120	7
दिल्ली . . .	4	5	15	6
हैदराबाद . .	2	1	15	4
मद्रास . . .	44	39	150	61
उड़ीसा. . .	11	1	18	1
पंजाब . . .	37	14	52	21
उत्तर-प्रदेश . .	22	4	158	4
पश्चिमी-बंगाल . .	24	–	119	4
योग . .	262	72	1,405	127

(ख) लगभग। (ग) अनुमानित। (घ) जैसे कि 31 मार्च 1952 को थी।
(ङ) जैसे कि 31 मार्च, 1952 को थी। (च) जैसे कि 31 मार्च, 1951 को थी।

नीचे की तालिका में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इस विभाग का कितना विस्तार हुआ यह दिखलाया गया है :

तालिका 125

कार्यालय	31-3-1948 की स्थिति के अनुसार	31-8-1953 की स्थिति के अनुसार
ग्रामीण डाकखाने	19,181	38,168
शहरी डाकखाने . . .	4,160	5,782
तार-घर	7,330	8,360 (क)
टेलीफोन एक्सचेंज (इन मे पी० बी० एक्सचेज भी शामिल हैं)	2,487	4,277 (क)
सार्वजनिक टेलीफोन-स्थान . . .	479	1,839 (ख)
टेलिफोन सम्बन्ध	1,14,922	1,99,934 (क)

तार और टेलीफोन

टेलीफोन

जब से भारत स्वतत्र हुआ है, तब से यहा टेलीफोनों की संख्या भी बढ़ी है। तब से 85 हजार टेलीफोन और बढे है। सारे देश मे 600 से ऊपर टेलीफोन एक्सचेज है, और दो लाख टेलीफोन है। इस के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में सार्वजनिक टेलीफोनगृह खोले गये है। बरावर लोग टेलीफोन की माग करते है और यह अनुमान किया जाता है कि 1953-54 के अन्त मे भी टेलीफोन मागने के सम्बन्ध मे 1 लाख 20 हजार आवेदनपत्र विचारार्थ बाकी बच रहेगे।

टेलीफोन के "मालिक बनो कार्यक्रम"

यह योजना दिसम्बर 1949 मे अहमदाबाद, अमृतसर, बगलौर, भटिण्डा, वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, धुबरी, एरोड, गुन्टूर, हैदराबाद, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, मेरठ, नागपुर, राजकोट और सूरत में चालू की गई। इस योजना के अनुसार वम्बई और कलकत्ता मे एक टेलीफोन के लिये 2,500 रुपये और बाकी स्थानों में 2,000 रुपये बीस साल के लिये ले लिये जाते हैं। प्रतिमास इसे कायम रखने के रूप मे 2 रुपये लिये जाते है। इस योजना के अनुसार लगभग 13,109 लोगों को टेलीफोन मिल चके, और 3,19,87,500 रुपये उन से 1952 के अन्त तक लिये जा चके थे।

अपने एक्सचेंज के मालिक बनो

यह योजना 1950 में चालू की गई। इस योजना के अनसार डाक तार विभाग 50 लाइनों वाला एक एक्सचेंज खोल सकता है बशर्ते कि संस्थायें, कोठियां तथा व्यक्ति 2¾ प्रतिशत सूद पर पचास हजार रुपये का ऋण पेशगी देने के लिये तैयार हों। यह रकम बीस साल बाद वापिस मिल सकती है। अब तक इस योजना के अनुसार 7 एक्सचेंज खुल चुके हैं।

(क) 31 दिसम्बर, 1952 की स्थिति के अनुसार।
(ख) 1 अप्रैल, 1952 की स्थिति के अनुसार।

प्रति सन्देश पद्धति

इस पद्धति का प्रवर्तन 1947 के अप्रैल मे हुआ । इस पद्धति के अनुसार ग्राहकों को प्रति बार टेलीफोन करने के लिये शुल्क देना पडता है, और साथ ही एक निर्दिष्ट मासिक किराया देना पडता है । यह पद्धति 13 स्थानो पर यानी अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, पूना, शिमला, और त्रिवेन्द्रम मे चालू है ।

ट्रंक काल

1952-53 मे एक करोड दस लाख ट्रक काले हुईं । इस ओर कितनी प्रगति हुई यह इस से जाना जा सकता है कि 1948-49 मे चवालीस लाख ट्रक काल हुई थी । यह बढती शायद इस कारण हुई कि 1951 के 1 सितम्बर मे 362 5 मील से अधिक दूर की ट्रक काले रियायती दर पर करने दिये जाने लगी । अन्य दरे इस प्रकार है :—

(1) पहले जहा प्रति 12.5 मील पर 3.2 आने लिये जाते थे, अब उस की जगह पर प्रति 25 मील पर चार आने लिये जाते है ।

(2) पहले 500 मील से अधिक दूर पर प्रति 12·5 मील पर 3·2 आने लिये जाते थे, अब उस की जगह प्रति 50 मील या उस के अश के लिये 6 आने लिये जाते है ।

स्वयंगतिक एक्सचेंज

कलकत्ता मे स्वयगतिक टेलीफोन एक्सचेज का काम जारी है । अनुमान है कि उस मे कुल मिला कर 13 करोड 40 लाख रुपये लगेगे । जून 1953 तक एक्सचेज की दो इमारते बनी, जिनकी कुल क्षमता 14 हजार लाइनो की है । बम्बई की टेलीफोन पद्धति की क्षमता 8,100 लाइनो की है, श्रौर श्राशा है कि मार्च 1954 तक 7,200 लाइने काम करने लगेगी ।

1953 की 24 जनवरी को दिल्ली के तीसहजारी स्वयगतिक एक्सचेज मे 29 हजार लाइने जारी थी और इन के अलावा 1,100 लाइने लगाई जा रही थी ।

रेडियो टेलीफोन सेवा

भारत से बर्मा, मिस्र, इडोनीशिया, ईरान, जापान, नैरोबी, और इग्लैड का प्रत्यक्ष टेलीफोन सम्बन्ध है । लन्दन के जरिये से भारत और निम्नलिखित देशो मे रेडियो टेलीफोन सेवा जारी है—आस्ट्रेलिया, बरबादोस, बेलजियम, बरमूडा, कनाडा, क्यूबा, चैकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रास, जिब्राल्टर, हंगरी, आइसलैंड, इटली, केनिया, लक्जमबर्ग, मैक्सिको, हालैंड, उत्तरी रोडेशिया, नार्वे, सार, स्पेन, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी आयर्लैण्ड, दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टैगानिका, उगान्डा, सयुक्त राज्य अमेरिका, वैटिकन शहर तथा पश्चिमी जर्मनी । कुछ जहाज ऐसे है जो समुद्र मे चलते रहने पर भी टेलीफोन द्वारा हम से सम्बद्ध रहते है, उन के नाम ये है—क्वीन मेरी, क्वीन एलिजाबेथ, एक्वीटेनिया, ओसलोफोर्ड, न्यूर, कारोनिया, मैरेटेनिया, अमेरिका ।

टेलीफोन सम्बन्धी प्रशिक्षण पाने के लिये सात प्रशिक्षण केन्द्र है—सहारनपुर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली, नागपुर, अम्बाला । इन में प्रतिवर्ष 800 टेलीफोन कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ।

तार

1951 के 31 दिसम्बर को इस देश मे 8,360 तार के दफतर थे। हमारे सामने लक्ष्य यह है कि 5,000 से ऊपर आबादी वाले हरेक कस्बे में तार–दफतर की सुविधा हो। यह कार्य अच्छी तरह चल रहा है। वी० एफ० टी० पद्धति चालू किये जाने के कारण इन महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच टेलीग्राफ सरकिट्स बढ गये—बम्बई और जोधपुर, नागपुर और बेलगांव, राजकोट और सिकन्दराबाद, त्रिवेन्द्रम और कोयमबत्तूर, नई दिल्ली और जोधपुर, जोधपुर और कराची। एफ० एम० पद्धति के अलावा वी० एफ० टी० पद्धति वाला सरंजाम नई दिल्ली और कलकत्ता के बीच प्रयोग मे लाया गया। इन दोनों पद्धतियों को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है।

टेलीप्रिन्टरो का काम काफी तरक्की पर है। इसके फलस्वरूप तार जल्दी पहुंच रहे हैं, और साधारण तारों में जनता का विश्वास बढ़ गया है। जहां 1948-49 में भेजे हुए तारों में से 45 प्रतिशत एक्सप्रेस तार होते थे, वहां 1951-52 में कुल 29·4 प्रतिशत तार ही एक्सप्रेस भेजे गये ह। ऊपर जो बातें बतलाई गईं, उनके अलावा तार विभाग इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहा है कि तार जल्दी पहुचे और जल्दी मिल जाये। इस सम्बन्ध में कई अन्य उपाय भी काम मे लाये गये है।

तार सम्बन्धी अन्य सुविधायें

1953 की एक जनवरी से तार विभाग ने एक नई सुविधा प्रदान की। पहले जहां केवल एक साल या छ: महीने के लिये ही तार के सक्षिप्त पते स्वीकृत और पजीकृत होते थे, अब तीन माह, छ: माह, और नौ माह तथा एक साल के लिये भी तार के सक्षिप्त पते पजीकृत हो सकते है। बम्बई और लन्दन के बीच तथा लन्दन के जरिये से न्यूयार्क और यूरोप के साथ फोटो टेलीग्राम सेवा जारी है। अब बेलजियम, फिनलैंड, नार्वे तथा स्वीडन के साथ भी यह सम्बन्ध जारी कर दिया गया है।

द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के बाद विदेशो के लिये डीलक्स टेलीग्राम सेवा बन्द कर दी गई थी पर अब फिर से यह जारी हुई है। अदन, ऐशेन्शन, बरमूडा, साइप्रस, फिजी (केवल सूवा), गाम्बिया, जिब्राल्टर, गोल्डकोस्ट (केवल अकरा), हागकांग, मलय (केवल सिंगापुर और पेनाग), माल्टा, मारीशश, नाइजीरिया (केवल लागोस), उत्तर बोर्नियो, न्यासालैंड रोड्रीगुइज, सेंट हेलेना, शिशेलिस, सियर्रा लियोने (केवल फ्री टाऊन), इंग्लैंड और जजीबार के लिये यह सेवा फिर से प्राप्त है। पाकिस्तान के लिये भी यह पद्धति चालू है बशर्तेकि आन्तरिक दर के अतिरिक्त प्रति तार पर चार आने और दिये जायें।

बेतार के तार

एक तरफ बम्बई और दूसरी तरफ लन्दन, मेलबोर्न, शंघाई, टोकियो, न्यूयार्क, काबल और जकार्ता तथा नई दिल्ली और लन्दन और नई दिल्ली तथा मास्को के बीच सीधे सर्किट मौजूद हैं।

जलवर्ती केबल तार सेवा

इस उपाय द्वारा (1) लन्दन से बजरिये अदन, पोर्ट सूडान, अलग्जैंड्रिया इत्यादि बम्बई संयुक्त है। इस प्रकार सारे यूरोप से सम्बन्ध मौजूद है। (2) मद्रास से पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग

इत्यादि का, इस प्रकार दूरपूर्व का सम्बन्ध है। (3) बम्बई का जंजीबार और अदन का और इस प्रकार पूर्वी और दक्षिणी अफ़्रीका से सम्बन्ध है।

अभ्यान्तरिक बेतार

कलकत्ता और अगरतल्ला के बीच एक रेडियो टेलीफोन सेवा है। मद्रास और रंगून के बीच अत्यन्त द्रुत बेतार सेवा कायम की गई है।

बेतार मानिटरिंग

बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और जबलपुर में पांच मानिटरिंग स्टेशन इस समय चालू हैं।

भारतीय भाषाओं में तार

1949 की एक जनवरी को देवनागरी लिपि में तार सम्बन्धी सेवा का आरम्भ किया गया। फोनोकोम पद्धति के चालू हो जाने के कारण अब देवनागरी लिपि में भारतीय भाषाओं के तारों को 455 दफतरों में लिया और दिया जा सकता है। इस सुविधा को बढ़ाने के लिये आगरा, कलकत्ता, जबलपुर, पटना और पूना में पांच हिन्दी तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। हैदराबाद और सिकन्दराबाद में हिन्दी मोर्स पद्धति चालू की गई है। यह अंग्रेजी की मोर्स कोड पर आधारित है। उदाहरणस्वरूप अंग्रेजी अक्षर "के" के लिये जो सिगनल है, उस को हिन्दी अक्षर "क" के लिये प्रस्तुत किया गया है इत्यादि। अंकों के लिये अंग्रेजी सिगनल ही रक्खे गये हैं। 1950 की जुलाई से अभिनन्दन सम्बन्धी तार हिन्दी में लिये जाते हैं। जिन स्थानों पर हिन्दी की तार सेवा मौजूद है, उन स्थानों में देवनागरी लिपि के लिखे हुए अन्य भारतीय भाषाओं के तार लिये जाते हैं। हिन्दी में तार और मनीआर्डर भेजने तथा नागरी लिपि में तार के पतों का पंजीकरण भी स्वीकृत कर लिया गया है।

हिन्दी टेलीप्रिन्टर

जबलपुर के प्रशिक्षण केन्द्र में अंग्रेजी टेलीप्रिन्टर को हिन्दी की आवश्यकताओं के अनुसार बदल दिया गया है। 1953 की जनवरी में हैदराबाद के नानलनगर नामक स्थान में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस में इन बदले हुए टेलीप्रिन्टरों के जरिये से लगभग 400 सन्देश नई दिल्ली भेजे गये।

तार विभाग की शताब्दी जयन्ती

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने दिल्ली में भारतीय तार विभाग की शताब्दी जयन्ती का उद्घाटन किया। इस अवसर के उपलक्ष्य में तार विभाग के द्वारा तार सचार प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई थी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने अक्तूबर 1851 से ले कर इस विभाग ने जो उन्नति की उस पर संतोष प्रकट किया। अक्तूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच यानी इक्कीस मील दूरी पर तार की पहली लाइन काम करने लगी थी।

पंचवर्षीय योजना

पंचवर्षीय योजना में डाक तार और टेलीफोन के विकास के लिये पचास करोड़ रुपये आवंटित हैं, जिस में से अब तक अठारह करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस विकास योजना में विशेष रूप से देहाती इलाकों की सुविधा तथा बड़े शहरों में टेलीफोन की सुविधा पर जोर दिया गया है।

वह दिन दूर नही है, जब डाक की सेवा यंत्रीकृत हो जायेगी, और पोस्टकार्ड तथा लिफाफे बेचने के लिये स्टाल मशीनें काम करेगी। तार संचार विभाग ने बड़े शहरों में टेलीफोन एक्सचेंजों को बढाने, ट्रंक—टेलीफोन सेवा के आधुनिकीकरण तथा विस्तार तथा अतिरिक्त तार—सर्किट की स्थापना के लिये योजनाएं बनाई हैं।

डाक की चालू दरें

देश के अन्दर के पत्र

एक तोले से अधिक नही . . .	2 आने
प्रत्येक अतिरिक्त तोला या उस के भग्नाश के लिये .	1 आना

पोस्टकार्ड

(1) स्थानीय	
(क) एक	6 पाई
(ख) जवाबी	1 आना
(2) साधारण	
(क) एक	9 पाई
(ख) जवाबी	1 आना 6 पाई
(3) लैटर कार्ड	1 आना 6 पाई

पुस्तक, पैटर्न या नमूने के पैकेट

5 तोला तक	1 आना
प्रति अतिरिक्त $2\frac{1}{2}$ तोला या उस के भग्नाश के लिये .	6 पाई
अधिक से अधिक वजन जो भेजा जा सकता है .	200 तोला

समाचार-पत्र : देश के अन्दर की दर

10 तोला से अधिक नही. . . .	3 पाई
10 तोले से ऊपर या 20 तोले तक . .	6 पाई
दो औंस की प्रति इकाई या उस के भग्नाश के लिये .	3 पाई
प्रति दस तोला या उस के भग्नाश के लिये . .	6 पाई

पार्सल

40 तोले से अधिक नही	8 आने
प्रत्येक अतिरिक्त 40 तोले या उस के अंश के लिये .	8 आने
अधिक से अधिक वजन	1,000 तोला या $12\frac{1}{2}$ सेर

440 तोले से अधिक के पारसलो की रजिस्ट्री अनिवार्य है।

रजिस्ट्री

रजिस्ट्री की फीस	6 आने प्रति अदद

बीमा

100 रुपये के मूल्य तक की वस्तु के लिये बीमा की फीस .	6 आने

प्रति अतिरिक्त 100 रुपये के बीमा मूल्य के लिये 3 आने
अधिकसे अधिक बीमा कितने का हो सकता है . 5,000 रुपये

हवाई डाक

पत्रों, पोस्टकार्डों और लैटर कार्डों के लिये कोई अतिरिक्त शुल्क नही है ।

पैकेटो के लिये प्रति तोला 6 पाई के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क लगता है ।

आन्तरिक हवाई पारसलो के लिये प्रति 20 तोला या उस के भग्नाशो के लिये 10 आने लगते है ।

विदेशी डाक

1. पत्र

एक औस से अधिक नही . . . . . 4 आने
प्रति अतिरिक्त औस या भग्नाश के लिये . . 2 आने 6 पाई

2. पोस्टकार्ड

एक . . . . . . 2 आने 6 पाई
जवाबी . . . . . . 5 आने
छपे हुए कागज प्रति 2 औस या उस के भग्नाश के लिये . 1 आना

3. व्यापार सम्बन्धी कागजात

8 औस से अधिक नही . . . . 4 आने
प्रति अतिरिक्त 2 औस या उस के भग्नाश के लिये . 1 आना

4. नमूने के पैकेट

औस से अधिक नही . . . . 2 आने
प्रति अतिरिक्त 2 औस या उस के भग्नाश के लिये . 1 आना

हवाई शुल्क : विदेशी

	पत्र (प्रति आधा औंस या उस के अंश)			पोस्ट कार्ड			हवाई पत्र		
	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.
अफगानिस्तान	0	6	0	0	4	0	0	5	0
बर्मा	0	6	0	0	4	0	0	5	0
चीन	0	10	0	0	6	0	0	8	0

	पत्र (प्रति आधा औंस या उस के अंश)			पोस्ट कार्ड			हवाई पत्र		
	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.
हिन्द-चीन	0	10	0	0	6	0	0	8	0
हिन्देशिया	0	10	0	0	6	0	0	8	0
ईरान, ईराक, इजराइल	0	10	0	0	6	0	0	8	0
जापान, कोरिया, मलय	0	10	0	0	6	0	0	8	0
मिस्र, तुर्की	0	10	0	0	6	0	0	8	0
आस्ट्रिया	0	14	0	0	6	0	0	8	0
डेनमार्क	0	14	0	0	6	0	0	8	0
फ्रांस	0	14	0	0	6	0	0	8	0
जिब्रालटर	0	14	0	0	6	0	0	8	0
ग्रेट ब्रिटेन	0	14	0	0	6	0	0	8	0
ग्रीस	0	14	0	0	6	0	0	8	0
नार्वे	0	14	0	0	6	0	0	8	0
पोलैंड	0	14	0	0	6	0	0	8	0
स्विट्जरलैण्ड	0	14	0	0	6	0	0	8	0
सोवियत यूनियन	0	14	0	0	6	0	0	8	0
इथियोपिया	0	14	0	0	6	0	0	8	0
केनिया	0	14	0	0	6	0	0	8	0
लीबिया	0	14	0	0	6	0	0	8	0
सूडान	0	14	0	0	6	0	0	8	0
आस्ट्रेलिया	1	2	0	0	8	0	0	10	0
न्यूजीलैंड	1	2	0	0	8	0	0	10	0
गोल्ड कोस्ट	1	2	0	0	8	0	0	10	0
मारीशश	1	2	0	0	8	0	0	10	0
दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका	1	2	0	0	8	0	0	10	0
दक्षिण-अफ्रीका यूनियन	1	2	0	0	8	0	0	10	0
बरमूडा	1	8	0	0	10	0	0	12	0
कनाडा	1	8	0	0	10	0	0	12	0
क्यूबा	1	8	0	0	10	0	0	12	0
मैक्सिको	1	8	0	0	10	0	0	12	0
अमेरिका	1	8	0	0	10	0	0	12	0
ब्रिटिश गयाना	1	8	0	0	10	0	0	12	0
कोलम्बिया	1	8	0	0	10	0	0	12	0
पेरू	1	8	0	0	10	0	0	12	0
वेनेज्युएला	1	8	0	0	10	0	0	12	0

पुस्तकों, नमूने के पैकेटों तथा पैटर्न्स को द्वितीय श्रेणी के हवाई डाक से लंका, पाकिस्तान और पुर्तगाली भारत भेजने के लिये साधारण अन्तर्देशीय डाक-महसूल के अतिरिक्त डेढ़ आना प्रति तोला वायु-उपरि-शुल्क भी लिया जायेगा।

हवाई पारसल	प्रथम पौंड के लिये डाक-महसूल (जिसमे वायु-शुल्क भी शामिल है)			उस के बाद प्रति 4 औंस या उस के अंशों के लिये डाक-महसूल (जिस मे वायु शुल्क भी शामिल है)		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
अफगानिस्तान . .	5	8	0	0	11	0
आस्ट्रेलिया . .	10	8	0	2	5	0
लंका . .	2	0	0	(प्रति पौंड तथा उसके अंश के लिये)		
मिस्र . . .	7	12	0	1	2	0
फ़्रांस . . .	11	0	0	1	14	0
यूनाइटेड किंगडम .	9	12	0	1	14	0
स्विट्जरलैण्ड . .	9	8	0	1	12	0
अमेरिका . .	15	8	0	3	8	0

विविध

मनीआर्डर

5 रुपये तक	2 आना
5 रुपये से अधिक और 10 रुपये तक . .	3 आना
10 रुपये से अधिक और 15 रुपये तक . .	4 आना
15 रुपये से अधिक और 25 रुपये तक . .	6 आना
प्रति 25 रुपये	6 आना

तार द्वारा मनीआर्डर

तार द्वारा मनीआर्डर भेजने के लिये साधारण मनीआर्डर द्वारा भेजने मे जो शुल्क लगता है उस मे तार का मूल्य और 2 आने का उपरि-शुल्क जोड कर शुल्क देना होता है।

पोस्टल आर्डर

पोस्टल आर्डर.	1 आना प्रति आर्डर
एक्सप्रेस डिलीवरी	2 आना
व्यापारी जवाबी पोस्टकार्ड व लिफाफे (वार्षिक परमिट) .	10 रुपये

पोस्ट बाक्स थैले

वार्षिक	12 रुपये
त्रैमासिक	4 रुपये
सम्मिलित पोस्टबाक्स व बैग (वार्षिक) . .	15 रुपये

सेविंग्स बैंक

यह निश्चय किया गया है कि :

(1) जमा किये जा सकने वाले धन का अधिकतम परिमाण बढा कर प्रति व्यक्ति 15,000 रुपया और सम्मिलित रूप से 30,000 रुपया कर दिया जाये।

(2) 10,000 रुपये तक की जमा रकम पर 2 प्रतिशत ब्याज तथा 10,000 से अधिक की जमा रकम पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज दिया जाये ।

(3) सप्ताह में दो बार धन निकालने दिया जाये यदि कुल निकाला गया धन 10,000 रुपये तक हो, और

(4) बम्बई जी० पी० ओ० तथा बम्बई सर्किल के कुछ विशेष हैड पोस्टआफिसो से चेक द्वारा धन निकालने दिया जाये ।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स

बारह वर्षीय सर्टिफिकेट्स

दर्जा—5 रु०, 10 रु०, 50 रु०, 100 रु०, 500 रु०, 1,000 रु०, और 5,000 रु० ।

भुनाने के समय मूल्य—7 रु० 8 आ०, 15 रु०, 75 रु०, 150 रु०, 750 रु०, 1,500 रु० और 7,500 रु० ।

सात वर्षीय सर्टिफिकेट्स

दर्जा—5 रु०, 10 रु०, 50 रु०, 100 रु०, 1,000 रु०, और 5000 रु० ।

भुनाने के समय मूल्य—6 रु० 4 आ०, 12 रु० 8 आ०, 62 रु० 8 आ०, 125 रु०, 1,250 रु० और 6,250 रु० ।

पांच वर्षीय सर्टिफिकेट्स

दर्जा—5 रु०, 10 रु०, 50 रु०, 100 रु०, 1,000 रु० और 5,000 रु० ।

भनाने के समय मूल्य—5 रु० 12 आ०, 11 रु० 8 आ०, 57 रु० 8 आ०, 115 रु०, 1,150 रु० और 5,750 रु० ।

कोई अकेला व्यक्ति 25,000 रु० के मूल्य तक के सर्टिफिकेट ले सकता है पर किसी अन्य व्यक्ति के संग मिल कर वह सयुक्त रूप से 50,000 रु० के मूल्य तक के सर्टिफिकेट ले सकता है। पंच और सप्तवर्षीय सर्टिफिकेट कभी भी भनाये जा सकते हैं, परन्तु बारह वर्षीय सर्टिफिकेट केवल एक निर्धारित अवधि के बीत जाने पर ही भनाये जा सकते हैं ।

पोस्टल जीवन-बीमा

1 जनवरी, 1949 से सेना-विभाग के कर्मचारियो को पोस्टल जीवन बीमा फड से लाभ उठाने की सुविधा दी गई । इस योजना को उन औद्योगिक कार्यों के कर्मचारियो पर भी लागू करने का प्रस्ताव है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, अथवा जिन मे सरकार का बडा भाग है ।

देशीय तार

भारत, वर्मा, श्रीलका, या पाकिस्तान स्थित स्थानो को या उन स्थानो से भेजे गये तार देशीय तारो के वर्ग मे आते है । देशीय तारों पर निम्नलिखित दरो के अनुसार महसूल लिया जाता है :

भारत में प्राप्ति

	एक्सप्रेस			साधारण		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
न्यूनतम शुल्क (8 शब्दो तक के लिये) . .	1	8	0	0	12	0
8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द पर .	0	2	0	0	1	0

बर्मा और पाकिस्तान में प्राप्ति

	एक्सप्रेस			साधारण		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
न्यूनतम शुल्क (8 शब्दों के लिये) . .	2	12	0	1	6	0
8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द पर . .	0	4	0	0	2	0

प्रेस तार भारत में प्राप्ति

न्यूनतम शुल्क (50 शब्दो तक के लिये) .	1	8	0	0	12	0
50 से ऊपर प्रति अतिरिक्त 5 शब्दों पर .	0	2	0	0	1	0

बधाई के तार

उत्सवो के अवसर पर बधाई के तार, भारत के किसी भी तार घर से भारत के किसी भी तार-घर को, विशेषरूप से घटाई गई दरो पर भेजे जा सकते है :

शब्दो की सख्या :

(क) प्राप्त करने वाले का नाम व पता .	4 शब्द
(ख) बधाई (एक विशेष अंक द्वारा इगित) .	1 शब्द
(ग) भेजने वाले का नाम . . .	1 शब्द
	6 शब्द

	एक्सप्रेस			साधारण		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
इन 6 शब्दो के लिये	1	0	0	0	8	0
6 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द के लिये .	0	2	0	0	1	0

स्थानीय तार

भारत के समस्त तार-घरो और डाक-प्राप्त करने वाले कार्यालयो मे स्थानीय तार भेजने की व्यवस्था है जिस के लिये न्यूनतम शुल्क 6 आना है (8 या उस से कम शब्दो के लिये) और 8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द के लिए 6 पाई शुल्क देना होता है ।

फ्लैश तार

प्रेस की सुविधा के लिये 15 अगस्त, 1947 से एक नये प्रकार के तार चलाये गये जिन्हे "फ्लैश समाचार" कहा जाता है । यद्यपि इस तार के लिये उसी दर से शुल्क देना पडता है जो वैयक्तिक एक्सप्रेस तार के लिये है तथापि इसे उस से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त होती है । फ्लैश तारो के लिए टेलिफोन द्वारा भेजने की भी सुविधा उपलब्ध है ।

जीवन-संकट तार

ये तार दुर्घटना, गम्भीर रुग्णावस्था, अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर भेजे जा सकते है और इन पर देशीय एक्सप्रेस तारो की दर पर शुल्क लगाया जाता है । इस प्रकार के तारो को अन्य सभी अर्जेन्ट और एक्सप्रेस तारों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है ।

अठारहवा अध्याय

सहकारी आन्दोलन

सहकारी आन्दोलन सर्वत्र जनता का आन्दोलन है । यदि जनता जोश के साथ इस मे हाथ बटाये, तभी यह आन्दोलन सफल हो सकता है । यद्यपि सविधान के अनुसार यह राज्य सरकार के विषय के अन्तर्गत रक्खा गया है और यद्यपि प्रत्येक राज्य सरकार इस सम्बन्ध मे यथा साध्य कर रही है, फिर भी इसका कार्य बहुत कुछ परामर्श देने तक ही सीमित है, और जनता ही इसे सफल बना सकती है ।

1950–51 के अन्त मे सब तरह की सहकारी समितियो की सख्या 1,81,189 थी, जब कि 1949–50 के अन्त मे उन की सख्या 1,73,094 थी । इसी युग मे प्राथमिक समितियो की सदस्य सख्या 1 करोड 26 लाख से 1 करोड 37 लाख हो गयी । यदि मोटे तौर पर यह मान लिया जाये कि एक भारतीय परिवार मे औसत रूप मे 5 व्यक्ति आते है, तो यह कहा जा सकता है कि 1950-51 मे 6 करोड 85 लाख यानी सारी जनता का 19.1 प्रतिशत सहकारी आन्दोलन से लाभ उठा रहा था । जब कि 1949–50 मे केवल 18.2 प्रतिशत लोग ही इस का फायदा उठा रहे थे । इस सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिये कि कई व्यक्ति एक से अधिक सहकारी समिति के सदस्य हो सकते है इसलिये इस आकडे का प्रयोग समझ बूझ कर ही किया जा सकता है ।

सब तरफ की सहकारी समितियो की कुल पूजी 1949–50 के अत मे 233 करोड 10 लाख रुपये और 1951 की 30 जून को 275 करोड 85 लाख पये थी । इसमे से 40 8 प्रतिशत जमा रकमे थी । मिल्कियत कोष कार्यशील पूजी के 29 प्रतिशत और कुल जमा धन के 71 प्रतिशत थे ।

नीचे की तालिका मे प्राथमिक समितियो के ऋण सम्बन्धी आदान प्रदान की प्रगति देखी जा सकती है :

तालिका 126

(करोड पयो मे)

	1948–49	1949–50	1950-51
प्राथमिक समितियो द्वारा दिया गया ऋण	60 06	70 56	86 57
चुका दिये गये ऋण .	50.56	59 45	72 66
बकाया ऋण . .	61 84	71.37	83 86
30 जून को ऐसे ऋण जिन्हे चुकाने का समय निकले बहुत दिन हो चुके थे .	7.80	8.91	9 78

रिजर्व बैंक, राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों से बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण प्राथमिक समितियो के द्वारा दिये जाने वाले कर्जों मे बहुत वृद्धि हुई है । यह वृद्धि मुख्यत:

"क" भाग के राज्यो में हुई। उन राज्यो मे कर्ज 60 करोड 88 लाख रुपये से 72 करोड़ 8 लाख रुपये हो गया। "ख" भाग के राज्यो मे इसी प्रकार कर्ज 10 करोड 49 लाख रुपये से बढ़कर 11 करोड 78 लाख रुपये पहुच गया। भुगतान के योग्य पुराने कर्ज घटते हुए मालूम हुए। 1948-49 में इन का परिमाण 12 6 प्रतिशत, 1949-50 मे 12.5 प्रतिशत और 1950-51 मे 11.7 प्रतिशत रहा।

अल्पकालीन कर्ज

1949-50 की तुलना में 1950-51 में भुगतान किये हुए कर्जों में और मौजूदा कर्ज मे वृद्धि हुई। कुछ भी हो विभिन्न किस्म की सहकारी समितियो के यहां जो रकम जमा हुई है उन मे आनुपातिक दृष्टि से कोई वृद्धि नही हुई। इस का नतीजा यह रहा कि केन्द्रीय वित्तीय सस्थाओ पर ही निर्भर करना पड़ा।

तालिका 127

(करोड रुपयो में)

	शिखर बैंक		केन्द्रीय बैंक		प्राथमिक कृषि-ऋण समितिया	
	1949-50	1950-51	1949-50	1950-51	1949-50	1950-51
सख्या	14	15	498	505	1,16,534	1,15,462
सदस्य सख्या	18,618	20,932	1,89,722	2,07,074	48,17,545	51,53,907
वर्ष पर्यन्त दिया गया कुल ऋण	29 6	42 1	75 4	82 8	18 0	22 9
वर्ष पर्यन्त चुका दिया गया कुल ऋण	31.6	38 2	76 2	77 2	13 5	18 3
बकाया ऋण	14 1	17 9	28 9	34 1	25 0	29.1
लगायी गयी पूजी	11.6	11 4	13 1	14 1	1.0	1.2
स्वामित्व प्राप्त निधि	3.4	3 8	8.1	8 8	15.3	17.3
जमा किया गया धन	21.2	22.1	35 0	37.8	4 1	4.5
अन्य उधार	5.9	8.5	6.8	9.7	15.8	19.2
कार्यकारी पूंजी	30.5	34.4	49.9	56.4	35.2	41.0

सहकारी बैंक

केन्द्रीय बैंक

1950-51 में केन्द्रीय बैंकों की सख्या जिस मे बैंकिग यूनियन भी सम्मिलित है, 498 से बढ़ कर 505 हो गयी। उसी युग में उन के सदस्यो की सख्या 1,89,722 से बढ़कर 2,07,074 हो गयी और शेयर पूंजी तथा रिजर्व क्रमशः चार करोड़ चार लाख रुप` और 4 करोड़ 79 लाख रुपये हो गया।

केन्द्रीय बैंको की कार्यकारी पूजी (56 करोड 37 लाख रुपये) की बनावट का अध्ययन करने से यह पता लगा है कि शिखर तथा अन्य सस्थाओ से कर्ज लिये हुए कोष पर निर्भरता अधिक है, जैसा कि नीचे के आकडो से स्पष्ट है :

तालिका 128

	कार्यकारी पूजी का प्रतिशत	
	1949-50	1950-51
स्वामित्व प्राप्त (ओन्ड) निधि .	16 2	15 7
जमा किया गया धन .	70.2	67 0
अन्य उधार . .	13 6	17 3

केन्द्रीय बैंको ने 1950-51 मे व्यक्तियो, बैंको तथा समितियो को 82 करोड़ 84 लाख रुपये दिये, जब कि 1949-50 मे 75 करोड 44 लाख रुपये दिये गये थे । केवल बम्बई मे व्यक्ति और समितियो के मद मे 3 करोड 50 लाख रुपये की वृद्धि हुई ।

सरकारी कागजो (सिक्युरिटी) तथा इस प्रकार के अन्य कागजो मे केन्द्रीय बैंको की जो पूंजी लगी हुई थी (यह कर्ज का जिकर नही है) वह 14 करोड 13 लाख रुपये की है ।

राज्य बैंक

विन्ध्य प्रदेश मे शिखर बैंक की स्थापना के साथ साथ राज्य बैंकों की सख्या 1950-51 मे बढ कर 15 हो गयी । सदस्यो की सख्या में भी कुछ वृद्धि हुई । उस साल सदस्यो में 8,266 व्यक्ति तथा 12,666 बैंक और समितिया थी । 1949-50 के अन्त मे शेयर पूंजी और रिजर्व क्रमश. 1 करोड़ 58 लाख रुपये तथा 2 करोड 22 लाख रुपये हो गयी । शिखर बैंको ने जो पूजी पेशगी दी थी उस का परिमाण 42 करोड 13 लाख रु० था जिस मे से सहकारी बैंक और समितियो को 34 करोड 40 लाख रुपये यानी कुल 82 प्रतिशत पूजी मिली ।

शिखर सस्थाओ ने धन की बढती हुई माग को अधिक कर्ज लेकर पूरा किया । 1949-50 में लिये हुए कर्ज की रकम जो 5 करोड 31 लाख रु० थी, वह अब 8 करोड 34 लाख रुपये हो गयी । जमा धन राशि मे थोडी सी वृद्धि हुई, यानी यह 21 करोड 17 लाख रुपये से 22 करोड़ 7 लाख रुपये मे पहुच गयी ।

बैंक की कुल लागते करीब करीब अपरिवर्तित रूप से 11 करोड 42 लाख रुपये बनी रही । सरकारी कागजो मे लगी हुई पूंजी सब से अधिक थी यानी 10 करोड 74 लाख रुपये थी । बाकी पूंजी जमीन, इमारतो तथा सहकारी संस्थाओ के शेयरो मे लगी रही ।

कृषि समितियां

कर्ज समितियां

1949-50 की तुलना मे कर्ज समितियों की संख्या 1,072 से घट कर 1,15,462 रह गयी । कुल मिलाकर "क" भाग के राज्यो की समितियों की संख्या मे कुछ वृद्धि हुई, पर

"ख" और "ग" भाग के राज्यो की समितियो की सख्या मे 1,925 की कमी हुई । यद्यपि इसी प्रकार समितियो की सख्या तो घट गयी, पर इनके सदस्यो की सख्या 3,36,362 बढ कर 51,53,907 पहुच गयी ।

1950-51 मे समितियो ने अपने सदस्यो को जो कर्ज दिया, उस का परिमाण 22 करोड 90 लाख रुपये था । जब कि 1949-50 मे इसी का परिमाण केवल 18 करोड रुपये ही था । इसी प्रकार 1950-51 के अन्त मे भुगतान लायक पुराने कर्ज 29 करोड 12 लाख रुपये था, जब कि इस के पहले साल यह कुल 24 करोड 96 लाख रुपये ही था । 6 करोड 38 लाख रुपये की बीतकाल दिये हुए कर्ज की रकम 22 प्रतिशत थी, जब कि 1949-50 मे बीतकाल दिये हुए कर्ज की रकम 21.5 प्रतिशत थी ।

कर्ज समितिया अपनी कार्यकारी पूजी के लिये मुख्यत केन्द्रीय वित्तीय जरिये पर निर्भर रहती है । इस प्रकार 1950-51 मे स्थिति यह थी कि उन की कार्यकारी पूजी का 47 प्रतिशत कर्ज से प्राप्त था । (अपना कोष) ओड फंड 17 करोड 26 लाख रुपये का था, यानी कार्यकारी पूजी का 42 प्रतिशत था, जब कि जमा की कुल रकम 4 करोड 48 लाख रुपये थी । युद्ध के बाद के युग मे कार्यकारी पूजी के मुकाबले मे जमा का अनुपात बराबर गिरता गया । उदाहरणस्वरूप 1946-47 मे यह अनुपात 14.4 था, 1950-51 मे यह घटकर 10 प्रतिशत हो गया । इस से यह ज्ञात होता है कि अल्पकालीन ऋण की खेती के लिये कर्ज की व्यवस्था का वृहत्तर भाग बढता रहा, पर उसी अनुपात मे यह बडी रकम को आकर्षित नही कर सका । सहकारी आन्दोलन को अपने पैरो पर खडा करने के लिये यह जरूरी है कि अधिक से अधिक रकम आकृष्ट करने के लिये बराबर प्रयत्न किया जाये । निम्नलिखित आकडो से औसत सदस्य सख्या, शेयर पूंजी तथा जमा की रकम ज्ञात होती है—

औसत सदस्य . . .		45
प्रति समिति औसत शेयर पूजी	लगभग	727 रुपये
प्रति सदस्य औसत शेयर पूजी .	लगभग	16 रुपये
प्रति समिति लगभग जमा रकम	लगभग	388 रुपये
प्रति सदस्य औसत जमा रकम . .	लगभग	9 रुपये

प्रति समिति औसत कार्यकारी पूजी बम्बई मे सब से अधिक थी (11,065 रुपये) इस के बाद कुर्ग का नम्बर आता है (7,991 रुपये) फिर मद्रास आता है (7,398 रुपये)। पेप्सू, बम्बई, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, और पजाब मे प्रति सदस्य पर औसत कार्यकारी पूंजी अधिक थी जो क्रमश इस प्रकार थी, 152 रु०, 148 रु०, 119 रु० 116 रु० और 111 रु० ।

सहकारी आन्दोलन का एक मुख्य उद्देश्य शुरू से यह रहा कि खेतिहरो को कम सूद पर खेती के लिये कर्ज मिले, इतना कम सूद जितना कि वे दे सकते है । इस दिशा मे बहुत सीमित सफलता हुई है । खेतिहरों को अब भी सूद अधिक देना पड़ रहा है । कई क्षेत्रो मे तो उन्हे 12.5 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश और बिहार मे तो 15 प्रतिशत तक देना पड रहा है ।

गैर-कर्ज समितियां

1950 की 30 जून को राज्यीय गैर-कर्ज समितियों की सख्या 22 थी । पर 1950-51 के अन्त मे यह संख्या बढ़ कर 35 हो गयी । इन सस्थाओं की कार्यकारी पूंजी 8 करोड 74 लाख

रुपये थी, और यह मालिक तथा ऐजेन्टों के रूप में 21 करोड 32 लाख रुपये का माल बेच लेते थे ।

गैर कर्ज ढाचों मे इस के बाद ही गैर कर्ज समितियो का नम्बर आता है, जिन की संख्या 2,201 है। इनमे से 1,860 उत्तर प्रदेश में ही है। 14,06,907 व्यक्ति तथा 46,228 समितियां इन की सदस्य थी। उन की कार्यकारी पूंजी 1951 के 30 जून को 12 करोड़ 45 लाख रुपये थी और उन्होने 86 करोड 7 लाख रुपये का माल बेचा जब कि 1949-50 मे उन्होने 53 करोड़ 34 लाख रुपये का ही माल बेचा था।

1950 की 30 जून को प्राथमिक समितियो की सख्या 25,860 थी, पर 1950-51 के अन्त मे उनकी सख्या 33,815 हो गई। इन की कार्यकारी पूजी 13 करोड़ 14 लाख रुपये से बढ़ कर 16 करोड़ 54 लाख रुपये हो गयी और 1949-50 मे जहा उन को केवल 55 लाख रुपये का लाभ हुआ था अब उन्हे 65 लाख 35 हजार रुपये का लाभ हुआ।

भूमि बन्धक बेंक

यद्यपि ऐसे बैंको की सख्या पांच ही बनी रही, पर इन के द्वारा दिये गये कर्ज की रकम जहा 1949-50 मे 1 करोड 1 लाख रुपये थी वहा 1950-51 में यह रकम 1 करोड 33 लाख रुपये हो गयी। इस में से 83 लाख रुपये यानी कर्ज का लगभग 62 प्रतिशत मद्रास, केन्द्रीय भूमि बन्धक बेक के द्वारा दिया गया। देय कर्ज का परिमाण 5 करोड 12 लाख रुपये से 5 करोड 98 लाख रुपये हो गया। देय ऋण पत्रों का परिमाण 5 करोड 82 लाख रुपये से 6 करोड 74 लाख रुपये हो गया। इस मे से केवल मद्रास वाली रकम 5 करोड रुपये से कुछ ऊपर है।

अकृषि समितिया

कर्ज समितियां

1950-51 के अन्त मे भारत मे 7,810 प्राथमिक अकृषि कर्ज समितिया थी जबकि इस के पहले साल इन की सख्या 7,534 थी। इस की कार्यकारी पूंजी बढकर 56 करोड 78 लाख रुपये हो गयी और दिए हुए कर्ज का परिमाण 47 करोड 29 लाख रुपये हो गया। उनकी कार्यकारी पूंजी की बनावट इस प्रकार थी—

	कुल का प्रतिशत
अपना कोष (ओड फड)	30.8
जमा	61.8
कर्जे	7.4
योग	100.0

गैर-कर्ज समितियां

1950-51 के अन्त में 20,518 ऐसी समितियां थीं जिन के 28,03,256 सदस्य थे, और जिन की कार्यकारी पूंजी 35 करोड़ 22 लाख रुपये थी। 1949-50 की तुलना में ये आंकड़े उन्नति के सूचक है क्योंकि उस साल 19,739 समितिया थी जिन के सदस्य 25,49,494 और पूंजी 26 करोड़ 70 लाख रुपये थी। इन समितियों को मालिक अथवा

एजेन्ट के रूप में क्रमश 90 करोड 77 लाख रुपये और 2 करोड 67 लाख रुपयों का माल प्राप्त हुआ । विभिन्न किस्मों की सहकारी समितियों के शुद्ध लाभ इस प्रकार थे :

तालिका 129

(लाख रुपयों में)

	1949-50	1950-51
राज्य और केन्द्रीय बैंक	66 10	70 62
राज्य और केन्द्र की ऋण न देने वाली समितियां	57.50	119 94
कृषि ऋण समितियां	74 75	87 72
ऋण न देने वाली कृषि समितियां	55 04	65 36
अ-कृषि ऋण समितियां	83 60	104 04
ऋण न देने वाली अ-कृषि समितियां	60 89	242 57
भूमि बन्धक बैंक और समितियां	6 67	7 04
योग	404 55	697.29

ऊपर के आंकडों से ज्ञात होता है कि देश में सहकारी आन्दोलन कहीं अधिक फैल रहा है तथा कहीं कम । इसके साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि कहीं इसका रूप कुछ है और कहीं कुछ और । "क" भाग के राज्यों के आन्दोलन यथेष्ट फैले हुए है, फिर भी ये दूसरे स्थानों में कम फैले है, और "ख" तथा "ग" भाग के राज्यों में करीब करीब अविकसित है । सच तो यह है कि भारत में इस समय जो 1,15,462 खेती सम्बन्धी प्राथमिक कर्ज समितियां है, उनमे केवल मद्रास, उत्तर प्रदेश और बम्बई में ही 52,422 समितियां यानी कुल का 45 4 प्रतिशत है ।

जमींदारी प्रथा के हटा दिये जाने से तो खेती करने वालों के लिये वित्त के वैकल्पिक साधन लुप्त हो जाने से सहकारी आन्दोलन की जिम्मेदारी बहुत बढ गई है । पंचवर्षीय योजना में खेती वाले कर्जों के सम्बन्ध में कुछ लक्ष्य नियत किया गया है, जैसे अल्पकालीन कर्जों के लिये प्रति वर्ष 100 करोड रुपये, मध्यकालीन कर्जों के लिये प्रति वर्ष 25 करोड रुपये और दीर्घकालीन कर्जों के लिये प्रति वर्ष 5 करोड रुपये लक्ष्य रक्खा गया है । इस का अर्थ यह है कि यह आन्दोलन बढेगा, तभी कार्य बढेगा । बढ यह तभी सकता है जब कि इस सगठन का दायरा और कार्यकुशलता बढे ।

आंकडे : एक दृष्टि मे

	1949-50	1950-51
समितियो की कुल सख्या	1,73,094	1,81,189
प्राथमिक समितियो की सदस्य सख्या	1,25,61,016	1,37,15,020

	1949-50	1950-51
सब प्रकार की समितियों की कार्यकारी पूंजी . . .	2,33,10,28,870 रु०	2,75,85,23,956 रु०
प्राथमिक समितियों द्वारा दिया गया ऋण	70,56,08,272 रु०	86,56,58,475 रु०
सब प्रकार की समितियों द्वारा अर्जित लाभ	4,04,54,307 रु०	6,97,29,650 रु०
प्रान्तीय बैंक		
सख्या . . .	14	15
सदस्यों की सख्या . .	18,618	20,932
दिया गया ऋण . .	29,57,73,390 रु०	42,13,30,561 रु०
कार्यकारी पूजी . . .	30,45,42,441 रु०	34,42,07,198 रु०
केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिंग यूनियन		
सख्या . . .	498	505
सदस्य सख्या . . .	1,89,722	2,07,074
दिया गया ऋण . . .	75,43,47,929 रु०	82,84,04,052 रु०
कार्यकारी पूजी . . .	49,87,34,416 रु०	56,36,76,766 रु०
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां		
सख्या . . .	1,16,534	1,15,462
सदस्य सख्या . . .	48,17,545	51,53,907
दिया गया ऋण . . .	17,98,68,995 रु०	22,89,71,810 रु०
कार्यकारी पूजी . . .	35,21,75,427 रु०	40,95,77,395 रु०
प्राथमिक अ-कृषि समितियां		
सख्या . . .	7,534	7,810
सदस्य संख्या . . .	20,65,990	21,77,551
दिया गया ऋण . . .	38,71,57,342 रु०	47,29,02,608 रु०
कार्यकारी पूंजी . . .	51,60,24,194 रु०	56,78,02,055 रु०
अ-ऋण प्रान्तीय समितियां		
संख्या . . .	22	35
सदस्य संख्या . . .	9,364	20,068
प्राप्त माल का मूल्य . .	8,26,62,628 रु०	21,29,10,083 रु०
विक्रय किये माल का मूल्य . .	11,51,48,865 रु०	21,32,05,330 रु०
कार्यकारी पूंजी . . .	2,09,56,530 रु०	8,74,63,865 रु०

	1949-50	1950-51
अ-ऋण केन्द्रीय समितियां		
सख्या . . .	2,091	2,201
सदस्य सख्या . .	13,37,738	14,53,135
प्राप्त माल का मूल्य . .	44,92,81,935 रु०	84,29,55,169 रु०
विक्रय किये माल का मूल्य . .	53,34,55,767 रु०	86,07,01,253 रु०
कार्यकारी पूजी . .	11,27,68,745 रु०	12,44,67,042 रु०
अ-ऋण प्राथमिक कृषि समितियां		
सख्या . . .	25,860	33,815
सदस्य सख्या . . .	29,41,157	33,65,243
प्राप्त माल का मूल्य . .	46,80,65,548 रु०	52,12,48,666 रु०
विक्रय किये माल का मूल्य . .	48,60,64,453 रु०	55,00,25,115 रु०
कार्यकारी पूजी . . .	13,14,48,329 रु०	16,53,82,046 रु०
प्राथमिक अ-ऋण अ-कृषि समितियां		
सख्या . . .	19,739	20,518
सदस्य संख्या . . .	25,49,494	28,03,256
प्राप्त माल का मूल्य . .	71,91,20,296 रु०	93,43,82,356 रु०
विक्रय किये माल का मूल्य .	76,57,41,180 रु०	1,00,81,50,776 रु०
कार्यकारी पूजी . . .	26,70,75,761 रु०	35,21,68,399 रु०
केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक		
सख्या . . .	5	5
सदस्य सख्या . . .	8,871	9,848
दिया गया ऋण . . .	1,01,08,270 रु०	1,32,92,943 रु०
कार्यकारी पूजी . . .	6,86,93,711 रु०	7,72,06,284 रु०
प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक		
सख्या . . .	283	286
सदस्य सख्या . . .	1,86,330	2,15,063
दिया गया ऋण . . .	1,01,10,789 रु०	1,29,01,950 रु०
कार्यकारी पूजी . . .	5,86,09,316 रु०	6,65,72,906 रु०

तालिका 130

सहकारी समितियां, सदस्य और कार्यकारी पूंजी

राज्य वार (1950–51)

राज्य	जनसंख्या (10 लाख में) (क)	समितियों की कुल संख्या	प्रति लाख व्यक्ति पर समितियों की संख्या	प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या	प्रति 1000 व्यक्ति पर प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या	कार्यकारी पूंजी: योग	कार्यकारी पूंजी: प्रति व्यक्ति पीछे आना की संख्या
भाग 'क' के राज्य							
मद्रास	57.0	24,205	42.5	33,82,495	59.3	85,32,44,721	235.0
बम्बई	35.9	16,076	44.8	22,43,577	62.5	82,97,10,922	369.8
पश्चिमी बंगाल	24.8	15,441	62.3	9,38,012	37.8	17,78,41,121	114.7
उत्तर प्रदेश	63.2	36,211	57.3	17,05,553	27.0	23,03,43,170	58.2
मध्य प्रदेश	21.2	10,202	48.1	4,19,714	19.8	9,72,56,089	73.3
पंजाब	15.3	14,052	91.8	7,42,922	48.6	12,52,50,472	130.9
बिहार	40.2	14,548	36.2	6,35,846	15.8	5,20,40,534	20.6
उड़ीसा	14.6	5,145	35.2	2,82,596	19.4	4,27,46,014	46.6
आसाम	9.0	2,929	32.5	2,83,960	31.6	1,95,61,196	34.7
योग	281.2	1,38,809	49.4	1,06,34,675	37.8	2,42,79,94,239	138.1
भाग ख, ग, और घ के राज्य (ख)							
मैसूर	9.1	5,190	57.0	4,94,822	54.4	6,90,90,904	121.4
हैदराबाद	18.6	15,077	81.1	14,56,478	78.3	10,13,28,235	87.0
मध्यभारत	7.9	6,601	83.6	1,77,036	22.4	4,13,78,831	83.7
राजस्थान	15.3	3,151	20.6	1,40,735	92.0	2,28,69,833	23.8
तिरुवांकुर-कोचीन	9.3	2,631	28.3	3,53,345	38.0	2,65,24,859	45.6
पेप्सू	3.5	1,453	41.5	42,732	12.2	1,54,64,963	70.1
जम्मू और कश्मीर (ग)	—	3,288	—	1,69,548	—	1,38,56,924	—
सौराष्ट्र	4.1	767	18.7	41,347	10.1	51,21,432	19.8
अजमेर	0.7	967	138.1	33,597	48.0	82,09,297	187.5
भोपाल	0.8	265	33.1	10,863	13.6	14,22,425	28.3
दिल्ली	1.7	983	57.8	60,267	35.5	1,57,90,316	148.4
कुर्ग	0.2	356	178.0	48,255	241.2	58,42,339	476.4
हिमाचल प्रदेश	1.0	843	84.3	23,982	24.0	21,36,783	34.1
विन्ध्य प्रदेश	3.6	464	12.9	10,682	30.2	3,93,628	1.8
मणिपुर	0.6	328	54.7	15,369	25.6	7,08,629	18.9
त्रिपुरा	0.6	9	1.5	653	1.1	1,54,650	4.0
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	0.03	7	—	634	21.1	2,35,669	125.6
योग	77.03	42,380	55.0	30,80,345	40.0	33,05,29,717	68.6
सर्व योग	358.23	1,81,189	50.6	1,37,15,020	38.3	2,75,85,23,956	123.2

(क) जन-संख्या के आंकड़े भारत की जनगणना पेपर नं० 1 1952 में से लिये गये हैं।

(ख) बिलासपुर और कच्छ में सहकारी समितियां नहीं हैं।

(ग) जम्मू और काश्मीर में वहां की परिस्थिति विशेष के कारण जन-गणना नहीं की गयी।

उन्नीसवां अध्याय

शिक्षा

1947 मे शिक्षा विभाग केन्द्र का एक पूर्णावियव मंत्रालय बन गया। राज्य शिक्षा सम्बन्धी मामलो मे स्वतत्र है और उन पर जनता की शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। केन्द्र का काम यह है कि वह शिक्षा के मामले मे राष्ट्रीय मान-दण्ड कायम रखने मे सहायता करे तथा यह देखरेख रक्खे कि शिक्षा का चरित्र राष्ट्रीय रहता है।

भारत सरकार "ग" भाग के राज्य तथा "घ" भाग के भूभागो की शिक्षा के लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अजमेर, कुर्ग, दिल्ली अन्दमान और निकोबार द्वीप पुज सविधान के लागू होने के पहले केन्द्र के द्वारा प्रशासित थे। केन्द्रीय सरकार कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और भोपाल की शिक्षा के लिये भी जिम्मेदार है।

सरकार को इस सम्बन्ध मे जो अधिकार प्राप्त है, वे आशिक रूप से विश्वविद्यालयो, सैकेन्ड्री तथा इटर शिक्षा बोर्डों, जिला बोर्डों तथा कुछ परोपकारी और धार्मिक संस्थाओ मे बटे हुए है। नीचे की तालिका मे देश की स्वीकृत शिक्षा सस्थाओ के सम्बन्ध मे सूचनाए है। यह आकडे 1951-52 के है (क)

तालिका 131

सस्था का रूप	सस्थाओ की संख्या	छात्र सख्या (हजारो मे)	व्यय (लाख रुपयो मे)
वश्वविद्यालय	30	26	4,66
माध्यमिक और इटरमीजियेट शिक्षा बोर्ड	12	—	75 (ख)
कला और विज्ञान कालेज (ग)	579	3,47	8,33
धंधों की शिक्षा तथा विशेष शिक्षा देने वाले कालेज	311	71	5,20
माध्यमिक पाठशालाए	22,500	56,48	33,40
प्रारम्भिक पाठशालाएं	2,14,862	1,89,01	40,15
प्राक प्रारम्भिक पाठशालाएं	331	23	15
व्यावासयिक तथा विशेष शिक्षा देने वाली पाठशालाएं	51,999	14,84	5,44
योग	2,90,264	2,65,00	98,08 (घ)

(क) संस्थाएं अस्थायी है।

(ख) इस में उन पांच बोर्डों पर हुआ व्यय सम्मिलित नही है जिन पर व्यय परोक्ष व्यय के अन्तर्गत ले लिया गया है।

(ग) इस मे शोध संस्थाएं भी सम्मिलित है।

(घ) इसमें 23.52 करोड़ रुपये का परोक्ष व्यय सम्मिलित नही है।

सार्जेन्ट योजना

1944 मे केन्द्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना बनाई। इस योजना को आमतौर से सार्जेन्ट योजना कहा जाता है। इस योजना मे 6 से 14 साल की उम्र के बच्चो और बच्चियो की सार्वजनिक अनिवार्य नि.शुल्क शिक्षा के सम्बन्ध मे सुझाव रक्खे गये थे। प्राथमिक विद्यालयो मे निम्न तथा उच्च नई तालीम के स्कूल आ जाते हैं। इस योजना में 11 से लेकर 17 साल तक के बच्चो के लिये एक छः साला पाठयक्रम भी आ गया था। हाई स्कूल या उच्च विद्यालयो के सम्बन्ध मे तय किया गया था कि वे दो विभिन्न किस्मो के होंगे, यानी एक तो विद्यापीठ ढग के और दूसरे प्रौद्योगिक या व्यवसायिक। इस योजना मे यह कहा गया था कि इटर पाठ्यक्रम का उच्छेदन कर दिया जाये और उच्च विद्यालय की अवधि मे एक साल तथा कालेज की अवधि मे एक साल और जोड़ा जाये। सार्जेन्ट योजना के अनुसार सारे देश के लिये एक चालीस साला शिक्षा सम्बन्धी रचनात्मक योजना बनाने की बात कही गयी थी। इन सुझावो पर खेर समिति ने विचार किया, और उस ने ऐसे उपाय बताये जिस से कि यही काम 16 साल के अन्दर पूरा हो सकता था। मोटे तौर पर भारत सरकार ने इस योजना को स्वीकार किया है।

सब से पहले दिल्ली के हायर सैकेन्ड्री एजूकेशन बोर्ड ने इटरमीडियेट कोर्स समाप्त कर दिया, और स्कूल के दोयम सोपान मे एक साल जोड दिया। अब इसे हायर सैकेन्ड्री कहते है। बाकी एक साल डिग्री पाठ्यक्रम मे जोड दिया।

इस समय हमारे यहा शिक्षा का जो ढाचा है, वह इस प्रकार है —(1) प्राथमिक विद्यालय जिन में क्षेत्र की भाषा यानी मातृभाषा माध्यम है, (2) मिडिल स्कूल जिन मे क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी या केवल क्षेत्रीय भाषा मे शिक्षा दी जाती है, (3) सैकेन्ड्री स्कूल जिन मे मैट्रिकुलेशन यानी उस के तुल्य स्टैन्डर्ड की शिक्षा के लिये सुविधा रहती है, (4) इटर कालेज जो बोर्डों या विश्व-विद्यालयो के अन्तर्भुक्त है, (5) डिग्री कालेज जो विश्व-विद्यालयो के अधीन है, और (6) स्नातकोत्तर या शोध सस्थाए।

प्राथमिक शिक्षा

कुछ राज्यो मे विविध प्रकार के नर्सरी स्कूल या शिशु विद्यालय हैं। इन की सख्या बहुत कम है। कुछ ऐसे विद्यालयों को निजी सस्थाए चलाती हैं। कुछ विद्यालय ईसाई मिशनो के द्वारा चलाये जाते हैं। इस क्षेत्र मे बहुत विस्तार की गुंजाइश है, परन्तु प्रशिक्षित शिक्षको की कमी होने के कारण शिशु विद्यालयो का बडे पैमाने पर विस्तार सम्भव नही है। प्रत्येक राज्य मे शिशु विद्यालय अलग अलग ढंग से चलाये जाते हैं। किसी राज्य मे तीन से पाच साल तक की उम्र के बच्चे शिशु विद्यालय मे ले लिये जाते है, पर दूसरो मे सात साल के बच्चे ही लिये जाते हैं। 1950–51 में हिसाब लगा कर देखा गया था कि ऐसे शिशु विद्यालयो की सख्या लगभग 300 है।

प्राथमिक शिक्षा चार से छ साल तक के लिये है। हमारे देश की जनता का बहुत बड़ा भाग गाव मे रहता है, इस कारण अधिकांश प्राथमिक विद्यालय गावो मे हैं। 1949–50 मे यह हिसाब लगाया गया था कि कुल 2,07,354 प्राथमिक शिशु विद्यालयो मे से 1,65,056 प्राथमिक विद्यालय देहातों में अवस्थित हैं। गाव के प्राथमिक विद्यालयो के सम्बन्ध मे एक बत

यह भी बता देने योग्य है कि गावो के प्राथमिक विद्यालयो मे से आधो मे केवल एक ही शिक्षक होता है।

जूनियर बेसिक शिक्षा

शिक्षा के केन्द्रीय परामर्श बोर्ड ने यह सुझाव रक्खा है कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम 8 साल तक बेसिक शिक्षा दी जाये, जिस मे से जूनियर बेसिक शिक्षा के प्रथम सोपान मे पाच वर्ष लगेगे। मद्रास सरकार ने बेसिक शिक्षा का रूप और भी विस्तृत इस प्रकार कर दिया है कि उन्होने आरम्भिक शिक्षा की एक नयी पद्धति चलाई है। भारत सरकार ने राज्य सरकारो को यह परामर्श दिया है कि 6 से 11 साल के बीच के बच्चो मे अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा के लिये जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करे और ऐसा जातपात, धर्म और सामाजिक स्थिति का ख्याल न रख कर किया जाये। इस शिक्षा पद्धति की आधारभूत बात यह है कि शिक्षार्थी काम करता जाये, और सीखता जाये। जूनियर बेसिक स्कूलो मे पाठ्यक्रम वही है जो प्राथमिक विद्यालयो मे है, पर इन मे आधारभूत दस्तकारियो, जैसे खेती, कताई, बुनाई, फलो की रक्षा, तरकारी उत्पादन, बढईगीरी, चमडे का काम, पुस्तक सम्बन्धी काम (जिस मे कागज और कार्डबोर्ड का काम भी आ जाता है) और घरेलू शिल्प जैसे खाना पकाना, सिलाई, गृहप्रबन्ध इत्यादि पर जोर दिया जाता है। इस सम्बन्ध मे यह मान लिया गया है कि यदि बच्चा बागवानी करे, तो खेती मे उसकी रुचि होगी, यदि वह सूत काते, तो बुनाई की तरफ उस का ध्यान आयेगा, और यदि वह मिट्टी के माडल बनायेगा तो बर्तन बनाने और लकडी के काम आदि की तरफ उस का ध्यान जायेगा। यह तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकार के स्कूल केवल स्कूली इमारत से चल नही सकते। इमारत हो या न हो, स्कूल के साथ साथ बागबानी आदि के लिये दो एकड भूमि होनी चाहिये, और उस मे सिचाई की सुविधा होनी चाहिये। ऐसी आशा की जाती है कि कुछ सालों के अन्दर जितने भी प्राथमिक विद्यालय है उन सब को जूनियर बेसिक स्कूलो मे परिणित किया जा सकेगा।

बेसिक प्रशिक्षण

भारत मे जिन सस्थाओ मे बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमे ये सस्थाये विशेष रूप से उल्लेखनीय है :—सेवाग्राम का नई तालीम भवन, जामिया मिलिया दिल्ली की शिक्षक प्रशिक्षण सस्था, शान्तिनिकेतन का विद्याभवन और सर्वोदय महाविद्यालय या बिहार कम्यूनिटी कालेज। कुछ ऐसे अच्छे प्रशिक्षण विद्यालय भी है, जो निजी देखरेख मे चलाये जाते है। मद्रास का रामकृष्ण मिशन विद्यालय तथा उदयपुर का विद्याभवन ऐसे विद्यालयो मे है। इन के अलावा प्रत्येक राज्य ने अपने बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय तथा स्नातकोत्तर बेसिक प्रशिक्षण कालेज भी स्थापित किये है।

सैकेन्ड्री शिक्षा

सैकेन्ड्री विद्यालयो मे दो विभाग है। एक जूनियर और दूसरा सीनियर। जूनियर श्रेणी तक का सेकेण्ड्री स्कूल कही तो मिडिल या कही लोअर सैकेन्ड्री स्कूल कहलाता है। इस मे तीन से चार साल लगते है। साधारण रूप से मिडिल स्कूल भी दो किस्म के है। एक तो देशी भाषा मिडिल स्कूल और दूसरे आग्ल देशी भाषा मिडिल स्कूल। अब यह भेद जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है।

सीनियर बेसिक शिक्षा जूनियर बेसिक शिक्षा की पूरक है। इस के लिये निर्दिष्ट उम्र ग्यारह से चौदह साल है। सीनियर बेसिक स्कूलों में शिल्प और दस्तकारी पर जोर दिया जाता है। जूनियर बेसिक विद्यालयों के 80 प्रतिशत बच्चे सीनियर बेसिक स्कूलों में जाते हैं, जब कि बाकी 20 प्रतिशत बच्चे हाई स्कूलों के जूनियर विभागों में जाते हैं, जहां उन्हें विश्वविद्यालयों में जा कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

हाई स्कूल का सोपान

हाई स्कूल में पहले 10 साल आ जाते हैं। छात्रों में से बहुत अधिक संख्या हाई स्कूलों में से निकलकर पढ़ना छोड़ देते हैं। जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, या तो वे विश्वविद्यालयों में चले जाते हैं, या उच्च शिक्षा के किसी केन्द्र में भरती हो जाते हैं। जो छात्र हायर सैकेन्ड्री पास कर लेते हैं, वे ऐसे विश्वविद्यालयों की डिग्री की श्रेणियों में भरती हो जाते हैं जहां डिग्री के लिये तीन साल अध्ययन करना पड़ता है। कुछ राज्यों में इंटर कालेज, सैकेन्ड्री और इंटर शिक्षा बोर्डों के अधीन होते हैं, विश्वविद्यालयों के अधीन नहीं। दूसरे राज्यों में चार साल का डिग्री पाठ्यक्रम दो साल इंटर में तथा दो साल डिग्री में बंट जाता है।

सैकेन्ड्री शिक्षा आयोग

भारत सरकार ने सैकेन्ड्री शिक्षा आयोग स्थापित किया। इस के सभापति मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियर नियुक्त किये गये। इस आयोग को ये काम सौंपे गये—(क) भारत में इस समय सैकेन्ड्री शिक्षा की क्या परिस्थिति है, उसके सब पहलुओं पर जांच की जाये, और एक प्रतिवेदन दिया जाये, और (ख) इस के पुनर्गठन तथा उन्नति के लिये उपाय बताये जायें, विशेषकर (1) सैकेन्ड्री शिक्षा के उद्देश्यों, संगठन और अन्तर्गत वस्तु, (2) प्राथमिक बेसिक तथा उच्चतर शिक्षा के साथ इसका सम्बन्ध, (3) विभिन्न प्रकार के सैकेन्ड्री स्कूलों का पारस्परिक सम्बन्ध, (4) दूसरी मिली जुली समस्याओं का स्पष्टीकरण। इस जांच का उद्देश्य यह था कि सारे देश में इस समय जैसे भिन्न भिन्न सैकेन्ड्री शिक्षा पद्धति प्रचलित हैं, वैसी न रह कर उन्हें जहां तक हो सके युक्तिसंगत ढंग से एकरूप कर दिया जाये।

आयोग ने लगभग एक साल तक जांच करने के बाद 1953 के अगस्त में कुछ सुझाव दिये, जिन का सार यों है —

(1) चार या पांच साल प्राथमिक तथा जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद हाई स्कूल शुरू होगा। इस में इस प्रकार की विभिन्न बातें आ जायें जैसे भाषा, सामाजिक अध्ययन, साधारण विज्ञान और दस्तकारी। एक उच्चाधिकार-समिति पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करे। छात्र किन विषयों को ले इस सम्बन्ध में उसे सही पथ-प्रदर्शन तथा सलाह का मौका मिलना चाहिये।

(2) शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो, इस के अलावा मिडिल स्कूल में राष्ट्रभाषा तथा एक विदेशी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिये।

(3) साल में काम के दिन 200 से कम नहीं होने चाहिये, प्रति सप्ताह 35 पीरियड हों जो 45 मिनट के हों।

(4) परीक्षाओं तथा श्रेणी चढ़ाने के मामले मे विद्यालय के रिकार्डों पर विचार होना चाहिये ।

(5) प्रारम्भिक सोपान मे प्रौद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये बहुधन्धी विद्यालय खोले जाने चाहिये ।

(6) सैकेन्ड्री विद्यालय के शिक्षको तथा स्नातक शिक्षको के प्रशिक्षण के लिये अलग अलग ग्रेड होने चाहिये । शारीरिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाये ।

(7) सैकेन्ड्री शिक्षा बोर्ड, शिक्षक प्रशिक्षण-बोर्ड तथा राज्य परामर्श बोर्ड भी हो । प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य समितियो को समय समय पर मिलकर अपने कार्यों को संयुक्त करना चाहिये । निरीक्षण तथा सचालन के अधिकारी वर्ग बहुत उच्च अर्थ में विशेषज्ञ हो ।

(8) प्रत्येक स्कूल मे प्रबन्ध बोर्ड हो, जो कम्पनी विधि के अनुसार पजीकृत हो । प्रधान शिक्षक इसके पदेन सदस्य होगे ।

(9) स्कूल की ईमारते हवादार हो, और उनके साथ खेल के मैदान हो ।

(10) कृषि, उद्योग धन्धा, व्यापार, व्यवसाय, नागरिकता मे प्रशिक्षण की प्रगति की दृष्टि से केन्द्र को चाहिये कि सैकेन्ड्री शिक्षा के वित्तीय प्रबन्ध की व्यवस्था करे ।

उच्चतर शिक्षा

मैट्रिकूलेशन और इटर परीक्षाओ को पास करने के बाद छात्र कला, विज्ञान, व्यवसाय, कृषि, इंजीनियरिग, चिकित्साशास्त्र आदि की डिग्री की श्रेणियों मे भरती किये जाते है ।

बी. ए., बी. एस. सी. (प्रौद्योगिक), बी. काम., बी. एग., बी. ई., एम. बी. बी. एस., बी. टी., बी. एड., एल. एल. बी., आदि डिग्रियां विश्वविद्यालयो के विभिन्न विभागो के द्वारा दी जाती हैं । स्नातकोत्तर डिग्रियां ये है—एम. ए., एम. एस. सी., एम. काम., एम. ई., एम. डी., एम. एड. तथा एल. एल. एम. और इनसे भी ऊची शोध सम्बन्धी डिग्रियां ये है—पी. एच. डी., डी. एस. सी., डी. लिट., एल. एल. डी., इत्यादि । कुछ विश्वविद्यालय इंजीनियरिग और प्रौद्योगिक विज्ञान, व्यवसाय, शिक्षा विधिशास्त्र इत्यादि विषयों में अपने विभागों, परिषदो तथा स्नातकोत्तर शिक्षण विभागो के जरिये से उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करते है ।

विश्वविद्यालय

नाम	स्थिति	रूप	वर्ष
1. कलकत्ता .	पश्चिमी बंगाल	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।	1857
2. बम्बई .	बम्बई .	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली । (पुनस्संगठित) .	1857 1928
3. मद्रास .	मद्रास .	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली । (पुनस्संगठित) .	1857 1923

नाम	स्थिति	रूप	वर्ष
4. इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	शिक्षा देने वाली, एकात्मक और स्थानीय । (पुनस्सगठित)	1887 1922
5. बनारस	उत्तर प्रदेश	शिक्षा देने वाली और स्थानीय	1916
6. मैसूर	मैसूर	सम्बन्धित करने वाली और शिक्षा देने वाली ।	1916
7. पटना	विहार	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।	1917
8. उसमानिया	हैदराबाद	शिक्षा देने वाली तथा स्थानीय	1918
9. अलीगढ	उत्तर प्रदेश	शिक्षा देने वाली तथा स्थानीय	1920
10. लखनऊ	उत्तर प्रदेश	शिक्षा देने वाली, एकात्मक तथा स्थानीय ।	1920
11. दिल्ली	दिल्ली	शिक्षा देने वाली, एकात्मक, तथा स्थानीय ।	1922
12. नागपुर	मध्य प्रदेश	शिक्षा देने वाली ओर सम्बन्धित करने वाली ।	1923
13 आन्ध्र	आन्ध्र	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।	1926
14. आगरा	उत्तर प्रदेश	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।	1927
15. अन्नामलाई	मद्रास	शिक्षा देने वाली, एकात्मक और सम्बन्धित करने वाली ।	1929
16. तिरुवाकुर	तिरुवाकुर-कोचीन	शिक्षा देने वाली, सम्बन्धित करने वाली तथा स्थानीय ।	1937
17. उत्कल	उडीसा	सम्बन्धित करने वाली	1943
18. सागर	मध्य प्रदेश	शिक्षा देने वाली तथा सम्बन्धित करने वाली ।	1946
19 राजपुताना	राजस्थान	सम्बन्धित करने वाली तथा शिक्षा देने वाली ।	1947
20. पंजाब	पजाब	सम्बन्धित करने वाली तथा शिक्षा देने वाली ।	1947
21. गौहाटी	आसाम	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।	1948
22. पूना	बम्बई	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।	1948
23. रुड़की	उत्तर प्रदेश	शिक्षा देने वाली, एकात्मक और स्थानीय ।	1948
24. जम्मू और काश्मीर	काश्मीर	सम्बन्धित करने वाली	1948
25. बडौदा	बम्बई	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।	1949
26. कर्नाटक	बम्बई	शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।	1950
27. गुजरात	बम्बई	सम्बन्धित करने वाली	1950

नाम	स्थिति	रूप	वर्ष
28 श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे भारतीय नारी विश्वविद्यालय ।	बम्बई	सम्बन्धित करने वाली	1951
29 विश्व-भारती	पश्चिम बंगाल	शिक्षा देने वाली, एकात्मक और स्थानीय ।	1951
30 बिहार	बिहार	सम्बन्धित करने वाली	1952

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड एक परामर्श समिति के रूप में काम करता है। इसके सामने विश्वविद्यालयों की समस्यायें आती रहती हैं। यह बोर्ड विदेशों में अपनी डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं को स्वीकृत कराने के लिये प्रयास करता है। 1953 के अप्रैल में 'क' तथा 'ख' भाग के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा उपकुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय की शिक्षा के सामान्य मान-दण्ड को ऊपर उठाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर बातचीत हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी यह निर्देश दिया गया था कि अपने विशेष कर्तव्यों के अतिरिक्त वह इन सुझावों को कार्यरूप में परिणत करे। उच्चतर शिक्षा तथा शोध कार्य के विकास के लिये योजना आयोग ने तीन करोड़ तीस लाख रुपये की व्यवस्था की है।

गैर-विश्वविद्यालय संस्थायें

विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन में स्नातक बनने के पहले, स्नातक बनने तथा स्नातकोत्तर कार्य और प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं। इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। (1) ह्यूमेनिटीज, (2) वैज्ञानिक शोध, (3) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान, (4) कृषि और (5) चिकित्सा शास्त्र।

ह्यूमेनिटीज

देश भर में इस समय दस संस्थाएं हैं जिनमें शिक्षा, भारतीय अभिलेखागार, प्राच्य विद्या, इंडोलोजी या भारत-तत्व, दर्शन, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों में उच्चतर शिक्षा दी जाती है।

वैज्ञानिक शोध

इस समय देश में वैज्ञानिक संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं की संख्या 78 है। इनमें से 12 तो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जिन्हें कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च चलाती है, बाकी संस्थाएं निजी सभाओं या उद्योगपतियों के द्वारा चलाई जाती हैं।

इंजीनियरिंग विद्या और प्रौद्योगिक विज्ञान

इस समय देश भर में 14 ऐसी ऊंचे दर्जे की संस्थाएं हैं जिनमें इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक विज्ञान की सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण विषय जिनकी शिक्षा इन संस्थाओं में दी जाती है, ये हैं—

(1) वैमानिक इंजीनियरिंग, (2) आटोमोबील इंजीनियरिंग (3) रासायनिक इंजीनियरिंग (4) सिविल इंजीनियरिंग, (5) विद्युत इंजीनियरिंग, (6) विद्युत एवं यान्त्रिक

इंजीनियरिंग (सम्मिलित), (7) मार्ग निर्माण इंजीनियरिंग, (8) आतर-दहन इंजीनियरिंग, (9) यान्त्रिक इंजीनियरिंग, (10) नाविक भास्कर्य, (11) रेडियो इंजीनियरिंग, (12) टेली-संचार, (13) खनिज-विज्ञान, (14) धातु-कर्म, (15) भू-भौतिकी, (16) व्यावहारिक भौतिक विज्ञान, (17) रासायनिक प्रौद्योगिकी, (18) चलचित्र विज्ञान और ध्वनि प्रौद्योगिकी, (19) मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी और नौका-नयन, (20) चर्म प्रौद्योगिकी, (21) मुद्रण प्रौद्योगिकी, (22) शर्करा प्रौद्योगिकी, (23) वस्त्र प्रौद्योगिकी, (24) व्यावहारिक कला कौशल, (25) भास्कर्य और (26) वाणिज्य ।

कृषि

देश भर में ऐसी 13 संस्थाए है, जहा पर कृषि इत्यादि अन्य प्रयुक्त विज्ञानो के अध्ययन की सुविधाए है । यह एक बहुत ही मार्के की बात है कि चावल तथा अन्य पुष्टिकर द्रव्यो के लिये उपयुक्त एवजी तैयार करने मे बहुत प्रगति हुई है ।

चिकित्सा शास्त्र

कई विश्वविद्यालयो के साथ मैडिकल कालेज तथा चिकित्सा-शास्त्र विभाग लगे हुए है । पर इनके अलावा लिप्रसी इंस्टीच्यूट या कुष्ट संस्था तथा ट्यूबरक्लोसिस ऐसोसियशन या तपेदिक संघ ऐसी संस्थाए मौजूद है जिनमे विशेष विषयो पर अध्ययन की सुविधा है । यो तो ये संस्थाए आत्मशासित है, पर इन्हे सरकार से वित्तीय अनुदान मिलता रहता है ।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

भारत सरकार ने 1948 के नवम्बर मे डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सभापति बना कर एक आयोग नियुक्त किया कि वह विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रिपोर्ट देता हुआ उन्नति के सुझाव रक्खे । आयोग ने जो सुझाव रक्खे, वे इस प्रकार है––विश्वविद्यालय के शिक्षको के वेतन के स्केल बढा दिये जाये, छात्रो को तभी विश्वविद्यालय मे भरती किया जाये जबकि वे विश्वविद्यालय से पहले 12 साल की शिक्षा समाप्त कर चुके हो, शिक्षा का वर्ष परीक्षाओ के अतिरिक्त 180 कार्यकारी दिनो का हो, तीन टर्म हो जिनमे से प्रत्येक लगभग ग्यारह सप्ताह का हो, उच्च शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य है यानी साधारण सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा और पेशा सम्बन्धी शिक्षा । इन विषयो पर अधिक ध्यान दिया जाये––(1) कृषि, (2) व्यवसाय, (3) शिक्षा, (4) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान, (5) विधि शास्त्र और (6) चिकित्सा-शास्त्र । इस समय मौजूदा इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक विज्ञान की संस्थाए राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप मे समझी जाये और उन्हे उन्नत बनाने के लिये सब प्रकार के प्रयास किये जाये । प्रशासनीय सेवाओ के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक न समझी जाये । विभिन्न सरकारी सेवा मे भरती होने के लिये राज्य की ओर से होने वाली परीक्षाए सब प्रार्थियो के लिये खुली हो, प्रथम डिग्री के लिये प्रस्तुत करने मे तीन साल लगते है, इसलिये यह वाछनीय नही है कि इस अरसे मे किये गये सारे कार्य की जाच केवल एक परीक्षा से की जाये, जहा तक हो सके परीक्षाए कई टकडो मे हो, परीक्षा का मान-दण्ड सर्वत्र ऊचा किया जाये और सब विश्वविद्यालयो मे वह एक रूप कर दिया जाये, विश्वविद्यालय की शिक्षा सहायक (कानकरेन्ट) सूची मे रक्खी जाये ।

शिक्षा के केन्द्रीय परामर्श बोर्ड ने सामान्यत आयोग की सिफारिशो को मजूर किया, पर उन्हे कार्यरूप मे परिणत करने के लिये कुछ दिक्कते थी । इसलिये उन्हे दूर करने के लिये कानून

बनाये जा रहे है। बाकी सिफारिशें फौरन कार्यान्वित हो रही है। विश्वविद्यालय मे स्नातकोत्तर ोध को उन्नत तथा विस्तृत करने के लिये 8 विश्वविद्यालयो को लगभग साढे चार करोड रुपयों ा अनुदान दिया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा

हमारे देश मे प्रौढ शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। देश भर मे कई तरह की प्रौढ शिक्षाए है, जिनमे अल्पकालीन तथा व्यापक पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। अल्पकालीन पाठ्यक्रम का उद्देश्य साक्षरता के विस्तार तक सीमित है पर स्वास्थ्य, सफाई और नागरिक शास्त्र मे वृहत्तर पाठ्यक्रमो की भी व्यवस्था है। सेवाग्राम में एक देहाती विश्वविद्यालय और दिल्ली मे एक जनता कालेज है। इनमे देहाती इलाको के लिये नेतृत्व की शिक्षा दी जाती है।

श्रव्य-दृश्य सहायताएं

शिक्षा मत्रालय ने श्रव्य—दृश्य शिक्षा के लिये राष्ट्रीय बोर्ड कायम कर दिया है जिसका काम यह है कि इस क्षेत्र में होने वाले कार्यों मे परस्पर सयोग कायम रक्खे तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को परामर्श दे। इस बोर्ड की ओर से अत्यन्त दूर देहातों मे मोटर गाडियां भेजी जाती है, जिनमे ग्रामोफोन, मैजिक लालटैन, फिल्मे तथा फिल्म दिखाने के साधन होते है। इनके द्वारा लोगो को सामाजिक शिक्षा दी जाती है। आल इडिया रेडियो के सभी केन्द्रो से ग्रामवासियो के उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। आल इडिया रेडियो के कुछ केन्द्रो से औद्योगिक क्षेत्रो यानी विशेषकर हमारे मजदूर भाइयों के लिये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। कई राज्य सरकारो ने तो सामाजिक शिक्षा के लिये सगीत तथा नाटको द्वारा मनोरजन के कार्यक्रम को भी अपनाया है। इनके अलावा कई राज्यो मे मेले और प्रदर्शनिया भी सगठित की जाती है, जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ हो।

दृश्य कलाएं और शिल्प

दृश्य कलाओ और शिल्पों, कृषि, सगीत, चित्र विद्या इत्यादि से शिक्षा देने के लिये विद्यालय तथा कालेजो मे सुविधाए है :

तालिका 132

राज्यों में मान्यता-प्राप्त शिक्षण संस्थायें 1951-52 (क)

राज्य 1	सस्थाए 2	छात्रो की सख्या (हजारो मे) 3	व्यय (लाख रुपये मे) 4
आसाम	13,882	8,84	2,56
बिहार	30,238	19,80	7,82
बम्बई	42,250	42,92	22,62
मध्य प्रदेश (क)	31,113	14,90	5,34
मद्रास	43,718	51,26	22,48

(क) सख्याए अस्थायी है।

1	2	3	4
उडीसा . . .	11,528	6,19	2,13
पंजाब	6,195	9,08	5,51
उत्तर प्रदेश . . .	38,023	38,11	17,28
पश्चिमी बगाल . . .	20,085	22,53	12,39
हैदराबाद (क) . . .	9,753	7,32	4,70
जम्मू और काश्मीर (क) .	1,449	91	37
मध्य-भारत	5,239	3,64	1,82
मैसूर	13,876	9,26	3,50
पेप्सू	1,432	1,66	92
राजस्थान . . .	6,332	4,62	2,65
सौराष्ट्र (क) . .	2,777	2,83	1,22
तिरुवाकुर-कोचीन (क)	5,534	15,14	3,39
अजमेर . .	653	58	63
अडमान और निकोबार द्वीप-समूह	23	2	1
भोपाल . . .	373	20	16
बिलासपुर .	36	6	3
कुर्ग . .	163	25	15
दिल्ली .	1,921	2,33	2,88
हिमाचल प्रदेश .	627	42	19
कच्छ .	287	23	8
मणिपुर .	681	53	15
त्रिपुरा	497	35	16
विन्ध्य प्रदेश .	1,948	1,02	46
भारत . .	2,90,624	2,65,00	1,21,60

तालिका 133

मान्यता प्राप्त संस्थाओं में छात्रों की संख्या श्रेणी—अनुसार (1951–52) (ख)

	लडके	लडकिया	योग
कालेज शिक्षा			
इटरमीजियेट . .	2,19,000	28,000	2,47,000
बी ए., बी. एस. सी .	85,000	13,000	98,000
एम. ए, एम एस सी	14,000	2,000	16,000
शोध कार्य	1,000	—	1,000
व्यावसायिक और प्रौद्योगिक शिक्षा .	1,07,000	9,000	1,16,000
योग . .	4,26,000	52,000	4,78,000

(क) इन सख्याओ का सम्बन्ध 1950-51 से है।

(ख) सख्याये अस्थायी हैं।

	लडके	लडकियां	योग
स्कूल शिक्षा			
पूर्व-प्रारम्भिक	19,000	14,000	33,000
प्रारम्भिक	1,37,74,000	54,66,000	1,92,40,000
माध्यमिक	43,78,000	8,91,000	52,69,000
व्यावसायिक और प्रौद्योगिक शिक्षा	12,15,000	2,63,000	14,78,000
योग . .	1,93,86,000	66,34,000	2,60,20,000
सर्व योग	1,98,12,000	66,86,000	2,64,98,000

सघ सरकार ने शिक्षकों को बेसिक शिक्षा, कला और शिल्प, सगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिये दिल्ली के जामिया मिलिया तथा शातिनिकेतन की विश्व-भारती में व्यवस्था की है। कुछ भारतीय विश्वविद्यालयो ने प्रशिक्षण देने के लिये विशेष व्यवस्था की है और उनकी तरफ से प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा दिये जाते है। 1953 की जनवरी में नृत्य, नाटक और सगीत की राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की गई। सघ सरकार ने कला और साहित्य के क्षेत्र मे विभूतियो को वित्तीय सहायता देने की एक व्यवस्था भी की है।

अक्षमों की शिक्षा

अक्षमो की शिक्षा को दो श्रेणियो मे बाटा जा सकता है। एक तो उन अक्षमो की शिक्षा के लिये विद्यालय जो अन्धे, बहरे या गूगे है यानी जो शारीरिक दृष्टि से अक्षम है और दूसरे मानसिक रूप से अक्षमो के लिये विद्यालय।

अन्धो के लिये 50 तथा गूगो और बहरो के लिये 42 सस्थाए है, मानसिक रूप से अक्षमो के लिये केवल दो ही सस्थाए है, एक पश्चिमी बगाल मे तथा दूसरी बम्बई मे।

सभी राज्यो मे अन्धो को ब्रेल पद्धति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओ के जरिये से शिक्षा दी जाती है। छात्रो को दर्जीगीरी, कढाई, बुनाई, बढईगीरी आदि की शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयो मे सगीत की भी शिक्षा दी जाती है।

1950 की जनवरी मे देहरादून मे वयस्क अधो के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था। यहा अच्छा काम हो रहा है। देहरादून मे केन्द्रीय ब्रेल छापाखाना है, और यहा हिन्दी मे ब्रेल की पुस्तके प्रकाशित हो रही है। ओठ के द्वारा पढाई के अतिरिक्त गूगो, बहरो को शब्दस्फुट करना तथा ऐसे शिल्प सिखलाये जाते है जैसे चित्र विद्या, बढईगीरी, दर्जीगीरी इत्यादि।

प्रौद्योगिक शिक्षा

शिक्षा मत्रालय का एक डिवीजन देश की प्रौद्योगिक शिक्षा की देखरेख करता है। सघ सरकार ने प्रौद्योगिक शिक्षा के लिये एक अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य यह है कि वह प्रौद्योगिक शिक्षा, विकास तथा मानदण्डीकरण के सम्बन्ध मे परामर्श दे। परिषद् ने इजीनियरिग व्यवसाय, रासायनिक इजीनियरिग और वस्त्र प्रौद्योगिक

विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों के लिये अखिल भारतीय बोर्डों की एक सयुक्त समिति भी कायम की है । साथ ही परिषद् ने आगामी पाच वर्षों तथा दीर्घकालीन आधार पर प्रौद्योगिक जनशक्ति की कितनी आवश्यकता है इसके प्रमापन के लिये एक उपसमिति नियुक्त की है । सरकार ने क्षेत्रीय समितिया भी नियुक्त की हैं, जिनका प्रधान सहायक औद्योगिक परामर्शदाता होता है । इनका काम यह है कि एक तरफ तो शिक्षा सस्थाओ और दूसरी तरफ सरकार के औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक विभागों में सम्पर्क कायम रक्खे ।

छात्रवृत्ति की योजनाये

समुद्रपार छात्रवृत्ति की योजनाएं

युद्ध के बाद की विकास योजनाओं मे प्रौद्योगिक दृष्टि से सहायक सिद्ध होने के लिये भारत सरकार ने प्रौद्योगिक उच्च शिक्षा के लिये 1945 मे समुद्रपार छात्रवृत्तियों की योजना बनाई थी । तब से इस योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है । और 1952-53 के प्रारम्भ से तीन साल तक के लिये यह योजना कुछ परिवर्तित करके मजूर की गई है ।

इस समय यह योजना विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की अन्य सस्थाओ तक ही सीमित है । 1952-53 मे 25 व्यक्ति छात्रवृत्तियो के लिये चुने गये ।

केन्द्रीय राज्य छात्रवृत्ति योजना

यह योजना 'ग' भाग के राज्यो तथा 'घ' भाग के क्षेत्रो तक ही सीमित है । आम तौर पर विदेश मे जाकर अध्ययन करने के लिये प्रति वर्ष एक छात्रवृत्ति दी जाती है ।

ब्रिटिश उद्योग संघ की योजना

इस योजना के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन मे छात्रो की शिक्षा के लिये भारत सरकार को और छात्र 200 पौंड देना पड़ता है । इस के अनसार 1952-53 मे उद्योग धधो मे व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये भारतीयो को सात छात्रवृत्तिया दी गईं ।

भारत जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना

पश्चिमी जर्मनी के संघी प्रजातत्र ने 50 भारतीय छात्रो को स्नातकोत्तर सुविधाए देने के अतिरिक्त 250 भारतीय इजीनियरो और शिक्षार्थियो को जर्मन भारी उद्योग धधों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये निशुल्क सुविधाये देना स्वीकार किया । इस के जवाब मे भारत सरकार ने दस जर्मन छात्रो को भारतीय भाषाओं, धर्म, दर्शन के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तिया दी है ।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित उपजातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों को छात्रवृतियां

1952-53 मे ऊपर बताये हुए वर्गों के छात्रो को मैट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा के लिये साढे सत्रह लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । बाद को चल कर इस मद मे 12 लाख 60 हजार पया जोड दिया । 1952-53 मे कुल मिला कर 5,893 छात्रवृत्तिया दी गई जिन मे से 1,726

पेशों के लिये, 276 स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये, 953 स्नातक बनने के लिये और 2,938 छात्रवृत्तियां प्राकस्नातक अध्ययन के लिये दिये गये। 1953-54 में इस के लिये चालीस लाख रुपये की व्यवस्था है।

एशिया अफ्रीका तथा कामनवेल्थ के दूसरे देशों की ओर से छात्रवृत्तियां

भारत तथा दूसरे देशो में सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने तथा भारत में शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाने के लिये 1949 में 70 छात्रवृत्तियो की एक आम योजना बनाई गई। इसके फल-स्वरुप 1952-53 मे विभिन्न देशो से 91 छात्र आये 1953-54 में इसी योजना के अनुसार 100 छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई है।

फ्रांसीसी छात्रों को फैलोशिप

फ्रासीसी सरकार ने भारतीय छात्रों को कुछ छात्रवृतिया दी है। इसके जवाब में भारत सरकार ने फांसीसी छात्रो को छात्रवृत्तिया दी है।

संयुक्त राष्ट्र संघीय और यूनेस्को फैलोशिप

भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघीय सामाजिक कल्याण फैलोशिपों तथा छात्रवृत्तियों के कार्यक्रमो मे 1947 से बराबर भाग लेती रही है। फैलोशिपों तथा छात्रवृतियों के कार्यक्रमों की शर्तो के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को मासिक वृत्ति दी जाती है। अध्ययन के लिये निर्वाचित देश के अनुसार मासिक वृत्ति की रकम अलग होती हैं। इसके साथ ही समाज का खर्च तथा पुस्तकों के क्रय तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये भी खर्च दिया जाता है।

1952 मे भारत को 35 से ले कर 40 संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामाजिक कल्याण फैलोशिप तथा 10 से ले कर 15 छात्रवृत्तियां दी गई। 1953 के कार्यक्रम के लिये भारत सरकार से 70 प्रार्थियों के आवेदन पत्र भेजने के लिये कहा गया था।

हिन्दी प्रचार

हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिये शिक्षा मंत्रालय ने एक पंचवर्षीय योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि संविधान के अनुसार हिन्दी को पन्द्रह वर्ष के अन्दर संघ की सरकारी भाषा बना दी जाये। इसी उद्देश्य से मंत्रालय मे एक हिन्दी विभाग भी खोला गया है। विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रो मे हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिये हिन्दी शिक्षा समिति नाम से एक समिति की स्थापना हुई है, जो मंत्रालय को इस संबंध मे सलाह देगी। 1950 मे वैज्ञानिक, प्रशासनीय तथा दूसरे प्रौद्योगिक शब्दों के लिये कोष तैयार करने के लिये वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना हुई है।

मंत्रालय ने सरकारी नौकरो को हिन्दी शिक्षा देने के लिये श्रेणियां खोल दी है। अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली; साहित्यकार संसद्, इलाहाबाद; संसदीय हिन्दी परिषद्, तथा वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को विशेष अनुदान दिये गये है। धीरे धीरे एक हिन्दी पुस्तकालय बन रहा है। हिन्दी के मौलिक लेखकों तथा अनुवादकों के लिये 29,000 रुपये के पुरस्कारो की घोषणा की गई है।

तालिका 134

शिक्षा बजट (राजस्व लेखा) (क)

सरकार	1952-53 कुल व्यय (लाख रुपयों में)	1952-53 सम्पूर्ण बजट का प्रतिशत	1953-54 कुल व्यय (लाख रुपयों में)	1953-54 सम्पूर्ण बजट का प्रतिशत
आसाम .	185	14·7	200	13·3
बिहार .	412	13·8	521	15·6
बम्बई .	1,280	20·3	1,282	18·9
मध्य प्रदेश	314	15·8	467	19·0
मद्रास	1,180	16·6	1,205	14·9
उडीसा . .	140	11·6	177	12·2
पंजाब . .	191	11·4	251	12·5
उत्तर प्रदेश .	785	12·0	854	10·8
पश्चिमी बंगाल . .	400	9·7	487	11·2
हैदराबाद	505	16·0	476	16·9
जम्मू और काश्मीर	45	9·6	56	12·0
मध्य-भारत .	177	13·4	178	12·3
मैसूर . .	338	16·9	373	16·8
पेप्सू .	78	13·3	109	15·4
राजस्थान	250	14·5	294	15·1
सौराष्ट्र	122	14·0	147	14·7
त्रिवाकुर-कोचीन	320	17·0	381	17·8
अजमेर . .	50	29·7	61	31·0
अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह	2	1·6	3	1·7
भोपाल	27	7·5	35	13·7
बिलासपुर	34	23·7	4	16·2
कुर्ग	12	13·5	25	17·9
दिल्ली	113	[illegible]	142	33·2
हिमाचल प्रदेश .	29	11·7	38	13·0
कच्छ	11	11·4	12	11·0
मणिपुर . .	10	21·6	12	18·4
त्रिपुरा . .	19	17·3	20	16·3
विन्ध्य प्रदेश .	66	19·4	84	18·8
भारत .	7,068	15·0	7,894	15·0

(क) केवल शिक्षा विभागों के।

तालिका 135

स्रोतों के अनुसार शिक्षा पर अपरोक्ष व्यय

स्रोत	1948-49		1950-51	
	राशि (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत
सरकारी निधि . .	33 59	49 0	64 55	56 9
स्थानीय संस्था निधि .	9 51	13 9	12 48	11 0
फीस . .	16 47	24 1	23 12	20·4
अन्य स्रोत .	8 89	13 0	13 28	11 7
योग . .	68·46	100·0	113 43	100 0

तालिका 136

मदों के अनुसार शिक्षा पर व्यय

मदे	1948-49		1950-51	
	राशि (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत
1. प्रारम्भिक पाठशालाएं	22.9	—	37.15	32.8
2. माध्यमिक पाठशालाएं .	18.15	—	30.39	26.8
3. व्यावसायिक तथा विशेष पाठशालाएं .	3.60	—	6.23	5.5
4. कला और विज्ञान कालेज	4.03	—	6.7	5.9
5 धंधों की शिक्षा देने वाले और विशेष कालेज	2.85	—	4.41	4.0
6 विश्वविद्यालय और माध्यमिक एवं इंटरमीजियेट शिक्षा के बोर्ड	2.0	—	5.9	5.2
7 निर्देशन और निरीक्षण	1.93	—	—	2.4
8. भवन . .	5.61	—	9.8	8.5
9 विविध . .	6.40	—	7.1	6.0

बीसवां अध्याय

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य का विषय राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है, फिर भी बहुत से मामलों में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह अधिकार है कि वह स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करे। राज्यों के मामलों में स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य विशुद्ध रूप से परामर्श देने तथा राज्यों के कार्यों को परस्पर संयुक्त करने का है। स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर अत्यावश्यक सूचनाएं भी भेजता रहता है। इस के अतिरिक्त देशवासियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिये परामर्श तथा अन्य सहायता देना भी स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर ही यह भार है कि विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के साथ सम्बन्ध कायम रखे। बन्दरगाहों में क्वारान्टीन का विषय भी उन्हीं के हाथ में है। बाहर से मंगाई हुई दवाओं के मानदण्ड की जांच करते रहना, केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर देखरेख रखना, इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च तथा अन्य संस्थाओं के जरिए से शोध कार्य को प्रोत्साहन देना, यह भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य है। केन्द्र ने चिकित्सा शास्त्र, फरमासी विज्ञान, दन्त चिकित्सा तथा धात्रीविद्या के विकास के लिये भी सहायता देता रहता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों तथा अन्य स्वास्थ्य विभागों में आंकड़े मूलक सूचनाएं भी भेजी जाती हैं।

इन कार्यों के अतिरिक्त इसे निम्नलिखित उद्देश्यों से केन्द्रीय स्वास्थ्यसेवा निर्माण करना तथा उसे कायम रखना पड़ता है—(क) केन्द्र में प्रशासन के ऊंचे मानदण्ड कायम रहें, (ख) राज्यों के साथ सहयोग के द्वारा उनके प्रशासनों में उसी प्रकार के उच्च मानदण्ड कायम रखे जायें और (ग) केन्द्र तथा राज्यों को शिक्षा, शोध तथा चिकित्सा संस्थाओं के लिये उच्च शिक्षित कर्मचारी वर्ग की सेवाएं प्राप्त की जायें।

पंचवर्षीय योजना

पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 99 करोड़ 55 लाख रु० निर्दिष्ट हैं। इस रकम में से केन्द्रीय सरकार मुख्यतः प्रस्तावित अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था तथा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण पर 17 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च करने का इरादा रखती है। ऊपर बताये हुए 99 करोड़ 55 लाख रुपये का केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की चिकित्सा तथा सार्वजनिक योजनाओं में किस प्रकार खर्च होगा, यह नीचे देखा जा सकता है :

तालिका 137

(लाख रुपयों में)

	चिकित्सा-सम्बन्धी	सार्वजनिक स्वास्थ्य	योग
केन्द्र सरकार . .	565.23	1,222.20	1,787.43
भाग "क" के राज्य .	3,394.30	2,956.00	6,350.30
भाग "ख" के राज्य .	580.70	657.40	1,238.10
जम्मू और काश्मीर .	46.00	82.20	128.20
भाग "ग" के राज्य .	222.50	228.00	450.50
योग . .	4,808.73	5,145.80	9,954.53

1950-51 मे भारत सरकार ने एक करोड रुपया खर्च किया, जिस मे से साढे सात लाख रुपये विकास योजनाओ पर खर्च किये गये। पचवर्षीय योजना के समय मे केन्द्र की विकास योजना' पर खर्च बढ कर 3 करोड 57 लाख रुपये सालाना तक पहुच जाने की सभावना है।

राज्य सरकारे चिकित्सा सम्बन्धी योजनाओ पर जो 42 करोड 41 लाख रुपया खर्च करने वाली है, उनमे से 33 करोड रुपये तो उन योजनाओ पर खर्च होगे, जो इस समय चालू है। बाकी रकम नई योजनाओ के लिए रिजर्व रखी जाएगी। राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के लिये जो 39 करोड 23 लाख रुपये अलग रखे गये है, उनमे से 17 करोड रुपये चालू योजनाओ पर और बाकी रुपये नई योजनाओ पर खर्च होंगे। नीचे एक तुलना मूलक तालिका प्रस्तुत की जा रही है :

तालिका 138

(लाख रुपयो मे)

राज्य	चिकित्सा सम्बन्धी			सार्वजनिक स्वास्थ्य		
	1950-51 मे विकास के लिये व्यय	योजना मे परि-कल्पित वार्षिक व्यय	वृद्धि का प्रतिशत	1950-51 मे विकास के लिये व्यय	योजना मे परि-कल्पित वार्षिक व्यय	वृद्धि का प्रतिशत
भाग "क" के राज्य	525.31	678.86	29.2	316.57	591.2	86.9
भाग "ख" के राज्य	78.66	116.14	47.9	51.48	131.4	55.4
भाग "ग" के राज्य	1.48	44.52	2,908.0	1.12	45.6	3,970.0

चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी शिक्षा

जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त केन्द्रीय और राज्य सरकारे मिल कर पचवर्षीय योजना काल मे 47 करोड 62 लाख रुपया खर्च करेगी।

नीचे की तालिका मे यह दिखलाया गया है कि यह खर्च किस प्रकार बटा हुआ है और 1950-51 के साथ उसका तुलनात्मक रूप किस प्रकार बैठता है :

तालिका 139

(लाख रुपयो मे)

	1950-51 मे व्यय	योजना काल मे जो राशि व्यय की जायेगी	योजना काल मे वार्षिक औसत
प्रशासन . . .	3.2	62.2	12.4
शिक्षा और प्रशिक्षण . . .	235.2	1,891.7	378.3
अस्पताल और दवाखाने . . .	331.3	2,486.7	497.4
अन्य योजनाएं . . .	43.3	322.1	64.5
योग . . .	613.0	4,762.7	952.6

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे पचवर्षीय योजना की विकास योजनाओ को आगे बढ़ा रही है। नीचे की तालिका मे राज्यों ने इस सम्बन्ध म किस प्रकार प्रगति की है यह देखा जा सकता है :

तालिका 140

(लाख रुपयो मे)

	1950-51 (वास्तविक)	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (सशोधित)	1953-54 (बजट)	पाच वर्षो का योग
प्रशासन	3·4	3·5	3·5	5·5	22.2
शिक्षा और प्रशिक्षण	291.7	270.4	167·3	217·7	1,345·8
अस्पताल और दवाखाने	241.6	378.7	436·7	525·0	2,472.4
अन्य योजनाए	18.2	32.5	42.4	55.2	434·3

पंच-वर्षीय योजना मे कुल जितना खर्च प्रस्तावित है, उसका 50 प्रतिशत अस्पताल तथा औषधालयो पर खर्च होगा। पचवर्षीय योजना काल मे अस्पतालों, ओषधालयो तथा रोगी-शय्याओ की सख्या मे किस प्रकार वृद्धि होगी यह नीचे की तालिका मे देखा जा सकता है :

तालिका 141

	1950-51	1951-52 (सम्पन्न)	1952-53 (सम्पन्न)	1953-54 (प्रत्याशित)	1951-56
अस्पताल .	1,915	158	155	165	258
पलग	1,16,731	7,343	6,609	4,684	16,324
दवाखाने .	6,589	231	395	202	1,574
पलग .	7,072	1,587	2,899	393	9,620
स्वास्थ्य इकाई	433	101	55	50	314

सार्वजनिक स्वास्थ्य

जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य योजना के अन्तगत सावजनिक स्वास्थ्य योजनाओ पर 50 करोड़ 63 लाख रुपया खर्च करेगे ।

तालिका 142 मे यह बताया गया है कि यह खर्च किस प्रकार बंटा हुआ है, और साथ ही इसकी तुलना 1950-51 की स्थिति से की गई है ।

तालिका 142

(लाख रुपयों में)

	1950-51 में व्यय	योजना काल में व्यय किया जायेगा	योजना काल मे वार्षिक औसत
प्रशासन	15.6	210.8	42.2
शिक्षा . . .	1.0	130.7	26.1
जल और नालियो की व्यवस्था . .	270.5	2,334.4	466.9
मलेरिया निरोधक योजना . .	45.4	1,715.2	343.0
अन्य योजनाएं . . .	35.5	672.5	134.5
योग . . .	268.0	5,063 6	1,012 7

राज्य सरकारो के स्वास्थ्य कार्यक्रम पच-वर्षीय योजना काल मे किस प्रकार रहेगे, यह नीचे देखा जा सकता है :

तालिका 143

(लाख रुपयो मे)

	1950-51 (वास्तविक)	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (सशोधित)	1953-54 (बजट)	पाच वर्षों का योग
प्रशासन .	15.0	30 4	21.3	22.0	224.5
शिक्षा .	1.4	1.2	3.7	3.8	41.8
जल और नालियो की व्यवस्था .	264.2	354.9	407 5	412.2	2,407.9
मलेरिया निरोधक योजनाएं .	47.2	61.7	81.6	125.0	727.1
अन्य योजनाएं	35.9	55.7	71.6	117.7	548.3

केन्द्र और राज्य सरकारे मिल कर जो 99 करोड 55 लाख रुपये की रकम खर्च करेगी, नसके अतिरिक्त राज्यों मे स्थानीय अधिकारी विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा यूनिसेफ की तरह अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से कई अन्य चिकित्सा सम्बन्धी तथा सावजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित करेंगे ।

चिकित्सा की देशी पद्धतियां

राष्ट्रीय योजना समिति की सिफारिश तथा 1946 मे स्वास्थ्य मत्रियो का जो सम्मेलन हुआ था, उसके अनसार 1946 के दिसम्बर मे देशी दवा की पद्धतियो के प्रशिक्षण तथा शोध सम्बन्धी सुविधाओ पर जाच करने के लिये तथा इस क्षेत्र मे राज्य का नियत्रण स्थापित करने की वाच्छनीयता पर विचार करने के लिये श्री आर० एन० चोपडा के सभापतित्व मे एक समिति नियुक्त की गई थी ।

1948 के नवम्बर मे होम्योपैथिक जाच समिति की नियक्ति हुई, और इसको यह भार सौपा गया कि यह होम्योपैथिक पद्धति के नियत्रण तथा विकास के लिये सुझाव पेश करे ।

इन समितियो ने जाच के बाद जो प्रतिवेदन पेश किये, उन पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अपने अध्ययन प्रस्तुत किये । 1950 के अगस्त-सितम्बर मे स्वास्थ्य मत्रियो के तृतीय सम्मेलन मे इन सब पर विचार किया गया ।

1949 मे पडित कमेटी के नाम से एक छोटी समिति को यह भार सौपा गया कि वह आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियो पर वैज्ञानिक ढग से शोध करने के लिये क्या सुविधा दी जाये, उनका पता लगाये । समिति ने 1951 मे अपना प्रतिवेदन पेश किया । इस समिति ने यह सिफारिश की कि देशीय चिकित्सा पद्धतियो पर जो केन्द्रीय शोध सस्था प्रस्तावित है, वह जामनगर की गुलाब कुवरबा आयुर्वेदिक सस्था के साथ मिल कर काम करे । सरकार ने यह सिफारिश मजूर कर ली, और यह सस्था 1953 के 24 अगस्त से काम करने लगी ।

कुछ दिनो से लोगो मे यह भावना फैली हुई थी कि देशी चिकित्सा पद्धतियो की उतनी कदर नही की गई, जितनी कि करनी चाहिये । चोपडा समिति, 1950 के स्वास्थ्य मत्रियों के सम्मेलन और पडित समिति सब ने वैद्यो और हकीमो की शिक्षा को पुनस्सगठित करने के विषय पर विचार किया । इस सम्बन्ध मे सभी लोग सहमत है कि देशी चिकित्सा पद्धतियो के पाठ्यक्रम मे शरीर शास्त्र (ऐनाटोमी और फिजिओलोजी) तथा शल्य विद्या होनी चाहिये ।

देशी चिकित्सा पद्धतियो मे शिक्षा देने वाले 50 तथा होम्योपेथिक पद्धतियो पर शिक्षा देने वाले 8 कालेज मौजूद है ।

देशी दवा पद्धतियो के सम्बन्ध मे इन सस्थाओ मे शोध किया जाता है—स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन कलकत्ता, केन्द्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, जम्मू तथा सेन्ट्रल इस्टीट्यूट फार रिसर्च इडीजिनस सिस्टम आफ मेडिसन । ठाकुर दत्त शर्मा धर्मार्थ ट्रस्ट की देखरेख में 1953 की 31 जुलाई को एक आयर्वेदिक शोध सस्था भी खोली गई । वम्बई में वैज्ञानिक तरीकों पर आयवदिक चिकित्सा पर शोध करने के लिये तथा झासी आयर्वेदिक कालेज की देखरेख मे एक शोध सस्था खोली गई है ।

पंच वर्षीय योजना में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर शोध करने के लिये 37 लाख 50 हज़ार रुपय की व्यवस्था है ।

इसी कार्य के लिये राज्यो ने कुल मिला कर 95 लाख 23 हजार रुपये का व्यय निर्दिष्ट रखा है, और वे अस्पतालो तथा औषधालयो के लिये 1 करोड 6 लाख रुपये खर्च करना चाहते है ।

एलोपैथी पद्धति ने रोगो के प्रतिशोध तथा आरोग्य करने मे जो महान प्रगति की है, उसे देखते हुए सरकार ने इसके स्थान पर किसी और पद्धति को अपनाना उचित नही समझा । देश मे अनेक ढग की चिकित्सा पद्धतिया प्रचलित होने के कारण गडबडी उत्पन्न होती है, इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि केवल एक ही पद्धति स्वीकार की जाये, यद्यपि दूसरी पद्धतियो की अच्छी बाते एलोपैथी मे ली जा सकती है । भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि देशी तथा होम्योपैथिक पद्धतियो पर शोध किया जाये, साथ ही यह भी जरूरी समझा गया कि जिन लोगो ने उचित ढग से शिक्षा नही पाई, उन लोगो की नीमहकीमी बन्द की जाये ।

चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी शिक्षा

1951 मे इस बात की एक विशेष गिनती की गई कि देश मे कितने लोग चिकित्सा शास्त्र तथा स्वास्थ्य सेवाओ मे लगे हुए है। इस प्रमापन का परिणाम नीचे देखा जा सकता है :

तालिका 144

वर्ग	सख्या
पजीकृत चिकित्साजीवी . . .	91,930
वैद्य, हकीम, और अन्य ऐसे व्यक्ति जो चिकित्साजीवी है परन्तु पजीकृत नही हुए है	96,147
कम्पाउडर	38,407
नर्से	31,517
धात्रिया	23,938
टीका लगाने वाले	5,928
दत-चिकित्सक	3,283
अन्य सभी व्यक्ति जो अस्पतालो मे या अन्य ऐसे सस्थानों मे कार्य करते है जो चिकित्सा या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करते है (मेहतरों तथा अन्य सफाई-कर्मचारियों के सहित)	72,970
योग . .	3,64,120

हमारे यहा डाक्टरों तथा चिकित्सा कार्य मे लगे हुए अन्य लोगों की संख्या इतनी कम है कि हमारी कम से कम आवश्यकता भी पूरी नही हो सकती । 1943-44 में डाक्टरों की सख्या 47,500 बताई गई थी । इसी सख्या को ले कर स्वास्थ्य प्रमापन तथा विकास समिति ने यह राय दी कि 1971 तक भारत को और भी 1,85,000 डाक्टरों की जरूरत है । भारत सरकार ने इस समय मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने में कोई बात उठा नही रखी है । इस दिशा म क्या प्रगति हुई है यह तालिका 145 देखा जा सकता है :

तालिका 145

	1950-51	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (वास्तविक)	1953-54 (प्रत्याशित)	1951--56 (लक्ष्य)
डाक्टर	5,336	1,325	967	1,029	4,153
कम्पाउडर	894	765	461	439	1,945
धात्रिया	1,149	441	607	1,068	3,501
उपचारिकाए	2,212	1,008	860	709	4,648

इस समय 33 मेडिकल कालेज, 2 मेडिकल स्कूल, 6 दन्त चिकित्सा कालेज और 5 अन्य सस्थाए है जो एलोपैथी मे शिक्षा देती ह । उनकी सूची नीचे दी जाती है :

मेडिकल कालेज

1 मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास ।
2 स्टेनली मेडिकल कालेज, मद्रास ।
3 आध्र मेडिकल कालेज, विशाखपट्टनम् ।
4 क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेलोर ।
5 गुटूर मेडिकल कालेज, गुटूर ।
6. ग्राट मेडिकल कालेज, बम्बई ।
7 सेट जी० एस० मेडिकल कालेज, परेल, बम्बई ।
8 टोपी वाला नेशनल मेडिकल कालेज, बम्बई ।
9 बी० जे० मेडिकल कालेज, पूना ।
10 बी० जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद ।
11 बड़ौदा मेडिकल कालेज, बड़ौदा ।
12 मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।
13 आर० जी० कार मेडिकल कालेज, बेलगछिया, कलकत्ता ।
14. नील रतन सरकार मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।
15 नेशनल मेडिकल इस्टीट्यूट, कलकत्ता ।
16. महात्मा गाधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
17 सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा ।
18 प्रिस आफ वेल्स मेडिकल कालेज, पटना ।
19 दरभगा मेडिकल कालेज, दरभगा ।
20. मेडिकल कालेज, अमृतसर ।
21. आसाम मेडिकल कालेज, डिबरूगढ ।
22 मेडिकल कालेज, नागपुर ।
23. श्री रामचन्द्र भग मेडिकल कालेज, कटक ।
24. लेडी हार्डिंग महिला मेडिकल कालेज, नई दिल्ली ।

25. महात्मा गाधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, इदौर ।
26. गजरा राजा मेडिकल कालेज, ग्वालियर ।
27. सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर ।
28. मेडिकल कालेज, मैसूर ।
29. उसमानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद (दक्षिण) ।
30. मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम ।
31. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लधियाना ।
32. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल ।
33 मेडिकल कालेज, पटियाला (पेप्सू)

मेडिकल स्कूल

1. आर्य मेडिकल स्कूल, लधियाना ।
2. युनिर्वासिटी मेडिकल स्कूल, बंगलोर ।

दन्त-चिकित्सा कालेज

1. नय्यर हास्पिटल डेंटल कालेज, बम्बई ।
2. करीम भाई इब्राहीम मेमोरियल हास्पिटल एण्ड डेंटल कालेज, बम्बई ।
3. कलकत्ता डेंटल कालेज, कलकत्ता ।
4. डेंटल कालेज, अमृतसर ।
5. किंग जार्जेस मेडिकल कालेज (दन्त चिकित्सा विभाग), लखनऊ ।
6. मद्रास मेडिकल कालेज, दत-चिकित्सा विभाग, मद्रास ।

अन्य सम्बद्ध कालेज

1. आल इंडिया इस्टीट्यूट आफ हाइजीन एंड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता
2. मलेरिया इस्टीट्यूट आफ इंडिया, दिल्ली ।
3. कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली ।
4. स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता ।
5. श्री वल्लभभाई पटेल चेस्ट इस्टीट्यूट, दिल्ली ।

योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में परिस्थिति ऐसी हो जाये कि सारे देश भर के मेडिकल कालेजो में 4,000 छात्रों की नई भरती की व्यवस्था हो। 1951 में नई भरती सम्बन्धी व्यवस्था इस प्रकार थी :

तालिका 146

संस्था	छात्रो की सख्या		
	पुरुष	नारी	योग
मेडिकल कालेज (30) .	2,056	514(क)	2,570(क)
मेडिकल स्कूल (2) .	137	24	161
दंत-चिकित्सा कालेज (4) .	77	8	85

(क) लेडी हार्डिंग महिला मेडिकल कालेज, नई दिल्ली, में प्राविष्टयों की संख्या (जो कि 40 है) का सम्बन्ध 1950 से है ।

II मेडिकल स्कूलो को कालेज की मर्यादा दी गई। निम्नलिखित विभागों की भी मर्यादा बढा दी गई है :

मेडिकल कालेज, पटना का दैहिकी विभाग, टाटा-स्मारक अस्पताल, बम्बई का कैसर शोध केन्द्र, अखिल भारत स्वास्थ्य-विद्या एव सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता का औद्योगिक स्वास्थ्य-विद्या विभाग; सरकारी आम अस्पताल, मद्रास का गुप्त-रोग विभाग; मेडिकल कालेज, मद्रास का शरीर विभाग, सरकारी महिला और शिशु अस्पताल, मद्रास का धात्री-विद्या और स्त्री-रोग-विद्या का विभाग, दिल्ली विश्व विद्यालय का क्षय-रोग विभाग।

वेल्लौर के युनिवर्सिटी मेडिकल कालेज को एक लाख रु० इस उद्देश्य से दिया गया कि वहा औरस (थोराकिक) शल्य विद्या के विभाग का मानदण्ड ऊचा किया जाये । उसी प्रकार अन्य सस्थाओ मे अन्य विभागो के मानदण्ड को ऊचा उठाने के लिये 1953-54 के बजट मे 6,73,400 रुपये की व्यवस्था है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा सस्था

अखिल भारतीय चिकित्सा सस्था के खोलने के लिये सारी प्रारम्भिक बातें ो चकी हैं। आरम्भ के रूप मे नई दिल्ली के सफदरजग अस्पताल में छात्रों को परीक्षणमूलक प्रशिक्षण की सुविधा दी जायेगी। इस सस्था का मुख्य उद्देश्य इसको एक प्रदर्शन केन्द्र बनाना होगा, जहा पूर्व-स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध क्षेत्रो के प्रशिक्षण के लिये उच्च मानदण्ड रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त देश के चिकित्सा सम्बन्धी कालेजो के शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा।

विशेष प्रशिक्षण

भारत भर के करीब करीब सभी अस्पतालो मे धात्रीविद्या सिखाने की व्यवस्था है। दिल्ली तथा वेल्लोर के धात्री विद्या कालेजों मे ऐसे पाठ्य क्रम हैं, जो बी० एस० सी० के मानदण्ड के है। भारतीय धात्री विद्या परिषद् ने सहायक धात्रियों के लिए सरल और संक्षिप्त शिक्षाक्रम स्वीकृत किया है। आन्ध्र महिला सभा ट्रस्ट बोर्ड ने सहायक धात्रियों तथा दाइओं के प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना के लिए एक योजना बनाई थी। इसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है। 1951-52 मे सभा बोर्ड को 80 हजार रु० अनावर्तक अनुदान दिया गया और 1952-53 तथा 1953-54 के बजट के अनुमानो मे 15,000 रुपये का आवर्तक अनुदान सभा के लिए स्वीकृत हो चुका है। नई दिल्ली मे जो धात्री विद्या कालेज है, उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास, पूना, बम्बई, नागपुर, हैदराबाद इत्यादि में हेल्थ विजिटर्ज के लिए प्रशिक्षण केन्द्र है। योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि दाइओं को प्रशिक्षण की जो सुविधाए प्राप्त है उनको विस्तृत करना चाहिए। देशी दाइओं को कुछ राज्यों में भी प्रशिक्षण दिया गया है। अखिल भारतीय इस्टीच्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता के मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य विभाग की मातृत्व तथा शिशु कल्याण शाखा को एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप मे विकसित किया गया है, और साथ ही साथ इस पर कुछ अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताए भी है। भारत की मलेरिया सस्था मे अब तक चिकित्सा अधिकारियो को मलेरिया के सम्बन्ध मे छः सप्ताह शिक्षा लेनी पडती थी, पर उन्हे बारह सप्ताह शिक्षा लेनी पडेगी। भारत सरकार ने पुष्टि विज्ञान के सम्बन्ध मे भी एक सक्षिप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया है। इस पाठ्यक्रम मे कृषि फार्मिंग, दुग्धशाला विज्ञान, पशु पालन, मत्स्यपालन इत्यादि के वे पहल

भी आ जाएंगे, जिनका सम्बन्ध पुष्टि से है । देश में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, जिनमें तपेदिक शिक्षार्थियों को शिक्षा दी जाती है ।

भारत सरकार ने छात्रों को देश के बाहर जाकर प्रशिक्षण देने के लिए छात्रवृत्तियां दी हैं । 1948 से वरिष्ठ शिक्षकों तथा शोध करने वालों को भ्रमण सम्बन्धी छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कामनवेल्थ औद्योगिक सहायता कार्यक्रम के अनुसार आस्ट्रेलिया तथा कनाडा ने क्रमशः 37 और 10 छात्रवृत्तियां भारतीय छात्रों को दीं । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ की ओर से विदेशों में उच्चतर चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रों को फैलोशिप दिए जाते हैं ।

शोध

पुष्टि

कुन्नूर की पुष्टि विज्ञान शोध प्रयोगशाला, कलकत्ता, बम्बई तथा बंगलोर की शोध संस्थाओं तथा देश की अन्य शोध संस्थाओं में पुष्टि विज्ञान के सम्बन्ध में शोध जारी है । इनमें से कुन्नूर वाली प्रयोगशाला का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । इसमें सबसे पहले ऐसे लोगों के सम्बन्ध में जैसे बेरी-बेरी और फीलपांव के सम्बन्ध में शोध कार्य शुरू हुआ, जिनका सम्बन्ध पुष्टिगत कमी से है, पर अब इसका दायरा ऐसे विषयों तक विस्तृत हो गया है जैसे पुष्टि के कृषि सम्बन्धी पहलू, देश में आम तौर से प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न खाद्य द्रव्यों के पौष्टिक मूल्यों का निर्णय, खाद्यगत प्रमापन तथा शरीर पर कुछ खाद्य द्रव्यों के कुपरिणामों का अध्ययन ।

1953 के 31 मार्च को हैदराबाद में पुष्टि-शोध प्रयोगशाला की स्थायी इमारत का शिलान्यास किया गया था ।

शोणित विज्ञान के सम्बन्ध में भारत में 1930 से 1939 तक के दशक के प्रारंभिक वर्षों में लगभग शोध कार्य शुरू हुआ । तब से चिकित्सा सम्बन्धी शोध की भारतीय परिषद् ने शोणित विज्ञान में शोध की बहुत सी योजनायें रखी हैं और अभी हाल में शोणित विज्ञान पर शोध के लिए एक विशेष विभाग स्थापित हुआ है ।

विरस-शोध केन्द्र

पूना में 1953 की 4 फरवरी को विरस शोध केन्द्र का बाकायदा उद्घाटन किया गया । भारत में विशेष रूप से पाए जाने वाले विरस से उत्पन्न रोगों पर यहां शोध कार्य होगा, और साथ ही यहां विरस शोध के क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया जायगा । चिकित्सा सम्बन्धी शोध की भारतीय परिषद् तथा राकफेलर फाउन्डेशन ने यह कार्य संयुक्त रूप से किया है इस केन्द्र को चलाने की वित्तीय जिम्मेदारियां प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार पर नहीं हैं ।

चिकित्सा सम्बन्धी शोध की भारतीय परिषद् ने विरस शोध में विशेष दिलचस्पी ली है, इसके अलावा कसौली में कुछ समय से रेबीज शोध केन्द्र काम कर रहा है ।

इनफ्लुएञ्जा केन्द्र

इनफ्लुएञ्जा के विभिन्न पहलुओं पर कुन्नूर पास्तूर संस्था के इनफ्लुएञ्जा केन्द्र 1950 से शोध कार्य जारी है । इस केन्द्र में अब तक इनफ्लुएञ्जा के ग्यारह प्रकार के विरस अलग किए गए हैं, इसके अलावा मद्रास, कुन्नूर, ऊटकमंड, बम्बई इत्यादि स्थानों में इस रोग का जो प्रकोप हुआ

था, उस पर भी शोध किया गया। यहा पर रैबीज, हैजा तथा सर्पविष प्रतिशोधकों पर भी प्रतिशोध हो रहा है, भारत मे ज्वर कितना होता है इस पर भी खोज हो रही है। साथ ही गुप्त रोगो के निदान के सीरियोलौजिकल उपायों में भी तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। इन्फलूएन्जा निवारक वैकसिनो तथा सिरमो को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। उनका परिणाम अच्छा रहा है, इसलिए एक प्रस्ताव यह है कि इसके लिए एक प्रारम्भिक कारखाना खोला जाय। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

विश्व स्वास्थ्य सगठन की सहायता से तपेदिक के सम्बन्ध मे विशेषकर बी० सी० जी० के साथ इसके सम्बन्ध को दृष्टि मे रखते हुए शोध कार्य शुरू हो चुका है। तपेदिक शोध मद्रास के मदनापल्ले नामक स्थान के यूनियन मिशन टी० बी० सेनेटोरियम मे हो रहा है। तपेदिक के महामारी रूप सम्बन्धी शोध की एक योजना स्वीकृत हो चुकी है। यह योजना विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा चिकित्सा शोध की भारतीय परिषद् की सहायता से कार्यान्वित की जाएगी।

कुष्ठ

स्वास्थ्य प्रमापन और विकास समिति की सिफारिश पर पचवर्षीय योजना मे मद्रास के चिगलपट नामक स्थान मे एक केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षा तथा शोध सस्था की स्थापना की व्यवस्था की गई है। यह प्रस्ताव है कि लेडी विलिगडन कुष्ठ सेनेटोरियन तथा सिलवर जुबली शिशु रोग परीक्षणगृह को यह सस्था अपने अन्तर्गत कर ले।

कैन्सर

1946 मे बम्बई के टाटा मेमोरियल अस्पताल मे केन्सर सम्बन्धी शोध जारी हो गया। अपग्रेडिग समिति या उन्नयन समिति की सिफारिश पर इस शोध कार्य को केसर शोध के राष्ट्रीय केन्द्र की मर्यादा प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने अनावर्तक तथा आवर्तक अनुदानो के रूप मे इस केन्द्र को बहुत बडी रकमे दी है।

प्रयोगशालाएं

निम्नलिखित सस्थाओं मे अपने अपने विषय के लिए शोध की सुविधाए है। मद्रास के गिण्डी नामक स्थान के के० ई० एम० अस्पताल की बी० सी० जी० वेक्सिन की प्रयोगशाला (स्थापित 1948), कलकत्ता की केन्द्रीय ड्रग प्रयोगशाला (स्थापित 1947) कलकत्ता की सेरेलोजिस्ट प्रयोगशाला (स्थापित 1914) कसौली की केन्द्रीय शोध सस्था (स्थापित 19c6)।

बी० सी० जी० वेक्सिन प्रयोगशाला मे देश की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए यथेष्ट वेक्सिन उत्पन्न हो रहा है। हाल ही मे विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा यूनिसेफ ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशो की बी० सी० जी० सम्बन्धी आवश्यकताओ के लिए इस प्रयोगशाला को आर्डर दिए है। कसौली की केन्द्रीय शोध सस्था से देश भर की टी० बी०, हैजा, रैबीज तथा विष निवारक सिरमो और वैक्सिनो की पूर्ति होती है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

संविधान के 263 अनुच्छेद के अनुसार 1952 के 9 अगस्त को दिए हुए राष्ट्रपति के एक आज्ञा पत्र के अनुसार यह संस्था बनी। इस सस्था का उद्देश्य यह है कि संयुक्त रूप से कार्य किया जाए, और केन्द्र तथा राज्य आपस मे मिल कर प्रयत्न करे। यूनियन की स्वास्थ्य मत्री इस परिषद् की प्रधान तथा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रीगण इसके उपप्रधान है। 1953 की जनवरी में

परिषद् की पहली सभा हैदराबाद मे हुई और इसमे अन्य विषयों के साथ साथ राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम, चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के मानदण्डो विशेषकर वैद्यो को, हकीमो को दृष्टि में रखते हुए विचार हुआ।

औषधि नियन्त्रण

1940 की औषधि विधि तथा 1945 के ओषधि सम्बन्धी नियम 'क' भाग के सब राज्यों में तथा 'ग' भाग के राज्यो मे से अजमेर, कुर्ग तथा दिल्ली मे 1947 की पहली अप्रैल को लागू हो गये। यह विधि तथा नियम अब 'ख' भाग के सब राज्यों मे (सिवा जम्मू और काश्मीर के तथा नये बने हुए 'ग' भाग के राज्यों मे) लागू हो चुके है। इस विधि के अनुसार यूनियन सरकार को यह अख्तियार दिया गया है कि केवल उन्ही दवाओं को बाहर से मगाने दिया जाये जो एक स्वीकृत मानदण्ड तक की हो। राज्य सरकारो को यह अधिकार है कि वे स्थानीय रूप से उत्पन्न होने वाली दवाओं का उत्पादन, बिक्री और वितरण पर नियन्त्रण रखें। केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्रालय इस विधि को भी कडाई के साथ बरतना चाहता है।

स्वास्थ्य सेवाओ के डायरेक्टर जनरल के अधीन एक कन्ट्रोलर या नियन्त्रक तथा चार सहायक नियन्त्रक औषधि विधि मे वर्णित कार्यों को करने के लिए नियुक्त हुए है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के प्रोद्योगिक विषयों पर परामर्श देने तथा प्रशासन में एकरूपता प्राप्त करने के लिए औषधि प्रोद्योगिक परामर्श बोर्ड तथा औषधि सलाहकारी समिति का निर्माण हुआ है।

मेडिकल डिपो और कारखाने

असैनिक तथा सैनिक विभागों को उपयुक्त तथा स्वीकृत ढंग की दवाएं पहुंचाने के लिए मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और करनाल में दवाओं के सरकारी डिपो मौजूद है। मद्रास वाले डिपो के साथ कुछ कारखाने भी हैं। इन कारखानों में बहुत बड़े परिमाण में बाहर से मंगाए हुए तथा देशीय कच्चे माल से बहुत सी दवाएं उत्पन्न की जाती है।

पेनिसिलीन और डी० डी० टी०

केन्द्रीय सरकार की यह योजना है कि पूना मे एक पेनिसिलीन का कारखाना खोला जाये यह योजना अच्छी प्रगति कर चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीयों को प्रशिक्षित करने के अतिरिक्त तीन लाख तीस हजार डालर के मूल्य तक की प्रौद्योगिक सहायता देने का निश्चय किया है। यूनिसेफ इस कारखाने तथा उसके यन्त्रों के लिए साढे आठ लाख डालर देना चाहता है। बम्बई सरकार बम्बई के पास जल्दी ही एक डी० डी० टी० का कारखाना खोलने वाली है। बंगाल तथा मद्रास सरकार सिन्कोना के ऐसे कारखानों की मालिक है, जिनमें एक लाख पौंड सिन्कोना प्रति-वर्ष उत्पन्न होता है। बम्बई की हैफकिन संस्था ऐसी सलफा दवाएं प्रस्तुत कर रही है जो विश्व मे उत्पन्न सलफा की सर्वोत्तम दवाइयों मे समझी जाती हैं।

फरमासी जांच समिति

भारत सरकार ने फरमासी उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर खोज करने तथा भारत सरकार को ऐसी बातो की सिफारिश करने जिससे यह धधा मजबूत हो जाए एक समिति नियुक्त की है।

दवाओं के विज्ञापन पर नियन्त्रण

दवाओं के विज्ञापनों को नियत्रित करने के लिए भारतीय ससद् ने एक विधि बना दी है। इस विधि के अनुसार तिलस्मी आरोग्य शक्ति तथा अनाप सनाप दावा करने वाले लोगों को सजा दी जायेगी।

रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण

1947 में कुछ शहरों और देहाती इलाको के अतिरिक्त 'क' तथा 'ख' भाग के सब राज्यों में टीका सम्बन्धी विधि लागू थी। 'क' भाग के सब राज्यों तथा 'ख' भाग के अजमेर, कुर्ग और दिल्ली मे 82 कसबे, 204 देहाती वृत्त तथा 621 गाव ऐसे थे जहा प्रारम्भिक टीका लगाना अनिवार्य नही था, तथा 589 कसबे, 815 देहाती वृत्त, 621 गाव ऐसे थे, जहा दोबारा टीका लगवाना अनिवार्य नही था। 'क' भाग के राज्यो मे तथा अजमेर, कुर्ग और दिल्ली मे 1947 के दौरान मे 2,12,49,020 व्यक्तियो को टीके लगे थे। हैजा तथा ताऊन के लिए क्रमश: 2,18,58,094 तथा 62,95,157 व्यक्तियो को टीके दिए गए थे।

राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम

इस समय मौजूदा नियन्त्रण कार्यक्रम से लगभग तीन करोड व्यक्तियो को यानी भारत की कुल आबादी के आठ प्रतिशत से कुछ अधिक लोगो को मलेरिया से सरक्षण प्राप्त होता है। यह तो स्पष्ट है कि केवल इतने लोगो को सरक्षण देने से काम नही चलता, इसलिए 1952 की जुलाई वाले भारत अमेरिका समझौते के अनुसार एक राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना चालू की जाएगी। इस योजना के दो अश है, एक तो तीन साल तक रोग के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा, और इसके बाद कुछ कम पैमाने पर उस परिणाम को कायम रखा जायेगा। उद्देश्य यह है कि तेरह करोड़ लोगो को मलेरिया से सरक्षण मिले और व्यावहारिक मलेरिया नियन्त्रण टीमो की सख्या तीस से 1955–56 तक 130 कर दिया जाए। 1953–54 तक टीमो की कुल सख्या 75 तक ले जाना था। भारत सरकार राज्यो को 1954–55 और 1955–56 मे 60 लाख रुपये के मूल्य का डी० डी० टी० और अगले तीन सालो मे सवा पाच लाख रुपये के मूल्य की मलेरिया निवारक दवाइया मुफ्त देगी। केन्द्रीय सरकार कुछ राज्यो को नये कार्यक्रम शुरू करने तथा अपने वर्तमान कार्यक्रमो को बढाने के लिए सहायता देने का विचार रखती है। राज्य सरकार को डी०डी०टी० के अलावा बाकी सब व्यावहारिक खर्च और अतिरिक्त सामान के लिए आरम्भिक खर्च उठाना पडेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य को यह प्रतिज्ञा करनी पडेगी कि इन तीन वर्षों मे वे अपनी तरफ से बराबर मलेरिया निरोध के लिए जो कुछ खर्च करते रहे है, उसे बन्द नही करेंगे। टी० सी० ए० की ओर से डी० डी० टी० अनुदान के रूप मे सहायता दी जाएगी। यह द्रष्टव्य है कि मलेरिया के नियन्त्रण मे यही सबसे अधिक खर्च वाली चीज है। इसके अलावा टी० सी० ए० की ओर से आवश्यक सामग्री भी दी जाएगी। बम्बई में 1953 की तीन जून को राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना चालू की गई।

तालिका 147

(करोड रुपयो में)

	राष्ट्रीय मलेरिया नियत्रण योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व औसत वार्षिक व्यय	राष्ट्रीय मलेरिया नियत्रण योजना काल मे व्यय
राज्य .	1 41	5
केन्द्र . .	—	10

रौकफेलर फाउन्डेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, एफ० ए० ओ० तथा अमेरिका के प्रौद्योगिक सहयोग प्रशासन आदि अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं ने मलेरिया के विरुद्ध मूल्यवान सहयोग दिया गया है। मलेरिया की टीमें जिनमें डब्ल्यू० एच० ओ० तथा राज्य सरकारों के लोग है, तराई तथा मैसूर के मालनद इलाके में काम कर रही है।

दिल्ली की भारतीय मलेरिया संस्था पद्धतिगत रूप से शोध, महामारी सम्बन्धी अनुसधान तथा मलेरिया निवारक उपाय करती रहती है। साथ ही वह व्यावहारिक मलेरिया निवारण मे लगे हुए लोगों को प्रशिक्षण भी देती है।

तपेदिक

अनुमान है कि लगभग पचीस लाख व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते है, जिनमे से पांच लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष मर जाते हैं। 1947 में 'क' भाग के राज्यों तथा 'ग' भाग के राज्यों मे अजमेर, कुर्ग, दिल्ली में 3,71,045 व्यक्ति सास सम्बन्धी बीमारियों से तथा 47,639 हृदय के तपेदिक से मर गए। यह हिसाब लगाया गया है कि इन रोगों के कारण 90 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक मनुष्य दिनों की हानि होती है, इसलिए यदि यह कहा जाये कि हानि बहुत ही भारी है, तो इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं। तपेदिक का सामना करने तथा उसके नियन्त्रण के लिए ये उपाय किए गए है :

बी० सी० जी०

बीस साल से ऊपर तजुरबा करने के बाद यह मालूम हुआ है कि बी० सी० जी० का टीका तपेदिक नियन्त्रण करने के लिए सुन्दर उपाय है। भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा यूनिसेफ के साथ यह समझौता किया है कि देशव्यापी बी० सी० जी० कार्यक्रम चलाया जाये। 1948 मे बी० सी० जी० टीकों का कार्यक्रम आरम्भ हुआ, और 1951 के अप्रैल मे बडे पैमाने पर इसे चलाया जा रहा है।

1953 के सितम्बर के अन्त तक सोलह राज्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हो चुके थे। 1953 के अगस्त के अन्त तक दो करोड़ दस लाख व्यक्ति की ट्यूबरकुलिन के लिए परीक्षा हो चुकी थी। इनमें से 65 लाख व्यक्ति ट्यूबरकुलिन नेगेटिव पाए गए, इसलिए उन्हे बी०सी० जी० का टीका दिया गया। इस कार्यक्रम को ढग से चलाने के लिए एक केन्द्रीय बी० सी० जी० संगठन बनाया गया है, और 1953-54 के लिए 3,78,000 रुपयों की व्यवस्था की गई है। यह तो केन्द्र की बात हुई, राज्य सरकारों से भी कहा गया कि वे इस प्रकार के संगठन कायम करें।

100 से अधिक बी०सी० जी० टीमें देश भर में काम कर रही है। गिन्डी स्थित बी० सी० जी० वेक्सिन प्रयोगशाला इतनी अधिक वेक्सिन उत्पन्न करती है कि वह देश की आवश्यकता के लिए यथेष्ट है।

तपेदिक पर विजय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस कार्य के लिये लोग यथेष्ट संख्या में प्रशिक्षित हों। दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में जो तीन प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन केन्द्र हैं, उनमें चिकित्सा-शास्त्र के छात्रों, स्नातकोत्तर कार्यकर्ताओं, धात्रियों, हेल्थ विज़िटरों तथा प्रौद्योगिक विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय तपेदिक संघ प्रतिवर्ष कुछ हेल्थ विज़िटरों को प्रशिक्षित करता है।

दिल्ली के वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा चिकित्सा शास्त्र सम्बंधी विभिन्न पहलुओ पर शोधकार्य होता है। इस संस्था मे कई विभाग खोले जाने का विचार है जिनमें विभिन्न प्रकार के पहलुओ पर शोधकार्य होगा ।

तपेदिक से लोहा लेने के लिए यह आवश्यक है कि देश भर मे बहुत अधिक सख्या मे रोगी निवास, अस्पताल तथा प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि हो। योजना आयोग ने इन सस्थाओ की वृद्धि तथा जो संस्थाए मौजूद है, उनके विस्तार के लिए सिफारिश की है। इस सम्बन्ध मे क्या प्रगति अभीष्ट है, यह निम्नलिखित तालिका मे देखा जा सकता है

तालिका 148

	1950–51		1955–56	
	सस्थाओ की सख्या	पलगो की सख्या	सस्थाओ की सख्या	पलगो की सख्या
आरोग्य-गृह	37	4,161	46	5,656
अस्पताल	48	3,077	50	4,814
रोगी चिकित्सा गृह	127	2,323	180	2,562

1952 मे इतनी उन्नति हो चुकी थी कि 1947 मे जहा पाच हजार पलगो का ही प्रबन्ध था, वहा उस साल 13,000 पलंगो का प्रबन्ध हो चुका था। तपेदिक रोग से मुक्त लोगो के लिए रोगोत्तर सेवा उपनिवेशो तथा सुपात्र गरीब रोगियो की सहायता के लिए एक कोष का होना बहुत आवश्यक है। तपेदिक के रोगी अच्छे हो जाने पर भी अपने पहले के कार्यों पर लौट नही पाते, क्योकि लोग उनसे एक प्रकार मे बचना चाहते है। इसके अलावा यह भी बात सही है कि यदि वे कठिन परिश्रम करे, तो वे फिर से रोगी हो सकते है। एक प्रस्ताव यह है कि पश्चिमी बगाल मे एक रोगोत्तर सेवा उपनिवेश स्थापित किया जाए, और इसके लिए दस लाख रुपये का लक्ष्य रख कर एक कोष एकत्र किया जा रहा है। केन्द्र मे गरीब रोगियो की सहायता के लिए एक कोष खोला जा चुका है। इस कोष का प्रबंध-भार केन्द्रीय तपेदिक सघ को दे दिया गया है।

टी० बी० सीलों का कार्यक्रम

तपेदिक सघ ने टी० बी० सीलो का बेचना जारी करके गैर-सरकारी तपेदिक विरोधी सस्थाओ के लिए अच्छी सुविधा प्रस्तुत कर दी है। इससे पैसे एकत्र करने का तथा जनता मे वैयक्तिक दिलचस्पी पैदा करने का अच्छा मौका मिला है। गत तीन अभियानो मे लगभग तीस लाख रुपये एकत्र हो चुके है। जो लोग तपेदिक के क्षेत्र मे सेवा कार्य कर रहे है, उनका मिल जुल कर काम करना तथा पारस्परिक तजुरबे से फायदा उठाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से केन्द्रीय तपेदिक संघ सम्बन्धित लोगों का एक सम्मेलन बुलाता है। 1953–54 की दो फरवरी को मैसूर मे तपेदिक कार्यकर्त्ताओ का दसवां सम्मेलन हुआ था।

केन्द्र मे एक तपेदिक परामर्शदाता है। यह सम्भव है कि जल्दी ही सभी मुख्य राज्यो मे इसी प्रकार के परामर्शदाता होंगे। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे तपेदिक सेवा मे लगे हुए विभिन्न संगठनों तथा संस्थाओं को अनुदान देती है।

यौन रोग

अब यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ऐसे स्थानो मे यौन रोग का अनुपात बहुत अधिक है। इन राज्यो मे पांच से सात प्रतिशत व्यक्ति उपदश से पीडित है। देहातों में क्या परिस्थिति है, यह नही मालूम, पर काश्मीर से लेकर आसाम तक की पहाडी इलाके विशेष कर काश्मीर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश और आसाम मे यह रोग बहुत अधिक फैला हुआ है। पश्चिमी बगाल तथा हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टरेट के कर्मचारीवर्ग मे ऐसे अधिकारी मौजूद है जो केवल यौन रोग दमन करने वाले है। मद्रास राज्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक मेडिकल सलाहकार की सेवाए प्राप्त की गई है।

भारत सरकार के सामने एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार मद्रास और बम्बई के मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत यौन विभाग को उच्चतर मर्यादा दी जाएगी। पश्चिमी बगाल मे यौन रोग नियन्त्रण की एक बहुत ही व्यापक योजना चालू है, जिसमे 84 लाख 30 हजार रुपये खर्च होते है। पंचवर्षीय योजना काल मे इस मद में केन्द्र तथा राज्य इस प्रकार खर्च करेगे।

राज्य	1 करोड 3 लाख रु०
केन्द्र	5 लाख 79 हजार रु०

कुष्ठ

भारत मे लगभग दस लाख व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीडित रहते है। इन स्थानो के कुछ इलाको में कुष्ठ का जोर सबसे अधिक हो रहा है--पश्चिमी बगाल, बिहार, उडीसा, मद्रास, तिरुवाकुर-कोचीन। .

इस समय कुष्ठ निवारण का अधिकाश कार्य स्वयसेवक ढग के सगठनो के द्वारा किया जाता है। इस कार्य मे मिशन टू लेपर्ज सस्था सबसे आगे है। 1875 मे पजाब में चम्बा नामक स्थान में इस संस्था की स्थापना हुई। अब 95 सस्थाएं इससे सयुक्त है। हाल ही मे राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने कुष्ठ रोगियो के रहने का प्रबन्ध करने की चेष्टा की, पर कुल मिला कर देश भर मे केवल 14,000 कुष्ठ रोगियों के लिए स्थान प्राप्त है। हिन्द कुष्ठ निवारण संघ ने 1925 मे ब्रिटिश साम्राज्य कुष्ठ निवारण सघ की भारतीय परिषद् के रूप मे काम शुरू किया। गाधी स्मारक निधि ने भी एक कुष्ठ निवारण सघ स्थापित किया है और इस रोग को रोकने के लिए 90 लाख रुपये का अनुदान दिया है।

जिन स्थानों मे कुष्ठ का विशेष प्रकोप है, उन स्थानों मे अधिक कार्य करने के लिए कुछ योजनाए केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्रालय के विचाराधीन है।

कैन्सर

साल में लगभग दो लाख व्यक्ति कैंसर मे मरते है। बम्बई का टाटा स्मारक अस्पताल तथा कलकत्ते का चितरंजन अस्पताल ये ही दो ऐसे अस्पताल है, जहा कैंसर का इलाज होता है। मद्रास में इसी प्रकार का अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। टाटा स्मारक अस्पताल में शोध भी हो रहा है।

1951 की दो मई को बम्बई मे भारतीय कैंसर सोसायटी की स्थापना हुई। इसके दो प्रधान दफ्तर कलकत्ता और दिल्ली में है। दिल्ली वाला दफ्तर 1953 के अप्रैल में स्थापित हुआ था।

जलपूर्ति

भारत में केवल छ: प्रतिशत नगरो मे शोधित जल पूर्ति की व्यवस्था है। इस प्रकार भारत की कुल आबादी के 6.15 प्रतिशत तथा शहरी आबादी के 48.5 प्रतिशत को ही शोधित जल मिलता है। बडे शहरो मे जल की व्यवस्था काफी बिगडी है। देहाती इलाको मे तथा छोटे शहरो मे लोगों को शोधित जल नही मिलता। एनवायरेनमेन्टल हाईजीन कमेटी ने इस सम्बन्ध मे पचवर्षीय योजना तैयार की है, जिसमे उन इलाको को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमे जल दुर्लभ है, हैजा का प्रकोप रहता है इत्यादि। इस कमेटी ने जो योजना रखी है उसमे प्रतिवर्ष 16 करोड 77 लाख रुपये खर्च होंगे।

एक लाख की आबादी से ऊपर वाले 48 शहरो मे से 23 मे मल अपवहन पद्धति मौजूद है। बारह शहरो मे आंशिक रूप से मल अपवहन प्रणालिया है। इस प्रकार केवल तीन प्रतिशत लोगो को इस प्रणाली से लाभ प्राप्त होता है। ऊपर बताई हुई कमेटी ने इस सम्बन्ध मे पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो प्रस्ताव रखा है उसमे पद्रह करोड रुपया खर्च आएगा।

'क' भाग के राज्यो मे बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बगाल, बिहार, 'ख' भाग के राज्यो मे मध्य प्रदेश, मैसूर तिरुवाकुर-कोचीन और 'ग' भाग के राज्यो मे भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर ने अपनी जल पूर्ति तथा मल अपवहन प्रणाली को उन्नत करने के लिए यथेष्ट खर्च किया है। राज्यो की जल पूर्ति और मल अपवहन के पचवर्षीय कार्यक्रम मे 23 करोड 49 लाख रुपये खर्च होगे। इसमे केन्द्र दस करोड रुपये देगा, जो पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय विकास कार्यों के लिए प्राप्त तीस करोड रुपये की रकम मे से दिया जाएगा।

एक आदर्श व्यापक जन स्वास्थ्य विधेयक बनाने के लिए एक समिति नियुक्त हुई है। इसमें परिस्थितिगत सफाई के सारे पहलू आ जाएगे जैसे मकान की जल पूर्ति, सामान्य सफाई, विविध व्यवसायो, धधो तथा पेशो की व्यवस्था।

पुष्टि

1935 और 1948 के बीच भारत मे खाद्यो का जो प्रमापन किया गया, उससे यह ज्ञात हुआ कि एक औसत भारतीय के खाद्य मे अनाज बहुत अधिक रहता है, पर उसमे प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा विटामिन जैसे सरक्षण खाद्यो का अभाव रहता है। इस प्रकार का भोजन असन्तुलित होता है और इससे अपुष्टि होती है। इसके कारण बच्चो, माताओ तथा साधारण लोगों मे मृत्यु सख्या अधिक होती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिषद् और भारतीय कृषि शोध परिषद् की सयुक्त समिति ने खेती की उपजों को दृष्टि मे रख कर मनुष्यों तथा पशुओ की पुष्टि के सम्बन्ध मे एक नपी तुली

योजना रखी है। नीचे जो तालिका दी गयी है, उसमें प्रति वयस्क व्यक्ति को कितना खाना प्राप्त है तथा 1956 तक हमारा क्या लक्ष्य है, यह दिखाया गया है :

तालिका 149

तीस करोड़ वयस्क इकाइयों की आवश्यकता-पूर्ति का लक्ष्य

खाद्य पदार्थ	1950 में प्रति वयस्क व्यक्ति उपलब्ध मात्रा (औंसों में)	दैनिक आवश्यकताए (औंसो में)	वार्षिक आवश्यकताएं (दस लाख टनों में)
अनाज .	13 71	14	43
दाले .	2 1	3	9
दूध	5.5	10	31
फल .	1 5	3	9
तरकारिया .	1 3	10	29
चीनी .	1 6	2	6
मछली और गोश्त .	0.3	3	9
अंडे . .	—	1 (अक)	10,95,000लाख अडे
वनस्पति तेल और घी .	1	2	6

भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिषद् की एक पुष्टि परामर्श समिति है। इसके अलावा कई पुष्टि शोध प्रयोगशालाएं भी है। केन्द्र मे भी एक अन्तर्विभागीय समिति है। बगाल, बम्बई, तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ऐसी समितिया बना ली है। मद्रास, बिहार तथा पंजाब की सरकारें इस विषय पर विचार कर रही है।

खाद्य मे मिलावट की ओर सरकार की दृष्टि गई है, और ससद् खाद्य मिलावट विधेयक पर विचार चल रहा था।

स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा

सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा केन्द्रीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनता मे स्वास्थ्य सम्बन्धी विचारों को फैलाने के लिए फिल्मो, पोस्टरों पुस्तिकाओ, माडलो, फोटो आदि का प्रयोग होता है।

स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टरेट जनरल से एक केन्द्रीय स्वास्थ्य फिल्म पुस्तकालय भी सम्बद्ध है। इस पुस्तकालय में स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे जो फिल्म रहते है, वे राज्य सरकारो को, शिक्षा संस्थाओं को, स्थानीय संस्थाओं को, सामूहिक कार्य प्रशासन सस्थाओ को तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं को उधार दिये जाते है, जिससे कि वे उनका लाभ उठा सकें। बीस बहुरंगी चित्रमय पोस्टर तथा पैंतीस पुस्तिकाएं अंग्रेजी और हिन्दी मे प्रकाशित हो चुकी है, और निःशुल्क बाटी जा रही है। नुमाइशों मे बहुत से वृहदीकृत फोटो तथा अन्य प्रदर्शन योग्य चीजे दिखाई जाती है। केन्द्रीय स्वास्थ्य अजायबघर की स्थापना भी की जा चुकी है।

जनसंख्या का नियन्त्रण

स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टरेट जनरल मे अभी हाल मे ही आबादी-नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक नया विभाग खोला गया है। इस सम्बन्ध मे तीन प्रारम्भिक प्रयोग किये जा रहे है। इनमे

से दो प्रयोग दिल्ली मे और एक मैसूर मे किया जा रहा है। परिवार नियत्रण के सम्बन्ध मे जो खतरे से खाली दिन का सिद्धान्त है, उसकी उपयोगिता तथा मूल्य पर अध्ययन तथा प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा समझा जाता है कि 1954 के अन्त तक यह अध्ययन समाप्त हो जायेगा। भारत सरकार को परिवार–नियन्त्रण के सम्बन्ध मे शोध सम्बन्धी तथा अन्य योजनाओं पर परामर्श देने के लिए एक परिवार–नियन्त्रण शोध तथा कार्यक्रम समिति का निर्माण किया जा चुका है।

योजना आयोग ने इस कार्य के लिए 65 लाख रुपये की व्यवस्था की है। 1952–53 मे उसके लिए तीन लाख रुपये की व्यवस्था थी, जिसमें से केवल एक ही अंश खर्च हुआ था। 1953–54 के बजट मे भी इस सम्बन्ध मे तीन लाख रुपये की व्यवस्था है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्ध

भारत को 1948 से विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा 1949 से यूनिसेफ से सहायता प्राप्त हो रही है। इन सगठनो से जो सहायता प्राप्त होती है, वह साधारणत मौजूदा सेवाओं को उन्नत करने के लिए विशेषज्ञ परामर्श, चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य, साज-सामान तथा धात्रियों और दाइयों को प्रशिक्षित करने के लिए फैलोशिप और छात्रवृत्तियों के रूप मे होती है। इन अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ की तरफ से हमारे यहा जो तरह तरह के प्रशिक्षण तथा शोध कार्य चालू है, उनके लिए पथ प्रदर्शक तथा शिक्षक भी भेजे जाते है। यूनिसेफ की ओर से भूचाल तथा दुर्भिक्ष पीडित क्षेत्रों के लिए भी सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बच्चो तथा आसन्न प्रसवा माताओं को खिलाने पिलाने के सम्बन्ध मे भी इसके कार्यक्रम भी चालू है। इसकी ओर से भारत के 28 राज्यों के मातृमंगल तथा शिशु कल्याण केन्द्रो मे 3,06,900 पौड साबुन बाटा जा चुका है।

1952–53 के बजट मे विश्व स्वास्थ्य सगठन मे बीस लाख रुपये अलग रखे गये थे। 1952 में भारत सरकार ने यूनिसेफ के कोष मे बारह लाख रुपये दिये। 1953 मे इस सस्था को पन्द्रह लाख रुपये देने को व्यवस्था है।

तालिका 150

माह		जन्म		मृत्यु	
		योग (हजारो मे)	(हजार व्यक्ति पीछे) दर	योग (हजारो मे)	(हजार व्यक्ति पीछे) दर
1		2	3	4	5
1950		6,728	24.8	4.333	16 0
1951 (क)	जनवरी	468	24 3	283	14.7
	फरवरी	445	23 4	269	14 1
	मार्च	464	23 2	289	14 4
	अप्रैल	448	22 4	285	14.2
	मई	460	22 6	316	15.6
	जून	463	22 9	291	14 4
	जुलाई	503	26.C	281	13.9

(क) इनका उन इकाइयों से सम्बन्ध है जिन्हें पहले प्रांत कहा जाता था।

1		2	3	4	5
	अगस्त .	522	26.4	267	13.5
	सितम्बर .	522	28.2	260	14.1
	अक्तूबर .	516	27.8	290	15.7
	नवम्बर .	517	27.4	250	13.2
	दिसम्बर .	515	25.1	267	13.0
1952(क)	जनवरी .	—	24.4	—	12.7
	फरवरी .	—	23 6	—	12.4
	मार्च .	—	24.2	—	13.3
	अप्रैल .	—	24.4	—	13.1
	मई .	—	24.6	—	13.0
	जून .	—	26.0	—	12.9
	जुलाई .	—	29.6	—	14.6
	अगस्त .	—	31.7	—	15.6
	सितम्बर .	—	32.6	—	16.4
	अक्तूबर .	—	34 4	—	17.0
	नवम्बर .	—	29 5	—	14.8
	दिसम्बर .	—	32.6	—	17.3

(क) अस्थायी ।

इक्कीसवां अध्याय

श्रम

केवल कुछ संगठित भागों के सम्बन्ध मे जैसे कारखानो, खानों, बागानों, रेलो, डाक और तार विभाग मे लगे हुए लोगों के सम्बन्ध मे ही आकडे प्राप्त है। पर असली काम करने वालो की संख्या इनसे कही अधिक है। 1950 मे सगठित धधो मे कितने लोग काम करते थे, उसका लेखा इस प्रकार है :—

कारखाने	25,04,399
खाने	4,71,761
रेले	9,23,154
ट्राम मार्ग	13,662
डाक और तार	1,74,230
मुख्य बन्दरगाह	53,258
सी० पी० डब्ल्यू० डी०	4,08,190

1950 मे बागानों मे कितने लोग काम करते थे, इसके आंकड़े प्राप्त नही है। पर 1949 मे बागानो मे 12,10,964 व्यक्ति लगे हुए थे। सी० पी० डब्ल्यू० डी०, डाक और तार विभाग, मुख्य बन्दरगाहो और ट्रामो पर 1951 मे क्रमश 2,29,032; 1,93,302, 49,082 और 17,740 व्यक्ति लगे हुए थे। 1952 के 31 मार्च को रेल विभाग मे 9,25,319 व्यक्ति लगे हुए थे।

काम से गैर-हाजिरी

काम से गैर-हाजिरी के कारण उत्पादन सम्बन्धी साधनो पर बडा जोर पडता है। तालिका 151 से 153 मे कुछ धधो के सम्बन्ध मे परिस्थिति स्पष्ट की गई है :

(देखिये पृष्ठ 346 पर तालिका 151)

तालिका 152

कोयला-खानों के मजदूरों की अनुपस्थिति-वृत्ति (प्रतिशत)

अवधि	भू-गर्भ मे	खुले मे	धरातल पर	कुल मिलाकर
1951 (औसत)	15 18	14·56	10·55	13·31
1952 (औसत)	14 78	14·31	10·38	13·11
जनवरी 1953	15·37	14·71	8 98	12·77
फरवरी 1953	14·23	14·08	10 77	13·01
मार्च 1953	15·78	16·91	11·60	14·40
अप्रैल 1953	13.99	14·38	10·70	12·86
मई 1953	14·07	14·51	11·06	13·05
जून 1953	15·90	15·00	11·86	14·34

तालिका 151

उत्पादन करने वाले उद्योगों में अनुपस्थिति—वृत्ति

[कार्य के लिए निर्धारित व्यक्ति-पालियों (मैन-शिफ्टस) के मुकाबले व्यर्थ गयी व्यक्ति-पालियों का प्रतिशत]

वर्ष	सूती मिलें							ऊनी मिलें		इंजीनियरिंग कारखाने		टेलिग्राफ वर्कशाप	ट्रामवे वर्कशाप्स	लोहे व इस्पात के कारखाने	आर्डिनेंस कारखाने	सीमेंट के कारखाने	दियासलाई के कारखाने	चमड़े के कारखाने
	बम्बई	अहमदाबाद	शोलापुर	मद्रास	मदुरा	कोयम्बटूर	कानपुर	कानपुर	धारीवाल	बम्बई	पश्चिमी बंगाल	अखिल भारत	अखिल भारत	अखिल भारत	अखिल भारत	अखिल भारत	अखिल भारत	कानपुर
1947	14·4	6 4	19 1	10 3	14·7	13·8	16·1	11·5	–	13·8	–	–	–	–	10·6	12·2	12·4	15·5
1948	13·3	5·9	18 1	9·1	13 9	9 6	16·1	10·6	–	13·4	–	–	–	14·3	8·5	10·9	10·9	8·0
1949	15·9	7·4	21·3	8·6	13·1	8·1	15·6	11·0	–	13·6	–	–	–	13·5	8·0	10·1	10·8	11·3
1950	14·5	8 4	20·1	9·5	14·6	9·7	16·1	12·5	9·3	13·1	11·1	8·1	15·7	12·4	8·9	10·6	11·0	8·4
1951	12·7	8·3	18·7	8.9	11·3	10·0	12·0	13·2	10·6	13·9	10·1	8·5	13·0	11·0	8·6	11·8	10·5	7·8

तालिका 153

आसाम के चाय बागों में अनुपस्थिति-वृत्ति (प्रतिशत)

1944-45	28 8
1945-46	25 5
1946-47	25·6
1947-48	24·6
1948-49	25 9
1949-50	19·3

कोयला-खान बोनस योजना, और कोयला-खान प्राविडेंट फंड योजना, जो मुख्यत: कोयला-खान-मजदूरो की नौकरी के आकस्मिक रूप को समाप्त करने के उद्देश्य से बनायी गयी है, और उपस्थिति बोनस के कारण अनुपस्थिति-वृत्ति कम हो गयी है ।

उत्पादनक्षमता

श्रम की उत्पादनक्षमता के विषय मे हाल ही मे अध्ययन प्रारम्भ किया गया । निम्नलिखित तालिका से कोयला खानो मे श्रम की उत्पादनक्षमता के विषय मे कुछ अन्दाज लग सकेगा—

तालिका 154

कोयला-खानों में उत्पादनक्षमता (औसत)

अवधि	खुदाई और ढुलाई करने वाले	भू-गर्भ मे और खुले मे कार्य सलग्न सभी व्यक्ति	खान के भीतर बाहर कार्य सलग्न सभी व्यक्ति
1	2	3	4
1951 (औसत)	1 03	0 55	0 34
1952 (औसत)	1·04	0 56	0 35
जनवरी 1953	1 06	0 57	0·33
फरवरी 1953	1 03	0 57	0 37
मार्च 1953	1 06	0 57	0·36
अप्रैल 1953	1 05	0 57	0 37
मई 1953	1 03	0 56	0·36
जून 1953	1 06	0 57	0·35

उत्पादनक्षमता और परिणामों के द्वारा भुगतान पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन टीम

1952 की 5 दिसम्बर को पांच विशेषज्ञो का बना हुआ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन मिशन भारत आया । नई दिल्ली मे कुछ प्राथमिक विचार विनिमय करने के बाद मिशन दो हिस्सो मे बंट गया । एक तो वस्त्र व्यवसाय के सम्बन्ध मे सक्रिय हो गया, और दूसरा इंजीनियरिंग धंधों पर काम करने लगा । इन टीमो ने बम्बई राज्य की कपडा मिलो तथा कलकत्ते के पाच इंजीनियरिंग धंधों मे बहुत ब्यौरेवार जाचकार्य किया ।

इस मिशन का उद्देश्य यह जाच करना था कि कार्य करने के आधुनिक उपायों, कारखाने के संगठन तथा जहा भी उपयुक्त हो भुगतान की उपयुक्त पद्धति के प्रवर्तन से भारतीय मज़दूरों की उत्पादनक्षमता तथा मज़दूरी किस प्रकार बढ़ सकती है। मिशन ने कुछ चुने हुए लोगों को तथा मजदूर सघ के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है और इसका नतीजा बहुत उत्साहप्रद रहा। अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारत मे एक राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता केन्द्र खोला जाये।

बेकारी

चाय के धधे पर 1952 मे जो आफत आई थी, वह 1953 मे भी कायम रही। कपड़े के धंधे को भी हानि पहुची, यहा तक कि मिले बन्द करने, छाट करने तथा मजदूरो के निकाले जाने की नौबत आ गई। इसके अतिरिक्त शिक्षित लोगो मे भी बेकारी बढ गई। 1952 के अन्त मे काम-दिलाऊ केन्द्रों के रजिस्टरो पर शिक्षित बेकारो की सख्या 1,61,599 दिखाई गई थी, यह संख्या 1953 के जून के अन्त मे 1,94,881 हो गई। 1953 की जुलाई मे आगरा अधिवेशन मे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश मे फैली हुई बेरोजगारी के पतनकारी परिणामो की ओर ध्यान आकर्षित किया था। ससद् के दोनो भवनो के शरद् तथा शीत अधिवेशनों मे इस सम्बन्ध मे गैर-सरकारी सदस्यो ने प्रस्ताव भी रखे। कुछ राज्यो की विधान सभाओ मे भी इस प्रश्न पर विचार हुआ। योजना आयोग ने इस समस्या पर ध्यान दिया और परिस्थिति का सामना करने के लिए कुछ कदम उठाये।

बेकारी दूर करने के उपाय

देश मे बेकारी बहुत अधिक बढ चुकी ह, पर इस सम्बन्ध मे कुछ ही उपाय काम मे लाये जा सकते है। फिर भी बेरोज़गारी दूर करने के लिये जो कुछ भी सम्भव है किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर पचवर्षीय योजना मे संशोधन किया जा रहा है। केन्द्रीय और राज्य सरकारे विकास कार्यों के लक्ष्यो को जल्दी से जल्दी पूरा करने मे लगी हुई है। निजी धधो को भी अपनी उत्पादनक्षमता बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस क्षेत्र मे देश के प्रयासो को सही मार्ग दिखलाने के लिए एक एकादश-सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। शिक्षित बेकारो की समस्या पर आपत्तिकाल के ढग से विचार हो रहा है। एक शिक्षक वाले विद्यालयो का एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमे 1953–54 मे 33,000 शिक्षक खप जायेगे और 1954–55 मे 50,000 और शिक्षक खपेगे। इसके अतिरिक्त 30,000 विशेष शिक्षा केन्द्र 1953–54 मे तथा 5,000 विशेष शिक्षा केन्द्र 1954–55 मे खोले जायेगे, ऐसी आशा है। राष्ट्रीय विस्तार योजना से 84,000 नौकरिया निकलेगी। केन्द्रीय सरकार ने रोजगार बढाने के लिए चौदह करोड सत्तर लाख रुपये खर्च करने का निर्णय किया है। अब तक अठारह राज्य केन्द्र का प्रस्ताव स्वीकार कर चुके है। इस मद मे राज्यों मे धन इस प्रकार से बांटा जायेगा :

बिहार . . .	11.50 लाख रुपये
पंजाब . . .	5.50 लाख रुपये
पेप्सू . . .	2.00 लाख रुपये

राजस्थान . . . 3.72 लाख रुपये
सौराष्ट्र . . . 1.00 लाख रुपये

छंटनी किये हुए तथा हटाये हुए मजदूरों के लिए क्षतिपूर्ति

1953 की जुलाई मे स्टैंडिंग लेबर कमेटी या स्थायी श्रम समिति के तेरहवे अधिवेशन में पूंजीपतियो और मजदूरों के बीच जो समझौता हुआ था उसी को राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के रूप मे 1953 के अक्तूबर मे प्रकाशित किया गया। इसमे यह कहा गया है कि जो मजदूर मौसमी कारखानो के अलावा ऐसे कारखानो मे काम करते है जहा पचास या उससे अधिक लोग काम करते है और कारखानेदार उसे हटाना चाहता है, तो यदि उस मजदूर के सामने कोई उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार नही है, तो कारखानेदार उसे एक साल मे 45 दिन के हिसाब से जितने दिन बनेगे उन के लिये पचास प्रतिशत मजदूरी और महगाई भत्ता देगा। अध्यादेश मे यह भी कहा गया था कि यदि कोई मजदूर किसी मालिक के अधीन कम से कम एक साल रहा है, तो उसे निकालने के लिए एक महीने का नोटिस या नोटिस के ऐवज मे एक महीने का वेतन तथा जितने साल या छः महीने मे अधिक समय उसने पूरा किया, उतने सालो के लिये 15 दिन के औसत वेतन के हिसाब से एक मुश्त रकम देनी पडेगी।

(देखिये पृष्ठ 350 पर तालिका 155)

काम दिलाऊ केन्द्रो मे अनुसूचित जातियो, छटनी मे निकाले हुए सरकारी नौकरो तथा विस्थापितो को नौकरी दिलाने मे प्राथमिकता दी जाती है। 1952 मे इस संस्था की ओर से 8,596 छटनी मे निकाले गये सरकारी नौकरो, 17,088 विस्थापितो तथा 49,044 अनुसूचित जातियो के प्रार्थियो को नौकरिया दिलाई गई। हाल ही मे काम दिलाऊ केन्द्रों में एक नया विभाग खोला गया है जो दर्जा I तथा दर्जा II के गेजेटेड तथा कमीशन प्राप्त फालतू तथा छटनी मे निकाले हुए अधिकारियो को नौकरिया दिलाने का काम करेगा। 1952 मे दर्जा I तथा दर्जा II के गेजेटेड तथा छटनी मे निकाले हुए कमीशन प्राप्त अधिकारियों के विशेष रजिस्टर पर 307 व्यक्तियो के नाम दर्ज किए गए थे।

देहातो तथा काम दिलाऊ केन्द्रों के दफ्तरो से बहुत दूर के स्थानो मे नौकरी चाहने वाले लोगो की मदद के लिए तेरह काम दिलाऊ केन्द्रो की ओर से चलते फिरते दफ्तर खोले गये। 1952 मे प्रति मास औसतन 6,370 व्यक्तियो को नौकरी दिलाई गई। नौकरी चाहने वालो को गतिशील बनाने मे भी काम दिलाऊ केन्द्र सहायक हो रहे है। प्रति मास देश भर के काम दिलाऊ केन्द्रो मे गतिशील श्रम परिस्थिति विवरण के द्वारा लगभग 2,800 व्यक्तियो के सम्बन्ध मे ब्यौरे प्रचारित किये गये और प्रति मास औसतन 402 से अधिक व्यक्तियों को अपने जिलों से बाहर नौकरी दिलाई गई।

प्रशिक्षण योजनाएं

1946 मे काम दिलाऊ केन्द्रो की ओर से जो प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाये बनाई गई थी, उनमें केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्रौद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

1945 मे काम दिलाऊ केन्द्र इस उद्देश्य से खोले गये कि लड़ाई से छूटे हुये सिपाहियों को नौकरिया दिलाई जाये । अभी यह समस्या निपट नही पाई थी कि शरणार्थियों की समस्या आ गई और 1947 मे उनको काम दिलाने की समस्या इस संस्था के सुपुर्द की गयी । बाद को काम दिलाऊ केन्द्रों का दायरा और बढा दिया गया । इन केन्द्रों के कुछ कार्यों पर नीचे की तालिका मे रोशनी पड़ेगी :

तालिका 155

अवधि	अवधि की समाप्ति पर केन्द्रों की संख्या	अवधि मे पजीकृत हुए व्यक्तियों की सख्या	उन प्रार्थियो की संख्या जिन्हे इस अवधि मे रोजगार दिलवाया गया	उन पजीकृत व्यक्तियो की संख्या जिन्हे अवधि की समाप्ति पर रोजगार नही दिलवाया जा सका था	उन नियोजको की सख्या जो केन्द्रो से लाभ उठा रहे थे	अवधि मे प्रकाशित रिक्त स्थानों की मासिक संख्या	अवधि की समाप्ति पर ऐसे रिक्त स्था जिन्हे भरना शेष था
15 अगस्त, से लेकर दिसम्बर 1947	75	2,07,838	61,729	2,36,734	2,879	97,892	68,756
1948	77	8,68,787	2,59,774	2,39,033	3,422	3,80,118	55,131
1949	110	10,66,351	2,56,809	2,74,335	4,483	3,62,011	29,292
1950	122	12,10,358	3,31,193	3,30,743	5,566	4,19,307	28,189
1951	126	13,75,351	4,16,858	3,28,719	6,364	4,86,534	21,776
1952	128	14 76 699	3,57,828	3,83,992	6,023	4,29,551	22,293
जनवरी से लेकर जून 1953 तक	126	6,95,573	1 05,379	4,73,917	—	1,43,240	22,662

नीचे की तालिका मे प्रति वर्ष की जुलाई मे कितने प्रशिक्षण केन्द्र थे तथा कितने लोगो को प्रशिक्षण दिया जाता था, इसका ब्यौरा दिया जा रहा है

तालिका 156

प्रशिक्षण के आकड़े

(इसके अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की योजनाएं आती है)

माह	अवधि की समाप्ति पर केन्द्रो की सख्या	अवधि की समाप्ति पर उन व्यक्तियो की सख्या जिन्हे प्रशिक्षण दिया जा रहा था				योग
		पुरुष			नारी	
		प्रौद्योगिक	व्याव-सायिक	शिक्षार्थी	व्याव-सायिक	
जुलाई 1948	377	9,178	3,691	1,494	288	15,337
जुलाई 1949	533	10,958	4,571	2,439	255	18,226
जुलाई 1950	98	6,022	1,162	—	322	7,506
जुलाई 1951	199	7,640	2,304	789	390	11,123
जुलाई 1952	106	9,371	476	302	14	10,163
जुलाई 1953	259	7,718	48	572	9	8,347

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था

दस्तकारो को प्रशिक्षित करने के अलावा मध्य प्रदेश के कोनी-बिलासपुर की केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्था शिक्षको तथा इंस्पेक्टरो या निरीक्षको को भी प्रशिक्षित करती है। एशिया मे यह सस्था अपने ढग की एक है, और यहा केवल छ: महीने की शिक्षा दी जाती है। 1952 मे इस सस्था मे 207 व्यक्ति प्रशिक्षित हुए थे। इस प्रकार अब तक कुल 874 व्यक्तियो को यहा प्रशिक्षित होने का अवसर मिला।

राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणीकरण बोर्ड

भारत सरकार ने 1951 मे एक केन्द्रीय बोर्ड इसलिये नियुक्त किया कि वह प्रत्येक विषय मे मानदड नियत करे, परीक्षाए ले तथा कार्यकुशलता के प्रमाणपत्र दे।

शिवाराव समिति

ससद् सदस्य श्री शिवाराव की अध्यक्षता मे प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा संगठन समिति नाम से एक समिति नियुक्त हुई, जिसका काम यह है कि पुनर्वास तथा रोज़गार संगठन के भविष्य सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करे।

औद्योगिक सम्बन्ध

मजदूर संघ

सरकार की औद्योगिक नीति का मूल मत्र यह है कि मज़दूर संघों को ठोस तथा स्वस्थ आधार पर सगठित किया जाये। 1926 की मजदूर संघ विधि के अनुसार पंजीकृत मज़दूर

संघों को एक विधिगत तथा सामूहिक मर्यादा दी गई, और उन्हे मजदूर-पूजीपतियों के झगडों के सम्बन्ध में कुछ विमुक्तिया प्राप्त हुई। मजदूर संघ के कोषों पर जो थोड़ी बहुत रोकथाम रखी गई है उसका उद्देश्य उसे विवेकहीन व्यक्तियो के शोषण से बचाना है। 1947 में एक सशोधित विधि बनी जिसके अनुसार मजदूर संघों की अनिवार्य स्वीकृति, तथा अवैध आचारो के विरुद्ध उपाय बने। पर यह विधि तब तक लागू नही होगी, जब तक कि कुछ मामलों मे सरकार की अन्तिम नीति स्पष्ट नही हो जाती। सरकार ने जो नई नीति अपनाई है, उसका उद्देश्य यह है कि मजदूर संघ अपनी सगठित शक्ति तथा सामूहिक सौदा करने की सामर्थ्य पर निर्भर करे तथा जो समझौते हों उन्हे कार्यान्वित करने मे अपनी कर्मशक्ति का उपयोग करें, न कि सरकार का मुह ताके।

पजीकृत मजदूर सघों तथा उनके कोषों के सम्बन्ध मे नीचे की तालिकाओ मे सारी बाते आ जाती है:

तालिका 157

पंजीकृत संघों की संख्या और सदस्य संख्या 1949-50

मजदूर संघ	सघो की सख्या जो रजिस्टर पर थी	ऐसे संघों की सख्या जो आय-विवरण देते थे	आय-विवरण देने वाले संघो की सदस्य सख्या	
			वर्ष के प्रारम्भ मे	वर्ष के अन्त मे
नियोजको के सगठन	39	29	3,760	4,877
मजदूरो के सगठन	3,483	1,897	18,14,648 (क)	18,16,255 (क)
योग	3,522	1,926	18,18,408	18,21,132

तालिका 158

1949-50 के लिये आय-विवरण देने वाले पंजीकृत मजदूर सघों के सामान्य कोष

(रुपयो में)

	आय विवरण देनेवाले मजदूर संघों की संख्या	प्रारम्भिक अंतर	आय	व्यय	सवरण अन्तर
मजदूर संघ					
केन्द्रीय संघ	40	1,30,693	3,36,192	2,81,204	1,85,681
राज्यीय संघ	1,857	36,19,136	41,02,797	34,63,225	42,58,708
योग .	1,897	37,49,829	44,38,989	37,44,429	44,44,389
नियोजक संघ :					
केन्द्रीय संघ	1	53,804	5,862	3,152	56,514
राज्यीय संघ	28	19,13,689	25,14,719	20,69,247	23,59,161
योग .	29	19,67,493	25,20,581	20,72,399	24,15,675
सर्व योग	1,926	57,17,322	69,59,570	58,16,828	68,60,064

(क) सदस्य सख्या के ये आकडे 1919 के मजदूर संघो से सम्बद्ध है।

इस समय मज़दूर संघ आन्दोलन चार राष्ट्रीय संगठनों में बंटा हुआ है । इस प्रकार से एक ही धंधे में एक से अधिक मज़दूर संघ मौजूद हैं । उद्योग धंधे के एक ही विभाग में विभिन्न और कई बार परस्पर विरुद्ध विचारधाराओं के मज़दूर संघ काम कर रहे हैं । कहना न होगा कि यह परिस्थिति मज़दूर संघ की वृद्धि के लिए हितकर नहीं है । यद्यपि यह सारा मामला मज़दूरों का निजी मामला है, फिर भी सरकार ने बार बार यह बात कही है कि एक धंधे में एक मज़दूर संघ होना वांछनीय है । अब तो मज़दूर संघ के नेता भी इस बात को समझने लगे हैं । भारतीय मज़दूरों के चार राष्ट्रव्यापी संगठनों के साथ कितने-कितने मज़दूर संघ हैं, तथा उनके कितने सदस्य हैं, यह नीचे की तालिका में दिया जा रहा है ।

तालिका 159

अखिल-भारत मज़दूर-संगठन

संगठन	सम्बद्ध संघों की संख्या			सदस्य संख्या		
	1949	1950	1951	1949	1950	1951
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस .	847	1,043	1,232	10,23,117	14,31,878	15,48,56
आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस .	754	722	736	7,41,035	7,30,636	7,58,314
हिन्द मज़दूर सभा .	419	460	517	6,79,287	6,98,720	8,04,33
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	254	306	332	3,31,991	3,66,401	3,84,962
योग	2,274	2,531	2,817	27,75,430	32,27,635	34,96,181

केन्द्रीय श्रम संस्था

1953 के पूर्वार्द्ध में अमेरिका के प्रौद्योगिक सहायता कार्यक्रम के अनुसार यह निर्णय हुआ कि एक केन्द्रीय श्रम संस्था की स्थापना की जाये । इस योजना के कई भाग हैं जैसे—(1) औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्य अजायबघर; (2) औद्योगिक सफाई प्रयोगशाला; (3) प्रशिक्षण केन्द्र तथा (4) पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र । इस प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र का मुख्य कार्य श्रम प्रशासकों तथा इस प्रकार के अन्य लोगों को प्रशिक्षण देना है । श्रम तथा सूचना केन्द्रों में सारी श्रम समस्याओं पर प्रामाणिक सूचनाओं की पूर्ति तथा अध्ययन और शोध की सुविधाएं होंगी । औद्योगिक सफाई प्रयोगशाला स्थापित की गई है, और औद्योगिक अजायबघर खोलने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । इसके अलावा मुक्त मज़दूर संघों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने एक एशियाई मजदूर संघ कालेज स्थापित किया है । यह कालेज एशिया में अपने ढंग का एक है और इसमें तीस प्रशिक्षणार्थियों को तीन महीने प्रशिक्षित किया जाता है । इस कालेज की देख रेख में विभिन्न देशों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू है । जल्दी ही काडला में इसी कालेज की देखरेख में परिवहन कार्यकर्ताओं के लिए एक शिक्षण केन्द्र खोला जायेगा ।

औद्योगिक झगड़े

1939 से औद्योगिक झगड़ों का लेखा इस प्रकार रहा :

तालिका 160

वर्ष	झगड़ों की संख्या		उन मजदूरों की संख्या जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से झगड़ों में फंसे थे		अवधि में व्यर्थ गये दिनों की कुल संख्या
	जो वर्ष में प्रारम्भ हुए	जो वर्ष भर या उसके किसी भाग में चलते रहे	जो वर्ष में प्रारम्भ हुए	जो वर्ष भर या उसके किसी भाग में चलते रहे ।	
1939 .	--	406	—	4,09,189	49,92,795
1940 .	—	322	--	4,52,539	75,77,281
1941 .	—	359	—	2,91,054	33,30,503
1942 .	--	694	—	7,72,653	57,79,965
1943 .	—	716	—	5,25,088	23,42,287
1944 .	--	658	—	5,50,015	34,47,306
1945 .	—	820	—	7,47,530	40,54,499
1946 .	--	1,629	—	19,61,948	1,27,17,762
1947 .	—	1,811	--	18,40,784	1,65,62,666
1948 .	—	1,259	—	10,59,120	78,37,173
1949 .	--	920	--	6,85,457	66,00,595
1950 .	—	814	—	7,19,883	1,28,06,704
1951 .	—	1,071	—	6,91,321	38,18,928
1952	--	963	—	8,09,242	3,33,696
जनवरी से लेकर जून 1953 तक	—	357	—	2,35,801	13,33,547

झगड़ों को रोकने तथा मिटाने का उपाय

1947 की औद्योगिक कलह विधि मे (बाद के सशोधन के साथ) एक सुलह अधिकारी, सुलह बोर्ड, जांच अदालत, औद्योगिक ट्रिब्यूनल तथा श्रम अपीलेट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है । सम्बद्ध सरकारों को तदर्थ ट्रिब्यूनलों की स्थापना का अधिकार दिया गया है । कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने कानून बनाये हैं । बम्बई वाली विधि में दो नई संस्थाओं यानी श्रम अदालत तथा मजदूरी बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्रीय सुलह संगठन

1945 में यह संगठन बनाया गया था । अब इस में 79 अधिकारी हैं जिनमें एक मुख्य श्रम आयुक्त, दो सहायक श्रम आयुक्त, सात क्षेत्रीय आयुक्त, सत्रह सुलह अधिकारी और 52 श्रम निरीक्षकों की व्यवस्था है, जो विभिन्न इलाकों में रहते हैं । कुछ श्रम विधियों के प्रशासन का भार भी इस संगठन पर है । राज्यों में सुलह कराने के अपने अपने साधन हैं ।

औद्योगिक ट्रिब्यूनल

दो औद्योगिक ट्रिब्यूनल हैं—एक धनबाद में तथा दूसरा कलकत्ते में। राज्यों के अपने अपने ट्रिब्यूनल हैं।

श्रम अपीलेट ट्रिब्यूनल

कलकत्ता, बम्बई और लखनऊ में इस ट्रिब्यूनल की शाखाएं हैं। प्रधान दफ्तर कलकत्ता में है।

तदर्थ रेल ट्रिब्यूनल

1953 की जुलाई में एक सदस्यीय रेल ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था जिसके सामने पांच कलहपूर्ण विषय रखे गये। इनका सम्बन्ध कुछ रेल कर्मचारियों के वेतन के ग्रेड और स्केल, छुट्टी तथा दूसरे के एवज में कार्य करत समय के वेतन आदि से था।

अखिल भारतीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल (बैंक के झगड़े)

1953 के अप्रैल में बैंक के झगड़ों पर पहले जो तीन सदस्यों वाला ट्रिब्यूनल बैठाया गया था, उसकी सिफारिश सामने आई। वेतन तथा भत्ता की दृष्टि से ट्रिब्यूनल ने बैंकों को उनके कार्यकारी कोषों के अनुसार चार वर्गों में बांटा है, और उनके कार्यक्षेत्र को रहन-सहन के व्यय की विभिन्नता के अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा है। प्रत्येक वर्ग के लिए समय सम्बन्धी स्केल तथा श्रम के घंटे निर्दिष्ट कर दिये गये हैं। निर्वाह निधि, बोनस, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, छुट्टी, छटनी के लिए क्षतिपूर्ति तथा भर्ती, तबादला और अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई के सम्बन्ध में सिफारिशें की गई।

इसी प्रकार प्रतिरक्षा विभाग के श्रमिकोंकी शिकायतों पर प्रतिवेदन देने के लिये जांच समिति की सिफारिशें मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। सरकार ने कोयले की खानों के मजदूरों की कुछ शिकायतों को भी एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल के सामने रखने का फैसला कर लिया है। एक ऐसे ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रयास हो रहा है।

त्रिदलीय यंत्र

कुछ सालों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के नमूने पर देश भर में सरकार, पूंजीपति तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के सगठन काम करते रहे हैं। इन सगठनों का होना हितकर पाया गया है और अब वे देश की औद्योगिक नीति के एक अंग हो गये हैं। इन लोगों ने समझौते की भावना, शुभेच्छा, पारस्परिक विश्वास उत्पन्न कर के बडी कठिन तथा जटिल समस्याओं को सुलझाया है।

त्रिदलीय ढग के महत्वपूर्ण सगठनों में यह हैं—भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति और विविध औद्योगिक तथा परामर्श समितियां। अधिकांश राज्यों में इसी ढग पर स्वतन्त्र त्रिदलीय यंत्र हैं। 1953 की 27 और 28 जुलाई को स्थायी श्रम समिति का अधिवेशन हुआ था। उसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार हुआ और इच्छा के विरुद्ध बेकारी तथा छटनी के सम्बन्ध में उन्होंने एक स्वीकृत सूत्र विकसित किया, जिसके द्वारा क्या रकम दी जायेगी तथा कितने समय के लिये लाभ होगा, यह बताया गया था। यद्यपि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को त्रिदलीय सगठन नहीं कहा जा सकता, पर वह घनिष्ठ रूप से संयुक्त तो है ही। 1953 की छः और सात फरवरी को इनका दसवां अधिवेशन हुआ और इसमें, औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

[पृष्ठ 358 पर जारी]

1950-51 मे केन्द्रीय कारखानो मे 323 कार्य समितियां थीं । 1951 के 30 सितम्बर को जितनी कार्य निर्वाहक और उत्पादन समितियां थी, उन का लेखा इस प्रकार है—

तालिका 161

कार्य और उत्पादन समितियो की सख्या 30 सितम्बर, 1951 को

अनुक्रम	बम्बई		बिहार		मद्रास		उडीसा		पंजाब		पश्चिमी बंगाल	
	का	उ	का	उ	का	उ	का	उ	का	उ	का	उ
1. कागज मिलें	30 (क)	7 (क)	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
2 काच के कारखाने	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
3 विद्युत संस्थान	5	3	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–
4 चीनी के कारखाने	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
5 तेल मिले	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
6 कुम्हार का काम	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
7 छापाखाने	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1
8 कपडा मिले	–	45	–	2	–	–	1	–	25	13	28	5
9 चावल मिले	–	–	–	–	–	–	11	2	–	–	–	–
10 इंजीनियरिंग और धातुएं	69	20	–	7	–	–	–	–	17	5	8	11
11 रासायनिक	39	17	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
12 खाद्य, पेय और तबाकू	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
13 खाले और चमडा	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
14 सीमेंट	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
15 दियासलाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16 यातायात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17 विविध	85	22	102	4	–	–	1	2	56	35	34	2
योग	245	115	102	20	486 (ख)	200 (ख)	20	5	98	53	78	23

अनुक्रम	हैदराबाद		मध्यभारत		पेप्सू		राजस्थान		सौराष्ट्र		अजमेर		भोपाल		दिल्ली		हिमाचल प्रदेश	
	का	उ	का	उ	का	उ	का	उ	का	उ	का	उ	का	उ	का	उ	का	उ
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–
8	–	–	1	–	–	–	4	–	5	–	4	4	–	–	4	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–
11	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	–	–	–	2	–	20	–	4	–	–	–	1	–	11	–	7	8
योग	2	–	1	–	6	–	35	–	15	–	5	4	2	–	40	–	7	8

का-कार्य समितिया उ-उत्पादन समितिया

(क) इसमें छापाखाने भी शामिल हैं । (ख) उद्योगवार वितरण अप्राप्य है ।

तथा ऐसे प्रश्न जैसे--चाय बागानों मे फालतू श्रम, फैक्टरी इस्पेक्टरेट का तगडा किया जाना तथा निजी कारखानो मे चिकित्सा निरीक्षको का नियुक्ति ग्रौर राष्ट्रीय छुट्टियो तथा त्यौहार के लिये भुगतान के एक एकीभूत मानदण्ड पर विचार हुग्रा ।

संयुक्त समितियां

मालिको ग्रौर मजदूरो की कार्य निर्वाहक समितिया झगडो को निपटाने मे प्रारम्भिक स्थिति मे बहुत काम कर सकती है । ये समितिया मुख्यत: मुक्त तथा खुले वाद-विवादो के द्वारा परस्पर के दृष्टिकोण को समझ सकती है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे 1947 की ग्रौद्योगिक विधि तथा ग्रन्य कानूनो के ग्रनुसार समय समय पर सौ या उससे ग्रधिक मजदूरो को काम मे लगाने वाले कारखानो मे मालिक मजदूर समितियो का निर्माण करवा सकती है ।

(देखिये पृष्ठ 356-57 पर तालिका 161)

औद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी आज्ञापत्र

स्थायी ग्राज्ञापत्रो मे पहले से सेवा की ग्रवस्थाए, कार्य की प्रगति, काम के घन्टे, छुट्टिया, मजदूरी का भुगतान, मजदूरी मे किसी तरह की कमी करने के नियम ग्रौर ग्रनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के विषय मे बातें ही होती है । पहले से ये नियम बने होने से मनमुटाव तथा झगड़े के कारण कम मे कम हो जाते है । 1946 की ग्रौद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी ग्राज्ञापत्र विधि के ग्रनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को इस बात का ग्रधिकार प्राप्त है कि वे ग्रादर्श नियम बनावे । तदनुसार इन सरकारो ने ग्रादर्श नियम बनाये है, ग्रौर सौ या उससे ग्रधिक मजदूर वाले कारखानो मे वे चाहती है कि ये नियम लागू कर दिये जाये । उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो यह ग्राज्ञा दी है कि जिन कारखानो मे सौ से कम व्यक्ति काम करते हों वे भी ग्रपने यहा के स्थायी ग्राज्ञापत्र की पद्धति चालू करें । ग्रासाम सरकार ने तो इस विधि को ऐसे कारखानो मे जिनमे दस या उससे ग्रधिक लोग काम करते है, लागू कर दिया है ।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

ग्रस्थायी ससद मे जो ग्रौद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पेश किया गया था वह ग्रस्थायी ससद के समाप्त हो जाने पर स्वय समाप्त हो गया । केन्द्रीय सरकार ने इस मौके से फायदा उठाया, ग्रौर इस बीच में जो ग्रालोचनाए हुई थी, उनकी रोशनी मे विधेयक पर विचार किया गया । जून 1952 मे एक व्यापक प्रश्नपत्र गश्ती रूप से घुमाया गया । ग्रक्तूबर 1952 के भारतीय श्रम सम्मेलन मे इस प्रश्न पर विचार भी हुग्रा । दिसम्बर 1952 मे सात व्यक्तियो की एक समिति मे इसकी ग्रौर छानबीन भी की गयी । इस के बाद केन्द्रीय सरकार के रोजगार वाले मंत्रालयों ने इस पर विचार किया । फिर फरवरी 1953 में श्रम मंत्रियो के सम्मेलन में इसके सब पहलुग्रों पर विचार हुग्रा । इन वाद-विवादो तथा ग्रालोचनाग्रो के फलस्वरूप यह विधेयक ग्रब ग्रतिम रूप मे है, ग्रौर शायद संसद मे शीघ्र ही पेश हो ।

मजदूरी और उपार्जन

मजदूरों के जीवन में मजदूरी ग्रोर उपार्जन को बहुत ग्रधिक महत्व प्राप्त है, ग्रौर यह तो कहने की ग्रावश्यकता है ही नही कि मजदूरी का ग्रसर ग्रौद्योगिक सद्भाव तथा उत्पादनक्षमता पर पड़ता है । 1939 के बाद से कारखाने के मजदूरो के उपार्जन में वृद्धि हुई है, यह इन ग्रांकड़ों से ज्ञात होगा ।

इस विधि पर 1950 मे किस प्रकार से काम हुआ है, यह निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है ।

तालिका 162

राज्य	उन सस्थानों की अनुमानित सख्या जिन पर वह कानून लागू होता था	स्थायी आदेशो के प्रमाणीकरण के लिये आए प्रार्थना-पत्रो की सख्या		उन प्रार्थना पत्रो की सख्या जिनका वर्ष मे निबटारा कर दिया गया	31-12-50 को ऐसे संस्थानो की सख्या जिन्हे प्रमाणीकृत स्थायी आदेश प्राप्त थे	31-12-49 को ऐसे संस्थानो की कुल संख्या जिन्हें प्रमाणीकृत स्थायी आदेश प्राप्त थे
		जो वर्ष के आरम्भ मे विचाराधीन थे	जो उसी वर्ष प्राप्त हुए			
आसाम	638 (क)	55	7	6	561	555
बिहार	180 (ख)	74	26	48	85	37
बम्बई	556	138	88	10	10	कुछ नही
मध्य प्रदेश	115	—	11	11	11	—
मद्रास	739	245	196	293	566	273
उडीसा	22	6	2	5	7	2
पंजाब	130	3	69	16	16	कुछ नही
उत्तर प्रदेश	701 (ग)	346	100	65	413 (घ)	348 (घ)
पश्चिमी बगाल	1,131	191	96	182	872	690
अजमेर	6	1	—	1	6	5
कुर्ग	7	4	11	15	76	61
दिल्ली	34	10	1	3	21	18
केन्द्रीय क्षेत्र के कार्य	1,424	73	116	62	375	313

(क) इस मे 149 ऐसे सस्थान भी शामिल हे जिन मे सौ से कम मजदूर काम करते हे, परन्तु जो इस कानून की धारा 1 (3) के अन्तर्गत आ जाते हे ।

(ख) लगभग ।

(ग) इस मे 422 ऐसे संस्थान भी शामिल हे जिन मे सौ से कम मजदूर काम करते हें, परन्तु जो इस कानून की धारा 1 (3) के अन्तर्गत आ जाते हे ।

(घ) इस मे 56 ऐसी चीनी फैक्ट्रियां भी शामिल हे जिन के स्थायी आदेश, इस कानून के अधीन प्रमाणीकृत कर दिये गये थे, परन्तु जिन्हें आगे चल कर इसलिए छूट प्रदान कर दी गयी थी कि उन के स्थायी आदेशों का उत्तर प्रदेश औद्योगिक कलह कानून, 1947 के अधीन निबटारा हो चुका था ।

तालिका 163

उन फैक्ट्री मजदूरों की औसत वार्षिक आय जिनकी मासिक आय 200 रुपये से कम है (ग)

राज्य	1939	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951 (क)
आसाम	263.7	660.5	687.5	755.5	795.8	942.8	1,018.6	1,017.9
बिहार	415.5	538.7	544.0	819.8	946.2	983.9	1,059.1	1,239.3
बम्बई	370.4	814.7	812.3	977.9	1,141.9	1,210.1	1,170.3	1,270.5
मध्य प्रदेश	...	530.6	479.7	572.3	609.2	841.9	936.8	862.0
मद्रास	175.9	357.6	422.2	560.3	611.8	726.6	591.2	664.9
उड़ीसा	161.8	417.2	440.1	493.6	612.6	527.0	680.6	749.1
पंजाब	296.0	578.8	602.0 (ख)	628.2	675.9	858.7	771.3	756.0
उत्तर प्रदेश	235.6	551.7	593.6	672.8	887.1	993.0	933.0	960.4
पश्चिमी बंगाल	248.7	465.5	496.3	567.7	723.9	839.0	877.5	942.3
अजमेर	163.7	419.8	447.8	445.3	527.2	552.0	660.0	694.2
दिल्ली	309.4	699.9	837.2	877.7	1,047.3	1,028.4	1,061.6	1,292.6
तिरुवांकुर-कोचीन	...	...	...	...	...	...	...	632.1
अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह (ख)	...	...	...	...	...	...	732.9	718.1

(क) अस्थायी ।

(ख) अनुमानित ।

(ग) इसमें, रेलवे वर्कशाप के अतिरिक्त, खाद्य, पेय, तम्बाकू, रुई की ओटाई और गांठ बंधाई सम्मिलित नहीं हैं ।

मजदूरी भुगतान विधि 1936

इस विधि के अनुसार मजदूरी नियमित रूप से देना तथा उसमें से किस प्रकार की कितनी कमी की जा सकती है, इस सम्बन्ध में नियम दिये गये हैं। यह उन मजदूरों पर लागू है जो प्रति मास 200 रुपये या उससे कम पाते हैं। इस विधि के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी औद्योगिक कारखाने तक इस विधि का विस्तार करे तथा उसके निरीक्षण के लिये निरीक्षक नियुक्त करे। सच तो यह है कि यह विधि रेलों, खानों, कारखानों, बगानों, कुछ राज्यों की कुछ विशेष परिवहन सेवाओ तथा अन्य व्यवसाय केन्द्रो तक प्रसारित की जा चुकी है।

न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी विधि 1948

विभिन्न ढंग के निर्णयपत्रों, समझौतों, विभिन्न अनुसंधान समितियों की सिफारिशों तथा केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अनेक धन्धो मे लगे हुए मजदूरो की कम से कम मजदूरी तय कर दी गयी है। न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी विधि का महत्व यह है कि इसके द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह ऐसे कई कम मजदूरी वाले धन्धो के लिये न्यूनतम अनुविहत मजदूरी निर्दिष्ट करे, जिनमें अपनी मागों को मनवा सकने की सांगठनिक शक्ति बहुत कम है। विभिन्न राज्यो मे अनुसूची के भाग एक के अन्तर्भुक्त कई तरह के श्रमो के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट है। एक संशोधन के अनुसार सब राज्यो के लिये यह जरूरी कर दिया गया है कि वे इस वर्ग के लिये 31 दिसम्बर 1953 तक न्यूनतम मजदूरी तय कर दे। खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी भी इसी अवधि मे निर्दिष्ट होने वाली थी। कुछ राज्यों ने जैसा कि वे इस विधि के अनुसार कर सकते हैं कई ऐसे धन्धों पर भी इस विधि को लागू कर दिया है, जिनका उल्लेख विधि में नही है।

सरकार ने कई धन्धो के सम्बन्ध मे उचित मजदूरी निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध मे एक कदम उठाने की सोची है। अस्थायी संसद् के विलय हो जाने पर उचित मजदूरी विधेयक भी समाप्त हो गया। इस पर और भी विचार हो रहा है, और ऐसी आशा की जाती है कि जल्दी ही अंतिम राय प्राप्त होगी। 1946 की औद्योगिक सम्बन्ध विधि के अनुसार कपास तथा रेशम के कारखानों में मजदूरी को एक सतह पर लाने के लिये बम्बई में मजदूरी बोर्ड स्थापित हुए हैं। 1948 की कारखाना विधि तथा 1952 की खान विधि के अनुसार समयानन्तर (ओवर टाइम) कार्य के लिये भुगतान का दर मामूली से दुगुना निश्चित हुआ है।

कोयले की खानों की बोनस सम्बन्धी योजना

मजदूरों की बोनस सम्बन्धी मांग सैद्धान्तिक रूप से मान ली गयी है। रहा यह कि रकम क्या हो इसका निर्णय औद्योगिक अदालतों तथा सुलह बोर्डों पर छोड़ा हुआ है। कोयले की खानों की बोनस सम्बन्धी योजना के अनुसार खानों में काम करने वाले मजदूरों का बोनस पाना निश्चित है, और इस सम्बन्ध में रकम का निर्णय भी उन लोगों के आधारभूत उपार्जन पर होता है, जो इसके हकदार हैं।

बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश के कुछ कोयले की खानो मे 1950–51 मे कितने मजदूर थे, तथा उन्हे कितना बोनस मिला यह नीचे दिखाया गया है—

तालिका 164 (क)

त्रैमास की समाप्ति का माह	उन कोयला-खानों की सख्या जो आय विवरण देती हैं	आय विवरण देने वाली कोयला खानो मे काम कर रहे मजदूरो की सख्या	उन मजदूरो की सख्या जिन्होने बोनस पाने का अधिकार प्राप्त किया	वितरण किये गये बोनस की राशि
बिहार				
जून 1950 .	165	1,29,919	58,178	11,19,898
सितम्बर 1950	89	79,803	39,799	8,03,150
दिसम्बर 1950	113	89,520	40,981	7,62,199
मार्च 1951 .	80	73,235	40,909	8,59,876
पश्चिमी बंगाल				
जून 1950 .	93	1,04,814	31,640	5,67,006
सितम्बर 1950	42	31,956	10,664	1,92,688
दिसम्बर 1950	58	48,185	14,244	2,53,878
मार्च 1951 .	37	24,344	6,414	1,08,113
मध्य प्रदेश				
जून 1950 .	45	40,744	14,998	3,16,252
सितम्बर 1950	23	27,868	12,363	2,23,652
दिसम्बर 1950	22	35,718	13,493	2,97,936
मार्च 1951 .	17	16,164	6,967	1,30,549

लागत और रहन सहन का मानदण्ड

रहन सहन के बढ़े हुए मूल्य का मजदूरों के जीवन पर क्या असर पड़ा इसका अंदाज लगाने के लिये विभिन्न सूत्रों से आवश्यक सामग्री तैयार होती है। केन्द्रीय सरकार ने अपने श्रम ब्यूरो के जरिये से रहन सहन के मूल्य सूचक अंकों के सोलह वर्ग तैयार किये है, और इस कार्य के लिये 1944 या 1939 आधारभूत वर्ष माना गया है। इसी प्रकार से कुछ राज्य सरकारें कुछ विशेष वर्ग के मजदूरों के लिये रहन सहन के मूल्य सम्बन्धी सूचक अंक तैयार कर रही है। नियमित रूप से ये अंक सरकारी गजटों में प्रकाशित होते हैं। इस के अतिरिक्त कुछ राज्यों में मजदूरों के पारिवारिक बजटों के सम्बन्ध में भी कुछ अनुसन्धान किया जाता है। तालिका 165 तथा 166 में 1945 से लेकर सारे भारत तथा सोलह चुने हुए स्थानों के लिये रहन सहन के सूचक अंक या देशनांक दिये जाते हैं :

(क) प्रादेशिक श्रम आयोग (केन्द्रीय) धनबाद द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित।

तालिका 165

मजदूर-वर्ग के रहन-सहन के मूल्य का अखिल भारतीय औसत देशनांक

(आधार : 1944=100)

1944	100
1945 (औसत)	100
1946 ,,	106
1947 ,,	120
1948 ,,	134
1949 ,,	138
1950 ,,	138
1951 ,,	144
1952 ,,	141

तालिका 166

श्रम ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत मजदूर-वर्ग के रहन-सहन के मूल्य का देशनांक

(आधार : 1944=100)

केन्द्र	वार्षिक औसत						
	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951
1. दिल्ली	103	108	122	132	132	132	142
2 अजमेर	110	118	152	161	161	168	178
3 झरिया	97	122	139	153	159	182	184
4. देहरी	99	131	158	171	170	185	197
5 जमशेदपुर	100	103	123	136	138	145	160
6. मुंगेर और जमालपुर	105	132	153	166	171	193	188
7. कटक	102	106	117	134	147	163	181
8. बरहमपुर	101	111	126	145	154	162	190
9. गौहाटी	90	86	97	117	128	126	141
10. सिलचर	92	96	110	132	138	146	159
11. तिनसुकिया	94	83	93	109	110	114	124
12. अकोला	98	107	139	156	168	162	165
13. जबलपुर	95	101	123	146	151	153	168
14. लुधियाना	105	119	142	168	164	165	167
15. खड़गपुर	97	100	111	132	137	137	136
16. मरकारा-(क)	–	–	–	–	111	116	118

(क) बग़ान मजदूरों के लिए अन्तरिम शृंखला (आधार: जुलाई से दिसम्बर 1948=100)

षि सम्बन्धी श्रम के विषय में जांचपड़ताल

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर खेतिहर मज़दूरों की अवस्था के सम्बन्ध ' एक राष्ट्रव्यापी जांचपड़ताल का सूत्रपात किया था। इस का उद्देश्य रोज़गार, पार्जन तथा रहन सहन के मूल्य और मानदण्ड पर तथ्य एकत्र करना था। कुल मिलाकर मने के गांव मे रहने वाले एक लाख चालीस हजार परिवारों का पर्यवेक्षण किया गया। नमूने ; गांव में खेतिहर तथा गैरखेतिहर परिवारों का अनुपात 78 और 22 का था।

सामाजिक सुरक्षा

जिन उपायों से देश के औद्योगिक मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है वे यों हैं– म्प्लाईज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, 1948; प्रौविडेन्ट फंड ऐक्ट, 1952; कोल माइन्स प्रौविडेन्ट ंड एण्ड बोनस स्कीम ऐक्ट 1948; वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट 1923; और मैटरनिटी बेनिफिट क्ट, इन विषयों का कुछ ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

एम्प्लाईज़ स्टेट इन्श्योरेन्स ऐक्ट

यह विधि दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने ढंग की सबसे पहली है। 1951 मे इस मे सशोधन सलिये किया गया कि दिल्ली तथा कानपुर के मालिको ने उत्पादन की बढ़ी हुई लागत की ाकायत की थी। इस विधि की व्यवस्थाएं देश के विभिन्न स्थानों मे दर्जाबदर्जा लागू की जाती ही है।

ेत्र

यह विधि उन सब स्थायी कारखानों पर लागू है, जिनमे विद्युत का प्रयोग होता है और हा बीस या उससे अधिक लोग काम करते है। मज़दूर चाहे सीधे रखे गये हों या परोक्ष प से, उन सब पर तथा क्लर्कों पर भी यह विधि लागू है। यह विधि उन लोगों पर लागू हीं है जिनका वेतन 400 रुपये मासिक से अधिक है। सेना के लोग इस विधि ं नहीं आते।

प्रशासन

इस योजना का प्रशासन एम्प्लाइज स्टेट इन्शोरेन्स कारपोरेशन के द्वारा होता है। इस ारपोरेशन के 38 सदस्य हैं, जिनमें मज़दूर, मालिक, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा डाक्टरी शे के लोग तथा संसद-सदस्य हैं। इनमें से भी तेरह सदस्यों की एक स्थायी समिति है, जिस पर ाधारण प्रशासन का भार है। एक मैडिकल बेनिफिट कौंसिल भी है, जिस के 28 सदस्य हैं। ह कारपोरेशन को चिकित्सा सम्बन्धी हितों पर सलाह देती है। कारपोरेशन का प्रबन्धकर्ता ायरेक्टर जनरल है। इसके आधीन चार मुख्य अधिकारी हैं। डायरेक्टर जनरल क्षेत्रीय था स्थानीय दफतरों के जरिये से काम करता है। क्षेत्रीय सलाहकारी बोर्ड में मालिकों, मज़दूरों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।

अनुदाय

अनुदाय की दृष्टि से विधि में जो लोग आते हैं, उन्हें आठ वर्गों में बांटा गया है और उनके अनुदाय का दर तथा उनके तथा उनके मालिकों के अनुदाय का दर एक अनुसूची में निश्चित किया गया है। जिन मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन एक रुपये से कम हो, उन्हें कुछ नही देना पड़ता, पर उनके मालिक अनुदाय देने से बरी नहीं हैं। अनुदाय के ये दर एक संशोधित विधि में निर्दिष्ट अनुदाय में परिवर्तित कर दिये गये हैं। यह तब तक चालू रहेगा, जब तक सारा देश योजना के अन्तर्गत नही आ जाता। सशोधित विधि के अनुसार सारे देश के मालिकों को मजदूरी के कुल बिलों का 0.75 प्रतिशत विशेष अनुदाय देना पडता है। पर जिन इलाको में मजदूर कल्याण सम्बन्धी नियम लागू हो चुके हैं, वहा के मालिकों को मजदूरी मे दिये हुए अपने बिलों का 1.25 प्रतिशत अनुदाय देना पडेगा। बात यह है कि यहा इन लोगो को मजदूरों की क्षतिपूर्ति विधि तथा मातृमंगल विधि के अनुसार क्षतिपूर्ति देनी नही पड़ती। जिन इलाकों मे यह योजना अभी लागू नही हुई है वहा के मजदूरो को कुछ भी देना नही पडता। सबसे ताजे आंकड़ो से ज्ञात होता है कि दो करोड रुपये से अधिक अनुदाय के रूप में प्राप्त हो चुके है जिस मे से मालिको से 174 लाख रुपये और मजदूरों से 39 लाख रुपये प्राप्त हुए है। इस विधि मे जिन लोगो की व्यवस्था है वे इस प्रकार है—(1) बीमारी के लाभ, (2) मातृ मंगल, (3) पगु हो जाने पर लाभ, (4) आश्रित लोग सम्बन्धी लाभ, और (5) चिकित्सा सम्बन्धी लाभ।

चिकित्सा सम्बन्धी लाभ

बीमा किये हुए लोगो को बीमारी की हालत में चिकित्सा सम्बन्धी लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा तथा दवा मुफ्त होती है। इस समय केवल बीमा किये हुए लोगों को ही चिकित्सा सम्बन्धी लाभ प्राप्त हैं, पर यदि कारपोरेशन तथा राज्य सरकारे सम्भव समझे तो वे ये लाभ उन लोगो को भी मिल सकते हैं जो बीमा किये हुए नही हैं।

बीमारी के लाभ

यदि एक बीमा किये हुए व्यक्ति ने छः महीने की अपनी अनुदाय अवधि मे कम से कम बार अनुदाय दिये हैं तो बीमारी की हालत मे उसे बीमारी के लाभ प्राप्त होंगे। इसका रूप यह होगा कि 365 दिनों तक लगातार काम करने पर अधिक से अधिक आठ सप्ताह का नकद वेतन मिलेगा। यह दर मोटे तौर पर उसकी औसत मजदूरी का 7/12 है।

मातृमंगल लाभ

स्त्रियों को मातृत्व लाभ इस रूप मे दिया जाता है कि उन्हे बारह सप्ताह की छुट्टी मिलती है। इन बारह सप्ताहो मे से प्रसव की सम्भव तारीख के पहले छः सप्ताह से अधिक छुट्टी नही मिल सकती। इस समय के लिये प्रति दिन बारह आने या बीमारी के लाभ के दर से, इनमें से जो भी अधिक हो उस दर से पैसे मिलते हैं।

पर लाभ

यदि कोई बीमा किया हुआ व्यक्ति काम करते हुए चोट खा जाये और उसके फलस्वरूप पंगु हो जाये तो उसे समय समय पर सहायता दी जाती है। सामयिक रूप से पंगु हो जाने की

अवधि के लिये लगभग आधी औसत मजदूरी दी जाती है। यदि व्यक्ति पूरे तरीके से पंगु हो जाये, तो मजदूरों की क्षतिपूर्ति विधि के अनुसार एक मुश्त रकम दिये जाने के बजाय बीमा किये हुए लोगों को उपार्जन सामर्थ्य में जिस अनुपात में हानि हुई है उस अनुपात से आजीवन पेंशन पाने का अधिकार है।

आश्रितों के लाभ

यदि कोई बीमाशुदा व्यक्ति काम करते समय चोट के फलस्वरूप मर जाये, तो उसके आश्रित लोगों को कुछ लाभ दिये जाते हैं। यह लाभ बीमा किये हुए व्यक्ति के बच्चो तथा स्त्री को दिये जाते हैं—पूरे दर के 3/5 मृत व्यक्ति की विधवा को तब तक मिलता है, जब तक कि वह फिर से शादी नही करती। पूरे दर का 2/5 प्रत्येक वैध तथा गोद लिये हुए लड़के को पंद्रह साल की उम्र तक मिलता है तथा पूरे दर का 2/5 प्रत्येक वैध अविवाहित लडकी को पंद्रह साल की उम्र तक मिलता है। मजदूरों के राज्य बीमा निगम की ओर से दिल्ली तथा कानपुर के मजदूरों को किस प्रकार का कितना लाभ 1953 के 30 सितम्बर तक दिया गया, उसका लेखा इस प्रकार है :—

वे बीमार जिनकी दवाखानो मे देखभाल की गयी	16,10,028
वे बीमार जिनके विषय मे अस्पतालों से राय मागी गयी	1,801
विशेष जाच	14,463
कितनी बार बीमारों के घर जाया गया	16,951
रुग्णता सम्बन्धी लाभ	11,25,987 रु०
अस्थायी अपागता लाभ	1,64,828 रु०
स्थायी अपागता लाभ	6,137 रु०
आश्रितो को लाभ	3,954 रु०
मातृ मंगल लाभ	1,866 रु०

योजना की प्रगति

पहले पहल यह योजना 24 फरवरी 1952 को दिल्ली और कानपुर मे लागू की गई। इस में डेढ़ लाख मजदूर और 1,200 मालिक आ गए। दूसरी स्थिति तब सामने आयी, जब 17 मई 1953 को पंजाब में इसका प्रवर्तन किया गया। यह इन नगरो मे लागू है अमृतसर—(छहारटा का नोटिफाइड एरिया भी आ जाता है) अम्बाला, जालन्धर, लुधियाना अब्दुल्लापुर, जगाधरी, बटाला और भवानी जहा तीस हजार मजदूर हैं। इस योजना को बम्बई, पश्चिमी बगाल, मद्रास, मैसूर और मध्य प्रदेश में लागू करने का विचार है। पश्चिमी बंगाल में हावड़ा जिला तथा कलकत्ता में एक योजना चालू करने का प्रस्ताव है। हाल ही में पश्चिमी बगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय ने मजदूरों के राज्य बीमा निगम के पश्चिमी बंगाल बोर्ड का उद्घाटन किया। इस से कलकत्ता और हावड़ा जिले के लगभग दो लाख चालीस हजार मजदूरो को लाभ होगा। जब अन्त तक यह योजना सारे राज्यों में लागू हो जायेगी, तो छः लाख औद्योगिक मजदूरों को फायदा पहुचेगा। मद्रास सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोयम्बटूर चुना है।

12 नवम्बर 1953 को यूनियन सरकार के श्रम मंत्री ने मद्रास क्षेत्रीय बोर्ड का उद्घाटन किया। मैसूर सरकार बंगलोर में चिकित्सा सम्बन्धी लाभ देने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रही थी। मध्य प्रदेश ने एक प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी को दिल्ली, कानपुर और पंजाब में इस योजना का अध्ययन करने तथा नागपुर में कार्यान्वित करने की संभावनाओं की रिपोर्ट देने का भार सौंपा है। यह आशा की जाती है कि यह योजना 1954 में उन सब औद्योगिक क्षेत्रों मे लागू की जाएगी, जहां पांच हजार या अधिक मजदूर हैं।

एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड ऐक्ट

1952 में यह विधि पारित हुई थी। 1953 के अक्तूबर मे राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश निकाल कर इसे संशोधित किया। अध्यादेश में उदारतर पैमाने पर कुछ उद्योग धन्धों को इससे मुक्त कर दिया गया है। साथ ही प्राविडेन्ट फंड या निर्वाह निधि के निरीक्षण की भी व्यवस्था है। यह विधि छः प्रधान धन्धों—सीमेंट, सिगरेट, वैद्युतिक, यान्त्रिक तथा साधारण इजीनियरिंग, लोहा और इस्पात, कागज और कपड़े पर लागू होगी बशर्ते कि उसमे पचास या उस से अधिक व्यक्ति काम में लगे हों। सरकार तथा स्थानीय अधकारियो की देख-रेख मे चलने वाले उद्योग धन्धे तथा वे धन्धे जिन को आरम्भ हुए अभी तीन साल नही हुए इस विधि के दायरे के बाहर हैं। अब 1,643 कारखाने (जिन मे से 473 बरी हैं और 1,170 बरी नही हैं) तथा 13,63,000 मजदूर (जिन मे से 8,16,000 बरी हैं और 5,47,000 ऐसे कारखानो मे हैं जो बरी नही हैं) इस विधि मे आ जाते हैं। अब तक इस आवश्यकता को पूरा न करने के कारण सत्रह मालिकों पर मुकदमा चलाया गया।

अनुदाय

इस कोष मे मालिकों का अनुदाय मुलाजिमो को दी जाने वाली आधारभूत मजदूरी तथा महंगाई भत्ता का 6¼ प्रतिशत होगा। मुलाजिमो से भी यह आशा की जाती है कि मालिक जितनी रकम देंगे वे भी उतनी ही रकम देगे; वे चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हैं। पर किसी भी हालत मे आधारभूत मजदूरी और महगाई भत्ते के 8⅓ प्रतिशत से अधिक नही दे सकते।

प्रशासन

इस विधि के अनुसार ट्रस्टियों का एक बोर्ड स्थापित किया गया है और एक केन्द्रीय प्राविडेन्ट फंड या निर्वाह निधि आयुक्त नियुक्त हुआ है। इस कोष का प्रशासन 1954 के अन्त तक विकेन्द्रित हो जायेगा। राज्य बोर्डों के स्थापित होते ही यह कार्य स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जायेगा।

कोयले की खान की प्राविडेंट फंड और बोनस योजना विधि

कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों के प्राविडेन्ट फंड की योजना उल्लिखित विधि के अनुसार दिसम्बर 1948 मे बनाई गई थी। और यह इसके बाद पश्चिमी बगाल, बिहार,

उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अनुदर्शी रूप से लागू होगी। कुछ मामूली संशोधनों के साथ बाद मे यह विधि आसाम, रीवा, तलचर, कोरिया और मध्य प्रदेश के आंशिक रूप से बहिर्भूत इलाकों में लागू की गई है। योजना को बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के आंशिक रूप से बहिर्भूत इलाकों को कोयले की खानों में लागू किया गया है। हैदराबाद, सौराष्ट्र और राजस्थान में इसे लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

इस योजना के अनुसार बोनस पाने का अधिकारी प्रत्येक मुलाज़िम कोयले की खान सम्बन्धी बोनस योजना के अनुसार त्यों ही बोनस पाने का अधिकारी हो जाता है, ज्यों ही वह बोनस पाने का अधिकारी होने के बाद अगली तिमाही मे पदार्पण करता है। आयु के विभिन्न वर्गों मे अनुदाय के विभिन्न दर तय किये गये हैं। अनुदाय मासिक तथा साथ ही साप्ताहिक रूप में देने की व्यवस्था है। 1952 के दिसम्बर तक मालिकों और मुलाज़िमों की तीन करोड़ रुपये की रकम इस कोष में जमा हो चुकी थी। कोयले की खानो के निर्वाह निधि आयुक्त जो साथ ही कोष के मुख्य प्रबन्धकर्ता है नियुक्त किये जा चुके हैं। प्राविडेन्ट फड की योजना को लागू करने के लिए कुछ इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये है, 1951 के 31 मार्च को अन्त होने वाले वर्ष मे अधिकारियों और निरीक्षकों ने 1,627 कोयले की खानों का निरीक्षण किया। सितम्बर 1951 के अन्त तक शर्त पूरी न कर पाने वाले खान मालिकों से जवाबतलबी करते हुए तीन सौ नोटिसे दी गई थी, और 150 के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई थीं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि कोयले के सभी बडे कार-खानों में यह योजना लागू की जा चुकी है। यह पता लगा है कि यह योजना जनप्रिय सिद्ध हुई है।

मजदूरों की क्षतिपूर्ति विधि 1923

इस विधि के अनुसार काम करते समय लगी हुई चोटो, पेशे के कारण उत्पन्न रोग तथा इस प्रकार की चोटों और रोगों से होने वाली मृत्युओ के लिए क्षति-पूर्ति देने की व्यवस्था है। यदि मजदूरों को यह चोट शराब पीने की वजह से या किसी ऐसे नियम को जानबूझ कर न मानने की वजह से आई है जो खतरो से बचाव वाली हिदायत के रूप मे है, तो मालिक उस हालत मे क्षतिपूर्ति देने के लिए मजबूर नही है। यदि चोट सात ही दिन या उससे कम रही है, तो भी कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। अब तक मजदूरो के सत्ताइस वर्ग इस विधि के अन्तर्भुक्त किये गए हैं। पेशे के कारण उत्पन्न ऐसे रोगो की सूची जिन मे क्षतिपूर्ति दी जाती है, विधि मे दी हुई है। राज्य सरकारों को उचित नोटिस देने के बाद इस सूची मे इजाफा करने का अधिकार है।

क्षतिपूर्ति की राशि

यदि कोई नाबालिग मर जाये या बिलकुल पंगु हो जाये, तो उस के लिए क्रमशः 200 तथा 1,200 रुपये की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

इस विधि मे मजदूरों के हितों की उचित रूप से रक्षा की गई है। क्षतिपूर्ति के लिए जो रकम लगेगी, वह न तो जब्त की जा सकेगी, न बन्द की जा सकेगी, और न किसी और को दी जा सकेगी, बशर्ते कि दावा ऐसा न हो, जो विधि में वर्णित है। यदि मालिकों का दिवाला निकल जाता है, या ऐसा कोई शर्तनामा है जिसके अनुसार अनुविहित क्षतिपूर्ति के अधिकार में कोई कमी आती है, तो उस हालत में भी मजदूरों के हित सुरक्षित हैं।

प्रशासन

राज्य सरकारो के द्वारा नियुक्त मजदूरों की क्षतिपूर्ति आयुक्त इस विधि के प्रशासक हैं । 1929 से ले कर 1950 तक मृत्यु, स्थायी रूप से पंगु हो जाने तथा सामयिक रूप से पगु हो जाने पर दी गई क्षतिपूर्ति का लेखा नीचे दिया जाता है—

तालिका 167

दुर्घटनाओं की संख्या और क्षतिपूर्ति-राशि

वर्ष	उन दुर्घटनाओं की सख्या जो कारण वनी				दी गयी क्षति-पूर्ति-राशि रुपयो मे			
	मृत्यु का	स्थायी अपागता का	अस्थायी अपागता का	योग	मृत्यु	स्थायी अपागता	अस्थायी अपांगता	योग
1929 . .	888	1,345	16,632	18,865	5,87,390	3,97,177	2,75,597	12,60,164
1934 . .	598	1,287	15,005	16,890	3,71,762	2,94,131	2,02,954	8,68,847
1939 . .	832	1,929	35,920	38,681	5,81,080	5,16,444	4,11,803	15,09,327
1945 . .	1,250	3,943	62,194	67,390	13,30,644	20,30,576	8,64,119	42,25,339
1946 (क) . .	1,154	3,536	50,551	55,241	13,68,681	13,03,113	9,54,014	36,25,808
1947 (ख) . .	1,011	3,228	49,335	53,574	11,79,087	12,09,974	9,37,434	33,26,495
1948 (ग) . .	1,032	3,850	61,894	66,776	15,80,450	16,15,390	10,24,228	42,20,068
1949 . .	1,063	3,972	55,441	60,476	18,70,568	20,25,227	13,19,617	52,15,412
1950 (घ) . .	969	4,062	50,706	55,737	18,20,082	21,82,788	12,86,902	52,89,772

(क) पजाब और सिध के अतिरिक्त ।

(ख) इनका सम्बन्ध पजाव के अतिरिक्त भारतीय यूनियन के उन सब राज्यो से है जिन्हे पहले प्रान्त कहा जाता था ।

(ग) 1948 और उसके बाद के वर्षों के आकड़े भारतीय यूनियन के उन सब राज्यों से सम्बन्धित है जिन्हे पहले प्रात कहा जाता था ।

(घ) आंकड़ अस्थायी; इनमे उड़ीसा के आंकडे सम्मिलित नही है।

मातृमंगल के लाभ

मातृमंगल के भुगतान के सम्बन्ध में भारतीय यूनियन के करीब करीब सभी राज्यों में कानून मौजूद हैं। बारह राज्यों ने अपनी विधान सभाओं में मातृमंगल विधि पारित की, बाकी राज्यों ने दूसरे राज्यों की विधियों को अपने यहां लागू कर दिया। इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय विधि है जो खानों पर लागू है। कुछ राज्य विधिया उन्हीं के क्षेत्राधिकार के सारे नियमित कारखानों पर लागू हैं, और कुछ विधियां ऐसी हैं जो स्थायी या गैर-मौसमी कारखानों पर ही लागू हैं। पश्चिमी बंगाल में एक अलग विधि है जो बगानों में काम करने वाली स्त्रियों पर लागू है।

जितने समय के लिये लाभ मिलता है, लाभ का दर क्या है तथा लाभ की रकम क्या है, यह प्रत्येक स्थान की विधि मे अलग अलग है। आसाम मातृमंगल विधि तथा पश्चिमी बगाल चाय बागान मातृमंगल विधि के अनुसार 150 दिन, मद्रास विधि के अनुसार 240 दिन, कोचीन विधि के अनुसार बारह महीने, बिहार, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय विधिओं के अनुसार छः महीने तथा बाकी विधियों के अनुसार नौ महीने काम कर लेने पर ही कोई स्त्री मातृमगल विधि के लाभ पाने की अधिकारिणी होती है। हैदराबाद तथा पश्चिमी बगाल चाय बागान विधि के अनुसार स्त्रियों को बारह सप्ताह, मद्रास विधि के अनुसार सात सप्ताह, पजाब विधि के अनुसार साठ दिन तथा बाकी विधियों के अनुसार आठ सप्ताह के लिए लाभ मिलता है। पजाब, हैदराबाद और केन्द्रीय विधियों के अनुसार लाभ बारह आने, प्रतिदिन आसाम विधि के अनुसार साढे ग्यारह आने (इसमें खाद्य सम्बन्धी रियायतें शामिल नही हैं), पश्चिमी बंगाल चाय बागान विधि के अनुसार सवा पांच रुपये प्रति सप्ताह तथा बाकी विधियों के अनुसार आठ आने प्रति दिन या औसत दैनिक मज़दूरी जो भी अधिक हो, दिया जाता है।

ऊपर जो लाभ बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त बिहार और उत्तर प्रदेश की विधियो के अनुसार पांच रुपये तथा केन्द्रीय विधियों के अनुसार तीन रुपये का बोनस उन स्त्रियों को दिया जाता है, जो प्रसव के समय प्रशिक्षित धात्रियों या दाइयों का उपयोग करती हैं। चिकित्सा सम्बन्धी निःशुल्क सहायता, शिशु-शालाओं तथा काम के बीच में अतिरिक्त छुट्टियों की भी व्यवस्था कुछ विधियों में भी की गई है। यदि मालिक ऐसी स्त्रियों को नौकरी से अलग करना चाहे तो उसके लिए भी उचित संरक्षण रखा गया है और यदि फिर भी करे तो उसके लिए सजा की व्यवस्था है। मातृमंगलवाली छुट्टियों के जमाने में स्त्रियो से काम लेना दण्डनीय अपराध है। यदि कोई स्त्री इन छुट्टियों में काम करती पाई जाये तो उसे अनुविहित लाभ से वंचित किया जाता है।

मातृमंगल लाभ पाने के लिए कितनी स्त्रियां दावा पेश करती है, और पाती हैं, उनकी औसत संख्या तथा दी हुई रकम नीचे दिखाई गई है :

तालिका 168

1950 में विभिन्न राज्यो तथा अथवा खानों मे दिया गया मातृमंगल-लाभ

राज्य	प्रति दिन काम पर लगायी जाने वाली औरतों की औसत संख्या	उन औरतों की संख्या जिन्होने मातृ-मंगल-मागा	उन औरतो की संख्या जिन्हे मातृ-मंगल-लाभ पूरा या आंशिकरूप मे दिया गया	उन मामलो की संख्या जहा अंश गर्भपात या मृत्यु के कारण बोनस या मातृमंगल-लाभ दिया गया	कुल प्रदत्त राशि (रुपयों मे)
अजमेर	13,336	47	39 (क)	...	990
आसाम	2,12,463	45,652	44,339	...	17,14,707
बिहार	11,535	1,028	944	83	64,314
बम्बई	47,108	4,671	4,530	...	1,81,132
दिल्ली	511	16	14 (ख)	...	428
मध्य-प्रदेश	5,256	600	581	...	27,348
मद्रास	88,526	3,723	3,249	...	1,36,181
पंजाब	1,640	15	15	...	634
उत्तर-प्रदेश	1,352	94	73	11	3,587
पश्चिमी-बंगाल (ग)	54,875	4,539	4,505	...	4,77,670
खाने	93,899	6,437	6,325 (घ)	1,706	2,38,125

श्रम कल्याण

1948 की कारखाना विधि, 1952 की खान विधि, 1951 की बगान श्रमिक विधि के अनुसार कैंटीनों, शिशुशालाओं, विश्रामगृहो, धोने की सुविधाओं तथा चिकित्सा सम्बन्धी

(क) आठ मामले अभी निबटे नही है ।

(ख) इसमे एक 1949 का मामला भी शामिल है । 1950 के दो मामले अभी निबटे नही हैं ।

(ग) इस सूचना का 1949 से सम्बन्ध है ।

(घ) इस संख्या मे 180 ऐसे मामले भी शामिल है जिनमे लाभ की प्रथम किश्त 1949 में दे दी गयी थी ।

सहायता की व्यवस्था की गई है। यदि कारखाने में कम से कम मजदूर जो इस विधि के लिए जरूरी है, लगे हुए हैं तो श्रम अधिकारियो की नियुक्ति आवश्यक है।

1951 के 31 मार्च को कोयले की खानों में 65 पिटहैड गुसलखाने तथा 89 शिशुशालाएं बनाई गई थी और 93 पिट हैड गुसलखाने तथा 104 शिशुशालाए बन रही थी।

1947 की कोयले की खानों की श्रम कल्याण कोष विधि, 1946 की अभ्रक खान कल्याण कोष विधि, 1951 की उत्तरप्रदेश चीनी और पावर इल्कोहल धन्धों के श्रम कल्याण तथा विकास कोष विधि तथा 1953 की बम्बई श्रम कल्याण कोष विधि का दायरा बहुत विस्तृत है। इन विधियों के अनुसार कल्याण योजना बनाते समय मजदूरों के सारे जीवन को सामने रख कर यह चेष्टा की जाती है कि मजदूर तथा उसके परिवार पूर्ण रूप से पनपे।

तालिका 169

कोयला-खान श्रम कल्याण कोष का प्राप्ति-व्यय लेखा

(रुपयो में)

वर्ष	सामान्य कल्याण का लेखा		आवास-प्रबंध लेखा	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
1946-47	43,42,500	17,15,531	...	...
1947-48	50,70,964	40,00,000 (क)	40,00,000 (क)	...
		22,93,034	11,18,862	6,46,485
1948-49	63,05,351	41,07,528	16,73,673	18,52,417
1949-50	47,11,298	55,22,048	66,99,159	30,26,547
1950-51	50,10,720	37,01,282	79,71,273	11,80,394
योग	3,15,41,043	2,17,66,159	2,14,62,967	67,05,843
1 अप्रैल 1951 को जमा बाकी आई :		97,74,884 रु०	1,47,57,124 रु०	

कोयले की खानों में श्रम कल्याण

1948 से मातृमंगल केन्द्र वाले चार क्षेत्रीय अस्पताल तिसरा और कतरास और (झरिया की खानें), चोरा और सियरसोल (रानीगंज की खानें) काम कर रहे हैं। धनबाद का केन्द्रीय अस्पताल 6 दिसम्बर 1951 को खोला गया था। 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1951 तक इन अस्पतालों में 16,463 ऐसे रोगी थे, जो अस्पतालों में भरती किये गये थे, और 50,122 ऐसे रोगी थे, जो बाहर रह कर चिकित्सा कराते थे। इसका लेखा तालिका 170 में दिया हुआ है।

(क) सामान्य-कल्याण लेखा से आवास-प्रबन्ध लेखा को एतदर्थ स्थानान्तर।

तालिका 170

अस्पताल	इलाज किये गये मरीजो की सख्या							
	अस्पताल मे दाखिल मरीज				बाहर से आने वाले मरीज़			
	पुरुष	नारी	शिशु	योग	पुरुष	नारी	शिशु	योग
कतरास	3,521	1,213	346	5,080	6,882	6,772	5,121	18,775
तिसरा	1,119	781	474	3,374	4,831	6,117	2,936	13,884
सियर-साल	4,339	331	91	4,761	7,261	2,934	1,249	11,444
कोरा	2,420	688	140	3,248	2,712	1,733	1,574	6,019
सब अस्पताल	12,399	3,013	1,051	16,463	21,686	17,556	10,880	50,122

आसनसोल मे एक और केन्द्रीय अस्पताल बन रहा है। बोकारो कोयले की खान मे फुसरो नामक स्थान मे एक क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण का निर्णय हो चुका है, और पंच घाटी मे एक क्षेत्रीय अस्पताल खोलने की योजना विचाराधीन है। कतरास और सियरसोल में तपेदिक रोगी-परीक्षण गृह खोले गये हैं। कुछ स्वास्थ्य निवासो मे खान मे काम करने वालो के लिए कुछ पलग रिजर्व रखे गये हैं। आसनसोल में खान मे काम करने वाले तथा उन के परिवारो के लिये एक शोणित बैंक चालू है। लगभग कोयले की खान के सभी क्षेत्रो मे मलेरिया प्रतिशोधक कार्यक्रम चालू है। बी० सी० जी० टीके का भी एक अभियान चालू है।

कई कोयले के क्षेत्रों मे ऐसे बहुमखी कल्याण केन्द्र खोले गये हैं जहां पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन तथा कल्याण सम्बन्धी अन्य कार्य भी जारी रहते हैं। 1951-52 के लिए ऐसे ग्यारह तथा 1952-53 के लिए ऐसे सात केन्द्रों का खोलना मंजूर हुआ था। धनबाद के केन्द्रीय अस्पतालों में पंगू खान-मजदूरों के लिए एक पुनर्वास केन्द्र खोला गया है। हैदराबाद की कोयले की खानों मे खान मजदूरों के लाभ के लिए कुछ कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं। खान मजदूरों के मनोरंजन के लिए रेडियो, चलते फिरते सिनेमा और खेल के मैदानो की व्यवस्था है। केन्द्रीय श्रम कल्याण सम्बन्धी विभाग के अन्तर्गत 1951-52 तथा 1952-53 के लिए कोयले की खानों के श्रमिकों के कल्याण के लिए क्रमशः 72,44,000 रुपयों तथा 70,18,200 रुपयों का बजट बना हुआ था।

तालिका 171

अभ्रक-खान श्रमिक कल्याण कोष का आय-व्यय लेखा

वर्ष	प्राप्ति		व्यय	
		रु० आ० पा०		रु० आ० पा०
1950-51	रोकड़ बाकी आई	42,07,178-5- 4	बिहार मे	1,11,857-8- 0
	प्राप्तियां वर्ष की अवधि मे	20,63,304-3- 6	मद्रास मे	77,714-14- 2
			रोकड बाकी रही	60,80,910- 2- 8
	प्राप्ति योग	62,70,482-8-10		62,70,482- 8-10
1951-52	अनुमानित प्राप्ति	15,00,000-0- 0	अनुमानित व्यय-बिहारमे	13,39,310- 0- 0
			मद्रास मे	4,02,623 - 0- 0

अभ्रक की खानों में कल्याण कार्य

बिहार के कर्मा नामक स्थान मे एक केन्द्रीय अस्पताल बनाने की मजूरी 1950–51 मे दी गई थी। मद्रास के कलिचेडू नामक स्थान मे इस प्रकार एक अस्पताल बनाने की मजूरी 1951–52 मे दी गई। बिहार के धाब नामक स्थान मे एक मातृकल्याण तथा शिशु–कल्याण केन्द्र बनाने की मंजूरी 1952–53 मे दी गई। नैल्लोर तथा गुडूर के सरकारी अस्पतालो मे केवल खान मजदूरो के लिए कुछ पलग रिजर्व थे।

1950–51 मे एक बहुमुखी कल्याण केन्द्र स्थापित करने की योजना मजूर की गई थी। 1952–53 मे राजस्थान मे ऐसे आठ केन्द्र खोलने की योजना विचाराधीन थी। खान मजदूरो के बच्चों को प्रौद्योगिक, उच्च सेकेन्डरी तथा कालेजो की शिक्षा देने और उन्हे मुफ्त पुस्तके और स्लेटे देने के लिए धन राशि मजूर की गई थी।

ऊपर बताए गये कोष से कई काम और किये जाते है। जरूरत की चीजो तथा परचून की दुकान खोली जाती है, और चलते फिरते सिनेमा दिखाये जाते है इत्यादि। 1951-52 मे अभ्रक कल्याण कोष के बजट के अनुसार बिहार और मद्रास के लिए क्रमश: नौ लाख और सवा लाख रुपये का बजट निर्दिष्ट था। 1952–53 के बजट मे बिहार के लिए 7,75 000 रुपये की; मद्रास के लिये 4,00,000 रुपये की; राजस्थान के लिये 1,37,000 रुपये की और अजमेर के लिए 2,000 रुपये की व्यवस्था थी।

बागान श्रमिक सम्बन्धी कल्याण

चाय बागान के श्रमिकों का भी उचित ध्यान रखा गया है। चाय बागानो मे काम करने वालों को चिकित्सा सम्बन्धी क्या सुविधाएं देनी चाहिए, इस सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए

एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जो सुझाव रखे वे सब के सब मान लिये गये। कुछ मालिको ने इन सुझावों को पूर्ण रूप से मान लिया। 1951–52 मे केन्द्रीय चाय बोर्ड से चाय बागान के मजदूरो के कल्याण के लिए चार लाख रुपये प्राप्त किये गये। यह रकम राज्य सरकारो मे बाट दी गई, और इनके लिये जो कल्याण कार्य किये गये उनमे मनोरजन के अलावा, दर्जीगिरी, कढाई, बुनाई, टोकरी बनाना इत्यादि उपयोगी शिल्प आते है। चाय बागान के मजदूरो को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए आदर्श केन्द्र सगठित करने के लिए एक जापानी विशेषज्ञ बुलाया गया है।

स्वेच्छा से किए जाने वाले उपाय

द्वितीय महायुद्ध के जमाने मे श्रम कल्याण कोष इसलिए बनाये गये कि मजदूरो के लिए कल्याण कार्य किये जा सके। 1947–48 मे सब केन्द्रीय सस्थाओ को यह कहा गया कि वे इस प्रकार के कोषो का निर्माण करे। 1950–51 मे 221 केन्द्रीय सस्थाओ मे कल्याण कोष स्थापित किये जा चुके थे। मत्रालयो की दृष्टि से किस प्रकार यह कोष बटे हुए है यह नीचे देखा जा सकता है :

मत्रालय	ऐसी सॅस्थाओ की सख्या जिनमे कल्याण कोष है
प्रतिरक्षा	193
वित्त	4
निर्माण, उत्पादन और पूर्ति . . .	6
संचार	8
स्वास्थ्य	4
खाद्य एवं कृषि . . .	6
योग . .	221

इन कोषो मे सात लाख रुपया एकत्र है, और इनमे लगभग एक लाख बीस हजार मजदूरो को लाभ पहुचता है। कोष से मजदूरो के लिए विशेष कर घर के अन्दर खेले जाने योग्य खेल तथा बाहर खेले जाने योग्य खेल, वाचनालय, पुस्तकालय, रेडियो, शिक्षा तथा मनोरजन की व्यवस्था की जाती है। विभिन्न सस्थाओ तथा मजदूर सगटनो के द्वारा चलाये हुए मातृकल्याण केन्द्र, क्लबों, स्कूलो तथा सामाजिक सेवा केन्द्रो को अनुदान भी दिये जाते है।

राज्य सरकारे भी कुछ कल्याण केन्द्र चलाती है। कल्याण कार्यो के आकार प्रकार तथा प्रकृति के अनुसार यह केन्द्र 'क' 'ख' 'ग' 'घ' वर्गो मे वर्गीकृत है। इन केन्द्रो के बारे मे सब से ताजे आकडे इस प्रकार है—बम्बई 53, उत्तर प्रदेश 33, पश्चिमी बगाल 19, सौराष्ट्र 17, बिहार, हैदराबाद और तिरुवांकुर-कोचीन—प्रत्येक मे 3 और मैसूर मे 2 ।

कल्याण ट्रस्ट फंड

निजी मालिकों को समझा बुझाकर अपने यहा काम करने वाले लोगो के लाभ के लिए कल्याण ट्रस्ट कोष खोलने के लिए राजी किया गया। प्रयास यही किया गया कि ये कोष सामयिक स्वेच्छा के आधार पर बनाये जाये, यदि ऐसा न हो सका तो यह निर्णय किया गया कि

इसके लिए कानून बना कर लोगों को मजबूर किया जाये । नवम्बर 1952 मे केन्द्रीय सरकार न राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र के औद्योगिक कारखानो को यह समझाने के लिए कहा कि वे इस प्रकार के कोष जारी करें । कल्याण कोष के सुन्दरतर उपयोग तथा निर्माण के लिए एक अखिल भारतीय विधि बनाने का विचार है ।

अकेले मालिक (जैसे टाटा कम्पनी जमशेदपुर), कई मालिको की संस्थाएं (जैसे भारतीय जूट मिल्स एसोसियेशन और भारतीय चाय एसोसियेशन) और कई मजदूर संस्थाएं (जैसे वस्त्र श्रमिक एसोसियेशन, अहमदाबाद) अपने अपने ढंग से श्रम कल्याण मे लगे हुए हैं ।

मजदूरों के लिए मकान

1948 के अप्रैल मे केन्द्रीय सरकार ने दस साल के अन्दर मजदूरों के लिए दस लाख मकान बनाने का निश्चय किया । आर्थिक दिक्कत के कारण 1949 के अप्रैल में एक संशोधित योजना घोषित की गई । इस योजना के अनुसार 1950–51 मे तथा 1951–52 मे राज्य सरकार को जो कर्ज दिये गये, वे इस प्रकार थे :

तालिका 172

(लाख रुपयो मे)

राज्य	1950-51	1951-52
आसाम	...	10
बिहार	5	30
बम्बई	75	44
मध्य प्रदेश	10	10
मद्रास	...	9
उडीसा	10	10
पंजाब	...	5
हैदराबाद	...	20
मैसूर	...	20
तिरुवाकुर-कोचीन	...	10
योग	100	168

मजदूरों के लिये सहायताप्राप्त मकान

1952 के अन्त में केन्द्रीय सरकार ने मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त मकानों की एक योजना की घोषणा की । यह योजना 1956 के मार्च तक याने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जारी रहेगी । केन्द्रीय सरकार मुख्य वित्तीय जिम्मेदारी ग्रहण करेगी, साथ ही साथ सामान और परिवहन की सुविधाएं भी देगी । विद्यालयों, औषधालयों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जायेगी । मालिक तथा मजदूर युक्तिसंगत किराया देने के जिम्मेदार होंगे ।

1952-53 के लिए सात करोड़ सोलह लाख रुपये की लागत पर 28,500 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है । पर यह योजना देर से चालू हुई इसलिए कर्ज के रूप में 3,01,10,265 रुपयों तथा सहायता के रूप में 2,70.18,786 रुपयों की लागत पर 19,635 मकानों के बनाने

की मजूरी दी गई। इनमे से 1,189 की मंजूरी (जिनमे कर्ज के रूप मे 11,11,435 रुपये तथा सहायता के रूप मे 11,98,401 रुपये मंजूर थे) रद कर देनी पड़ी क्योंकि मकान बनाना शुरू ही नही हुआ था। 1953-54 के लिए सात करोड सढसठ लाख रुपयो की लागत पर 22,000 मकानो के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनसे यह आशा की जाती है कि 14,000 मकान राज्य सरकारो तथा हाउसिंग बोर्डों के द्वारा, 3,500 सहकारी समितियो तथा 4,500 मालिकों के द्वारा बनाये जायेगे। अगस्त 1953 तक 1,802 मकानो के बनने के लिए 34,55,775 रुपये की कुल रकम मंजूर की गई थी। 1953 के सितम्बर मे इनके अलावा एक कमरे वाले एक मजिल के 980 मकानो के लिए और भी 23,43,837 रुपये मजूर किये गये थे। 1953 के अक्टूबर मे एक कमरे वाले एक मजिल वाले 2,164 मकानो को बनाने के लिए 48,95,710 रुपयों की एक रकम और मजूर की गई।

गत वर्ष जो तजरबे हुए, उनके अनुसार इस योजना मे कुछ सशोधन हुए। साथ ही मजदूरो की सहकारी समितियो की सुविधा के लिए भी परिवर्तन किये गये। गत वर्ष के मुकाबले मे एक मुख्य परिवर्तन यह हुआ है कि 150 रुपये मासिक या उससे अधिक कमाने वाले मजदूरो के लिए दो कमरे वाले मकान बनाने तय हुए है।

पंचवर्षीय योजना

मकान बनाने के लिए पचवर्षीय योजना मे 48,69,00,000 रुपयो की व्यवस्था है। इस रकम मे से केन्द्रीय सरकार 38 करोड 50 लाख रुपये और राज्य सरकारे 10 करोड 19 लाख रुपये खर्च करेगी। 1953-54 मे इस सम्बन्ध मे जितने खर्च की व्यवस्था है, उसमे तथा बाद के वर्षों मे खर्च के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव रखे जायेंगे उनमे यह ध्यान रखा जायेगा कि कुल 38 करोड 50 लाख रुपया खर्च करना है।

केन्द्रीय सरकार के उदाहरण का अनुसरण करते हुए लगभग सभी राज्य सरकारे मजदूरो के लिए मकान सम्बन्धी अपने कार्य क्रमो को कार्यान्वित करने मे लगी हुई है। बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर ने क्रमशः बम्बई हाउसिंग ऐक्ट 1948, उ० प्र० शुगर एण्ड पावर एलकोहल इण्डस्ट्रीज लेबर वेलफेअर एण्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट 1951, मध्य प्रदेश हाउसिग बोर्ड ऐक्ट 1950 और मैसूर लेबर हाउसिंग ऐक्ट 1949 पास कर लिया है। इन विधियो के द्वारा मकान बनवाने के लिए सरकारें वित्त ले सकेगी। इस सम्बन्ध मे वित्त आने के साधन केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त राज्य अनुदान, मालिको और मुलाजिमो से प्राप्त अनुदान तथा किराये है। इन कोषों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि सम्बद्ध सरकारों से पहले से स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक ऋण प्राप्त करें। बम्बई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रासगिक विधियों के अनुसार अनुविहित हाउसिंग बोर्ड स्थापित किये गये है। मैसूर सरकार ने लेबर हाउसिंग कारपोरेशन की शक्तियां तथा जिम्मेवारियां बगलोर नगरोन्नयन ट्रस्ट को सौप दी है। बिहार सरकार ने मई 1951 में एक अस्थायी औद्योगिक गृह निर्माण बोर्ड स्थापित की है। उन गृहनिर्माण बोर्डों को इस बात का कानूनी अधिकार कि वे भूमि प्राप्त करें, और उसको उन्नयन करे तथा औद्योगिक मजदूरो के लिए मकान बनवाये और उन्हें कायम रखे।

भारत सरकार ने हाल ही की एक विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित कर दिया है कि पंचवर्षीय योजना आयोग ने जिस राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को स्थापित करने की सिफारिश की, उस

की सब प्रारम्भिक तैयारियां हो चुकी है। इस सगठन मे कौन लोग होगे, यह भी अन्तिम रूप से तय हो चुका है। जल्दी ही इस सम्बन्ध में घोषणा होने वाली है।

कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये मकान

अपने अपने यहा के स्वास्थ्य सम्बन्धी खान बोर्डों के आदेश के अनुसार झरिया, आसनसोल, हजारीबाग के कोयले की खानों के मालिकों ने क्रमश: 37,386, 16,110 और 1,442 मकान बनवाये है। इतना हो जाने पर भी निवास-स्थान की बहुत कमी थी क्योंकि खान में काम करने के लिए दूर दूर से लोग आते है। कोयले की खान के मजदूरो की कल्याण कोष विधि 1948 के अनुसार जो कल्याणकारी संगठन बने हैं, वे खान मे काम करने वाले मजदूरों के रहने के लिए मकान बनवाने का एक अलग हिसाब रखते है। 1 अप्रैल 1951 की इन सगठनों का आयव्यय और बाकी क्रमश: इस प्रकार था—2,14,62,967 रुपये, 67,05,843 रुपये तथा 1,47,57,124, रुपये। इस सगठन ने अब तक झरिया क्षेत्र के भूलि नामक स्थान में 1,566 तथा रानीगंज की कोयले की खान के विजयनगर नामक स्थान में 48 मकान बनवाये है। बोकारो, करगालो, भर-कण्डा और कुरसिया की सरकारी खानों मे इस कोष से 184 मकान बन चुके है और 355 बन रहे है। कल्याण कोष सगठन ने खान-स्वास्थ्य बोर्ड से यह अनुरोध किया है कि वह मालिकों से यह कहे कि खान मजदूरों के लिए उन्नत किस्म के मकान बनवाएं।

श्रम विधियों का प्रशासन

श्रम विधियों का प्रशासन विभक्त जिम्मेवारी का है, याने केन्द्रीय सरकार खानों, रेलो तथा अन्य केन्द्रीय उद्योगों पर लागू श्रम विधियों को अपने विभिन्न दफ्तरों के जरिये से प्रशासित करती है। राज्य सरकारे बाकी विधियो को अपने सगठनों के जरिये से लागू करती है। तत्सम्बन्धी केन्द्रीय संगठन ये है :—

(1) मुख्य श्रम-आयुक्त का दफ्तर, नई दिल्ली।
(2) कोयले की खानों के कल्याण आयुक्त का दफ्तर, धनबाद।
(3) कोयले की खानों के प्राविडेंट फंड आयुक्त का दफ्तर, धनबाद।
(4) अभ्रक की खानो के श्रम कल्याण कोष के कल्याण आयुक्तों के दफ्तर, धनबाद तथा नेल्लौर।
(5) खानों के मुख्य निरीक्षक का दफ्तर, धनबाद।
(6) कारखानों के मुख्य परामर्शदाता का दफ्तर, नई दिल्ली।
(7) बाहर से आये हुए श्रमिको के कट्रोलर का दफ्तर, शिलाग।
(8) मुलाजिमो के राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल का दफ्तर, नई दिल्ली।
(9) लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर का दफ्तर।

औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सभी राज्यों ने अपने इलाकों के अन्दर लागू सभी श्रम विधियों के प्रशासन तथा लागू करने के लिए संगठन बनाये है। जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त सभी 'क' तथा 'ख' भाग के राज्यों मे इस उद्देश्य से आयुक्त नियुक्त हुए है।

बाईसवां अध्याय

पत्र-पत्रिकाएं, फिल्म और रेडियो द्वारा प्रसार

1947 के अगस्त मे भारत मे प्रकाशित समाचार पत्रो और सामयिक पत्रो की सख्या 3,000 थी, जिस मे 300 दैनिक पत्र थे। 1 अप्रैल 1953 को यही सख्या 8,134 मे पहुच गई, जिस मे 683 दैनिक पत्र, 2,666 साप्ताहिक पत्र, 2,911 मासिक पत्र और 1,874 दूसरे सामयिक पत्र थे। इन मे से अग्रेजी मे 74 दैनिक, 299 साप्ताहिक, 465 मासिक, और 439 दूसरे सामयिक पत्र प्रकाशित होते थे।

नीचे की तालिका मे भाषावार लेखा प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 173

किस भाषा मे प्रकाशित होता है	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक	अन्य पत्रिकाए	योग
हिन्दी	176	705	777	297	1,955
अग्रजी	74	299	465	439	1,277
उर्दू	170	391	317	79	957
बगला	24	235	300	211	770
मराठी	52	168	49	80	349
तमिल	16	161	249	92	518
तेलगू	8	103	162	62	335
मलयालम	13	54	105	19	191
कन्नड	28	96	33	20	177
गुजराती	48	154	60	88	350
सस्कृत	...	3	8	...	11
काश्मीरी	...	..	..	..	...
गुरमुखी	22	35	52	6	115
असमिया	1	27	11	32	71
उडिया	3	15	32	6	56
द्वै-मासिक या बहु-मासिक	33	161	252	424	870
अन्य भाषाए (सिधी आदि)	15	59	39	19	132
योग	683	2,666	2,911	1,874	8,134

भारत मे दैनिक पत्रो के प्रकाशन की अनुमानित कुल सख्या बीस लाख से ऊपर है। दूसरे देशों के मुकाबले मे यह संख्या बहुत कम है। प्रति एक हजार व्यक्तियो के पीछे ब्रिटेन मे 596 दैनिक, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे 354, इजराइल मे 235, जापान मे 224, लेबनान मे 81,

लंका मे 27, फिलीपीन द्वीप मे 25 और इराक मे 10 दैनिक लिए जाते है, जब कि भारत मे मोटे तौर पर प्रत्येक हजार व्यक्तियो के पीछे 6 पत्र छपते हैं। भारत सरकार ने 1952 के 23 सितम्बर को न्यायाधीश राजध्यक्ष की अध्यक्षता मे एक मुद्रणालय आयोग (प्रेस कमीशन) इसलिए नियुक्त किया कि वह पत्र-पत्रिकाओ की वर्तमान अवस्था की पडताल करे और भविष्य मे उसका किस प्रकार विकास हो, यह बताये। निर्देशय शर्तों के अनुसार आयोग को इन बातो पर विचार करना था-(1) समाचार पत्रों, सामयिक पत्रो, खबर देने वाली एजेंसियों तथा फीचर सिन्डीकेटो का नियन्त्रण, उनकी व्यवस्था, मिल्कियत तथा उनका वित्तीय ढाचा क्या है। (2) एकाधिकार तथा पत्रों की मालाए किस प्रकार चलती हैं। (3) पत्रकारिता के विकास पर अधिकारी कम्पनी तथा विज्ञापनो का क्या असर पडता है। (4) वेतन प्राप्त पत्रकारो की भर्ती, प्रशासन, वेतन तथा काम करने की अवस्थाए क्या हैं। (5) न्यूजप्रिंट की पूर्तियो तथा छापेखाने कहा तक उपयुक्त हैं। (6) पत्रकारिता के ऊचे मानदण्ड के लिए क्या आवश्यक है। (7) कौन सी विधिया ऐसो ह जिनको बिना हटाये या सशोधन किये बिना पत्रकार-कला की स्वतन्त्रता नही रह सकती। इन मामलों पर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए आयोग ने एक प्रश्नावली गश्ती रूप मे जारी की और इस पर लोगों की गवाहिया ली गई। आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है।

छापेखाने की स्वतंत्रता

संविधान के 19वे अनुच्छेद मे यह गारटी दी गई है कि प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त होगा। 1951 की सविधान (प्रथम सशोधन) विधि के अनुसार ससद् इस अधिकार को देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रो के साथ मित्रता के सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरुचि या सुनीति, अदालत का अपमान, मानहानि या किसी अपराध के लिए उत्तेजना की दृष्टि से इस अधिकार को यक्तिसगत रूप से रोक सकती है। संशोधन के कारण 'युक्तिसंगत रूप से रोकने' के जो शब्द आ गये, उनके कारण अब इस अधिकार को रोकते हुए जो कानून बनते हैं, वे एक तरफ जहां उचित हो गए, वही दूसरी तरफ वे कही युक्तिसंगत हद से आगे तो नही निकल गये, इस पर अदालत के सामने मुकदमा दायर हो सकता है।

फिल्म

1930 तक भारतीय फिल्म व्यवसाय की प्रगति बहुत मामूली रही। उन दिनो जितने विदेशी फिल्म भारत मे दिखाय जाते थे, उनकी लम्बाई भारतीय फिल्मों की सात गुनी होती थी। 80 प्रतिशत फिल्म तो अमेरिका से ही मगाये जाते थे। पर अब परिस्थिति यह है कि जितने फुट फीचर फिल्म भारत ने बनाये जाते हैं, वे बाहर से मंगाये हुए फिल्मो से अधिक लम्बे होते हैं। अब भारत में लगभग 200 निर्माता, 60 स्टुडियो, 40 प्रयोगशालाएं और लगभग 6,600 वितरक और उपवितरक काम करते है। मुख्य उत्पादन-केन्द्र बम्बई, कलकत्ता और मद्रास है। इस धधे मे कुल पूंजी चालीस करोड़ पये लगी हुई है। और इससे प्रति वर्ष बीस करोड़ रुपये कुल राजस्व प्राप्त होता है। अब तो परिस्थिति यहा तक पहुंच गई है कि यहा की फिल्मे देश के बाहर भी खपने लगी है।

संसार के फिल्म उत्पादकों मे भारत का स्थान दूसरा है । 1953 मे भारत ने 259 फिल्मे तैयार की । इस समय अन्य देशों के वार्षिक आकडे इस प्रकार है —संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 450 फीचर फिल्म, जापान 150, इटली 120, फ्रास 110, जर्मनी और ब्रिटेन प्रत्येक 85, चीन 26 और रूस 15 ।

1931 से विभिन्न भारतीय भाषाओं मे किस गति से फिल्म उत्पन्न हुए इसका लेखा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 174

भारतीय भाषाओं मे निर्मित फीचर-फिल्मे (1931–53)

वर्ष	हिन्दी	गुजराती	मराठी	बंगला	तमिल	तेलगु	कन्नड	पंजाबी	मलयालम	अन्य	योग
1931 .	23	...	...	3	1	1	...	...	...	...	28
1932 .	61	2	8	5	4	2	...	...	...	1	83
1933 .	75	...	6	9	7	5	...	...	...	1	103
1934 .	121	1	11	10	14	3	2	...	...	2	164
1935 .	154	1	9	19	38	7	1	1	...	3	233
1936 .	135	3	6	19	38	12	1	1	...	2	217
1937 .	102	...	11	16	37	10	3	...	...	...	179
1938 .	88	...	14	19	39	10	...	1	1	...	172
1939 .	82	1	12	15	35	12	...	7	...	1	165
1940 .	86	1	10	16	36	14	...	7	1	...	171
1941 .	79	1	14	18	34	16	2	2	1	3	170
1942 .	97	...	13	18	19	8	2	5	...	1	163
1943 .	108	...	5	21	13	6	4	...	...	2	159
1944 .	86	...	4	14	13	6	...	2	...	1	126
1945 .	73	...	...	9	11	5	1	...	...	...	99
1946 .	155	1	2	15	16	10	...	1	...	...	200
1947 .	186	11	6	38	29	6	5	...	...	7	288
1948 .	148	28	7	37	32	7	2	1	1	2	265
1949 .	157	17	15	62	21	7	6	1	1	2	289
1950 .	115	13	19	42	19	18	1	4	6	4	241
1951 .	100	6	16	38	26	20	2	4	7	2	221
1952 .	102	2	17	43	32	25	1	...	11	...	233
1953 .	96	...	21	50	42	29	7	3	7	4	259

1945–46 के बाद से बाहर से कितनी फिल्में मंगाई गईं इनका लेखा यों है :—

तालिका 175

(सख्याये लाखों मे)

वर्ष (अप्रैल से मार्च तक)	कच्ची फिल्म		प्रयुक्त (एक्सपोज्ड) फिल्म		ध्वनि रेकार्डिंग और यंत्र सम्बन्धित सामग्री (मूल्य रूपयों में)	प्रदर्शन यंत्र और संबधित सामग्री (मूल्य रुपयो में)
	फुटों मे लम्बाई	मूल्य रुपयो मे	फुटो मे लम्बाई	मूल्य रुपयो मे		
1945-46	808·94	29·05	161·88	45·28	15·37	19·10
1946-47	1,286·23	54·11	151·15	24·60	23·17	46·70
1947-48	1,742·00	79·96	150·88	19·98	84·64	61·51
1948-49	1,564·16	76·96	123·91	31·52	24·53	37·14
1949-50	1,787·50	95·30	146·32	38·18	11·50	61 08
1950-51	2,085·38	125·59	145·37	35·79	9·53	61·94
1951-52	1,981·74	135·55	105·96	28·01	17·56	53·79
1952-53	2,476·41	166·07	129·47	39·69	10·70	25·58

भारत मे लगभग 3,250 सिनेमाघर हैं, जिन मे से 850 चलते फिरते है। इनमे से बीस प्रतिशत ऐसे शहरो अथवा नगरों मे है, जिनकी आबादी एक लाख मे ऊपर है। बाकी छोटे नगरो तथा कस्बो मे अवस्थित हैं। कुल मिलाकर साल मे सिनेमा घरो मे उपस्थिति 60 करोड़ रहती है।

डाक्यूमेन्टरी तथा खबरों की रीलें

सूचना एवं प्रसार मत्रालय के अन्तर्गत फिल्म डिवीजन ऐसी डाक्यूमेंटरी तथा खबरो की रीलों का निर्माण करता है, जिन मे भारतीय जीवन के विभिन्न पहलू दिखलाये जाते है। इन फिल्मो मे इतिहास, सस्कृति, सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा चालू घटनाएं दिखाई जाती हैं। भारत सरकार के फिल्म डिवीजन को 1948 मे पुनर्जीवित किया गया। 1953 के दिसम्बर के दूसरे सप्ताह तक यह डिवीजन 269 समाचार रीले प्रस्तुत कर चुका था और प्रतिवर्ष औसत 39 डाक्यूमेंटरी तैयार कर रहा था। 1948 और 1953 के बीच के डाक्यूमेंटरी का लेखा इस प्रकार रहा है —

तालिका 176

वर्ष	डाक्यूमेंटरी फिल्मों की सख्या
1948	3
1949	28
1950	39
1951	38
1952	39
1953 (नवम्बर के अंत तक) . .	30
योग .	177

सरकार साधारणतः पांच भाषाओं मे फिल्म तैयार करती है। हिन्दी, बंगला, तमिल, तेलगु और अंग्रेजी। चुने हुए डाक्यूमेंटरी तथा खबर की रीले अब व्यापारिक प्रदर्शन के लिये विदेश स्थित भारतीय मिशनो मे भी भेजी जाती है। इसके अलावा ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेलिवीजन कार्यक्रमो मे भी उनका अब इस्तेमाल होता है।

फिल्मों का सेन्सर

जनवरी 1951 मे फिल्म सेंसरो का केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया गया, और उस समय जो विभिन्न राज्य बोर्ड थे उनका स्थान उसे मिला। इस प्रकार एक संस्था स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय संस्कृति, शिक्षा, तथा मनोरंजन के माध्यम के रूप मे फिल्मो के मान-दण्ड को ऊंचा करने के लिये सेन्सर के कार्य मे एकरूपता स्थापित की जाये।

बोर्ड का उद्देश्य यह है कि फिल्मो को सार्वजनिक रूप से दिखाने की दृष्टि से उनकी परीक्षा की जाये तथा उन्हे मंजूर किया जाये। बोर्ड म सभापति को लेकर सात सदस्य होते है। इस का प्रधान दफ्तर बम्बई मे है। इसके अलावा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास मे इस के क्षेत्रीय दफ्तर है। बोर्ड दो प्रकार के प्रमाण-पत्र देते है, एक तो वह प्रमाण-पत्र जिस के अनुसार फिल्म सब को दिखलायी जा सकती है, दूसरा वह प्रमाण-पत्र जो केवल वयस्को को दिखलाने की आज्ञा देता है। प्रथम प्रमाण-पत्र को यू० प्रमाण-पत्र और दूसरे को ए० प्रमाण-पत्र कहा जाता है। यदि कोई निर्माता बोर्ड के निर्णय से असन्तुष्ट है, तो उसे भारत सरकार से अपील करने का अधिकार है। 1 अप्रैल 1952 और 31 मार्च 1953 के बीच मे 33 फिल्मो (जिन मे 26 विदेशी फिल्मे थी) को वयस्कों के लिये तथा 3,164 फिल्मो को सर्व प्रकार की जनता के लिये प्रमाणपत्र दिये गये। इसी युग मे कितनी फीचर फिल्मो को और कितनी संक्षिप्त फिल्मो को प्रमाणपत्र दिये गये, उसका हिसाब यों है :—

	भारतीय	विदेशी
फीचर फिल्मे . . .	262	500
छोटी फिल्मे . . .	369	2,066
योग	631	2,566

प्रसारण

आल इंडिया रेडियो के 21 प्रसार केन्द्र है। 1953 के 2 अक्तूबर को पूना मे एक प्रसार केन्द्र खोला गया, पर साथ ही औरंगाबाद का स्टेशन बन्द हो गया। इस प्रकार प्रसार केन्द्रो की संख्या उतनी ही बनी रही।

देश मे लाइसेंसयुक्त रेडियो सैटों का प्रचार जोरों के साथ हुआ। 1947 मे जहां इनकी संख्या 2,75,956 थी, वहा 1952 के दिसम्बर के अन्त तक इनकी संख्या 7,58,620 हो गयी। इसमें से अधिकतर घरेलू सेट है, जिनकी संख्या लगभग 6,94,000 है।

लाइसेंसो की सख्या मे किस प्रकार प्रगति रही उसका लेखा इस प्रकार है —

तालिका 177

वर्ष	कुल सख्या
1947	2,75,955
1948	3,18,999
1949	4,08,060
1950	4,46,319
1951	6,85,508
1952	7,58,620

1952 के अन्त में प्रति हजार व्यक्ति पीछे भारत मे लगभग दो रेडियो सेट थे, जब कि 1950–51 मे इजराइल मे प्रति हज़ार व्यक्ति पीछे 123 सेट, जापान मे 106, लेबनान मे 36 टर्की मे 16, मिस्र मे 12, और लंका में 4 थे । पश्चिमी देशो मे यह सख्या बहुत अधिक है, यह तो बताने की आवश्यकता ही नही है । अधिक से अधिक लोगो को रेडियो का लाभ देने के लिये देहातो के औद्योगिक क्षेत्रो तथा विद्यालयो मे सामूहिक सेट लगाये गये हैं । वर्तमान समय में 6,600 ऐसे रिसीवर हैं ।

विकास योजनाएं

1953 मे प्रसार के विकास की एक पचवर्षीय योजना बनायी गयी । इस योजना मे बम्बई, अहमदाबाद, बंगलोर, कलकत्ता, जालन्धर तथा इलाहाबाद मे अत्युच्च शक्तियुक्त ह्रस्व तरंग सप्रेषण लगेंगे तथा नागपुर, गौहाटी, मद्रास, इंदौर, हैदराबाद में मझोले तरग सप्रेषण लगने है । जयपुर, जोधपुर (केवल रिले केन्द्र), ग्वालियर तथा राजकोट मे नये प्रसार केन्द्र खुलने है । इसके अलावा कलकत्ता और मद्रास मे स्टूडियो की इमारते बनेगी और नई दिल्ली मे जो इमारत है, उसका विस्तार होगा ।

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के प्रसार केन्द्र ह्रस्व तथा मझोली तरग के सप्रेषणो के द्वारा अपने अपने इलाके की सेवा करते है । मझोली तरग पर जो दूसरे केन्द्र काम करते है, वे सीमित रूप से अपने इर्द-गिर्द की सेवा करते है । इन केन्द्रो से जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, उनमें सगीत, खबरे, शिक्षा सम्बन्धी प्रसार, नाटक, बच्चो, स्त्रियो के लिये फीचर तथा देहाती भाइयो और मजदूरो के लिये कार्यक्रम होते है ।

1952–53 मे कार्यक्रमो के उन्नयन के लिये कुछ कदम उठाये गये । आल इडिया रेडियो को पक्के गाने तथा सरल संगीत (हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटकी दोनों के) प्रसारित करने वाले कलाकारो को चुनने मे सहायता देने के लिये विषेशज्ञो की एक समिति चुनी गयी । साथ ही साथ हल्के गानो के मान-दण्ड का भी उन्नयन हो रहा है । फिल्म सगीत के सम्बन्ध मे काफी कमी की गयी है और इस प्रकार जो समय बच रहा है उसमे ऐसा सगीत प्रसारित किया जा रहा है, जो वाछनीय मान-दण्ड का है । आल इंडिया रेडियो दिल्ली से सगीत का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी

इसलिये शुरू किया गया है कि लोगों में एकता बढ़े। इस कार्यक्रम को सभी स्टेशन प्रसारित करते हैं तथा उच्च कोटि का हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत सर्वसाधारण में प्रसारित किया जाता है।

संवाद प्रसार

आल इंडिया रेडियो की संवाद प्रसार सम्बन्धी सेवा दिल्ली के संवाद सेवा डिवीजन में केन्द्रित है और दिल्ली के प्रसारित संवाद सम्बन्धी विज्ञप्तियां क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रसारित होती हैं।

आल इंडिया रेडियो इस समय प्रतिदिन 73 संवाद विज्ञप्तियां प्रसारित करता है, जिनमें से 44 देश के अन्दर के लोगों के लिये होती हैं, तथा 29 विदेशों में रहने वाले भाइयों के लिये होती हैं। इन विज्ञप्तियों में लगभग 14 घंटे लगते हैं और ये 27 भाषाओं में प्रसारित की जाती हैं। इनमें से 16 भारतीय भाषाएं हैं और शेष 11 विदेशी।

एक्सटर्नल सरविसेज में एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के विभिन्न देशों तथा वेस्ट इंडीज के लिये कार्यक्रम प्रसारित होता है। प्रति दिन इस कार्यक्रम में 21 घंटे लगते हैं।

1947 में आल इंडिया रेडियो से प्रसार का कुल समय 26,342 घंटे था। 1952 में यह 74,640 घंटे हो गया। छुट्टी के सप्ताहांत दिवसों में प्रसार का समय केन्द्र की शक्ति के अनुसार पांच से दस घंटे तक होता है।

प्रसार केन्द्र

आल इंडिया रेडियो के प्रसार केन्द्र चार क्षेत्रों में बटे हुए हैं—उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर क्षेत्रीय सेवा में ये केन्द्र आ जाते हैं—दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जलन्धर-अमृतसर। पूर्वी क्षेत्रीय सेवा में, कलकत्ता, कटक, शिलांग और गौहाटी आते हैं। मद्रास, तिरुची, विजयवाडा, मैसूर, त्रिवेन्द्रम और कोजीकोड दक्षिण सेवा में आते हैं, और पश्चिम क्षेत्रीय सेवा में बम्बई, नागपुर, बडौदा, अहमदाबाद, धारवाड, हैदराबाद और पूना आते हैं।

दिल्ली में संप्रेषण की दो अलग धाराएं हैं "क", "ख"। संप्रेषण "क" में कुल नौ घंटे बीस मिनट और संप्रेषण "ख" में आठ घंटे तीस मिनट प्रसार होता है। सप्ताह के कुछ दिनों में विद्यालयों के लिये जो विशेष कार्यक्रम होता है, उनको इस में नहीं दिखाया गया है। दिल्ली "क" में हिन्दी, उर्दू, हरियाना और अंग्रेजी व्यवहार में आती है। हिन्दी और उर्दू के सारे कार्यक्रम दिल्ली "क" से शुरू होते हैं। इसमें वे कार्यक्रम भी हैं जो बच्चों, स्त्रियों, देहाती भाइयों तथा विद्यालयों के लिये हैं। दिल्ली "ख" में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के "क" वाले कुछ कार्यक्रमों को पुनः प्रसारित करने के अतिरिक्त पंजाबी और गोरखाली श्रोताओं के लिये कार्यक्रम प्रसारित होता है। पश्चिमी संगीत तथा सेनाओं के लिये कार्यक्रम दिल्ली "ख" से प्रसारित होते हैं। फरवरी 1953 तक लखनऊ, इलाहाबाद और पटना इस विचार से एक साथ बंधे हुए थे कि इन क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं प्राप्त हैं वे सबके लिये हैं। पर 1953 की पहली फरवरी को बिहार के श्रोताओं के लाभ की दृष्टि से पटना केन्द्र को अलग कर दिया गया। इन केन्द्रों में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के कार्यक्रम होते हैं। प्रत्येक केन्द्र से साढे आठ घंटे प्रसार होता है। इसमें विद्यालयों के लिये विशेष दिनों में होने वाले कार्यक्रम नहीं गिनाये गये। लखनऊ और इलाहाबाद के प्रथम और द्वितीय संप्रेषण सामान्य हैं, और लखनऊ से ही उनका आरम्भ होता है। इन दो केन्द्रों में वार्ताओं, नाटकों, फीचरों तथा संगीत कार्यक्रमों की सामान्य सूची होती है। विद्यालयों, बच्चों

तथा स्त्रियों के लिये कार्यक्रम भी सामान्य है । देहाती इलाको के लिये तथा स्थानीय बोलियों म जो सामयिक दिलचस्पी के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, व दोनो स्टेशनो से अलग अलग होते हैं । देहाती भाइयो के लिये लखनऊ से जो कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसमे मजदूरो के लिये भी पद्रह मिनट का एक कार्यक्रम रहता है ।

जालन्धर और अमृतसर मे कार्यक्रम अक्सर सामान्य होते हैं । इन केन्द्रो मे हिन्दी, पजाबी उर्दू और अग्रेजी काम मे लायी जाती है । प्रतिदिन कुल साढे पाच घटे प्रसार का काम होता है ।

बम्बई मे दो अलग अलग धारायें हैं 'क' और 'ख', जिनमे से प्रत्येक मे कुल मिला कर नौ घटे पचीस मिनट सप्रेषण का कार्य होता है । इसमे विद्यालयो के कार्यक्रम शामिल हैं । बम्बई 'क' से गुजराती और अग्रेजी भाषा मे प्रसार होता है । मजदूरो के लिए भी एक कार्यक्रम होता है । बम्बई 'ख' से हिन्दी, उर्दू, मराठी और कोन्कनी मे प्रसार कार्य होता है ।

नागपुर मे प्रतिदिन साढे सात घटे प्रसार होता है । यहा से हिन्दी, मराठी और अग्रेजी मे प्रसार कार्य होता है ।

बडौदा और अहमदाबाद जुडे हुए हैं, और उनके अधिकाश कार्यक्रम सामान्य हैं । बडौदा से देहाती भाइयों के लिए गुजराती मे और अहमदाबाद से मजदूरो के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते हैं । यहा केन्द्र मे कुल मिला कर प्रति दिन सवा छः घटे प्रसार होता है ।

धारवाड से सप्ताह के सातो दिन साढेसात घटे प्रसार का काम होता है । यहा कन्नड, हिन्दी और अग्रेजी काम मे आती है ।

हैदराबाद मे प्रति दिन आठ घटे पैंतीस मिनट कार्यक्रम प्रसारित होता है । यहा से उर्दू, मराठी, कन्नड और अग्रेजी मे प्रसार होता है ।

कलकत्ता मे 'क' और 'ख' दो कार्यक्रम चलते हैं । कुल मिला कर प्रति दिन दस घटे प्रसार का काम होता है । 'क' मे बगला, हिन्दी और अग्रेजी तथा 'ख' मे इन भाषाओ के अलावा उडिया भी काम मे लायी जाती है । कलकत्ता 'ख' के अधिकाश कार्यक्रम कलकत्ता 'क' से प्रसारित किये जाते हैं । कलकत्ता 'ख' का भाव यह है कि उडिया मजदूरो तथा देहाती सुनने वालो के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाये । कटक से प्रति दिन साढे पाच घटे प्रसार होता है और वहा उडिया, हिन्दी तथा अग्रेजी काम मे आती है ।

शिलाग, गौहाटी मे प्रति दिन पाच घटे पैंतीस मिनट कार्यक्रम प्रसारित होता है, और यहा की भाषा आसामी, हिन्दी और अग्रेजी है । गौहाटी और शिलाग से साथ ही साथ देहाती सुनने वालो के लिए स्थानीय बोली मे और उपजातियों के लिए खासी-जयन्तिया भाषा मे कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है ।

मद्रास मे 'क' और 'ख' दो कार्यक्रम चलते हैं । प्रति दिन 'क' मे नौ घटे पैंतीस मिनट और 'ख' मे दस घंटे पाच मिनट प्रसार किया जाता है । 'ख' के कार्यक्रम मे विद्यालयो के कार्यक्रम भी शामिल हैं । 'क' से तमिल, हिन्दी और अग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं जो तमिल भाषी इलाकों के लिए होते हैं । 'ख' मे हिन्दी, अंग्रेजी और तेलगू मे कार्यक्रम प्रसारित होते है । सप्ताह में पाच दिन मजदूरो के लिए तथा देहाती सुनने वालो के लिए तेलगू मे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं । मद्रास के 'क' से कोई देहाती कार्यक्रम प्रसारित नही होता ।

तिरुची से प्रति दिन तमिल में आठ घंटे पैंतीस मिनट कार्यक्रम प्रसारित होता है। यहां से देहाती कार्यक्रम होते हैं तथा सप्ताह में पांच दिन प्राथमिक स्कूलों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित होता है।

त्रिवेन्द्रम और कोजीकोड एक साथ जुड़े हुए हैं और इन से मलयालम और अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। अधिकांश कार्यक्रम सामान्य होते हैं। स्थानीय दिलचस्पी के कार्यक्रम अलग अलग प्रसारित होते हैं। त्रिवेन्द्रम से प्रति दिन पौने सात घंटे और कोजीकोड से पौने छ: घंटे कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

मसूर से कुल मिला कर पौने सात घंटे का संप्रेषण होता है। यहां से कन्नड, हिन्दी, अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित होता है।

बाहर की सेवाएं

बाहर की सेवा को मोटे तौर पर दो हिस्से में बांटा जा सकता है--एक पूर्वी सेवा और दूसरी पश्चिमी सेवा। दिल्ली से उच्च शक्तियुक्त संप्रेषकों पर प्रसार का काम जारी रहता है।

पूर्वी सेवा पांच पृथक इलाकों के लिए है, और इनमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के भारतीयों के लिए होने वाले सामान्य कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। गानों तथा फीचर कार्यक्रमों के अतिरिक्त हिन्दी, तमिल और अंग्रेजी में खबरें भी प्रसारित की जाती हैं। बर्मी, चीनी (क्युयु), केन्टनी तथा इंडोनेशियाई भाषाओं में प्रतिदिन समाचार प्रसारित किये जाते हैं। विशेष दिलचस्पी के संगीत और वार्ताएं तथा बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

पश्चिमी सेवा में सुनने वालों के कार्यक्रम आठ पृथक वर्गों के लिए प्रसारित होते हैं तथा इसमें पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों के लिए सामान्य सेवा भी रहती है। गानों तथा अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त हिन्दी, गुजराती तथा अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किये जाते हैं। वेस्टइंडीज संप्रेषण में हिन्दी में वार्ताएं, संगीत, नाटक इत्यादि होते हैं। अरबी ईरानी, अफगान तथा पश्तो संप्रेषणों में पूर्वी तथा पश्चिमी संगीत के अतिरिक्त इन भाषाओं में समाचार भी प्रसारित होते हैं। यूरोपीय संप्रेषण में दो विभिन्न कार्यक्रम हैं--एक अंग्रेजी में और दूसरा फ्रांसीसी में।

तेईसवां अध्याय

पुनर्वास

1951 की जनगणना के अनुसार भारत में विस्थापितों की कुल संख्या 74 लाख 80 हजार है। इनमें से मोटे तौर पर 49 लाख 5 हजार पश्चिमी पाकिस्तानी और 25 लाख 75 हजार पूर्वी पाकिस्तानी हैं।

मई-अक्तूबर 1952 के समय में पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच हिन्दुओं का आवागमन बढ़ता गया। पर 1952 के 15 अक्तूबर से जब से पासपोर्ट पद्धति का सूत्रपात हुआ तब से उनकी गतिविधि में यथेष्ट कमी आयी है। मई 1953 के बाद फिर कुछ गतिविधि बढ़ी। 1953 के जुलाई में लगभग 46,100 हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में आये, और 44,200 हिन्दू पश्चिमी बंगाल छोड़कर पूर्वी बंगाल गये। यह अंदाज लगाया जाता है कि जनगणना के बाद छः लाख विस्थापित पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं, इसलिए मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूर्वी पाकिस्तान से 32 लाख आदमी आये।

देहाती बस्तियां

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को खेती में फिर से लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पंजाब और पेप्सू में पश्चिमी पंजाब तथा सिन्ध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, बलोचिस्तान और बहावलपुर में आये हुए पंजाबी खेतिहरों को लगभग स्थायी आधार पर निष्क्रातों की खेती वाली जमीन दी गई है। कुल मिलाकर इन दो राज्यों में 23 लाख 80 हजार स्टैंडर्ड एकड़ जमीन 4 लाख 75 हजार विस्थापित खेतिहरों को मिल चुकी है।

पंजाब और पेप्सू में लगभग 33 हजार विस्थापित परिवार गैर-मौरूसी काश्तकारों के रूप में बसा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए अधिकांश रूप में गैर पंजाबी 56 हजार विस्थापित खेतिहर परिवार अजमेर, भोपाल, बम्बई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में बसा दिये गये हैं। 7 लाख 65 हजार एकड़ से अधिक भूमि इनमें आवंटित की गई है।

विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पूर्वी राज्यों में कई योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। लगभग 1,96,000 परिवार पश्चिमी बंगाल में भूमि, चाय बगान तथा खेती से सम्बद्ध पेशों में लगा दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त 34 हजार परिवारों को आसाम, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, उ० प्रदेश, अन्डमान तथा निकोबार द्वीप पुंज में बसा दिया गया है। 1953 के मार्च के अन्त तक केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने बैल, चारा, खाद्य, खेती के औजार, बीज तथा मकान और कुओं की मरम्मत और निर्माण के लिये विस्थापितों को 16 करोड़ 94 लाख रुपया दिया था। इस रकम में से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लोगों को क्रमशः 7 करोड़ 83 लाख रुपया तथा 9 करोड़ 11 लाख रुपया दिया गया। 1953–54 के लिए 2 करोड़ 79 लाख रुपये की व्यवस्था है जिस में 25 लाख रुपये पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के लिए और 2 करोड़ 54 लाख रुपये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये है।

शहरी बस्ती

1953 के मार्च के अन्त तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने मिल कर पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितो के लिये 1,39,000 मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी थी। इनमें मे लगभग 1,13,000 मकान जून 1953 तक पूरे हो चुके थे, और जो मकान बाकी थे, वे निर्माण की विभिन्न स्थिति मे थ। विस्थापितो ने व्यक्तिगत रूप से या सहकारी समितियों के रूप में जो भी सगठन किया, उन्हे सरकार की ओर मे मकान बनाने के लिये स्थान तथा कर्ज मिले हैं।

1952-53 मे 1,81,000 मकानो के बनाने का कार्यक्रम सामने रक्खा गया था। पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए 9 लाख 10 हजार विस्थापितो के लिये इन मकानों के बन जाने से समस्या हल हो जाती थी। सरकार ने इस कार्यक्रम पर 46 करोड़ 44 लाख रुपये खर्च किये।

पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध मे परिस्थिति को देखते हुए सामान्य नीति यह रही है कि उन्हें इमारत बनाने के स्थान तथा कर्ज देने की व्यवस्था की जाये और मकान बनाने का काम विस्थापितो का रहे पर फिर भी सरकार ने कुछ निर्माण कार्य अपने हाथ में लिये हैं। फूलिया और हावड़ा-बैगाछी मे दो नये नगर बसाये गये है। इस के अलावा पूर्वी राज्यों में सरकार ने लगभग 10 हजार मकान बनाये।

व्यापार और उद्योग-धन्धों को सहायता

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितो को निष्क्रान्तों की लगभग 29 हजार दुकाने तथा औद्योगिक कारखाने दिये गये। इसके अलावा विभिन्न नगरों में लगभग 31 हजार नयी दुकाने तथा कई बाजार बनाये गये है। दिल्ली मे तथा उसके इर्द-गिर्द विस्थापितों के लिये जो नये नगर बसाये गये हैं, उनके अतिरिक्त लगभग 130 नगरोपकन्ठीय बस्तियां तथा नये नगर बसाये गये है। ऐसे बसाये हुए स्थानों मे फरीदाबाद, गाधीधाम, राजपुरा, नीलोखेरी, त्रिपुरी, सरदारनगर, उल्हासनगर, हस्तिनापुर और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यद्यपि नगरोपकन्ठीय बस्तियां पुराने शहरो के विस्तार रूप है फिर भी उनके निजी स्कूल अस्पताल, दुकाने तथा खेल के मैदान हैं।

रोजगार

जून 1953 के अन्त तक काम दिलाऊ दफ्तर ने 9,56,800 विस्थापितों को पंजीकृत किया। इस मे से 2,07,200 (जिनमे पूर्वी पाकिस्तान के 35,900 लोग आ जाते है) नौकरी दिलायी गयी थी।

प्रौद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण

इस समय विस्थापितो को प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये तीन तरह की योजनाये है—(1) एक तो वे जिन मे श्रम मत्रालय के फिर से बसाये जाने और काम दिलाऊ विभाग के डायरेक्टरेट जनरल की अधीनता मे काम होता है, (2) ऐसी योजनाए जिनका निर्माण राज्य सरकारो ने किया है, और (3) पुनर्वास मत्रालय के द्वारा शुरू किये हुए कार्यक्रम।

प्रथम योजना उन लोगों तक सीमित है जो ऐसे व्यवसाय सीखना चाहते हैं, जिन में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत आगे बढ़े हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। इन योजनाओ के अधीन 31 प्रशिक्षण केन्द्र है। 1953 के जून के अन्त तक 11 410 विस्थापित इन केन्द्रों मे

प्रशिक्षित हो चुके थे और 2,095 प्रशिक्षित हो रहे थे । 4,015 विस्थापित स्वीकृत निजी औद्योगिक संस्थाओं में शिक्षार्थी के रूप मे प्रशिक्षित हो चुके थे और 536 विस्थापित पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश मे प्रशिक्षण पा रहे थे ।

जून 1953 तक जो 15,400 विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षित हुए थे,उन मे से 4,200 पूर्वी पाकिस्तान से तथा बाकी पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए थे ।

फिर से बसाने तथा काम दिलाने के डायरेक्टरेट जनरल ने प्रशिक्षण की जो सुविधाएं दी थी उन्हें सहायता पहुचाने के लिये कई राज्य सरकारों ने प्रशिक्षण—श्रम केन्द्र खोले है । पुनर्वास मत्रालय ने भी इसी प्रकार के केन्द्र खोले थे पर वे अब या तो बन्द कर दिये गये है या स्थानीय राज्य सरकारो को सौप दिये गये है । केवल एक विशेष प्रशिक्षण—श्रम केन्द्र अरब की सराय मे जारी है, जिसे पुनर्वास मत्रालय चला रहा है । नीलोखेरी, फूलिया, फरीदाबाद तथा गाधीधाम आदि नये बसाये हुए शहरो मे प्रशिक्षण केन्द्र स्थानीय अधिकारी चला रहे है ।

1953 के जून के अन्त तक पश्चिमी पाकिस्तान से 50,500 विस्थापित व्यक्ति शिल्पो तथा दस्तकारियों मे प्रशिक्षित हो चुके थे । इन के अलावा नौ हजार लोगों का एक जत्था विभिन्न केन्द्रो मे प्रशिक्षण ले रहा था । इस के अलावा पूर्वी पाकिस्तान से आये 6,000 विस्थापित पूर्वी राज्यो मे प्रशिक्षित हो चुके थे और 2,000 प्रशिक्षण पा रहे थे ।

शिक्षा

विस्थापितो की शिक्षा की ओर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है । वित्तीय सहायता की एक सशोधित योजना के अनुसार हाई स्कूल के मानदण्ड तथा नि शुल्क शिक्षा तथा पुस्तकों और लेखन सामग्रियों के लिये सुपात्र छात्रों को नकद अनुदान दिया जाता है । प्रतिभाशाली छात्रो को कला, विज्ञान और प्रौद्योगिक विषय मे कालेजो मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये वृत्तिया दी जा रही है ।

ऋण

'अल्प ऋण योजना' के अनुसार शहरी इलाको से आये हुए विस्थापितो को वाणिज्य, व्यापार, उद्योग-धन्धो तथा शिक्षित पेशो के लिये अधिक से अधिक 5,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है । विस्थापितो की सहकारी समितियों को ऋण देने मे कोई सीमा नही रखी गयी है । फिर भी सहकारी समितियो की कुल धनराशि या प्रति सदस्य पीछे 2,500 रुपये (इनमे से जो भी बड़े हों) के ऊपर साधारण रूप से ऋण नही दिया जाता ।

इस योजना के अनुसार जो बहुत से कर्ज गत छः सालो मे दिये गये थे, उनके भुगतान का समय आ चुका है, फिर भी पुनर्वास मत्रालय ने यह निश्चय किया है कि जिन विस्थापितो को पश्चिमी पाकिस्तान में सम्पत्तिया है, उन्हे क्षतिपूर्ति की पहली किश्त जब तक अदा नही की जाती, तब तक उन से कर्ज की रकम की अदायगी रोकी रक्खी जाये । ऐसी रिआयत केवल उन्ही क्षेत्रों में दी जायेगी जहां ऋण सम्बन्धित व्यक्ति के प्रमाणीकृत दावे के 10 प्रतिशत से अधिक न हो ।

छोटे कर्जों की योजना मे हाल ही मे सुधार किया गया है और शहरी इलाको मे अब केवल निम्नलिखित लोगो को ही कर्ज दिया जाता है :—

(1) जिन्होंने किसी सरकारी योजना के अनुसार प्रौद्योगिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जो अपने धन्धे जारी करना चाहते हों ।

(2) नये बसाये हुए नगरो में बसने वाले ।

(3) अपाहिज गृहो से निकले हुए ऐसे लोग जिन के सम्बन्ध मे यह कहा गया हो कि वे योग्य नही है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितो के सम्बन्ध मे ऊपर की शर्तें ढीली कर दी गयी हैं और राज्य सरकारे अपने निर्णय के अनुसार कर्ज देती है ।

1952-53 मे कुल 16 करोड 75 लाख रुपये ऋण के रूप मे दिये गये । इनमें से 10 करोड़ 79 लाख रुपये पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितो को और 5 करोड़ 96 लाख रुपये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितो को दिये गये ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन व्यक्तियो, हिस्सेदारों, निजी लिमिटेड कंपनियो को 5,000 रुपये से ऊपर ऋण देता है । 1953 के 30 जून तक 13,081 प्रार्थियो के लिये 10 करोड़ 37 लाख रुपये मजूर किये गये थे । पर वास्तव में कुल 6 करोड़ 23 लाख रुपये दिये गये ।

सहायता

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के शिविर बहुत पहले ही बन्द कर दिये गये और पूर्वी राज्यों में भी अधिकांश शिविर 1952 के अप्रैल मे बन्द कर दिये गये । पर 1952 की मई से अक्तूबर तक पूर्वी पाकिस्तान से कुछ नये शरणार्थी आ गये, इसलिये कुछ शिविरों को फिर से खोलने की जरूरत पड़ी । पासपोर्ट पद्धति के प्रवर्तन के साथ-साथ इन शिविरों मे भारतीयों की सख्या बराबर घटती गयी है । जून 1953 के अन्त मे पूर्वी राज्यो के शिविरों की कुल आबादी 87,000 थी और यह लोग सब सामयिक रूप से सहायतार्थी वर्ग के थे ।

इस समय लगभग 77 हजार ऐसी स्त्रिया तथा बच्चे है, जिनका कोई नही है । इनमे बुड्ढे तथा अपाहिज लोग भी है । पूर्वी पाकिस्तान से आयी 40,500 और पश्चिमी पाकिस्तान से आयी 36,500 स्त्रिया इसमे आती है । इन लोगों को शिविरो, आश्रमो तथा अपाहिजगृहो मे रक्खा गया है । पुनर्वास मंत्रालय की ओर से अन्तरिम सहायता के रूप मे विधवाओ, अनाथ स्त्रियो, नाबालिगों या ऐसे विस्थापित लोगों को जो बुढापा, अपांगता, रोग तथा अन्य कारणों से रोटी कमाने मे असमर्थ है या जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान की शहरी अचल सम्पत्ति से मिलने वाली आय पर सम्पूर्णरूप से निर्भर है, उन्हे निर्वाह भत्ता देना स्वीकार किया गया है । भत्ता अधिक से अधिक 100 रुपये मासिक का दिया जाता है । अब तक लगभग 1 करोड 1 लाख 58 हजार रुपये खर्च किये जा चुके है और इस रूप मे 14,200 लोगों को सहायता दी जा रही है ।

दावों की जाच

विस्थापितों की दावा विधि 1950 के अनुसार 1953 की 31 मई के दिन तक जाच के लिय पेश किये गये दावो की स्थिति यो थी :

तालिका 178

	शहरी और ग्रामीण घर	कृषि भूमि	योग
भरे गये सम्पत्ति-पत्रो की कुल संख्या	10,39,842	1,51,976	11,91,818
उन दावों की कुल सख्या जिनकी जाच की जा चुकी है ।	—	—	5,25,454
उन सम्पत्ति-पत्रो की कुल सख्या जिन की जाच की जा चुकी है	10,23,307	1,47,682	11,70,989

अन्य दावे

1949 की अप्रैल में नई दिल्ली में जो हिन्द-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था उस के एक निर्णय के अनुसार दोनो देशों मे पेंशनों, प्राविडेंट फंडो, सरकारी नौकरो, राज्यो तथा स्थानीय संस्थाओं के नौकरो (जो पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आये थे) के पैन्शनों, प्राविडेंट फंडों और छुट्टी के वेतनो के मामले को जल्दी से जल्दी तय करने के लिये दोनो देशो मे केन्द्रीय दावा संगठन कायम किया गया था। भारतीय केन्द्रीय दावा सगठन पैन्शनो, प्राविडेंट फंडों तथा भारत सरकार की अपनी अन्तरिम सहायता योजना के अनुसार विस्थापितो के कुछ वर्गों को स्थायी रूप से भुगतान करने का प्रबन्ध करता है।

अन्तरिम-क्षतिपूर्ति-योजना

चूंकि अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नही हो सका, इसलिये पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितो को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध मे कोई अन्तिम योजना मजूर नही हो सकी। क्षतिपूर्ति के लिये निष्क्रान्तों की सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध मे भी कोई कानून इस कारण नही बनाया जा सका, फिर भी इस बीच मे सरकार ने 1953 के 18 नवम्बर को विस्थापितो के कुछ वर्गों के लिए अंतरिम क्षतिपूर्ति योजना मजूर कर ली गई। इस योजना के अनुसार फौरन 50 हजार से अधिक दावेदारों को लाभ पहुचा जो इन वर्गों मे आ जाते हैं। यह स्मरण रहे कि नीचे जो आकड़े दिये गये है वे मोटे तौर पर सही है :—

(1)	विधवाए, बुड्ढे तथा अपाहिज व्यक्ति जो निर्वाह भत्ता पा रहे है	10,250
(2)	स्त्रियों के आश्रमों तथा अपाहिज गृहो के रहने वाले अनाथ स्त्रियों, तथा बच्चे, ऐसे बुड्ढे और अपाहिज जो आश्रमों आदि के बाहर रहते हुए सहायता पा रहे है (इस मे नकद सहायता पाने वाले 1,100 लोग भी है)	4,250
(3)	ऐसी विधवाएं जिन के अपने नाम पर दावे है . .	13,600
(4)	जो लोग कुछ सरकारी और निर्मित नगरों या उपनिवेशो मे रहते है	18,100
(5)	पजाब के मिट्टी के मकान वाले उपनिवेशों मे रहने वाले .	5,450

क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास अनुदान की दरे इस सिद्धान्त पर तैयार की गयी कि दावेदार जितना ही छोटा हो उसे उतनी ही अधिक सहायता दी जाये। किसी भी दावेदार को अधिक से अधिक 8,000 रुपये की रकम देनी निश्चित हुई। स्वीकृत दावे का 16 से 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। और बाकी रकम पुनर्वास अनुदान के रूप मे दावेदार की आवश्यकता को देखते हुए दी जा रही है। आश्रमों तथा अपाहिज घरों मे रहने वाले दावेदारों के लिये उदार दरे मंजूर की गयी है।

सच तो यह है कि अन्तरिम क्षतिपूर्ति को धीरे धीरे और विस्तृत किया जायेगा, जिस से कि अधिक से अधिक दावेदारों को लाभ पहुंचे। भूमि के कुछ मालिको तथा दूसरे दावेदारों से क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध मे प्रार्थना-पत्र मागे जा चुके हैं।

व्यय

1947 से 1952-53 के अन्त तक पुनर्वास मन्त्रालय ने पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों पर कुल मिला कर 175 करोड 74 लाख रुपये खर्च किये थे। इस का ब्यौरा यो है :—

तालिका 179

(करोड रुपयो मे)

व्यय की मद	पश्चिमी-पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो पर	पूर्वी-पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर	योग
अनुदान .	56.59	21.17	77.76
ऋण .	19.90	13 79	33 6
आवास प्रबन्ध . .	46 44	11.70	58.14
प्रस्थापना . .	0.86	0.06	0.92
विधि . . .	0.01	—	0.01
योग . .	123.80	46.72	170.52
पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋण . .			5.22(क)

1953-54 के लिए व्यवस्था इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति . . .	16.76
पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति . . .	12.69
पुनर्वास-वित्त-प्रशासन	2.50
योग .	31.95

आंकड़े : एक दृष्टि म

देशान्तरगमन

1. 1951 की अखिल-भारत जनगणना के अनुसार पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की सख्या . . 74.80 लाख
   - (i) पश्चिमी पाकिस्तान से . . 49.05 लाख
   - (ii) पूर्वी पाकिस्तान से . . 25.75 लाख

(क) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो के लिए।

ग्रामीण क्षेत्र मे फिर से बसाने का कार्य

1. पश्चिमो पाकिस्तान से आये उन विस्थापित परिवारों की सख्या जिन्हे कृषि-योग्य भूमि पर बसाया गया		5.64 लाख
(i) लगभग स्थायी नियतन . .	4.75 लाख	
(ii) जो असामी के रूप मे बसाये गये .	0.33 लाख	
(iii) अस्थायी नियतन . . .	0.56 लाख	
2. पूर्वी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित परिवारो की संख्या जिन्हे कृषि-योग्य भूमि, चाय बगानो, और सहायक धधो मे लगाया गया . .		2.3 लाख
3. ग्रामीण क्षेत्रो मे बसे विस्थापित परिवारो को दिया गया ऋण		16.94 करोड़ रुपये
(i) पश्चिमा पाकिस्तान से आये परिवारो को	9.11 करोड़ रुपये	
(ii) पूर्वी पाकिस्तान से आये परिवारों को	7.83 करोड रुपये	

आवास प्रबन्ध

1. पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो के लिये उपलब्ध को गयी निवास ईकाइयो की सख्या		
(i) निष्क्रात व्यक्तियो के मकान .		1.79 लाख
(ii) सरकार द्वारा नव-निर्मित . .		1.39 लाख
(iii) सरकार द्वारा आशिक सहायता प्राप्त लोगो द्वारा निजी रूप से नव-निर्मित		0.42 लाख
2. पश्चिमी पाकिस्तान से आये उन नागरिक विस्थापित व्यक्तियो को सख्या जिन के लिए आवास-व्यवस्था कर दी गयी है . . .		23.80 लाख
(i) निष्क्रात व्यक्तियो के मकानो मे .	14.70 लाख	
(ii) नव-निर्मित मकानो मे अथवा उन मकानो म जो बन रहे है . .	9.10 लाख	

रोजगार

विस्थापित व्यक्ति जिन्हे काम-दिलाऊ केन्द्रों के द्वारा रोज़गार मिला . . .		2.07 लाख
(i) पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए .	1.71 लाख	
(ii) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए .	0.36 लाख	

औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण

1 पश्चिमी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियो की सख्या जिन्हे		
(i) प्रशिक्षण दिया जा चुका है . .		0.62 लाख
(ii) प्रशिक्षण दिया जा रहा है . .		0.10 लाख
2. पूर्वी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियो की सख्या जिन्हे		
(i) प्रशिक्षण दिया जा चुका है . .		0.10 लाख
(ii) प्रशिक्षण दिया जा रहा है . .		0.04 लाख

व्यापारिक और औद्योगिक गृह

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो को दी गयी इकाइयो की कुल सख्या .		0.60 लाख
(i) निष्क्रान्त व्यक्तियो की दुकाने और औद्योगिक गृह	0.29 लाख	
(ii) नई दुकाने	0.31 लाख	

ऋण

(क) अल्प ऋण		16.75 करोड रु०
(i) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो को	10.79 करोड रु०	
(ii) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को	5.96 करोड रु०	
(ख) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन द्वारा दिया गया ऋण		
(i) उन विस्थापित व्यक्तियो की सख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत हुआ .		13,081
पूर्वी पाकिस्तान से आये . .	3,816	
पश्चिमी पाकिस्तान से आये .	9,265	
(ii) स्वीकृत राशि		1,037·23 लाख रु०
पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए	286·93 लाख रु०	
पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो के लिए .	750·30 लाख रु०	
(iii) प्रदत्त राशि		623.03 लाख रु०
पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो को	160·21 लाख रु०	
पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को .	462·82 लाख	

सहायता

1. उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हे सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है . . . 1·64 लाख
   - (i) अस्थायी दायित्व (पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति) . . 0·87 लाख
   - (ii) स्थायी और अर्ध-स्थायी दायित्व . 0·77 लाख
2. निर्वाह भत्ता
   - (i) प्रदत्त मासिक भत्ता . . 3·50 लाख रु०
   - (ii) पाने वालों की सख्या . . 0·14 लाख

व्यय

विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय की कुल राशि
- (i) 1947-48 से 1952-53 तक[1]. 175·74 करोड रु०
- (ii) 1953-54 के लिए की गयी व्यवस्था 31·95 करोड़ रु०

तालिका 180

1951 में विस्थापित व्यक्तियों का राज्यवार आवंटन

(हजारों में)

राज्य	कुल जन-संख्या (क)	विस्थापित जन-सख्या (ख)
'क' भाग के राज्य		
1. आसाम . .	9,044	277
2. बिहार . .	40,226	79
3. बम्बई . .	35,956	341
4. मध्य प्रदेश . .	21,248	121
5. मद्रास . .	57,016	10
6. उडीसा . .	14,646	21
7. पजाब . .	12,641	2,468
8. उत्तर प्रदेश . .	63,216	476
9. पश्चिमी बगाल . .	24,810	2,118
योग .	2,78,803	5,911
'ख' भाग के राज्य		
10. हैदराबाद .	18,655	4
11. जम्मू और काश्मीर	जनगणना नही हुई	---
12 मध्य-भारत	7,954	68
13 मैसूर	9,075	8
14 पेप्सू . .	3,494	380
15 राजस्थान	15,291	313
16 सौराष्ट्र	4,137	61
17 तिरूवाकुर-कोचीन .	9,280	---
योग	67,886	834

(क) अंतिम योग। (ख) अस्थायी योग।

राज्य	कुल जनसंख्या (क)	विस्थापित जन-संख्या (ख)
'ग' भाग के राज्य		
18. अजमेर . .	683	72
19. भोपाल . .	836	18
20 बिलासपुर .	126	---
21 कुर्ग . .	229	---
22 दिल्ली . .	1,744	510
23 हिमाचल प्रदेश . .	983	5
24 कच्छ . . .	568	12
25 मणिपुर . .	578	1
26 त्रिपुरा . .	639	100
27 विन्ध्य-प्रदेश . .	3,575	15
योग .	9,971	733
28 अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह . . .	31	2
29 सिक्किम .	138	...
योग .	169	2
सर्व योग (ग)	3,56,289	7,480 (घ)

तालिका 181

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवार जिन्हें कृषि-योग्य भूमि पर बसाया गया (जून 1953) (च)

राज्य	बसाये गये परिवारो की संख्या	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ो मे)
पेप्सू	61,451	3,67,197 (ङ)
पंजाब	4,13,156	20,12,429 (ङ)
योग .	4,74,607	23,79,626 (ङ)
अस्थायी आवंटन		
अजमेर	235	1,981
भोपाल	827	10,840
बम्बई . .	1,198	12,492

(क) अन्तिम योग। (ख) अस्थायी योग।

(ग) जम्मू और काश्मीर के तथा आसाम के भाग 'ख' के जन-जातीय क्षेत्रो के आकड़े वहा जन-गणना-कार्य न होने के कारण नही दिये जा सके है।

(घ) प्रस्तुत अस्थायी योगों के अन्तर्गत (जिन का सम्बन्ध 1 मार्च 1951 से है) भारत आने के पश्चात उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, आसाम, उडीसा, मद्रास, विन्ध्य प्रदेश, पश्चिमी बगाल के कुछ भागो और बिहार मे विस्थापित व्यक्तियो के पैदा हुए शिशु भी सम्मिलित है। अन्य स्थानो मे पैदा हुए इस प्रकार के शिशु इन योगो के अन्तर्गत सम्मिलित नही है।

(ङ) 'प्रमापीकृत' (स्टैंडर्ड) एकड़।

(च) जहां जून 1953 के आकड़े अप्राप्य है वहा ताजे से ताजे आकडे ले लिये गये है।

राज्य	बसाये गये परिवारों की संख्या	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)
अस्थायी आवंटन—जारी		
दिल्ली .	1,177	12.690
हिमाचल प्रदेश	27	2,361
कच्छ .	326	2,400
मध्य भारत .	420	7.033
मध्य प्रदेश .	134	3.775
मनीपुर	1	[illegible]
राजस्थान . .	44,158	6,28.800
राजपुरा (पेप्सू) .	1,017	9,530
सौराष्ट्र . .	615	0,320
उत्तर-प्रदेश .	5,382	59 787
विन्ध्य प्रदेश .	306	4,201
योग .	55,823	7.65.215

तालिका 182

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए सरकारी भवन-निर्माण योजनाओं की प्रगति

(30 जून 1953)

राज्य	1952–53 के अन्त तक के लिए स्वीकृत भवन-निर्माण कार्यक्रम		
	बनाये जा चुके मकानों/वास-स्थानों की संख्या	उन मकानों/वास-स्थानों की संख्या जो बन रहे हैं या जिनका निर्माण विचाराधीन है।	योग
1	2	3	4
अजमेर . .	776	...	776
भोपाल . .	326	580	906
बिहार . . .	262	288	550
बम्बई . .	18,603	8,634	27.237
दिल्ली	31,381	6,819	38.200
कच्छ	3,320	400	3,720
मध्य-भारत .	1,403	70	1.473
मध्य-प्रदेश . .	2,313	4,000	6,313

1	2	3	4
मद्रास .	108	...	108
मैसूर . .	56	.	56
पेप्सू .	4,215	...	4,215
पंजाब .	32,349	529	32,878
राजस्थान .	1,435	500	1·935
सौराष्ट्र	1,501	725	2,226
उत्तर-प्रदेश (क)	14,604	2,801	17·405
विन्ध्य- प्रदेश	.	780	780
योग .	1,12,652	26,126	1,38,778

तालिका 183

काम दिलाऊ केन्द्रों द्वारा पंजीकृत और रोजगार में लगाये गये विस्थापित व्यक्ति

(30 जून 1953)

राज्य	वे विस्थापित व्यक्तियों जिन्हें	
	पंजीकृत किया गया है	रोजगार दिलवाया गया है
आसाम	17,370	2,499
बिहार	10,982	1,698
बम्बई	59,196	11,650
दिल्ली अजमेर और राजस्थान	1,52,890	20,315
हैदराबाद	143	42
मध्य प्रदेश	11,547	1,861
मद्रास	832	149
उड़ीसा	1,043	165
पंजाब	3,82,098	1,20,762
उत्तर प्रदेश	81,564	16,530
पश्चिमी [illegible] .	2,39,110	31,536
योग	9,56,775	2,07,207

दृष्टव्य : इस ब्यौरे के अन्तर्गत दो निर्माण-कार्य नहीं लिये गये हैं जो स्वयं विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अथवा सरकारी सहायता से उन की सहकारी समितियों द्वारा उठाये गये । ऐसे कार्यों की संख्या लगभग 42,000 है ।

जहां जून की रिपोर्ट प्राप्य नहीं थीं वहां ताजे से ताजे आंकड़े ले लिये गये हैं ।

(क) अस्थायी ।

तालिका 184

श्रम मंत्रालय के अधीन संचालित प्रशिक्षण योजनाओं की प्रगति

(30 जून 1953)

राज्य	उन विस्थापित व्यक्तियों की सख्या जो प्रशिक्षण पा चुके है				उन विस्थापित व्यक्तियो की सख्या जो प्रशिक्षण पा रहे है			
	टेकनिकल	व्याव-सायिक	शिक्षार्थी	योग	टेकनिकल	व्याव-सायिक	शिक्षार्थी	योग
आसाम .	36	32	—	68	89	31	—	120
बिहार .	156	16	—	172	58	—	—	58
बम्बई .	423	93	26	542	42	11	—	53
दिल्ली }	1,210	612	176	1,998	123	—	—	123
अजमेर }					13	—	—	13
राजस्थान }					9	—	—	9
मध्यप्रदेश .	121	100	—	221	60	—	—	60
उड़ीसा .	46	—	—	46	76	—	—	76
पजाब .	2,473	416	1,415	4,304	153	—	—	153
उत्तर प्रदेश .	2,526	553	947	4,026	471	—	289	760
पश्चिम बगाल	1,911	386	1,451	3,748	803	156	247	1,206
योग	8,902	2,208	4,015	(क) 15,125	1,897	198	536	2,631

तालिका 185

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए बनायी गयीं प्रशिक्षण योजनाओं की प्रगति

(30 जून 1953)

राज्य/उप-नगर	उन विस्थापित व्यक्तियों की सख्या जिन्हे प्रशिक्षण	
	दिया जा चुका है	दिया जा रहा है
1	2	3
अजमेर .	394	146
भोपाल . .	1,294	143
बम्बई . . .	6,031 (ख)	801

(क) इसके अतिरिक्त 285 और व्यक्तियों को भी हाल ही मे प्रशिक्षण दिया गया है। इन व्यक्तियों के राज्य-वार आवटन के विषय मे सूचना प्राप्त नही है।

(ख) ताजी सूचनाओ के आधार पर सख्याओ मे सशोधन किया गया है।

1	2	3
दिल्ली . . .	10,426 (क)	1,419
मध्य भारत . .	2,200	146
पेप्सू . . .	1,261	181
पंजाब . . .	15,101 (क)	3,163
राजस्थान . .	256	744
सौराष्ट्र . .	592	267
उत्तर प्रदेश . .	7,759	1,458
फरीदाबाद उप-नगर . .	—	39
नीलोखरी उप-नगर . .	3,010	191
राजपुरा उप-नगर . .	717	310
योल शिविर में बसे काश्मीरी विस्थापित व्यक्ति . .	1,443	—
योग .	50,484	9,008

तालिका 186

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिया गया ऋण

(30 जून 1953)

प्रांत/राज्य जो प्रार्थी का मूल निवास-स्थान था	प्राप्त आवेदनपत्रों की कुल सख्या	उन आवेदन-पत्रों की सख्या जिनका निबटारा कर दिया गया	स्वीकृत आवेदन-पत्र	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	प्रदत्त राशि (लाख रुपयों में)
बहावलपुर राज्य .	959	750	246	19·72	9·16
बलोचिस्तान .	898	787	212	16·80	9·79
पूर्वी पाकिस्तान .	18,819	12,887	3,816	286·93	160·21
उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त . .	4,261	2,882	774	58·96	36·01
सिंध और खैरपुर राज्य	19,572	15,574	3,893	281·92	152·91
पश्चिमी पंजाब .	19,490	15,530	4,140	372·90	254·95
अन्य . .	1,696	358	—	—	—
योग .	65,695	48,768	13,081	1,037·23	623·03

(फुटनोट देखिए पृष्ठ 402 पर)

द्रष्टव्य :

इस ब्यौरे के अन्तर्गत डी० जी० आर० ई० के अधीन सचालित योजनाओ के अतिरिक्त सभी योजनाए ली गयी है। इन योजनाओ को या तो सरकार सीधे स्वय चलाती है या ऐसी सम्मानित गैर-सरकारी सस्थाओ द्वारा चलवाती है जिन्हे सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त है।

जहा जून 1953 की रिपोर्ट नही मिली वहा ताजी से ताजी प्राप्य सूचना को आधार बनाया गया।

(क) ताजी सूचनाओं के आधार पर संख्याओं में संशोधन किया गया है।

तालिका 187

पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर किया गया कुल व्यय (1947–48 से 1952–53 तक) (क)

(लाख रुपयों में)

	पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो पर	योग
1. अनुदान			
(i) सहायता (जिसमें कर्मचारी-मंडल पर व्यय, निष्क्रांति व्यय, आदि सम्मिलित हैं) .	4640·22	1546·66	6186·88
(ii) पुनर्वास .	1018·48	570·81	1589·29
योग .	5658·70	2117·47	7776·17
२. ऋण			
(i) शहरी .	1078.67	595·93	1674.60
(ii) ग्रामीण .	911.17(ख)	782.92(ख)	1694.09
(iii) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन	—	—	521.90
योग .	1989.84	1378.85	3890.59
३. आवास-प्रबन्ध			
(i) ऋण . .	3126.58	1170.55	4297.13
(ii) असैनिक कार्यों पर लगाई गई पूंजी .	1462.34	—	1462.34
(iii) शेयर-क्रय .	55·00	—	55·00
योग .	4643.92	1170.55	5814.47
४. परिस्थापना			
पुनर्वास मंत्रालय का सचिवालय . .	86.40	6.14	92.54
५. पाकिस्तान से आगमन-बढ़ाव नियंत्रण विधि की व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले व्यक्तियों की शारीरिक निष्क्रान्ति . .	0.51	—	0.51
कुल योग .	12379·37(ग)	4673·01(ग)	17574 28

1. खोले गये ऋण खातों की कुल सख्या	8,070
2. 30–6–1953 तक जो किश्तें देनी बकाया थीं	94·80 लाख रु०
3. 30–6–1953 तक जो किश्तें मिल चुकी थीं	45·87 लाख रु०

(क) 1951–52 और 1952–53 के आंकड़ो का अन्तिम अनुदान राशि से सम्बन्ध है ।

(ख) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो के लिए ।

(ग) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों के अतिरिक्त ।

चौबीसवां अध्याय

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े हुए वर्ग

पिछड़े हुए वर्गों मे जो दो मुख्य समूह आते हैं उनमे अनुसूचित जातिया और अनुसूचित जनजातिया हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 5 करोड़ 14 लाख है और वह विभिन्न उपवर्गों मे बटे हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लोगो की सख्या 1 करोड़ 91 लाख है। पिछड़े हुए वर्गों की कुल आबादी 3 करोड़ 56 लाख 60 हजार है जिनमे 2 करोड़ 94 लाख 80 हजार गावो मे तथा 61 लाख 80 हजार शहरी इलाको मे बसते है। सविधान मे इन जातियों के कल्याण के लिए तथा किसी भी रूप मे उनके साथ भेदभाव का बर्ताव करने के विरुद्ध बड़ा ही सरक्षण है।

सविधान मे बचाव

सविधान के पद्रहवे अनुच्छेद के अनुसार धर्म नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेद रखना निषिद्ध है। इन कारणो से किसी भी नागरिक को रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरजनगृहो तथा उन स्थानो मे रोका नही जा सकता जिन पर राष्ट्रीय कोष से पूर्णत या अशत खर्च होता है या जो आम जनता के समर्पित है।

सत्रहवे अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत समाप्त कर दी गयी और किसी भी रूप मे इसका पालन निषिद्ध है।

पचीसवे अनुच्छेद के अनुसार राज्यो को यह अधिकार दिया गया है कि वे हिन्दू मन्दिरो इत्यादि मे सब हिन्दुओ के प्रवेश के सम्बन्ध मे कानून बना सकते है या इसके सम्बन्ध मे जो कानून है, उनको जारी रख सकते है।

उन्तीसवे अनुच्छेद मे यह बता दिया गया है कि राष्ट्र के द्वारा चलाई जाने वाली सहायता प्राप्त किसी भी सस्था मे नागरिको को धर्म, नस्ल या जाति या भाषा के आधार पर रोका नही जा सकता।

राष्ट्र की नीति के नियामक सिद्धातो मे दो बाते जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उनमे से एक तो यह है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा जनता का कल्याण करे। दूसरा नियम यह है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के लोगो, विशेष कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगो की शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक सुविधाओं की रक्षा करे और हर हालत मे सामाजिक अन्याय तथा सभी तरह के शोषण से उनकी रक्षा करे।

सविधान के 338वे अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने 18 नवम्बर 1950 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया। इस अनुच्छेद की धारा द, के अनुसार आयोग के कार्य यह है कि सविधान मे बनाए गये सब बचावो की जाच करे तथा उनके अनुसार होने वाली कार्रवाइयों की उतने उतने अरसे मे रिपोर्ट दे जैसा कि राष्ट्रपति आदेश दे।

तालिका 190 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्यों के विधान मंडलों में कौन सी विधियां पारित हुई, यह दिखाया गया है। जहां तक 'ख' भाग के राज्यों का सम्बन्ध है, सूचनाएं अभी सम्पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हैं। हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, सौराष्ट्र और त्रिवांकुर-कोचीन में इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। जो विधियां 'क' भाग के राज्यों में लागू हैं, केन्द्रीय सरकार ने उन्हें 'ख' भाग के राज्यों पर भी लागू कर दिया है।

सेवाओं में संरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 335 में यह कहा गया है कि प्रशासन की कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को केन्द्र तथा राज्यों की सेवाओं में स्थान दिया जाए। केन्द्र तथा राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में किस प्रकार कार्य करेंगी यह अनुच्छेद 16 (4) में साफ कर दिया गया है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो, राज्यों को किसी भी पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों में नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संरक्षण कायम करने का अधिकार होगा बशर्ते कि राज्य की राय में उस वर्ग को राज्य सरकार की सेवाओं में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

1934 में ही भारत सरकार ने यह आज्ञा दी थी कि इन वर्गों के योग्य व्यक्तियों को केवल इस कारण नौकरियों से वंचित न किया जाये कि वे खुली प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकते। उस समय यह जरूरी नहीं समझा गया कि इन वर्गों के लिए नौकरियों का कुछ निर्दिष्ट प्रतिशत रिजर्व रखा जाये, पर 1942 में यह पता लगा कि उन्हें उस नियम से कोई फायदा नहीं पहुंचा। भारत सरकार का यह मत था कि योग्य उम्मीदवार प्राप्त न होने के कारण ऐसा हो रहा है। फिर यह उचित समझा गया कि उनके लिए कुछ नौकरियां सुरक्षित कर दी जायें, तब लोग आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की ओर झुकेंगे। यह समझा गया कि उम्र सम्बन्धी नियमों को ढीला करने तथा परीक्षाओं की फीस घटाने से उपयुक्त वातावरण उत्पन्न होगा। तदनुसार अगस्त 1943 में $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत रिक्त स्थान उनके लिए सुरक्षित कर दिए गए, पर यह केवल सीधी भरती के मामलों में ही लागू थी। जून 1946 में संरक्षण का प्रतिशत बढ़ा कर $12\frac{1}{2}$ कर दिया गया अर्थात यह प्रतिशत देश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के बराबर कर दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह तय हुआ कि प्रतियोगिता के आधार पर रिक्त स्थानों में उसमें $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रहे। बाकी सब नौकरियों के लिए सुरक्षित भाग $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत कर दिया गया।

इसीके साथ साथ सारे देश में नियुक्तकारी अधिकारियों विशेष कर आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अधिकारियों को यह आज्ञा दी गई कि वे अनुसूचित जातियों के योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की बात याद रखें। जुलाई 1949 में उम्र तथा फीस के सम्बन्ध में अब तक जो रियायतें, अनुसूचित जातियों को दी जाती हैं वे अब अनुसूचित जनजातियों को भी दी जाने लगीं।

संसद् तथा विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व

संविधान के लागू होने के दिन से लेकर दस वर्षों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संसद् और राज्यों के विधान मंडलों में विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। संविधान के 330, 332 और 334 अनुच्छेद में यह आदेश है। इस सम्बन्ध में परिस्थिति क्या है यह तालिका 191 और 192 में देखी जा सकती है।

ंत्रियों की नियुक्ति

सविधान के 164 वें अनुच्छेद के प्रतिबन्ध 1 तथा 238 अनुच्छेद की छठी धारा के अनुसार ाध्य भारत, मध्य प्रदेश, बिहार और उडीसा के लिए यह जरूरी है कि वह अनुसूचित जनजातियो, ानुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गो के कल्याण पर देख रेख रखने के लिए मत्री नियुक्त रे। कुछ दूसरे राज्यों में भी इन लोगों के कल्याण के विभाग खोले हुए है। केन्द्रीय तथा राज्य ारकार मे जितने मत्री, उपमत्री तथा संसदीय सचिव हे उनमे स 31 अनुसूचित जातियो तथा पछड़े हुए वर्गों के ह।

अनुसूचित तथा जनजातीय इलाके

यह तो पहिले ही बताया जा चुका है कि संविधान म पिछड़े हुए वर्गो के कल्याण ़े लिए विशेष रूप से वर्णन है। पिछड़े हुए इलाकों को सविधान के पचम अनुच्छेद े पैरा छः के अनुसार आसाम के अतिरिक्त 'क' तथा 'ख' भाग के राज्यो मे अनुसूचित इलाके था आसाम म जनजातीय इलाके करार दिए गए। जिन राज्यो मे अनुसूचित इलाके है, उनमे सविधान के पचम अनुच्छेद के पेरा चार के अनुसार एक जनजाति परामर्श परिषद् कायम करने की ात की गई है, जो राज्यपाल या राजप्रमुख को अनसूचित जातियो की उन्नति तथा कल्याण के म्बन्ध मे परामर्श देगी। यदि राष्ट्रपति आज्ञा दे तो ऐसे किसी भी राज्य मे इस प्रकार की परिषद् नेयुक्त हो सकती है, जिसमे अनुसूचित जनजातिया तो हे, पर अनसूचित इलाके नही हे। इस समय क बिहार, मध्य भारत,मध्य प्रदेश, मद्रास, उडीसा, पजाब और राजस्थान, बम्बई और हैदराबाद ं जनजाति परामर्श परिषद कायम हो चुकी है। राष्ट्रपति ने यह आज्ञा दी है कि पश्चिमी बगाल े भी इस प्रकार की एक परिषद् खोली जाये।

सविधान की पचम अनुसूची के तीसरे पेरा के अनुसार किसी ऐसे राज्य के र ... राजप्रमुख को जिसके किसी भाग को अनसूचित इलाका घोषित किया गया है प्रतिवर्ष इन इलाकों क प्रशासन के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देना पडेगा।

यह स्मरण रहे कि अनुसूचित जनजातियो के मामले अनुसूचित जातियो की तरह जटिल नही है, क्योंकि शोषित लोगो के विरुद्ध समाज मे जिस प्रकार की विरोधी धारणाए है, उनके विरुद्ध वैसी नही है। शताब्दियों से अनुसूचित जनजातिया घने जगलो और पहाडो मे रहती थी। इसलिए वह समाज से दूर रहती हे। उनको उन्नत करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है, और कुछ राज्यो ने उनकी उन्नति के लिए पचवर्षीय योजना बनाई है। इसके लिए उन्हे सविधान के 205वें अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय सरकार मे यथेष्ट सहायता मिलती है। 1952 के जून मे अनुसूचित जनजातियो तथा अनुसूचित इलाको का एक सम्मेलन बुलाया गया था, और उसमे अनुसूचित जनजातियो की उन्नति तथा अनुसूचित इलाको के विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी।

शिक्षा तथा अन्य कल्याण योजनाएं

सविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार जनता के कमजोर हिस्से विशेष कर अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा सम्बन्धी और आर्थिक हितो को विशेष रूप से उन्नयन और उन्हे सब तरह के शोषण के साथ सामाजिक अन्याय से बचाने की बात की गई है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो ने इस सम्बन्ध मे बहुत कुछ कार्य किया है।

1951-52 में जहा अनुसूचित जातियो तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण कार्य के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च हुए थे वहां 1952-53 में यह खर्च 3 करोड़ 50 लाख रुपये था, और 1953-54 में यह खर्च 5 करोड 20 लाख रुपये कर दिया गया।

भारत सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रो के लिए छात्रवृत्तिया देती है। तालिका 188 में इसका लेखा प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 188

(रुपयो में)

व्यय	1951-52		1952-53
	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत
अनुसूचित जातियां .	8,25,000	8,17,976	14,50,000
अनुसूचित जनजातियां .	3,00,000	2,81,780	5,00,000
अन्य पिछड़ी जातियां .	3,75,000	4,41,186	10,50,000
योग .	15,00,000	15,40,942	30,00,000

दिसम्बर 1952 के अन्त तक अनुसूचित जातियो को 3,065, अनुसूचित जनजातियो को 1,094 तथा दूसरे पिछडे हुए वर्गो को 1,734 छात्रवृत्तिया दी गई याने कुल मिला कर 5,893 छात्रवृत्तिया दी गई। पूर्व वर्षो की तुलना मे इन जातियो के लोगो ने चिकित्सा, इजीनियरिग, कृषि इत्यादि की शिक्षा प्राप्त की। यह देखा गया था कि बहुत से छात्र गरीबी के कारण मैट्रिक या इटर के बाद पढ़ना छोड देते है। कुछ राज्यो मे इन छात्रो को शिक्षा के सब सोपानो मे फीस से मुक्त कर दिया गया है, पर कुछ राज्यो मे उन्हे ये रियायते केवल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयो मे दी जाती है। भारत सरकार ने सब राज्यो से यह कहा है कि वे उन जातियो के छात्रों को सब सोपानो मे निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार करें।

विकास योजनाएं

सविधान के 275वे अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो को इसलिए अनुदान देगी कि वे पिछडे हुए वर्गो के लाभ के लिए विकास योजनाओ को आगे बढावें। 1951-52 के 'क' तथा 'ख' भाग के राज्यों को इसके अनुसार 1 करोड़ 74 लाख 75 हजार रुपयें, 1952-53 मे 1 करोड 80 लाख रु० का अनुदान दिया गया। 1952-53 मे भारत सरकार ने 'ग' भाग के राज्यो को जनजातियों के कल्याण के लिए 24 लाख रुपया और दिया। इस सम्बन्ध मे भारत सरकार अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो के आयुक्त की सलाह से कार्य करती है।

पंचवर्षीय योजना के लाभ

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गो के लिए पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ रु० की व्यवस्था है। जनजातियों के इलाकों की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण तथा विकास के महत्व पर भी विचार किया है।

पंचवर्षीय योजना के अनुसार 'क' भाग के राज्य 1,548 लाख रुपये, 'ख' भाग के राज्य 316·6 लाख रुपये तथा 'ग' भाग के राज्य 22·5 लाख रुपये खर्च करेंगे। यह किस प्रकार वितरित है नीचे देखा जा सकता है :

	राशि (लाख रुपयों में)
'क' भाग के राज्य	
आसाम	209·6
बिहार	160·0
बम्बई	213·6
मध्य प्रदेश	136·4
मद्रास	467·6
पंजाब	116·4
उड़ीसा	...
उत्तर प्रदेश	236·2
पश्चिमी बंगाल	8·3
	1,548·1
'ख' भाग के राज्य	
हैदराबाद	...
मध्य भारत	80·0
मैसूर	100·0
पेप्सू	10·0
राजस्थान	42·2
सौराष्ट्र	24·4
तिरुवांकुर-कोचीन	60·0
	316·6
'ग' भाग के राज्य	
अजमेर	...
भोपाल	5·0
बिलासपुर	...
कुर्ग	...
दिल्ली	...
हिमाचल प्रदेश	...
कच्छ	2·5
मणिपुर	...
त्रिपुरा	...
विन्ध्य प्रदेश	15·0
	22·5
सब राज्यों का सम्पूर्ण योग	1,887·2

तालिका 189

अनुसूचित और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए बनायी गयी कल्याण योजनाओं पर व्यय

(रुपयों में)

राज्य	अनुसूचित जातियां		अन्य पिछड़ी जातियां		योग	
	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (परिकल्पित)	1951-52 (वास्तविक)	1952-53 (परिकल्पित)	1951-52	1952-53
आसाम	1,836	1,836	18,036	18,036	19,872	19,872
बिहार	15,87,020	15,34,092	6,22,026	6,65,991	22,09,087	37,44,083
बम्बई	22,66,826	24,71,088	24,95,763	35,35,970	47,62,589	60,07,058
मध्य प्रदेश	1,06,716	1,24,965	—	—	1,06,716	1,24,965
मद्रास	1,00,86,289	1,26,18,598	13,04,214	18,71,800	1,13,90,503	1,44,90,398
पंजाब	7,98,300	5,52,700	—	—	7,98,300	5,52,700
उत्तर प्रदेश	39,20,000	49,62,000	4,75,300	5,60,200	43,95,300	55,22,200
पश्चिमी बंगाल	7,51,508	7,00,000	अप्राप्य	अप्राप्य	7,51,508	7,00,000
हैदराबाद	42,637	1,91,264	32,665	80,281	75,302	2,71,545
मध्य भारत	2,12,371	5,47,249	—	—	2,12,371	5,47,249
मैसूर	18,14,607	19,03,000	—	—	18,14,607	19,03,000
पेप्सू	3,78,137	8,01,138	—	—	3,78,137	8,01,138
राजस्थान	—	—	29,517	11,000	29,517	11,000
सौराष्ट्र	80,000	3,92,000	—	1,10,000	80,000	7,02,000
तिरुवांकुर-कोचीन	6,35,000	9,12,600	—	—	6,35,000	9,12,600
अजमेर	25,080	25,080	—	—	25,080	25,080
भोपाल	अप्राप्य	10,000	—	—	अप्राप्य	10,000
बिलासपुर	600	600	—	—	600	600
कुर्ग	50,000	50,000	—	—	50,000	50,000
दिल्ली	58,414	1,53,200	—	—	58,414	1,53,200
हिमाचल प्रदेश	—	2,45,840	—	—	अप्राप्य	2,45,840
कच्छ	10,780	53,400	—	—	10,780	53,400

द्रष्टव्य : जहां अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी जातियों को अलग-अलग नहीं लिया जाता वहां प्रशासन के कार्यों के लिए दोनों को संग ले लिया गया है।

पिछड़े हुए वर्ग

यद्यपि सविधान मे इस सम्बन्ध मे कुछ स्पष्ट नही कहा गया, फिर भी सामाजिक रूप से और शिक्षा मे पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को पिछड़े वर्ग का माना जाता है। संविधान के 15वे अनुच्छेद के अनुसार राज्य को अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त सामाजिक रूप से तथा शिक्षा मे पिछड़े हुए किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए विशेष नियम बनाने के अधिकार है। कुछ राज्यो मे अनुसूचित जातियो तथा पिछड़े हुए वर्गो मे कोई फर्क नही किया जाता है। विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए वर्गों की कल्याण योजनाओ पर खर्च का लेखा तालिका 189 मे प्रस्तुत किया गया है।

पिछड़े हुए वर्गो का आयोग

भारत सरकार ने श्री काका साहब कालेलकर के सभापतित्व मे एक पिछड़े हुए वर्गो का आयोग नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने 18 मार्च 1953 को इसका उद्घाटन किया। इसका काम तीन तरह का है: पहला तो यह है कि यह बताये कि कोई वर्ग या समूह पिछड़ा हुआ किस आधार पर माना जा सकता है। दूसरा कार्य है सारे भारत के लिए इस प्रकार के पिछड़े हुए वर्गो की एक सूची तैयार की जाये। तीसरा कार्य यह है कि वह पिछड़े हुए वर्गों की कठिनाइयों की जाच करे और उन्हे दूर करने के उपाय बताये।

आयोग जिस राज्य मे जाएगा, उस राज्य से कम से कम दो सदस्य ले सकेगा, जिसमे एक स्त्री हो सकती है। निर्देश्य शर्तो मे अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो तथा सामाजिक, आर्थिक रूप से और शिक्षा मे पिछड़े हुए कुछ अन्य समूह पर छानबीन करनी है। आयोग विभिन्न सरकारों तथा निजी सस्थाओं से प्राप्त तथ्यों पर अपना उपसहार अवलम्बित करेगा।

हिन्दुओं मे सामाजिक अनर्हताए दूर करने के लिए 31 दिसम्बर 1951 तक क्या किया गया, इसका लेखा इस प्रकार है:

तालिका 190

राज्य 1	स्वीकृत विधान 2	क्या इस कानून के अतर्गत आने वाले अपराध कार्य-वाही किये जाने योग्य है 3
1. बिहार	बिहार हरिजन (नागरिक-अनर्हताओ का निवारण) कानून, 1949 और संशोधन कानून, 1951	हा
2. बम्बई	(1) बम्बई हरिजन (नागरिक अनर्हताओं का निवारण), 1947	हा
	(2) बम्बई हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून, 1947	हां
3. मध्य प्रदेश	(1) सी० पी० और बरार अनुसूचित जातियां (नागरिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1947	हां
	(2) सी० पी० और बरार मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1947	हां
4. मद्रास	(1) नागरिक अनर्हताओं का निवारण कानून, 1938	हां
	(2) मद्रास मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1947 और सशोधन कानून, 1949	हां
5. उडीसा	(1) उडीसा (नागरिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1946	नही
	(2) उडीसा मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1948	हां

1	2	3
6. पंजाब .	पूर्वी पंजाब (धार्मिक और सामाजिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1947 .	हा
7. उत्तर प्रदेश	उ० प्र० (सामाजिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1947 . .	नही
8. पश्चिमी-बंगाल	पश्चिमी बंगाल हिन्दू (सामाजिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1948 .	हा
9. हैदराबाद .	(1) हैदराबाद हरिजन मन्दिर प्रवेश विनियम 1358 एफ० की स० 55 (1948-49) .	हां
	(2) हरिजन (सामाजिक अनर्हताओं का निवारण) विनियम 1358 एफ० की स० 56 (1948-49)	हा
10. मध्य भारत	हरिजन अनर्हताओं का (निवारण) कानून, 1949 और संशोधन कानून, 1950	हा
11 मैसूर .	(1) नागरिक अनर्हताओं का निवारण कानून, 1943	हा
	(2) 1948 और 1949 के संशोधन कानून .	हा
	(3) मैसूर मन्दिर-प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1948 और संशोधन, कानून, 1949	हा
12 सौराष्ट्र .	सामाजिक अनर्हताओं का निवारण अध्यादेश, 1948	हा
13 तिरुवाकुर-कोचीन	(1) तिरुवाकुर-कोचीन मन्दिर-प्रवेश (अनर्हता निवारण) कानून, 1950 .	हा
	(2) संयुक्त राज्य तिरुवाकुर-कोचीन (सामाजिक अनर्हता-निवारण) कानून, 1950	हा
14 अजमेर	उत्तर प्रदेश (सामाजिक अनर्हता निवारण) कानून, 1947, अजमेर राज्य पर भी लागू कर दिया गया	नही
15 भोपाल	उत्तर प्रदेश (सामाजिक अनर्हता निवारण) कानून, 1947, ... 1951 में भोपाल राज्य पर भी लागू कर दिया गया	नही
16 बिलासपुर.	उत्तर प्रदेश (सामाजिक अनर्हता निवारण) कानून, 1947, जून 1951 से बिलासपुर राज्य पर भी लागू कर दिया गया	नही
17. कुर्ग .	(1) कुर्ग अनुसूचित जातिया (नागरिक और सामाजिक) अनर्हता-निवारण) कानून, 1949 .	हां
	(2) कुर्ग मन्दिर-प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1949 .	नही
18 दिल्ली	बम्बई हरिजन (सामाजिक-अनर्हता-निवारण) कानून 1947 इस राज्य पर भी लागू कर दिया गया	हा
19 हिमाचल-प्रदेश .	उत्तर प्रदेश (सामाजिक-अनर्हता-निवारण) कानून 1947, मई 1951 से इस राज्य पर भी लागू कर दिया गया .	नही
20. कच्छ .	बम्बई हरिजन (सामाजिक-अनर्हता निवारण) कानून, 1947, मई 1951 से कच्छ राज्य पर भी लागू कर दिया गया . . .	हा
21. त्रिपुरा .	पश्चिमी-बंगाल हिन्दू (सामाजिक-अनर्हता-निवारण) कानून, 1948, मई 1951 से त्रिपुरा राज्य पर भी लागू कर दिया गया . . .	हां
22. विंध्य-प्रदेश	उत्तर प्रदेश (सामाजिक-अनर्हता-निवारण) कानून, 1947, विंध्यप्रदेश राज्य पर भी लागू कर दिया गया .	नही

नीचे यह दिखलाया गया है कि 1953 की मई के परिसीमन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी सीटों का प्रबंध ा। यह प्रस्ताव ताजी जनगणना के आधार पर किया गया है :

तालिका 191

राज्य अथवा क्षेत्र का नाम	लोक सभा में स्थानों की कुल संख्याएं	अनुसूचित जातियों के लिए सरक्षित स्थानों की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों के लिए सरक्षित स्थानों की संख्या
'क' भाग के राज्य :			
1. आंध्र . .	28	4	1
2. आसाम . .	12	1	2 1 (क)
3. बिहार . .	55	7	6
4. बम्बई . .	49	4	5
5. मध्य प्रदेश .	29	4	3
6. मद्रास . .	49	8	नहीं
7. उड़ीसा . .	20	4	4
8. पंजाब .	17	3	नहीं
9. उत्तर प्रदेश .	86	16	नहीं
10 पश्चिमी बंगाल .	34	6	2
'ख' भाग के राज्य :			
1. हैदराबाद .	25	4	नहीं
2. जम्मू और काश्मीर .	6 (ख)	नहीं	नहीं
3. मध्य भारत	11	2	1
4. मैसूर . .	13	2	नहीं
5. पेप्सू . .	5	1	नहीं
6. राजस्थान .	21	2	नहीं
7. सौराष्ट्र . .	6	नहीं	नहीं
8. तिरुवाकुर-कोचीन .	13	1	नहीं
'ग' भाग के राज्य :			
1. अजमेर . .	1	नहीं	नहीं
2. भोपाल . .	2	नहीं	नहीं
3. बिलासपुर .	1	नहीं	नहीं
4. कुर्ग . .	1	नहीं	नहीं
5. दिल्ली . .	3	नहीं	नहीं
6. हिमाचल प्रदेश .	2	नहीं	नहीं
7. कच्छ . .	2	नहीं	नहीं
8. मणिपुर . .	2	नहीं	1
9. त्रिपुरा . .	2	नहीं	1
10. विन्ध्य प्रदेश .	5	1	1
11. अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह .	1 (ख)	नहीं	नहीं
12. 'ख' भाग के जन-जातीय क्षेत्र . .	1 (ख)	नहीं	नहीं
योग .	502	71	28

(क) स्वसत्ता-प्राप्त जिलों में।

(ख) राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये जायेंगे।

राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं, इसका लेखा नीचे दिया गया है :

तालिका 192

राज्य का नाम	व्यवस्थापिका सभा में स्थानों की संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या	अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या
भाग 'क' के राज्य			
1 आन्ध्र . .	168	22	4
2 आसाम . .	108	5	{ 9(क) 17(ख)
3. बिहार	330	41	33
4 बम्बई .	294	25	27
5 मध्य प्रदेश .	232	32	27
6 मद्रास .	245	39	1
7 उड़ीसा	140	25	28
8 पंजाब .	119	22	—
9 उत्तर प्रदेश .	430	78	—
10 पश्चिमी बंगाल .	238	45	11
भाग 'ख' के राज्य			
1. हैदराबाद .	175	26	3
2. मध्यभारत .	99	16	13
3 मैसूर	117	21	—
4. पेप्सू .	60	12	—
5. राजस्थान	168	18	3
6. सौराष्ट्र .	60	2	1
7 तिरुवांकुर-कोचीन	104	10	—
भाग 'ग' के राज्य			
1 अजमेर	30	6	—
2 भोपाल	30	5	2
3 कुर्ग	24	3	3
4 दिल्ली .	48	6	—
5 हिमाचल प्रदेश	36	8	—
6 विन्ध्य प्रदेश .	60	6	6
योग	3,315	473	188

(क) जन-जातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त ।

(ख) स्वसत्ता-प्राप्त जिलों में ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरे पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को किन किन विषयों में छात्रवृत्तियां दी गई है, यह नीचे दिखाया गया है :

तालिका 193

अध्ययन विषय	छात्रवृत्ति प्राप्त लोगो की सख्या			
	अनुसूचित जातिया	अनुसूचित जनजातियां	अन्य पिछडी जातियां	योग
व्यावसायिक शिक्षा				
डाक्टरी	236	52	341	629
इजीनियरिंग	250	32	377	659
कृषि	59	11	80	150
पशु चिकित्सा सम्बन्धी	2	5	2	9
प्रौद्योगिक	16	2	2	20
कानूनी	119	19	30	168
अध्यापक प्रशिक्षण	27	11	45	83
कला-कौशल	3	1	4	8
				1,726
स्नातकोत्तर श्रेणी				
पी० एच० डी०	4	—	3	7
एम० एस० सी०	25	4	35	64
एम० ए०	138	29	27	194
एम० काम०	5	—	6	11
				276
स्नातक श्रेणी				
बी० एस० सी०	161	36	116	313
बी० ए०	235	190	118	543
बी० काम०	53	19	25	97
				953
प्राक-स्नातक श्रेणी				
आई० एस० सी०	807	179	340	1,326
आई० ए०	812	460	159	1,431
आई० काम०	113	44	24	181
				2,938
योग	3,065	1,094	1,734	5,893

पच्चीसवां अध्याय

'क' भाग के राज्य

आन्ध्र

राज्यपाल चन्दूलाल त्रिवेदी

मंत्री

1. मुख्य मंत्री तथा सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक, सूचना और प्रचार **विभाग**	टी० प्रकाशम
2. उप-मुख्य मंत्री, गृह, पुलिस, कानून और व्यवस्था, पासपोर्ट व्यवस्थापन, निर्वाचन, सार्वजनिक कार्य और यातायात	एन० संजीव रेड्डी
3. लगान, अन्न तथा रजिस्ट्रेशन . .	के० कोटि रेड्डी
4 वित्त, कानून, धर्मार्थ, परिगणित क्षेत्र तथा आदिवासी .	टी० विश्वनाथन
5. आयोजन, स्वास्थ्य, सहयोग, श्रम तथा हरिजन सेवा .	डी० सजीवय्या
6 शिक्षा, व्यवसाय, आन्तरिक कर, मद्यनिषेध, नारी उन्नति और व्यापारिक कर . . .	एस० बी० पी० पट्टाभि रामाराव
7. स्थानीय शासन, कृषि, जगल, पशुपालन तथा मछली व्यवसाय	पी० थिम्मा रेड्डी

आन्ध्र राज्य का जन्म 1 अक्तूबर 1953 को हुआ था और तब से करनूल इसकी अस्थाई राजधानी है। यह राज्य पहले मद्रास राज्य का भाग था। इसका क्षेत्रफल 67000 वर्गमील है और आबादी 2,12,82,000।

वित्त

आन्ध्र का 1953-54 का बजट इस प्रकार है :

	रुपये
आय	27,77,00,000
व्यय	22,80,00,000
बचत	4,97,00 000

शिक्षा

आन्ध्र विश्वविद्यालय की स्थापना आज से 27 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत के विश्वविद्यालयों मे इसका निर्माण अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। इस विश्वविद्यालय के अधीन 29 कालेज है और उनमे ज्ञान, विज्ञान, भारतीय अध्ययन, कानून, व्यापार, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि और शिक्षण की शिक्षा का प्रबन्ध है।

खाद्यान्न तथा कृषि

आन्ध्र की 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है और वहा अपनी आवश्यकता से 3 लाख टन अधिक अन्न उत्पन्न होता है। आन्ध्र मे 155 लाख एकड़ भूमि पर कृषि की जाती है। 1953–54 मे वहा 33 लाख टन चावल पैदा हुआ था। भारत में कुल जितना तमाखू उत्पन्न होता है, उसका 80 प्रतिशत आन्ध्र मे पैदा होता है।

पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत आन्ध्र मे दो जल विद्युत् कार्यों का निर्माण जारी है। उनमें से तुगभद्रा कार्य द्वारा आन्ध्र और मैसूर को लाभ होगा तथा मचकुण्ड कार्य द्वारा आन्ध्र और उडीसा को।

व्यवसाय

आन्ध्र मे चीनी के 7 कारखाने, सीमेन्ट के 2 कारखाने और शीशा, एनेमल, कागज़, वनस्पति और खांड की मिठाई बनाने के एक-एक कारखाने हैं। पंचवर्षीय आयोजना में इस राज्य के औद्योगिक विकास के लिए 46,28,000 रुपये स्वीकार किए गए हैं। विशाखापटनम के जहाजों के कारखाने का विकास तथा तेल शुद्धि का कारखाना खोलना वहा की योजना के मुख्य भाग हैं। विजयवाडा के निकट वुय्यूरू के चीनी के कारखाने में उप-उत्पादनों के व्यावसायिक प्रयोग का प्रबन्ध किया जा रहा है।

आन्ध्र विधान सभा

अध्यक्ष—एन० वेंकटरमैया

के० आदिकेसवलु नायडु (चन्द्रागिरि)
जी० अजनयलू (वन्दर)
के० अप्पला नायडु (श्रीकाकुलम्)
बोज्जा अप्पलास्वामी (अमलापुरम्, सरक्षित परिगणित जाति)
राजा मेका रगय्या अप्पाराव (नूजवीड)
टी० सी० अच्चन्ना नायडु (चीपुरुपल्ली)
वाइ० आदिनारायण रेड्डी (रायचोटी)
के० बालनारायण रेड्डी (प्रोद्दुतूर)
एम० बापैया चौदुरी (बेल्लमकोण्डा)
के० बाप्पन्ना दोरा (भद्राचलम सरक्षित परिगणित जाति)
जी० बापय्या (दिवी, सरक्षित परिगणित जाति)
पी० बापु नाइडू (येल्लमनचिल्ली)
डी० बस्विरेड्डी (पेनुगोण्डा)
चन्द्र रामलिंगय्या (दिवी, सरक्षित परिगणित जाति)
के० चवूराम नायडू (कन्दूकूर)
वी० चिदानन्दम् (बडवेल)
पी० चिन्नम्मा रेड्डी (चित्तूर)
वी० सी० चूडामणि देव (पार्वतीपुरम्)
डी० दशरथरमैया नायडू (रापूर)
एम० डोरयकन्नू (तिरुतानि, सरक्षित परिगणित जाति)
पी० वी० आर० गजपतिराजू (विजय नगरम्)
बी० गगैया नायडू (माडूगोल)
पी० गोपालकृष्ण रेड्डी (गूडूर)
वी० गोपालकृष्णैया (सेट्टनपल्ली)
के० गोविन्दराव (अनकापल्ली)
पी० गुन्नैया (चीपुरुपल्ली, संरक्षित परिगणित जाति)

एम० हनुमन्त राव (रेपल्ले)
चि० इन्द्रय्या (तणुकू)
जी० जोसेफ (अमरतलूर)
एस० कासीरेड्डी (दर्मी)
जी० सी० कोण्डय्या (आत्माकुर)
पी० कोटय्या (चीराला)
के० कोटि रेड्डी (कडप्पा)
श्रीमती तम्मा कोटम्मा रेड्डी (प्रत्तिपाडू)
वी० वी० कृष्णाम् राजु (तुनी)
बी० कृष्णमूर्ति राव (पुगनूर)
के० कृष्ण राव (नेल्लोर)
वाई० वी० कृष्ण राव (भद्राचलम्)
एम० कूने राव (चिन्तलपुडी)
एल० लक्ष्मणदास (पातपटनम्)
टी० लक्ष्मीनारायण रेड्डी (पेनूकोण्डा)
एम० लक्ष्मण स्वामी (कंकीपाडू)
डी० लक्ष्मैया (मगलगिरि)
आर० लक्ष्मी नरसिंहम दारा (टेक्कली)
वी० लक्ष्मीनरस राजू (नरसापुर)
जी० लच्चन्ना (सोमपेट)
के० मालकोडय्या (ओंगोल संरक्षित परिगणित जाति)
टी० मल्लय्या (अदोनी संरक्षित परिगणित जाति)
एस० आर० ए० पी० मूर्ति राजू (ताडेपल्ली गुडेम)
जी० नागभूषणम् (रायदुर्ग)
जी० नागेश्वर राव (गजाल)
ए० नागेश्वर राव (दुग्गीराला)
टी० नागि रेड्डी (अनन्तपुर)
एन० वी० एल० नरसिंह राव (गुन्तूर)
पी० नरसिंह रेड्डी (राजमपेट)
के० नारायण (श्रीकाकुलम्, संरक्षित परिगणित जाति)
एम० नारायणप्पा (कल्याण दुर्ग)
डी० नारायण राजू (उण्डी)
एम० नारायण स्वामी (ओंगोल)

ए० नीलाद्रिराव रेड्डी (इच्छापुरम्)
के० वी० एस० पद्मनाभ राजु (अलमण्डा)
के० पट्टाभिरामैया (रामचन्द्रपुरम्)
एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव (पामरू)
एम० पेन्टन्नायडू (पातपटनम्, संरक्षित परिगणित जन-जाति)
टी० पोता राजू (विजयवाडा)
सी० प्रभाकर चौधरी (राजामुन्द्री)
टी० प्रकाशम् (मुगवरपुकोटा)
सी० पुल्लारेड्डी (नन्दीकोटकुर)
पी० पुण्डरीकाक्षाचार्युलु (होजरम्)
के० राजगोपाल राव (गुडिवाडा)
एम० राजेश्वरराव (कोवूर, संरक्षित परिगणित जाति)
एन० रामभद्र राजू (अमलापुरम्)
डी० रामब्रह्मम (पलमनेर)
पी० एस० रामचन्द्र राव (कोवूर)
बी० रामकृष्ण रेड्डी (कावली)
एच० रामालिंगा रेड्डी (अदोनी)
के० राममूर्ति (गालगाण्डा)
जी० रामा राव (गुडिवाडा संरक्षित)
एन० वी० रामाराव (वनपुडी)
पी० रामाराव (तिरूवूर)
वी० रामाराव (कंचिकचेर्ला)
थोटा रामास्वामी (पेद्दापुरम्)
के० वी० रामेशम (चोडवरम्)
के० रमैया, चौधरी (उदयगिरि)
के० रमैया (जम्मल मडुगु)
के० रगा राव (चिलकलूरिपेटा)
पी० रगा रेड्डी (कम्बम)
सी० वी० के० राव (काकिनाडा)
पी० सगम नाइडू (पालकोण्डा)
एन० सजीव रेड्डी (कालाहस्ती)
डी० सजीवैया (करनूल, संरक्षित परिगणित जाति)
एन० शकर रेड्डी (करनूल)
बी० शकरय्या (कोवूर)

के० सांतप्पा (कल्याणदुर्ग, संरक्षित परिगणित जाति)
जी० सत्यनारायण (एलूरू)
एच० सत्यनारायण डोरा (नरसन्नापेट)
पी० सत्यनारायण रेड्डी (अनपर्ति)
डी० सीतारमैया (मदनपल्ली)
के० षनमुखम् (कण्डुकुर, संरक्षित पारिगणित जाति)
आर० सिद्धन्ना गौड (मड़कसिरा)
एन० शिवरामी रेड्डी (कमलापुरम्)
जी० शिवशंकर रेड्डी (हिन्दुपुर)
वी० श्री कृष्णा (बापत्ला)
के० श्रीनिवासुलु (धर्मवरम्)
श्रीरामम् (चित्तूर, संरक्षित परिगणित जाति)
वी० सुब्बा राजू (भीमवरम्)
के० सुब्बा रेड्डी (पलनाड)
एम० सुब्बा रेड्डी (नन्द्याल)
सी० सुब्बारायडु (नाडिपत्री)
आर० वी० वी० सुदर्शन वर्मा (कारवेतिनगर)
पी० सूर्यचन्द्र राव (आलम्पुरम्)
जी० सूर्यनारायण (विजयनगरम् संरक्षित परिगणित जाति)
के० सूर्यनारायण (भीमुनीपटनम्)
सूर्यनारायण राजू (पयकाराओपेट)
पी० श्यामसुन्दर राव (नरसपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
पी० थिम्मा रेड्डी (पीलेरू)
के० वरदाचारी (तिरुत्तनी)
एम० वीरभद्रम (परवड)
के० वीरन्ना पडाल (गोल्लुगोण्डा) संरक्षित परिगणित जन जाति
के० वी० वेमा रेड्डी (कदिरि)
एस० वेमैय्या (नेल्लोर संरक्षित परिगणित जाति)
के० वेकय्या (पोन्नूर)
आर० वेकटजग्गा राव (पिठापुरम्)
के० वेकट कुर्मी नायड (बोबिली)
ए० वेकटरामराजु (राजोल)
एन० वेंकटरामैय्या (नरसराओपेट)
के० वेकट शेट्टी (धोन)
पी० वेकट शिवैय्या (विनूकोण्डा)
एम० वेकट सुब्बा रेड्डी (कुयलकुन्टला)
टी० एन० वेकट सुब्ब रेड्डी (घट्टूर)
पी० वेकटसुब्बैय्या (राजमपेट संरक्षित परिगणित जाति)
ए० वेकटसुब्रमण्यम् (कैकलूर)
एन० वेकटय्या (मार्कपुर)
पी० वेकटेश्वरलू (जग्गय्यापेट)
के० वेकट नारायण डोरा (मालुरू)
ए० वेकटरमैय्या (तेनाली)
एस० वेंकटराव (काकीनाड, संरक्षित परिगणित जाति)
पी० वेंकटस्वामी रेड्डी (वेकटगिरी)
टी० विश्वनाथम् (विशाखपत्तनम्)
जी० येलमन्दा रेड्डी (कनिगिरि)

आसाम

राज्यपाल — जयरामदास दौलतराम

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, गृह, नियुक्ति, समन्वय तथा आ [illegible] सियों की उन्नति . . . विष्णुराम मेधी
2. वित्त तथा लगान . . . मोतीराम बोरा
3. सार्वजनिक कार्य तथा यातायात . सिद्धिनाथ शर्मा
4. श्रम, शि [illegible] -विकास . ओमियोकुमार दास

5. अन्न, कृषि, सहयोग, प्रचार तथा कुटीर व्यवसाय	.	महेन्द्र मोहन चौधरी
6. पूर्त्ति, व्यापार और वाणिज्य .	.	वैद्यनाथ मुखर्जी
7. न्याय और स्वास्थ्य . .	.	रूपनाथ ब्रह्म
8. जंगल, व्यवस्थापन और बिजली .	.	रामनाथदास
9. आन्तरिक कर, जेल, रजिस्ट्रेशन तथा स्टैम्प	.	जे० जे० एम० निकोलस राय
10. स्थानीय स्वराज्य, पशु चिकित्सा तथा पशुवृद्धि विभाग	.	अब्दुल मतलिब मजूमदार

उपमंत्री

1. लगान. सहायता तथा पुनर्वास .	.	हरेश्वर दास
2. श्रम और शिक्षा . .	.	पूर्णानन्द चेटिया

वित्त

(लाख रुपयो मे)

बजट के आंकडे		आय	व्यय	बचत (+) या घाटा (—)
1950-51	(लेखा)	9,92	9,28	+ 64
1951-52	(लेखा)	11,29	10,93	+ 36
1952-53	(सशोधित)	12,72	12,68	+ 4
1953-54	(बजट)	13,01	14,97	— 196

शिक्षा

1952-53 मे आसाम मे सब तरह की शिक्षा सस्थाओं की उन्नति हुई। 1951-52 मे वहा प्रारम्भिक स्कूलों की सख्या, 9,610 थी, जो गत वर्ष बढ कर 9,860 हो गई। इसी तरह शिक्षकों की सख्या 14,253 से 14,603 और विद्यार्थियो की सख्या 5,69,640 से बढ कर 6,00,000 हो गई। 1953-54 में वहा शिक्षा पर 72,29,000 रुपया खर्च किया गया।

गत वर्ष वहां 11 सब-डिविजनों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। आजकल 12 नगरो और 4,000 गावों मे शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है और उसके अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष तक की आयु के 2,80,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे है। परिगणित जातियों तथा आदिवासियों मे भी शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार किया जा रहा है।

गत वर्ष ऐसे प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या, जिनमें बेसिक ढंग की शिक्षा दी जाती है, 142 तक पहुंच गई। 1951 में वहां शिक्षा पर 33,21,000 रुपये व्यय किए गए और 1952-53 में 47,26,000। माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय संस्थाओं को काफी बड़ी संख्या में सहायता दी गई। पहाड़वासियों को आसामी भाषा की शिक्षा देने के लिए टीटाबर प्रशिक्षण संस्था में एक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र जारी किया गया। इस केन्द्र में 33,000 रुपयों के व्यय से प्रति वर्ष 40

शिक्षक तैयार किए जायेंगे। 1952–53 में माध्यमिक श्रेणियों में हिन्दी और सामाजिक सेवाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को राज्य की सरकार ने हिन्दी के प्रचार के लिए 25,000 रुपये दिये।

खाद्य तथा कृषि

1952–53 में चीनी, रूई, सुपारी तथा जूट के अनुसंधान के लिए कई योजनाएं जारी की गईं। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत एक सप्तमुखी कार्य शुरू किया गया। इसके अनुसार अच्छे बीज, खाद, सिंचाई का प्रबन्ध, पौधों की रक्षा, व्यर्थ भूमि का उपयोग तथा वर्ष में दो बार फसल पैदा करने के कार्य भी प्रारम्भ किए गए।

गत वर्ष 5,00,000 रुपये के व्यय से सिंचाई के 900 छोटे-छोटे कार्य चालू किए गए। इनसे अन्न की उपज मे 35,000 टन की वृद्धि होने की आशा है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो सिंचाई के 24 बड़े-बड़े कार्यों का निर्माण कर रहा है, उनमें से 8 गत वर्ष पूरे कर लिए गए। इसके अतिरिक्त 47,492 एकड परती भूमि को उपजाऊ बना लिया गया और वह कृषिरहित किसानों और शरणार्थियो मे बाट दी गई।

उद्योग

15 अगस्त 1952 से 31 मार्च 1953 तक राज्य के कुटीर उद्योग विभाग ने घरेलू उद्योगों की उन्नति के लिए 54,500 रुपये उधार दिए। इसी तरह छोटे उद्योगो के विकास के लिए राज्य की ओर से कुछ और सहायताएं भी दी गई। पहाड़ी प्रदेशों मे शहद उद्योग को उन्नत करने का प्रयत्न किया गया तथा चापरमुख मे एक वारनिश बनाने के कारखाने का निर्माण जारी किया गया।

गत वर्ष चाय बागान, चावल तथा तेल की मिलों, मोटर और यातायात के कार्यों मे काम करने वाले मजदूरो का न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिया गया। चाय बागान के वेतनो पर अभी पुनर्विचार किया जाएगा। इन साधनों द्वारा चाय के 27 बगीचो को बन्द होने से बचा लिया गया, क्योंकि राज्य का चाय-व्यवसाय एक बड़े सकट मे से गुज़र रहा था।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों मे कालाज़ार के इलाज के लिए 2 अस्पताल खोले गए। दुदनाई तथा गोलपाड़ा जिलों में भी 20–22 बिस्तरों के दो कालाजार अस्पताल खोले जाएंगे। पेट के कीड़ों तथा मलेरिया से बचाव का प्रयत्न भी किया गया और 20,000 रुपयों की दवाइयां मुफ्त बांटी गईं। इन्हीं दिनों कोढ के सम्बन्ध में जाच पड़ताल करने का व्यापक प्रयत्न किया गया। कोढ़ के 37 अस्पतालों में 429 रोगियों की चिकित्सा की गई और 251 रोगियों की चिकित्सा अभी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चाओं के लिए तथा शिशुओं की चिकित्सा के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त किया गया। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को चिकित्सा सम्बन्धी विशेष सहायता पहुंचाई गई और संक्रामक बीमारियों को रोकने का अधिकाधिक प्रयत्न किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था के अधीन स्त्रियों और बच्चों को 498 दुग्धचूर्ण के पीपे बांटे गए।

आसाम विधान सभा

अध्यक्ष—कुलधर चलिहा

ए० अल्ले (नगपो., सरक्षित परिगणित जन जाति)
आरान संगमा (दैनाडूबी, सरक्षित परिगणित जन जाति)
अब्दुल मतलीब मजुमदार (हाइला कादि)
अब्दुल जलील (बदरपुर)
अजित नारायण देव (कोकराझर, सिदली)
ए० एस० खोगफाई (नोगस्टोन, सरक्षित परिगणित जन जाति)
अक्षयकुमार दास (सरभोग)
आनन्दचन्द्र बेजबरुवा (नाजिरा)
वैद्यनाथ मुकर्जी (रातावादी पाथरकादी)
बैकुण्ठनाथ दास (पतचरकुशी बारमा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
डालीराम दास (मरीगाव बिंग, सरक्षित परिगणित जन जाति)
विजयचन्द्र भागवती (सूतिया)
विमला कान्त बोरा (जमुनामुख)
विष्णुराम मेधी (हाजो)
विश्वदेव शर्मा (तेजपुर उत्तर)
बु० च० सपरगा (आइजल पश्चिम सरक्षित परिगणित जन जाति)
चानू खेरिया (गोलाघाट पश्चिम)
दलवीरसिंग लोहार (डिगबोय)
दण्डीराम दत्त (कलियाइगाव)
डेविडसन भोबोरा (पानेरी, सरक्षित परिगणित जन जाति)
देवेश्वर राजखोवा (डेरगाव)
धरणीधर वसुमतारी (रगिया, सरक्षित परिगणित जन जाति)
एमर्नसिंग सगमा (फुलवारी, संरक्षित परिगणित जन जाति)
एमारसन मोमिन (तुरा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
फैजनूर अली (डिब्रूगढ पश्चिम)
गहनचन्द्र गोस्वामी (गोहपुर)
गौरीशकर भट्टाचार्य (गौहाटी)
गौरीशकर राय (कातलीचेरा)
घनकान्त गगै (मोरान)
गिरीन्द्रनाथ गग (शिवसागर)
हाकिमचन्द्र राभा (गोआलपाडा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
हरेश्वर दास (उत्तर सालमरा)
हरेश्वर गोस्वामी (पलाशवारी)
हरिहर चौधुरी (डूमडूमा)
हैरिसन मोमिन (वाधमर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
हरिनारायण बरुवा (तियक)
हेमचन्द्र चक्रवर्ती (हाइला कान्दि, शिलचर)
हेमचन्द्र हजारिका (उत्तर लखीमपुर)
नरनारायण गौस्वामी (पतचरकुची, बरमा)
इन्द्रेश्वर खाउन्द (तिनसुकिया उत्तर)
यादवचन्द्र खाखलाड़ी (डिगबोई, सरक्षित परिगणित जन जाति)
यदुनाथ भूयान (तिनसुकिया दक्षिण)
यतीन्द्र नारायण दास (गोसाइगाव)
जयभद्र हगजर (उत्तर कछार पहाडिया, सरक्षित परिगणित जन जाति)
जे० जे० एम० निकोलस राय (शिलाग)
योगकान्त बरुवा (जयपुर)
कमलाप्रसाद अगरवाल (तेजपुर दक्षिण)
खगेन्द्रनाथ (गोयालपारा)
कार्कचन्द्र दोले (उत्तर लखीमपुर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
खर्रसिह तेराग (मिकिर पहाड़िया, पूर्व संरक्षित परिगणित जन जाति)
किष्टोविन रिम्बाय (जावाय, सरक्षित परिगणित जन जाति)

कोबाद हुसैन अहमद (मानकछार)
कृष्णानन्द ब्रह्मचारी (बिजनी)
कुलधर चलिहा (जोरहाट दक्षिण)
लीलाकान्त बेडा (कलीआबर)
महादेव दास (बरपेटा उत्तर पूर्व, सरक्षित परिगणित जन जाति)
माहम सिंह (चैरा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
नूरुल इस्लाम (लाहारीघाट)
मुहम्मद इद्रिस (रूपाही हाट)
मुहम्मद अली (पाथरकडी करीमगज)
महेन्द्र मोहन चौधरी, (बरपेटा उत्तर पूर्व)
महेन्द्र हजारिका (नगांव, रहा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
मालचन्द्र पेगू (गोलाघाट पश्चिम, सरक्षित परिगणित जन जाति)
माणिकचन्द्र दास (बरडुबी)
मेहराबअली लस्कर (शिलचर)
महेन्द्र नाथ डेका (कमलपुर)
महीकान्त दास (ढेकियाजुली दक्षिण)
मोयनल हक चौधरी (शिलचर सोनाई)
मोतीराम बेरा (मरीगाव धिग)
ताजउद्दीन अहमद (बरपेटा पश्चिम)
मुहम्मद पहाड खान (तारावाडी)
मुहम्मद उमरुद्दीन (विलासीपाडा)
नामवर अली बरभूंया (काटीगोरा)
नन्दकिशोर सिंह (सोनाई)
निह रंगफेर (मिकिर पहाडिया, पश्चिम)
नीलमणि फूकन (जोरहाट उत्तर)
अमिय कुमार दास (ढेकियाजली उत्तर)
प्रभातचन्द्र गोस्वामी (नलवारी उत्तर)
प्रतापचन्द्र शर्मा (नगांव रहा)
पुरन्दर शर्मा (मगलदय)
पूर्णानन्द चेतिया (सोनारी)
रबीन काकती (आमगुरी,
राधिका रामदास (पूबबगसर, शिलसुन्दरी धोपा)
राधाचरण चौधुरी (बेको)
रघुनन्दन धोबी (लखीपुर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
पु० आर० डेगथुआमा (लूगलेह, सरक्षित परिगणित जन जाति)
पु० लालबुआइया (आइजल पूर्व सरक्षित परिगणित जन जाति)
राय चाद नाथ (बरखोला)
राजेन्द्र नाथ बरुवा, (गोलाघाट पूर्व)
रमेशचन्द्र दास चौधुरी (रातावारी पाथरकान्दी, सरक्षित परिगणित जन जाति)
रमेशचन्द्र बरूवा (डिब्रुगढ़ पूर्व)
रामनाथ दास (जोरहाट उत्तर, सरक्षित परिगणित जाति)
रामप्रसाद चौबे (लखीमपुर)
रणेन्द्र मोहन दास (करीमगज)
रुपनाथ ब्रह्म (कोकराझार सिदली, सरक्षित परिगणित जन जाति)
सहादतअली मण्डल (दक्षिण सलमारा)
सन्तोषकुमार बरूवा (गोलोकगज)
सरजूप्रसाद सिंह (तीताबर)
सर्वेश्वर बरूवा (बिहपुरिया)
शशधर घोष (पानेरी)
सिद्धिनाथ शर्मा (रगिया)
प्रफुल्लचन्द्र गोस्वामी (नलवाडी दक्षिण)
तमीजुद्दीन प्रोधानी (धूबरी)
थानूराम गगै (नाजिरा सोनारि)
उषा बडठाकुर (सामगुरी)
रिक्त (नागा पहाडिया उत्तर)
रिक्त (नागा पहाडिया केन्द्र)
रिक्त (नागा पहाडिया दक्षिण)

बिहार

राज्यपाल रगनाथ आर० दिवाकर

मंत्री

1. मुख्य मत्री, राजनीतिक तथा नियुक्ति विभाग . श्री कृष्ण सिन्हा
2. वित्त, कृषि और श्रम . . . अनुग्रहनारायण सिंह

3. लगान, जंगल तथा गृह कर . . . . . कृष्णवल्लभ सहाय
4. शिक्षा . . . . बदरीनाथ वर्मा
5. सिंचाई और बिजली . . . . रामचरितसिंह
6. नागरिक पूर्ति तथा स्वास्थ्य . . . . . हरिनाथ मिश्र
7. व्यवसाय, यातायात तथा सूचना . . . . महेशप्रसाद सिंह
8. न्याय तथा व्यवस्थापन . . . . . शिवनन्दनप्रसाद मंडल
9. सहयोग तथा पशु चिकित्सा . . . . दीपनारायण सिंह
10. स्थानीय स्वराज्य और पिछड़ी जाति-कल्याण . . भोला पासवान
11. जेल तथा पुनर्वास . . . . . . एस० मोहम्मद उजैर मु०
12. सार्वजनिक कार्य . . . . . . मोहम्मद शफी

उप मंत्री

1. तारापद मुखर्जी
2. वीरचन्द्र पटेल
3. अब्दुल अहद मुहम्मद नूर

वित्त

(लाख रुपयों में)

बजट के आंकड़े	आय	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1950–51 (लेखा) .	28,97	26,05	+292
1951–52 (लेखा) .	34,30	32,82	+148
1952–53 (संशोधित) .	35,77	31,36	+441
1953–54 (बजट) .	33,00	33,34	—34

शिक्षा

1952–53 में पटना युनिवर्सिटी को एक शिक्षात्मक यूनिवर्सिटी बना दिया गया और पटना के सब कालेज उसके अधीन कर दिए गए। बिहार के शेष सब कालेज एक नए बिहार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिए गए।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस उद्देश्य से परिवर्तन किया गया कि राज्य के हाई स्कूलों में धंधों की शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जा सके। मैट्रिक्युलेशन परीक्षा अब विश्वविद्यालय के अधीन नहीं रही। इस परीक्षा को अब एक स्कूल परीक्षा बोर्ड के अधीन कर दिया गया है। टुर्की में एक बेसिक शिक्षा का कालेज खोला गया। पौर्वात्य विषयों की शिक्षा के सम्बन्ध में नालन्दा पाली संस्था और मिथिला संस्कृत संस्था ने विशेष उन्नति की। काशीप्रसाद जायसवाल अनुसंधान संस्था ने कुमराहार में खुदाई का काम किया और तिब्बती पाण्डुलिपियों का सम्पादन किया। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के तत्वावधान में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् ने 'साहित्य का आदिकाल' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया।

खाद्य तथा कृषि

बिहार मे 1952-53 मे अन्न की कमी थी। इसलिए शहरों में 1,846 और गावों में उचित मूल्य की 9,613 दूकानों द्वारा अन्न बाटा गया। इस सम्बन्ध मे लोगो को सहायता देने के लिए और भी कितने ही कार्य किए गए, यथा मुफ्त बीज और गेहू बाटना आदि। इन कार्यों पर सरकार ने 360 लाख रुपये व्यय किए।

2 अक्तूबर 1952 को राज्य मे सामुदायिक विकास कार्यों का प्रारम्भ किया गया। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार बिहार मे इस तरह की 190 योजनाएं चलाई जाएगी जिन पर 5,729 लाख रुपये व्यय होगे। 1952-53 मे इन योजनाओ पर 1,223 लाख रुपये व्यय किए गए।

सिंचाई की छोटी योजनाओं के अनुसार उत्तर बिहार के कुल 300 ट्यूबवैलो मे से 175 ट्यूबवैल गत वर्ष लगा दिए गए और दक्षिण विहार के 283 मे से 205। इनके अतिरिक्त विभिन्न नदियो पर 250 चल (मोबाइल) पम्प लगाए गए।

सिंचाई के मुख्य कार्यों मे गत वर्ष 12 बाढ रोकने वाले बाध पूरे कर लिए गए जिनमे 3 लाख एकड भूमि को लाभ होगा। नालियो द्वारा पानी के निष्कासन की 26 योजनाएं जारी की गईं, जिनके द्वारा 77,000 एकड भूमि का उद्धार हुआ। इसी तरह कुछ छोटी नदियो का सुधार तथा सिंचाई की नालियो आदि की व्यवस्था भी की गई। साथ ही छोटा नागपुर के कासी और फकीदीह कार्य तथा चम्पारन में 19 मील की बेल्वा साथी नहर के कार्य पूरे किए गए।

उद्योग

1953-54 मे मध्यम आकार के उद्योगो के लिए सरकार ने 10 लाख रुपया दिया। छोटे उद्योगो के पुनर्सगठन के लिए 14 श्रेणिया खोली गईं, जिनमे रूई, रेशम, ऊन आदि की बुनाई, बर्तन निर्माण, चाकू छुरी निर्माण, रगाई छपाई और चमडे के काम की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

मलेरिया और कालाजार को रोकने का विशेष प्रयत्न किया गया। राज्य के 6,49,500 व्यक्तियो की इस सम्बन्ध मे परीक्षा की गई कि उन्हे तपेदिक की बीमारी तो नही है। बी० सी जी० के 3 लाख टीके लगाए गए। 1952-53 मे बिहार सरकार ने पटना के तपेदिक केन्द्र मे 69,764 रुपयो से 44 नए बिस्तरो का प्रबन्ध किया। इसी तरह ग्रामीण तथा शहरी हल्को मे स्वास्थ्य सुधार और चेचक निरोध के गम्भीर प्रयत्न किए गए। अस्पतालो को चीरफाड के नए औजार और दवाइया दी गईं। पटना के मैडीकल कालेज के अस्पताल का विस्तार किया गया और 250 बिस्तरो का एक नया सर्जिकल वार्ड बनाया गया। रांची और भागलपुर मे दो पैथोलोजिकल अनुसधान शालाए खोली गईं।

बिहार विधान सभा

अध्यक्ष—विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा

रामेश्वर प्रसाद शास्त्री (मनेर)
जगत नारायण लाल (दानापुर)
बदरीनाथ वर्मा (पटना शहर पश्चिम-नौवतपुर)
मूंगरी लाल (पटना शहर पश्चिम नौवतपुर, सरक्षित परिगणित जाति)

सैयद महम्मद मेहदी (पटना शहर पूर्व)
शिव महादेव प्रसाद (फ़तुहा)
राम खेलावन सिंह (पुनपुन-मसौढ़ी)
श्रीमती सरस्वती चौधरी (पुनपुन मसौढ़ी सरक्षित परिगणित जाति)
धनराज शर्मा (चान्दी)
लालसिंह त्यागी (एकंगरसराय)
शिवशरणप्रसाद शर्मा (इसलामपुर सिलाव)
महावीर प्रसाद (इसलामपुर-सिलाव सरक्षित परिगणित जाति)
जगदीश नारायण सिंह (मोकामाह्)
राणा शिवलाखपतिसिंह (बाढ़)
ताजुद्दीन (स्थावा)
गिरवरधारी सिंह (बिहार उत्तर)
सैयद मुहम्मद अकिल (बिहार दक्षिण)
श्रीमती सुन्दरी देवी (बख्तियारपुर)
श्रीमती मनोरमा देवी (बिहटा)
राम लखनसिंह यादव (पालीगज)
मजूर अहमद (पकरीबरांव—वार्सलीगज)
चेतूराम (पकरीबराव—वार्सलीगज) सरक्षित परिगणित जाति)
रामकिसुन सिंह (नवदा हासुआ)
शक्तिकुमार (नवादा-हसुआ, सरक्षित परिगणित जाति)
राधाकृष्ण प्रसाद सिंह (रजौली-वारिसगज)
महावीर चौधरी (रजौली वजीरगज संरक्षित परिगणित जाति)
रामेश्वर प्रसाद यादव (अतरी)
केशो प्रसाद (गया शहर)
जगलाल महतो (शेरघाटी ईमामगज)
देधारी चमार (शेरघाटी ईमामगज, संरक्षित परिगणित जाति)
जोगेश्वर प्रसाद खलिश (बुद्धगया परय्या)
रामेश्वर माझी (बुद्धगया परय्या सरक्षित परिगणित जाति)
देदानी सिंह (अरवल)
रामचरन सिंह (कुर्था)
शिवभजन सिंह (जहानाबाद)
रामचन्द्र यादव (घोसी)
रामेश्वर यादव (मखदूमपुर)
मिथिलेश्वरप्रसाद सिंह (टेकारी)
रामनरेश सिंह (दाऊद नगर)
मुन्द्रिका सिंह (गोह)
एस० एम० लतिफुर्रहमान (रफीगंज)
प्रियव्रत नारायण सिंह (औरंगाबाद)
पदारथ सिंह (ओबरा)
अनुग्रह नारायण सिंह (नवीनगर)
राम विलास सिंह (बड़हरा)
अम्बिकासिंह (आरा मुफ़स्सिल)
रणबहादुर प्रसाद (आरा शहर)
देव नारायण सिंह (सहार)
गुप्तनाथ सिंह (चैनपुर)
राम नगीना सिंह (भभुआ मोहनिया)
दुलारचाद राम (भभुआ-मोहनिया, सरक्षित परिगणित जाति)
जगन्नाथ सिंह (सस.राम-रोहतास)
गोविन्द चमार (ससाराम रोहतास, सरक्षित-परिगणित जाति)
बसावन सिन्हा (देहरी)
रामचन्द्र राय (रामगढ)
राजाराम आर्य (इटाढी)
लक्ष्मीकान्त तिवारी (बक्सर)
हरिहर प्रसाद सिंह (डुमराव)
लल्लन सिंह (ब्रह्मपुर)
रामानन्द तिवारी (शाहपुर)
श्रीमती सुमित्रादेवी (जगदीशपुर)
हेमराज यादव (विक्रमगज)
रघुनाथ प्रसाद शाह (नोखा)
रामानन्द उपाध्याय (दिनारा)
राधामोहन राय (तड़ारी-पीरो)
देवी दयाल राम (तड़ारी-पीरो, सरक्षित परिगणित जाति)
शिव कुमार पाठक (कुचायकोट)

कमला राय (गोपालगज)
अब्दुल गफूर मिया (बरौली)
शिवबचन त्रिवेदी (बैकुण्ठपुर)
नन्दकिशोर नारायण (कटैया भोरे)
चन्द्रिका राम (कटैया-भोरे, संरक्षित परिगणित जाति)
जनार्दन सिंह (मीरगज)
मौलवी घसीरुल हक (बड़हरिया)
शंकरनाथ (सिवान)
रामबसावन राम (सिवान, संरक्षित परिगणित जाति)
गदाधर प्रसाद (भैरवा)
रामायण शुक्ल (दरौली)
रामानन्द यादव (रघुनाथपुर)
गिरीश तिवारी (माझी)
महामायाप्रसाद सिंह (महाराजगज)
लक्ष्मीनारायण सिंह (एकमा)
कृष्णकान्त सिंह (बसन्तपुर पश्चिम)
हरिकिशोर प्रसाद (बसन्तपुर पूर्व)
बैजनाथ सिंह (मसरख उत्तर)
सुखदेव नारायण सिंह महथा (मसरख दक्षिण)
यमुना प्रसाद सिंह (मरहौरा)
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र (बनियापुर)
मुरलीमनोहर प्रसाद (छपरा कस्बा)
प्रभुनाथ सिंह (छपरा मुफस्सिल-गरखा)
जगलाल चौधरी (छपरामुफस्सिल-गरखा, संरक्षित परिगणित जाति)
दरोगाप्रसाद राय (परसा)
रामविनोद सिंह (दिघवारा)
जगदीश शर्मा (सोनपुर)
केदार पाण्डे (बड़हा-रामनगर)
विश्वनाथ सिंह (शिकारपुर लौरिया)
रघूनी बैठा (शिकारपुर-लोरिया, संरक्षित परिगणित जाति)
फजुल रहमान (सिकटा)
सुदामा मिश्र (धनहा)
श्रीमती केतकी देवी (बेतिया)
श्रीमती पार्वती देवी (नौतन)
जय नारायण प्रसाद (सगौली)
हरिवंश सहाय (हरसीडीह)
गणेशप्रसाद शाह (मोतीहारी पिपरा)
जमनाराम (मोतीहारी पिपरा, संरक्षित परिगणित जाति)
राधा पाण्डे (रक्सौल)
रामसुन्दर तिवारी (अदापुर)
राम अयोध्या प्रसाद (घोड़ासाहन)
मौलवी मसूद (ढाका)
गदाधर सिन्हा (पटाही)
ब्रज बिहारी शर्मा (मधुबन)
शिवधारी पाण्डे (गोविन्दगज)
श्रीमती प्रभावती गुप्त (केसरिया)
श्रीमती रामदुलारी (मेजरगज)
डा० गिरजानन्दन सिंह (शिवहर-बेलसन्ड)
चुल्हई दुसाध (शिवहर बेलसन्ड संरक्षित परिगणित जाति)
रामसेवक शरण (सीतामढी दक्षिण)
कुलदीप नारायण यादव (सीतामढी पश्चिम)
दामोदर झा (सीतामढी)
विवेकानन्द गिरी (रूनी सैदपुर)
महन्त श्यामनारायण दास (पुपरी दक्षिण)
डा० मोहम्मद हबीबुर्रहमाहन (पुपरी उत्तर)
तिलधारी महतो (सोनबर्षा फ्रन्टियर)
रामचरित्र राय यादव (सुरसन्ड)
ब्रजनन्दन प्रसाद सिंह (साहबगज)
रामचन्द्र प्रसाद शाही (बरुराज)
जमुना प्रसाद त्रिपाठी (कान्टी)
कपिलदेव नारायण सिंह (कुरहनी)
बीरचंद पटेल (महुआ)
फुदेनीप्रसाद (महुआ, संरक्षित परिगणित जाति)
नवलकिशोर प्रसाद सिंह (पारू उत्तर)
हरिहर शरण दत्त (पारू दक्षिण)
ललितेश्वर प्रसाद साही (लालगंज)

चन्द्रमणि लाल चौधरी (लालगंज, सरक्षित परिगणित जाति)
सरयूप्रसाद (हाजीपुर)
हरवंश नारायण सिंह (राघोपुर)
जनक सिंह (मीनापुर)
मथुराप्रसाद सिंह (कटरा उत्तर)
नीतेश्वर प्रसाद सिंह (कटरा दक्षिण)
विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा (मुजफ्फरपुर कस्बा)
महेशप्रसाद सिंह (मुजफ्फरपुर सकरा)
शिवनन्दन राम (मुजफ्फरपुर—सकरा सरक्षित परिगणित जाति)
नथुनीलाल मेहता (पातेपुर)
दीपनारायण सिंह (महनार)
अब्दुल समी नाद्वी (जाले)
रामरूमप्रसाद राय (मोहीउद्दीननगर)
कपूरी ठाकुर (ताजपुर)
वशिष्ठ नारायण सिंह (वारिस नगर)
धनपति पशवन (वारिसनगर, सरक्षित परिगणित जाति)
यदुनन्दन सहाय (समस्तीपुर)
सुन्दर महतो (समस्तीपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
सहदेव महतो (दलसिहसराय पूर्व)
देवकी नन्दन झा (दलसिहसराय पश्चिम)
महावीर राउत (रोसेड़ा)
बालेश्वर राम (रोसेड़ा, सरक्षित परिगणित जाति)
सईदुल हक (दरभगा)
हृदय नारयण चौधरी (दरभगा उत्तर)
राधाकान्त चौधरी (दरभगा दक्षिण)
बाबूलाल महतो (दरभगा दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
मुहम्मद शफी (बेनीपट्टी पश्चिम)
सुबोध नारायण यादव (बेनीपट्टी पूर्व)
देवचन्द्र मिश्र (बिरौल)
श्रीमती कृष्णा देवी (बहेरा दक्षिण)
जयनारायण झा 'विनीत' (बहेरा, उत्तर)
नरेन्द्रनाथ दास (बहेडा, उत्तर पूर्व)
गजेन्द्र नारायण सिंह (सिंधिया)
जानकी नन्दन सिंह (मधेपुर)
श्रीमती जनक किशोर देवी (हरलाखी)
कुंवर महाबल (जयनगर)
शकूर अहमद (खजौली)
देव नारायण यादव (लादनिया)
हरिनाथ मिश्र (मधुबनी)
रामकृष्ण महतो (मधुबनी सरक्षित परिगणित जाति)
कपिलेश्वर शास्त्री (झझरपुर)
जोगेश्वर घोष (लौकहा)
काशीनाथ मिश्र (फुलपरास)
श्रीकृष्ण सिन्हा (खडगपुर)
बासुकीनाथ राय (तारापुर)
योगेन्द्र महतो (जमालपुर कस्बा)
निरापद मुखर्जी (मुगेर कस्बा)
राजेश्वरी प्रसाद सिंह (सूरजगढ लखीसराय)
भागवतप्रसाद (सूरजगढ लखीसराय, सरक्षित परिगणित जाति)
चन्द्रशेखर सिंह (झाझा)
दुर्गा मडल (लक्ष्मीपुर, जमुई)
गुरू चमार (लक्ष्मीपुर, जमुई, सरक्षित परिगणित जाति)
कृष्ण मोहन प्यारे सिंह (बरबीघा)
शाह मुश्ताक साहिब (शेखपुरा सिकन्दरा)
रघुनन्दन प्रसाद (शेखपुरा सिकन्दरा सरक्षित परिगणित जाति)
राम नारायण चौधरी (बरियारपुर)
मिट्ठन चौधरी (बछवारा)
रामचरित्र सिंह (तेघरा)
मुहम्मद इलियास (बेगूसराय उत्तर)
सरयूप्रसाद सिंह (बेगूसराय दक्षिण)
शिव व्रत नारायण सिंह (बखरी)
ब्रह्मदेव नारायण सिंह (बलिया)
द्वारिकाप्रसाद (खगड़िया)
जियालाल मण्डल (बख्तियारपुर—चौथम)

मिश्री मुशर (बख्तियारपुर—चौथम, सरक्षित परिगणित जाति)
घनश्यामसिंह (गोगरी)
त्रिवेणीकुमार (परबट्टा)
कामताप्रसाद गुप्त (निर्मली)
खूबलाल महतो (प्रतापगज)
लहटन चौधरी (सुपौल)
बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल (त्रिवेणीगज मधेपुर)
भोली सरदार (त्रिवेणीगज मधेपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
रमेश झा (धरहार)
उपेन्द्र नारायण सिंह (सबदर बाजार सोनवर्सा)
जोगेश्वर हाजरा (सबदर बाजार सोनवर्सा सरक्षित परिगणित जाति)
शिवनन्दन प्रसाद मण्डल (मुरलीगज)
कमलेश्वरी प्रसाद यादव (किशुनगज)
तनुकलाल यादव (आलम नगर)
कुमार रघुनन्दन प्रसाद (नौगछिया बीहपुर)
रामजन्म महतो (कहलगांव)
सत्यन्द्र नारायण अग्रवाल (भागलपुर कस्बा)
सैयद मक़बूल अहमद (भागलपुर मुफस्सिल)
रास बिहारी लाल (सुलतानगज)
पशुपति सिह प्रबल (धुरइया अमरपुर)
भोलानाथ दास (धुरइया अमरपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
राघवेन्द्र नारायण सिंह (बाका)
शीतलप्रसाद भगत (बेलहर कटोरिया)
पीरू माझी (बेलहर कटोरिया सरक्षित परिगणित जाति)
सियाराम सिंह (पीरपैती)
रामनारायण मण्डल (नरपतगंज धराहर)
डूमरलाल बैठा (नरपतगंज धराहर, संरक्षित परिगणित जाति)
लक्ष्मीनारायण "सुधांशु" (धमदाहा कोर्हा)
भोला पासवान (धमदाहा कोर्हा, संरक्षित परिगणित जाति)
मोहितलाल पण्डित (रूपौली)
अनाथकान्त बसु (ठाकुरगंज)
चौधरी महम्मद अफाक (इसलामपुर)
रावतमल अग्रवाल (किशुनगंज)
मुहम्मद एहसान (बहादुरगज)
मोहिउद्दीन मुख्तार (करनदीघी)
जीवत्स 'हिमांशु' शर्मा (कदवा)
बोकाय मण्डल (फारबिसगज)
पुण्यानन्द झा (पलासी)
हाजी जियाउर रहमान (अररिया)
मुहम्मद ताहिर (अमौर)
अबुल अहद मुहम्मद नूर (बैसी)
कमलदेव नारायण सिंह (पूर्णिया)
सुखदेव नारायण सिंह (कटिहार बरारी)
बाबूलाल माझी (कटिहार बरारी, सरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती पार्वती देवी (आजम नगर)
जैठा किस्कू (राजमहल दामिन, सरक्षित परिगणित जन जाति)
राम चरण किस्कू (पकौर दामिन सरक्षित परिगणित जन जाति)
बाबूलाल टुडू (गोड्डा दामिन, संरक्षित परिगणित जन जाति)
विनोदानन्द झा (महगामा)
बुद्धिनाथ झा "कैरव" (गोड्डा)
जगदीशनारायण मण्डल (परैयाहाट जारमण्डी)
चुनका हेमब्रोम (परैयाहाट, जरमुण्डी, संरक्षित परिगणित जन जाति)
सुपई मुरमु (रामगढ़ संरक्षित परिगणित जन जाति)
देवी सोरेन (दुमका, संरक्षित परिगणित जन जाति)
शत्रुहन बेसरा (जामतारा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
मदन बेसरा (मसलिया, संरक्षित परिगणित जन जाति)

विलियम हेमब्रोम (शिकारीपाडा, संरक्षित परिगणित जन जाति)
जीतू किस्कू (महेशपुर, संरक्षित परिगणित जन जाति)
श्रीमती ज्योतिर्मयी देवी, (पकौर)
मुहम्मद बुरहानुद्दीन खा (राजमहल)
भुवनेश्वर पाण्डे (देवघर)
जानकीप्रसाद सिंह (मधुपुर सारथ)
गोकुल मेहरा (मधुपुर सारथ, संरक्षित परिगणित जाति)
कृष्ण गोपाल दास (नारायणपुर)
सदानन्द प्रसाद (जमुआ-गांवा)
किशुन राम दास (जमुआ-गावा, सरक्षित परिगणित जाति)
अवध बिहारी दीक्षित (कोडरमा)
पुनीत राय (धनवार)
कृष्णवल्लभ सहाय (गिरिडीह-डुमरी)
लक्ष्मण माझी (गिरिडीह डुमरी, सरक्षित परिगणित जन जाति)
तपेश्वर देव (बगोदर)
बी० बेदु (पेतरबार)
अब्दुल कय्यूम अंसारी (गोमिया)
वसन्त नारायण सिंह (रामगढ-हजारीबाग)
बिगन राम (रामगढ-हजारीबाग, सरक्षित परिगणित जाति)
रामेश्वर प्रसाद महथा (बरही)
नन्दकिशोर सिह (चम्पारन)
कामाख्या नारायण सिंह (बडकागाव)
सुखलाल सिंह (चतरा)
शोमा भगत (मन्दार, सरक्षित परिगणित जन जाति)
भोलानाथ भगत (सिल्ली)
पाल दयाल (रांची)
राम रतनराम (राची, सरक्षित परिगणित जाति)
जगन्नाथ महतो वकील कुर्मो (सोनाहाटू)
नियारन मुण्डा (तमार)
हरमन लकड़ा (बेरो, संरक्षित परिगणित जन जाति)
सुकरा उरांव (गुमला, संरक्षित परिगणित जन जाति)
जुनस सुरीन (बसिया, सरक्षित परिगणित जन जाति)
लुकस मुण्डा (खुटी, संरक्षित परिगणित जन जाति)
एस० के० बागे, (कोलेबीरा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
अलफ्रेड उरांव (सिमदेगा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
देवचरण मांझी (चैनपुर सरक्षित परिगणित जन जाति)
बलिया भगत (सेसाई, सरक्षित परिगणित जन जाति)
इगनसे कुजूर (लोहारदगा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
राजकिशोर सिह (हुसैनाबाद—गढवा)
देवचन्द राम पासी (हुसैनाबाद—गढवा सरक्षित परिगणित जाति)
कुमारी राजेश्वरी सरोज दास (नगर उन्तरी)
अमिय कुमार घोष (डालटनगज)
भुवनेश्वर चौबे (लेसलीगज चतरपुर)
जीतू राम (लेसलीगज चतरपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
गिरिजानन्दन सिंह (लेटेहार—मनाटू)
भगीरथी सिह (लेटेहार—मनाटू सरक्षित परिगणित जाति)
पूर्णेन्दु नारायण सिंह (तोपचाची)
श्रीमती मनोरमा सिंह (कतरास)
राम नारायण शर्मा (टण्डी-निरसा)
टीकाराम मांझी (टुण्डी—निरसा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
पुरुषोत्तम चौहान (धनबाद)
राजा काली प्रसाद सिंह (बलियापुर)
अनन्दा प्रसाद चक्रवर्ती, (काशीपुर रघुनाथपुर)
बुद्धन मांझी (काशीपुर रघुनाथपुर, संरक्षित परिगणित जन जाति)

देवशंकरी प्रसाद सिंह (पारा चास)
शरत मोची (पारा-चास, संरक्षित परिगणित जाति)
देवेन्द्र नाथ महता (झालदा)
सिरीशचन्द्र बनर्जी (बाघमुण्डी)
समरेन्द्र नाथ ओझा (पुरुलिया—हुरा)
दीनू चर्मकार (पुरुलिया—हुरा, सरक्षित परिगणित जाति)
सत्य किंकर मेहता (मानबाजार—पटमदा)
सरदार निताई सिंह (मान बाजार पटमदा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
भीमचन्द्र महता (बडा बाजार-चादिल)
भईया अतुलचन्द्र सिंह (बडा बाजार-चादिल, सरक्षित परिगणित जन जाति)
शुभनाथ देवगम (मनोहरपुर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
सुखदेव माझी (चक्रधरपुर सरक्षित परिगणित जन जाति)
सिदुई हेमब्रोम (कोलहन, संरक्षित परिगणित जन जाति)
अंकुरा हो (जामदा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
सुरेन्द्र नाथ बिरुआ (मनजारी, सरक्षित परिगणित जन जाति)
उजेन्द्र लाल हो (खरसावा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
कवि मिहिर (सराय केला)
शिव चन्द्रिका प्रसाद (जमशेदपुर)
हरिपद सिंह (जुगसलाई—पोतका)
कैलाश प्रसाद (जुगसलाई-पोतका, सरक्षित परिगणित जाति)
मुकुन्दराम तान्ति (घाटशिला बहर गोडा)
घनीराम सान्थाल (घाटशिला बहर गोडा, संरक्षित परिगणित जन जाति)
एम, मोरिस (नामजद)

बिहार विधान परिषद्

सभापति—श्यामाप्रसाद सिन्हा

कृष्ण बहादुर (स्नातक —पटना डिवीजन)
सिद्धेश्वरी प्रसाद (स्नातक—पटना डिवीजन)
सांवलिया बिहारी लाल वर्मा (स्नातक तिरहुत डिवीजन)
लक्ष्मीनाथ झा (स्नातक—तिरहुत डिवीजन)
रावणेश्वर मिश्र (स्नातक, भागलपुर डिवीजन)
अनिल कुमार सेन (स्नातक, छोटा नागपुर, डिवीजन)
धर्मराज किशोर (अध्यापक, पटना डिवीजन)
मथुराप्रसाद दूबे (अध्यापक तिरहुत डिवीजन)
विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र (अध्यापक भागलपुर डिवीजन)
हरगौरी तिवारी (अध्यापक, भागलपुर डिवीजन)
महेन्द्र प्रसाद (अध्यापक, छोटा नागपुर डिवीजन)
शशांक शेखर घोष (अध्यापक छोटा नागपुर डिवीजन)
देवशरण सिंह (पटना डिवीजन)
महन्थ महादेवानन्द गिरि (पटना डिवीजन)
कुमार झा (पटना डिवीजन)
शिवनाथ प्रसाद (पटना डिवीजन)
विष्णु शकर (पटना डिवीजन)
मथुराप्रसाद सिंह (पटना डिवीजन)
ब्रजेन्द्र बहादुर (तिरहुत डिवीजन)
कुमार कल्याण लाल (तिरहुत डिवीजन)
वैद्यनाथ मिश्र (तिरहुत डिवीजन)
ब्रज बिहारी प्रसाद (तिरहुत डिवीजन)
राम बहादुर राय (तिरहुत डिवीजन)
श्रीनिवास नारायण सिंह (तिरहुत डिवीजन)
वीर नारायण चन्द (भागलपुर)
जागेश्वर मंडल (भागलपुर)

सागर मोहन पाठक (भागलपुर)
जमुना प्रसाद सिंह (भागलपुर)
मायानन्द ठाकुर (भागलपुर)
कुदरतुल्लाह (भागलपुर)
आर० नरसिंह राव (छोटा नागपुर डिवीजन)
रामप्रकाश लाल (छोटा नागपुर डिवीजन)
अजीतप्रसाद सिह देव (छोटा नागपुर डिवीजन)
कन्तु कुमार लाल (छोटा नागपुर डिवीजन)
सुबोध कुमार सेन (छोटा नागपुर डिवीजन)
शम्भुनाथ राय (छोटा नागपुर डिवीजन)
अबुल हयात चान्द (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
सैयद अमीन अहमद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
वसन्त चन्द्र घोष (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रामानन्द चौधरी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
गौरीशंकर डालमिया (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीमती रामप्यारी देवी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
हबीबुल हक (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
बरियार हेम्ब्रोम (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
जयदेव नारायण सिह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
जीतूलाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीमती नइमा खातून हैदर विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
नूरुल्लाह (विधाना सभा द्वारा निर्वाचित)
राधा गोविन्द प्रसाद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
शाह मुहम्मद औजैर मुनेमि (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
इन्द्रनारायण सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
कुशेश्वर सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रघुवंशप्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
राम शेखर प्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीकृष्ण सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
कामताप्रसादसिंह 'काम' (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्यामाप्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
गीता प्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
ब्रजेन्द्र नारायण यादव (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
सीताराम यादव (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
मोहनलाल महतो 'वियोगी' (नामजद)
जगन्नाथ प्रसाद मिश्र (नामजद)
त्रिदिव नाथ बनर्जी (नामजद)
लेडी अनीस इमाम (नामजद)
नारायणजी (नामजद)
ब्रजनन्दन प्रसाद (नामजद)
फतेह नारायण सिंह (नामजद)
रामेश्वर प्रसाद सिंह (नामजद)
वृजराज कृष्ण (नामजद)
हरेन्द्र बहादुर चन्द्र (नामजद)
रामचरण सिह (नामजद)
जयदेव प्रसाद (नामजद)

बम्बई

राज्यपाल . . . गिरजाशंकर बाजपेयी

1. मुख्य मंत्री तथा गृह, राजनीतिक और सेवा विभाग . . . . मुरारजी आर० देसाई
2. लगान, कृषि और जंगल . . . बी० एस० हिरे
3. शिक्षा और कानून . . . दिनकरराव एन० देसाई
4. वित्त, मद्यनिषेध तथा व्यवसाय . . जीवराज एन० मेहता
5. स्थानीय स्वराज्य और सहयोग . . एम० पी० पाटील
6. सार्वजनिक कार्य . . . एम० एम० नायक निम्बालकर
7. पुनर्वास, मछली व्यवसाय तथा पिछड़ी हुई जातियां . जी० डी० तपासे
8. श्रम तथा स्वास्थ्य . . . शान्तिलाल एच० शाह
9. नागरिक पूर्ति . . . वाई० बी० चव्हाण

उपमंत्री

1. शिक्षा . . . श्रीमती इन्दुमती चमनलाल
2. सार्वजनिक कार्य . . . बी० जे० पटेल
3. पिछड़ी हुई जातियां . . . डी० एन० वाण्ड्रेकर
4. कृषि तथा जंगल . . के० एफ० पाटिल
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य . . बी० डी० [illegible]
6. स्थानीय स्वराज्य तथा सहयोग . बी० डी० देशमुख
7. मद्यनिषेध . . टी० आर० नरवाने
8. लगान . . . एम० जी० फा[illegible]
9. नागरिक पूर्ति . . बी० के० म[illegible]

वित्त

(लाख रुपयों में)

बजट के आंकड़े	आय	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1950-51 (हिसाब)	64,39	64,37	—6
1951-52 (हिसाब)	62,77	62,58	+12
1952-53 (संशोधित)	64,34	68,24	—390
1953-54 (बजट)	68,84	67,76	+8

शिक्षा

सन् 1952–53 में बम्बई में 4 करोड़ रुपये अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किए गए, 51,05,000 रुपये स्कूलों की इमारत बनाने पर, 150 लाख रुपये बेसिक शिक्षा पर तथा 50 लाख रुपये शिक्षकों को ट्रेंड बनाने पर। कुल नए 16 कालेज बनाने की योजना में से 13 नए कालेज जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए 92,03,000 रुपये स्वीकृत हुए, जिनमें से 14,40,000 रुपये बम्बई राज्य में प्रविष्ट होने वाले नए क्षेत्रों के लिए थे। टेक्निकल तथा

धंधों की शिक्षा के लिए 1,35,00,000 रुपये रखे गए। माध्यमिक शिक्षा देने वाले कुछ स्कूलों को टेक्निकल शिक्षा देने वाले स्कूलो मे परिवर्तित कर दिया गया। नए पुस्तकालयो के लिए, 24,41,000 रुपये स्वीकृत हुए और 10 लाख रुपये व्यवहारिक शिक्षा के लिए।

खाद्यान्न तथा कृषि

कृषि सम्बन्धी नए कानूनो के अनुसार कृषित भूमि का लगान उपज का $\frac{1}{6}$ नियुक्त किया गया जबकि पहले वह सिंचाई रहित भूमि का एक तिहाई और सिंचाई वाली भूमि का एक चौथाई था। कानून द्वारा कृषि की भूमि किराए पर लेने के कुछ दूषित प्रकार के प्रचलित ढग बन्द कर दिए गए। राज्यो मे जो नए क्षेत्र मिले थे, उनकी ओर इस सम्बन्ध मे विशेष ध्यान दिया गया। इन सुधारो का उद्देश्य यह था कि किसानो का भाग बीच की अनावश्यक पार्टियो को न मिलने पावे।

1952–53 मे सरकार ने अच्छे बीज और खाद बाटने का प्रयत्न किया। सिंचाई की सुविधाए बढाई गई और गेहू, चावल, दाल, गन्ना आदि की उपज के सम्बन्ध मे उपयोगी अनुसधान किए गए। 53 लाख के व्यय से मेशवा नहर कार्य पूरा कर लिया गया। इस समय राज्य मे 6 वडे और 10 छोटे सिंचाई के कार्यों का निर्माण जारी है, जिन पर एक करोड रुपये व्यय हो चुके है। केन्द्र की सरकार से उधार लेकर राज्य की सरकार ने 587 कार्य पूरे कर लिए है और 661 कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

अच्छे पशुओ की सख्या बढाने के लिए राज्य मे कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र खोले गए है। राज्य मे 14 मुख्य केन्द्र ग्राम बनाए गए है, जिनमे से प्रत्येक मे 500 गउओ को रखा गया है। बम्बई के निकट 'आरे दुग्ध उपनिवेश' बसाया गया है जहा से सम्पूर्ण बम्बई नगर को वैज्ञानिक ढग से शुद्ध किया हुआ दूध उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकेगा। इस उपनिवेश मे आजकल 12,000 दूध देने वाले पशु है और प्रतिदिन 3,200 मन दूध प्राप्त होता है।

पचवर्षीय आयोजना के अनुसार बम्बई राज्य मे आयोजना पर 146 करोड रुपये व्यय किए जाएगे। जिनमे से 130 करोड रुपये राज्य की सरकार देगी। अभी तक विकास की विभिन्न योजनाओ पर 53 करोड रुपये व्यय किए जा चुके है। सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रम के लिए राज्य मे 13 ब्लाक बनाए गए है, जिनमे 1,233 गाव है। इनका कुल क्षेत्रफल 7,07,994 एकड है और आबादी 1,22,859।

बिजली शक्ति के लिए 7 मुख्य योजनाए जारी की जा रही है। ये है—कोल्हापुर की राधानगरी जल विद्युत् स्कीम और पचगगा का विद्युत् गृह, जोग विभाजन स्कीम, चोला का बिजली घर, दक्षिण गुजरात की बिजली स्कीम और सतारा जिले का कोयना कार्य।

व्यवसाय

1948 के फैक्टरी कानून के अनुसार राज्य मे 7,000 फैक्टरिया रजिस्टर्ड है। पिछले वर्ष कितनी ही नई कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए। जिनमे सीमेंट, कागज, दवाइया, रेडियो सेट, स्टूडियो का सामान, पैट्रोल, फलास्क, बैटरी आदि बनाने की फैक्टरिया भी थी। इन कारखानो पर 6,57,79,000 रुपया लगा हुआ है। छोटे व्यवसायो को सहायता देने के लिए राज्य ने एक व्यावसायिक साख संस्था की स्थापना की, जिसे 2 करोड पये विभिन्न व्यवसायो को उधार देने के लिए दिए गए। व्यवसायो के लिए एक सलाहकार समिति भी बनाई गई है। विकास योजना के अनुसार व्यावसायिक सगठन की समस्याओं पर विचार करने और उन्हे सुलझाने के लिए इस सस्था को 125 लाख रुपये दिए गए है। व्यवसायक शिक्षा तथा टेक्निकल शिक्षा देने वाली सस्थाओं का शीघ्रता से विकास किया जा रहा है।

राज्य में विभिन्न व्यवसायों में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन भी निश्चित कर दिया गया है। बम्बई का व्यवसाय सम्बन्धी कानून चीनी के कारखानों पर भी लागू किया गया। जनकल्याण का काम करने वाले केन्द्रों के लिए 38,78,000 रुपये रखे गए हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

1945-46 में बम्बई में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केवल 164 लाख रुपये व्यय किए जाते थे, 1952-53 में यह व्यय बढ कर 461 लाख हो गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान देने तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को बढाने का परिणाम यह हुआ है कि मृत्यु संख्या 1,000 के पीछे 25 5 से घट कर 18 31 हो गई है; बच्चों की मृत्यु प्रति हजार पीछे 160.83 से घट कर 128 66 हो गई है और जच्चाओं की मृत्यु संख्या प्रति 1,000 के पीछे 6.92 से घट कर 5 38 हो गई है।

औंध के तपेदिक अस्पताल में शरणार्थियों के लिए 50 अतिरिक्त बिस्तरों का प्रयत्न किया गया है। 30,89,000 रुपये में एक नया अस्पताल खोलने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। मलेरिया की रोकथाम के लिए 1,27,22,000 रुपये व्यय किए गए और डी० डी० टी० का कारखाना लगाने के लिए 40 लाख रुपये दिये गये। 1953 में बम्बई में 23 मलेरिया निरोधक केन्द्र थे। बम्बई राज्य की 3,50,00,000 आबादी में से 1,17,20,000 व्यक्तियों ने डी० डी० टी० से लाभ उठाया। 22,48,000 रुपये से 5 नए अस्पताल खोले गए और शोलापुर के कोढ़ी उपनिवेश के लिए डेढ़ लाख रुपये की रकम रखी गई।

बम्बई के मेडिकल प्रेक्टिशनर कानून में सुधार किया गया और उसके द्वारा अप्रशिक्षित लोगों को चिकित्सा करने से मना कर दिया गया। डैण्टल कौंसिल की रचना में भी सुधार किया गया और आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणालियों को संगठित करने का प्रयत्न किया गया। नर्सों और दाइयों के नियंत्रण के लिए भी एक कानून बनाया गया। दवाइयों के विशुद्ध निर्माण के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की गई।

बम्बई विधान सभा

अध्यक्ष : डी० के० कुन्टे

मोहम्मद ताहिर हबीब (अग्निपाडा-मदनपुरा-फारसरोड-चूना भट्टी)
भवानीशंकर बापुजी मेहता (अहमदाबाद शहर)
बृजलाल केशवलाल मेहता (अहमदाबाद शहर नं० 1)
जयकृष्ण हरिवल्लभदास पटेल (अहमदाबाद शहर नं० 2)
श्रीमती इंदुमती चिमनलाल (अहमदाबाद शहर नं० 3)
हम्मद शरीफ अलारखजी छीपा (अहमदाबाद शहर नं० 4)
शामप्रसाद रूपशंकर वसीवदा (अहमदाबाद शहर नं० 5)
मोरारजी आर० देसाई (अहमदाबाद शहर नं० 6—7)
केशवजी रणछोड़जी वघेला (अहमदाबाद शहर नं० 6-7, संरक्षित परिगणित जाति)
मदनमोहन मंगलदास (अहमदाबाद शहर नं० 8)
विट्ठल गणपत कुटे (अहमदनगर)
भास्कर तुकाराम औटी (अहमदनगर-पारनेर)

मडिवालप्पा बंडप्पा कवाडी (अक्कलकोट—दक्षिण शोलापुर)

गणपत लक्ष्मण सोनवणे (अक्कलकोट—दक्षिण शोलापुर, संरक्षित परिगणित जाति)

दत्ता आप्पाजी देशमुख (अकोला—सगमनेर)

गोपाल श्रवण भागरे (अकोला—सगमनेर, सरक्षित परिगणित जाति)

दत्तात्रय काशीनाथ कुन्टे (अलीबाग)

नामदेव यादव पाटील (अमलनेर)

अण्णासाहब गोपालराव आवाटे (अम्बगाव)

जीवराज नारायण मेहता (अमरेली—दामनगर)

शनूभाई महजीभाई पटेल (आनंद उत्तर)

नटवरसिंहजी केसरीसिंहजी सोलंकी (आनंद दक्षिण)

हरिसिंहजी भगुभाई (अंकलेश्वर—हंसोट—जगादिया—वालिया)

मोहन नरसी (अकलेश्वर—हसोट—जगादिया वालिया, संरक्षित परिगणित जनजाति)

वालमो पुरसो कदम (अंकोला—कारवार)

नरसगौडा येलगौडा पाटील (अ नी)

पदमप्पा हिरियप्पा गुजाल (अथनी-चिकोडी)

वेंकनगौड हनमन्त गौड पाटील (बदामी)

वसप्पा तम्मन्ना मुर्नाल (बागलकोट)

होलीबसाप्पा शिवलिंगप्पा मेग्गुड (बैलहोंगल)

चतुरभाई जेठाभाई चौहाण (बालासीनोर—कपाडवज)

दत्तात्रय नथोबा वाद्रेकर (वांद्रा—खार-जुहू)

मधुभाई जयसिंह पटेल (बंसदा—दक्षिण व्यारा, सरक्षित परिगणित जनजाति)

गुलाबराव दादासाहब मलिक (बारामती)

माकनजी पुरुषोत्तम पटेल (बारडोली-वालोद—पलसाना—महुवा)

खुशालभाई धनाभाई धोदिया (बारडोली—वालोद—पलसाना—महुवा, सरक्षित परिगणित जनजाति)

छोटाभाई झवेरभाई सुतारिया (बड़ौदा शहर)

मगनभाई शकरभाई पटेल (बड़ौदा—बाघोडिया)

मीठाभाई रामजीभाई चौहाण (बड़ौदा—वाघोडिया, सरक्षित परिगणित जाति)

तुलसीदास सुभर्णराव जाधव (बारसी—माधा)

नरसिंग तात्या देशमुख (बारसी उत्तर)

सदानन्द गोपाल वार्ती (बसीन)

सदाशिवराव बापुराव भोसले उर्फ कुत्रे (बेलगाम—ग्रामीण)

भुजग केशव दलवी (बेलगाम शहरी)

मोतीराम शामराव सूर्यवशी (भादगावम—चालीसगाव)

जलमखा सादेबजखा ताडवी (भादगाव—चालीसगाँव, सरक्षित परिगणित जन-जाति)

मुस्तफा गुलाम नबी फकी (भिवडी—मुरबाद—पूर्व कल्याण)

पाण्डुरग धर्माजी जाधव (भिवडी—मुरबाद—पूर्व कल्याण, सरक्षित परिगणित जाति)

नामदेव सदाशिव मोहोल (भोर—वेल्हे—दक्षिण मुलशी)

विश्वनाथ तुकाराम पाटील (भूधरगड—अजरा)

कोदरदास कालीदास शाह (भूलेश्वर मार्केट)

नीलकठ गणेश साने (भुसावल—जामनेर)

केशव राघव वानखेडे (भुसावल-जामनेर, संरक्षित परिगणित जाति)

मल्लनगौड रमणगौड पाटील (बीजापूर)

कैलाशनारायण शिवनारायण नरौला उर्फ डा० कैलाश (बोरी बन्दर—मरीन लाइन्स)

माधव कृष्ण देशपांडे (बोरिवली)

शिवाभाई रणछोडभाई पटेल (बोरसद न० 1)

ईश्वरभाई खुदाभाई चावड़ा (बोरसद नं० 2)

दिनकरराव नरभेराम देसाई (भड़ोच)
अमूल मगनलाल देसाई (बलसार--चिखली)
भूलाभाई नारनभाई पटेल (बलसार-चिखली, संरक्षित परिगणित जनजाति)
अलेभाई अब्दुल कादर (चकला--माडवी चीच बन्दर)
रामदास किलाचंद (चानसमा--हारिज-पाटण)
खेमचन्दभाई एस० चावडा (चानसमा हारिजपाटण, संरक्षित परिगणित जाति)
विठ्ठल सीताराम पाटील (चांदगड)
माधवराव लक्ष्मणराव जाधव (चांदोर--कलवान--बगलान)
डोंगर रामा मोरे (चांदोर--कलवान--बगलान, संरक्षित परिगणित जाति)
नौशीर गुरसेठजी भरुच (चौपाटी--ग्रांट रोड--तारदेव)
रतीलाल बेचरदास मेहता (चेम्बूर--घाटकोपर और अन्य गांव और सीव, उत्तर)
भैजीभाई गरबन्धभाई तडवी (छोटा उदेपुर, संरक्षित परिगणित जनजाति)
शंकर दादोबा कोठावले (चिकोडी)
श्रीमती राधाबाई मातुरी श्रेयकर (चिकोडी, संरक्षित परिगणित जाति)
वसन्तराव लखगौड पाटील (चिकोडी-रायबाग)
भागीरथ सदानन्द झा (चिंचपोकली--लोअर परेल--लव ग्रोव)
बापू चन्द्रसेन काम्बले (चिंचपोकली--लोअर परेल--लव ग्रोव, संरक्षित परिगणित जाति)
तुकाराम कृष्ण शेट्ये (चिपलूण--खेड)
सूडकोजी बाबूराव खेडेकर (चिपलूण--खेड, संरक्षित परिगणित जाति)
मानुशंकर मंघाराम याज्ञिक (चीरा बाजार--ठाकुरद्वार--फणसवाडी)
माधव गोटे पाटील (चोपडा)
कल्याणजी विठ्ठलभाई मेहता (चौरासी)
नाथालाल डायाभाई परेख (कोलाबा-फोर्ट)
अम्बालाल छोटालाल शाह (दुभोई)
त्रिम्बक रामचन्द्र नरवाने (दादर--सैतानचौकी)
शामराव रामचन्द्र पाटील (डहानू-उम्बर गांव)
भीमरा रडका रूपजी (डहानू--उम्बर गांव, सरक्षित परिगणित जाति)
रावसाहेब भाऊसाहेब थोरात (डाग्स--सुरगना पीट--दिन्डोरी)
अनन्त लहानू जाधव (डाग्स-सुरगना-पीट दिन्डोरी, सरक्षित परिगणित जनजाति)
वजुद्दीन अहमद परकत (दापोली खेड)
छोटालाल जीवाभाई पटेल (दसकोरी)
पोपटलाल मूलशकर जोशी (दीसा--धनेरा)
जीवनभाई खोडीदास (देहगाम)
शान्तिलाल स्वरूपचन्द शाह (देवदार--काकरेज, वाव-थराड)
जोइटा अजाजी सोलकी (देवदार--काकरेज, वाव-थराड, सरक्षित परिगणित जाति)
वामन नागोजी राणे (देवगड)
गुलाम रसूल मिया साहब कुरेशी (धन्दुका)
भीखाभाई जीनाभाई, अतारा (धरमपुर, सरक्षित परिगणित जनजाति)
बसवराज अयाप्पा देसाई (धारवार)
बसवन्नप्पा रामप्पा तम्बाकड (धारवार-कलघटकी)
माणेकलाल चुन्नीलाल शाह (धोलका)
नवल आनंद पाटील (धुलिया)
सोनुजी देवराम वानखेदर (धुलिया, सरक्षित परिगणित जाति)
जयसिंह मानसिंह सोलकी (दोहड, संरक्षित परिगणित जनजाति)
विठ्ठलराव नानासाहेब पाटील (पूर्व सतारा)
--र्यसिंह दौलतसिंह राऊल (पूर्व शहाडा--सिन्धखेडा--नन्दुरबार)
तुकाराम हुराजी गाविट (पूर्व शहाडा--सिन्धखेडा--नन्दुरबार, संरक्षित परिगणित जाति)

माफतलाल मोतीलाल पटेल (पूर्व सिद्धपुर)
एकनाथराव सम्पतराव पाटील (एदलाबाद)
सीताराम हीराचन्द बीर्ला (एरंडोल)
कुबेरप्पा पराप्पा गदग (गदग)
चनबसप्पा सदाशिवाप्पा हुलकोटी (गदग-मुडर्गी)
महादेव दंडाप्पा श्रेष्ठि (गर्डहिंग्लाज)
कीकूभाई गुलाबभाई नाइक (गणदेवी)
भगवान भाभाभाई बारद (धोधो—कोडीनार)
श्रीमती लीलावती धीरजलाल बैंकर (गीरगाव—खेतवाडी)
डायाभाई लल्लाभाई राजपूत (गोधरा)
अप्पन्ना रामप्पा पचगवी (गोकाक)
महादेव रामचन्द्र पवार (गुहागर)
मडीवलप्पा रुद्रप्पा पटटणसेट्टी (गुलेदगुड-कमतगई)
रामचन्द्र गोपाल कामत (हलिया येल्लापुर—सुपल)
सिद्धप्पा चनबसप्पा सिन्धूर (हनगल)
बाबा साहब भाऊ साहब खंजीरे (हाटकनागले)
दत्तात्रय शान्ताराम पोवार (हाटकनागले, सरक्षित परिगणित जाति)
मार्तण्ड धोंडीबा मगर (हवेली धोड)
गणपत सम्भाजी खराट (हवेली धोड, सरक्षित परिगणित जाति)
जी० वी० हल्लीकेरी (हवेली)
परषोत्तम जदुराव त्रिवेदी (हिम्मतनगर)
खेमजी रूपाजी गरसिया (हिम्मतनगर, सरक्षित परिगणित जनजाति)
शंकरगौड यशवन्तगौड पाटील (हिप्पर्गी बागेवाडी)
वी० वी० पाटील (हीरेकेरूर)
रामकृष्ण नरसिंह कामत (होनावर)
आनन्दप्पा सिद्धाप्पा काम्बली (हुबली)
धरमाप्पा यलाप्पा साम्रान (हुबली, संरक्षित परिगणित जाति)
मालगौड पुनागौड पाटील (हुकेरी)
शिवलिंगाप्पा रुद्राप्पा कन्ठी (हुनगुड)
दलजीतसिंह जी हिम्मतसिंह जी (इडर)
शकरराव बाजीराव पाटील (इन्दापुर)
मल्लपा करबसप्पा सुरपुर (इन्डी सिन्दगी)
लक्ष्मण जेट्टप्पा कबाडी (इन्डी सिन्दगी, संरक्षित परिगणित जाति)
सदाशिवराव दाजी पाटील (इस्लामपुर)
गुलाम रसूल हाजी हसन भगवान शेख (जलगांव—म्हसवड)
भगवान बुधाजी खंडकरे (जलगाव—म्हसव, सरक्षित परिगणित जाति)
छोटाभाई माकनभाई पटेल (जम्बूसर)
बसप्पा दानप्पा जत्ती (जमखंडी)
विजयसिंहराव रामराव दाफले (जथ)
बाबासाहेब जगदेवराव शिन्दे (जावली—महाबलेश्वर)
लालचन्द धूलाभाई नीनामा (झालोद, सरक्षित परिगणित जनजाति)
दत्तात्रय अमृतराव धोबले (जुन्नार)
पुरुषोत्तमदास रणछोडदास पटेल (कडी)
मल्हारराव राजारामराव देसाई (कागल)
भगवानदास मायाचन्द सेठ (कलोल)
मोहनभाई मानाभाई राठौड (कलोल)
खानचन्द गोपालदास (कल्याण सेन्ट्रल—कल्याण कैम्प)
कानजी गोविन्द करसन (कल्याण-पश्चिम)
विश्वनाथराव राजन्ना तुल्ला (कामाठीपुरा—नागपाडा)
केशव व्यकटेश राणे (कनकवली)
शंकरलाल हरजीवनदास शाह (कापडवंज)
यशवन्त बलवन्त चव्हाण (कराड उत्तर)
यशवन्तराव जीजाबा मोहिते (कराड दक्षिण)
चीनूभाई किशोरभाई पटेल (कर्जन सिनौर)

नामदेव महादेव जगताप (करमाला)
नारायण तुकाराम सरनाईक (करवीर)
गन्डू दशरथ पाटील (कव`-महन्काल (मीरज) तासगांव पूर्व]
बसप्पा शिदलिंगप्पा अरगावी (खानापुर)
दत्ताजीराव भाऊसाहेब देशमुख (खानापुर)
लक्ष्मण बाबाजी भिंगारदेव (खानापुर, संरक्षित परिगणित जाति)
ईशाकभाई अब्बासभाई बन्दूकवाला (खारा तलाव—कुम्बारवाडा)
तात्या आनन्दराव जाधव (खटावा)
पन्ढरीनाथ रामदास कबीरबुवा (खेड)
शंकरजी ओखाजी ठाकोर (खेरालू)
बलवन्त धोंडो बारले (कोल्हापुर शहर)
खादिरसाब अब्दुलसाब शेख (कोन्नूर)
जगन्नाथ शंकर बारहाटे (कोपर गांव)
शंकरराव गणपतराव घारगे (कोरेगाव)
जगन्नाथ सीताराम धोन्ड (कुडाल)
रामकृष्ण बीरन्ना नाईक (कुमटा होनावर)
इन्द्रवदन मनमोहनराय ओझा (कुर्ला—बान्दरा पूर्व)
माधव दताश्रय देसाई (लालबाग परेल)
विठ्टल गणेश कालम्बटे (लान्जा)
जयन्तीलाल झवेरभाई पटेल (लूनावाडा—सन्तरामपुर)
तेरसिंह मोतीसिंह भाभूनोर (लूनावाडा—सन्तरामपुर, संरक्षित परिगणित जन-जाति)
बाबूराव बाजीराव पाटील (माढा मोहोल)
मुहम्मद अब्दुल लतीफ (माहीम धारावी)
शंकरराव नारायणराव मोहिते (मालसीरास)
श्रीपाद सदाशिव महाजन (मालवण)
शिवप्पागौड बापुगौड पाटील (मानगोली—बाबलेश्वर)
शान्ताराम लक्ष्मण पेजे (मन्डनगड— दापोली)
प्रभाकर रामकृष्ण देशमुख (मानगांव—म्हसला—महाड)
दताश्रय मालोजी तलेगांवकर (मानगाव—म्हसला—महाड, सरक्षित परिगणित जाति)
माधवीलाल भाईलालभाई शाह (मातर कम्बे)
अलाभाई नाथूभाई (मातर कम्बे, सरक्षित परिगणित जाति)
सालवती सुब्रमण्यम (माटुंगा सीव—कोलीवाडा)
वीरधवल यशवन्तराव दाभाडे (मावल—उत्तर मुलशी)
एम० यू० मसकरणहास (मजगाव घोडपदेव)
मानकलाल चुन्नीलाल मोदी (मेहमदाबाद)
हरगोविन्दभाई धनाभाई पटेल (मेहसान—उत्तर पाटण)
केशवलाल भोलीदास पटेल (मेहसाना दक्षिण)
विश्राम हरी पाटील (मेवासा—तलोडा—अकरानी—पश्चिम शहाडा)
जनार्दन फोयारिया वलवी (मेवासा—तलोडा—अकरानी—पश्चिम शहाडा, सरक्षित परिगणित जनजाति)
श्रीमती श्रीमतीबाई चारुदत्त कलंटे (मीरज)
रमणलाल पीताम्बरदास सोनी (मोडासा-मेघराज)
लडकू नाऊर भोयर (मोखाडा—वाडा—शाहापुर)
अमृत राधो पवार (मोखाडा—वाडा—शाहापुर, संरक्षित परिगणित जनजाति)
प्राणेश गुरभट्ट सिद्धान्ती वकील (मड्डेबीहाल)
हीरालाल बन्दूलाल शाह (मुधोल)
भास्कर नारायण दीघे (मुरूड श्रीवर्धन)
उदयसिंह वीरसिंह वडोदिया (नाडियाद उत्तर
बाबूभाई जशभाई पटेल (नाडियाद दक्षिण)

दलपत उर्फ दामाजी बूचर (नांदौड—डेडीपाडा—सागबारा, संरक्षित परिगणित जनजाति)

पाण्डुरंग महादेव मुरकुटे (नासिक–इगतपुरी)

दत्तात्रय तुलसीराम काले (नासिक–इगतपुरी सरक्षित परिगणित जाति)

भीका त्रिम्बक पवार (नासिक–इगतपुरी, सरक्षित परिगणित जनजाति)

भूलाभाई दूलाभाई तडवी (नसवाडी, संरक्षित परिगणित जनजाति)

आदिवेप्पागौड शीदन्नागौड पाटील (नवलगुड-नारगुड)

लल्लूभाई माकनजी पटेल (नवसारी)

नारनभाई माधवभाई राठौड (नवसारी, सरक्षित परिगणित जाति)

यशवत सखाराम देसाले (नवपुर सकरी)

बकाराम मुकाराम कोकणी (नवपुर–सकरी, सरक्षित परिगणित जनजाति)

मोहम्मद साबिर अब्दुल सत्तार (उत्तर-मालेगाव)

श्रीमती राजे निर्मला देवी विजयसिंह भोसले (उत्तर शोलापुर)

मोहनलाल वृजभाई सेजलिया (ओखा-मण्डल-धारी खम्बा)

छोटूभाई वनमालीदास पटल (ओलपाड-मगरौल–माडवी–कामरेज)

प्रभुभाई धनाभाई पटेल (ओलपाड मंगरौल-माडवी-कामरेज, संरक्षित परिगणित जनजाति)

जुलालसिंह शंकरराव–पाटील (पाचोरा)

जसवन्तलाल सौभाग्यचन्द शाह (पादरा)

यूसुफ मियाजी (पालणपुर–डीसा)

गलबा नानजी चौधरी (पालनपुर-आबू-वडगाम-दांसा)

गामा फाता वासिया (पालनपुर-आबू-वडगाम डांसा, संरक्षित परिगणित जनजाति)

मारुती पद्माकर मेहेर (पालधर-जव्हार)

त्रिम्बक भाऊ मुकणे (पालधर–जव्हार, संरक्षित परिगणित जनजाति)

जयवन्त घनश्याम मोरे (पन्ढरपुर–मंगलवेढा)

मारुती महादेव काम्बले (पन्ढरपुर-मंगलवेढा, सरक्षित परिगणित जनजाति)

आतमाराम पाण्डुरग सावन्त (बावडा-पन्हाला)

नरहर परशराम ठोसर (पनवेल-कर्जत-माथेरान-खालापुर)

मनोहर कुशाबा पडीर (पनवेल कर्जत-माथेरान-खालापुर, सरक्षित परिगणित जनजाति)

हेमप्पा वीरभद्रप्पा कौजलगी (परसगड)

रेवला मुकर पटेल (पारडी)

भगवन्तराव दामोदर देशमुख (परोला)

दौलतराव श्रीपतराव देसाई (पाटण)

माधव मारुती नीरहाली (पत्थरडी)

अम्बाजी तुकाराम पाटील (पेण-उरण)

भास्कर रामभाई पटेल (पेटलाद-उत्तर)

मणीभाई प्रभुदास परीख (पेटलाद-दक्षिण)

मालोजीराव नाईक निम्बालकर उर्फ नाना साहेब (फल्टन-मान)

गणपतराव देवजी तपासे (फल्टन-मान, संरक्षित परिगणित जनजाति)

दिगम्बर विनायक पुरोहित (पोलादपुर-महाड)

विनायक कृष्ण साठे (पूना शहर सेन्ट्रल)

श्रीमती मालती माधव शिरोले (पूना शहर उत्तर-पश्चिम)

पोपटलाल रामचन्द्र शाह (पूना शहर दक्षिण पूर्व)

श्रीधर महादेव जोशी (पूना शहर दक्षिण–पश्चिम)

गोपालदास बेणीदास पटेल (प्रांतिज–बयाड-मालपुर)

पुरुषोत्तम जेठाभाई सोलकी (प्रांतिज–बयाड–मालपुर, संरक्षित परिगणित जनजाति असंगठित)

माधवराव नारायणराव मेमाने (पुरन्धर)
ज्ञानदेव सन्तराम खाण्डेकर (राधानगरी)
लक्ष्मणराव माधवराव पाटील (राहुरी)
सीताराम मुरारी सूबेदार (राजापुर)
हनुमन्त यैल्लाप्पा मूम्बरड्डी (रामदुर्ग)
कल्लनगौडा फकीरगौडा पाटील (रानेबेन्नूर)
सीताराम नाना सूर्वे (रत्नागिरि)
धनजी महारू बोन्डे (रावेर)
मारुती सीताराम सावन्त (रोहा सुधागड)
अंदानेप्पा ज्ञानप्पा दोड्डुमेटी (रोग)
शान्तिलाल त्रिकमलाल (साणद)
बसन्तराव बन्दु पाटील (सागली)
रामदास भाऊसाहेब शिरके (सगमेश्वर)
केशवराव श्रीपतराव राऊत (सगोला)
भाना भाई गुलाबभाई तडवी (सखेडा सरक्षित परिगणित जनजाति)
भाणेकलाल नाथालाल वखारिया (सन्तालपुर–राधनपुर–सामी)
प्रतापराव देवराव भोसले (सावन्तवाडी)
मणीलाल हरगोविन्ददास पाठक (सावली)
प्रतापसिंह हीराभाई पटेल (सेहरा–लीमखेडा-पूर्व हरिया)
वीरसिंह कानजीभाई निसारता (सेहरा–लीमखडा–पूर्व हरिया, सरक्षित परिगणित जनजाति)
माधव गगपतराव माने (सिवरी-काला चौकी–नायगाम–बडाला)
सीताराम नामदेव शिवतरकर (सिवरी-काला-चौकी–नायगाम–बडाला, सरक्षित परिगणित जनजाति)
रंगराव नामदेव पाटील (शाहूवाडी)
त्रिम्बक शिवराम भारडे (शिवगांव)
मलप्पा बसप्पा हुरालिकोप्पी (शेगांव)
वेकटेश तिम्मन्ना मागडी (शिरहट्टी)
राजाराम तुकाराम बागडे (शिरोल)
श्रीमति सरोजिनी कृष्णराव बाबर (शिरला-वलवा)
गजमल दलपत माली (शिरपुर)
शिवराव भवानराव थोरात (श्रीगोंडा)
बाबूराव महादेव भारसकर (श्रीगोंडा, सरक्षित परिगणित जाति)
भाऊराव गोविन्दराव चौगुले (श्रीरामपुर—नेवासा)
गोविन्द दत्तात्रेय साने (शोलापुर शहर दक्षिण)
शिवशकर मल्लप्पा धनशेट्टी (शोलापुर शहर उत्तर)
तिम्मप्पा मनिप्पा मोटनसर (सिद्धपूर सिरसी–मुन्डगोड)
नारायण सहदेव पाटील (सिन्धखेडा)
वसन्त नारायण नाम्रीक (सिन्नर–नीफाड)
अमृतराव धोन्डिबा रनखम्बे, (सिन्नर–नीफाड, सरक्षित परिगणित जनजाति)
विठ्ठल दत्तात्रय घाटे (सिरूर)
वनमाली तागनिया चौधरी (सोनगढ उत्तर व्यारा, सरक्षित परिगणित जनजाति)
भाऊसाहब सखाराम हीरे (दक्षिण मालेगाव—उत्तर नांदगाव)
गोर्धनदास रणछोडदास चोखावाला (सूरत शहर पूर्व)
मोहम्मदहुसैन अब्दुस्समद गोलन्दाज (सूरत शहर पश्चिम)
सयाजी लक्ष्मण सिलम (टैंक पाखडी-बाईक-कालाचौकी पश्चिम)
दत्ताजीराव भाऊराव सूर्यवशी (तासगांव–पश्चिम)
माधव विनायक हेडगे (थाना)
फजले अब्बास तैय्यबअली जमीदार (थासरा)
चनबसप्पा जगदेवप्पा अम्बली (तिकोटा–विलगी)
भवानी शकर पद्मनाथ दिवगी (उमरखाडी–डागरी–वाडी बन्दर)
इब्राहीम अली पटेल (वागरा–आमोद)

परशराम कृष्णाजी सावन्त (वेन्गुर्ला)
कचराभाई कानजीदास पटेल (बीजापुर उत्तर)
मानसिंह पृथ्वीराज पटेल (बीजापुर दक्षिण)
शान्तीलाल हरजीवन शाह (विर्ले पार्ले–अंधेरी वर्सोवा)
मगनभाई रणछोड़भाई पटेल (वीरमगाम)
शिवाभाई प्रभुदास पटेल (विसनगर)
दादासाहब खासेराव जगताप (वाई–खडाला)
होमी जहांगीरजी तल्यारखा (बालकेश्वर–महालक्ष्मी)
श्रीमती इन्दुबेन नानूभाई देसाई (पश्चिम बारिया)
बाबूराव बाला साहब धोरपडे (पश्चिम सातारा)
दयालजी त्रिभुवन पटेल (पश्चिम सिद्धपुर–पूर्व पाटण)
माधव नारायण बीरजे (वोरली–प्रभादेवी)
विठ्ठलराव नथू पाटील (यावल)
माधवराव त्रिम्बक (पाटील) शिन्दे (येवला नन्दगाव)
श्रीमती इरिन लिलीयन जिलेस्पी (नामजद)

बम्बई विधान परिषद्

सभापति : आर० एस० हुक्केरीकर

काशीनाथ मन्नालाल अग्रवाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
गविशिद्धपा शिद्धप्पा बेलवाडी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
सदाशिव लक्ष्मण बेनाडीकर (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
आत्माराम रावजी भट (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
दाजीसाहब रामराव चव्हान (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
पन्नालाल मानेकलाल चिनाई (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
जोसफ अल्तिनो कोर्लैको (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
दीनशाजी रतनजी दाबू (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
शान्ताराम महादेव दहानूकर (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीमती लीलावती हीरालाल देसाई (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीमती रमाबाई नारायण देशपांडे (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
पाण्डुरंग वासुदेव गाडगिल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
गुलाम हैदर वलीमुहम्मद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रामराव श्रीनिवासराव हुक्केरीकर (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
पद्मनाभ सुब्राया कामत (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
अर्जुनलाल भोगीलाल लाला (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
महालदार गौस मोहिउद्दीन (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रामराय मोहनराय मुंशी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
विट्ठल सखाराम पागे (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
मगनभाई भीखाभाई पटेल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
चिमनलाल कुबेरदास शाह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीमती ज्योत्स्नाबेन बहुसुखराम शुक्ल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
वामन गंगाधर यार्दी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
बिदेश तुकाराम कुलकर्णी (स्नातक, बम्बई शहर I.)

दाभूभाई छगनभाई शुक्ल (स्नातक, अहमदाबाद शहर)

चन्द्रकात छोटालाल मेहता (स्नातक, उत्तरी डिवीजन)

संतुसिंग धनसिंग पाटिल (स्नातक, मध्य डिवीजन)

माधव हरी गोडबोले (स्नातक, दक्षिणी डिवीजन)

उत्तमराव लक्ष्मण पाटील (स्नातक, मध्य डिवीजन)

वामन दिनकर साठे (स्नातक, पूना शहर)

मोरेश्वर वासुदेव डोंडे (अध्यापक, बम्बई शहर)

ठाकोरलाल श्रीपतराय ठाकोर (अध्यापक, अहमदाबाद शहर)

जगन्नाथ बलवन्त कुमठेकर (अध्यापक, पूना शहर)

देसाईभाई नाथाभाई पटेल (अध्यापक, उत्तरी डिवीजन)

गजानन श्रीपत खैर (अध्यापक, मध्य डिवीजन)

केशव गोपाल पण्डित (अध्यापक, दक्षिणी जन)

दयाशंकर बिहारीलाल अगरवाल (स्थानीय अधिकारी, पूना)

चुनीलाल दामोदर बर्फीवाला (स्थानीय अधिकारी,—बम्बई शहर)

वेजनजी अहदरजी दलाल (स्थानीय अधिकारी, बम्बई शहर)

रामचन्द्र अन्नाजी खेडगीकर (स्थानीय अधिकारी, बम्बई शहर)

देवजी रतनसी (स्थानीय अधिकारी, बम्बई शहर)

भोगीलाल धीरजलाल लाला, (स्थानीय अधिकारी, अहमदावाद शहर)

प्रभुदास बालुभाई पटवारी (स्थानीय अधिकारी अहमदाबाद जिला)

श्रीमती मनीबेन चन्दुभाई पटेल (स्थानीय अधिकारो, बड़ौदा-अमरोली)

मोतीलाल हरगोविन्ददास विन (स्थानीय अधिकारी, भडौच पच महाल)

शामलदास खेमचन्द पटेल (स्थानीय अधिकारी, मेहसाना—बनसकठा)

चुनीभाई मनजीभाई पटेल (स्थानीय अधिकारी, खेडा)

प्रेमशंकर केशवराम (स्थानीय अधिकारी, सूरत)

बसंतराव बलवंत देशमुख (स्थानीय अधिकारी, पूना शहर)

दत्तात्रय सेन मिरूद (स्थानीय अधिकारी पूर्व खानदेश)

गोपाल रामजी थिटे, (स्थानीय अधिकारी नासिक शहर)

गणपतराव धोंडिबा साठे (स्थानीय अधिकारी, शोलापुर)

रामचन्द्र नारायण भावे (स्थानीय अधिकारी, उत्तर-सातारा)

शकरराव चन्नप्पा एडके (स्थानीय अधिकारी, बीजापुर)

सदानन्द केशव गोल्वणकर (स्थानीय अधिकारी, कोलाबा-थाना)

हुच्चय्या फकीरय्या कट्टीमणी (स्थानीय अधिकारी, धारवार)

शकर विठ्ठल लिगराम (स्थानीय अधिकारी, कोल्हापुर—दक्षिण सातारा)

चूडामन आनन्द रावन्डले (स्थानीय अधिकारी, अहमदनगर—पश्चिम खानदेश)

देवचद छगनलाल शाह (स्थानीय अधिकारी, बेलगाम)

जगन्नाथ रामकृष्ण तावडे (स्थानीय अधिकारी, रत्नागिरि—कनारा)

जी० डी० अम्बेडकर (नामजद)

मगन भाई पी० देसाई (नामजद)

वी० एस० डोगरे (नामजद)

एफ० डी० धोडके (नामजद)

के० ए० हमीद (नामजद)

श्रीमती सुशीला जयदेव कुलकर्णी (नामजद)
बी० सी० लागू (नामजद)
वी० जी० लिमाये (नामजद)
बचूभाई पोपटभाई रावत (नामजद)
श्रीमती जेठी टी० सिपाहीमलानी (नामजद)
डी० एस० सोंधी (नामजद)
रामशंकर जयशकर उपाध्याय (नामजद)

मध्य प्रदेश

राज्यपाल . . . बी० पट्टाभि सीतारमय्या

मंत्री

1. मुख्यमंत्री तथा साधारण व्यवस्था, तालमेल, नियुक्ति, पुलिस और प्रचार विभाग . . रविशकर शुक्ल
2. व्यवसाय तथा वाणिज्य, कानून और जगल . डी० के० महता
3. शिक्षा, लगान तथा भारतीय भाषाए . पी० के० देशमुख
4. वित्त, लगान और रजिस्ट्रेशन . . ब्रिजलाल बियाणी
5. कृषि, पशु चिकित्सा, सहयोग, और ग्रामीण विकास . शकरलाल तिवारी
6. स्वास्थ्य और जेल . . . एम० एम० कन्नमवार
7. आदिवासी कल्याण सार्वजनिक कार्य, तथा बिजली . नरेशचन्द्रसिंह
8. अन्न, श्रम और पुनर्वास . . दीनदयाल गुप्त
9. लगान, सैटलमेंट, लैण्ड रिकार्ड तथा नागरिक पूर्ति . बी० ए० मंडलोई
10. योजना तथा विकास . . . आर० के० पाटिल

उपमंत्री

1. वित्त . . . . पी० एल० धगट
2. गृह . . . . वीरेन्द्र बहादुरसिंह
3. शिक्षा . . . . अब्दुल कादिर सिद्दिकी
4. कृषि . . . . गणेशराम अनन्त
5. लगान . . . वसन्तराव पी० नाइक
6. वाणिज्य और व्यवसाय . . . श्रीमती पी० बी० जकातदार

वित्त (लाख रुपयों में)

बजट के आंकडे	आय	व्यय	बचत (+) या घाटा (—)
1950-51 (हिसाब) .	1.965	1,674	+291
1951-52 (हिसाब) .	2,360	1,822	+538
1952-53 (संशोधित) .	2,390	2,120	+270
1953-54 (बजट) .	2,506	2,453	+53

गत वर्ष कोई नए कर तो नहीं लगाए गए, परन्तु अदालती शुल्कों की दर में कुछ परिवर्तन किया गया। करघे के माल और हाथ से बने माल पर बिक्री कर में कुछ रियायतें दी गई। बजट का 56·4 प्रतिशत भाग देहाती क्षेत्रो के विकास पर व्यय किया जाएगा। शेष रुपया शहरी क्षेत्रों मे व्यय होगा। परन्तु उससे भी शहरी और देहाती दोनो क्षेत्रो का लाभ होने की आशा है।

जुलाई 1953 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक करोड़ रुपये का 10 वर्षीय ऋण जारी किया है। इस पर 4 प्रतिशत सूद मिलेगा और इसका प्रारम्भिक मूल्य 100 रुपये की जगह 99 रुपये 8 आना रखा गया है। यह ऋण पूर्ण रूप से बिक गया है।

शिक्षा

1952 मे मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्निकल शिक्षा देने वाली कुछ संस्थाओं को अपने अधीन कर लिया। अगले वर्ष सामाजिक शिक्षा विभाग की ओर से 5,036 वयस्क शिक्षा-केन्द्र खोले गए, जिनमे 11,040 शिक्षको ने कार्य किया और 2,60,453 बडी उमर के व्यक्तियो को साक्षर बनाया गया। राज्य मे 700 छोटे छोटे पुस्तकालय खोलने की योजना भी बनाई गई और उसके अनुसार 100 से लेकर 150 पुस्तके रखने के बक्से विभिन्न केन्द्रों मे बांटे गए। सामाजिक शिक्षा की उन्नति के लिए भी एक कमेटी बनाई गई।

खाद्यान्न तथा कृषि

रायपुर, बस्तर, होशगाबाद और अमरावती ज़िलों में सामूहिक विकास योजना के 4 क्षेत्र खोले गए है। अन्न की उत्पत्ति पर विशेष बल देने के उद्देश्य से यह विकास केन्द्र उन क्षेत्रो मे खोले गए ह, जहां ज़मीन विशेष रूप से उपजाऊ है। बस्तर का सामूहिक विकास केन्द्र इस इरादे से खोला गया है कि उससे आदिवासियों को भी लाभ पहुंच सके।

1952 मे मध्य प्रदेश में वर्षा की कमी के कारण खेती को नुकसान पहुचा और कम अन्न उत्पन्न हुआ। इस कारण लगान में 28लाख रुपये की कमी कर दी गई और किसानों को 6,71,000 रुपये सहायता के रूप में बांटे गए। तकावी के ऋण के रूप मे विभिन्न विभागों के अन्तर्गत एक करोड रुपय किसानों को बांटे गए। इस वर्ष विभिन्न तरह की सहायता के रूप में 19 लाख रुपये और भी दिए गए। सहायता देने के उद्देश्य से 30 सडकें, 24 धात तोडने वाले केन्द्र और 14 तालाबों के निर्माण कार्य भी जारी किए गए। कमी के इन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है, इस कारण आदिवासियों की आर्थिक स्थिति की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

राज्य की सरकार ने भूदान यज्ञ आन्दोलन को सब तरह की और अधिकतम सहायता देने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से राज्य की विधान सभा ने एक कानून बना कर भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड का कार्य भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि की देखभाल करना और उसका विभाजन करना है।

पंचवर्षीय-आयोजना के अन्तर्गत 6 बड़े और 23 छोटे सिंचाई के कार्य जारी किए गए हैं। इन पर 3,81,45,000 रुपये व्यय आयेंगे और इनके द्वारा 2 लाख एकड़ भमि की सिंचाई हो सकेगी। इनमें से 2 बड़े और 2 छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है।

व्यवसाय

बल्लरपुर पेपर मिल्स तथा नेपा मिल्स ने अपने कार्यों मे अच्छी उन्नति की । गत वर्ष 118 क्वैरियो के और 129 खानो के पट्टे दिए गए । दामुआ, कालीछप्पर और राखीकोल की कोयले की खानो मे प्राप्त कोयले नमूने धनबाद की कोयला अनुसन्धान सस्था मे भेजे गए और उनके सम्बन्ध मे आवश्यक परीक्षण का कार्य जारी किया गया । राज्य के व्यवसाय विभाग की ओर से विभिन्न केन्द्रों मे बुनाई, रगसाजी और छपाई के कार्यों का प्रदर्शन किया गया । इन कामो मे मेहनत बचाने का तरीका निकालने का प्रयत्न भी किया गया और जुलाहो तथा बुनकरो को अच्छे ढंग के परदे, पलगपोश और गिलाफ आदि बनाने की विशेष शिक्षा दी गई । गृहोद्योग परीक्षण-शाला मे एक नए ढग की स्याही बनाने का प्रयत्न किया गया । स्टेशनरी बनाने की पूरी मशीन इसी परीक्षणशाला ने बनाई ।

बुनाई, सीमेंट, बिजली, मैकेनिकल और इजीनियरिंग व्यवसायो मे कार्यकर्त्ताओ के प्रोविडण्ड फण्ड की स्कीम जारी की गई । इस स्कीम से 38 हजार कार्यकर्त्ताओ को लाभ पहुचने की आशा है ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

मैडिकल कालेज की मुख्य इमारत का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने 20 मार्च 1953 को किया । इस वर्ष मैडिकल कालेज के अस्पताल मे तपेदिक के मरीजो के बिस्तरो की सख्या 50 से बढा कर 75 कर दी गई । इसी तरह देहाती हलको मे आयुर्वेदिक अस्पतालो की स्थापना करने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जिले के अस्पतालो को क्रमश: राज्य के अधीन किया जा रहा है और प्रति वर्ष 3 अस्पताल राज्य अपनी देख-रेख मे ले लेता है । 1953-54 के बजट मे अकोला, खडवा और बिलासपुर अस्पतालो को राज्य की देख रेख मे लिया गया इसी तरह रायपुर की आयुर्वेदिक फार्मेसी को राज्य ने इस उद्देश्य मे अपने हाथ मे ले लिया है कि जिला सभाओ और म्युनिसिपल कमेटियो मे आयुर्वेदिक दवाइया पहुच सके ।

प्लेग की रोक-थाम के लिए राज्य की सरकार ने एक योजना बनाई और एक प्लेग कण्ट्रोल यूनिट स्थापित किया । 1953–54 मे केन्द्र की सरकार ने 8 राष्ट्रीय मलेरिया नियत्रण यूनिट मध्यप्रदेश सरकार को दे दिए । योजना के अनुसार खडवा, जलगाव, चादा, जगदलपुर, नागपुर आदि स्थानो पर मलेरिया निरोध के प्रयत्न जारी है । विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा हैदराबाद, उडीसा और मद्रास की सरकारों के सहयोग से मध्यप्रदेश सरकार ने चादा जिले के अहीरी नामक स्थान में या-निरोधी (anti yaws) आन्दोलन जारी किया ।

मध्यप्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष : कुजीलाल दुबे

अमृतराव गणपतराव सोनार (अचलपुर)
हाजी मुहम्मद मसूद खां अकबर खां (अकलतरामस्तूरी)
कुलपतसिंह सूर्यवंशी (अकलतरा–मस्तूरी, संरक्षित परिगणित जाति)
ब्रिजलाल नन्दलाल बियाणी (अकोला)

साकी नियाजी मुहम्मद सुभान (आर्काट)
अर्जुनसिंह सिसोदिया (अमरवाड़ा)
नारायण मनीरामजी वाडिवा (अमरवाड़ा, संरक्षित परिगणित जनजाति)
रामानुज सरनसिंह देव (अम्बिकापुर)
ठा० पारसनाथ (अम्बिकापुर, संरक्षित परिगणित जनजाति)
गिरधारीलाल चतुर्भुज शर्मा (आमगाव)
वामनराव गोपालराव जोशी (अमरावती)
बाबूलाल काशी प्रसाद (अमरावती, संरक्षित परिगणित जाति)
लखनलाल गुप्ता (आरंग-खरोरा)
सुखचैन दास (आरंग-खरोरा, संरक्षित परिगणित जाति)
जगजीवन गणपतराव कदम (आर्वी)
कृष्णराव गोपालराव नाईक (बैहर)
हरेसिंह बखतसिंह (बैहर, संरक्षित परिगणित जनजाति)
कन्हैयालाल बहादुर सिंह (बालाघाट)
घियासुद्दीन सैयद नसीरुद्दीन काज़ी (बालापुर)
दगडू झागोजी पलसपगार (बालापुर, संरक्षित परिगणित जाति)
केशवलाल गोमाश्ता (बालोद)
श्रीमती दारनबाई (बालोद, संरक्षित परिगणित जनजाति)
कृष्णानन्द रामचरण (बन्डा)
बिसाहूदास महन्त (बारद्वारा)
रामराव उत्रगडे (बारघाट)
जयदेव गदाधर सतपथी (बसना)
विश्वनाथ यादवराव तामस्कर (बेमेतरा)
शिवलाल (बेमेतरा, संरक्षित परिगणित जाति)
दीपचन्द लक्ष्मीचन्द गोठी (बैतूल)
रामराव कृष्णराव पाटिल (भद्रावती)
आनन्दराव सोनाजी लोखंडे (भैंसदेही)
राम बकाराम लान्जेवार (भंडारा)
चक्रपाणि शुक्ल (भाटापारा-सीतापुर)
बाजीराव हबिारी (भाटापारा-सीतापुर, संरक्षित परिगणित जाति)
लक्ष्मीनारायण दास (भटगाव)
हीराशाह (बीजापुर स० प० जनजाति)
लक्ष्मी शकर (विजयराघोगढ़)
डा० शिव दुलारे मिश्र (बिलासपुर)
श्रीमती रानी पद्मावती देवी (बोरी देवकर)
भूतनाथ (बोरी देवकर, संरक्षित परिगणित जाति)
मुरारीराव कृष्णराव नागमोती (ब्रह्मपुरी)
नामदेव पुजाजी पवार (बुलढाना)
अब्दुलकादिर सिद्दिकी (बुरहानपुर)
रामकृष्ण राठौर (चापा)
लक्ष्मण कृष्णाजी वासेकर (चान्दा)
गजानन शर्मा (चन्द्रपुर बिर्रा)
मूलचन्द टीकाराम (चन्द्रपुर बिर्रा, संरक्षित परिगणित जाति)
पुण्डलीकराव बालकृष्ण चोरे (चान्दुर)
लाल श्याम शाह (चौकी, संरक्षित परिगणित जन जाति)
कृष्ण गणेष रेखडे (छिंदवाड़ा)
शंकर प्रतापसिंह (चिचली)
मोहकमसिंह उइके (चिचोली, संरक्षित परिगणित जनजाति)
त्र्यंबक भिकाजी खेडेकर (चिखली)
डोरा डोक्का (चित्रकोट, संरक्षित परिगणित जनजाति)
हरिश्चन्द्र लक्ष्मीचन्द मरोठी (दमोह)
बोडा दादा (दंतेवारा, संरक्षित परिगणित जनजाति)
देवराव शिवराम पाटिल (दारवा)
श्रीमती कोकिलाबाई जगन्नाथ गावडे (दर्यापुर)
किसन नारायण खंडारे (दर्यापुर, संरक्षित परिगणित जाति)

गोकरन सिंह (देवभोग)
महादेव तुकाराम ठाकरे (देवली)
शंकर विट्ठल सोनवणे (देवली, सरक्षित परिगणित जाति)
रामगोपाल शर्मा (धमतरी)
चन्द्रचूड प्रसाद सिह देव (धरम जयगढ)
बुधनाथ साय (धरम जयगढ, सरक्षित परिगणित जनजाति)
अलिहसन मम-दानी (दिग्रस)
द्वारिका प्रसाद अनन्तराम (डिंडोरी)
रूपसिंह उमरावसिंह (डिडोरी, सरक्षित परिगणित जनजाति)
विजय लाल (डोगरगढ)
धन्नालाल जैन (डोगरगाव)
घनश्याम सिह गुप्त (दुर्ग)
निरजनसिंह रिद्धसिंह (गाडरवाडा)
कीर्तिमन्तराव भुजंगराव (गढचिरोली–सिरोचा, सरक्षित परिगणित जनजाति)
नामदेवराव बालाजी पोरेडीवार (गढचिरोली-सिरोचा)
ऋतुपर्ण किशोरदास (गन्डयी)
दुर्गाचरण (घरघोडा)
ललित कुमार सिह (घरघोडा, सरक्षित परिगणित जनजाति)
रामचन्द्र वासुदेव कथडे (गोडपिपरी)
मनोहर भाई बाबरभाई (गोदिया)
पन्नालाल बिहारीलाल दुबे (गोरेगाव)
श्यामसुन्दर नारायण लक्ष्मीनारायण (गोटेगाव)
मूलचन्द बागडी (गुढियारी)
महेशदत्त मिश्र (हरदा)
प्रेमनाथ ऋषी वाल्मीक (हरदा, सरक्षित परिगणित जाति)
मिश्रीलाल शेरमल साड (हरसूद)
प्रेमशकर लक्ष्मीशकर ढगट (हट्टा)
कडोरेलाल (हट्टा, संरक्षित परिगणित जाति)
रामकिशनदास मोतीलाल मोहता (हिन्गनघाट)
मोहम्मद अब्दुल्ला खा पठान (हिंगणा)
नन्हेलाल भूरेलाल (होशगाबाद)
जगदीश नारायण अवस्थ (जबलपुर १)
मटुआ (जबलपुर १, सरक्षित परिगणित जाति)
कुजीलाल दुबे (जबलपुर २)
विद्यानाथ ठाकुर (जगदलपुर)
डूमार (जगदलपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
काशीराव रायभान पाटिल (जलगाव)
लखेशर लाल (जाजगीर–पामगढ)
गणेश राम अनत (जाजगीर पामगढ सरक्षित परिगणित जाति)
रामकृष्ण आत्माराम बेलसरे (जरूड)
विजय भूषण सिंह देव (जशपुरनगर)
जोहन (जशपुरनगर, सरक्षित परिगणित जनजाति)
नारायण राव झुगलाजी नन्दुरकर (कलम्ब)
बजरगजी लहानूजी कडू ठेकेदार (कामठी)
कौशलनाथ लक्ष्मीचन्द (कामठा)
मनोहर राव जटार (कान्हीवारा)
भानु प्रताप देव (काकेर)
रामप्रसाद धमसान (काकेर, सरक्षित परिगणित जनजाति)
विट्ठल सिह जसिह ठाकूर (कारजा)
शकरलाल तिवारी (कटगी)
मोतीराम ओडक्या (कटगी, सरक्षित परिगणित जाति)
बनवारी लाल नौबतराम (कटघोरा)
आदित्य प्रताप सिंह त्रिभुवन प्रताप सिह (कटघोरा, सरक्षित परिगणित जनजाति)
शकरराव दौलतराव गेडाम (काटोल)
गंगा प्रसाद उपाध्याय (कवर्धा)
राजमन पटलू (केसकाल, संरक्षित परिगणित जनजाति)

वीरेन्द्र बहादुरसिंह (खैरागढ)
जगमोहनदास महेश्वरी (खमरिया)
पुरुषोत्तम गोविन्द एकबोटे (खामगाव)
भगवन्तराव अन्नाभाऊ मडलोई (खंडवा)
देवकरन बालचन्द (खंडवा, सरक्षित परिगणित जाति)
कृष्णचन्द्र ताराचन्द्र शर्मा (खुरई)
प्यारेलाल खुमन (खुरई, सरक्षित परिगणित जाति)
बृजलाल वर्मा (कोसमंडी–कसडोल)
नैनदास (कोसमंडी–कसडोल, सरक्षित परिगणित जाति)
काशीराम तिवारी (कोटा)
भोपाल राव पवार (कुरूद)
तिलोचन सिंह साहू (कुथरेल)
कृष्णराव दागोजी ठाकुर (लाखान्दुर)
सीताराम जैराम भाबोरे (लाखान्दुर, संरक्षित परिगणित जाति)
दुर्गाशंकर मेहता (लखनादोन)
बसन्तराव उइके (लखनादोन, सरक्षित परिगणित जनजाति)
शान्तिलाल सबसुखलाल जैन (लालबर्रा)
तेजलाल हरिशचन्द्र टेभरे (लाजी)
अयोध्या प्रसाद शर्मा (महासमुन्द)
परमानन्द भाई पटेल (मझोली–पनागर)
भिकू फकीरा शेलकी (मलकापुर)
रूपनारायण ज्ञानकलाल चतुर्वेदी (मंडला निवास)
भूपतसिंह उइके (मडला निवास, संरक्षित परिगणित जनजाति)
ज्वाला प्रसाद (मनेन्द्रगढ)
प्रीतराम कुर्रे (मनन्द्रगढ, सरक्षित परिगणित जाति)
बाबाराव आनन्दराव देशमुख (मंगरूलपीर)
शिवराय कृष्णय्या गगशेट्टीवार (मारेगाव)
आनन्द राव मारोतीराव पवार (मेहकर)
लक्ष्मण ठकुजी गवई (मेहकर, संरक्षित परिगणित जाति)
बालकृष्ण मूलचन्द भंडारी (मेलघाट)
श्रीमती प्रभावती बाई जयवन्त जकातदार (मोहाडी)
पजाबराव बालकृष्णराव सदातपूरे (मोर्शी)
मारोतराव साम्बशिव कन्नमवार (मूल)
बिहारीलाल देवराव (मुलताई)
भाकरु केवजी पटेल (मुलताई, संरक्षित परिगणित जाति)
कालूसिंह शेरसिंह (मुडी)
रामगोपाल वशीधर तिवारी (मुंगेली)
अंजोरदास देवदास (मुगेली, सरक्षित परिगणित जाति)
शामराव देवराव धोत्रे (मुर्तिजापुर)
गोविन्द प्रसाद शर्मा (मुरवाडा)
रिक्त (नैनपुर-मोहगाव)
अकाली बमोरी (नैनपुर-मोहगांव, संरक्षित परिगणित जनजाति)
मदनगोपाल जोधराज अग्रवाल (नागपुर १)
दीन दयाल गुप्त (नागपुर २)
श्रीमती विद्यावती बाई पन्नालाल जी देवडिया (नागपुर ३)
मंचेरशा रुस्तमजी आवारी (नागपुर ४)
विनायक जगन्नाथ चगोले (नागपुर ४, संरक्षित परिगणित जाति)
राजकुमार शुक्ल (नादगाव–दुर्ग जिला)
पंजाबराव बापूराव यावलीकर (नादगाव—अमरावती जिला)
जालमसिंह इगले (नादुरा)
रामेश्वर अर्जुन (नारायणपुर, सरक्षित परिगणित जनजाति)
रामेश्वर प्रसाद शर्मा (नरगोडा)
श्रीमती सरला देवी द्वारका प्रसाद पाठक (नरसिंहपुर)
डा० खूबचन्द बघेल (पचेडा)

धरमपाल जैसवाल (पाल)
भंडारीराम (पाल, सरक्षित परिगणित जनजाति)
पद्मराज सिंह राजा रघुराज सिंह (पंडरिया)
उदयराम (पंधर)
दत्तात्रेय कृष्णराव देशमुख (पाढरकवडा)
ताराचन्द साहू (पान्डुका)
ठाकुर नेक नारायण सिंह (पाटन)
मथुरा प्रसाद बशीधर दुबे (पेंडरा)
नारायण सिंह दंगलसिंह (पिपरिया)
गणपत राव दानी (पिथौरा)
नारायण सिंह सम्पत सिंह उइके (पुराडा)
बसन्तराव फूलसिंह नाईक (पुसद)
दौलत लक्ष्मण खडसे (पुसद, संरिक्षत परिगणित जाति)
बैजनाथ मोदी (रायगढ)
ठा० प्यारेलाल सिंह (रायपुर)
श्रीमती श्यामकुमारी देवी (राजीम)
रुद्रसरन प्रतापसिंह (रामपुर, सरक्षित परिगणित जनजाति)
चिन्तामणराव गोविन्द तिडके (रामटेक)
ललैन्द्र रामचन्द्र वासनीक (रामटक, सरक्षित परिगणित जाति)
बाला प्रसाद उर्फ बालाजी (रहेली)
कुजीलाल स्वर्णकार (रीठी)
मुहम्मद शफी मुहम्मद सुबराती (सागर)
अर्जुनगणाजी समरीत (साकोली)
नाशिक खताडू तिरपुडे (साकोली, सरक्षित परिगणित जाति)
लीलाधर सिंह (सक्ती)
शिवबक्ष राम (सामरी, संरक्षित परिगणित जनजाति)
नरेन्द्र महीपति तिडके (सावनेर)
रविशकर शुक्ल (सरायपाली)
नरेशचन्द्र सिंह (सारंगढ)
वेदराम (सारगढ, सरक्षित परिगणित जाति)
निलकंठ राव (सौंसर)

झिंगरू पूसे (सौसर, सरक्षित परिगणित जाति)
शेषराव कृष्णा जी वानखेडे (सावरगाव)
काशीप्रसाद पांडे (सिहोरा)
दादू महेन्द्रनाथ सिंघ (सिवनी)
गंगाचरण बिहारीलाल (शाहपुर)
दत्तात्रेय तुकाराम ठाकरे (शंकरपुर सिन्देवाही)
पाण्डुरग अन्ताराम चूनारकर (शंकरपुर--सिन्देवाही, सरक्षित परिगणित जाति)
तुकाराम गणपत खुमकर (शेगाव)
बापूराव मारोतराव देशमुख (सिन्दी)
हरभजन सिंह (सीतापुर, सरक्षित परिगणित जनजाति)
बसन्त कुमार मिश्र (स्लीमनाबाद)
हरिप्रसाद नन्दलाल (सोहागपुर)
पीलू गगरू (सुकमा, सरक्षित परिगणित जनजाति)
ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी (सुरखी)
चन्द्रभूषण सिंह शिवराज सिंह (तखतपुर)
भाऊ राव गुलाबराव जाधव (तलेगाव)
शान्ति सरूप शर्मा (तामिया-परासिया)
फूलभानु शाह (तामिया-परासियः सरक्षित परिगणित जनजाति)
रघुबर प्रसाद मोदी (तेन्दूखेडा)
शालिग्राम रामरतन दीक्षित (तिरोरा)
नारायण सम्भूजी (तुमसर)
श्रीमती राधादेवी किसनलाल गोयनका (उगवा)
रामचन्द्र पाण्डुरग लाजेवार (उमरेड)
श्रीधर नाथोबा जवादे (वाढोना)
पुरुषोत्तम काशीराव देशमुख (वलगाव)
देवराव यशवन्तराव गोहोकर (वणी)
थानसिंह टीकाराम बिसेन (वारासिवनी)
श्रीमती शांताबाई नारूलकर (वर्धा)
महादेवराव नागोराव पावडे (वरोडा)
शंकर सदाशिव कुलकर्णी (वाशिम)
मारोती काशीराम खिराडे (वाशिम, सरक्षित परिगणित जाति)
ताराचन्द शेरमल सुराणा (यवतमाल)
मेजर पी० ब र्डि (नामजद)

मद्रास

राज्यपाल	श्रीप्रकाश
मंत्री	
1. मुख्य मंत्री और गृह, पुलिस तथा सार्वजनिक विभाग	के० कामराज नाडर
2. स्वास्थ्य, सहयोग, भवन निर्माण तथा पैन्शन-याफ्ता सेवक विभाग	ए० बी० शैट्टी
3. कृषि, पशुपालन, स्त्री कल्याण, व्यवसाय और श्रम	एम० भक्तवत्सलम
4. वित्त, अन्न, शिक्षा, अदालतें, और जेल	सी० सुब्रमण्यम
5. यातायात, हरिजन उद्धार, हिन्दू धार्मिक दान संस्थाये, रजिस्ट्रेशन तथा मद्यनिषेध	बी० परमेश्वरम्
6. सार्वजनिक कार्य	एस० राजेश्वर सेतुपति
7. लगान	एम० ए० मानिकवेलु नैकर
8. स्थानीय शासन	एस० एस० रामास्वामी पादयाची

वित्त (लाख रुपयो मे)

बजट के आंकड़े	आय	व्यय	बचत (+) या घाटा (—)
1950-51 (हिसाब)	5,816	5,945	-129
1951-52 (हिसाब)	5,943	6,444	-501
1952-53 (संशोधित)	6,336	6,875	-539
1953-54 (बजट)	6,575	6,575	—

शिक्षा

1952-53 मे मद्रास राज्य में शिक्षा पर 12,00,00,000 रुपये व्यय किये गये, जब कि 7 वर्ष पहले यह व्यय केवल 4,59,73,000 था। कितने ही प्राथमिक तथा साधारण ट्रेनिंग स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। 1953 में वहा 50 बेसिक ट्रेनिंग स्कूल थे और 715 बेसिक प्रारम्भिक स्कूल। 27 स्कूलों में ढाई से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। परिगणित जातियों तथा आदिवासियों की शिक्षा की ओर विशष ध्यान दिया गया और उन्हें इस सम्बन्ध में यथेष्ट सहायता दी गई। सरकारी कालेजो मे 15 प्रतिशत स्थान आदिवासियों के लिये सुरक्षित कर दिये गये और 25 प्रतिशत स्थान पिछड़ी हुई जातियों के लिये।

हाल ही में राज्य ने एक आदेश द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक श्रेणियो में नौन-गज़ेटेड सरकारी कार्यकर्त्ताओं के बच्चों के लिये तथा स्थानीय संस्थाओ के 300 रुपये या उस से कम मासिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के बच्चो के लिये मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया है। इन बच्चो से हाई स्कूल की शिक्षा के लिये आधी फीस ली जायगी ।

खाद्यान्न तथा कृषि

1952-53 में मद्रास मे कृषि तथा मछली व्यवसाय के विकास पर 3,28,29,000 रुपये व्यय किये गये। 1953-54 के लिये यह रकम 3,73,13,000 कर दी गई है। पचवर्षीय आयोजना के अनुसार, आशा है कि, 1955-56 तक मद्रास राज्य मे 8,60,000 टन अतिरिक्त चावल आदि तथा 7,50,000 गाठें अतिरक्त रुई पैदा होने लगेगी। सिंचाई के सरकारी कार्य-क्रम मे 300 सिंचाई के छोटे कार्य तथा बहुमुखी माध्यमिक कार्य सम्मिलित है। 1952-53 मे मद्रास मे 1,580 लाख रुपये सिचाई पर खर्च किये गये थे। 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत वहा के लिये 338 सिंचाई की स्कीमे स्वीकार की गई थी और उन पर 454 लाख रुपये व्यय आने का अनुमान था। इससे 1,63,600 एकड नई भूमि की सिंचाई होने लगेगी। आन्ध्र राज्य के निर्माण से पूर्व मद्रास सरकार ने रायलसीमा के कमी वाले इलाके मे सहायता पहुंचाने के अनेक कार्य किये। लगभग 10 करोड़ रुपया दुष्काल निवारण के लिये व्यय किया गया ।

व्यवसाय

5 मार्च 1953 को 70 लाख रुपये के व्यय से दक्षिण आर्काट जिले मे कोयला निकालने का कार्य प्रारम्भ किया गया। जाच पडताल से मालूम हुआ है कि इस क्षेत्र के लगभग 100 वर्ग मील दायरे मे 2 अर्ब लाख टन कोयला विद्यमान है।

1952-53 मे मद्रास राज्य मे 3,554 ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां थी, 1,192 तेल के कारखाने, 17 चीनी के कारखाने और 85 कपड़ा बनाने के कारखाने थे। राज्य की सरकार की ओर से 9 क्षेत्रों में गृह तथा छोटे उद्योग धधो के विकास के सम्बन्ध मे आवश्यक जांच पडताल की गई है ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 527 लाख रुपये व्यय किये गये। 18 जिलो के 3,600 गावों मे, जिनका क्षेत्रफल 10,000 वर्गमील के लगभग है 37 मलेरिया निरोधक कार्य प्रारम्भ किये गये। अन्य क्षेत्रों मे भी मलेरिया को रोकने का भरसक प्रयत्न किया गया। अस्पतालो मे रोगियों के बिस्तरों की संख्या बढाई गई और उनके कार्य का दर्जा ऊंचा किया गया ।

मद्रास विधान सभा

अध्यक्ष : शिवषण्मुखम पिल्लै

एस० वेन्कटराम अय्यर (आदिरामपट्टिनम्)
जी० नारायणस्वामी नायडू (आडुतुराइ)
तेवरचिन्नथम्बी (आलनगुलम्)
आर० कृष्णन् (आलत्थुर)
ओ० कोरान (आलत्थुरा संरक्षित परिगणित जाति)
पी० चोक्कालिंगम् (अम्बासमुद्रम)
मोहम्मद सालीहु मरैकायर (अरन्तांगी)

एस० पंचाक्षरम् (आर्काट)
एम० पलनियांडी (अरियलूर)
बी० भक्तवत्सलु नायडू (अरकोनम)
वी० के० कन्नन (आर्नी)
जयराम रेड्डियार (अरुप्पुक्कोटाइ)
एन० रत्न गाउडर (अरवकुरुची)
एम० पी० सुब्रह्मण्यम् (आत्तुर)
श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन् (अत्थूर)
के० मोइडुड (बडगारा)
एम० गंगाप्पा (बेलरी)
बी० के० नल्लस्वामी (भवानी)
वी० कृष्णास्वामी पडयाची (भुवनगिरि)
एस० एस० कोल्किबेइल (ब्रह्मावर)
के० टी० श्रीधरन (कन्ननोर)
एन० सी० रामस्वामी कन्दर (चेनगम्)
एस० चेल्लपांडियन (चेरनमहादेवी)
ए० अप्पु (चेवयूर)
वी० धरमालिंग नायकर (चेय्यार)
जी० वाघीसम पिल्लै (चिदम्बरम)
ए० एस० सहजानन्दा (चिदम्बरम्, संरक्षित परिगणित जाति)
के० विनायकम् (चिंगलपट)
एस० सी० सी० एन्थोनी पिल्लै (चूलै)
सी० सुब्रह्मण्यम् (कोयम्बत्तूर)
ओइ० मजय्या शेट्टी (कूडपुर)
एस० एस० रामस्वामी पादयाच्ची (कडलूर)
ए० रत्नम (कडलूर, संरक्षित परिगणित जाति)
पी० टी० राजन् (कंबम—मदुराई जिला)
सेनापति गाउंडर (धरमपुरम्)
पी० आर० राजगोपाल गाउंडर (धर्मपुरी)
एम० एस० मुनिस्वामी पिल्लै (डिंडिगल)
एस० अर्धनारीश्वर गाउडर (एडप्पाडी)
आर० कृष्णस्वामी नायडू (एडिरकोट्टै)
के० टी० राजू (इरोड)
अरंगनाथन (जिंजी)
पी० एस० नल्ल गाउण्डर (गोबीचेट्टिपालयम्)
के० कामराज नाडर (गुडियात्तम)
टी० मणवालन (गुडियात्तम, संरक्षित परिगणित जाति)
डा० यू० कृष्णराव (हारबर)
डुरै स्वामी गाउडर (हरूर)
ओ० ए० नंजप्पा (हरूर, सरक्षित परिगणित जाति)
एम० नारायणन नम्बियार (होस्द्रुग)
एम० मुनिरेड्डी (होसुर)
के० आर० विश्वनाथन (जयंकोडन)
ए० अय्यारु (जयकोडन, सरक्षित परिगणित जाति)
वेणुगोपाल कृष्णस्वामी (कडम्बूर)
आर० ए० नटराज मुदलियार (कलसपक्कम्)
के० पार्थसारथी (कल्लकुरिची)
एल० आनन्दन् (कल्लकुरिची, सरक्षित परिगणित जाति)
एस० देइवसिगामणी (काचीपुरम)
के० ज० पलनिस्त्राम। गाउडर (कागेयम)
एआर० ए० आरएम० चोक्कालिगम् चेट्टियार (कारैकुडि)
ए० बी० शेट्टी (कारकल)
एम० मानिक्कासुन्दरम (करूर)
टी० वी० सन्नामी (करूर, सरक्षित परिगणित जाति)
एम० एस० मोग्राल (कसारगोड)
के० आर० नल्लशिवम (कोडुमुडी)
वी० के० पलनिस्वामी गाउडर (कोइलपालयम)
एस० सी० वीरूपाक्षय्या (कोल्लेगाल)
सी० अहमद कुट्टी (कोट्टक्कल)
के० पी० कुट्टिकृष्णन् नायर (कोझीकोड)
डी० कृष्णमूर्ति गाउडर (कृष्णगिरि)
फरनाण्डेज (नामजद)
टी० आर० वरदन (कुम्बकोनम्)
वी० आर० कृष्ण अय्यर (कुत्थुपरम्बा)
राजचिदम्बरम् (लालगुडि)

आर० कुप्पुस्वामी (मदुक्करै)
ओ० वकटसुब्बा रेड्डी (मदुरातकम्)
बी० परमेश्वरन् (मदुरातकम्, संरक्षित परिगणित जाति)
पी० राममूर्ति (मदुरै—उत्तर)
टी० के० रामा (मदुरै दक्षिण)
के० एम० सीथी साहिब (मलप्पुरम्)
एम० चडयन (मलप्पुरम, सरक्षित परिगणित जाति)
एन० राजगोपाल (मनचनल्लुर)
पी० एस० कृष्णस्वामी अय्यगार (मानामदुरै)
एन्थोनी पीटर (मनप्पारै)
एल० सी० पेइस (मगलोर)
के० सी० गोपालन उन्नी (मन्नारघाट)
सी० कंडसामी (मन्नारगुडी)
ए० के० सुब्बैया (मन्नारगुडी, सरक्षित परगणित जाति)
के० माधवन नम्बियार (मत्तनुर)
के० आर० सम्बन्दम् (मयूरम)
ए० वेल् (मयूरम, सरक्षित परिगणित जाति)
एम० कंडसामी कदर (मेचेरी)
वी० गोपाल गाउंडर (मेलमलयनुर)
चिन्नकरुप्प तेवर (मेलूर)
वी० एस० शिवप्रकाशम् (मेलूर, सरक्षित परिगणित जाति)
केम्पै गाउडर (मेट्टूपालयम)
यू० मुत्युरामलिग तेवर (मुदुकुलत्थूर)
एम० मोट्टयन् (मुदुकुलत्थूर, सरक्षित परिगणित जाति)
एन० एन० सुवर्ना (मुल्की)
एस० पी० तंगवेलु (मुसरी)
मी० राजम रामस्वामी (मैलापुर)
ई० के० सकरवर्मा राजा (नादपुरम)
एन० शिवराज (नागपट्टिनम्)
एस० वडिवेलु (नागपट्टिनम्, संरक्षित परिगणित जाति)
के० वी० रामस्वामी (नामक्कल)
एम० पी० पेरिय स्वामी (नामक्कल, संरक्षित परिगणित जाति)
पी० जी० करुलिरुमन् (नम्बियुर,)
पी० जी० मानिक्कम् (नम्बियुर, सरक्षित परिगणित जाति)
एम० जी० शंकर (नागुनेरी)
एम० डी० त्यागराज पिल्लै (नन्निलम)
एम० सी० मुत्तुकुमारस्वामी (नन्निलम, सरक्षित परिगणित जाति)
पी० के० गोपालकृष्णन् (नट्टिका)
पी० वेकटेश शोलगर (निडमगलम)
बी० आर० एम० मुत्तु तेवर (निलक्कोट्टै)
ए० अय्यनार (निलक्कोट्टै, सरक्षित परिगणित जाति)
एच० बी० अरि गौडर (नीलगिरि)
के० एच० बोम्मन् (नीलगिरि, संरक्षित परिगणित जाति)
पी० रत्नस्वामी पिल्लै (ओमलूर)
के० एस० लक्ष्मीपति नायकर (ओट्टनचत्रम्)
एम० नारायण कुरुप (ओट्टपालम्)
टी० गणपति (पलवूर)
के० रामकृष्णन (पालघाट)
एम० पी० मगल गाउडर (पलनी)
बी० बैकुठ बालिगा (पने मगलूर)
एस० राधाकृष्णन (पनरुटी)
एस० स्वयप्रकाशम (पापनासम्)
जी० गोविन्दन (परमक्कुडी)
आर० रगास्वामी गाउडर (परामती)
बी० संकरनारायण मेनन (पट्टाम्बी)
वी० नाडिमुत्तु पिल्लै (पट्टुकोट्टै)
के० पी० गोपालन (पेय्यनूर)
एस० कडास्वामी गाउडर (पेन्नगरम)
एन० परमसिव उडयार (पेरम्बलूर)
एम० पलनिमुत्तु (पेरम्बलूर, सरक्षित परिगणित जाति)
पी० कुन्हीरामकिडाव (पेरम्बा)
एम० पक्किरिस्वामी पिल्लै (पेरम्बूर)

कुन्ही मोहम्मद शाफ़ी (पेरिन्तलमन्ना)
मूकैया तेवर (पेरियकुलम्)
वी० मुत्तु (पेरियकुलम, संरक्षित परिगणित जाति)
एन० महालिगम (पोल्लाच्ची)
पी० के० तिरुमूर्ति (पोल्लाच्ची संरक्षित परिगणित जाति)
एम० ए० मनिक्कवेलु नायकर (पोलुर)
एन० गोपाल मेनन् (पोन्नानी)
ई० टी० कुन्हन (पोन्नानी, संरक्षित परिगणित जाति)
के० गजपति रेड्डि (पोन्नेरी)
ओ० चेनगम पिल्ले (पोन्नेरी, संरक्षित परिगणित जाति)
टी० अनन्त पै (उडिप्पि)
वी० बालकृष्णन् (पुदुकोट्टाइ)
के० वेंकटरमन गौडा (पुत्तूर, दक्षिण कनारा जिला)
के० ईश्वरा (पुत्तूर, दक्षिण कनारा जिला, संरक्षित, परिगणित जाति)
सी० कुन्हीराम कुरुप (क्विलांडी)
षन्मुग राजेस्वर सेतुपति (रामनाथपुरम्)
के० जी० मुनिस्वामी गाउंडर (रानीपेट)
टी० एम० कालियन्नन (रासिपुरम्)
एन० रामकृष्ण अय्यर (सैदापेट)
टी० पी० एलुमलै (सैदापेट, संरक्षित परिगणित जाति)
एस० लक्ष्मण कदार (सेलम—ग्रामीण)
डा० पी० वरदराजुलु नायडू (सेलम—नागरिक)
जी० सामिय कूर्यार (सालयमंगलम्)
रामसुन्दर करुणालयपाडियन् (संकरनयनारकोइल)
ऊर्कावलन (संकरनयनारकोइल, संरक्षित परिगणित जाति)
के० टी० कोसलराम (सात्तनकुलम)
एस० रामस्वामी नायडू (सात्तूर)
एस० तिनकरस्वामी तेवर (सेडपट्टी)
एम० सुब्रह्मण्य नायकर (शोलिंगर)
सी० मुत्तैया पिल्लै (सीकाली)
आर० वी० स्वामीनाथन (सिवगंगा)
टी० षन्मुगम (श्रीपेरुम्बुदूर)
डा० जी० चित्रम्बलम् (श्रीरंगम्)
डी० के० राजू (श्रीविल्लीपुत्तूर)
ए० वैकुठम (श्रीविल्लीपुत्तूर, संरक्षित परिगणित जाति)
ए० साम्बसिवम (तलैवासल)
टी० सी० नारायणन् नम्बियार (तालिपरम्बा)
एस० रामलिगम (तजोर)
एम० मारिमुत्तु (तजोर, संरक्षित परगणित जाति
सी० एच० कनारन (तेल्लिचेरी)
ए० के० सुब्रमण्य पिल्लै (तेनकासी)
आर० एम० पलनियप्प (तिरुमयम्)
वी० चिन्नय्या (तिरुमयम् संरक्षित परिगणित जाति)
के० वेंकटस्वामी नायडू (थाउजेंड लाइट्स)
जे० शिवषणमुखम पिल्लै (थाउजेंड लाइट्स संरक्षित परिगणित जाति)
पी० रगसामी रेड्डियार (तुरैयुर)
एम० वेणुगोपाल गाउंडर (तिडिवनम्)
एम० जगन्नाथन (तिंडिवनम्, सरक्षित परिगणित जाति)
टी० एस० अर्धनारी (तिरुचेन्गोड)
एस० आरूमुगनं पिल्लै (तिरुचेन्गोड, संरक्षित परिगणित जाति)
एस० टी० आदित्थन (तिरुचेंदुर)
वी० अरुमुगम (तिरुचेंदुर, संरक्षित परिगणित-जाति)
एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली—उत्तर)
ए० रामस्वामी तेवर (तिरुचिरापल्ली—दक्षिण)
टी० डी० मुत्तुकुमारसामी नायडू (तिरुकोयिलूर)
ए० मुत्तुसामी (तिरुकोयिलूर, सरक्षित परिगणित जाति)
के० राजाराम (तिरुमंगलम्)
एस० एन० सोमयाजुलु (तिरुनेलवेली)

आर० एस० आरूमुगम (तिरुनेलवेली, संरक्षित परिगणित जाति)
एम० ए० मुत्तैया चेट्टियार (तिरुपत्तुर, रामनाथपुरम् ज़िला)
ई० एल० राधव मुदलियार (तिरुपत्तुरउत्तर, आरकाट ज़िला)
एम० आर० रामचन्द्रन (तिरुप्पोरुर)
रगस्वामी नायडू (तिरुप्पूर)
एस० आर०आरुमुघम (तिरुप्पूर, सरक्षित परिगणित जाति)
के० उप्पी साहेब (तिरुर)
के० रामस्वामी दास (कोकिल पट्टी)
पी० चेन्लदुरै (तिरुवाडानै)
वी० गोविन्दस्वामी नायडू (तिरुवल्लूर)
एम० धर्मलिंगम (तिरुवल्लूर, संरक्षित परिगणित जाति)
ए० रामचन्द्र रेड्डियार (तिरुवन्नामलै)
आर० तंगवेलू (तिरुवन्नामलै, संरक्षित परिगणित जाति)
वी० सी० पलनिस्वामी गाउंडर (तोंडमुत्तूर)
ए० एम० संबन्दम (त्रिपलिकेन)
डा० के० बी० मेनन (त्रितला)
जे० एल० पी० रोच विक्टोरिया (ट्यूटीकोरिन)
माउनगुरूस्वामी नायडू (उडुमलपेट)
एम० कन्डसामी पडयाची (उलुंदूरपेट)
पी० एम० मुनुस्वामी गडण्डर (उद्धनपल्ली)
ए० एस० सुब्बराज (उत्तमपालयम्)
पलनिस्वामी (उत्तुकुली)
वी० के० रामस्वामी मुदलियार (उत्तिरमेरूर)
चिन्नस्वामी नायडू (वडमदुरै)
पी० कन्दसामी गाउंडर (वेलप्पाडी)
ए० के० हनुमन्तराय गाउडर (वानियंबाडी)
वी० मदनगोपाल (वेदासदूर)
ए० के० मासिलामनि चेट्टियार (वेल्लूर)
एच० एम० जगन्नाथम (वेल्लूर, संरक्षित परिगणित जाति)
ए० गोविन्दस्वामी नायगर (विक्रवांडी)
पी० सेलवराज (विलतिकुलम्)
वी० आर० नागराजन् (विल्लुपुरम्)
के० षन्मुगम (विरुधुनगर)
एस० स्वामी कन्नु (वृद्धाचलम)
एम० कट्टिमुत्तु (वृद्धाचलम, सरक्षित परिगणित जाति)
एस० सोमसुन्दर गाउडर (वंडिवाश)
डी० दशरथन (वडिवाश, संरक्षित परिगणित जाति)
पी० जीवानन्दम् (वाषरमेनपेट)
एम० के० पद्मप्रभा गाउडर (वैनाड)
सी० वेल्लुक्कन (वैनाड, संरक्षित परिगणित जाति)

मद्रास विधान परिषद्

सभापति : पी० वी० चेरियन

एम० के० एम० अब्दुल सलाम (दक्षिण, आर्काट—तजौर—तिरुचिरापल्ली)
ए० एम० अल्लापिचैइ (विधान सभा)
एन० अन्नामलै पिल्लै (विधान सभा)
के० बालसुब्रह्मण्य अय्यर (मद्रास स्नातक)
वी० भाष्यम अय्यंगार (नामजद)
के० भाष्यम (मद्रास स्नातक)
एम० भक्तवत्सलम (विधान सभा)
वी० चक्कराई चेट्टी विधान सभा)
पी० वी० चेरियन (मद्रास स्नातक)
मेरी सी. क्लबवाला जाधव (नामजद)

टी० एम० देवशिखामनी आचरियार (नामज़द)
टी० वी० देवराज मुदलियार
एम० इथिराजुलु (विधान सभा)
ए० गजपति नायगर (विधान सभा)
एलेक्ज़ांडर ज्ञानमुत्तु (दक्षिण मद्रास अध्यापक)
के० गोपालन (पश्चिमी तट)
एम० पी० गोविंदमेनन् (राज्य विधान सभा)
वी० गुरुनन्दन राव (विधान सभा)
वी० के० जॉन (विधान सभा)
जोती वेंकटाचलम (विधान सभा)
जी० कृष्णमूर्ति (मद्रास अध्यापक)
टी० जी० कृष्णमूर्ति (विधान सभा)
ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियर (मद्रास स्नातक)
मोहम्मद उस्मान (नामजद)
एस० मंजुभाषणी (विधान सभा)
सी० मरुतावनम् पिल्लइ (दक्षिण अर्काट—तंजौर—तिरुचिराप्पल्ली)
मोहम्मद रजा ख़ान (विधान सभा)
टी० एम० नारायणस्वामी पिल्लै (विधान सभा)
एन० नल्ला सेनापति सरकराइ मन्राडियार (विधान सभा)
एस० नरसपया (विधान सभा)
के० एन० पलनिस्वामी गाउंडर (सेलम—कोयम्बटूर—नीलगिरी)
ई० एच० परमेश्वरन् (मद्रास अध्यापक)
सी० पेरूमाल स्वामी रेड्डी (मद्रास—चिंगलपुट—उत्तर आर्काट)
टी० पुरुषोत्तम (मद्रास—चिंगलपुट—उत्तर आर्काट)
सी० राजगोपालाचारी (नामजद)
वी० वी० रामस्वामी (विधान सभा)
ओ० पी० रामास्वामी रेड्डियार (नामजद)
वी० आर० रंगनादन (मद्रास अध्यापक)
वी० रंगास्वामी (सेलम—कोयम्बटूर—नीलगिरी)
टी० एस० संकरनारायणा पिल्लइ (मदुराइ—रामनाथपुरम्—तिरूनेलवेली)
एस० पी० सिवसुब्रह्मण्य नाडार (मदुराइ—रामनाथपुरम्—तिरूनेलवेली)
ए० सोमसुन्दरा रेड्डियार (दक्षिण आर्काट—तजौर—तिरूचिराप्पल्ली)
ए० श्रीनिवासन (मद्रास स्नातक)
एस० श्रीनिवास राव (विधान सभा)
ए० सुब्रमण्यम (विधान सभा)
बी० वी० सुब्रह्मण्यम (विधान सभा)
आर० एस० सुब्बलक्ष्मी (नामजद)
पी० बी० के० त्यागराज रेड्डियार (सेलम—कोयम्बटूर—नीलगिरी)
पी० पी० उम्मर कोया (पश्चिमी तट)
जी० वेंकटाचलम (नामजद)
ए० चिदंबरा मुदालियार

उड़ीसा

राज्यपाल — पी० कूमरस्वामी राजा

मंत्री

1. मुख्य मंत्री तथा गृह-कार्य, नदी घाटी विकास योजना, पुनर्वास और सार्वजनिक सम्बन्ध।	नवकृष्ण चौधरी
2. कानून, विकास और स्वास्थ्य	दीनबन्धु साहू
3. व्यवसाय और यातायात	किशोरदेव भंज

4. आदिवासी और ग्राम सुधार, श्रम और व्यापार — सोनाराम सोरेन
5. वित्त और शिक्षा — राधानाथ रथ
6. लगान, पूर्ति और आन्तरिक कर — सदाशिव त्रिपाठी

उपमंत्री

1. स्वास्थ्य — श्रीमती वसतमजरी देवी
2. कार्य — भैरवचन्द्र महन्ती
3. जेल, राजनीतिक तथा व्यापार — नीलमणि रौबाई
4. सार्वजनिक सम्बन्ध — अनूपसिंह देव
5. कृषि तथा स्थानीय स्वराज्य — शान्तनु कुमार दास
6. यातायात — तीर्थवासी प्रधान
7. पूर्ति — कृपानिधि नायक

वित्त (लाख रुपयो मे)

बजट आकड़े	आय	व्यय	बचत (+) या कमी (—)
1950-51 (लेखा)	1,031	1,201	- 170
1951-52 (लेखा)	1,196	1,086	+ 110
1952-53 (सशोधित)	1,360	1,240	+ 120
1953-54 (बजट)	1 357	1,446	- 89

शिक्षा

1952-53 मे उडीसा मे 884 नये प्रारम्भिक स्कूल खोले गये और 110 को उच्च प्रारम्भिक दर्जे का कर दिया गया। राज्य के 4,000 चुने हुए स्कूलों मे तथा 16 प्रारम्भिक ट्रेनिग स्कूलों मे नई शिक्षा पद्धति जारी की गई। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्सगठन करने के लिये राज्य की व्यवस्थापिका सभा मे बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा बिल पास हुआ। इसी वर्ष 25 नये मिडिल अंग्रेजी स्कूल तथा 15 नये हाई स्कूल जारी किये गये। इस तरह राज्य भर मे इन स्कूलों की कुल सख्या 550 और 198 हो गई। राज्य के कालेजो मे शिक्षा का दर्जा ऊचा करने का भरसक प्रयत्न किया गया और उनकी सहायता मे वृद्धि की गई। प्रौढ शिक्षा के 162 नये केन्द्र खोले गये और राज्य के 3 क्षेत्रों मे 15,666 प्रौढो को साक्षर बना दिया गया। सामाजिक शिक्षा पर 140 लाख रुपये खर्च किये गये।

खाद्यान्न तथा कृषि

गत वर्ष राज्य मे 3,000 एकड नई भूमि पर कृषि प्रारम्भ हुई। गहरी खेती करने के उद्देश्य से अच्छे बीजों, अच्छे खादों और कृषि के नये उपकरणों का वितरण किया गया। ग्रामवासियों को कृषि की बीमारियों से बचने के उपाय बताये गये और इस सम्बन्ध मे उचित कार्यवाही की गई।

1952-53 में उड़ीसा मे सिंचाई के बड़े साधनों पर 25 लाख रुपये व्यय हुए और छोटे साधनों पर 23,589 रुपये ।

पहली नवम्बर 1952 से 31 अक्तूबर 1953 तक राज्य में 2 लाख टन चावल प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था । मार्च 1953 के अन्त तक इसमे से 1,91,412 टन चावल प्राप्त हो चुका था, जब कि गत वर्ष इसी अवधि में चावल की उत्पत्ति केवल 96,335 टन हुई थी ।

व्यवसाय

राज्य मे इन कारखानो को स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है : सूतकताई का एक कराखाना, 10,000 टन अल्युमिनियम पैदा करने वाला एक कारखाना, एक बुनाई कारखाना और एक 30,000 लोहे की ट्यूबे बनाने वाला कारखाना । लोहे की चादरे बनाने वाला कारखाना जारी हो चुका है और एक कागज बनाने वाली मिल और एक जूट मिल लगाई जा रही है । इनके अतिरिक्त रूई साफ करने का कारखाना तथा व्यावसायिक उपयोग के तेल बनाने का कारखाना खोले जाने की दो स्कीमें बनी हैं । छोटे दर्जे के तथा मध्यम व्यवसायों को काफ़ी मात्रा मे आर्थिक सहायता दी गई । कटक का रिकार्डिंग प्लांट, सम्बलपुर और बहरामपुर के पावर लूम कारखाने और बिस्कुट और नमक के कारखानो की ओर राज्य की सरकार ने विशेष ध्यान दिया ।

राज्य में लकड़ी के खिलौने बनाने तथा मिट्टी के मजबूत खिलौने बनाने और बालासोर जिले मे पीतल की घंटिया और बरतन बनाने के कार्यों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है । ये सब काम छोटे उद्योगों के अंग हैं । मार्च 1953 तक उड़ीसा मे 1,03, 779 गज खादी बनाई गई और हाथ के करघों द्वारा 6 लाख गज कपडा बुना गया ।

1952-53 में 67 नई फैक्टरियां रजिस्टर्ड हुईं और उनकी लाइसेस फ़ी से 26,000 से अधिक रुपये प्राप्त हुए । व्यवसाय के सम्बन्ध में आवश्यक गणनायें एकत्र की गईं ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952-53 मे उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य पर 54 लाख रुपये खर्च किये । रामचन्द्र भज मैडिकल कालेज तथा कटक के अस्पताल मे बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई और नये सामान और अतिरिक्त स्टाफ पर 2 लाख रुपये खर्च किये गये । उदितनारायणपुर के तपेदिक अस्पताल मे 10 बिस्तर बढाये गये । 40,000 रुपये कटक में तपेदिक का क्लिनिक बनाने के लिये स्वीकार किये गये । राज्य की ओर से अंधों को सहायता देने के लिये लगभग 6,000 रुपये विभिन्न सस्थाओं को बांटे गये । कलहंदी और पुरी जिलों में पागल कुत्तों के काटे का इलाज करने के लिये दो केन्द्र खोले गये ।

कटक के जच्चा अस्पताल के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार ने 30,000 रुपये दिये । जिन क्षत्रों में बीमारियां फैलती हैं, वहां डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया । संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था की ओर से 12½ टन, 50 प्रतिशत डी०डी०टी० वाला पाउडर तथा एक लाख पौंड घोल प्राप्त हुआ । तपेदिक की रोकथाम करने के लिये गत वर्ष 3 दलों ने दौरा किया । उन्होंने 1,52,026 व्यक्तियों की परीक्षा की और 29,735 को बी० सी० जी० के टीके लगाये । ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा पानी पहुंचाने के लिये 11 लाख रुपये खर्च किये गये ।

उड़ीसा विधान सभा

अध्यक्ष : नन्दकिशोर दास

पधान मकरध्वज (अम्भाभोना मुरा)
जनार्दन भंज देव (आनन्दपुर)
भाइगा मेठी (आनन्दपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
हृषिकेश त्रिपाठी (आगुल हिन्दोल)
अखिना नायक (आगुल, हिन्दोल, संरक्षित परिगणिन जाति)
हरिहरदास (अस्क)
मोहन नायक (अस्क, संरक्षित परिगणित जाति)
राधानाथ रथ (आठगढ)
किशोर चन्द्र (अठमल्लिक)
विपिन विहारी दास (अट्टावीरा)
शैलेन्द्र नारायण भंज देव (औल)
सोरेन मुनारम (बहालदा, संरक्षित परिगणित जनजाति)
सुरेन्द्र नाथ दास (बालासोर)
यादव पद्रा (बालिगुडा, संरक्षित परिगणित जनजाति)
प्राण कृष्ण परीजा (बलीकुडा)
इन्दुभूषण महन्ति (बम्रा)
जयदेव ठाकुर (बम्रा, सरक्षित परिगणित जनजाति)
यादव माझी (बंग्रीपोशी, संरक्षित परिगणित जनजाति)
गोकुलानन्द पहराज (बांकी)
गोदावरीश मिश्र (बानपुर)
गोकुलानन्द मोहान्ति (बांठ)
नवकृष्ण चौधरी (बरछना)
तीर्थवासी प्रधान (बारहगढ़)
गिरीश चन्द्र राय (बारीपदा)
सुरेन्द्र सिंह (बारीपदा, संरक्षित परिगणित जाति)
सेनापति त्रिलोचन (बेस्ता)
गण्डाधर पाइकेरा (बेगुनिया)
नायिक वृन्दावन (बेरहामपुर)
नायक मोहन (बेरहामपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
मुहम्मद हनीफ (भद्रक)
योगीश चन्द्र सिंह देव (भवानी पटना)
जनार्दन माझी (भवानी पटना, सरक्षित परिगणित जनजाति)
शशि कांत भज (भोगराई)
सत्यप्रिय महन्ति (भुवनेश्वर)
महनु मलिक (भुवनेश्वर, सरक्षित परिगणित जाति)
बैकुण्ठ नेपक (बिनिका)
पद्मनाभ राय (बिन्जारपुर)
नव किशोर मल्लिक (बिन्जारपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
अच्युतानन्द महाकुर (वीरमहाराजपुर)
मदनमोहन अमात (बिसरा, सरक्षित परिगणित जनजाति)
श्याम घन उलाका (बिसरेमक्टक, संरक्षित परिगणित जनजाति)
नन्द किशोर मिश्र (बोलगीर)
अछूता महानन्द (बोलगीर, संरक्षित परिगणित जाति)
नीलमणि सिंह दण्डपत (वोनाय, संरक्षित परिगणित जनजाति)
हिमांशु शेखर पाधि (बौद्ध)
विश्वनाथ परीदा (ब्रह्मगिरि)
गुरु चरण नायक (चम्पुआ, संरक्षित परिगणित जनजाति)
चक्रधर वेहेरा (चांदबाली)
वृन्दावन दास (चांदबाली, संरक्षित परिगणित जाति)
वी. सीतारमैया (छत्रपुर)
भैरव चरण महन्ति (कटक)

लक्ष्मण मलिक (कटक, ग्रामीण, संरक्षित परिगणित जाति)
बीरेन मिश्र (कटक कस्बा)
किशोर चन्द्र भंज देव (दशपला)
नीलमणि राउत्र (धामनगर)
परमानन्द मोहान्ति (धरमशाला)
वैष्णव चरण पटनायक (धेनकनल)
भावन देहरी (ढेनकनाल, सरक्षित परिगणित जन जाति)
गौरीश्याम नायक (एरसमा)
गमग भगीरथी (गुनुपुर), संरक्षित परिगणित जन जाति)
नीलमणि प्रधान (जगतसिंहपुर)
झजरू झोडिया (जयपत्ना काशीपुर संरक्षित परिगणित जन जाति)
गदाधर दास (जाजपुर)
शान्तनु कुमार दास (जाजपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
करुणाकर पाणीग्रही (जलेश्वर)
हरिहर मिश्र (जेपुर)
लोइछन नायको (जेपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
विजय कुमार पानि (झरसुगुडा—रामपेला)
मनोहर नायक (झरसुगुडा—रामपेला, संरक्षित परिगणित जन जाति)
विजयानन्द पटनायक (जे. प्रसाद)
प्रताप किशोर देव (जूनागढ)
दयानिधि नायक (जूनागढ, सरक्षित परिगणित जाति)
हर चन्द्र हंसदा (काणतीपाडा, संरक्षित परिगणित जन जाति)
मुदिली गेंगा (कोरापुत, संरक्षित परिगणित जन जाति)
उपेन्द्र मोहान्ति (काकटपुर—निमपारा)
गोविन्द चन्द्र सेठी (काकटपुर-निमपारा, संरक्षित परिगणित जाति)
दीनबन्धु साहू (केन्द्रपारा)
लक्ष्मीनारायण भंजदेव (क्योझार)
गोविन्द मुण्डा (क्योंझार, सरक्षित परिगणित जनजाति)
राजकृष्ण बसु (केसनगर)
राम चन्द्र मर्दराज देव (खालीकोट)
हरिहर सिह गर्दराज भ्रामरवर देव (खण्डपारा)
शारेन शाकीह (खुण्टा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
माधव चन्द्र राउत्र (खुरदा)
बनमाली महाराणा, (कुदाला)
दास प्रदीप्त किशोर (महंगा)
लक्ष्मणगौदो (मल्कनगिरि)
प्रसन्न कुमार दास (मुरुदा)
भोगोबान खेमेन्दु नायक (नन्दपुर)
वृन्दावन साहु (नरसिहपुर)
अनुप सिंह देव (नवपारा)
चेतन माझी (नवपारा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
कृष्ण चन्द्र सिंह मान्धाता (नयागढ)
नीलाम्बर दास (नीलगिरि)
चैतन्य सेठी (नीलगिरी, सरक्षित परिगणित जाति)
सदाशिव त्रिपाठी (नौरंगपुर)
मुदिनायको (नौरगपुर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
अनिरुद्धा मिश्र (पदमपुर)
लाल रंजीत सिंह बरिहा (पदमपुर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
गणेश्वर महापात्र (पदुआ)
सुबाहु सिंह महेश चन्द्र (पाल—लहरा के. नगर)
बैधर नायक, (पाल—लहरा के. नगर, संरक्षित परिगणित जाति)
विश्वनाथ साहु (पंचपीर)
घासीराम शाण्डील (पचपीर—सरक्षित परिगणित जाति)

जगन्नाथ मिश्र (परलाकिमेदी)
अप्पन्ना डोरा विश्वासराय (परलाकिमेदी, संरक्षित परिगणित जनजाति)
लोकनाथ मिश्र (पतकुरा)
अर्जुनदास (पटनागढ़)
गणेशराम बरिया (पटनागढ, संरक्षित परिगणित जन जाति)
दिवाकर पटनायक (पत्रापुर)
कुमारी राम राज ((पट्टामुण्डई)
गोविंद प्रधान (पट्टापुर)
सदानन्द साहु (फुलबनी—उदयगिरि)
बालकृष्ण मल्लिक, (फुलबनि—उदयगिरि, संरक्षित परिगणित जन जाति)
जयकृष्ण महान्ति (पिप्ली)
फकीर चरण दास (पुरी)
हरिहर दास (पुरुषोत्तमपुर)
हरदेव त्रिया (रायरगंपुर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
लक्का अगापीट (राजनगर, संरक्षित परिगणित जन जाति)
श्रीमती सरस्वती देइ (राजनगर)
श्रीमती वसतमंजरी देवी (रणपुर)
कामय्या मदंगी (रायगदा, संरक्षित परिगणित जन जाति)
दीनबन्धु बेहेडा (रोस्सुलकोंडा)
सुरेन्द्र नाथ पटनायक (सालेपुर)
पुरनन्द सामल, (सालेपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
श्राद्धकर सुपाकर (सम्बलपुर—रैराखोल)
भिखारी घासी (सम्बलपुर—रैराखोल) (सरक्षित परिगणित जाति)
नीलकण्ठ दास (सत्यवादी)
भिखारी साहु (सोहेल्ला)
बीसी बिभार (सोहेल्ला, सरक्षित परिगणित जाति)
अन्त राम नन्द (सोनपुर)
नन्द किशोर दास (मोरो)
कृपानिधि नायक (सुन्दरगढ)
द्वारिका नाथ कुसुम (सुन्दरगढ, सरक्षित परिगणित जाति)
नारायण चन्द्र पति (सकिंदा)
पवित्र मोहन प्रधान (तलचर)
निशामणि कुतिया (तिरतोल)
मुरलीधर पाण्डा (टीटलगढ)
रमेशचन्द्र भोई (टीटलगढ, सरक्षित परिगणित जन जाति)
पत्तु मोलिको (उदयगिरि—मोहाना, सरक्षित परिगणित जन जाति)

पंजाब

राज्यपाल चन्द्रिकेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

मंत्री

1. मुख्यमंत्री तथा साधारण व्यवस्था, प्रचार, कानून और शान्ति, जेल, न्याय, पंचायत, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति	भीमसेन सच्चर
2. लगान, विकास (कृषि, जगल और पशुचिकित्सा) तथा भूमि का एकत्रीकरण	प्रतापसिंह कैरो
3. सिंचाई, बिजली और सहयोग समितियां	लहरीसिंह
4. वित्त, व्यवसाय और पुनर्वास	उज्जलसिंह
5. शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात	जगतनारायण
6. श्रम, स्टेशनरी, आन्तरिक कर, अन्य टैक्स, परिगणित जातियां और पिछडी हुई जातियां	सुन्दरसिंह

7. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बड़े कार्य और स्थानीय स्वराज्य — गुरबचनसिंह बजवा

वित्त

(लाख रुपयो मे)

बजट आंकड़े	आय	व्यय	बचत (+) या कमी (—)
1950-51 (खा)	1,686	1,600	+ 86
1951-52 (लेखा)	1,817	1,645	+ 172
1952-53 (सशोधित)	1,856	1,689	+ 167
1953-54 (बजट)	1,974	2,005	— 31

शिक्षा

पंजाब मे शिक्षा प्रसार के लिये एक चतुर्मुखी योजना जारी की गई, जिसके अनुसार कम कीमत पर शिक्षा देने, पाठ्य पुस्तकों की कीमत घटाने, नये स्कूल खोलने, शिक्षको को ट्रेण्ड करने और शिक्षा के लिये एक सलाहकार बोर्ड बनाने के कार्य जारी किये गये । 1952–53 मे प्रारम्भिक शिक्षा पर 1,06,50,000 रुपये व्यय किये गये । इसके अतिरिक्त ग्रामीण इलाको म स्कूलों की इमारते बनाने के लिये 6 लाख रुपये व्यय किये गये । गत वर्ष राज्य मे 25 बेसिक, 900 प्रारम्भिक और 30 हाई स्कूल नये खोले गये । रोपड़ मे शारीरिक शिक्षा देने के लिये एक कालेज खोला गया और चडीगढ़ मे एक गवर्नमेट कालेज । पाठ्य पुस्तको की कीमते 30 प्रतिशत घटाई जा रही है । शिक्षा पर 1952-53 मे 203 लाख रुपये व्यय किये गये और 1953-54 में 244 लाख रुपये ।

खाद्यान्न और कृषि

1952 मे पजाब से अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति के बाद 46,000 टन गेहू, 50,000 टन चावल और 5,000 टन जौ निर्यात किया गया । कृषि के सुधार के लिये कितनी ही नई स्कीमे जारी की गई, जिनके अनुसार भूमि का पुनरुद्धार, ग्रामीण खादो का प्रयोग और खेती की बीमारियों की रोकथाम का प्रयत्न जारी है । 1952 तक वहां 96,000 एकड नई भूमि पर खतीबाड़ी प्रारम्भ कर दी गई थी । इसी वर्ष 3 लाख एकड नई भूमि की सिचाई नहरो तथा 571 ट्यूबवैलो द्वारा की गई । रूई पैदा करने के क्षेत्र बढाये गये और उसकी उत्पत्ति 1952-53 म 2,67,000 गाठों तक पहुच गई, जब कि 1948-49 मे वह केवल 77,700 गाठे थी । किसानों को 67 लाख रुपये की कीमत का 20,000 टन अमोनियम सल्फेट (बढिया रासायनिक खाद) बांटा गया ।

व्यवसाय

राज्य का व्यावसायिक विकास करने के लिये एक इंडस्ट्रियल फाइनेस कारपोरेशन बनाया गया, जिसे दो करोड रुपये उधार देने का अधिकार दिया गया । व्यवसायों और सरकार में निकटता लाने के लिये दो सलाहकार समितियां बनाई गईं । गत वर्ष पंजाब में 441 नई कम्पनियां रजिस्टर्ड हुईं, जिनका आज्ञप्त मूलधन 130 करोड़ रुपये है और प्राप्त मूलधन 134

लाख। 1952-53 में फैक्टरी क़ानून के अनुसार रजिस्टर्ड फैक्टरियों की संख्या 1,500 तक पहुंच गई। 1953 में कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य बीमा स्कीम भी जारी कर दी गई।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952 में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों की संख्या 118 तक पहुंच गई, जब कि 1948 में वह केवल 62 थी। इसी तरह औषधालयों की संख्या 255 से 473 हो गई। 1952 में एक डैण्टल कालेज और एक नया अस्पताल खोला गया और कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय भी जारी किये गये। 1952 में इन अस्पतालों में 59,09,048 बीमारों का इलाज किया गया।

पंजाब विधान सभा

अध्यक्ष : गुरदयाल सिंह ढिल्लो

गुरदयाल सिंह ढिल्लो (झब्बल)
सरूपसिंह (नारनौंद)
भीमसेन सच्चर (लुधियाना नगर दक्षिण)
प्रतापसिंह कैरों (पट्टी)
लहरीसिंह (गनौर)
जगतनारायण (चण्डीगढ़)
गुरबचन सिंह बाजवा (बटाला)
सुन्दरसिंह (गुरदासपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
प्रबोधचंद्र (गुरदासपुर)
अब्दुल गफ्फार खान (अम्बाला नगर)
अब्दुल गनी दार (नूह)
अभयसिंह (रेवाड़ी)
अच्छरसिंह (अजनाला)
अजमेरसिंह (समराला)
अमीरचन्द गुप्ता (अमृतसर नगर—मध्य)
बाबूदयाल (सोहना)
बचन सिंह (बाघा पुराना)
बदलूराम (कलानौर)
बालूराम (बलाचौर)
बालू (फतेहाबाद, संरक्षित परिगणित जाति)
बलवन्तराय तायल (हिसार नगर)
बलवन्तसिंह (खालरा)
बनारसीदास गुप्त (थानेसर)
भागसिंह (मुक्तसर)
भागसिंह (कोट भाई, संरक्षित परिगणित जाति)
बिशनराम (नवांशहर, संरक्षित परिगणित जाति)
चाननसिंह (टांडा)
चन्दनलाल जौड़ा (अमृतसर नगर, उत्तर)
चांदराम अहलावत (झज्जर, संरक्षित परिगणित जाति)
चांदीराम वर्मा (अबोहर)
चूनीलाल (रेवाड़ी, संरक्षित परिगणित जाति)
दरबारसिंह (नूरमहल).
दर्शनसिंह (तरन तारन, संरक्षित परिगणित जाति)
दौलतराम (कैथल)
दौलतराम शर्मा (हमीरपुर)
डी. डी. पुरी (जगाधरी)
देवीलाल (सिरसा)
देवेन्द्रसिंह (मोगा, धर्मकोट)
देवराज आनन्द (अम्बाला छावनी)
देवराज सेठी (रोहतक नगर)
धर्मवीर वसिष्ठ (हसनपुर)
गजराजसिंह (गुड़गांव)
गोपालसिंह (जगरांव, संरक्षित परिगणित जाति)
गोपीचन्द (पुण्डरी)
गोरखनाथ (नारोट जयमल सिंह)

गुरांदास हंस (होशियारपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
गुरबचनसिंह अत्वाल (नवांशहर)
गुरबन्तासिंह (आदमपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
गुरदयालसिंह (करतारपुर)
गुरुदत्त सिंह (पलवल)
गुरुनेजसिंह (सीड़ा)
हरभजनसिंह (गढशंकर)
हरीचंद (आनन्दपुर)
हरीराम (धरमशाला)
हरीसिंह (दसूया)
हरकिशन सिंह सुरजीत (नकोदर)
हरनामसिंह सेठी (फीरोजपुर)
इकबालसिंह (जगरांव)
जगतराम भारद्वाज (होशियारपुर)
जगदीशचन्दर (शाहबाद)
जगदीशचन्द्र (लधियाना शहर, उत्तर)
जोगिन्दरसिंह (डेरा बाबा नानक)
कन्हैयालाल बुटैल (पालमपुर)
करतारसिंह (गढशकर)
कस्तूरीलाल गोयल (असध)
केदारनाथ सहगल (बल्लभगढ)
केशोदास (पठानकोट)
खेमसिंह (अमृतसर, संरक्षित परिगणित जाति)
खुशीराम गुप्त (अम्ब)
चौधरी कृष्णगोपाल दत्त (पानीपत)
लाजपतराय (हांसी)
लालचन्द प्रार्थी (कुल्लू)
मामचन्द (गोहाना, सरक्षित परिगणित जाति)
मामराज (भिवानी, संरक्षित परिगणित जाति)
मणीराम (फतेहाबाद)
मन्साराम कुठियाला (ऊना)
मारूसिंह मलिक (सम्पला)
मेहरसिंह (हमीरपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
मेहरसिंह (हरीपुर)
मोहनसिंह (तरन तारन)
मुहम्मद यासीन खा (फ़ीरोजपुर—झिरका)
मूलचन्द जैन (सम्भलका)
मोतासिंह आनन्दपुरी (आदमपुर)
मुख्तियारसिंह (मोगा—धर्मकोट—संरक्षित परिगणित जाति)
नन्दलाल (करनाल)
नान्हूराम (गोहाना)
नरजनदास धीमन (फिल्लौर)
नौरंगसिंह (समराला, सरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती प्रकाशकौर (रामदास)
प्रतापसिह (सुजानपुर)
प्रतापसिंह (रोपड़, संरक्षित परिगणित जाति)
प्रतापसिंह राय (गुरु हरसहाय)
प्रतापसिह (मल्लनवाला)
फग्गूराम (बटाना, सरक्षित परिगणित जाति)
पूरनसिंह (कोट भाई)
रघुवीरसिंह (सेराज)
राजेन्दरसिंह (रोपड़)
रालाराम (मुकेरिया)
रामचन्द्र (नूरपुर)
रामदयाल वैद्य (डबवाली)
रामकिशन (जालन्धर नगर, उत्तर-पश्चिम)
रामकुमार बिधत (भिवानी)
रामप्रकाश (मोलाना, सरक्षित परिगणित जाति)
रामसरूप (बुटाना)
रंजीतसिंह कैप्टिन (हिसार, सदर)
रत्तन अमोल सिंह (मोलाना)
रिज़कराम (राई)

साधूराम (नारायण गढ़)
समरसिंह (गरौण्डा)
सन्तराम (नकोदर, सरक्षित परिगणित जाति)
सरूपसिंह (अमृतसर नगर, पूर्व)
शमशेरसिंह (लुधियाना सदर)
श्रीमती शन्नो देवी (अमृतसर नगर, पश्चिम)
शेरसिंह (झज्जर)
शिवसिंह (रानिया)
श्रीराम शर्मा (सोनीपत)
श्रीमती सीतादेवी (जालन्धर नगर, दक्षिण पूर्व)
सोहनसिंह (ब्यास)
सोमदत्त (शिमला)
श्रीचन्द (बहादुरगढ़)
उत्तमसिंह (श्रीगोविन्दपुर)
वधवाराम (फाजिल्का)
वरियामसिंह (अमृतसर)
वज़ीरसिंह (देल्हन)

पंजाब विधान परिषद्

सभापति—कपूरसिंह

अविनाशचन्द्र (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
बलवन्त राय (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
गुलाबसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
हंसराज (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
कपूरसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
करतारसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
किशोरीलाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
करतारसिंह चौधरी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
साहिब राम सेठी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
तेजासिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
सोहनसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
उज्जलसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
यशपाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रामचन्द्र (स्नातकों का निर्वाचन क्षेत्र)
जोधसिंह (स्नातकों का निर्वाचन क्षेत्र)
सूरजभान (स्नातकों का निर्वाचन क्षेत्र)
चमनलाल (अध्यापकों का निर्वाचन क्षेत्र)
उदयसिंह (अध्यापकों का निर्वाचन क्षेत्र)
गुरचरनसिंह (अध्यापकों का निर्वाचन क्षेत्र)
मोहनलाल (होशियारपुर कांगड़ा-गुरदासपुर स्थानीय प्राधिकार)
गुरबख्श सिंह (होशियारपुर—कांगड़ा—गुरदासपुर स्था०)
कृष्णचन्द्र (होशियारपुर—कांगड़ा—गुरदासपुर स्था०)
नगिन्दरसिंह (जालन्धर—फीरोजपुर—अमृतसर—लुधियाना स्था०)
नरायणसिंह (जालन्धर—फीरोजपुर—अमृतसर—लुधियाना स्था०)
रामदयाल सिंह (जालन्धर—फीरोज़पुर—अमृतसर—लुधियाना स्था०)
दीनानाथ (जालन्धर—फीरोजपुर—अमृतसर—लुधियाना स्था०)
दरबारीलाल (अम्बाला—करनाल स्था०)
अमरनाथ (अम्बाला—करनाल)
बीरेन्द्रसिंह (गुड़गावां—रोहतक—हिसार—शिमला स्था०)
हरिसिंह (गुरगाव—रोहतक—हिसार—शिमला स्था०)
मोहरसिंह (गुरगावा—रोहतक—हिसार—शिमला स्था०)
प्रेमसुख दास (गुड़गावा—रोहतक—हिसार—शिमला स्था०)
सूर्यकान्त (नामज़द)
वीरसिंह (नामज़द)

एस० जी० ठाकुर सिंह (नामजद)
रामधन शर्मा (नामजद)
मोहनलाल (नामजद)
यशवन्तराय (नामजद)
कुमारी वी. जी. भान (नामजद)
बशीर-उद्दीन (नामजद)

उत्तर प्रदेश

राज्यपाल कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, तथा शासन व्यवस्था, आयोजना और सहयोग — गोविन्दवल्लभ पन्त
2. वित्त और शक्ति . . . मोहम्मद इब्राहीम
3. गृह तथा श्रम . . . . सम्पूर्णानन्द
4. व्यवसाय और पुनर्वास . . . हुक्मसिंह
5. सार्वजनिक कार्य . . . गिरधारीलाल
6. नागरिक पूर्ति और स्वास्थ्य . . चन्द्रभानु गुप्त
7. लगान और कृषि . . . चरणसिंह
8. न्याय और आन्तरिक कर . . . अली जहीर
9. शिक्षा और हरिजन सहायक . . हरगोविन्द सिंह
10. स्थानीय स्वराज्य . . . मोहनलाल गौतम
11. सूचना और सिंचाई . . . कमलापति त्रिपाठी
12. यातायात . . . . विचित्र नारायण शर्मा

उप-मंत्री

1. पार्लियामेंटरी कार्य और सहयोग — मगलाप्रसाद
2. जगल . . . . . जगमोहन सिंह नेगी
3. कृषि . . . . जगन्नाथ प्रसाद रावत
4. जेल . . . . . मुजफ्फर हुसैन
5. सार्वजनिक कार्य विभाग . . चतुर्भुज शर्मा
6. सिंचाई . . . . राममूर्ति
7. योजना . . . फूलसिंह

वित्त (लाख रुपयों में)

बजट आकडे	आय	व्यय	अतिरिक्त (+) या कमी (—)
1950-51 (लेखा)	5,189 (क)	5,184 (क)	+5
1951-52 (लेखा)	5,556 (क)	5,550 (क)	+6
1952-53 (संशोधित)	6,641 (क)	6,641 (क)	——
1953-54 (बजट)	7,438 (क)	7,880 (क)	—442

(क) आय और व्यय में, राज्य-परिवहन सेवा द्वारा कुल प्राप्ति और कुल व्यय भी सम्मिलित है।

शिक्षा

गत वर्ष उत्तर प्रदेश की ८6 म्युनिसिपल कमेटियो मे शिक्षा अनिवार्य कर दी गई । राज्य में विद्यार्थियों की संख्या 12 लाख तक पहुच गई । ग्रामीण क्षेत्रो मे भी शिक्षा के विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया गया और उसके लिये अधिक रुपये व्यय किये गये । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गांव से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने गावो के विकास के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके । उन मे प्रेरणा, सूझ, आत्मनियत्रण और आत्म-निर्भरता का विकास करने के लिये सामाजिक सेवा की एक विशेष स्कीम जारी की गई है । 17 जिलो में विद्यार्थियों को फौजी शिक्षा भी दी जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षा मे सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की । गूंगे और बहरों की शिक्षा की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया और इस कार्य के लिये एक अनावर्तक सहायता भी दी । देहरादून के अध-विद्यालय के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य की सरकार आधा-आधा खर्च दे रही है । 1953 मे हिन्दुस्तानी एकेडमी की कौसिल का 3 वर्षों के लिये पुर्ननिर्माण किया गया ।

इलाहाबाद के मनोविज्ञान ब्यूरो के कार्य का विस्तार करने के लिये मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर और बनारस मे मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोले गये । इन केन्द्रो मे विद्यार्थियो को इस बात की सलाह भी दी जाती है कि वे अपने लिये कौन-सा मार्ग चुने ।

खाद्यान्न और कृषि

1952–53 मे राज्य मे सैकडो नये ट्यूबवैल लगाये गये । कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कितनी ही सिचाई की नई नालिया खोदी गई । इसी वर्ष रगवान और अहरोरा बांध भी पूरे किये गये । इन कार्यों से 3,50,000 एकड नई भूमि की सिंचाई होगी ।

440 नये ट्यूबवैल लगाने का कार्य लगभग समाप्ति पर है । गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के जिलो मे लगभग 100 ट्यूबवैल लगाये गये, जिनसे 48,000 एकड भूमि की सिंचाई हो सकेगी । अल्मोडा, नैनीताल, गढवाल और टिहरी के इलाको मे 250 मील सिंचाई की नालिया खोदी गईं, जिनसे 20,000 एकड भूमि की सिंचाई होगी । केन्द्रीय क्षेत्रों मे 2,000 मील लम्बी नालिया बनाने का काम जारी है । शारदा और अपर-गंगा नहरो का जल-सामर्थ्य बढाने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसी तरह पूर्वी जमना नहर का भी विस्तार किया जा रहा है ।

1952 मे उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर मे कृषि महाविद्यालय मे एक नया अनुसन्धान विभाग स्थापित किया, जिसका उद्देश्य टैक्निकल अनुसन्धान और किसानो की आर्थिक आवश्यकताओं मे तालमेल पैदा करना है । तराई भाभर के जंगल मे हाथियो द्वारा ट्रैक्टर चलाने का परीक्षण भी किया जा रहा है ।

26 जिलों में जापानी ढंग से चावल बोने के कार्य जारी किये गये । आगरा और मथुरा में राजस्थान के रेगिस्तान की वृद्धि रोकने के लिये नये जंगल बोये गये ।

गत वर्ष व्यवस्थापिका सभा ने भूमि अधिकार सम्बन्धी एक नया कानून पास किया । अपने कार्य की शिक्षा लेने के लिये लगान सम्बन्धी बहुत से सरकारी कार्यकर्ता पंजाब में भेजे गये । जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये भूमि सम्बन्धी कितने ही कानून पास हुए । राज्य में राशन समाप्त कर दिया गया और खुली बिक्री की प्रथा जारी की गई । अन्न खरीदने की

प्रथा बन्द कर दी गई और राज्य में अन्न के यातायात पर से सब प्रतिबन्ध उठा लिये गये। अन्नों की कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिये गये। 1953 के प्रारम्भ में गेहूं तथा कुछ खाद्यान्नों की कीमतें कतिपय नगरों में ऊपर की ओर गईं, इसलिये ऐसे शहरों मे सरकार ने सस्ते दामों पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो छटांक आयात गेहूं देने का प्रबन्ध किया। जहां राशन जारी था, वहां सस्ते दामों पर अन्नों की बिक्री का प्रबन्ध भी किया गया। बाद में एक लाख से कम आबादी वाले नगरों मे से राशन हटा लिया गया। जिन पूर्वी और पहाड़ी जिलों में प्राकृतिक मुसीबतों के कारण अन्न की कमी हो गई थी, वहां सरकार ने अन्न पहुंचाने का प्रबन्ध किया। इस काम के लिये हवाई जहाज भी इस्तेमाल में लाये गये।

व्यवसाय

1952 में कानपुर में कार्यकर्ताओं की सरकारी बीमा स्कीम जारी कर देने से वहां एक लाख कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचा। कार्यकर्ताओं के लिए प्रोविडेण्ट फण्ड स्कीम भी जारी की गई। 1952–53 में गृह उद्योग कमेटी की जगह 'गृह व्यवसाय बोर्ड' स्थापित किया गया। हाथ के करघों को संरक्षण देने के लिये एक हैण्डलूम बोर्ड बनाया गया। राज्य मे हाथ से कता ऊनी और सूती कपड़ा बनाने के लिये क्रमशः 3 और 4 ग्रामीण केन्द्र स्थापित किये गये। आजमगढ़ जिले के मऊ नामक स्थान पर एक रंगने वाली फैक्टरी खोली गई। देहाती हलकों मे धधो की शिक्षा देने के लिये 1,21,000 रुपये के व्यय से जौनपुर में एक पोलिटैक्निक कालेज स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अच्छा अन्न पैदा करने के लिये सरकार ने 30 लाख रुपये की एक पंचवर्षीय योजना जारी की है।

मिर्ज़ापुर ज़िले में रौबर्ट्सगंज की सरकारी सीमेण्ट फैक्टरी विशेष उन्नति कर रही है। इमारत बन चुकी है और मशीनें लगाई जा रही है। लखनऊ के सरकारी यंत्र निर्माण केन्द्र में पानी के मीटरों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। 1952 में प्रति मास 700 मीटर बन रहे थे। यह संख्या अब काफी बढ़ गई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

छोटे कस्बों और देहाती इलाकों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने की ओर विशेष ध्यान दिया गया और गत वर्ष कितने ही नये औषधालय खोले गये। कितने ही ज़िलो मे नये अस्पताल जारी किये गये। देहरादून ज़िले के जौनसार बावर परगने मे लैगिक बीमारियो की रोकथाम के लिये एक चिकित्सक दल भेजा गया।

24 ज़िलों में मलेरिया की रोकथाम के प्रयत्न किये गये। प्लेग की रोक थाम के भी उपाय किये गये। नैनीताल जिले के गेथिया नामक स्थान पर विद्यमान एक तपेदिक के अस्पताल को सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया। अब विशेषतः विद्यार्थियों और अध्यापको की चिकित्सा के लिये एक और तपेदिक का सेनेटोरियम खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है। बस्ती और बदायूं में 2 तपेदिक वार्डो का निर्माण किया जा रहा है। डब्ल्यू० एच० ओ० टैक्निकल सहायता कार्यक्रम के अनुसार आगरा के सरोजिनी नायडू सरकारी मैडिकल कालेज मे एक अर्वाचीन ढंग का तपेदिक निरोधक क्लीनिक खोला जा रहा है।

आंख सम्बन्धी बीमारियों की रोकथाम के लिये एक ओपथैल्मिक एडवाइजरी कौंसिल (चक्षु सम्बन्धी सलाहकार समिति) बनाई गई। आंख की बीमारियों की चिकित्सा के लिये सरकार अब 75,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता देती है।

राज्य में होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये एक होमियोपैथिक बोर्ड बनाया गया है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि योग्य होमियोपैथिक चिकित्सक गांवों में जाकर अपना कार्य करें। जनता को शुद्ध दवाइयां प्राप्त हो सके, इसकी ओर भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष—आत्माराम गोविन्द खेर

देवकीनन्दन विभव (आगरा)
बाबूलाल मित्तल (आगरा शहर, उत्तर)
सी० वी० महाजन (आगरा शहर, पश्चिम)
रामनारायण त्रिपाठी (अकबरपुर पूर्व)
रामदुलारे मिश्र (अकबरपुर-दक्षिण)
जयराम वर्मा (अकबरपुर-पश्चिम)
रामदास (अकबरपुर पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)
मोहनसिंह शाक्य (अलीगंज दक्षिण)
कल्याणचन्द्र मोहिले (इलाहाबाद शहर सेन्ट्रल)
[गणेशप्रसाद जायसवाल (इलाहाबाद शहर पूर्व)
भूपालसिंह खाती (अलमोडा उत्तर)
गोवर्द्धन तिवारी (अलमोड़ा दक्षिण)
कुंवर रणंजयसिंह (अमेठी सेन्ट्रल)
ख्यालीराम (अमरोहा पूर्व)
मुहम्मद तकी हादी (अमरोहा पश्चिम)
दीनदयाल शर्मा (अनूपशहर उत्तर)
नाथूसिंह (आंवला पूर्व-फरीदपुर)
सुन्दरलाल (आंवला पूर्व-फरीदपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
नवलकिशोर (आवला पश्चिम)
श्रीनिवास (अतरौली उत्तर)
राजाराम (अतरौली दक्षिण-कोइल पूर्व)
सत्यनारायण (औरय्या भरथना दक्षिण)
तुलाराम (औरय्या-भरथना दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)
रामसनेही भारतीय (बबरू, पश्चिम)
हरख्याल सिंह (बागपत पूर्व)
रघवीरसिंह (बागपत दक्षिण)
चरणसिंह (बागपत पश्चिम)
शम्भूनाथ चतुर्वेदी (बाह)
राममूर्त्ति (बहेड़ी उत्तर पूर्व)
धर्मदत्त वैद्य (बहेड़ी दक्षिण पश्चिम बरेली पश्चिम)
शिवशरणलाल श्रीवास्तव (बहराइच पूर्व)
राजकिशोर राय (बहराइच-पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
त्रिलोकीनाथ कौल (बहराइच पश्चिम)
जमनाप्रसाद (बहराइच, पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)
राम अनन्त पाण्डे (बलिया, सेन्ट्रल)
राधामोहन सिंह (बलिया पूर्व)
जगन्नाथ सिंह (बलिया-पूर्व-बंसदी-दक्षिण पश्चिम)
बलदेव सिंह (बनारस, केन्द्रीय)
लालबहादुर सिंह (बनारस-उत्तर)
राजनारायण (बनारस दक्षिण)
देवमूर्त्ति शर्मा (बनारस, पश्चिम)
शेख मुहम्मद अब्दुल समद (बनारस शहर, उत्तर)
सम्पूर्णानन्द (बनारस शहर, दक्षिण)
पहलवान सिंह (बादा)
बैजनाथ सिंह (बंसदी, सेंट्रल)
शिवमंगल सिंह (बसदी पश्चिम)
केशभान (बसगांव सेन्ट्रल)
भगवती प्रसाद दुबे (बंसगांव पूर्व-गोरखपुर दक्षिण)
भृगुनाथ चतुर्वेदी (बसगांव दक्षिण-पूर्व)
गणेशप्रसाद पांडेय (बंसगांव, दक्षिण-पश्चिम)
श्रीमती यशोदादेवी (बंसगाव, दक्षिण-पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति)
मथराप्रसाद (बंसी, उत्तर)

पुद्धन राम (बंसी उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)
रामकुमार शास्त्री (बंसी, दक्षिण)
श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद (बरेली पूर्व)
गोविन्द वल्लभ पन्त (बरेली म्यूनिसिपैलिटी)
रामचरण लाल गंगवार (बरेली पश्चिम)
अंशुमान सिंह (बस्ती पूर्व)
प्रभुदयाल (बस्ती पश्चिम)
रामलाल (बस्ती पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)
रामस्वरूप गुप्त (भोगनीपुर पश्चिम डेरापुर दक्षिण)
गजेन्द्रसिंह (बिधुना पूर्व)
महरबानसिंह (बिधुना पश्चिम—भरथाना उत्तर--इटावा उत्तर)
घासीराम (बिधुना पश्चिम—भरथना उत्तर—इटावा उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती चन्द्रावती (बिजनौर केन्द्रीय)
अब्दुल लतीफ (बिजनौर–उत्तर नजीबाबाद पश्चिम)
शिवकुमार शर्मा (बिजनौर दक्षिण--धामपुर दक्षिण पश्चिम)
बृजबासी लाल (बीकापुर सेन्ट्रल)
अवधेश प्रतापसिंह (बीकापुर पूर्व)
रामहर्ष यादव (बीकापुर पश्चिम)
हरसहाय (बिलारी)
महीलाल (बिलारी, संरक्षित परिगणित जाति)
राधाकृष्ण अग्रवाल (बिलग्राम पूर्व)
वीरेन्द्रनाथ (बिलग्राम पश्चिम)
श्रीमती बृजरानी देवी (बिलहौर-अकबरपुर)
मुरलीधर (बिलहौर-अकबरपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
हरिप्रसाद (बिसालपुर सेन्ट्रल)
शिवराज सिंह यादव (बिसौली-गन्नौर पूर्व)
चुन्नीलाल सगर (बिसौली-गन्नौर पूर्व, सरक्षित परिगणित जाति)
सुरेशप्रकाश सिंह (निसवान-सिदौली पूर्व)
मुन्नूलाल (बिसवान-सिदौली पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
श्रीनिवास पंडित (बदाऊं उत्तर)
रिक्त (बदाऊं दक्षिण पश्चिम)
मुहम्मद नबी (बुधाना पूर्व-जनसठ दक्षिण)
रामदास (बुधाना पूर्व-जनसठ दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)
श्रीचनु (बुधाना पश्चिम)
बनारसी दास (बुलन्दशहर सेन्ट्रल)
मोहनसिंह (बुलन्दशहर उत्तर पूर्व)
इर्तजा हुसैन (बुलन्दशहर-उत्तर पश्चिम)
देवदत्त शर्मा (बुलन्दशहर दक्षिण-अनूपशहर दक्षिण)
धरमसिंह (बुलन्द शहर दक्षिण—अनूपशहर दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)
मुजफ्फर हुसेन (चैल उत्तर)
कमलापति त्रिपाठी (चकिया, चन्दौली दक्षिण पूर्व)
रामलखन (चकिया-चन्दौली दक्षिण-पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
शांतिप्रपन्न शर्मा (चकराता-पश्चिमी दून उत्तर)
गंगाधर मैठाली (चमोली पश्चिम-पौड़ी उत्तर)
कामताप्रसाद विद्यार्थी (चन्दौली उत्तर)
उमाशंकर तिवारी (चन्दौली दक्षिण-पश्चिम रामनगर)
रामहेत सिंह (छाता)
अवधेशचन्द्र सिंह (चिब्रामाऊ पूर्व-फरूखाबाद पूर्व)
पातीराम (चिब्रामऊ पूर्व फर्रुखाबाद पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
चिरंजीलाल पालीवाल (चिब्रामऊ दक्षिण कन्नौज दक्षिण)
राजकुमार शर्मा (चुनार उत्तर)
राजनारायण सिंह (चुनार दक्षिण)
उदभानसिंह (डलमाऊ पूर्व)

गुप्तारसिंह (दालमाऊ दक्षिण पश्चिम)
ओंकारसिंह (दातागंज उत्तर)
नरोत्तमसिंह (दातागंज दक्षिण बदायू दक्षिण-पूर्व)
फूलसिंह (देवबन्द)
हरदेव (देवबन्द, संरक्षित परिगणित जाति)
सत्यसिंह राणा (देवप्रयाग)
फारुक चिश्ती (देवरिया उत्तर पूर्व)
रामेश्वर लाल (देवरिया दक्षिण)
रामजी सहाय (देवरिया दक्षिण पश्चिम हाता दक्षिण पश्चिम)
सीताराम (देवरिया दक्षिण पश्चिम, हाता दक्षिण पश्चिम, सरक्षित पगिणित जाति)
शिवराम पाडे (डेरापुर उत्तर)
खूबसिंह (धामपुर उत्तर पूर्व-नगीना पूर्व)
गिरधारीलाल (धामपुर उत्तर पूर्व-नगीना पूर्व, सरक्षित परिगणित जाति)
मुहम्मद सुलेमान अधमी (डामरिया गंज उत्तर पूर्व-बसी पश्चिम)
रामलखन मिश्र (डोमरियागज उत्तर पश्चिम)
आदिल अब्बासी (डोमरियागज दक्षिण)
शिवमगलसिंह कपूर (डोमरिया गंज पश्चिम)
बृजभूषण (दूढी-रौवर्टगंज)
रामस्वरूप (दूढी-रौवर्टगंज, संरक्षित पगिणित जाति)
श्रीमती विद्यावती राठौर (एटा पूर्व-अलीगंज पश्चिम-कासगज दक्षिण)
होतीलाल दास (एटा दक्षिण)
गोपीनाथ दीक्षित (इटावा दक्षिण)
उल्फतसिंह चौहान "निर्भय" (एतमादपुर-आगरा पूर्व)
पुत्तूलाल (एतमादपुर-आगरा पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
मदनगोपाल वैद्य (फैजाबाद पूर्व)
नारायण दास (फैजाबाद पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
राजाराम मिश्र (फैजाबाद पश्चिम)
सियाराम गंगवार (फरुखाबाद सेन्ट्रल-करीमगंज पूर्व)
मथुराप्रसाद त्रिपाठी (फरुखाबाद पश्चिम-चिब्रामऊ)
अब्दुर रऊफ खा (फतेहपुर पूर्व—खागा उत्तर)
अवधशरण वर्मा उर्फ लल्लाजी (फतेहपुर उत्तर)
भगवतीप्रसाद शुक्ल (फतेहपुर दक्षिण)
अनन्तस्वरूप सिंह (फतेहपुर दक्षिण-खागा दक्षिण)
भगवानदीन (फतेहपुर दक्षिण—खागा दक्षिण)
इसरारुल हक (फीरोजाबाद-फतेहाबाद)
गगाधर (फिरोजाबाद-फतेहाबाद, सरक्षित परिगणित जाति)
रामसहाय शर्मा (गरोठा-मोठ उत्तर)
बृजबिहारी मेहरोत्रा (घाटमपुर-भोगलपुर पूर्व)
दयालदास भगत (घाटमपुर-भोगलपुर पूर्व, सरक्षित परिगणित जाति)
विचित्रनारायण शर्मा (गाजियाबाद उत्तर पूर्व)
तेजासिंह (गाजियाबाद- उत्तर पश्चिम)
कुंवर बलबीर सिंह (गाजियाबाद दक्षिण)
रिक्त (गाजीपुर दक्षिण पूर्व)
भोलासिंह यादव (गाजीपुर दक्षिण पश्चिम)
विश्वनाथसिंह गौतम (गाजीपुर पश्चिम)
रामसुन्दर पाडेय (घोसी पूर्व)
झारखडे राय (घोसी पश्चिम)
श्रीमती सज्जन देवी मेहनोत (गोंडा पूर्व)
ज्वालाप्रसाद सिन्हा (गोंडा पश्चिम)
इस्तफा हुसैन (गोरखपुर सेन्ट्रल)
केशव पाडेय (गोरखपुर उत्तर पूर्व)
महादेव प्रसाद (गोरखपुर उत्तर पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
अक्षयवर सिंह (गोरखपुर, दक्षिण पूर्व)
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह (गोरखपुर पश्चिम)
करनसिंह यादव (गन्नौर उत्तर)
बेचनराम गुप्ता (ज्ञानपुर पूर्व)
बंसनारायण (ज्ञानपुर उत्तर पश्चिम)
बेचनराम (ज्ञानपुर उत्तर पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (हमीरपुर-मौदहा उत्तर)
महाबीर प्रसाद शुक्ल (हंडिया दक्षिण)
श्रीमती प्रकाशवती सूद (हापुड़ उत्तर)
हरिसिंह (हापुड़ उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)
लुत्फअली खां (हापुड़ दक्षिण)
वीरसेन (हापुड़दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)
चन्द्रहास (हरदोई पूर्व)
किन्दरलाल (हरदोई पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
कृपाशंकर (हरय्या पूर्व-बस्ती पश्चिम)
शिवनारायण (हरय्या पूर्व-बस्ती पश्चिम, संरक्षित पिरगणित जाति)
प्रभाकर शुक्ल (हरय्या उत्तर पश्चिम)
सीताराम (हरय्या दक्षिण पश्चिम)
लताफ़त हुसैन (हसनपुर उत्तर)
जगदीशप्रसाद (हसनपुर दक्षिण-सम्भल पश्चिम)
सूर्य बली पाण्डेय (हाटा केन्द्रीय)
शिवप्रसाद (हाटा केन्द्रीय, संरक्षित परिगणित जाति)
महाबीरसिंह (हाता उत्तर)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (हाथरस)
हरदयाल सिंह पिपल (हाथरस, संरक्षित परिगणित जाति)
कल्याण राय (हजूर-मिल्क उत्तर)
शिवदानसिंह (इगलास)
रामगुलाम सिंह (जलालाबाद पश्चिम)
सहदेवसिंह (जलेसर-एटा उत्तर)
चिरंजीलाल (जलेसर एटा उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)
विष्णुदयाल (जसराना)
हरगोविंदसिंह (जौनपुर पूर्व)
दीपनारायण वर्मा (जौनपुर पश्चिम)
भगवतीदीन तिवारी (जौनपुर उत्तर-शाहगंज पश्चिम)
आत्माराम गोविन्द खेर (झांसी पूर्व)
काशीप्रसाद पांडेय (कादीपुर)
शंकरलाल (कादीपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
सुलतान आलम खां (कायमगंज पश्चिम)
केश गुप्त (कैराना उत्तर)
वीरेन्द्र वर्मा (कैराना दक्षिण)
सियाराम चौधरी (केसरगज सेन्ट्रल)
दीवान सुन्दरदास (केसरगंज उत्तर)
हुकुमसिंह (केसरगंज दक्षिण)
वीरेन्द्र शाह (कालपी-जालोन उत्तर)
बसन्त लाल (कालपी परिगणित जाति)
कालीचरण टन्डन (कन्नौज, उत्तर)
हमीदखां (कानपुर शहर केन्द्रीय पूर्व)
बासुदेव मिश्र (कानपुर शहर सेन्ट्रल पश्चिम)
जवाहरलाल (कानपुर शहर पूर्व)
सूर्यप्रसाद अवस्थी (कानपुर नगर उत्तर)
ब्रह्मदत्त दीक्षित (कानपुर शहर दक्षिण)
बेनीसिंह (कानपुर तहसील)
एच० एन० बहुगुना (करछना उत्तर-चैल दक्षिण)
जवाहरलाल (करछना उत्तर-चैल दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
शिवबक्श सिह (करहल पूर्व-भोगाव)
मिजाजीलाल (करहल पूर्व-भोगाव, सरक्षित परिगणित जाति)
वशीदास धागर (करहल पश्चिम-शिकोहाबाद पूर्व)
श्रीमती सईदा जहा बेगम मखफी (कासगज पूर्व-अलीगज उत्तर)
तिरमलसिह (कासगज उत्तर)
बाबूराम गुप्त (कासगज-पश्चिम)
जगनप्रसाद रावत (खैरगढ़)
लालबहादुर सिंह (केराकट-जौनपुर दक्षिण)
परमेश्वरी (केराकट-जौनपुर दक्षिण सरक्षित परिगणित जाति)
मोहनलाल गौतम (खैर-कोइल उत्तर पश्चिम)

रामप्रसाद देशमुख (खैर-कोइल उत्तर पश्चिम सरक्षित परिगणित जाति)
शिवराज बलीसिंह · (खजुहा पूर्व—फ़तेहपुर दक्षिण पश्चिम)
गुरुप्रसाद पांडेय (खजुहा पश्चिम)
अब्दुल मोईज खा (खलीलाबाद केन्द्रीय)
राजाराम शर्मा (खलीलाबाद उत्तर)
धनुष धारी पाण्डेय (खलीलाबाद दक्षिण)
रामसुन्दर (खलीलाबाद दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
कृष्ण स्वरूप भटनागर (खुर्जा)
भीमसेन (खुर्जा, सरक्षित परिगणित जाति)
रमेश वर्मा (किशौली)
मल्खानसिंह (कोइल केन्द्रीय)
चित्तर सिह निरंजन (कोंच)
रामनरेश शुक्ल (कुन्डा दक्षिण)
रामस्वरूप भारतीय (कुन्डा दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
बशीधर मिश्र (लखीमपुर दक्षिण)
छेदालाल चौधरी (लखीमपुर दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
तेजबहादुर (लालगज, उत्तर)
कालिकासिह (लालगज, दक्षिण)
कृष्णचन्द्र शर्मा (ललितपुर दक्षिण)
रामप्रसाद नौटियाल (लेंसडौन पूर्व)
जगमोहन सिंह नेगी (लासडौन पश्चिम)
हरीशचन्द्र बाजपेयी (लखनऊ, केन्द्रीय)
रामशकर रविवासी (लखनऊ, केन्द्रीय सं० प० जा०)
अली जहीर (लखनऊ शहर सेन्ट्रल)
चन्द्रभानु गुप्त (लखनऊ शहर पश्चिम)
पुलिन बिहारी बनर्जी (लखनऊ शहर पश्चिम)
नागेश्वर द्विवेदी (मछलीशहर उत्तर)
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी (मछलीशहर दक्षिण)
परिपूर्णानन्द वर्मा (महाराजगंज उत्तर)
रामप्रसाद सिंह (महाराजगज दक्षिण)
शुकदेव प्रसाद (महाराजगंज दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
मन्नीलाल गुरुदेव म (होबा-कुलपहाड़-चरखारी)
जोरावर वर्मा (महोबा-कुलपहाड़-चरखारी, सरक्षित परिगणित जाति)
वर्मा नकवी (महाराजगज- पूर्व सलोन उत्तर)
रामस्वरूप विशारद (महराजगज पश्चिम)
रामेश्वर प्रसाद (महराजगज पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति)
रामनाथ खेरा (महरौनी)
गणेशचन्द्र काछी (मैनपुरी उत्तर-भोगाव उत्तर)
वीरेन्द्र पति यादव (मैनपुरी दक्षिण)
श्याममनोहर मिश्र (मलीहाबाद-बाराबकी, उत्तर पश्चिम)
तुलाराम रावत (मलीहाबाद-बाराबकी, उत्तर पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति)
द्वारकाप्रसाद मौर्य (मरियाहू उत्तर)
रमेशचन्द्र शर्मा (मरियाहू दक्षिण)
लक्ष्मीरमण आचार्य (माट-सदाबाद पश्चिम)
दालचन्द (माट-सदाबाद पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति)
श्रीनाथ (मथुरा उत्तर)
आचार्य जुगलकिशोर (मथुरा दक्षिण)
जगपतसिह (मऊ-करवी-बबेरू पूर्व)
दर्शनराम (मऊ-करवी-बबेरू पूर्व, सरक्षित परिगणित जाति)
लक्ष्मणराव कदम (मऊ-मोठ-दक्षिण झासी पश्चिम ललितपुर उत्तर)
गज्जूराम (मऊ-मोठ दक्षिण-झासी पश्चिम ललितपुर उत्तर, सरक्षित परिगणित जाति)
तेजप्रताप सिह (मौदाहा दक्षिण)
विष्णुसरन दुबलिश (मवाना)
रामजीलाल सहायक (मवाना, सरक्षित परिगणित जाति)

कैलाशप्रकाश (मेरठ म्यूनिसिपैलिटी)
मंगलाप्रसाद (मेजा-करछना दक्षिण)
रघुनाथ प्रसाद (मेजा-करछना दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
कृष्णशरन आर्य (मिल्क दक्षिण शाहाबाद)
अमरेशचन्द्र (मिर्ज़ापुर उत्तर)
अज़ीज़ इमाम (मिर्ज़ापुर दक्षिण)
रामकृष्ण जैसवार (मिर्ज़ापुर दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)
गंगाधर शर्मा (मिसरीख)
डल्लाराम (मिसरीख, संरक्षित परिगणित जाति)
कमाल अहमद (मोहम्मदी-पूर्व)
रामभजन (मोहम्मदी)
पद्मनाथ (महमूदाबाद, गोहाना, दक्षिण)
हबीबुररहमान (महमूदाबाद उत्तर-घोसी दक्षिण)
श्रीनाथराम (महमूदाबाद उत्तर-घोसी दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
शिवपूजन राय (महमूदाबाद उत्तर पूर्व)
विजयशकर प्रसाद (महमूदाबाद दक्षिण)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव (मोहनलालगज)
दाऊदयाल खन्ना (मुरादाबाद उत्तर)
केदारनाथ (मुरादाबाद दक्षिण)
श्रीमती सावित्रीदेवी (मुसाफिरखाना केन्द्रीय)
नाज़िम अली (मुसाफिरखाना उत्तर—सुलतानपुर उत्तर)
गुलज़ार (मुसाफिरखाना उत्तर-सुलतानपुर उत्तर, सरक्षित परिगणित जाति)
गुरप्रसाद सिंह (मुसाफ़िरखाना दक्षिण अमेठी पश्चिम)
द्वारकाप्रसाद (मुजफ्फरनगर केन्द्रीय)
बलवन्तसिंह (मुजफ्फरनगर पूर्व—जनसाथ उत्तर)
राजेन्द्र दत्त (मुजफ्फरनगर पश्चिम)
एच० एम० इब्राहीम (नगीना दक्षिण पश्चिम—धामपुर उत्तर पश्चिम)
नारायणदत्त तिवारी (नैनीताल उत्तर)
लक्ष्मणदत्त (नैनीताल दक्षिण)
रतनलाल (नजीबाबाद उत्तर—नगीना उत्तर)
दाताराम (नाकुर दक्षिण)
वीरेन्द्रविक्रमसिंह (नानपारा पूर्व)
बसन्तलाल शर्मा (नानपारा उत्तर)
मुहम्मद सादत अली खा (नानपारा दक्षिण)
श्यामाचरण वाजपेयी (नरैनी)
नौरंगलाल (नवाबगंज)
जगतनारायण (नवाब गंज उत्तर)
उमाशकर मिश्र (नवाब गंज दक्षिण—हैदरगढ़ रामसनेही घाट)
घनश्यामदास (नवाबगंज दक्षिण—हैदरगढ़ रामसनेही घाट, संरक्षित परिगणित जाति)
करनसिंह (निघासन-लखीमपुर उत्तर)
जगन्नाथ प्रसाद (निघासन—लखीमपुर उत्तर, संरिक्षत परिगणित जाति)
चतुर्भुज शर्मा (उरई-जालौन दक्षिण)
गेंदासिंह (पडरौना पूर्व)
जगतनाथ मल (पडरौना उत्तर)
राजबंसी (पडरौना दक्षिण पश्चिम—देवरिया दक्षिण-पूर्व)
राम सुभग वर्मा (पडरौना पश्चिम)
रामराज (पट्टी पूर्व)
गिरजा रमण (पट्टी दक्षिण)
चन्द्रसिंह रावत (पौड़ी दक्षिण-चमोली पूर्व)
बलदेवसिंह (पौड़ी दक्षिण-चमोली पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
प्रेमकिशन खन्ना (पवायां-शाहजहांपुर पूर्व)
नारायणदीन (पवायां-शाहजहांपुर पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
गौरीराम गुप्त (फरेन्दा केन्द्रीय)
रामअवध सिंह (फरेन्दा उत्तर)
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय (फूलपुर केन्द्रीय)

शिवनाथ काटजू (फूलपुर केन्द्रीय)
भूवरजी (फूलपुर पूर्व-हन्डिया उत्तर पश्चिम)
बृजबिहारी मिश्र (फूलपुर उत्तर)
रामबचन यादव (फूलपुर दक्षिण)
श्रीमती आशालता व्यास (फूलपुर दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)
निरंजनसिंह (पीलीभीत पूर्व-बीसलपुर पश्चिम)
मकसूद आलम खा (पीलीभीत पश्चिम)
नरेन्द्रसिंह बिष्ट (पिथोरागढ चम्पावत)
खुशीराम (पिथोरागढ-चम्पावत संरक्षित परिगणित जाति)
भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ पूर्व)
राम आधार तिवारी (प्रतापगढ उत्तर पश्चिम-पट्टी उत्तर पश्चिम)
रामकिंकर (प्रतापगढ उत्तर पश्चिम-पट्टी उत्तर पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति)
राजाराम (प्रतापगढ पश्चिम कुंडा उत्तर)
मुनीद्रपाल सिंह (पूरनपुर—बीसलपुर पूर्व)
रामअधीन यादव (पुरवा सेन्ट्रल)
जटाशकर शुक्ल (पुरवा उत्तर—हसनगंज)
सेबाराम (पुरवा उत्तर—हसनगंज, सरक्षित परिगणित जाति)
देवदत्त मिश्र (पुरवा दक्षिण)
रामशकर द्विवेदी (रायबरेली-दलमऊ उत्तर)
रामप्रसाद (रायबरेली-दलमऊ उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)
फजलुल हक (रामपुर शहर)
महन्त जगन्नाथबक्श दास (रामसनेही घाट)
बाबूलाल कुशमेश (रामसनेही घाट, संरक्षित परिगणित जाति)
मदनमोहन उपाध्याय (रानीखेत उत्तर)
हरगोविंद (रानीखेत दक्षिण)
मन्धाता (रसरा पूर्व-बलिया दक्षिण पश्चिम)
रामरतन प्रसाद (रसरा पूर्व-बलिया दक्षिण पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)
गंगाप्रसाद सिंह (रसरा पश्चिम)
श्रीपति सहाय (रठ)
जयेन्द्रसिंह बिस्त (रावेन-तेहरी उत्तर)
दीनदयालु शास्त्री (रूड़की पूर्व)
अतहर हसन (रुड़की दक्षिण)
शुगनचन्द (रुड़की पश्चिम—सहारनपुर उत्तर)
जयपाल (रुड़की पश्चिम—सहारनपुर उत्तर, सरक्षित परिगणित जाति)
अशरफ अली खा (सादाबाद पूर्व)
शिवराम राय (सदर-आजमगढ़-उत्तर)
सुरजूराम (सदर-आजमगढ़-उत्तर सरक्षित परिगणित जाति)
हबीबुर्रहमान (सफीपुर—उन्नाव उत्तर)
मोहनलाल (सफीपुर—उन्नाव उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)
विश्राम राय (सगरी पूर्व)
उमाशकर (सगरी पश्चिम)
मजूरल नबी (सहारनपुर शहर)
महमूदअली खां (सहारनपुर उत्तर पश्चिम—नाकुर उत्तर)
केशवराम (सहसवान पूर्व)
मुश्ताक अलीखा (सहसवान पश्चिम)
कमलासिंह (सैदपुर)
देवराम (सैदपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (सलीमपुर पूर्व)
शिवबचन राव (सलीमपुर उत्तर)
बद्रीनारायण मिश्र (सलीमपुर दक्षिण)
देवनन्दन शुक्ल (सलीमपुर पश्चिम)
दलबहादुर सिंह (सलोन दक्षिण)
जगदीशशरण रस्तोगी (सम्भल पूर्व)
लेखराज सिंह (सम्भल पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती लक्ष्मीदेवी (सन्दीला-बिलग्राम दक्षिण पूर्व)
टीकाराम (सन्दीला-बिलग्राम दक्षिण पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
विश्वम्भरसिंह (सरधना-पूर्व)
फतेहसिंह राणा (सरधना पश्चिम)

छेदालाल (शाहाबादपूर्व-हरदोई उत्तर पश्चिम)
कन्हैयालाल बाल्मीकी (शाहाबाद पूर्व-हरदोई उत्तर पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)
ऐजाज़ रसूल (शाहबाद पश्चिम)
लक्ष्मीशंकर यादव (शाहगंज पूर्व)
बाबूनन्दन (शाहगंज पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
हबीबुर रहमान खां (शाहजहांपुर केन्द्रीय)
प्रतिपालसिंह (शाहजहापुर पश्चिम—जलालाबाद पूर्व)
महाराज सिंह (शिकोहाबाद पश्चिम)
हनुमानप्रसाद (सिधौली पश्चिम)
कन्हैयालाल (सिधौली पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति)
केवलसिंह (सिकन्दराबाद पूर्व)
रामचन्द्र विकल (सिकन्दराबाद पश्चिम)
नेत्रपाल सिंह (सिकन्दरा राऊ उत्तर–कोइल दक्षिण पूर्व)
नेकराम शर्मा (सिकन्दराराऊ दक्षिण)
रिक्त (सिराथू—मंझनपुर)
सुखीराम भारतीय (सिराथू—मंझनपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
बशीर अहमद हकीम (सीतापुर पूर्व)
हरीशचन्द्र अस्थाना (सीतापुर उत्तर-पश्चिम)
कृष्णचन्द्र गुप्त (सीतापुर, दक्षिण-पूर्व)
संग्रामसिंह (सोरांव उत्तर-फूलपुर पश्चिम)
परमानन्द सिन्हा (सोरांव दक्षिण)
रामबाली मिश्र (सुलतानपुर पूर्व-अमेठी पूर्व)
कुंवरकृष्ण (सुलतानपुर पश्चिम)
महमूदअली खां (सुमर-टाडा-बिलासपुर) .
मुहम्मद नासीर (टांडा)
रामसुमेर (टांडा, सरक्षित परिगणित जाति)
चन्द्रभानुशरण सिंह (तराबगंज दक्षिण-पूर्व-गोंडा दक्षिण)
गगाप्रसाद (तराबगज दक्षिण पूर्व-गोडा दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
महाराज कुमार बालेन्दुशाह (टेहरी दक्षिण-प्रतापनगर)
शिवस्वरूप सिह (ठाकुरद्वारा)
शिवकुमार मिश्र (तिल्हर उत्तर)
भगवान सहाय (तिल्हर दक्षिण)
रघुराज सिंह (तराबगज पश्चिम)
लीलाधर अष्थाना (उन्नाव दक्षिण)
एस० एम० शाहिद फकीरी (उतरौला केन्द्रीय)
बलभद्र प्रसाद (उतरौला उत्तर)
श्यामलाल (उतरौला उत्तर, , सरक्षित परिगणित जाति)
उम्मेदसिह (उतरौला उत्तर पूर्व)
अमृतनाथ मिश्र (उतरौला दक्षिण)
राघवेन्द्रप्रतापसिह (उतरौला, दक्षिण-पश्चिम)
देवनर शास्त्री (पश्चिमी दून दक्षिण-पूर्वी दून)

उत्तर-प्रदेश विधान परिषद्

सभापति—चन्द्रभाल

बद्रीप्रसाद कक्कड़ (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
बालकराम वैश्य (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
बशीर अहमद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
कुंवर गुरुनारायण (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
केदारनाथ खेतान (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
खुशालसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
कृष्णचन्द जोशी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
ललिताप्रसाद सोनकार (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
कुवर महावीरसिह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
प्रतापचन्द्र आज़ाद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

पूर्णचन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रामनारायण पाण्डे (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रामनन्दन सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रामलगान सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रुकनुद्दीन खां (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
सत्यप्रेमी उर्फ हरि प्रसाद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीमती शांतिदेवी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीमती शान्तिदेवी अग्रवाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
राणा शिव अम्वरसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्यामसुन्दर लाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
विश्वनाथ (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
डा० व्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक उ० प्र० पश्चिम)
डा० ईश्वरीप्रसाद (स्नातक उ० प्र० पश्चिम)
डा० बेनीप्रसाद टंडन (स्नातक उ० प्र० पश्चिम)
शिवप्रसाद सिन्हा (स्नातक उ० प्र० पूर्व)
गोविन्द सहाय (स्नातक उ० प्र० पूर्व)
निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक उ० प्र० पूर्व)
डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव (अध्यापक, उ० प्र० पश्चिम)
कन्हैयालाल गुप्त (अध्यापक, उ० प्र० पश्चिम)
शान्तिस्वरूप अग्रवाल (अध्यापक, उ० प्र० पश्चिम)
शिवकुमार लाल श्रीवास्तव (अध्यापक, उ० प्र० पूर्व)
हृदयनारायण सिंह (अध्यापक, उ० प्र० पूर्व)
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी (अध्यापक, उ० प्र० पूर्व)
ज्योतिप्रसाद गुप्त (उ० प्र० स्थानीय संस्थायें उत्तर पश्चिम)
तेलूराम (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर पश्चिम)
दीपचन्द्र (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पश्चिम)
महमूद असलम खा (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पश्चिम)
इन्द्रसिंह नयाल (उ० प्र० स्था० स० उत्तर-पूर्व)
शिवसुमरन लाल जौहरी (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पूर्व)
बाबू अब्दुल मजीद (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पूर्व)
रामलखन (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पूर्व)
प्रेमचन्द शर्मा (उ० प्र० स्था० सं० पश्चिम)
बृजलाल वर्मन (उ० प्र० स्था० स० पश्चिम)
अब्दुल शकूर नजमी (उ० प्र० स्था० सं० पश्चिम)
जगदीशचन्द्र वर्मा (उ० प्र० स्था० सं० पश्चिम)
जमीलुर्रहमान किदवई (उ० प्र० स्था० सं० मध्य)
लालसुरेश सिंह (उ० प्र० स्था० सं० मध्य)
राम-किशोर रस्तोगी (उ० प्र० स्था० सं० मध्य)
बंशीधर शुक्ल (उ० प्र० स्था० सं० मध्य)
लल्लूराम द्विवेदी (उ० प्र० स्था० सं० दक्षिण)
प्रसिद्धनारायण अनद (उ० प्र० स्था० सं० दक्षिण)
पन्नालाल गुप्त (उ० प्र० स्था० सं० दक्षिण)
नरोत्तमदास टंडन (उ० प्र० स्था० सं० दक्षिण)
जगन्नाथ आचार्य (उ० प्र० स्था० सं० पूर्व)
परमात्मानन्द सिंह (उ० प्र० स्था० सं० पूर्व)
प्रभुनारायण सिंह (उ० प्र० स्था० सं० पूर्व)
श्रीमती महादेवी वर्मा (नामजद)
वीरभान भाटिया (नामजद)
उमानाथ बली (नामजद)
श्रीमती तारा अग्रवाल (नामजद)
सैयद मुहम्मद नसीर (नामजद)
सभापति उपाध्याय (नामज़द)

विजयानगरम के महाराजकुमार डाक्टर विजय (नामजद)
सरदार सन्तोषसिंह (नामजद)
हयातुल्लाह अन्सारी (नामजद)
हरगोविन्द मिश्र (नामजद)
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (नामजद)
राय बजरग बहादुर सिंह (नामजद)

पश्चिमी बंगाल

राज्यपाल — **एच० सी० मुकर्जी**

मंत्री

1. मुख्य मत्री तथा गृह, व्यापार,व्यवसाय तथा विकास	विधानचन्द्र राय
2. घरेलू तथा छोटे व्यवसाय	जादवेन्द्र नाथ पंज
3. जगल और मछली व्यवसाय	हेमचन्द्र नस्कर
4. सिंचाई तथा जलमार्ग	अजयकुमार मुकर्जी
5. आन्तरिक कर	श्यामाप्रसाद बर्मन
6. कार्य तथा इमारतें	खगेन्द्रनाथ दास गुप्ता
7. आदिवासी कल्याण	राधागोविन्दराय
8. स्थानीय स्वराज्य	ईश्वरदास जालान
9 शरणार्थी सहायता और पुनर्वास	श्रीमती रेणुकाराय
10. बाढ़, सहायता तथा पूर्ति	प्रफुल्लचन्द्र सेन
11. शिक्षा	पन्नालाल बोस
12. कृषि तथा सहयोग	रफीउद्दीन अहमद
13. श्रम	कालिपद मुखर्जी
14. न्याय-व्यवस्थापन, भूमि और लगान	सत्येन्द्र कुमार बसु

मिनिस्टर आफ़ स्टेट

1. चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	अमूल्यधन मुखोपाध्याय
2. जेल	जीव रतन धर

उपमंत्री

1. यातायात	एस० सी० राय सिन्हा
2. गृह विभाग की रक्षा शाखा	एस० सी० घोष मलिक
3. प्रकाशन तथा जन सम्बन्ध	गोपिका बिलास सेन
4. नगर निर्माण तथा सहायता	तरुणकान्ति घोष
5 व्यापार और व्यवसाय	सौरीन्द्रमोहन मिश्र
6. आदिवासी कल्याण	तैनजिंग वागडी
7. पुनर्वास	बिदेशचन्द्र सेन
8. अन्न	समरजीत बन्दोपाध्याय
9. पूर्ति	रजनिकान्त प्रामाणिक
10. कृषि	अब्दुस शकूर
11. पार्लियामेंटरी कार्य	देवेन्द्रचन्द्र दे
12. सहयोग	चित्तरंजन राय
13. स्त्री शिक्षा	श्रीमती पूरबी मुकर्जी
14. श्रम	शिवकुमार राय

वित्त (लाख रुपयो में)

बजट के आकडे	आय	व्यय	अतिरिक्त(+) या घाटा (–)
1950–51 (लेखा)	3,430	3,733	–303
1951–52 (लेखा)	3,859	3,731	+128
1952–53 (सशोधित)	3,830	4,213	–383
1953–54 (बजट)	3,816	4,327	–511

शिक्षा

बगाल सरकार ने 1952-53 मे शिक्षा पर 3,39,00,000 रुपये व्यय किए । 4 वर्ष पहले यह संख्या 2 करोड से भी कम थी । एक नए कानून द्वारा देहानी हलको **की स्थानीय संस्थाओं को भी** शिक्षा को अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि 2 वर्षों मे बंगाल के पाचवे भाग मे शिक्षा पूर्ण रूप मे अनिवार्य कर दी जाय। माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकताओ को दृष्टि मे रख कर एक पश्चिमी बगाल माध्यमिक शिक्षा कानून पास किया गया । इसी तरह भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की सिफारिशो के अनुसार कलकत्ता विश्वविद्यालय कानून मे भी आवश्यक सुधार किए गए ।

गत वर्ष बगाल मे 1848 जूनियर बेसिक स्कूल थे । इनके अतिरिक्त 77 नए स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई । इन मे से प्रत्येक स्कूल पर 32,000 रुपया व्यय आयेगा । प्रारम्भिक स्कूलो के अध्यापकों को शिक्षा देने के लिए राज्य मे 31 ट्रेनिंग स्कूल पहले ही विद्यमान थे । अब 12 नए बेसिक ट्रेनिग स्कूल खोले गए है । राज्य की सरकार 708 शिक्षा केन्द्र चला रही है । इन मे से 300 में सामाजिक शिक्षा देने का भी प्रबन्ध है । इनके अतिरिक्त 200 **केन्द्र सहायता प्राप्त स्वयसेवक सगठनो द्वारा चलाए जा रहे हैं** ।

मैट्रिक पास विद्यार्थियो को टेक्निकल शिक्षा देने के लिए 7 पोलिटैकनीक सस्थाएं जारी है, जिनमे 15,000 से ऊपर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे है । शिवपुर मे बगाल इजीनियरिंग कालेज का सगठन किया जा रहा है। जादवपुर के इजीनियरिग तथा टैक्नोलोजी कालेज का विस्तार किया जा रहा है। सस्कृत कालेज मे एक स्नातकोत्तर अनुसन्धान विभाग भी खोला गया है ।

गत वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि बढा कर 16 लाख रु० कर दी गई । कलकत्ता प्रेजीडेसी कालेज मे विज्ञान के विद्यार्थियो की सुविधा और विस्तार के लिये 2,85,000 रुपये स्वीकार किए गए । दार्जिलिंग गवर्नमेंट कालेज के लिए 6,75,000 रुपये स्वीकार किए गए ।

खाद्यान्न तथा कृषि

गहरी कृषि के लिए सिंचाई के 447 छोटे कार्य जारी किये गए, जिनसे 1,46,256 एकड़ भूमि को लाभ पहुचा। इनके अतिरिक्त 290 छोटे कार्यों की पूर्ति का अधिकतम प्रयत्न किया जा रहा है । 277 तालाबों का पुनर्निर्माण किया गया और 325 में सुधार किया गया ।

यह लक्ष्य बनाया गया था कि 5 वर्षों के बाद बंगाल में जूट उत्पत्ति की वृद्धि 10 लाख गांठों तक और बढ़ जायेगी। परन्तु यह लक्ष्य 3 वर्षों में ही प्राप्त कर लिया गया और 1952-53 मे यहा 24,13,000 जूट की गांठें प्राप्त हुई। जनवरी 1953 मे चीनी का राशन प्रति सप्ताह प्रति व्यक्ति एक सेर से बढ़ा कर एक सेर पाच छटाक कर दिया गया। चावल प्राप्ति के उपायों मे भी सुधार किया गया और एक ज़िले से दूसरे ज़िले मे अन्न ले जाने पर से रुकावटे उठा दी गईं।

व्यवसाय

गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की सरकार ने एक विशेष विभाग निर्मित किया। इस विभाग की सिफारिशो के अनुसार सरकार गृह उद्योगों द्वारा बनाये गये सामान को बड़े उद्योगों द्वारा बनाये गये सामान के मुकाबले मे 15 प्रतिशत तक तरजीह देती है। करघों का सामान, खादी, चटाई, गुड़, हाथ का बना कागज़, आदि व्यवसायों के विकास की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इन व्यवसायो के लिए शिक्षा के केन्द्र खोले गये है, तथा प्रदर्शन आदि का भरसक प्रबन्ध किया जाता है। रेशम व्यवसाय को बढ़ाने के लिए शहतूत के वृक्ष ज्यादा सख्या मे बोये जा रहे है। ताड-गुड को सुरक्षित रूप मे रखने के सम्बन्ध मे नए तरीके निकाले गये है। कच्ची जूट तथा उसके सामान की कीमतों मे स्थिरता लाने के लिए सरकार ने फाटका बन्द कर दिया है। हिमालय की ऊची चोटियों पर उपयोगी दवाइयां उत्पन्न करने की भी एक योजना बनाई गई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952-53 मे 133 नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, जिनमे 1806 बीमारों की चिकित्सा का प्रबन्ध है। 120 बिस्तरों वाले 12 केन्द्र लगभग बन कर तैयार है तथा 452 बिस्तरों वाले 39 केन्द्रों का निर्माण हो रहा है।

कलकत्ता के प्रेज़िडेंसी अस्पताल तथा जिला अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है। 4 अन्य केन्द्रों में नये अस्पताल बनाने की योजना स्वीकार हो चुकी है। टॉलीगज मे 200 बिस्तरो वाला बगुर अस्पताल बन कर तैयार है कचनपारा के तपेदिक अस्पताल मे बिस्तरों की सख्या 600 से बढ़ा कर 1,000 कर दी गई है और दिग्री के बगुर स्वास्थ्य केन्द्र मे बिस्तरों की सख्या 130 से बढ़ा कर 200 कर दी गई है। गत वर्ष सरकारी अस्पतालों में तपेदिक के बीमारो की नि शुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया।

4 जिलों में मलेरिया की रोकथाम की स्कीमें जारी की गई। 14 जिलो मे मलेरिया निरोध के कार्यक्रम के लिये 16 यूनिट स्थापित किये गये है। इन पर प्रति वर्ष 26,00,000 रुपये व्यय आएगा।

मिदनापुर, हावडा, कृष्णगढ, बहरामपुर और बर्दवान मे राज्य की सरकार की ओर से कोढ के चिकित्सालय चलाये जा रहे है, जिन मे नवीनतम साधनो से चिकित्सा की जाती है। गत वर्ष 12 लाख व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 4 लाख से अधिक व्यक्तियों को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया।

1952-53 मे 37 नये जच्चा-घर खोले गये और लैंगिक बीमारियो की रोकथाम के लिये कलकत्ता में 14 तथा अन्य जिलो में 18 क्लिनिक्स खोले गये।

पश्चिमी बंगाल विधान सभा

अध्यक्ष : शैलकुमार मुखर्जी

सत्येन्द्रकुमार वसु (अलीपुर)
पिजूश कान्ति मुखर्जी (अलीपुर दुआर्स)
देवेन्द्र ब्रह्म मोहनलाल (अलीपुर दुआर्स, सरक्षित परिगणित जन-जाति)
तारापद प्रामाणिक (अमता केन्द्रीय)
अलामोहन दास (अमता उत्तर)
अरविन्द राय (अमता दक्षिण)
राधाकृष्ण पाल (आराम बाग)
मदन मोहन साहा (आराम बाग, सरक्षित परिगणित जाति)
सतीन्द्र नाथ वसु (आसनसोल)
आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (औसग्राम)
कनाईलाल दास (औसग्राम, सरक्षित परिगणित जाति)
शम्भू चरन मुखोपाध्याय (बगनान)
वृन्दाबन चट्टोपाध्याय (बालागोर)
रतनमणि चट्टोपाध्याय (बालागोरवाल्ली)
सरोजरजन चट्टोपाध्याय (बलूरघाट)
लक्षणचन्द्र हासदा (बलूरघाट, सरक्षित परिगणित जन जाति)
राखहरि चैटर्जी (बाकुरा)
ईश्वरदास जालन (बडा बाजार)
ज्योति वसु (बड़ानगर)
अमूल्यधन मुखोपाध्याय (बारासाल)
प्रफुल्लचन्द्र राय (बरजोड़ा)
फणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय (बैरकपुर)
अबदुलशकूर (बडुईपुर)
ललितकुमार सिन्ह (बडुईपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
प्रफुल्ल बैनर्जी (बसिरहाट)
बिरेन राय (बिहाला)
क्षितिशचन्द्र घोष (बैलडागा)
गणेश घोष (बैलगाचिया)
सुहृद कुमार मल्लिक चौधुरी (बेनीवाट)
जोगेशचन्द्र गुप्त (बेनियापुकुर-बालीगंज)
पुलिन बिहारी खटिक (बेनियापुकुर बालीगंज, सरक्षित परिगणित जाति)
विजयकुमार घोष (बेरहामपुर)
व्योमकेश मजूमदार (भद्रेश्वर)
रामेश्वर पण्डा (भगवानपुर)
गगाधर नसकर (भगोर)
हेमचन्द्र नसकर (भगोर, सरक्षित परिगणित जाति)
विजयेन्दु नारायण राय (भरतपुर)
दयाराम बेरी (भातपाडा)
श्रीमती मीरादत्त गुप्त (भोवानीपुर)
नृपेन्द्रगोपाल मित्र (बीनपुर)
मगलचन्द्र शरन (बीनपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
प्रभासचन्द्र राय (बिष्णुपुर)
वसन्त कुमार माल (बिष्णुपुर संरक्षित परिगणित जाति)
डा० मैत्रेयी वसु (बीजपुर)
हन्सेश्वर राय (बोलपुर)
भूषण हासदा (बोलपुर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
जीवन रतन घर (बीन गाव)
बिधानचन्द्र राय (बऊ बाजार)
बकिम मुखर्जी (बज-बज)
विनयकृष्ण चौधुरी (बर्दवान)
सुधीरचन्द्र राय चौधुरी (बडतोला)
सत्येन्द्रचन्द्र घोष मलिक (बर्दवान-खड़ग्राम)
सुधीर मण्डल (बर्दवान–खडग्राम, सरक्षित परिगणित जाति)
यज्ञेश्वर राय (केन्द्रीय द्वारस)
मगलदास भगत (केन्द्रीय द्वारस, संरक्षित परिगणित जाति)

समरजीत बन्दोपाध्याय (छपरा)
प्रबोधचन्द्र दत्त (चाटना)
कमलाकान्त हेम्ब्राम (चाटना, रक्षित परिगणित जन जाति)
ज्योतिषचन्द्र घोष (चिन्सुरा)
राधानाथ दास (चिन्सुरा, सरक्षित परिगणित जाति)
आनन्दीलाल पोद्दार (कोलूतोला)
सुधीरचन्द्र दास (कोन्टाई उत्तर)
नटेन्द्रनाथ दास (कोन्टाई दक्षिण)
मजीरुद्दीन अहमद (कूच-बिहार)
यतीन्द्रनाथ सरकार (कूच-बिहार, सरक्षित परिगणित जाति)
विश्वनाथ राय (कोसीपुर)
ज्ञानेन्द्रकुमार चौधुरी (डन्टन)
दल बहादुर सिंह गनतराज (दार्जिलिंग)
भूगेन्द्र भट्टाचार्य (दासपुर)
रफीउद्दीन अहमद (देगंगा)
धीरेन्द्र नारायण मुखर्जी (धनियाखाली)
लीमो हासदा (धनियाखाली, संरिक्षत परिगणित जन-जाति)
रवीन्द्रनाथ सिकदर (धूपगुरी)
जगदीश हालदार (डायमन्ड-हार्बर)
सतीशचन्द्र रायसी (दिनहाटा)
उमेशचन्द्र मण्डल (दिनहाटा, संरक्षित परिगणित जाति)
तारापद डे (डोमजूर)
कनाईलाल दास (डमडम)
देवेन्द्रचन्द्र डे (एन्टाली)
ज्योतिषचन्द्र राय (फालटा)
गयासुद्दीन (फड़ाक्का)
नरेन्द्रनाथ सेन (फोर्ट)
जियाउल हक (गईघाटा)
जटवेन्द्रनाथ पंजा (गालसी)
मोहितोश साहा (गालसी, संरक्षित परि-गणित जाति)
धीरेन्द्रनाथ चटर्जी (गंगाजलघाटी)
सतीन्द्रनाथ बसु (गंगारामपुर)
सरोज राय (गरवेटा)
एस० एम० अब्दुल्ल (गार्डेन-रीच)
धरनीधर सरकार (गजोल)
जातीशचन्द्र घोष (घाटल)
अमूल्यचरण दत (घाटल, संरक्षित परि-गणित जाति)
नरेन्द्रनाथ घोष (गोघाट)
धनन्जय कर (गोपी बल्लभपुर)
जगतपति हसदा (गोपी बल्लभपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
तरुणकान्ति घोष (हावडा)
ए० हमीद (हरिहर पाड़ा)
रामहरि राय (हरिचन्द्र पुर)
हेमन्त कुमार घोषाल (हरोआ-सन्देशखाली)
ज्योतिषचन्द्र राय (हरोआ-सन्देशखाली संरक्षित परिगणित जाति)
विजेशचन्द्र सेन (हसनाबाद)
राजकृष्ण मण्डल (हसनाबाद, संरक्षित परिगणित जाति)
शैलकुमार मुखोपाध्याय (हावड़ा-पूर्व)
बिरेन बनर्जी (हावडा-उत्तर)
बेणीचरण दत्त (हावडा-दक्षिण)
बंकिमचन्द्र कर (हावड़ा-पश्चिम)
बनमाली दास (इताहर)
अमृतलाल हाजरा (जगत बल्लभपुर)
ए० एम० ए० जामान (जलांगी)
खगेन्द्रनाथ दास गुप्त (जलपाईगुडी)
सरोजेन्द्र देव रायकूट (जलपाईगुड़ी, संरक्षित परिगणित जाति)
महेन्द्रनाथ महतो (झरग्राम)
मदनमोहन खान (झरग्राम, संरक्षित परिगणित जाति)
रामलगन सिंह (जोराबागान)
अमरेन्द्रनाथ बसु (जोरासांको)

शिवकुमार राय (जोरबंगलो)
सुबोध बैनर्जी (जयनगर)
दीनतारण मोनी (जयनगर, संरक्षित परिगणित जाति)
अबुल बरकत अताउल गनी (कालिया चाक उत्तर)
सौरीन्द्रमोहन मिश्र (कालिया चाक दक्षिण)
एस० एम० फजरुल रहमान (कालीगंज)
श्रीमती मनी कुन्तला सेन (कालीघाट)
नरवहादुर गरंग (कालिम्पोग)
राश बिहारी सेन (कालना)
वैद्यनाथ सन्ताल (कालना, संरक्षित परिगणित जाति)
गोइलबदन त्रिवेदी (कान्डी)
हरिपद चैटर्जी (करीमपुर)
सुबोध चौधुरी (कटवा)
गंगापद कुअर (केशपुर)
नगन्द्र दोलोई (केशपुर-संरक्षित परिगणित
तारापद गगोपाध्याय (केटूग्राम)
महम्मद हुसैन (खाडाघोश)
महमूद मुमताज़ (खड़गपुर)
तफज़ल हुसैन (खारवा)
अमूल्यरतन घोष (खटरा)
आशुतोश मल्लिक (खटरा, संरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती आभा मैती (खेजरी)
कौस्तुव क्रान्ति करन (खेजरी, संरक्षित परिगणित जाति)
खगेन्द्रनाथ बन्दोपाध्याय (खोयरसोल)
विजयलाल चट्टोपाध्याय (कृष्णनगर)
नलिनीकान्त हलदार (कुलपी)
प्राणकृष्ण कामार (कुलपी, संरक्षित परिगणित जाति)
जयनारायण शर्मा (कुलटी)
वैद्यनाथ मण्डल (कुलटी, संरक्षित परिगणित जाति)
नेपालचन्द्र राय (कुमारतली)
जार्ज मैहबर्ट (कुरसियोग-सीलीगुड़ी)
तेनजिंक वाग्डी (कुरसियोग-सीलीगुड़ी संरक्षित परिगणित जनजाति)
काजिमअली मिर्जा (लाल गोला)
आबुल हाशिम (मगराहाट)
अर्धेन्दुशेखर नसकर (मगराहाट सरक्षित)
सुधीरचन्द्र भन्डारी (महेलटोला)
कुमारदेव प्रसाद गर्ग (महीसदल)
सुरेन्द्रनाथ राय (मेनागरी, सरक्षित परिगणित जाति)
निकुज बिहारी गुप्त (मालदा)
रायपद दास (मालदा, सरक्षित परिगणित जाति)
भक्त चन्द्र राय (मगलकोट)
रनेन्द्र नाथ सेन (मानिक ताला)
पशुपति झा (मानिक चाक)
अन्नदा प्रसाद मन्डल (मंटेश्वर)
शारदा प्रसाद प्रामानिक (माधाभग)
भूषणचन्द्र दास (मथुरापुर)
वृन्दाबन गायन (मथुरापुर, संरक्षित परिगणित . जाति)
सत्यन्द्रप्रसन्न चैटजी (मेकलीगंज)
बसन्तकुमार पानिग्राही (मोहनपुर)
कानाईलाल भौमिक (मोयना)
शकरप्रसाद मित्र (मुचीपाडा)
योगेन्द्रनारायण दास (मूराराय)
दुर्गापद सिन्ह (मुर्शिदाबाद)
निरंजन मोदक (नवद्वीप)
सुरेशचन्द्र पाल (नई हटी)
जगन्नाथ मजूमदार (नकाली पाड़ा)
याकूब हुसैन (नलहाटी)
सुबोधचन्द्र मैती (नन्दीग्राम-उत्तर)
प्रबीरचन्द्र जाना (नन्दीग्राम-दक्षिण)
बसन्तलाल मुरारका (ननूर, संरक्षित परिगणित जाति)
कृष्णचन्द्र सतपाठी (नारायणगढ़)

सुरेन्द्रनाथ प्रामानिक (नारायण गढ़, संरक्षित परिगणित जाति)
मुहम्मद इसराईल (नोवाडा)
रजनीकान्त प्रामानिक (पांसकुरा-उत्तर)
श्यामा भट्टाचार्य (पांसकुरा-दक्षिण)
जनार्दन साहु (पटाशपूर)
पुलिन बिहारी मैती (पिंगला)
बिमलानन्द तर्कतीर्थ (पुरुबस्थाली)
गुलाम हमीदुर्रहमान (रायगंज)
श्यामाप्रसाद बर्मन (रायगंज, संरक्षित परिगणित जाति)
दाशरथी ताह (रैना)
मृत्युंजय प्रामानिक (रैना, संरक्षित परिगणित जाति)
यतीन्द्रनाथ बसु (रायपुर)
जदुनाथ मुर्मू (रायपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
बलाईलाल दास महापात्र (रामनगर)
श्रीकुमार बैनर्जी (रामपुरहाट)
पंचानन लेट (रामपुरहाट, संरक्षित परिगणित जाति)
केशवचन्द्र मित्र (रानाघाट)
विजयकृष्ण सरकार (रानाघाट, संरक्षित परिगणित जाति)
पशुपतिनाथ मालिया (रानीगंज)
छत्रजधारी मंडल (रानीगंज, संरक्षित परिगणित जाति)
जैनुल अबदीन काजी (रानीगनगर)
श्रीमती रेणुका राय (रतुआ)
गोपाल चन्द्र दास अधिकारी (सबोग)
श्यामापद भट्टाचार्य (सागरदीघी)
कुबेरचन्द हालदार (सांगरदीघी, संरक्षित परिगणित जाति)
हरिपद बागुली (सागोर)
विजयगोपाल गोस्वामी (सालबोनी)
कानाईलाल भट्टाचार्य (मकरैल)
कृपासिन्धु शा (मंकरैल, संरक्षित परिगणित जाति)
शशिभूषण खान (शान्तिपुर)
पान्नालाल बोस (सीयालदाह)
जितेन्द्रनाथ लाहिड़ी (श्रीरामपुर)
हेमन्तकुमार बसु (श्यामपुकुर)
शसबिन्दु बेरा (श्यामपुर)
अजीतकुमार बसु (सिगूर)
सुरेन्द्र नाथ साहा (सिंगूर संरक्षित परिगणित जाति)
भवतारन चक्रवर्त्ती (सोनामुखी)
शिशुराम मन्डल (सोनामुखी, सरक्षित परिगणित जाति)
गोपिकाविलास सेन गुप्त (सूरी)
निशापति माझी (सूरी, संरक्षित परिगणित जाति)
कुमारचन्द्र जाना (सुताहाट)
लुन्फुल हक (सूती)
मुहम्मद इसाक (स्वरूप नगर)
श्रीमती पूरबी मुखर्जी (तालडगरा)
शमसुल हक (तालटोला)
अजयकुमार मुखर्जी (तामलक)
पारवती हाजरा (तारकेश्वर)
रघुनन्दन विश्वाम (तेहट्टा)
कृष्णकुमार शुक्ल (टीटागढ़)
ज्योतिष जोआरदार (टालीगज)
प्रियरजन सेन (टालीगज उत्तर)
अम्बिका चक्रवर्त्ती (टालीगज दक्षिण)
विभूतिभूषण घोष (उलूबेरिया)
विजय भूषण मन्डल (उलूबेरिया, संरक्षित परिगणित जाति)
मनोरजन हाजरा (उत्तर पाडा)
नारायण चन्द्र राय (विद्यासागर)
राधा गोविन्द राय (विष्णुपुर)
किरणचन्द्र दीगर (विष्णुपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
काली मुखर्जी (वटगूंगे)
शसधर कर (पश्चिमी द्वारस)
ऐन्टनी तोप्नो मुडा (पश्चिमी द्वारा सरक्षित परिगणित जाति)
आर० ई० प्लेटल (नामजद)
रैगीनाल्ड आर्थर मैमी (नामजद)

पश्चिमी बंगाल विधान परिषद्

सभापति—सुनीतिकुमार चटर्जी

अब्दुल हलीम (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
नरेन्द्रनाथ बागची (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
बंकिमचन्द्र बैनर्जी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
सुबोधकुमार वसु (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
मुनीन्द्रमोहन चक्रवर्ती (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
के० पी० चट्टोपाध्याय (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
मोहम्मद सैयद मियां (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
प्रतापचन्द्र गुह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
मोहितोष राय चौधरी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
मिर्जा अब्दुर्रशीद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
कमलाचरण मुखर्जी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
रामकुमार भुवाल्का (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
कामदाकिंकर मुखर्जी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
विजयसिंह नाहर (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
लखन प्रधान (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
सुरेन्द्रकुमार राय (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
देवेन्द्रसेन (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
निर्मलचन्द्र भट्टाचार्य (स्नातक, कलकत्ता)
सुनीतिकुमार चटर्जी (स्नातक, पश्चिम बंगाल-दक्षिण)
चित्तरंजन राय (स्नातक-पश्चिम बंगाल-पश्चिम)
चारुचन्द्र सान्याल (स्नातक-पश्चिमी बंगाल-उत्तर)
कामिनी घोष (अध्यापक कलकत्ता)
विजनबिहारी भट्टाचार्यजी (अध्यापक बर्दवान डिवीजन)
सत्यप्रिय राय (अध्यापक प्रेजीडेंसी डिवीज़न-दक्षिण)
श्रीमती अनिला देवी (अध्यापक प्रेजीडेंसी डिवीजन-उत्तर)
आर० एस० प्रसाद (दार्जिलिंग)
सचीन्द्रनाथ मित्र (पश्चिम बंगाल-उत्तर)
तारकदास बन्दोपाध्याय (नादिया-मुर्शीदाबाद)
काली नारायण सिंह (नादिया, मुर्शीदाबाद)
कालीपद मुखर्जी (कलकत्ता-२४ परगना)
शरतचन्द्र साव् (कलकत्ता-२४ परगना)
सुधीरेंद्रनाथ मजूमदार (कलकत्ता-२४ परगना)
हृदयभूषण चक्रवर्ती (कलकत्ता-२४ परगना)
देवप्रसाद चटर्जी (कलकत्ता-२४ परगना)
प्रफुल्लकुमार गुह (कलकत्ता-२४ परगना)
प्रफुल्लचन्द्र सेन (हुगली-हावडा)
रवीन्द्रलाल सिंह (हुगली-हावडा)
सुनीतिकुमार बनर्जी (हुगली-हावडा)
चारूचन्द्र महन्ती (बर्दवान डिवीजन-उत्तर)
प्रणतेश्वर सरकार (बर्दवान डिवीजन-उत्तर)
बिमान बिहारी लाल सिंह (बर्दवान-डिवीजन-उत्तर)
अन्नदाप्रसाद चौधरी (बर्दवान डिवीजन-उत्तर)
शंकरदास बनर्जी (नामजद)
ताराशंकर बनर्जी (नामज़द)
गुरुगोविन्द बसु (नामज़द)
श्रीमती शान्ति दास (नामजद)
नरसिंह मल्ल उगल सैन्द देव (नामज़द)
श्रीमती लावण्यप्रभा दत्त (नामज़द)
मुशर्रफ हुसैन (नामज़द)
शेख मुहम्मद जान (नामज़द)
पन्नालाल सारोगी (नामज़द)

छब्बीसवां अध्याय

'ख' भाग के राज्य

हैदराबाद

राजप्रमुख	हैदराबाद के निजाम
मंत्री	
1. मुख्य मंत्री तथा साधारण व्यवस्था, सूचना और सामाजिक सेवायें।	वी० रामकृष्ण राव
2. गृह, पुनर्वास और कानून	डी० जी० बिन्दु
3. आन्तरिक कर, लगान, जगल	के० वी० रंगारेड्डी
4. वित्त, गणना, कर, व्यवसाय और व्यापार	विनायकराव विद्यालकार
5. सार्वजनिक कार्य और श्रम	जी० एस० मलकोटे
6. चिकित्सा तथा देहात पुनर्निर्माण	मेहदीनवाज जंग
7. शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य और व्यवस्थापन	गोपाल राव एकबोटे
8. कृषि, पूर्त्ति, योजना और विकास	एम० चेन्ना रेड्डी

हैदराबाद राज्य भारतीय यूनियन मे दिसम्बर 1949 मे सम्मिलित हुआ। राज्य में 16 जिले है 138 ताल्लुके है और कुल मिलाकर 22,000 गाव है ।

वित्त (लाख रुपयों मे)

बजट के आकडे	आय	व्यय	बचत (+) या घाटा (—)
1950-51 (लेखा)	2,618	2,755	—137
1951-52 (लेखा)	2,987	2,819	+168
1952-53 (मशोधित)	2,791	2,682	+109
1953-54 (बजट)	2 802	2,822	—20

शिक्षा

1953 में 'हैदराबाद अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा कानून' पास हुआ। उसके अनुमार 170 प्रारम्भिक और 70 माध्यमिक स्कूलो मे अतिरिक्त श्रेणिया जारी की गई। सामूहिक विकास योजना के क्षेत्रो में जो प्रारम्भिक स्कूल है तथा जो स्कूल बेसिक शिक्षा के ट्रेनिंग स्कूलों के निकट है, उन्हें बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। सरकार ने यह निश्चय किया है कि राज्य में टेक्निकल शिक्षा की उन्नति की जाय। इस कार्य के लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी

भी नियुक्त की गई थी, जिसकी कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। इसी उद्देश्य से राज्य के टेक्निकल कालेज को पुनस्संगठित किया गया है, जहां मैट्रिक पास विद्यार्थियों को तीन वर्षों के लिये मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है। चित्रकला, वास्तु-कला, व्यापारिक कला तथा निर्माण आदि की शिक्षा तथा डिप्लोमा देने के लिये एक स्कूल आफ़ आर्टस पुनस्संगठित किया गया है। शारीरिक शिक्षा के लिये एक एकेडेमी की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन जनवरी, 1953 में प्रधान मंत्री ने किया था। शिक्षा संस्थाओं की सहायता के मद में 2 लाख रुपयों की वृद्धि की गई।

खाद्यान्न तथा कृषि

पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार हैदराबाद में कृषि के विकास पर साढ़े तीन करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। खाद्यान्न तथा रूई के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। गत वर्ष सिंचाई के कितने ही नये कार्य किये गये। 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाले 20 माध्यमिक सिंचाई कार्यों का निर्माण पूरा कर लिया गया। 10,350 एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाले 3 माध्यमिक और 4 छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण जारी है। गतवर्ष हैदराबाद से 17,500 टन ज्वार बम्बई, मद्रास और मैसूर को भेजी गई। क्रमश राशन के क्षेत्रों को घटाया गया। आयोजना कमीशन की सिफ़ारिशों पर 1952-53 में हैदराबाद में एक टैनेन्सी कानून पास हुआ। किसानों के अधिकारों की रक्षा तथा भूमि के कार्यों पर देखभाल करने के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई। राज्य के 22,000 गांवों में से 21,798 गांवों में भूमि स्वामित्व के कागजों की देखभाल की गई और राज्य भर में 6 लाख से ऊपर किसानों को टैनेन्सी सर्टीफिकेट दिये गये।

व्यवसाय

1952-53 में हैदराबाद में सरकार ने उत्पादन वृद्धि की इच्छा से कुछ आधारभूत व्यवसायों को प्रारम्भ किया। आजमजाही तथा उस्मानशाही कपड़े की मिलों का तथा शाहाबाद की सीमैण्ट फैक्टरी का उत्पादन 50 प्रतिशत बढ़ाया गया। बोधन की चीनी की फैक्टरी का उत्पादन 200 प्रतिशत बढ़ा, कोयले का उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ा और कागज का 100 प्रतिशत। गृह व्यवसायों को सहायता देने के लिये राज्य में कुछ शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से एक हैंडीक्राफ्ट बोर्ड भी बनाया जा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष 45 नये चिकित्सालय खोले गये और हैदराबाद के तपेदिक अस्पताल में 45 नये बिस्तरों की वृद्धि की गई। उस्मानिया मैडिकल कालेज के अतिरिक्त प्रिन्सेस नीलोफर अस्पताल को भी राज्य की सरकार ने इस उद्देश्य से अपने हाथ में ले लिया है कि उसका विकास एक प्रथम श्रेणी के जच्चा अस्पताल के रूप में किया जा सके। मोमिनाबाद में एक तपेदिक का स्वास्थ्य केन्द्र भी खोला गया। प्लेग, कोढ़, मलेरिया और हैजा आदि की रोक थाम के लिये बहुत से प्रयत्न किये गये। बी० सी० जी० के टीके भी बहुत बड़ी संख्या में लगाये गये।

हैदराबाद शहर में 24 शिशुकल्याण केन्द्र बनाये गये और राज्य के जिलो में 21। डब्ल्यू० एच० ओ० की सहायता से राज्य मे नर्सों और दाइयों को ट्रेड करने का प्रयत्न किया जा रहा है और गावों मे स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे है।

हैदराबाद विधानसभा

अध्यक्ष — काशीनाथ राव वैद्य

दाजीशकर राव (आदिलाबाद)
अन्नाराव बासप्पा (अफजलपुर)
निवर्थि रेड्डी नामदेव रेड्डी (अहमदपुर)
पगा पुल्ला रेड्डी (अलमपुर-गडवाल)
नागन्ना (अलमपुर-गडवाल, सरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती अरुटला कमलादेवी (आलेर)
वीरेन्द्र पाटील (आल्लन्द)
भगवन्तराव गम्भीरराव गाढ़े (अवंड)
शरन गौड इनामदार (अन्दोल-जेवर्गी)
वैन्कट राजेश्वर जोशी (अन्दोल)
लच्छमन कुमार (अन्दोल, सरक्षित परिगणित जाति)
जी० राजाराम (अरमूर)
रुखमाजी धोंडिबा (आष्टी)
लक्ष्मण बापूजी कोंडा (आसिफाबाद)
काशीराम (आसिफाबाद, सरक्षित परिगणित जाति)
श्रीपादराव लक्ष्मण राव नेत्रासेकर (औरगाबाद)
देवसिंह वेन्कटसिंह चौहान (अवसा)
अनन्त रेड्डी (बालकोंडा)
श्रीमती लक्ष्मीबाई (बसवाडा)
भगवानराव गोपालराव बोरलकर (बसमत)
शामराव भिकाजी जाथ (बसमत, सरक्षित परिगणित जाति)
काशीनाथराव वैद्य (बेगमबाजार)
मुरलीधर राव श्रीनिवास राव कामटीकर (भालकी)
श्रीपतराव कदम (भीर)
दिगम्बरराव 'बिन्दु (भोकर)
भाऊराव दगडूराव (भोकरदन)
धोंडीराज काम्बले (भोकरदन, सरक्षित परिगणित जाति)
गोका रामलिंगम् (भोन्गीर)
शफीउद्दीन (बिदार)
नारायणराव नरसिहराव (बिलोली)
एस० एल० शास्त्री (बोधन)
गोपाल राव एक्बोटे (चांदघाट)
शंकरप्पा (चिचोली)
कान्चिनपल्ली वैन्कट रामा राव (चिन्नाकोन्डूर)
रुद्रप्पा (चितापुर)
जयवन्तराव ज्ञानेश्वर (देगलूर)
गणपतराव माणिकराव (देगलूर, संरक्षित परिगणित जाति)
करिबासप्पा गुरुबासप्पा (देवदुर्ग)
के० अनन्तराम राव (देवरकोंडा)
श्रीनिवास राव (डिचपल्ली)
जव्वादी दामोदर राव (एलगन्डाल)
पेन्डम वासुदेव (गजवेल)
रगराव देशमुख (गगाखेड)
के० आर० हीरामठ (गगावती)
रामराव (गेवराई)
मुहम्मदअली (गुलबर्गा)
माधवराव लालजी पाटील (हदगांव)
एस० मबाटला रामनाथन (हुनमकोंडा)
मिर्जा शुकूर बेग (हुसनपर्टी)
शामराव नाइक (हिंगोली)
माधवराव निरलीकर (हिंगोली, संरक्षित परिगणित जाति)
किशनराव बापुराव देशपांडे (हुलसर)

श्रीनिवासराव एखलीकर (हुमनाबाद)
शंकर देव (हुमनाबाद, संरक्षित परिगणित जाति)
पी० नारायणराव (हुजूराबाद)
जे० वेंकटशम (हुजूराबाद, सरक्षित परिगणित जाति)
मखदूम मोइनुद्दीन (हुजूरनगर)
थालमल्ला नरसिमलू (हुजूरनगर, संरक्षित परिगणित जाति)
सैयद हसन (हैदराबाद शहर)
पापी रेड्डी (इब्राहीमपटन)
एम० बी० गौतम (इब्राहीमपटन, संरक्षित परिगणित जाति)
विट्ठलराव देशपाण्डे (इप्पागुडा)
बद्दम मल्ला रेड्डी (जगतियाल)
बुट्टी राजाराम (जगतियाल, सरक्षित परिगणित जाति)
मुहम्मदअली मुसावी (जालना)
सय्यद अख्तर हुसैन (जनगाव)
भुजगराव नागोराव (जितूर)
रामलिगास्वामी (कैज)
अच्युतराव योगीराज (कल्लम)
एम० नरसिग राव (कलवाकुर्ती)
के० आर० वीरास्वामी (कलवाकुर्ती, सरक्षित परिगणित जाति)
जी० विट्ठल रेड्डी (कामारेड्डी)
वि० रामराव (कामारेड्डी, सरक्षित परिगणित जाति)
चन्द्रशेखर (कमलापुर)
गोविन्दराव नरसिह राव (कन्धार)
माधवराव सवाइ सीताराम सवाइ (कन्धार, सरक्षित परिगणित जाति)
रामगोपाल रामकृष्ण (कन्नड़)
सी० एच० वेंन्कटराम राव (करीमनगर)
नरेन्द्र (करवान)
बी० कृष्णय्या (खम्मम)
आर० बी० गुरमूर्त्ति (खम्मम, संरक्षित परिगणित जाति)
श्रीहरि (किनवत)
अनन्त रेड्डी (कोडागल)
वीरास्वामी (कोडागल, संरक्षित परिगणित जाति)
अनन्त रामचन्द्र रेड्डी (कोल्लापुर)
श्रीमती महादेवम्मा बसवानगौडा (कोप्पल)
एम० कोंडल रेड्डी (कुनाराम)
अन्दानप्पा (कुश्टगी)
विनायकराव कोरटकर (लातूर)
बसनगौडा (लिगासगूर)
विश्वनाथ राव (लक्षटीपेठ)
राजमल्लू (लक्षटीपेठ, सरक्षित परिगणित जाति)
कोडाबालू वेकय्या (मदिरा)
कनककान्ति श्रीनिवासराव (महूबाबाद)
बी० एम० चन्दरराव (महूबाबाद, सरक्षित परिगणित जाति)
पी० हनुमन्त राव (महबूबनगर)
श्रीमती शान्ताबाई (मखटाल-आत्माकुर)
बासप्पा (मखटाल-आत्माकुर, सरक्षित परिगणित जाति)
अब्दुल रहमान (मलकपेट)
लिम्बाजी मुक्ताजी (मजलेगाव)
जी० श्रीरामुलु (मन्थानी)
पाम्पन गौडा शकप्पा (मानवी)
वेकटेश्वरराव (मेदक)
वरकण्टम गोपाल रेड्डी (मेडचल)
गागुला भूमय्या (मेटपल्ली)
वामनराव रामराव (मोमिनाबाद)
द्वारका प्रसाद चौधरी (मोमिनाबाद, सरक्षित परिगणित जाति)
गोपाल शास्त्री देव (मुधोल)
हनुमन्त राव (मुलुग)
जी० एस० मलकोटे (मुशीराबाद)
ब्रह्म रेड्डी (नगारकुर्नुल)

डी० रामास्वामी (नगारकुर्नुल, संरक्षित परिगणित जाति)
कट्टाराम रेड्डी (नलगोंडा)
लक्ष्मय्या (नलगोडा, संरक्षित परिगणित जाति)
भगवानराव गांजवे (नान्देड)
आप्पाराव (नारायणखेड)
जे० रामा रेड्डी (नरसापुर)
शेषराव माधवराव (नीलवांगा)
गोपी रेड्डी गगा रेड्डी (निर्मल)
गगाराम (निर्मल, संरक्षित परिगणित जाति)
मुहम्मद दावर हुसैन (निज़ामाबाद)
सिंगी रेड्डी वेन्कट रेड्डी (नुस्रूलापुर)
फत्तचन्द रामचन्द्र गाधी (ओमर्गा)
उद्धवराव (उसमानाबाद)
कल्याणराव (उसमानाबाद, संरक्षित परिगणित जाति)
बापुजी मानसिह (पैठण गंगापुर)
गोविन्द राव केरोजी गायकवाड (पैठण गगापुर, सरक्षित परिगणित जाति)
गोपालराव (पाखल)
अन्नाजीराव (परभानी)
विश्वासराव पाटील (पारेन्डा)
श्रीमती शाहजहा बेगम (परगी)
के० केशव रेड्डी (परकाल)
अकुशराव वेन्कटराव (परतूर)
रामराव बालकृष्ण राव (पथरी)
रतनलाल कोटेचा (पटोडा)
के० वेन्कट रामा राव (पेद्दामुगल)
मुतय्या (पेद्दापल्ली)
मानिकचन्द केवलचपहाडे (फूलमारी)
एल० के० शाराफ़ (रायचूर)
के० वी० नारायण रेड्डी (राजगोपाल पेट)
कथाकूरी रामचन्द्र रेड्डी (रामन्नापेट)
ए० रामचन्द्र रेड्डी (रामायणपेट)
वी० बी० राजू (सिकन्दराबाद)
जे० बी० मुत्यालराव (सिकन्दराबाद, संरक्षित परिगणित जाति)
बी० रामकृष्णराव (शादनगर)
वेन्कट रंगा रेड्डी (शाहबाद)
विरूपाकशप्पा (शाहपुर)
श्रीमती मासूमा बेगम (शालिबंडा)
मल्लाप्पा (शोरापुर)
ए० गुरुवा रेड्डी (सिद्दीपेट)
नागेराव विश्वनाथ (सिल्लोड)
शिवबसन गौडा (सिंधनूर)
जोगनपल्ली आनन्दराव (सिरसिल्ला)
श्रीमती जे० एम० राजमणि देवी (सिरसिल्ला, सरक्षित परिगणित जाति)
एम० बुचैय्या (सिरपुर)
मेहदी नवाज जंग (सोमाजीगुडा)
ए० राज रेड्डी (सुलतानाबाद)
बी० धर्म भिक्शम (सूर्यपेट)
उप्पाल मलचूर (सूर्यपेट, संरक्षित परिगणित जाति)
जे० के० प्राणेशचार्य (तांडूर-सेरम)
माधवराव वेन्कटराव घोनसिकर (उदगीर)
तुलसीराम दशरथ काम्बले (उदगीर, संरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती आशाताई वाधामरे (वजापुर)
कांडिमल्ला रामकृष्ण राव (वेमसूर)
एम० चेन्ना रेड्डी (विकाराबाद)
ए० रामास्वामी (विकाराबाद, संरक्षित परिगणित जाति)
एम० राम रेड्डी (वानरपर्टी)
एम० एस० राजलिंगम (वारंगाल)
ए० लक्ष्मी नरसिंह रेड्डी (वारदन्नापेट)
जगन्नाथ राव (यादगीर)
अम्बादास (यादगीर, संरक्षित परिगणित जाति
ए० निगनगौडा (येलबुर्गा)
के० एल० नरसिंह राव (येल्लान्दू)
वुके नगय्या (येल्लान्दू, संरक्षित परिगणित जाति)
गंडेराव यशवन्त राव (ज़हीराबाद)

जम्मू और काश्मीर

सदरे रियासत	युवराज कर्णसिंह
मंत्री	
1. प्रधान मत्री, तथा साधारण व्यवस्था, कानून, अदालतें, योजना, सामुहिक विकास कार्य, पुलिस और यातायात इत्यादि	बख्शी गुलाम मुहम्मद
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रचार, सूचना और जेल .	गुलाम मुहम्मद सादिक़
3. वित्त, हिसाब, चुगी, आन्तरिक कर, आयकर, तथा बैंक	गिरधारीलाल डोगरा
4. विकास, व्यवसाय, जगल, स्थानीय स्वराज्य, यात्री, तथा प्रदर्शन	शामलाल सराफ
5 लगान, कृषि, ग्रामीण विकास, सहयोग, सहायता और पुनर्वास	मीर कासिम
उपमंत्री	
1 गृह	डी. पी. धर
2. शिक्षा तथा स्वास्थ्य . . .	जी. आर. रैन्जु
3 सरहदी मामले	कौशिक बकुला
4 विकास	ए यू मीर
5 लगान	प्यारासिंह

यह राज्य 27 अक्तूबर 1947 को भारत यूनियन मे सम्मिलित हुआ।

शिक्षा

राज्य की शिक्षा पुनस्संगठन समिति की सिफारिशो के आधार पर 1952–53 मे एक नई बहुउद्देशीय शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ किया गया। उसके अनुसार जम्मू और श्रीनगर मे दो बहु-उद्देश्यीय स्कूल खोले गये और इसी ढग का एक स्कूल श्रीनगर के निकट शालीमार गाव मे खोला गया। राज्य के 60 प्रारम्भिक स्कूलो को माध्यमिक स्कूलो मे परिवर्तित किया गया और 20 माध्यमिक स्कूलो को हाई स्कूलो मे। गत वर्ष शिक्षा पर 46,04,000 रुपये व्यय किये गये और इसके अतिरिक्त 8 लाख रुपये पचवर्षीय आयोजना के अनुसार शिक्षा कार्यों पर व्यय हुए। पुस्तकालयों तथा परीक्षणशालाओ के लिये पुस्तके तथा नया सामान आदि खरीदा गया।

1954 के लिये काश्मीर सरकार ने निश्चय किया है कि जम्मू, काश्मीर और लद्दाख मे 300 नये प्रारम्भिक स्कूल, 28 नये माध्यमिक स्कूल और 2 नये हाई स्कूल खोले जाये।

खाद्यान्न तथा कृषि

मार्च 1953 मे भूमि मुआवजा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य की विधान सभा के सम्मुख पेश की। उसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि जमीदारो को कोई मुआवजा न दिया जाय।

किसानो को भूमि बाटने का कार्य सन्तोषजनक रूप से जारी है। काश्मीर घाटी तथा लद्दाख मे यह कार्य पूरा किया जा चुका है और जम्मू प्रान्त में यह कार्य समाप्ति के करीब है। जो 9 लाख कनाल भूमि राज्य के अपने पास आई है, उसमे शरणार्थियों को बसाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जम्मू, कठुआ और राजौरी-पुंछ जिलो मे भूमि वितरण का कार्य जारी है।

व्यवसाय

1952-53 मे जम्मू काश्मीर सरकार ने कुछ मशीनें जापान से मंगवाईं। इन मशीनो के संचालन के प्रदर्शन के लिये एक ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया। काश्मीर का साबा शहर छपाई के कार्य के लिये प्रसिद्ध था। सरकार अब सांबा में इस व्यवसाय का पुनरुद्धार कर रही है। छोटे व्यवसायों के विकास और पुनर्निर्माण के लिये राज्य के व्यवसाय बोर्ड ने 20,000 रुपये कर्ज के रूप मे बाटे है। राज्य से काश्मीरी सामान का निर्यात अब बहुत सगठित रूप मे हो रहा है और यह प्रयत्न किया जाना है कि काश्मीर मे बने माल की किस्म घटिया न होने पावे। राज्य की व्यवस्थापिका सभा घटिया दर्जे के नमदो के निर्माण पर बंदिश लगा चुकी है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष जनता के स्वास्थ्य की ओर अधिकतम ध्यान दिया गया। राज्य के अस्पतालों मे नये ढग के उपकरण मगवाये गये। राज्य के अस्पतालो का पुनर्संगठन किया गया। श्रीनगर के अस्पताल के लिये एक लाख रुपये के व्यय से एक्स रे का नया प्लाण्ट आया। अब बारामूल के अस्पताल मे भी इसी तरह का यंत्र लाया जा रहा है।

जम्मू मे लैंगिक बीमारियों के निरोध के लिये प्रयत्न जारी है। राज्य के चिकित्सकों को इस सम्बन्ध मे शिक्षा लेने के लिये शिमला भेजा गया था। तपेदिक के निरोध के लिये ३ लाख व्यक्तियो की परीक्षा की गई और उन्हे बी. सी.जी का टीका लगाया गया। जम्मू और काश्मीर सरकार ने कुछ चलतेफिरते चिकित्सा यूनिट बनाये है, जो राज्य के विभिन्न स्थानो पर जाकर जनता की सेवा का कार्य करते हैं।

जम्मू और काश्मीर संविधान सभा

(जम्मू और काश्मीर की विधान सभा भी यही है)

संविधान सभा के अध्यक्ष : जी० एम० सादिक

विधान सभा के अध्यक्ष : जी० आर० रेन्जू

बख्शी गुलाम मुहम्मद (सफा कदल)
मुहम्मद अफज़ल बेग (अनन्तनाग)
गिरधारीलाल डोगरा (जसमेरगढ)
शामलाल सराफ (हब्बाकदल)
अब्दुल अजीज शाल (राजौरी)
अब्दुल गनी तराली (राजपोरा)
अब्दुल गनी गोनी (भलेसा—बुजवाह)
अब्दुल क़ुद्दूस (बिरवा)
बख्शी अब्दुल रशीद (चरारे शरीफ़)
अब्दुल कबीर खा (वाडीपुर—गुरेज़)
अब्दुल खालिक (सनिवारा)
अल्लाउद्दीन गिलानी (हन्द्वारा)
असद उल्लाह मीर (रामबन)
छज्जूराम (रणबीरसिंहपुर)
भगतराम शर्मा (लम्दर—टीकरी)
चूनीलाल कोतवाल (भदरवा)
चेलासिंह (छम्ब)
डी० पी० धर (कुलगाम)
गुलाम अहमद मीर (दच्छिनपारा)
मुहम्मद अब्दुल्ला (हज़रतबल)

गुलाम अहमद देव (डोड़ा)
गुलाम जिलानी (पाम्पुर)
गुलाम हुसन खा (नारवाव)
गुलाम रसूल रैना (नन्दी)
गुलाम हुसन (देवसर)
गुलाम मुहम्मद मसूदी (त्राल)
जी० एम० सादिक (टंकीपुर)
गुलाम मुहम्मद बेग (नोबुग—ब्रंग घाटी)
गुलाम मुहम्मद बट्ट जालिब (पटटन)
गुलाम मह्युद्दीन हमदानी (खानयार)
गुलाम मह्युद्दीन खा (खा साहेब)
गुलाम नबी हमदानी (जड्डिब्रल)
गुलाम नबी वानी (लोलाब)
गुलाम नबी वानी (दरीगाम)
गुलाम कादिर मसाला (द्रुगमूला)
गुलाम रसूल रेन्जू (अमीरा कदल)
गुलाम रसूल शेख (शोपिया)
गुलाम रसूल कार (हम्मल)
गुलाम रसूल कैाक (किश्तवार)
हबीब उल्लाह (सोपुर)
हरबंससिह आजाद (बारामूला)
हेमराज जन्डियाल (रामनगर)
इब्राहीम शाह (करगिल)
श्रीमती ईश्वरदेवी मैनी (जम्मू उत्तर)
जमालुद्दीन डार (दरहाल)
जामयतअली शाह (भेण्डर)
जानकीनाथ ककरू (कोठार)
कृष्णदेव सेठी (नौशेरा)
कुलबीरसिंह (पछ शहर)
कुशक बकुला (लेह)
मनसुखराय (रियासी)
महन्तराम शर्मा (बसोली)
मुहम्मद अफ़जल खा (उड़ी)
मुहमम्मद अकबर (टंगमर्ग)
मुहम्मद अनवर शाह (करनाह)
मुहम्मद अयूब खा (अरनास)
गुलाम मुहम्मद मीर (रामहाल)
मोतीराम बैगरा (उधमपुर)
मीर कासिम (डुरू शाहबाद)
मुबारिक शाह (मागाम)
नाहर सिंह (बिशना)
निजामुद्दीन (कगन)
नूरुद्दीन डार (खोवरपारा)
नुरुद्दीन सूफी (गान्धरबल)
प्यारासिह (कठुआ)
रामचन्द खजूरिया (बिलावर)
रामप्यारा सराफ (साम्बा)
रामदेवी (जम्मू दक्षिण)
रामरखा मल (काहनाचक)
रामसरन दास (जन्द्रा—घरोटा)
रामलाल (अखनूर)
सागरसिह (पुरमण्डल)
सनाउल्ला शेख (पूलवामा)
अली शाह सफवी (बडगाम)

मध्यभारत

राजप्रमुख . . . . महाराजा ग्वालियर

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, व्यवस्था तथा नियुक्तियां . . मिश्रीलाल गंगवाल
2. गृह तथा सार्वजनिक कार्य . . . मनोहर सिंह महता
3. लगान, अन्न, नागरिक पूर्ति सड़कें . तथा स्थानीय स्वराज्य . . शामलाल पाडवीय
4. कानून, व्यापार, व्यवसाय तथा सूचना . . सीताराम जाजू

5. कृषि, श्रम और विकास . . वी. वी. द्रविड
6. स्वास्थ्य, जगल तथा आदिवासी-कल्याण . प्रेमसिंह राठौर
7. वित्त (लगान को छोड़कर) . . सौभाग्यमल जैन
8. शिक्षा, सहायता और पुनर्वास . नरसिंहराव दीक्षित

उपमंत्री

1. राधावल्लभ विजयवर्गीय
2. सवाईसिंह सिसोदिया
3. सज्जनसिंह विशनार

मध्यभारत राज्य की स्थापना पिछली 25 रियासतो के मिश्रण से मई 1948 मे हुई थी।

वित्त (लाख रुपयो मे)

बजट के आकडे	आय	व्यय	बचत या (+) घाटा (—)
1950–51 (लेखा)	1,038	1,177	— 139
1951–52 (लेखा)	1,149	1,131	+ 18
1952–53 (संशोधित)	1,301	1,273	+ 28
1953–54 (बजट)	1,430	1,449	— 19

शिक्षा

इस समय मध्यभारत मे 5 डिग्री कालेज, 2 संस्कृत कालेज, 1 सगीत कालेज, 16 इंटरमीडिएट कालेज, 374 लडको के माध्यमिक स्कूल और 69 लडकियो के माध्यमिक स्कूल है। इनके अतिरिक्त 4,358 लडको के तथा 428 लड़कियो के प्रारम्भिक स्कूल है। विशेषज्ञो की एक समिति की राय के अनुसार सरकार ने यह निश्चय किया है कि वर्तमान प्रारम्भिक स्कूलो को बेसिक स्कूलो मे परिणत कर दिया जाय तथा कतिपय नये बेसिक स्कूल खोले जाये। राज्य भर मे शिक्षा का दर्जा, पाठ्यक्रम, अध्यापकों की उन्नति सम्बन्धी नियम, फीस आदि को एक समान कर दिया गया है। 16 जिलो के मुख्य स्थानो पर अनिवार्य शिक्षा जारी की गई है, जिससे 20,000 विद्यार्थियो को लाभ पहुच रहा है। पचवर्षीय आयोजना के अनुसार 1953–54 में शिक्षा के विस्तार पर 23,23,000 रुपये व्यय करने का निश्चय हुआ। राज्य की विधान सभा मध्यभारत यूनिवर्सिटी बिल पर विचार कर रही है।

खाद्यान्न तथा कृषि

1951 के जमीदारी निवारण कानून के अनुसार मध्यभारत में जमीदारी प्रथा का अन्त कर दिया गया है। इस कानून के अनुसार यह निश्चय हुआ है कि जमीदारो को 10 वर्षो मे अपनी वार्षिक आय का 8 गुना मुआवजे के रूप मे दे दिया जायगा। जागीर निवारण कानून पर कार्यवाही इसलिये रोक दी गई कि उसके सम्बन्ध में जागीरदारों ने कानूनी अपील की हुई है, और अभी सुप्रीम कोर्ट से उसके सम्बन्ध मे निर्णय प्राप्त नही हुआ।

गत वर्ष ट्रेक्टरो की सहायता से 39,000 एकड कास वाली भूमि तथा 4,500 एकड जगल वाली भूमि को साफ कर कृषि योग्य बना दिया गया। किसानो को बैल, बीज, खाद आदि खरीदने के लिये 60 लाख रुपये तकावी के रूप मे बाटे गये। हरमी, भेलसा और राजपुर क्षेत्रो में 3 कृषि तथा देहाती विकास योजनाएं जारी की गई।

व्यवसाय

राज्य के मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित है कपडा, चीनी, सीमेट, तेल, बिस्कुट और चीनी की मिठाई बनाने वाले कारखाने। कपडे के कारखाने मुख्यत: इन्दौर, ग्वालियर और उज्जैन मे है और उन मे प्रति वर्ष 26 करोड गज कपडा तैयार होता है। प्रति वर्ष राज्य मे 61 लाख टन सीमेट बनाई जाती है।

राज्य ने अपनी ओर मे चीनी के बर्तन, चमडे का सामान और इजीनियरिंग के कुछ व्यवसाय जारी किये हुए है। व्यक्तिगत कार्यो को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्वालियर की टैक्समैको फैक्टरी भारत भर में स्वयंचालित करघो को बनाने वाली एकमात्र फैक्टरी है। मंधाराम बिस्कुट फैक्टरी अपने ढग की एशिया भर मे सब से बडी फैक्टरियों मे मे है। मध्यभारत मे उस्तरे बनाने की भी एक फैक्टरी है। नागदा मे सूत बनाने का कारखाना और माहेश्वर मे पत्थर की नालिया बनाने का कारखाना जारी किया गया है।

गृह व्यवसाय का भी विकास किया जा रहा है। राज्य मे लगभग 125 गृह व्यवसाय जारी है जिनमे महत्वपूर्ण निम्नलिखित है कपडा, चमडे का सामान, चीनी और मिट्टी के बर्तन, लकडी के कार्य, धातु के कार्य, तथा तेल निकालना। चन्देरी और माहेश्वर के सूती और ऊनी कपडे भारत भर में प्रसिद्ध है। रेशम की उपज बढाने के लिये राज्य मे शहतूत के वृक्ष बोये जा रहे है। पचवर्षीय आयोजना के अनुसार मध्यभारत मे गृह उद्योगो के विकास के लिये 50 लाख रुपये व्यय किये जायेगे। इस कार्य के लिये एक गृह उद्योग बोर्ड स्थापित किया जा चुका है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

1953 मे ग्वालियर मे 45 अस्पताल थे, जिनमे से एक मानसिक रोगो की चिकित्सा के लिये था। आयुर्वेदिक चिकित्सालयो को मिला कर राज्य भर मे चिकित्सालयो की सख्या 496 थी।

पचवर्षीय आयोजना के अनुसार राज्य मे 13 तपेदिक के क्लिनिक खोलने का निश्चय किया गया था, जिनमे से अब तक 10 खोले जा चुके है। इन 10 मे से भिण्ड, राजगढ, मन्दसौर और धार के चारों क्लिनिक गत वर्ष खोले गये। तपेदिक की रोकथाम के लिये 12,50,000 व्यक्तियो की परीक्षा की गई और 3,50,000 को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया। 1953 मे 7 नये जच्चागृह खोले गये और उनकी कुल सख्या 46 तक पहुच गई। राज्य के दो जिलों में परीक्षण के तौर मे शराबबन्दी भी जारी की गई है। क्रमश शराबबन्दी का क्षेत्र बढाने का इरादा है।

मध्यभारत विधान सभा

अध्यक्ष : ए० एस० पटवर्धन

सौभाग्यमल जैन (आगर)
भीमा भील (अलिराजपुर, सरक्षित परिगणित जनजाति)
कुसुमकान्त जैन (अलौट)
चंदनलाल सामलीप्रसाद (अम्बा, सरक्षित परिगणित जनजाति)
जमुनाप्रसाद सिंह (अम्ब)
बाबूराम (अटेर)
सवाईसिंह सिसोदिया (बारनगर)
मिश्रीलाल गगवाल (बागली)
निरजन वर्मा (बसौदा)
जादवचन्द जैन (बरवाहा)
सीताराम साधु (बरवाहा, सरक्षित परिगणित जाति)
किशनसिंह (बरवानी, सरक्षित परिगणित जनजाति)
विमलकुमार मन्नालाल चोडिया (मानपुरा)
चतुर्भुज जातव (भीलसा, सरक्षित परिगणित जाति)
जमुनाप्रसाद मुखारिया (भीलसा)
नरसिहराव दीक्षित (भिंड)
वल्लभदास सीताराम (भीकनगाव)
मदनलाल अग्रवाल (बिश्रौरा)
बालमुकुन्द मुद्गल (बिजयपुर)
द्वारकादास गर्ग (चाचोरा)
कन्हैयालाल खादीवाला (दिपालपुर)
सज्जनसिंह बिशनार (दिपालपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
अनन्त सदाशिव पटवर्धन (देवास)
बापुलाल किशनलाल मालवीय (देवास, सरक्षित परिगणित जाति)
गोपालप्रसाद (धार—बादनवार)
जगन्नाथ (धार—बादनवार, संरक्षित गणित जाति)
एम० वी० धुले (घाटीगाव)
प्रभुदयाल (गोहड, संरक्षित परिगणित जाति)
रामधन सिंह (गोहाड)
वृन्दावन प्रसाद तिवारी (गुना)
पुरुषोत्तम लक्ष्मण राव इनामदार (ग्वालियर)
मनोहरसिंह मेहता (इन्दौर)
रामसिंह के० वर्मा (इन्दौर)
वी० वी० द्रविड (इन्दौर)
वी० वी० सरवते (इन्दौर)
चौधरी फैजुल्ला (जिश्रोरा)
बद्रीदत्त भट्ट (जादव)
श्रीमती जमुनाबाई (झाबुआ, सरक्षित परिगणित जनजाति)
प्रेमसिंह सोलकी (जोबाट, सरक्षित परिगणित जनजाति)
रामचरण मिश्र (जौरा)
भगवानदास चतुर्वेदी (करेरा)
भेरूलाल सेवाजी चौहान (खचरोद, सरक्षित परिगणित जाति)
रामचन्द्र विलासीराम नवल (खचरोद)
सवाईसिंह मन्डलोई (खारगोन, सरक्षित परिगणित जनजाति)
श्रीमती मंजुलाबाई बागले (खाटेगाव)
प्रभुदयाल चौबे (खिलचीपुर)
रघुराजसिंह (खिलचीपुर)
रतूसिंह रामसिंह (कुक्षी, सरक्षित परिगणित जनजाति)
रामसिह (कुरवई)
गोकुलप्रसाद कटरोलिया (लाहर, सरक्षित परिगणित जनजाति)
हरसेवक मिश्र (लाहर)
हरकिशोर वैश्य (लशकर)
भूमकिरत सिह (मनावर, दक्षिण, सरक्षित परिगणित जनजाति)

शिवभानु सोलंकी (मनावर, उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)
रामलाल (मनसा)
भगवानदास जैन (मंदसौर, उत्तर)
श्यामसुख गर्ग (मंदसौर, दक्षिण)
रुस्तमजी कावसजी जाल (मऊ)
करनसिंह (मोरेना, संरक्षित परिगणित जाति)
मुरलीधरसिंह (मोरेना)
कुन्दनलाल बारिया (मगरौली)
श्यामलाल पाण्डवीय (मोगट)
भवरलाल जीवन (नरसिंहगढ, संरक्षित परिगणित जाति)
राधावल्लभ विजयवर्गीय (नरसिंहगढ)
सीताराम जाजू (नीमच)
दूलीचन्द (पछार, संरक्षित परिगणित जाति)
रामदयाल सिंह रघुवंशी (पछार)
देदन रुद्र (पिछौर—भाण्डेर)
दिवान बरजोरसिंह (पिछौर, दक्षिण)
किशोरीलाल सुखाराम (पिछौर—भाण्डेर, संरक्षित परिगणित जाति)
लक्ष्मीनारायण वकील (पिछौर—उत्तर)
राजा बलभद्रसिंह (राघोगढ)
श्रीमती प्रतिभादत्त उभाना (राजगढ)
हीरालाल शर्मा (राजपुर)
देवीसिंह (रतलाम तहसील)
प्रेमसिंह (रतलाम शहर)
लक्ष्मीचन्द वैश (साँवलगढ)
जेटा भग्गा भगत (सरदाना, संरक्षित परिगणित जनजाति)
शंकरलाल गर्ग (सरदारपुर)
बारकू महादू चौहान (सेन्धवा, संरक्षित परिगणित जनजाति)
रमाकान्त खोडे (सेन्धवा)
रामचन्द्र विट्ठल बादे (सेन्धवा)
एच. एल. मसूरकर (शाजापुर)
कृष्णलाल नागाजी मालवीय (शाजापुर संरक्षित परिगणित जाति)
नरहरिप्रसाद (शिवपुरी—कोलारस)
तुलाराम (शिवपुरी—कोलारस, संरक्षित परिगणित जाति)
सोमे लाल्ली (शिवपुरी, संरक्षित परिगणित जनजाति)
उदयभानु सिंह (शिवपुर)
त्रियम्बक सदाशिव गोखले (शुजालपुर)
बापूराव चम्पालाल (सीतामऊ)
धनीराम सागर (सीतामऊ, संरक्षित परिगणित जाति)
विजयसिंह (सोनकाच)
राना मानसिंह (सुसनेर)
रामेश्वरदयाल तोतला (तराना)
लालसिंह (थाडला, संरक्षित परिगणित जनजाति)
गददूदास सूर्यवंशी (उज्जैन, तहसील, संरक्षित परिगणित जाति)
मसूद अहमद (उज्जैन तहसील)
वी. वी. द्रायाचित (उज्जैन शहर)
राणा रणविजयसिंह (उमरी)

मैसूर

राजप्रमुख . . . महाराजा मैसूर

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, वित्त, सेवायें, महल, हाईकोर्ट, योजना, तथा दलित जाति कल्याण . . . के० हनुमन्तय्य
2. कानून, शिक्षा, श्रम और सूचना . . . ए. जी. रामचन्द्र राव

3. स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य, आन्तरिक कर, तथा ग्रामीण विकास — टी चन्नय्य

4. लगान, सार्वजनिक कार्य, स्टैम्प तथा रजिस्ट्रेशन — के. मजप्प

. गृह, व्यवसाय, यातायात, अन्न तथा नागरिक पूर्ति — एच. सिद्दवीरप्प

6. कृषि, जंगल, पशु चिकित्सा, सहयोग, सहायता तथा पुनर्वास — आर नागन गौड

वित्त (लाख रुपयों में)

बजट के आकड़े	आय	व्यय	अतिरिक्त (+) या घाटा (—)
1950-51 (लेखा) .	1,441	1,351	+90
1951-52 (लेखा) .	1,831	1,835	—4
1952-53 (संशोधित) .	1,967	2,021	—54
1953-54 (बजट)	2,062	2,220	—158

शिक्षा

मैसूर राज्य ने शिक्षा पद्धति की परीक्षा के लिये 1952 मे जो समिति नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट मे ये बाते निर्दिष्ट थी :—शिक्षा पर जो व्यय किया जाता है उसका काफ़ी बड़ा भाग अनिवार्य प्रारम्भिक तथा बेसिक शिक्षा पर व्यय होना चाहिये । अनुसन्धान की सुविधायें बढ़ानी चाहिये तथा राज्य मे जनता कालेजों की स्थापना की जानी चाहिये । समिति की यह भी सिफारिश थी कि शिक्षा मे शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिये और सामाजिक सेवा को शिक्षा का आन्तरिक भाग बना देना चाहिये । इन सिफारिशों को किस तरह व्यवहार में लाया जाय, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

1952 मे मैसूर मे कुल 13,888 शिक्षा सस्थाये थी और उन मे 9,27,133 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इनमे 10,474 प्रारम्भिक स्कूल, 703 माध्यमिक स्कूल, 217 हाई स्कूल और 37 कालेज थे । 1953-54 के बजट मे शिक्षा के लिये 3,77,35,000 रुपये स्वीकार हुए थे ।

खाद्यान्न तथा कृषि

मई 1953 मे मैसूर मे राशन प्रणाली बन्द कर दी गई है । उससे पिछले वर्ष के लिये 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अनुसार भारत सरकार ने एक करोड़ रुपया उधार के रूप में और 31,10,000 रुपया सहायता के रूप में दिया था । विभिन्न योजनाओं पर 57,07,000 रुपये व्यय किये गये ।

कृषि के सम्बन्ध में राज्य ने कितने ही अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कार्य किये। आलुओं की अच्छी क़िस्म प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। राज्य में मिस्र की रूई बोई गई और उसका परिणाम सन्तोषप्रद निकला। भारतीय केन्द्रीय सुपारी कमेटी के सहयोग से सुपारी की उपज को अच्छा करने और बढ़ाने के प्रयत्न भी जारी है।

फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से 31 गांव के दर्जे के कार्यकर्ताओं को तयार किया गया और उन्हे मल्लवली ताल्लुके के कुछ गावो में नियुक्त किया गया। राज्य मे जापानी ढग से चावल बोने की पद्धति को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। कुछ नई किस्म की उपजों के सम्बन्ध मे परीक्षण किये जा रहे है।

व्यवसाय

गत वर्ष विभिन्न व्यवसायो पर राज्य ने 520 लाख रुपये की पूंजी लगाई। मैसूर के लोहे के कारखाने के प्रबन्ध, व्यवस्था आदि में सुधार किया गया। इस कारखाने के अतिरिक्त सरकारी बिजली कारखाना और सरकारी चीनी मिट्टी कारखाना के नियंत्रण के लिये एक संयुक्त बोर्ड बनाया गया। उद्देश्य यह है कि सभी व्यवसायों की उन्नति के लिये उनमे एक समान नीति बरती जाए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952-53 मे राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधीन 175 स्वास्थ्य यूनिट काम कर रहे थे। इस वर्ष के लिये 44 नये स्वास्थ्य यूनिटो की स्वीकृति दी गई है।

मैसूर विधान सभा

अध्यक्ष : आर० चन्निगरामय्य

आर० अनन्तरामन (चामराजपेट)
के० वी० बैरे गौड (बगलूर, उत्तर)
डी० एम० गोविन्दराजू (नेलमगल)
के० हनुमन्तय्य (रामनगरम)
एस० करियप्प (विरूपाक्षपुर)
बी० टी० केम्पराज (बगलूर, दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती लक्ष्मीदेवी रामण्ण (होसकोट आनेकल)
वी० एम० मास्करेन्हास (सेन्टजोन्स हिल)
आर० मुनीस्वामय्य (बगलूर, उत्तर सरक्षित परिगणित जाति)
वी० आर० नायडू (माल्लेश्वरम्)
ए० वी० नरसिंह रेड्डी (बगलूर, दक्षिण)
एम० पलनियप्पन् (उलसूर)
के० प्रभाकर (नेलमगल, सरक्षित परिगणित जाति)
एच० टी० पुट्टप्पा (होसकोटे—आनेकल)
पी० आर० रामय्य (बसवनगुडि)
बी० एम० शीनप्प (कब्बनपेटे)
टी० सिद्दलिंगय्य (दोड्डबल्लापुर)
एस० सिद्दप्प (मागडी)
के० जी० तिम्मे गौड (कनकपुरा)
वी० वेंकटप्प (चन्नपटन)
डी० वेंकटेश (गाधीनगर)
वाई० एम० चन्द्रशेखरय्य (कडूर)
जी० पुट्टस्वामी (चिकमगलूर—संरक्षित परिगणित जाति)

श्रीमती बी० एल० सुब्बम्मा (चिकमगलूर)
जी० बसप्प (होसदुर्ग)
ए० भीमप्प नायक (मोलकालमुरू)
जी० दुग्गप्प (होलकेरे, सरक्षित परिगणित जाति)
टी० हनुमय्य (हिरियूरू, सरक्षित परिगणित जाति)
जे० मुहम्मद इमाम (जगलूर)
वी० मसियप्प (हिरियूरू)
मुल्क गोविन्द रेड्डी (चित्रदुर्ग)
जी० शिवप्प (होललकेरे)
एच० सिद्दवीरप्प (हरिहर)
श्रीमती बल्लारी सिद्दम्म (दावणगेरे)
बी० एन० बोरण्ण गौड (बेलूर)
बी० चिकण्ण (जावगल)
डी० आर० करीगौड (हासन)
के० लक्कप (चन्नारायपट्टण)
के० पचाक्षरय्य (आरसीकेरे)
ए० जी० रामचन्द्र राव (होले नरसीपुर)
एच० के० सिदय्य (बेलूर, सरक्षित परिगणित जाति)
जी० ए० तिम्मप्प गौड (अरकलगाड)
एम० सी० आंजनेय रेड्डी (चिन्तामणि)
टी० चन्नय्य (मुलबगल-श्रीनिवासपुर सरक्षित परिगणित जाति)
आर० के० प्रसाद (बंगारपेटे)
एच० सी० लिंगारेड्डी (मालूर)
ए० मुनियप्प (सिडलघट्ट चिकबल्लापुर, सरक्षित परिगणित जाति)
एन० सी० नागय्य रेड्डी (गोरी बिदनूर)
जी० नारायण गौड (मुलबागल-श्रीनिवासपुर)
जे० नारायणप्प (चिन्तामणि, सरक्षित परिगणित जाति)
बी० बी० नारायण रेड्डी (बागेपल्ली-गुडी-बण्डे)
जी० पापण्ण (सिडलघट्ट-चिकबल्लापुर)
के० पट्टाभिरामन (कोलार)
पी० एम० स्वामि दौरे (कोलर गोल्ड फील्ड, संरक्षित परिगणित जाति)
के० एम० वासन (कोलार गोल्ड-फील्ड)
एम० चिक्कलिंगय्या (मालवल्ली, सरक्षित परिगणित जाति)
एस० एम० लिंगप्प (कृष्णराजपेट)
बी० पी० नागराज मूर्ति (मालवल्ली)
बी० वाई० नीले गौड (पाण्डवपुर)
के० पुट्टस्वामी (श्रीरंगपट्टण)
जी० एम० बोम्मे गौड (मण्ड्य)
के० सिंगारि गौड (नागमगला)
एच० के० वीरण्ण गौड (मद्दूर)
डी० देवराज अर्स (हुन्सूर)
एम० लिंगण्ण (नन्जनगड)
यू० एम० मादप्प (चामराजनगर)
एम० मादय्य (नन्जनगड, सरक्षित परिगणित जाति)
एस० एम० मरयप्प (पेरियापटना)
टी० मरियप्प (मैसूर शहर, उत्तर)
बी० नारायण स्वामी (मैसूर शहर, दक्षिण)
बी० राचय्य (येलन्दुरु, सरक्षित परिगणित जाति)
एम० राजशेखर मूर्त्ति (येलन्दुरु)
शिवनन्जे गौड (मैसूर तालूक)
सिद्दय्य उर्फ कुन्नय्य (गुन्डलुपेट-हैगडदेवनकोट सरक्षित परिगणित जाति)
एच० के० शिवरुद्रप्प (गुन्डलपेट-हैगडडेवन कोट)
एस० श्रीनिवास आय्यंगार (टी० नरसीपुर)
एस० एच० तिम्मय्य उर्फ हनुमन्ते गौडर तिम्मय्य (कृष्णराजनगर)
गंगानायक (सोराब-शिकारीपुर संरक्षित परिगणित जाति)

एस० गोपाल गौड (सागर हासनगर)
कुडिदाल मजप्प (तीर्थहाल्ली-कोप्प)
बी० माधवाचार (भद्रावती)
टी० मी० बसप्प (तारीकेरे)
एस० आर० नागप्पसेट्टी (शिवमोगा)
एच० एम० रुद्रप (होन्नाली)
रिवा (सोरब-शिकारीपुर)
एल० सिद्दप (चन्नगिरि)
सी० एम० अण्णय्यप्प (गुब्बि)
आर० चन्निगरामय्य (कोरटगेरे-मधुगिरि, मरक्षित परिगणित जाति)
सी० टी० हनुमन्तय्य (पावगड, मरक्षित परिगणित जाति)
बी० हुच्चे गौड (तुरुवेकेरे)
एन० हुचमास्ति गौड (हुलियुर्दुर्ग)
सी० एच० लिंगदेवरू (चिकनायकनहल्ली)
माली मरियप्प (पावगड़)
मुद्दुरामय्य (कोरटगेरे-मधुगिरि)
टी० एन० मुडलगिरि गौड (कुणिगल)
बी० मी० नंजुण्डय्य (कोरा)
एम० वी० रामराव (तुमकूरु)
बी० एन० रामे गौड (मीरा)
टी० जी० तिम्मेगौड (तिपटूर)
मिडरी ए० थामस (नामजद)
एम० गगप्प (ब ल रि)
कोटबसवरू गौड (कुडलिगी)
ड० आर० नागन गौड (होसपेट)
एम० परमेश्वरप्प (सिन्गुप्पा)
इजारि सिरमप्प (हरपनहल्ली)

मैसूर विधान परिषद्

सभापति के० टी० भाष्यम

जी० वीरप्प (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)
टी० एस० राजगोपाल आय्यगार (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)
ए० एन० रामराव (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)
एम० पी० एल० शास्त्री (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)
के० सम्पत गिरिराव (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)
एच० आर० अब्दुल गफ्फार (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)
सी० एच० वेन्कटरमणप्प (जिला कोलार)
डी० वेन्कटरामय्य (जिला कोलार)
टी० एन० केम्प हौन्नय्य (जिला तुमकूरु)
आर० सुब्बन्न (बंगलूर जिला)
एम० आर० गुरु उर्फ गुरुलिंगय्य (जिला बंगलूर)
ज० देवय्य (माड्या जिला)
पी० सीतारामय्य (मैसूर जिला)
आर० पी० रेवण्ण (जिला मैसूर)
वाई० धर्मप्प (जिला हासन)
एन० पी० गोविंद गौड (जिला चिकमगलूर)
यू० पी० शकर राव (शिमोगा जिला)
टी० वीरण्ण (चित्रदुर्ग जिला)
के० सजीव रेड्डी (चित्रदुर्ग जिला)
के० टी० भाष्यम (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
एल० एच० तिम्माबोवि (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
एच० एम० गगाधरय्य (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
मरिस्वामय्ये मलदपाटील (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
एम० एन० जीयम (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)
श्रीमती एम० आर० लक्षम्म (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

एम० एन० महन्त देवरू (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

बी० के० पुट्टरामय्य (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

एम० शंकरय्य (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

एस० शिवप्प (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

पी० तिरूमले गौड (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

एस० वीरबसप्प (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

एम० वैल्लरी (विधान सभा द्वारा—निर्वाचित)

एन० ए० अय्यंगार (नामजद)

टी० चौडय्य (नामजद)

जी० एच० वीरण्ण (नामजद)

रूमाले चेन्नबसवय्य (नामजद)

पी० गोपाल कृष्ण सेट्टी (नामजद)

सी० जे० देवनाथ (नामजद)

गोरुरु रामस्वामी अय्यंगार (नामजद)

सैयद गौस मोहिउद्दीन (नामजद)

पेप्सू

राजप्रमुख — महाराजा पटियाला

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, व्यवस्था और गृह . . . कर्नल रघुवीर सिंह
2. शिक्षा, वित्त और व्यवसाय . . . वृषभान
3. स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक कार्य . . . सरदार शिवदेव सिंह
4. विकास, कृषि तथा सहयोग . . . राजा सुरिन्दर सिंह
5. लगान, पुनर्वास तथा बन्दोबस्त . . . सरदार हरचरण सिंह

उपमंत्री

1. वित्त . . . . . . सरदार प्रेमसिंह
2. मुख्य मंत्री के सहायक . . . . साधुराम
3. अन्य — अमीरसिंह

वित्त

(लाख रुपयों में)

बजट के आंकड़े	आय	व्यय	बचत (+) या घाटा (–)
1950–51 (लेखा)	604	503	+101
1951–52 (लेखा)	609	466	+143
1952–53 (संशोधित)	625	579	+46
1953–54 (बजट)	635	704	—69

खाद्यान्न तथा कृषि

किसानों को जमीनों पर स्वामित्व देने तथा आर्थिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से राष्ट्रपति ने पेप्सू में दो कानून जारी किये। 1953 के ओक्युपेन्सी टेनेन्सी कानून के अनुसार

अब किसानों को उस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त हो गया है, जिस पर वे कृषि करते हैं। 'आला मलिकियत राइट्स कानून' के अनुसार राज्य में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई।

1952-53 में राज्य में एक लाख टन से ऊपर खाद्यान्न, जिनमें अधिकांश गेहूं था, प्राप्त किया गया और इसमें से 60 हजार टन कमी वाले क्षेत्रों में भेजा गया। 1952 के अन्त तक कृषि सुधार की दृष्टि से भूमि के एकीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। अनावृष्टि के कारण महेन्द्रगढ़ जिले के 1,300 गावों में 5 लाख रुपयों के लगान की छूट दी गई। 2,60,000 रुपये तकावी आदि के रूप में बांटे गये।

भाखड़ा योजना की पूर्ति के साथ पेप्सू में 13 लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई होने लगेगी। इसके अतिरिक्त सरहिन्द नहर के पानी का क्षेत्र भी बहुत बढ़ा दिया जायगा।

व्यवसाय

राज्य में कुल 550 रजिस्टर्ड कारखाने हैं, जिनमें से एक दर्जन बहुत बड़े हैं। इनमें राजपुरा की बिस्कुट फैक्टरी, राजपुरा, फगवाड़ा और फरीदकोट की स्टार्च फैक्टरियां, हमीरा और फगवाड़ा के चीनी के कारखाने और फगवाड़ा का कपड़े का कारखाना उल्लेखनीय करने योग्य हैं। इनके अतिरिक्त दो सीमेंट की और दो आटे की मिलें भी हैं।

छोटे व्यवसायों और बड़े व्यवसायों को उन्नत करने तथा उनमें तालमेल पैदा करने के लिये एक प्रारम्भिक जांच पड़ताल की गई थी। इसी उद्देश्य से एक व्यावसायिक वित्त कारपोरेशन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। नाभा में एक व्यावसायिक शिक्षा संस्था खोली गई है, जहां धातु के काम की शिक्षा, मकेनिक, बढ़ईगीरी आदि काम सिखलाये जाते हैं। 1953 में पटियाला में एक अखिल भारतीय व्यावसायिक प्रदर्शनी भी की गई थी।

श्रम

1953-54 में राज्य के विभिन्न कारखानों में 27,000 आदमी काम करते थे। मजदूरों के कल्याण के लिये भारत में जो कानून हैं, वे सब पेप्सू में भी क्रमशः जारी कर दिये गये हैं। पूंजीपतियों और मजदूरों में सहयोग और सौहार्द बढ़ाने के लिये 1953 में एक त्रिदलीय श्रम सम्मेलन बुलाया गया था।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

1953-54 में राज्य के स्वास्थ्य के लिये 47,30,000 रुपये रखे गये। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार पेप्सू में चिकित्सा सम्बन्धी विकास तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर 85 लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया गया है।

इस समय राज्य में 50 अस्पताल हैं, जिनमें 1200 बिस्तरों का प्रबन्ध है। पटियाला के प्रसिद्ध राजेन्द्र अस्पताल में 152 बिस्तरे थ, परन्तु वे अपर्याप्त समझे गये और अब 500 बिस्तरों का नया अस्पताल बन कर लगभग तैयार है। इसी अस्पताल के साथ एक मैडिकल कालेज खोलने का भी इरादा है। धर्मपुर के हार्डिंग तपेदिक चिकित्सालय में एक नया वार्ड बढ़ाया गया है। राज्य में आजकल 51 आयुर्वेदीय चिकित्सालय हैं। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार उनकी संख्या में 75 की वृद्धि की जायगी। तपेदिक की रोकथाम के लिये 3 दलों ने राज्य में 7,00,000 व्यक्तियों की परीक्षा की और 2,50,000 को बी० सी० जी० का टीका लगाया

पेप्सू विधान सभा

अध्यक्ष : रामसरन चन्द मित्तल

निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
1. अहमदगढ	चन्दासिंह	कांग्रेस
2. अमलोह	ज्ञानसिंह	स्वतंत्र
3. अमलोह (सरक्षित)	मिहनसिंह	स्वतंत्र
4. अटेली	श्याम मनोहर	कांग्रेस
5. बाधरा	श्रीमती चन्द्रावती	कांग्रेस
6. बनूड	किरपालसिंह	कांग्रेस
7. बनूड (सरक्षित)	हरचन्दसिंह	कांग्रेस
8. बरनाला	कर्तारसिंह	अकाली (क)
9. बस्सी	बेअन्तसिंह	अकाली (क)
10. भादसो	भगवन्तसिंह	कांग्रेस
11. भठिन्डा	हरचरणसिंह	कांग्रेस
12. भवानीगढ़	जंगीरसिंह	अकाली (क)
13. भोलत्थ	हरनामसिंह	अकाली (क)
14. बुढलाडा	धर्मसिंह	कम्युनिस्ट पार्टी
15. बुढलाडा (सरक्षित)	कृपालसिंह	अकाली (ख)
16. दादरी	अमीरसिंह	कांग्रेस
17. दादरी (सरक्षित)	रामचन्द	कांग्रेस
18. धनौला	हरदितसिंह	कम्युनिस्ट पार्टी
19. धुरी	परदुमनसिंह	कांग्रेस
20. धुरी (सरक्षित)	लहनासिंह	कांग्रेस
21. फरीदकोट	हरीन्द्रसिंह	स्वतंत्र
22. जैतों	हीरासिंह	कांग्रेस
23. जीन्द	दलसिंह	कांग्रेस
24. जुलाना	घासीराम	स्वतंत्र
25. कलायात	वृषभान	कांग्रेस
26. कंडाघाट	ज्ञानचन्द	कांग्रेस
27. कंडाघाट (सरक्षित)	रोशनलाल	कांग्रेस
28. कनीना	लालसिंह	कांग्रेस
29. कपूरथला	ठाकुरसिंह	कांग्रेस
30. कोट कपूरा	मंजीतीन्द्रसिंह	कांग्रेस
31. लहरा	प्रीतमसिंह गोजरां	अकाली (क)
32. लहरा (संरक्षित)	प्रीतमसिंह साहूके	अकाली (क)
33. मालेरकोटला	इफ्तखार अली खां	कांग्रेस

(क) मास्टर तारासिंह का दल

(ख) रामां दल

34. मानसा	जंगीरसिंह	कम्युनिस्ट पार्टी
35. मौड़	शमशेरसिंह	कांग्रेस
36. महेन्द्रगढ़	मगलसिंह	कांग्रेस
37. नाभा	शिवदेवसिंह	कांग्रेस
38. नालागढ	सुरेन्द्रसिंह	कांग्रेस
39. नहीयावाला-रामा	चेतसिंह	कांग्रेस
40. नहीयावाला-रामा (सरक्षित)	करतारसिंह	अकाली (क)
41. नगन्न चौधरी	निहालसिंह	कांग्रेस
42. नारनौल	रामसरन चन्द मित्तल	कांग्रेस
43. नरवाना	अलवेलसिंह	स्वतन्त्र
44. नरवाना (सरक्षित)	फकीरिया	कांग्रेस
45. पटियाला शहर	श्रीमती मनमोहन कौर	अकाली (क)
46. पटियाला सदर	रघुवीरसिंह	कांग्रेस
47. फगवाड़ा	हंसराज शर्मा	कांग्रेस
48. फगवाड़ा (सरक्षित)	साधुराम	कांग्रेस
49. फूल	अर्जुनसिंह	कम्युनिस्ट पार्टी
50. फूल (सरक्षित)	धन्नासिंह	अकाली (ख)
51. राजपुरा	प्रेमसिंह	कांग्रेस
52. सफीदों	कलीराम	कांग्रेस
53. समाना	सुरेन्द्रनाथ	स्वतन्त्र
54. समाना (सरक्षित)	प्रीतमसिंह	स्वतन्त्र
55. सगरूर	देवेन्द्रसिंह	कांग्रेस
56. सर्दूलगढ	प्रीतमसिंह	अकाली (क)
57. शेरपुर	गुरबख्शीशसिंह	कांग्रेस
58. सरहन्द	बलवन्तसिंह	कांग्रेस
59. सुलतानपुर	आत्मासिंह	अकाली (क)
60. सुनाम	महेशेन्द्रसिंह	कांग्रेस

राजस्थान

महाराजप्रमुख	मेवाड के महाराणा
राजप्रमुख	महाराजा जयपुर
मंत्री :	
1. मुख्य मत्री, सामान्य अनुशासन, तालमेल, वित्त तथा न्याय विभाग	जयनारायण व्यास*
2. कृषि तथा लगान	मोहनलाल सुखाडिया

(क) मास्टर तारासिंह का दल

(ख) रामा दल

3. सार्वजनिक कार्य, शिक्षा और यातायात — भोलानाथ
4. अन्न, नागरिक पूर्ति और सिंचाई — भोगीलाल पंड्या
5. जंगल, सहयोग, सहायता और पुनर्वास — अमृतलाल यादव
6. श्रम, स्थानीय स्वराज्य चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य — रामकरण जोशी
7. व्यापार और व्यवसाय — कुम्भाराम आर्य

उपमंत्री

1. वित्त तथा न्याय विभाग — चंदनमल वैद्य
2. सामान्य शासन और गृह — नरसिंह कछवाहा

वित्त

(लाखों रुपयों में)

बजट के आंकड़े	आय	व्यय	बचत (+) या घाटा (-)
1950-51 (लेखा)	1,461	1,391	+70
1951-52 (लेखा)	1,551	1,576	—25
1952-53 (संशोधित)	1,750	1,714	+36
1953-54 (बजट)	1,944	1,944	—

शिक्षा

1953-54 में राजस्थान में शिक्षा पर 2,91 90,000 रुपये व्यय हुए। जब कि चार वर्ष पहले यह व्यय केवल 160 लाख रु० था। 1953 में वहां 4,095 प्रारम्भिक स्कूल थे, जिनमें दो लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। माध्यमिक स्कूलों की संख्या 918 थी और उनमें 1,68,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कालेजों की संख्या 9 थी। इनके अतिरिक्त कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कृषि के चार कालिज भी जारी हैं। सामाजिक शिक्षा के 220 केन्द्र काम कर रहे हैं। गत वर्ष दो हाई स्कूलों को इंटरमीजियेट कालेजों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित 97 प्रारम्भिक स्कूलों और 21 माध्यमिक स्कूलों को राज्य की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। राज्य में स्नातकोत्तर ट्रेनिंग कालेज, प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये ट्रेनिंग कालेज, 3 बेसिक मॉडल स्कूल और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिये एक जनता कालेज खोलने का निश्चय किया गया। राजस्थान का पुरातत्व मन्दिर संस्कृत और राजस्थानी पुस्तकों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अन्वेषण कर रहा है और इस संस्था ने 2,500 दुर्लभ पुस्तकें और 2,000 पाण्डुलिपियां एकत्र की हैं। इनमें से कुछ पाण्डुलिपियां प्रकाशित भी की गई हैं।

खाद्यान्न तथा कृषि

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से गत वर्ष तक राजस्थान में किसानों की दशा सुधारने के लिये अनेक कानून बनाये गये। गत वर्ष भूदान यज्ञ बिल पास किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में भूदान यज्ञ आन्दोलन को सफल बनाना है। इसके अनुसार आचार्य विनोबा भावे द्वारा नियुक्त चार से सात व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का बंटवारा करेगी।

गत वर्ष जवाई और मोरेल के बांध पूरे कर लिये गये। इनसे 3 लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई होगी। मोरेल बांध से 2 नालिया निकाली गई है, जिनसे 43 हजार एकड भूमि की सिंचाई होगी। बीकानेर की गंग नहर में सुधार कर उससे 1 लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है। राज्य में 400 नये कूए खोदे गये और सैकड़ों कुओं की मरम्मत की गई। 500 जगहो पर रहट और पम्पिग सेट लगाये गये।

व्यवसाय

गृह उद्योगो से बने माल की खपत के लिये विशेष सुविधाये देने का प्रयत्न किया गया। मारवाड बलिया के सोडियम सल्फेट कारखाने से 14,000 टन रासायनिक पदार्थ भारत के विभिन्न कारखानो में भेजे गये। आदिवासी क्षेत्रो मे गुड बनाने वाले 4 नये केन्द्र खोले गये। शेखावटी भेडो के पालन पोषण के सम्बन्ध मे विशेष ध्यान किया गया। जयपुर के एक कारखाने मे राज्य मे प्राप्त होने वाली 400 किस्म की ऊनो का परीक्षण किया गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

सीकर, लाडनू श्रीमहावीर जी और कासली मे आखो की शल्य चिकित्सा के लिये 4 केन्द्र खोले गये। तपेदिक के इलाज के लिये एक स्वास्थ्यागार खोलने के उद्देश्य से 4 लाख रुपये स्वीकृत हुए और सम्पूर्ण राज्य मे बी० सी० जी० के टीके लगाने का प्रबन्ध किया गया। राज्य में अस्पतालो तथा औषधियो की सख्या इस प्रकार है :—

(1) डाक्टरी अस्पताल तथा औषधालय	शहरों मे 243 गावों में 140
(2) तपेदिक का स्वास्थ्यागार	1 (54 बिस्तरो वाला)
(3) आयुर्वेदिक औषधालय	54
(4) तपेदिक के अस्पताल	4 (172 बिस्तरे)
(5) कोढ के चिकित्सा-केन्द्र	2
(6) मानसिक रोगो के चिकित्सालय	3
(7) वे बीमार, जिन्हें अस्पताल मे रख कर चिकित्सा की गई	1,00,000
(8) वे बीमार जिन्होने अस्पताल से इलाज कराया	60,00,000

राजस्थान विधान सभा

अध्यक्ष : नरोत्तमलाल जोशी

छोटूसिंह (अलवर)
श्रीमती कमला कुमारी (आमेर, क)
अंगदराम (आमेर, ख)
चन्द्रकान्त राव (अतरू मांगरोल)
जयसिंह राणावत (असिन्द)
हिम्मतसिंह (अतरू)
जगतसिंह झाला (बडी सदरी कपासिन)
जयचन्द (बड़ी सदरी कपासिन संरक्षित परिगणित जाति)
हरीराम निनामा (बागीडोरा संरक्षित परिगणित जन जाति)
मुक्तिलाल मोदी (बैरेठ)
लछमनसिंह (बाली)
भैरोंसिंह (बाली देसुरी)

विशम्भरनाथ जोशी (बान्दीकुई)
बद्रीप्रसाद गुप्त (बांसुर)
यशोदादेवी (बासबाडा)
डा० मगलसिंह (बड़ी)
हंसराज जटिया (बडी, सरक्षित परिगणित जाति)
तनसिह (बारमेर, क)
नाथुसिह (बारमेर, ख)
माधोसिह (बारमेर, ग)
सुगनचन्द जैन (बेगुन)
रामजीलाल यादव (बेहरोर)
हंसराज आर्य (भद्रा)
हरीदत्त (भरतपूर)
मोहबतसिह (भावरी)
तेजमल बायना (भीलवाडा)
सग्रामसिह (भीम)
मोतीचन्द खजान्ची (बीकानेर शहर)
जसवन्तसिह (बीकानेर तहसील)
सन्तोषसिह कछवाहा (बिलारा)
छोतरलाल शर्मा (बूदी)
वदपाल त्यागी (छाबरा)
हरलालसिह (चिडावा)
प्रतापसिंह (चित्तौर)
कुम्भाराम चौधरी (चूरू)
प्रभुदयाल (चूरू, सरक्षित परिगणित जाति)
भैरोंसिह (दातराम गढ)
श्रीगोपाल भार्गव (धोलपुर)
मथुरादास (डिडवाना)
मोतीलाल चौधरी (डिडवाना–पर्वतसर)
हरीदेव जोशी (डुगरपुर)
सोभा वालू भील (डूगरपुर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
मोतीराम (गगानगर)
धूलजी भाई भावसर (घाटोल)
लालसिंह सक्तावत (गिरवा)
ऋद्धिचन्द पालीवाल (हिण्डौन)
छांगा (हिण्डौन, संरक्षित परिगणित जाति)
सज्जनसिंह (हिण्डोली)
रामदयाल उपाध्याय (जहाजपुर)
शाह अलीमुद्दीन (जयपुर शहर, क)
रामकिशोर (जयपुर शहर, ख)
गुलाबचन्द कासलीवाल (जयपुर शहर, ग)
नारायण चतुर्वेदी (जयपुर–चाकसू)
हरीशंकर सिद्धान्त शास्त्री (जयपुर चाकसू सरक्षित परिगणित जाति)
मोहनसिह (जैताराम पूर्व-गोजत पूर्व)
हनुवन्तसिह (जयसलमेर)
उमेदसिह (जयतारन उत्तर पश्चिम)
माधासिह (जलोर, क)
हरिसिह (जलोर, ख)
मानसिह (जमुवा रामगढ)
छतरसिह (जसवन्तपुर)
गणपतसिह (जसवन्तपुर-सांचोर)
भगवानसिह तरंगी (झालरापाटन)
माधोलाल मेहेर (झालरापाटन सरक्षित परिगणित जाति)
द्वारकादास पुरोहित (जोधपुर शहर क)
हरिकृष्ण व्यास (जोधपुर शहर, ख)
मगलसिह (जोधपुर तहसील उत्तर)
नरसिंह कछवाहा (जोधपुर तहसील दक्षिण)
मुहम्मद ब्राहीम (कामन)
ब्रिजेन्द्रपाल (करौली)
शिवदानसिह (खमनोर)
झुमारसिह (खानपुर)
रघुवीरसिह (खेतडी)
महादेव प्रसाद (खेतडी, सरक्षित परिगणित जाति)
विजयसिह (कुवलगढ)
रघुराजसिह (किशनगज)
जयनारायण व्यास* (किशनगढ)
हजारीलाल (कोटपुतली)
मानसिह (कुम्हेर)
बलवीर (लछमनगढ)

नारायणलाल (लछमनगढ़, संरक्षित परिगणित जाति)
भोलानाथ (लछमनगढ राजगढ)
सम्पतराम (लछमन गढ़ राजगढ़ संरक्षित परिगणित जाति)
दिलीपसिंह (लाडपुरा)
कंवरलाल जेलिया (लाडपुरा, सरक्षित परिगणित जाति)
रामकरन जोशी (लालसोट-दौसा)
रामलाल बसीवाल (लालसोट-दौसा, सरक्षित परिगणित जाति)
उदयलाल बंदिया (लमादिया)
हीरालाल पल्लीवाल (महुवा)
वीरेन्द्रनाथ (मलारना चौड)
दामोदरलाल (मालपुरा)
चुन्नीलाल (मांडल)
[illegible] बिजोलिया (माण्डलगढ)
[illegible] यादव (मण्डावर)
[illegible] (मनोहर थाना)
भोपालसिंह (मेड़ता पूर्व)
नाथूराम मिर्धा (मेड़ता पश्चिम)
श्यामलाल गोयल (नादोती)
गोपीलाल यादव (नगर)
रामनिवास मिर्धा (नागौर पूर्व)
केसरीसिंह (नागौर पश्चिम)
भीमसिंह (नवलगढ)
किशनलाल शाह (नात्रा)
लादूराम चौधरी (नीम का थाना, क)
रूपनारायण (नीम का थाना, ख)
कपिलदेव (नीम का थाना, ग)
मनफूलसिंह (नोहर)
कानसिंह (नोखा)
विशनसिंह (पाली—सोजत)
चांदमल महता (परबतसर)
बद्रीलाल (प्रतापगढ-नीम्बाहेड़ा)
मन्ना भील (परबतसर-नीम्बाहेड़ा, संरक्षित परिगणित जन जाति)
केसरीसिंह (पाटन)
अवनीकुमार (फागी)
हिम्मतसिंह (फलोदी)
तेजराज सिंह (पीपलदा)
गुरदयालसिंह सन्धु, (रायसिंहनगर करनपुर)
धरमपाल (रायसिंहनगर—करनपुर, सरक्षित परिगणित जाति)
भैरोंसिंह (राजसमन्द रेलमगारा)
अमृतलाल यादव (राजसमन्द, रेलमगरा, सरक्षित परिगणित जाति)
दुर्लभसिंह (रामगढ)
महादेवप्रसाद एम० पण्डित (रतनगढ)
श्रीभानसिंह (रूपबास)
भानुप्रताप सिंह (रूपनगर)
रामचन्द्र चौधरी (सादुलगढ)
भोगीलाल पण्डित (सागवारा)
राजनलाल (सायरा)
दीनबन्धु परमार (सायरा, संरक्षित परिगणित जाति)
मुहम्मद अब्दुल हादी (सांचोर)
लालबहादुर (सगोद)
धरमचन्द (सरोनरा)
मोहनलाल (शारदा—सालम्बर)
लक्ष्मण भील (सराड़ा, सालम्बर सरक्षित परिगणित जन जाति)
चन्दनमल बेद (सरदार शहर)
श्रीदास गोयल (सवाई माधोपुर)
शम्भूसिंह (शाहाड़ा)
अमरसिंह (शाहपुरा—बानेडा)
कस्तूरचन्द (शाहपुरा-बानेडा, सरक्षित परिगणित जाति)
अर्जुनसिंह (शिवगंज)
खेतसिंह (शेरगढ़)
ईश्वरसिंह (सीकर तहसील)
राधाकृष्ण मारू (सीकर कस्बा)
त्रिवेणी श्याम शर्मा (सिकराई)

जवानसिंह (सिरोही)
बृजसुन्दर शर्मा (सिरोज)
मोटाराम चौधरी (सिवाना)
केशरीसिंह (सोजत)
भैरोंसिह खेजड़ला (सोजत—देसूरी)
प्रताप सिंह (सुजानगढ़)
भवानीसहाय (थानागाजी)
रावराजा सरदारसिंह (उनियारा)
घासीराम (तिजरा)
रामरतन डिक्कीवाल (टोंक)
लालुराम (टोंक, संरक्षित परिगणित जाति)
देवीसिंह (उदयपुर)
मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर शहर)
आर० एस० दिलीपसिह (उन्ठाला)
घीसीसिंह कटाला (वेर)
तेजपाल (वेर, संरक्षित परिगणित जाति)

सौराष्ट्र

राजप्रमुख नवानगर के जामसाहब

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, मंत्रीमंडल तथा तालमेल विभाग, लगान और सेवाएं . . . . . यू० एन० धेबर
2. गृह, संवादवहन तथा सूचना . . आर० यू० पारिख
3. वित्त, लेखा परीक्षा तथा आंतरिक कर . . एम० एम० शाह
4. शिक्षा और सार्वजनिक कार्य. . . . . जे० के० मोदी
5. कानून, न्याय और चिकित्सा . . . डी० टी० दवे
6. पुनर्वास, व्यापार और व्यवसाय, अन्न पूर्ति तथा श्रम जी० सी० ओझा
7. विकास, योजना, स्थानीय स्वराज्य, तथा पिछड़ी जातियां आर० एम० अदानी

15 फरवरी 1948 के 200 रजवाड़ों के मिश्रण से सौराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था।

वित्त (लाख रुपयों में)

बजट के आंकडे	आय	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1950-51 (लेखा) .	777	742	-35
1951-52 (लेखा) .	752	863	-111
1952-53 (संशोधित) .	984	1,166	-182
1953-54 (बजट) .	942	995	-53

शिक्षा

शिक्षा विस्तार की नई योजना के अनुसार प्रारम्भिक स्कूलों में 75 नये अध्यापक नियुक्त किये गये तथा प्रारम्भिक स्कूलों के 311 अध्यापकों और 168 विद्यार्थियों

को ट्रेनिंग कालेज में भरती किया गया। गत वर्ष नये 100 प्रारम्भिक स्कूल खोले गये, इस तरह उनकी सख्या 2,486 तक पहुच गई। विद्यार्थियो में हाथ से काम करने की रुचि उत्पन्न करने के लिये प्रारम्भिक स्कूलों मे 10,000 चर्खे बांटे गये। राज्य में सामाजिक शिक्षा देने के 240 केन्द्र खोले गये। 1952-53 मे 7,04,000 रुपये यूनिवर्सिटी शिक्षा पर, 27,78,000 रुपये माध्यमिक शिक्षा पर और 70,21,000 रुपये प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किये गये। शिक्षा पर कुल 1,22,00,000 रुपये व्यय हुए।

खाद्यान्न तथा कृषि

कृषि के सम्बन्ध में अनेक अनुसन्धान तथा ट्रेनिंग स्कीमें जारी की गईं। ज्वार और बाजरा के सम्बन्ध में परीक्षण किये गये। आलू और रूई की कृषि के सम्बन्ध में विस्तार और सुधार के अतिरिक्त घास वाले मैदानों को सुधार कर वहां दुग्धशालायें खोलने की योजना बनाई गई। वर्तमान जंगल का सुधार और नये जगल का बोने का प्रयत्न भी किया गया।

व्यवसाय

पचवर्षीय आयोजना के अनुसार सौराष्ट्र मे 21,85,00,000 रुपये व्यय किये जायेंगे। इसमे से 14,80,000 रुपये व्यवसायों के विकास पर व्यय होगे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

हैजे और चेचक से बचने के लिये राज्य भर में टीके लगाये गये। मलेरिया की रोकथाम के लिये 22 केन्द्र खोले गये, जो 1,257 गावो मे काम कर रहे है। तपेदिक की रोकथाम के सम्बन्ध मे 63,895 व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 21,285 व्यक्तियों के बी० सी० जी० के टीके लगाये गये। गत वर्ष 25 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई थी, जिन मे से 14 मे कार्य जारी हो गया है। जिन गावो मे औषधालय खोलना सभव न था, वहा दवाइयो के बक्स बाटे गये है।

सौराष्ट्र विधान सभा

अध्यक्ष : मगनलाल जोशी

गजानन भवानीशकर जोशी (बावरा)
केशवजी अरजण पटेल (भाणवड-जमाजोधपुर)
व्रजलाल गोकुलदास वोरा (भावनगर शहर पूर्व)
अजीतराय मानशकर ओझा (भावनगर शहर पश्चिम)
करसन जराम कणबी (भावनगर-दसक्रोई सिहोर)
भूपत भाई व्रजलाल देसाई (दसाड़ा लखतर)
वजुभाई मणिलाल शाह (घोगाजी)
मनहरलाल मनसुखलाल शाह (धावधा)
हसराज जीवनदास कामाणी (धोलजोडिया)
गोविन्दजी केशवजी पटेल (गोडल कुकावाव)
हरिभाई राणाभाई भास्कर (गोंडल-कुकावाव सरक्षित परिगणित जाति)
लाभशकर मगनलाल शुक्ल (हलवद-भुलि)
कनुभाई जीवनलाल लहेरी (जाफराबाद-राजुला)
रतनशी भाजी पटेल (जामजोधपुर-लालपुर)

अब्दुल्लारखा हजा हमीरका (जामनगर-शहर पूर्व)
लवचन्द परसोत्तम तम्बोली (जामनगर शहर पश्चिम)
माननलाल भगवानजी जोशी (जामनगर तलुका)
प्रभातगिरि गुलाबगिरि गोसाई (जसदण)
बाबुभाई प्राणजीवन वैद्य (जेतपुर)
परमानन्ददास जीवन भाई कथोचा (जूनागढ-भेसान)
चितरंजन रघुनाथ राजा (जूनागढ शहर)
कल्याणजी हरजी वसन्त (कल्याणपुर)
भीमजी रुडाभाई चावेला (कन्डोरणा-मायावदर)
रतुभाई मूलशंकर अदाणी (केशोद)
चन्द्रसिंह जी दीपसिंहजी जडेजा (कालावड़-ध्रोल)
हरिलाल रामजी नकुम (खम्भालिया)
अमूलखराय कुशलचन्द खिमाणी (कुन्डला)
दयाशंकर त्रिकमजी दवे (कुटियाणा-राणावाव)
लिला जननत सवाणी (लाठी)
मोहनलरमशी वाघाणी (लीलिया)
लाभशंकर देवशंकर आचार्य (लिम्बडी-लखतर)
घनश्याम लाल छोटालाल ओझा (लिम्बडी-वठवाण)
हमीर जीवा वणकर (लिम्बडी-वठवाण, संरक्षित परिगणित जाति)
जादवजी केशवजी मोदी (महुवा तालुका)
जसवन्तराय नानुभाई मेहता (माहुवा-कस्बा)
कानजी कवरा मोरी (मालिया-हाटना-मेन्दरडा)
श्रीमती जयाबहन वजुभाई शाह (मगरौल)
राजेन्द्र रुगनाथ राय (मौरवी मालिया)
अब्दुल्ला हमीर काजडिया (मौरवी मालिया — सरक्षित परिगणित जनजाति)
बालकृष्ण दिनमणि शकर शुक्ल (पड़धरा-लोधिका-कोटडा-सांगाणी)
जोरसिंह कसलसिंह इन्द्राणी (पालीताणा चौक)
मोतीलाल गोर्धनदास जोशी (पाटन-वीरावल तालुका)
मथुरादास गोर्धनदास गुप्त (पोरबन्दर शहर)
मालदेव जी मण्डलिक जी ओडेद्रा (पोरबन्दर तालुका)
चिमनलाल नागरदास शाह (राजकोट शहर उत्तर)
गिरधरलाल भवानभाई कोटक (राजकोट शहर दक्षिण)
कुरजी जादवजी वेकरिया (राजकोट तालुका)
रसिकलाल उमेदचन्द परीख (मायला-चोटिला
छगनलाल लालजीभाई गोगाणी (सोनगढ़-उमराला)
प्रभुदास रामजी मेहता (तलाजा दाठा)
हमीर मरमण सोलंकी (तालाला)
मुरारभाई कालुभाई वरू (उना)
उछरंगराय नवलशंकर ढेबर (उपलोटा)
प्रेमचन्द मगनलाल शाह (वल्लभीपुर-गढडा)
काजी मवली रेवार (वल्लभीपुर-गघड़ा, सरक्षित परिगणित जाति)
रामजी परबत विकाणी (वन्थली-माणावदर बाटवा)
जीवराज विश्राम गोहेल, (वन्थली-माणावदर बाटवा, सरक्षित, परिगणित जाति)
श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनमेहता (बेरावल कस्बा)
नरसी वेलजी बोरड (विसावदर)
शान्तिलाल राजपाल शाह (वाकानेर)

तिरुवांकुर-कोचीन

राजप्रमुख — तिरुवांकुर के महाराज

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, सामान्य व्यवस्था, कानून, योजना, न्याय, सूचना, शिक्षा, खाद्य, नागरिक पूर्ति, व्यवस्थापन, निर्वाचन, देवमंदिर इत्यादि — ए० थानु पिल्लई

2. वित्त, लगान, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय और व्यापार, खनिज, जंगल, आन्तरिक कर तथा बन्दोबस्त — पी० एस० नटराज पिल्लई

3. सार्वजनिक कार्य, बिजली, यातायात, संवाद वहन, बन्दरगाह तथा रेलवे — ए० अच्युतन

4. स्वास्थ्य, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम सुधार, हरिजन कल्याण पिछड़ी जातियों की रक्षा, श्रम, रजिस्ट्रेशन, सहयोग तथा निवास — पी० के० कुंजु

तिरुवाकुर और कोचीन रियासतों के मेल से बना यह राज्य 1 जुलाई 1949 को भारत यूनियन में सम्मिलित हुआ।

वित्त (लाख रुपयों में)

बजट के आंकड़े	आय	व्यय	अतिरिक्त (+) घाटा (—)
1950-51 (लेखा)	1,399	1,274	+125
1951-52 (लेखा)	1,791	1,363	+428
1952-53 (संशोधित)	1,673	1,683	—10
1953-54 (बजट)	1,714	1,728	—14

शिक्षा

1952-53 में तिरुवांकुर कोचीन में शिक्षा पर 370 लाख रुपये व्यय किये गये। राज्य के 6 से 11 वर्ष तक की आयु के 98·8 प्रतिशत बालक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस का अभिप्राय यह है कि राज्य भर में शिक्षा व्यवहार रूप में अनिवार्य हो गई है। तिरुवाकुर कोचीन में इस समय 39 कालेज हैं, जिनमें चिकित्सा, इंजीनियरिंग, टैक्निकल कालेज आदि सम्मिलित हैं। गत वर्ष तक वहां हाई स्कूलों की संख्या 552 थी, माध्यमिक स्कूलों की 792, प्रारम्भिक स्कूलों की 4,133, संस्कृत स्कूलों की 32 और ट्रेनिंग संस्थाओं की 63। प्रारम्भिक स्कूलों में 13,65,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 20 प्रारम्भिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा जारी की गई तथा 57 अध्यापकों को बेसिक ट्रेनिंग दी गई।

परिगणित जाति के विद्यार्थियों के लिये 3 लाख रुपये की सहायता दी गई। उनके शुल्क भी माफ कर दिये गये। उन्हें टैक्निकल, व्यवसायिक तथा व्यापारिक शिक्षा देने की सुविधायें भी दी गई। इस सहायता पर 2,50,000 रुपये व्यय किये गये।

खाद्यान्न तथा कृषि

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत 37 लाख रुपयों का 13,950 टन खाद किसानों को बांटा गया। इससे चावल की उपज में 20,000 टनों की वृद्धि हुई। गहरी कृषि के उद्देश्य से किसानों को प्रति नये कुए के पीछे 600 रुपये दिये गये। 40 नये कुये खोदे गये और 35 की खुदाई अभी जारी है।

व्यवसाय

राज्य मे व्यावसायिक सहायता देने के लिये एक व्यावसायिक वित्त कारपोरेशन स्थापित किया गया, जिसे एक करोड रुपया दिया गया । 1952-53 मे राज्य में निम्नलिखित 3 नये कारखाने खोले गये : कोरट्टी में जमना थ्रेड मिल्स, तिरुवांकुर कोचीन कैमिकल्स मिल तथा अलवाये मे रेअर अर्थ फैक्टरी । पहली फैक्टरी में इतना सूत तैयार होगा कि उससे राज्य की सब आवश्यकताये पूरी हो जायेगी । दूसरी फैक्टरी 7,000 टन कास्टिक सोडा प्रति वर्ष तैयार कर रही है । तीसरी फैक्टरी का उद्घाटन दिसम्बर, 1952 मे प्रधान मत्री ने किया था । यह 1,680 टन क्लोराइड बना सकती है ।

गृह उद्योग बोर्ड की ओर से करघा, शहद, तेल आदि व्यवसायो के विकास के प्रयत्न किये गये । पंचवर्षीय आयोजना अनुसार सहयोग के ढग पर नारियल के जटा व्यवसाय को पुर्नसगठित किया जायगा । व्यावसायिक मदी पर नियत्रण रखने के लिये राज्य ने भरसक प्रयत्न किये । 5 लाख रुपये मजदूरो को सहायता के रूप मे बाटे गये । 26,000 रुपये वर्तन व्यवसाय के सगठन पर व्यय किये गये ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 142 लाख रुपये व्यय हुए । इस समय राज्य मे 234 चिकित्सा सस्थाये हैं । इनमे दो बडे तपेदिक अस्पताल, एक कोढ़ स्वास्थ्यागार, 3 कोढ चिकित्सालय, दो मानसिक रोगों के औषधालय, 6 बच्चो और औरतो के औषधालय और एक आखो का अस्पताल भी सम्मिलित हैं । गत वर्ष 15 लाख व्यक्तियो को चेचक का टीका लगाया गया । हैजा तथा मलेरिया की रोकथाम के लिये प्रयत्न किये गये । तपेदिक की रोकथाम के लिये 8,30,000 व्यक्तियो की परीक्षा की गई और 3,31,000 व्यक्तियों को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया ।

त्रिवेन्द्रम की सार्वजनिक स्वास्थ्य लेबोरेटरी मे बडी सफलता से तथा बडे पैमाने पर चेचक, हैजा आदि के निरोध के टीके तैयार किये जा रहे है ।

गत वर्ष राज्य में 11 आयुर्वेदिक अस्पताल, 4 आयुर्वेदिक औषधालय, 341 वैद्यशालाये, तथा 2 फार्मेसिया जारी थी । दो औषधालयो का दर्जा ऊचा किया गया तथा 26 नये औषधालय खोले गये ।

तरुवांकुरि-कोचीन विधान सभा

	निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
1.	अगस्तीस्वरम . . .	पी० ताणुलिंग नाडर	तिरुवाकुर तामिलनाड काग्रेस (ति० ता० का०)
2.	अलनगाड . . .	गोपाल मेनन	काग्रेस
3.	अलप्पी 1 . . .	के० सी० जार्ज	कम्युनिस्ट
4.	अलप्पी 2 . . .	टी० वी० टामस	कम्युनिस्ट
5.	अलवाए . . .	टी० ओ० बावा	काग्रेस

	निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
	अम्बल पूझा . . .	पी० नारायण पोट्टी	क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (क्रा० सो० पा०)
7.	अरूर . . .	अवीराकन	स्वतंत्र
8.	अट्टिंगल . .	आर० प्रकाशम	कम्युनिस्ट
9.	भरनीकाबू . . .	टी० भासकरन पिल्लइ	कम्युनिस्ट
10.	भरनीकाबू (सरक्षित) . .	कुट्टप्पन	कम्युनिस्ट
11.	चायामगलम . .	वी० गगाधरन	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
12	चालकुडी .	पनामपिल्ली गोविंद मेनन	कांग्रेस
13.	चगना चैरी	एन० परमेश्वरम पिल्लई	काग्रेस
14.	चवरा .	बेबी जौन	क्रा० सो० पा०
15.	चेगन्नूर . .	सी० के० रामचन्द्रन नैयर	प्र० सो० पा०
16.	चेगन्नूर (सरक्षित) .	पी० के० कुजाय्यन	कम्युनिस्ट
17.	चेरपू .	जोसफ मडासरी	स्वतंत्र
18.	चिर्रयिंकिल .	यू० नीलकण्ठन	स्वतंत्र
19.	चित्तूर	ए० आर० मेनन	काग्रेस
20	कोलाचेल . . .	टाम्पसन थमीराज डेनियल	नि० ता० का०
21.	क्रागनूर . . .	अब्दुल कादिर	काग्रेस
22.	देवीकोलम .	शेषादरी नाथ शर्मा	नि ता का
23.	देवीकोलम (सरक्षित) .	तनकय्या	नि ता का
24	एलानकुलम . .	एम० पद्मनाभ मेनन	स्वतंत्र
25	एरवीपुरम . . .	पी० के० सुकमारन	कम्युनिस्ट
26	एरवीपुरम (संरक्षित) .	चन्द्रशेखरम्	क्रा सो पा
27.	एरणाकुलम . . .	ओ० आर० चुम्मार	काग्रेस
28.	एट्टमानूर . . .	वी० वी० सेवस्टियन .	कांग्रेस
29.	एझूमात्तूर . . .	टी० एम० वर्गीस .	काग्रेस
30.	इरिनजालकूडा . .	के० के० बालकृष्णन .	कम्युनिस्ट
31.	इरिनजालकूडा (संरक्षित) .	पी० के० चाथन .	काग्रेस
32.	कडपरा . . .	वी०पी०परमेश्वरम नाम्पूथिरी	प्र० सो० पा०
33.	काडुथूरूथी . . .	के० एम० जार्ज . .	कांग्रेस
34.	कडुथूरूथी (संरक्षित) . .	टी० टी० केशवन शास्त्री	कांग्रेस
35.	कल्लूप्पारा . . .	एम० एम० मथाई	काग्रेस
36.	कन्याम्पूर . . .	एन० के० कुमारन्	कांग्रस
37.	कांजीरपल्ली . . .	टामस . . .	काग्रेस
38.	करकुलम . . .	आर बालकृष्ण पिल्लई .	कम्युनिस्ट

	निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
39	कार्त्तिकापल्ली . . .	ए० अच्यूतन	प्र० सो० पा०
40.	करुनागपल्ली . . .	ए० ए० रहीम . .	कांग्रेस
41.	किल्लीयूर . . .	आर० पोन्नप्पन नाडर	ति० ता० कां०
42.	कोडाकारा . . .	पोलीयेदेथ केशव मेनन	प्र० सो० पा०
43.	कोल्लेन्कोडे . . .	अलैक्जेंडर मैनुअल साइमन	ति० ता० कां०
44.	कोतकुलांगरा . . .	एम० ए० एन्थनी	कांग्रेस
45.	कोतमंगलम . . .	मचनाथ प्रभु . .	प्र० सो० पा०
46.	कोट्टारकरा . . .	बी० बी० पन्डारथिल	क्रां० सो० पा०
47.	कोट्टयम . . .	पी० भासकरन नैयर	कम्युनिस्ट
48.	कोट्टुकाल . . .	बी० विवेकानन्दन . .	स्वतंत्र
49.	कृष्णपुरम् . . .	पी० के० कुंजू .	प्र० सो० पा०
50.	कुमारमंगलम . . .	सी० ए० मैथ्यू . .	कांग्रेस
51.	कुन्नमकुलम . .	टी० के० कृष्णन . .	कम्युनिस्ट
52.	कुन्नत्तुनाड . . .	के० एम० चाको	कांग्रेस
53.	कुन्नत्तुनाड (संरक्षित) . .	के० कोचुकुटन	कांग्रेस
54.	कुन्नोतुकाल . . .	के० कृष्ण पिल्लई .	प्र० सो० पा०
55.	कुन्नात्तुर . .	पी० आर० माधवन पिल्लई	कम्युनिस्ट
56.	कुन्नात्तुर (संरक्षित) . .	के० एस० कृष्णा शास्त्री	क्रा० सो० पा०
57.	कुरीची . . .	पी० जे० सेवस्टियन .	कांग्रेस
58.	मानालूर . . .	कन्नोठ करुणाकरण .	कांग्रेस
59.	मणिमला . . .	के० एम० कोरा . .	कांग्रेस
60.	मरारीकोलम . . .	आर० सुगतन . .	कम्युनिस्ट
61.	मतानचेरी . . .	जे० अनन्त भट्ट . .	कांग्रेस
62.	मावेलीकरा . . .	आर० शंकरनारायन् ताम्पी	कम्युनिस्ट
63.	मिनायिल . . .	के० एम० चाण्डी . .	कांग्रेस
64.	मवात्तुपुझा . . .	एम० वी० चेरियन .	कांग्रेस
65.	नागरकोइल . . .	डी० अनन्तरामन	ति० ता० कां०
66.	नारक्काल . . .	के० सी० अब्राहम	कांग्रेस
67.	नेडूमनगड . . .	एन० नेलिकांतारु-यंड रायिल	कम्युनिस्ट
68.	नीण्डकरा . . .	ए० चिदाम्बरनाथ नाडर	ति० ता० कां०
69.	नेम्मारा . . .	के० ए० शिवराम भारती	प्र० सो० पा०
70.	नेमम . . .	पी० विश्वमभरन्	प्र० सो० पा०
71.	नय्यातिकर . . .	एम० भास्करन नैय्यर	कांग्रेस
72.	ओल्लूर . .	पी० आर० कृष्णन्	कांग्रेस

निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
73. ओमल्लूर . . .	एन० जी० चाको .	कांग्रेस
74. ऊल्लूर . . .	वी० श्रीधरन् . .	कम्युनिस्ट
75. उल्लूर (संरक्षित) . .	पी० कुजन् . .	प्र० सो० पा०
76. पद्मनाभपुरम् . .	नूर मुहम्मद . .	ति० ता० का
77. पल्लीवासल . . .	वी० जे० जोसफ .	कांग्रेस
78. पल्लीविरुती . . .	अलैक्जेंडर परम्बितरा .	कांग्रेस
79 पालोडे . . .	एन० चन्द्रशेखरन् नैयर .	प्र० सो० पा०
80 पारस्माला . . .	आर० कुंजन नाडर .	ति० ता० कां०
81. परवुर . . .	रविन्द्रन् . .	कम्युनिस्ट
82. पारूर . . .	के० ए० बालन . .	कम्युनिस्ट
83. पठनमतिट्टा . . .	पी० एस० वसुदेवन पिल्लई .	कांग्रेस
84. पठनमपुरम . . .	के० वेलायुधन नैयर .	कांग्रेस
85. पत्तियुर . . .	पी० के० यशोधरन .	का० सो० पा०
86 पेरम्बावूर . . .	के० पी० उरूमेस . .	कांग्रेस
87. पूजार . . .	ए० जे० जोण . .	कांग्रेस
88. पूनलूर . . .	पी० गोपालन	स्वतंत्र
89. पुतुकाड . . .	टी० पी० सीतारमय्यार	कांग्रेस
90. पुनुप्पल्ली . . .	टामस . .	कांग्रेस
91 कुईलौ . . .	टी० के० दिवाकरन्	का० सो० पा०
92. रामपुरम् . . .	जोसफ चाजीकाड . .	स्वतंत्र
93. रान्नी . .	वियाला एडीकुला	प्र० सो० पा०
94. शेनकोट्टाह . . .	के० सत्तानाथ कार्यालर	स्वतंत्र
95. शेरतल्लइ . . .	श्रीमती के० आर० गौरी .	कम्युनिस्ट
96. ताकजी . . .	नारायण कुरूप . .	कांग्रेस
97. तिरूवल्ला . . .	चन्द्रशेखरन पिल्लई .	कांग्रेस
98. तिरूवापू . . .	राघव कुरूप . .	कम्युनिस्ट
99. तिरुवट्टार . . .	पी० रामास्वामी पिल्लइ	कांग्रेस
100. तोडुपुजा . . .	ए० सी० चाको . .	कांग्रेस
101. तोवला . . .	टी० एस० रामास्वामी पिल्लइ	प्र० सो० पा०
102. त्रिचूर . . .	पी० पी० ऐन्थनी . .	कांग्रेस
103 त्रिक्कडबूर . . .	प्राक्कुलम भासी .	कां० सो० पा०
104. त्रिवेन्द्रम 1 . . .	पी० एस० नटराज पिल्लइ	प्र० सो० पा०
105. त्रिवेन्द्रम 2 . .	ए० थानु पिल्लइ . .	प्र० सो० पा०
106. त्रिवेन्द्रम 3 . . .	के० बालाकृष्णन्	कां० सो० पा०
107. तुरावूर . . .	सी० जी० सदाशिवन .	कम्युनिस्ट

निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
108. वैकम . . .	सी० के० विश्वनाथन .	कम्युनिस्ट
109. वरकला . . .	टी० ए० मजीद . .	स्वतंत्र
110. वरकला (संरक्षित) . .	कोचू कुंजू .	प्र० सो० पा०
111. वझूर . . .	के० नारायण कुरूप .	प्र० सो० पा०
112. वेलियम . . .	डी० दामोदरन् पोट्टी .	प्र० सो० पा०
113. विजयपुरम . . .	पी० एम० मारकोस .	कांग्रेस
114. विलवंकोड . . .	एम० विलियम .	ति० ता० कां०
115. विय्यूर . . .	के० आई० वैलायुधन .	कांग्रेस
116. वडक्कानचेरी . . .	वी० के० अच्युत मेनोन .	कांग्रेस
117. वडक्कानचेरी संरक्षित . .	सी० सी० अय्याप्पेन .	कम्युनिस्ट
118. अल्पमत . .	ऐन्थनी ऐन्ड्रयू डेनियल लुइज़	नामजद

सत्ताईसवां अध्याय

'ग' भाग के राज्य तथा 'घ' भाग के प्रदेश

अजमेर

चीफ कमिश्नर — एम० के० कृपलानी

मंत्री

1. मुख्य मंत्री — हरिभाऊ उपाध्याय
2. गृह, वित्त तथा सार्वजनिक कार्य विभाग — बालकृष्ण कौल
3. शिक्षा, लगान तथा स्थानीय स्वराज्य — बृजमोहनलाल शर्मा

अजमेर राज्य पहले अजमेर-मारवाड़ नाम से पुकारा जाता था। इस में अजमेर, ब्यावर, और केकड़ी के तीन सब-डिवीज़न सम्मिलित हैं।

वित्त (हज़ार रुपयों में)

बजट के आंकड़े	आय	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1952-53 (सशोधित) . .	22,629	22,269	+360
1953-54 (बजट) . .	18,876	18,876	—

शिक्षा

गत वर्ष केकड़ी सब-डिवीजन में 65 नए बेसिक स्कूल खोले गए और देहाती हलकों के 115 प्रारम्भिक स्कूलो को बेसिक स्कूलो मे परिवर्तित कर दिया गया। इस तरह राज्य में बेसिक संस्थाओं की संख्या 390 तक पहुंच गई और उन के विद्यार्थियों की संख्या 13,600 हो गई। राज्य में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को जारी करने का प्रयत्न किया जा रहा है और छोटे बेसिक स्कूलो का नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। सामाजिक शिक्षा के कार्यों का विस्तार किया गया। देहाती स्कूलों में अध्यापकों से सामाजिक शिक्षा का काम भी लिया गया। इस तरह गत वर्ष राज्य भर मे कुल 1,000 सामाजिक शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे थे।

खाद्यान्न तथा कृषि

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत राज्य के किसानों को 51,769 मन बीज 162 मन अमोनियम सल्फेट, 48 मन खली और 6 मन सुपर फास्फेट बांटा गया। साथ ही 118 नए कुएं खोदे गये और 347 पुराने कुओं की मरम्मत की गई। इस कार्य के लिए किसानों को तकावी बांटी गई। 2,266 पुराने कुओं को अधिक गहरा किया गया। टिड्डियों की रोकथाम के भरसक प्रयत्न किये गये और गांव वालों को अच्छा ताड़ गुड बनाने की शिक्षा दी गई।

व्यवसाय

1952-53 में 25 व्यावसायिक झगड़े आपसी समझौते द्वारा निबटाये गए। कुछ व्यवसायों के बारे में गणनाएं एकत्र की गईं तथा वस्त्र व्यवसाय और ऊन शुद्ध करने के व्यवसाय में कम से कम वेतन नियत कर दिया गया। आजकल 4 कपड़ा मिलों और दो होज़री फैक्टरियों में कार्यकर्ताओं का प्राविडेण्ट फण्ड कानून लागू है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

अजमेर के विक्टोरिया अस्पताल के साथ एक तपेदिक क्लिनिक भी जारी किया गया। बिजयनगर के औषधालय को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया और उस में अतिरिक्त स्टाफ भी नियत किया गया। देहाती क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम का प्रयत्न किया गया। तपेदिक की रोकथाम के लिए बी० सी० जी० का आन्दोलन जारी किया तथा एक लाख से ऊपर व्यक्तियों को टीका लगाया गया।

अजमेर वि ान सभा

अध्यक्ष—भागीरथसिंह

अर्जुनदास (अजमेर 1, दक्षिण-पश्चिम)
परसराम (अजमेर 1, दक्षिण-पश्चिम सरक्षित परिगणित जाति)
बालकृष्ण कौल (अजमेर 2, पूर्व)
हरजीतलाल (अजमेर 2 पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)
रमेशचन्द्र भार्गव (अजमेर 3, कालाबाग)
श्रीमनदास (अजमेर 4, टाऊन हाल)
अम्बालाल (अजमेर 5, नयाबाजार)
सैयद अब्बास अली (अजमेर 6, ढाई दिन का झोपड़ा)
कल्याणसिंह (भिनाय)
ब्रजमोहन लाल शर्मा (ब्यावर शहर, उत्तर)
जगन्नाथ शर्मा (ब्यावर शहर, दक्षिण)
छगनलाल गैना (देवलिया कलां)
हिम्मत अली (डेराठू)
रिक्त (गगवाना)
चिमनसिंह भाटी (जवाजा)
भागीरथसिंह (जेठाना)
हजारी (जेठाना, संरक्षित परिगणित जाति)
जेठामल (केकड़ी)
सेवादास (केकड़ी, सरक्षित परिगणित जाति)
नारायणसिंह (मसूदा)
सूर्यमल मौर्य (मसूदा, सरक्षित परिगणित जाति)
महेन्द्रसिंह पवार (नसीराबाद)
लक्ष्मीनारायण जी० जोनवाल (नसीराबाद, सरक्षित परिगणित जाति)
गणपति सिंह (नयानगर)
शिवनारायण सिंह (पुष्कर उत्तर)
जयनारायण शर्मा (पुष्कर दक्षिण)
लक्ष्मणसिंह (सावर)
वली मुहम्मद (शामगढ़)
हरिभाऊ उपाध्याय (श्रीनगर)
प्रेमसिंह (टाडगढ)

बिलासपुर

चीफ कमिश्नर **श्रीचन्द छाबड़ा**

बिलासपुर पहले पंजाब की रियासतों में था, अब 12 अक्तूबर 1948 से केन्द्र द्वारा शासित राज्य बन गया है

शिक्षा

गत वर्ष बिलासपुर मे एक इटरमिजिएट कालेज, 4 माध्यमिक तथा 6 प्रारम्भिक स्कूल नए खोले गए। एक ग्रामीण स्कूल तथा एक लड़कियो के माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया। इस के अतिरिक्त एक ट्रेनिंग कालेज तथा घुमारबिन मे एक जनता कालेज खोला गया। पेशों की तथा टेक्निकल शिक्षा देने के लिये 100-100 रुपये की पांच छात्रवृत्तिया स्वीकार की गईं। ग्रामीण क्षेत्रो मे एक केन्द्रीय वयस्क शिक्षा केन्द्र के अतिरिक्त 4 नए केन्द्र खोले गए। बिलासपुर मे एक केन्द्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय खोला गया।

खाद्यान्न तथा कृषि

बिलासपुर के लिये भारत सरकार ने उपज प्रतियोगिता, बीज मिश्रण और हरे खाद की स्कीमे स्वीकार की। ज्वार की उपज 1,953 मन हो गई जो पहले से लगभग तीन गुना है। राज्य मे कृषि के विकास के लिये सामूहिक योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 नई स्कीमे जारी की गई।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष राज्य मे दो जच्चा केन्द्र, दो एलोपैथिक औषधालय और एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया। 4 व्यक्तियो को हिमाचल प्रदेश मे सुश्रुषा की शिक्षा के लिये भेजा गया।

भोपाल

चीफ कमिश्नर . . . भगवानसहाय

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, गृह, शिक्षा, लगान, शासन, कानून, न्याय, विकास, आयोजना, वित्त, श्रम, व्यवसाय, आन्तरिक कर और कृषि . . . . शकरदयाल शर्मा
2. अन्न, नागरिक पूर्ति, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य, सार्वजनिक कार्य, तथा सिंचाई . . इनायतउल्लाखान तरज़ी मशरिकी

उप-मंत्री

1. जगल, सहयोग तथा हरिजन उद्धार . . उमरावसिह

भोपाल का शासन 1 जून 1949 को केन्द्र ने अपने हाथ मे लिया।

वित्त (हजार रुपयों में)

बजट के आकड़े	आय	व्यय	बचत (+) या घाटा (—)
1952-53 (संशोधित) . .	20,672	20,232	+440
1953-54 (बजट) . .	23,304	23,259	+45

शिक्षा

1952-53 में गवर्नमेंट हमीदिया कालेज का दर्जा बढ़ा कर स्नातकोत्तर कालेज तक कर दिया गया। वहां बी० एस० सी० की पढाई भी जारी की गई और बी० ए० तथा बी० काम० के लिये सायंकालीन श्रेणिया खोली गईं। राज्य में एक नया कृषि कालेज तथा 5 नए स्कूल खोले गये। 18 प्रारम्भिक स्कूलों का दर्जा बढा कर उन्हे माध्यमिक स्कूल बना दिया गया और 103 प्रारम्भिक स्कूल तथा 13 नए बेसिक स्कूल खोले गये। एक ही वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या 17,900 से बढकर 23,800 (1952-53) तक पहुंच गई। सामाजिक शिक्षा पर 23,000 रु० व्यय किये गये।

खाद्यान्न तथा कृषि

भोपाल मे 1952-53 मे 84,000 टन गेहूं पैदा हुआ, जो पिछले वर्ष से लगभग 25,000 टन अधिक था। मुख्य खाद्यान्नो की उपज गत वर्ष 1,78,000 टन हुई, जो गत वर्ष से 44,700 टन अधिक थी। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत गत वर्ष 30 नए तालाब बनाये गये, 1,056 कुओं की मरम्मत की गई, 93 नए कुएं खोदे गये और 16 नये बांध बाधे गये। इस पर 9 लाख रुपये व्यय आया। इन के अतिरिक्त गावों में 125 नए रहट लगाये गये। सिंचाई के बड़े कामों मे अष्टा का पार्वती बाध और भोजपुर के बेतवा बांध पूरे किये गये। अजनाल, अजनार, मछवाही और हेलाली में सिचाई की छोटी योजनायें पूरी की गईं। ताड़ गुड व्यवसाय योजना के अन्तर्गत 1,18,920 टन खाद तैयार किया गया और 60,615 टन खाद किसानों को बाटी गई।

व्यवसाय

छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिये अक्तूबर 1952 मे व्यवसाय विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग द्वारा छोटे व्यवसायो के लिये दो लाख रुपये कर्जों के रूप मे दिये गये। व्यवसायों के लिये आवश्यक ट्रेनिंग देने का भी प्रयत्न किया गया। स्त्रियों को सिलाई तथा कारीगरी की शिक्षा देने के लिये एक केन्द्र खोला गया। विभिन्न व्यावसायिक सहयोग समितियो तथा कारीगरों को आवश्यक मशीनो तथा पुरजो के रूप मे 30,000 रुपये का सामान बाटा गया। पुराने व्यवसायो के विकास और सीमेंट, चूना, लोहा, ऊन आदि नए व्यवसायो को प्रारम्भ करने का प्रयत्न भी किया गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष तपेदिक की रोकथाम के लिये 1,00,000 व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 40,000 को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया। तपेदिक के इलाज के लिये भोपाल में 20 बिस्तरों का एक क्लिनिक खोला गया। ईदगाह पहाड़ी पर 10 लाख रुपयो के व्यय से एक तपेदिक के अस्पताल का निर्माण जारी है। मलेरिया की रोकथाम के कार्य को भी संगठित किया जा रहा है। हमीदिया अस्पताल मे 26,000 रुपयों के व्यय से एक नया एक्सरे प्लांट लगाया गया है। देहाती क्षेत्रो मे 4 जच्चा केन्द्र तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोले जा रहे हैं। 1952-53 में राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिये हवाई नियंत्रण कानन तथा भोपाल चिकित्सक कानून पास किया गया।

भोपाल विधान-सभा

अध्यक्ष : सुलतान मुहम्मदखां

जलालुद्दीन कुरैशी (शाहजहाबाद)
सैयद ऐजाजुद्दीन (शीश महल)
इनायतुल्लाखां तरजी मशरिकी (जहांगीराबाद)
कुमारी लीला राय (बैरागढ)
बाबूलाल (बैरागढ़, संरक्षित परिगणित जाति)
सरदारमल ललवानी (हजूर)
शंकरदयाल शर्मा (बेरसिया)
शंकरदयाल (नजीराबाद)
सुलतान मुहम्मद खां (सिहोर)
उमराव सिंह (सिहोर, संरक्षित, परिगणित जाति)
बाबू लाल (श्यामपुर)
हरिकिशन सिंह (श्यामपुर, संरक्षित परिगणित जाति)
केसरीमल जैन (इच्छावर)
चन्दनमल (आष्टा)
गोपीदास (आष्टा, संरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती मैमूना सुलतान (कोटरी)
वंशीधर (नसरुल्लागंज)
लच्छमी नारायण अग्रवाल (बुधनी)
गुलाब चन्द (गोहर गंज)
दलीप सिंह (गौहरगंज, संरक्षित, परिगणित जन जाति)
कामता प्रसाद (रायसेन)
बाबूलाल (रायसेन, संरक्षित, परिगणित जाति)
कुन्दनलाल (बेगम गंज)
बाबूलाल कमल (सुलतान गंज)
लीलाधर राठी (सिलवानी)
दौलतसिंह (सिलवानी, संरक्षित परिगणित जन जाति)
नर्बदाचरण लाल (अमरावद)
श्यामसुन्दर (बरेली)
नितगोपाल (उदयपुरा)
रामकरन लाल (देवरी)

कुर्ग

चीफ कमिश्नर दयासिंह बेदी

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, लगान, आन्तरिक कर, योजना और विकास. . . . . सी० एम० पुनाचा
2. गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय . . . के० मल्लप्पा

वित्त

1953-54 का बजट इस प्रकार है :—

	(रुपये)
आय	1,04,00,000
व्यय	1,41,00,000
घाटा	37,00,000

शिक्षा

कुर्ग में केवल एक ही प्रथम श्रेणी का कालेज है, जो मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस के अतिरिक्त वहां 10 हाई स्कूल, 49 माध्यमिक स्कूल, 90 प्रारम्भिक स्कूल और

शिशुओ के स्कूल है । इन में से कुछ स्कूलों को बेसिक स्कूल बनाया जा रहा है । अप्रैल 1953 में कुर्ग की सरकार ने जिला बोर्ड के सब स्कूलों को अपने हाथ मे ले लिया ।

खाद्यान्न तथा कृषि

राज्य मे कुल 4,985 एकड भूमि की सिचाई होती है, जिस में से 900 एकड भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध हाल ही मे किया गया है । विकास योजना कार्यक्रम के अनुसार कुर्ग में एक विकास केन्द्र खोला गया है, जिस के अन्तर्गत 118 गांव हैं जिन की आबादी 75,000 है । भारत सरकार के निश्चय के अनुसार राज्य के शेष देहाती भागों के लिये दूसरे विकास केन्द्र बहुत शीघ्र जारी किये जायेंगे ।

कृषि विकास के लिये एक सलाहकार समिति बनाई गई है । राज्य मे जापानी ढंग से चावल बोने का प्रयत्न किया जा रहा है । गत वर्ष 900 एकड़ भूमि में उक्त ढग से चावल बोया गया । 1,72,327 एकड़ भूमि मे चावल, रागी, कौफी, सन्तरे और सुपारिया उत्पन्न होती हैं ।

व्यवसाय

राज्य के व्यवसाय सलाहकार बोर्ड की सलाह के अनुसार राज्य मे शहद, रेशम और फलों का रस, मुर्गी पालन, तेल, करघा, चटाई बनाना आदि व्यवसायो का विकास करने का निश्चय किया गया है । गत वर्ष राज्य में 240 करघे बाटे गये ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

कुर्ग मे 12 अस्पताल और 6 औषधालय है, जिन मे कार्य करने वालो की संख्या 190 है । गत वर्ष 3,53,029 बीमारो का इलाज किया गया ।

कुर्ग विधान-सभा

अध्यक्ष : बी० एस० कुशलाप्पा

सी० एम० पूनच्च (बेट्टीयन नाड)
के० मल्लप (शनीवारसंते)
बी० एस० कुशलप्प (मरकारा कस्बा)
के० एम० देवय्य (भागमण्डला)
जी० एम० मंजूनाथय्य (सुनटिकोप्पा)
पी० के० चेन्नय्य (शनीवारसंते, संरक्षित परिगणित जाति)
पी० लक्का (सुटिकोप्प, संरक्षित परिगणित जाति)
सी० के० कलप्प (सोमवारपेट उत्तर)
जी० लिंगराज्या (फरेजरपेट)
सी० ए० मन्दा (मुरनाड)
पी० डी० सुब्बय्य (मरकरा नाड)
पी० एम० नानयय्य (पोन्नमपेट नाड)
एम० डी० माचय्य (सिद्धापुर)
बी० काला (सिद्धापुर, संरक्षित परिगणित जन जाति)
वाई० बेल्ली (पून्नेमपेट नाड, संरक्षित परिगणित जन जाति)
पी० आई० बेल्लीयप्प (अम्माती नाड)
एच० टी० मुत्तन्ना (सुम्वर पेट, दक्षिण)
के० पी० करम्बय्या (श्री मंगला)
जी० सुबाया (श्री मंगला नाड, संरक्षित परिगणित जनजाति)
के० के० गणपति (हुदीकेरी)
एन० जी० अहमद (विराजपेट कस्बा)
पी० मी० उत्ताया (विराजपेट नाड)
ए० सी० तिम्मया (नापोक्लू)
एच० नाजा (विराजपेट नाड, संरक्षित परिगणित जाति)

दिल्ली

चीफ कमिश्नर ए० डी० पण्डित

मंत्री

1. मुख्य मंत्री तथा साधारण शासन प्रबन्ध, वित्त, नागरिक पूर्ति, शिक्षा, तथा स्थानीय स्वराज्य . ब्रह्मप्रकाश
2. स्वास्थ्य, यातायात, सहायता तथा पुनर्वास . . सुशीला नायर
3. विकास, कानून और न्याय . . . गोपीनाथ अमन

वित्त (हजार रुपयो में)

बजट के आकडे	आय	व्यय	बचत (+) घाटा (—)
1952-53 (संशोधित) .	36,253	36,253	—
1953-54 (बजट) .	42,563	42,563	—

शिक्षा

1953-54 के बजट में शिक्षा के लिये 1,29,77,000 रुपये रखे गये। स्कूलो की इमारतों की कमी के कारण दिल्ली के कई स्कूलों में दो बार क्लास लगाने का प्रबन्ध किया गया और इस तरह 40,000 अतिरिक्त विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। हरिजन विद्यार्थियों को दसवी श्रेणी तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। राज्य मे 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिये 10 नए नर्सरी स्कूल खोलने का निश्चय किया गया है। अनिवार्य शिक्षा के लिये एक मसविदा आजकल विचाराधीन है। देहाती हलको मे 6 से 11 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियो को शिक्षा देने के लिये लगभग 300 बेसिक स्कूल खोले गये हैं। अलीपुर में एक जनता कालेज की स्थापना की गई है जो शहर से 12 मील दूर है। कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने का भी प्रयत्न किया गया। इस कार्य के लिय संगीत के साज आदि पुरस्कार में बाटे गये।

खाद्यान्न तथा कृषि

1953-54 मे 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिये 8,55,000 रुपये रखे गये हैं। गत वर्ष 600 नए कुएं खोदे गये थे तथा 16 ट्यूबवैल और 400 रहट लगाए गए थे। इन कार्यों के द्वारा 11,000 एकड़ नई भूमि को सिचाई योग्य बना लिया गया। किसानों को 8 लाख रुपये तकावी के रूप मे बाटे गये और 22,020 रुपये की लगान मे छूट दी गई। इस के अतिरिक्त किसानो को 6 लाख मन खाद भी बांटा गया। इन साधनों से 22,500 मन अधिक अनाज उत्पन्न होने की आशा है। राज्य की ग्राम सम्बन्धी उन्नति के लिये अन्य भी कितने ही काम किये जा रहे हैं, उदाहरण के लिये 52 गावों में 40,998 एकड भूमि का संगृहीतिकरण किया गया। खेती-बाड़ी के औज़ारो को भी राज्य ही में बनाने का प्रबन्ध किया गया है। दिल्ली भर को दूध और अण्डे पहुंचाने के लिये योजना बनाई गई है। राज्य में पशुओं की उन्नति के लिये भी स्कीमें बनाई जा रही है। एक मछली विभाग भी बनाया गया है।

राज्य के विकास विभाग के प्रयत्न से दिल्ली के गांवों के निवासियों तथा राष्ट्रीय कैडिट कोरों ने स्वेच्छापूर्वक शारीरिक श्रम दान किया। इस श्रमदान द्वारा देहाती हलकों में 38 मील नालियों की सफाई की गई और उन का पुनरुद्धार किया गया। ज़मींदारी सम्बन्धी कानून में आवश्यक परिवर्तन किया जा रहा है और उन में वे सिद्धान्त बरते जा रहे हैं, जो अन्य राज्यों के ज़मीदारी-निरोध कानून में बरते गये हैं।

व्यवसाय

छोटे पैमाने के व्यवसायों की उन्नति के लिये व्यावसायिक सलाह बोर्ड ने अनेक स्कीमें बनाई हैं। इस उद्देश्य से राज्य की भूमि, जल और शक्ति के साधनों की जांच-पड़ताल की गई है। सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी आदि कुछ व्यवसायों का विशेष विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952-53 मे इरविन अस्पताल में 48 बिस्तरे बढाए गए। इसी तरह तपेदिक के अस्पताल मे 18 ओर संक्रामक बीमारियो के अस्पताल मे 24 बिस्तरों की सख्या बढाई गई। लाजपत नगर, मालवीय नगर, तिलक नगर और काल्काजी मे 16-16 नए बिस्तरों के 4 अस्पताल खोले गये। झीलकुरंजा में एक औषधालय खोला गया और सब्जीमंडी तथा करोलबाग क्षेत्र में 6 स्वास्थ्य केन्द्र। राज्य भर में हैज़ा, चेचक आदि के निरोध के लिये सफलतापूर्वक टीके लगाये गये। बी० सी० जी० आन्दोलन को खूब सफलतापूर्वक चलाया गया। राज्य की सरकार को मलेरिया के नियंत्रण करने के कार्य में असाधारण सफलता प्राप्त हुई, यह इस बात से स्पष्ट होगा कि 1933 में दिल्ली में प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे 180 व्यक्ति मलेरिया से बीमार हुआ करते थे, 1952 में यह सख्या घट कर 2.1 रह गई। गावों में भी इस सम्बन्ध में असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3,700 पौंड डी० डी० टी० छिडका गया। हैजा आदि पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सका। राज्य की विधान सभा आजकल एक नर्सिंग होम बिल पर विचार कर रही है।

दिल्ली विधान सभा

अध्यक्ष गुरमुख निहालसिंह

हरीचन्द (अजमेरी गेट)
मंगलदास (आर्यपुरा)
सुलतान यार खां (बल्लीमारां)
युद्धवीरसिंह (चांदनी चौक)
नुरुद्दीन एहमद (चावड़ी बाजार)
करतारसिंह (चित्रगुप्त)
हुकुमसिंह (चन्द्रावल)
श्रीमती कृष्णा सेठी (सिविल लाइन्स)
गुरमुख निहालसिंह (दरियागंज)
राघवेन्द्रसिंह (दिल्ली छावनी)
श्यामचरण (डिपुटीगंज)
हाथीसिंह (इशापुर)
गिरधारीलाल सलवान (झण्डेवाला)
भूपसिंह (कंझावला)
भगवानदास (कश्मीरी गेट)
जंगबहादुर सिंह (किंग्सवे कैम्प)
जगप्रवेश चन्द्र (किशनगंज, आनन्द पर्वत)
श्रीमती शान्ता वशिष्ठ (कोटला, फीरोज़शाह)
मुश्ताक एहमद (कूचा चेलां)
शिवनन्दन ऋषी (लोदी रोड)

आनन्द राज (मालीवाड़ा)
बी० डी० जोशी (मानकपुरा)
मुश्ताक राय खन्ना (मन्टोला)
सुख देव (मेहरौली)
मित्तरसैन (मेहरौली, संरक्षित परिगणित जाति)
दिलावर सिंह (नाईवालां)
ब्रह्मप्रकाश (नांगलोई)
मांगेराम (नरेला)
प्रभुदयाल (नरेला, सरक्षित परिगणित जाति)
अजीतसिंह (नजफगढ़)
चिन्तामणि (शाहदरा)
शिवनाथ (पहाड़ी धीरज--बस्ती जुलाहा, संरक्षित परिगणित जाति)
खुशालेश्वरप्रसाद शंकरा (पार्लियामेंट स्ट्रीट)
हरकिशनलाल भगत (फाटक हबश खान)
श्रीमती पुष्पादेवी (पुराना किला-विनय नगर)
शंकरलाल (राम नगर)
प्रफुल्ल रंजन चक्रवर्ती (रीडिंग रोड)
अमीचन्द (रीडिंग रोड, संरक्षित परिगणित जाति)
श्रीमती सुशीला नैयर (रैगरपुरा-देवनगर)
दयाराम (रैगरपुरा-देवनगर, संरक्षित परिगणित जाति)
कंवरलाल गुप्त (रोशनारा)
दलजीतसिंह (सफदर जंग)
हेमचन्द जैन (पहाडी धीरज—बस्ती जुलाहान)
शिवचरण दास (सीताराम बाजार-तुर्कमान गेट)
सुदर्शनसिंह (सीताराम बाजार-तुर्कमान गेट, संरक्षित परिगणित जाति)
रामसिंह (तिब्बिया कालेज)
गोपीनाथ अमन (टोकरीवाला)
फतेहसिंह (वजीराबाद)

हिमाचल प्रदेश

का० मों० एम० एस० हिम्मतसिहजी

मंत्री

1. मुख्य मन्त्री, साधारण व्यवस्था, वित्त और लगान . यशवन्तसिह परमार
2. शिक्षा, पुलिस, जेल, विकास, व्यवसाय और नागरिक पूर्ति . . . . . पद्म देव
3. सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य, यातायात तथा स्थानीय स्वराज्य . . . गौरीप्रसाद

15 अप्रैल 1948 को पंजाब की 30 छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतों को मिला कर हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई। 26 जनवरी 1950 को कोटगढ और कोटखाई का छोटा-सा भाग इस राज्य मे मिला दिया गया।

वित्त (हजार रुपयो में)

बजट के आकडे	आय	व्यय	बचत या (+) घाटा (—)
1952-53 (सशोधित) . .	23,969	23,694	+275
1953-54 (बजट) . .	26,683	26,596	+87

शिक्षा

1952-53 मे हिमाचल प्रदेश में दो माध्यमिक स्कूलो को हाई स्कूल बना दिया गया और 11 प्रारम्भिक तथा 21 छोटे स्तर के माध्यमिक स्कूलो को माध्यमिक स्कूल बना दिया गया। इन के अतिरिक्त 36 नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये थे। पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत प्रथम वर्षों

मे 145 नए माध्यमिक स्कूल खोले गये थे। वयस्क लोगो मे शिक्षा के प्रचार के लिये सामाजिक शिक्षा की एक योजना तैयार की गई है, जिस के द्वारा राज्य के अध्यापक और विद्यार्थी साक्षरता प्रसार का कार्य करेगे ।

खाद्यान्न तथा कृषि

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अच्छे बीजो के 4 फार्म खोले है। राज्य मे अच्छे फलों के वृक्ष बोने के लिये आवश्यक सलाह दी जाती है। गत वर्ष 19,100 फलो के वृक्ष लगाये गये और 1,438 वृक्षो मे कलमे लगाई गई। आलुओ की किस्म अच्छी बनाने के लिये आवश्यक परीक्षा की गई। राज्य की सरकार ने काश्मीर सरकार को 5,000 मन गेहू दिया और केन्द्रीय सरकार को 10,000 मन मक्का। किसानों की भलाई की दृष्टि से राज्य की सरकार ने 1952 मे दो आवश्यक कानून पास किये। लगान के सम्बन्ध मे छानबीन करने के लिये एक कमेटी भी नियुक्त की गई। मछली व्यवसाय के विकास, नियत्रण और सचालन के लिये आवश्यक नियम बनाये गये है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

महासू जिले के स्नोडन अस्पताल को राज्य की सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया है और उस का नाम हिमाचल प्रदेश अस्पताल रख दिया गया है। 34,000 रुपये की लागत से वहा एक नया एक्सरे प्लाट लगाया गया है। इसी के साथ एक परिवार नियत्रण केन्द्र तथा एक दांतों का क्लिनिक भी खोले गये है। मंडी मे 35,000 रुपयों के व्यय से एक नया मैटरनिटी वार्ड खोला गया है। चम्बा मे भी एक जच्चागृह खोला गया है। इन के अतिरिक्त 12 नए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का भी प्रस्ताव है।

राज्य मे लैंगिक बीमारियो की रोकथाम के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। महासू जिले मे एक तपेदिक अस्पताल खोला जा रहा है और सामूहिक विकास योजना क्षेत्र मे मलेरिया नियत्रण का उपाय किया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष : जयवन्त राम

सरजूसिह (भामला)
जयवन्तराम (भटियात)
गुरदित्तामल (भरमौर)
कृष्णचन्द्र (चच्योट)
पीरू (चच्योट, संरक्षित)
अवतारचन्द मेहता (चौराह)
विद्याधर (चौराह, संरक्षित)
चत्तरसिंह (चम्बा)
गोपालचन्द्र (चीनी)
बालानन्द (जुब्बल)
बेसरराम (योगेन्द्र नगर)
जीवनूराम (पछाद, संरक्षित)
शिवानन्द (पाओन्टा)
दौलतराम (पांगी)
पद्मदेव (रोड़ू)
घनश्याम (राजगढ)
हरदयालसिंह (रामपुर)
भगतराम (रामपुर, संरक्षित)
गौरीप्रसाद (रवालसर)
सूरतसिंह (रेणुका)
प्रतापसिंह (रेणुका, संरक्षित)
हीरासिंह पाल (सोलन)

हितेन्द्र सेन (कसुम्पटि)
रामदयाल (कुमारसैन)
रत्नसिह (करसोग)
करमसिह (महादेव)
कृष्णानन्द स्वामी (मण्डी सदर)
तपेन्द्रसिह (नाहन)
यशवन्तसिह परमार (पछाद)
रामदास (सोलन, संरक्षित)
सीताराम (सुनी)
बलदेवचन्द (सुन्दरनगर)
कश्मीरसिह (सन्धौल)
हरिसिह (सन्धौल, सरक्षित)
देवीराम (ठयोग)
जीवनू (ठयोग, संरक्षित)

कच्छ

चीफ कमिश्नर एस० ए० घाटगे

1 जून 1948 को कच्छ भारत यूनियन मे सम्मिलित हुआ।

वित्त

1953-54 का बजट इस प्रकार है —

आय	37,48,000 रु०
व्यय	1,57,59,000 ,,
घाटा	1,20,11,000 ,,

शिक्षा

कच्छ मे कुल 8 हाई स्कूल है, जिन मे विद्यार्थियो की सख्या 2,600 है। इस के अतिरिक्त वहा 13 माध्यमिक स्कूल 355 लडको के प्रारम्भिक स्कूल, और 135 लडकियो के प्रारम्भिक स्कूल है। वहा एक आर्ट्स स्कूल, एक अध विद्यालय, एक कृषि स्कूल, और लगभग 40 प्रौढ शिक्षा केन्द्र है। राज्य मे विद्यार्थियो की कुल सख्या 53,000 है। 1953 मे एक इटर कालेज खोला गया।

खाद्यान्न तथा कृषि

कच्छ म मख्यत बाजरा, गेहूं, जौ और रूई पैदा होती है। सिचाई के साधनो का अच्छा विकास किया गया है और इस कार्य के लिये वहा 46 तालाब है, जिन से 75,000 एकड भूमि की सिचाई होती है। पचवर्षीय आयोजना के अनसार 11 नए बाध बनाने का निश्चय किया गया है, जिन मे से 6 का निर्माण हो गया है और बाकी का निर्माण जारी है। इन बाधो के द्वारा 67,000 एकड नई भूमि की सिचाई हो सकेगी।

व्यवसाय

राज्य में बहुत ऊचे दर्जे की मिट्टी, पत्थर का चूना, लिगनाइट, सगमरमर तथा फिटकरी आदि पाई जाती है। साथ ही कच्छ अपने सुन्दर कसीदे तथा चादी पर पच्चीकारी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य की सरकार की ओर से 6 अस्पताल, 15 औषधालय और 2 जच्चागृह चलाए जा रहे हैं। इन के अतिरिक्त राज्य में 7 व्यक्तिगत अस्पताल तथा 31 अन्य औषधालय भी हैं। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार भुज में एक अस्पताल, मांडवी मे आंखों का एक अस्पताल, भुज

में एक मानसिक रोगो का अस्पताल तथा तपेदिक क्लिनिक और 5 चल-औषधालय जारी किये जायेगे। मलेरिया की रोकथाम, विटामिन की गोलियो का वितरण तथा बच्चों के लिये दूध और फलों के केन्द्र खोलने के निमित्त 10,00,000 रुपये रखे गये है।

कच्छ निर्वाचन मण्डल

नानालाल रामचन्द (आडेसर)
माणेकलाल नेणसी (आदौई)
पुरुषोत्तम सामजी (अन्जार)
हेतुभा रम्वाजी (मचाऊ)
खिमजी जेव्वत (भद्रेश्वर)
जमियतराय गुलाबशकर (भुज)
मगनलाल वेलजी (भुजपर)
शिवजी हरसी (विडडा)
सरूपचन्द न्यालचन्द (फतेहगढ)
गोविन्दजी मावजी (गठसीसा)
दुगरसी पुरुषोत्तम लोहाणा (गान्धीधाम)
हिरजी भाई रणछोडदास कोटक (केरा)
वकील मूलशकर कुवरजी (खावडा)
वानेचन्द घरमसी (किडीयानगर)
करसन दास हीरजी (कोडारा)
मावजी रामजी जोशी (लायजा मोटा)
मोतीलाल लक्ष्मण जैन (लाकडिया)
खराशंकर जटाशंकर जोशी (लखपत)
प्रेमजी भवानजी ठकर (माघापर)
हरीराम नथुभाई कोठारी (माडवी)
मनहरलाल मावजी कायस्थ (मानकुवा)
शिवलाल अमरजी गरनारा (मस्का)
कुमारजी जेडीसिहजी (मादाला)
वाघजी भाई केशवजी राजपूत (मुन्दरा)
नथु नानजी (नखत्राणा)
विशनजी कान्जी लोहाना (नलिया)
जुगतराम दलपतराम ब्राह्मण (नेतरा)
जादवजी मानसग लोहाना (रापर)
शिवुभा मोरजी जाडेजा (रतनाल)
मनसुख खिमकरण बारोट (रोहा, सुमरी)

मणिपुर

चीफ कमिश्नर — आर० पी० भार्गव

15 अक्तूबर 1949 को भारत सरकार ने मणिपुर का शासन अपने हाथ में लिया था। उस से पहले यह आसाम के अन्तर्गत एक छोटी सी रियासत थी।

वित्त

1953-54 का बजट इस प्रकार है —

	रुपये
आय	34,66,000
व्यय	1,08,44,000
घाटा	73,78,000

शिक्षा

मणिपुर में एक सरकारी कालेज है, 22 हाई स्कूल, 65 माध्यमिक स्कूल तथा 687 प्रारम्भिक स्कूल है। इन सब मे कुल मिला कर 46,096 विद्यार्थी है।

खाद्यान्न तथा कृषि

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत किसानो को अच्छे किस्म के बीज बाटे जा रहे है तथा राज्य की सम्पूर्ण भूमि पर खेती वाड़ी करने का प्रयत्न किया जा रहा है। समुसग

सुरक्षित क्षेत्र, जिस में 2,500 एकड़ भूमि है, का परिमापन पूरा कर लिया गया है। अन्य दो बड़े क्षेत्रों का परिमापन जारी है। लूशीपत और खारुंगपत में से नहरे काट कर उन का पानी निकालने का प्रस्ताव है।

व्यवसाय

राज्य के प्रमुख गृहव्यवसाय निम्नलिखित है—करघा, साबुन बनाना, तरखानी, रेशम, चमड़ा तथा रस निकालना। वस्त्र व्यवसाय को उन्नति के लिये गावो मे अच्छे ढग के करघे आदि उधार दिये जा रहे है। राज्य मे विदेशी रेशम के कीडो के पालन का प्रबन्ध भी किया जा रहा है। मणिपुर का बना कपडा अपने सौन्दर्य के लिये देश भर मे प्रसिद्ध है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

मणिपुर मे कुल 15 अस्पताल है, जिन मे से एक तपेदिक का अस्पताल है और एक कोढ का। इन के अतिरिक्त जो 12 अस्पताल है, उन मे से 3 चल है।

मनीपुर निर्वाचन मण्डल

अथुइबाऊ (आइमोल)
माइरेन्बम् कोइरगसिंह (विशेपुर—मोइराग)
सीरोंखाइब चौरजीतसिंह (चरागपात—खोमजोक)
सुमखोहेन (चुराचान्दपुर)
एलागबम् नदों सिंह (हिगागलम—सुगनु)
तखेल्लम्बम् इबोतोम्बी सिंह (इरिगबुग—याइरिपोक—तोप—चिगथा)
सिनाम विजय सिह (जीरी)
पुखम्बम् तोमचौ सिह (कक्चिग०वागजिग)
युमनाम मेघसिंह (कैशामथोंग)
श्रीमती विनोदिनी देवी (खुराई)
निगथौजम थोंगलेन सिंह (कुम्बीथाग)
तोम्बा मिया (लमलाई—कैराओ)
अलीमुद्दीन (लिलोंग)
दासो थोइसो (माओ—पूर्व)
हेपुनी कैखो (माओ—पश्चिम)
लाइश्रम गिरिमोहन सिंह (नम्बोल—कैनौ)
जरेम (फसात)
सलाम तोम्बी सिंह (सगोलबन्द)
आर० के० अङसिगा सिंह (सगोलमाग)
सोराम छत्रधारी सिंह (सलाम—खुम्बोग—कौन्थौजम)
ख्वाइराकपम् चाउबासिंह (सेकमाइ—लमशाग)
कैबेन (तमेंगलोग)
आत्नम अनल (तेंगनौपल)
खुमा (थानलौन)
एल० चाओयाइमा सिंह (थौबाल—चन्द्रखोंग)
सुइसा (उखुल)
हिदगमयुम् द्विजमणि शर्मा (उरिपोक—ललाम्बुग—थांगमैबन्द)
लाइश्रम अचौसिह (वाखै—कौगबा)
निंगथौजम् तोमचौसिह (वांगोइ—मयाग—इम्फाल)

त्रिपुरा

चीफ कमिश्नर वी० आई० ननजप्पा

15 अक्तूबर 1949 को त्रिपुरा केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत आया।

शिक्षा

1952-53 के बजट मे 4,36,800 रुपये कालेज शिक्षा के लिये तथा 4,86,000 रुपये प्रारम्भिक तथा प्रौढ शिक्षा के लिये रखे गये। 70 व्यक्तिगत सस्थाओ को 35,160 रुपये सहायता

के रूप में दिये गये। किसानों तथा आदिवासियों में शिक्षा प्रसार करने के लिये एक-एक अध्यापक वाले 80 निम्न प्रारम्भिक स्कूल खोले गये और दो-दो अध्यापकों वाले 10 उच्च प्रारम्भिक स्कूल। इन पर 50,000 रुपये व्यय किये गये।

खाद्यान्न तथा कृषि

गत वर्ष 300 टन खाद तैयार किया गया और 200 टन बाटा गया। सरकारी कृषि फार्म की ओर से चावल, गन्ना, मक्का आदि के श्रेष्ट कोटि के बीज बाटे गये। अगरतल्ला का $2\frac{1}{2}$ वर्ग मील का क्षेत्र, राज्य मे 'केन्द्र ग्राम' बनाने के उद्देश्य से चुना गया। मछली व्यवसाय के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया।

व्यवसाय

आयोजना कमीशन की ओर से त्रिपुरा मे छोटे व्यवसायो के विकास के लिये 2 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

अगरतल्ला के वी० एम० अस्पताल मे एक मेटरनिटी वार्ड खोला गया है, तथा ग्रामीण क्षेत्रो के लिये 7 औषधालय जारी किये गये हैं। राज्य के अस्पताल मे शिक्षित नर्सें और दाइया रखी गई हैं और जच्चा तथा शिशु कल्याण केन्द्र भी खोले गये हैं। गत वर्ष बी० सी० जी० के टीक लगाये गये तथा मलेरिया के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की गई।

त्रिपुरा निर्वाचन मण्डल

हेमन्तदेव (अगरतला सदर 1)
अतिकुल इसलाम (अगरतला सदर 2)
सुदानचन्द्र देब बर्मा (अगरतला सदर 3)
नन्दलाल चक्रवर्ती (अगरतला कस्वा 1)
उमेशलाल सिंह (अगरतला कस्वा 2)
जोएनल आबेदिन (बेलोनिया)
गारूमिया (वीरगंज)
आफताबदीन (विशालगढ़)
अघोरचन्द्र देव वर्मा (चारीलाम)
करुणचन्द्र नाथ (धर्म नगर—उत्तर)
अब्दुल वाजीद (धर्मनगर—दक्षिण)
प्यारी मोहन जग (घुम्बुर नगर)
गोकुलचन्द्र सिंह (फटिकराय)
अब्दुल लतीफ (कैलाशहर)
रामचरण (कल्याणपुर—दक्षिण)
गणसिंह (कमलपुर)
माधवचन्द्र मास्टर (कांचनपुर)
सतीश चक्रवर्ती (खोवाई आशारामबाडी)
श्रीमती कीर्णमाला देवी (खोआई कल्याणपुर)
कृष्णमणि त्रिपुरा (कुलाइनोर)
बसरतउल्ला (कुर्ती)
प्रमोदरजन दासगुप्त (मोहनपुर)
क्षेत्रमोहन मजूमदार (मुहुरीपुर)
सिराजुल इस्माइल (पुराना अगरतला)
इरशाद अली (राधाकिशोरपुर)
वंशीदेव बर्मा (सब्रूम)
मणीन्द्रकिशोर चौधरी (सालगढ)
काला मिया (सोनामुरा—उत्तर)
कृष्णचन्द्र देव बर्मन (सोनारपुरा—दक्षिण)
बीरचन्द्र देव बर्मा (ताकरजल)

विन्ध्यप्रदेश

लेफ्टिनेंट गवर्नर के० सन्तानम

मंत्री

1. मुख्यमंत्री तथा साधारण शासन वित्त और लगान . शम्भुनाथ शुक्ल
2. शिक्षा तथा सामाजिक सेवाएं . . . महेन्द्रकुमार मानव

3. गृह तथा स्थानीय स्वराज्य . . . लालाराम बाजपेयी
4. योजना तथा न्याय . . . . गोपाल शरण सिंह
5. व्यवसाय तथा नागरिक पूर्ति . . . दान बहादुर सिंह

पुरानी छोटी छोटी 36 रियासतों को मिला कर 1 जनवरी 1950 को विन्ध्यप्रदेश राज्य बनाया गया ।

वित्त (हजार रुपयों में)

बजट के आकडे	श्राय	व्यय	बचत (+) या घाटा (—)
1952-53 (सशोधित) . .	3,18,30	3,07,93	+10,37
1953-54 (बजट) . .	4,39,60	4,39,40	+20

शिक्षा

1952-53 में विन्ध्यप्रदेश में 150 नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये और इस तरह उन की संख्या 1,858 हो गई। इन स्कूलो मे कुल 67,059 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे है। गत वर्ष 15 प्रारम्भिक स्कूलो को माध्यमिक स्कूल बना दिया गया और 7 माध्यमिक स्कूलो को हाई स्कूल। अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध मे राज्य की सरकार ने एक कानून पास किया है। व्यावसायिक टैक्निकल तथा धधो की शिक्षा देने के लिए नौगाव मे एक पौलिटैक्नीक सस्था खोली गई है श्रौर रीवा मे एक नई कृषि सस्था। इस के अतिरिक्त प्रत्येक जिले मे 8 बेसिक स्कूल खोले गये है। टीकमगढ जिले के कुण्डेश्वर नामक स्थान पर एक बेसिक ट्रेनिग स्कूल खोला गया है।

खाद्यान्न तथा कृषि

'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत राज्य में 214 टन वैज्ञानिक खाद, 2,526 टन साधारण खाद, 1,000 मन गेहू, 1,680 मन आलू, 85 मन चावल और 380 मन अन्य प्रकार के बीज किसानो को बाटे गये। सिचाई की योजनाश्रो के अन्तर्गत 60 कुए खोदे गये और एक तालाब बनाया गया। इन से 1,180 एकड़ भूमि की सिचाई की गई। 10 लाख रुपये तकावी के रूप मे बांटे गये और चावल की कृषि मे जापानी ढग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया गया।

व्यवसाय

1953 मे रीवा मे एक राजकीय एम्पोरियम की स्थापना की गई तथा टैक्निकल इन्स्टीच्यूट के तरखानी विभाग का विकास किया गया। पचवर्षीय आयोजना के अनुसार विन्ध्यप्रदेश मे छोटे व्यवसायो के विकास पर 6 लाख रुपये व्यय किये जायेगे।

गत वर्ष टीकमगढ मे ताड गुड व्यवसाय जारी करने की योजना तथा सतना में हड्डियो से खाद बनाने की एक फैक्टरी बनाने की योजना स्वीकार हुई।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष 4 नए जच्चा और शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया, जिन मे से रीवां और नौगाव मे दो केन्द्र जारी भी कर दिये गये। लैगिक बीमारियों तथा कोढ़ की रोकथाम

के लिये राज्य में 4 क्लिनिक खोले जा रहे है। छतरपुर जिले में बी० सी० जी० आन्दोलन बहुत सफलतापूर्वक चलाया गया।

विन्ध्यप्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष : शिवानन्द (सतना, जिला सतना)

शत्रुसूदन सिंह (धरापुर)
ब्रजराज सिंह तिवारी (गुढ़)
श्रीनिवास तिवारी (मनगा)
मुनीप्रसाद शुक्ल (रेवा)
सरदार नर्मदाप्रसाद सिह (सिरमौर)
बकुठप्रसाद पाण्डेम (सेमरिया)
राणा शमशेरसिह (गढी)
राजेश्वरप्रसाद मिश्र (तियन्थर)
कुवर सोमेश्वरसिह (मउनगज, नई गढी)
सहदेइया (परिगणितजाति मउनगंज नई गढी)
भुवनेश्वर प्रसाद उर्फ ईश्वराचार्य (हनुमान)
कौशलेन्द्र प्रताप बहादुर सिह (कोठी)
रामाधार पाण्डेय (अमदरा)
चन्दा दीन (परिगणित जाति नागौद)
गोपालशरण सिह (नगोद)
कर्नल बलवन्तसिह (रामनगर)
केशवप्रसाद (मुकन्दपुर)
लालविहारीसिह (अमरपटान)
गोविन्दनारायण सिह (रामपुर बघेतान)
रामसजीवन (सभापुर)
भाईलाल (कनपुरी)
जगतबहादुर सिंह (चुरहट)
चन्द्रप्रताप तिवारी (सीधी, मडवास)
दाढी (परिगणित वन जाति, मडवास)
श्यामकार्त्तिक (सिगरौली निवास)
श्रीमती सुमित्री (परिगणित जनजाति, सिंग रौली निवास,)
जगदीशप्रसाद खरे (देवसर)
शम्भुनाथ शुक्ल (अमरपुर)
दानबहादुर सिह (पुष्पराजगढ)
रामप्रसाद सिह (परिगणित जन जाति पुष्पराज गढ)
बाबूलाल उदानिया (जैतपुर कोतमा)
रतन सिह (परिगणित जन जाति, जैतपुर कोतमा)
लाल राजेन्द्रबहादुर सिह (सोहागपुर)
सरस्वतीप्रसाद पटेल (बुढार)
लाल आदित्यनाथ सिह (उमरिया)
बाबादीन (परिगणित जाति, ब्योहारी)

रामकिशोर शुक्ल (ब्यौहारी)
नरेन्द्रसिह (पवई)
भरा (परिगणित जनजाति पवई)
लाल मुहम्मद (अजयगढ)
सरजूप्रसाद चदपुरिया (पन्ना)
रघुनाथसिह (बन्दला)
महेन्द्र कुमार मानव (लौडी)
गोकुलप्रसाद (राजनगर)
दशरथजैन (छतरपुर)
बिरवा (परिगणत जाति, छत्रपुर)
दीवान प्रतापसिह (बिजावर)
प्यारेलाल (परिगणित जाति, बिजावर)
रिक्त (मलहरा)
रिक्त (सेवढा)
रिक्त (परिगणित जाति, सेवढा)
कृष्णकान्त राय (टीकमगढ)
रिल्ली चमार (प० जा०, टीकमगढ,)
ठाकुरदास मिश्र (चन्दपुर)
सेठ नारायणदास (जतरा)
लालाराम वाजपेयी (निवारी)
रघुराज सिंह (लिधौरा)
श्यामलाल साहू (पृथ्वीपुर)

भाग 'घ' के प्रदेश

अन्दमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह

चीफ कमिश्नर एम० एन० मैत्रा

खाद्यान्न तथा कृषि

1952-53 में कुल 5,599 एकड भूमि पर चावल बोया गया। सरकारी परीक्षण फार्म में चावल की 16 किस्मे पैदा की गई। परीक्षण के तौर पर गन्ना, अरहर, रूई, रागी, और चना आदि भी बोये गये। मार्च 1953 मे एक कृषि तथा व्यावसायिक प्रदर्शनी संगठित की गई, जिस मे किसानो को पुरस्कार बांटे गये। अन्दमान मे एक सहायक मछली अनुसन्धान अफसर, मछली व्यवसाय के विभिन्न उपायो के सम्बन्ध मे अनुसन्धान कार्य कर रहा है।

व्यवसाय

अन्दमान मे दो बड़े कारखाने है। एक चैथम आरा मिल तथा दूसरा दियासलाई फैक्टरी। करघो मे बने माल की उन्नति के लिए एक करघा सोसाइटी कार्य कर रही है। कारनिकोबार द्वीप मे सहयोगी ढग पर खोपरा तेल व्यवसाय को विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

कारनिकोबार के नए अस्पताल का निर्माण कार्य समाप्तप्राय है। माया बन्दर मे 20 बिस्तरो का एक नया अस्पताल खोला गया है। नीकोबार द्वीपो मे लैंगिक बीमारियो की रोकथाम के लिये चिकित्सको का एक दल भेजने का प्रस्ताव है तथा रगट मे एक अस्पताल खोला जा रहा है। इन द्वीपो की सब से भयकर बीमारी मलेरिया है, अत उस की रोकथाम के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। गत वर्ष स्कूलो मे पढने वाले बच्चो की स्वास्थ्य परीक्षा की गई और जिन्हे आवश्यकता थी, उन का इलाज किया गया।

सिक्किम

5 दिसम्बर 1950 की सधि के अनुसार सिक्किम भारत सरकार का सुरक्षित राज्य है। राज्य की रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा यातायात और सवादवहन के सम्बन्ध मे भारत का विशेष उत्तरदायित्व है।

अठाईसवां अध्याय

खेल

हाकी

1928 से भारत का स्थान हाकी की दृष्टि से संसार में सर्वश्रेष्ठ है। तब से अब तक जितने ओलम्पिक खेल हुए है, उन सब में भारत हाकी में प्रथम आता रहा है। 1952 में हैलसिकी में भी भारत हाकी मे सर्वप्रथम आया और उसने अन्तिम सान्मुख्य में हालैंड को 6 के मुकाबले में 1 गोल से हराया था।

राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता (जून 1953)

सर्विसेज टीम ने पजाब को एक गोल से हराया।

पुराने विजयी : बंगाल (1952) पंजाब (1951)।

आगाखान टूर्नामेंट (अप्रेल 1953)

लूसिटैनियन्ज ने टाटा स्पोर्ट्स क्लब को एक गोल से हराया।

पुराने विजयी : टाटा स्पोर्ट्स क्लब (1950 से 1952)।

बेटन कप टूर्नामेंट (मई 1953)

टाटा स्पोर्ट्स क्लब ने नागपुर यूनाइटेड को कलकत्ता मे 2 गोलो के मुकाबले मे 1 से हराया।

पुराने विजयी मोहन बागान (1952)
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट (1951)

फुटबाल

सन्तोष मेमोरियल ट्राफ़ी (1953)

बंगाल ने मैसूर को 3 गोलों से हराया। बंगाल ने सातवी बार यह ट्राफी जीती।

पुराने विजयी : मैसूर (1952)
बंगाल (1951)

आई० ए० एफ० शील्ड (1953)

बम्बई की इंडिया कल्चर लीग तथा ईस्ट बगाल मे दो दिन मैच हुआ, फिर भी कोई निश्चय नही हो पाया। तब इडिया कल्चर लीग की शिकायत पर ईस्ट बगाल को खेल से हटा दिया गया, क्योकि उन के ो खिलाडी अनियमित रूप से खेल मे शामिल थे। इसलि े यह शील्ड इंडिया लीग को दी गई।

पुराने विजयी : मोहन बागान और राजस्थान (1952)
पूर्वी बंगाल (1951)

रोवर्स कप (**अक्तूबर** 1953)

बगलौर मुस्लिम को 2 गोलों से हरा कर हैदराबाद पुलिस ने चौथी बार यह कप जीता। यह सान्मुख्य 61 वर्षों से जारी है ।

डूराण्ड कप (**अक्तूबर-नवम्बर** 1953)

नेशनल डिफेन्स अकादमी को मोहनबागान ने 4 गोलो से हरा कर यह कप जीता।

पुराने विजयी : पूर्वी (बगाल 1951 और 52)

क्रिकेट

रंजी ट्राफी (मार्च 1953)

होल्कर ने पश्चिमी बगाल को पहली पारी मे अधिक रन बनाने के कारण हरा दिया। स्कोर यह रहे —

होल्कर	पहली पारी	496 (बी० बी० निम्बालकर 219)
	दूसरी ,,	9 विकटो पर 177 रन
पश्चिमी बगाल	पहली पारी	479
	दूसरी ,,	5 विकटो पर 320 रन (पारी समाप्ति घोषणा)

पिछले विजेता .

वर्ष	विजेता	पराजित
1934-35	बम्बई	उत्तरी भारत
1935-36	बम्बई	मद्रास
1936-37	नवानगर	बगाल
1937-38	हैदराबाद	नवानगर
1938-39	बगाल	दक्षिणी पजाब
1939-40	महाराट्र	उत्तर प्रदेश
1940-41	महाराष्ट्र	मद्रास
1941-42	बम्बई	मैसूर
1942-43	बडौदा	हैदराबाद
1943-44	पश्चिमी भारत	बगाल
1944-45	बम्बई	होल्कर
1945-46	होल्कर	बडौदा
1946-47	बडौदा	होल्कर
1947-48	होल्कर	बम्बई
1948-49 . .	बम्बई	बडौदा

1949-50 . . .	बडौदा	होल्कर
1950-51	होल्कर	गुजरात
1951-52	बम्बई	होल्कर

वेस्ट इंडीज़ मे भारतीय क्रिकेट टीम (1953)

पोर्ट आफ़ स्पेन में पहला टेस्ट

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ :

भारत	पहली पारी	. 417 (उमरीगर, 130)
	दूसरी ,,	294 (उमरीगर 69 · फाडकर 65)
वेस्ट इडीज	पहली पारी	438 (वीक्स 207; गुप्ते 162 रनो पर 7 विकटे)
	दूसरी ,,	. 142 कोई आउट नही ।

ब्रिजटाउन मे दूसरा टैस्ट

वेस्ट इडीज ने 142 रनो से मैच जीत लिया ·

वेस्ट इडीज	पहली पारी	. 296 (वालकौट, 98)
	दूसरी ,,	. 228
भारत	पहली पारी	. 253 (आप्टे 64, हजारे 63)
	दूसरी ,,	. 129 (रामाधीन 26 रनो पर 5 विकटे)

ट्रिनिडाड मे तीसरा टैस्ट

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ ·

भारत	पहली पारी	. 279 (रामचन्द 62, उमरीगर 61, किग 74 रनो पर 5 विकटे)
	दूसरी ,,	. 7 विकटो पर 362 रन (पारी समाप्ति घोषित) (आप्टे 163 रन, आउट नही हुए; मनकद 96 रन)
वेस्ट इडीज	पहली पारी	. 315 (वीक्स 161, गुप्ते 107 रनो पर 5 विकटे)
	दूसरी ,,	. 2 विकटो पर 192 रन, (लेगाल 104, आउट नही हुए)

जार्ज टाउन में चौथा टैस्ट

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ

भारत	पहली पारी	. 262
	दूसरी ,,	. 5 विकटो पर 190 रन
वेस्ट इडीज	पहली पारी	. 364 (वालकौट 125)

किंगस्टन में पांचवां टैस्ट

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ:

भारत	पहली पारी	. 312 (उमरीगर 117, राय 85)
	दूसरी ,,	,, 444 (राय 150, मंजरेकर 118)

वेस्ट इंडीज पहली पारी . 576 (वोरेल 237, वाल्कौट 118, वीक्स 109)
दूसरी „ . 4 विकटों पर 92 रन

पिछले टैस्ट मैच

भारत बनाम आस्ट्रेलिया (1947-48)

आस्ट्रेलिया ने जीते	4
भारत ने जीते	0
अनिर्णीत	1
कुल	5

भारत बनाम वेस्ट इंडीज (1948-49)

भारत ने जीते	0
वेस्ट इंडीज़ ने जीते—	1
अनिर्णीत	4
कुल	5

भारत बनाम इंगलैंड

वर्ष	खेले हुए मैचों की संख्या	जीते	हारे	अनिर्णीत
1932	1	0	1	0
1933-34	3	0	2	1
1936	3	0	2	1
1946	3	0	1	2
1951-52	5	1	1	3
1952	4	0	3	1
	19	1	10	8

रिकार्ड

अधिक से अधिक कुल संख्या	टीम	वर्ष
38 विकटों पर 2,376 रन	महाराष्ट्र बनाम बम्बई	1948-49
40 विकटों पर 2,078 रन	बम्बई बनाम होल्कर	1944-45

सब से अधिक रन बनाने वाला जोड़ा

वी० एस० हज़ारे (288) और गुल मुहम्मद (319) ने 577 रन बनाकर विश्व-रिकार्ड स्थापित किया। यह रिकार्ड उन्हों ने 1946-47 में बड़ौदा की ओर से होल्कर के विरुद्ध खेलते हुए चौथी विकट के पार्टनरशिप में स्थापित किया था।

1948-49 मे पूना में बी० बी० निम्बालकर और के० वी० भन्डारकर ने महाराष्ट्र की ओर से पश्चिमी भारतीय राज्य (वेस्टर्न इंडिया स्टेट्स) के विरुद्ध दूसरी विकेट पार्टनरशिप में खेलते हुए 455 रन बनाये ।

* * * * * *

1930 मे के० एस० दिलीपसिह जी ने होव मे ससेक्स की ओर से नार्थम्पटन शायर के विरुद्ध खेलते हुए 333 रन बनाये थे ।

* * * * * *

के० एस० दिलीपसिह जी ने ब्रिटेन मे 1931 मे एक के बाद एक लगातार 4 शतक बनाये ।

* * * * * *

भारत का सब से अधिक रन बनान का रिकार्ड 8 विकटों पर 912 रन (पारी समाप्ति घोषणा) होल्कर ने इन्दौर मे 1945-46 में होल्कर बनाम मैसूर के मैच मे स्थापित किया ।

भारत में रजतजयन्ती 1953-54

प्रथम टैस्ट (दिल्ली)

भारत एक पारी और 15 रन से जीता :

भारत : पहली पारी . 387 (जी० एस० रामचन्द 119, वी० एल० मन्जरेकर 86)

एस० जी० ओ० सी० टीम :

पहली पारी . 198 (सिम्पसन 57, गुप्ते 91 रनो पर 8 विकटे)

दूसरी ,, . 174 (सिम्पसन 59, वोरेल 54, गुलाम एहमद 52 रन पर 6 विकटे, गुप्ते 82 रनो पर 4 विकटे)

द्वितीय टैस्ट (बम्बई)

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ :

एस० जी० ओ० सी० टीम :

पहली पारी . 6 विकटो पर 504 रन (पारी समाप्ति घोषणा) (सिम्पसन 121, बैरिक 102, आउट नही हुए; मार्शल 90)

भारत : पहली पारी . 153 (उमरीगर 83)

दूसरी ,, . 5 विकटों पर 447 रन (मनकद 154, गडकारी 102, आउट नही हुए)

तृतीय टैस्ट (कलकत्ता)

एस० जी० ओ० सी० टीम 6 विकटों से मैच जीत गई :

भारत : पहली पारी . 238 (उमरीगर 112, आउट नही हुए)

दूसरी ,, . 190 (रामचन्द 111, इवर्सन न 47 रनो पर 6 विकटे हासिल की)

एस० जे० ओ० सी० टीम :

पहली पारी . 245 (गुप्ते 95 रनों पर 6 विकटे, मियूलमान 75)
दूसरी „ . 4 विकटो पर 187 रन (मार्शल 88, आउट नही हुए)

टेनिस

राष्ट्रीय लॉन टेनिस सर्व-विजय प्रतियोगिता (चैम्पियनशिप) (दिसम्बर 1953-54)

पुरुष अकेले

आर० कृष्णन ने स्ट्रेट सेट 6-2, 6-3, 7-5 पर आस्ट्रेलिया के जे० आर्किनस्टाल को हरा कर टाईटल प्राप्त किया।

पिछले विजेता : सुमन्त मिश्र

पुरुष जोडे

जे० आर्किनस्टाल और इफ्तिखार एहमद ने नरेश कुमार और नरेन्द्रनाथ को 3-6, 5-7, 8-6, 7-5, 6-3 पर हराया ,

मिले-जले जोडे

इफ्तिखार एहमद और मिस पी० शेख अपने प्रतिद्वदी जोडे नरेन्द्रनाथ और मिस थापर के न खेलने के कारण जीत गये।

स्त्रियां अकेली

कुमारी रीता डावर ने कुमारी थापर को 0-6, 6-2, 6-2 पर हराया।

टेबल-टेनिस

राष्ट्रीय सर्वविजयी प्रतियोगिता (चैम्पियनशिप) (दिसंबर 1953)

पुरुष अकेले

बम्बई के एस० ठाकरसे ने मद्रास के टी० तिरुवेन्गादम को हरा कर ओपन-सिन्गल्ज टाईटल प्राप्त किया 25-23, 21-13, 15-21, 21-19।

पिछले विजेता . के० जयन्त (1950), टी० तिरुवेन्गादम (1951), के० जयन्त (1952)।

पुरुष जोड़े

बम्बई के यू० एम० चन्दराना और डी० पी० सोमाया ने बगाल के एम० बनर्जी और आर० भडारी को हराया, 22-20, 18-21, 21-12, 22-24, 21-18।

स्त्रियां अकेली

कुमारी सुलताना ने श्रीमती सी० के० के० पिल्ले को हराया, 21-12, 21-16, 21-11।

पिछली विजेता : कुमारी सुलताना (1951 और 1952)।

मिले-जुले जोड़े

कुमारी सुलताना और भंडारी ने श्रीमती राजगोपालन और चन्दराना को हराया 21-16, 21-13, 21-13 ।

अन्तर्राज्यीय सर्वविजयी प्रतियोगिता (चैम्पियनशिप) (दिसम्बर 1953)

बम्बई ने बगाल को पाच मैचों मे हरा कर चेम्पियनशिप को जीत लिया ।

हैदराबाद ने पिछले विजेता बम्बई को तीन मैचो मे हरा कर स्त्रियो के जयलक्ष्मी कप को जीत लिया ।

राष्ट्रीय खेल-कूद (फरवरी 1953)

खेलों का आयोजन जबलपुर में हुआ । सेना (सर्विसिज) ने चेम्पियनशिप को 121.5 प्वाइट्स प्राप्त कर के जीत लिया । पेप्सू 30 प्वाइट्स प्राप्त कर द्वितीय रहा और बम्बई 23 प्वाइट्स प्राप्त कर तृतीय रहा ।

इन खेलो मे 7 नये अखिल-भारतीय रेकार्ड स्थापित किये गये ।

पुरुषो के खेल

100 मीटर दौड़
1 लेवी पिन्टो (बम्बई)
2 सती घोष (बिहार)
3 बलवन्तसिह (सेना)
समय 10 8 सेकन्ड

200 मीटर दौड
1 लेवी पिन्टो (बम्बई)
2 सती घोष (बिहार)
3 कृपालसिह (पजाब)
समय 21 8 सेकन्ड (नया रिकार्ड)

400 मीटर दौड
1 ईवान जैकब (मद्रास)
2 बलवन्तसिह (पेप्सू)
3. अप्परसिह (सेना)
समय : 49 6 सेकन्ड (नया रिकार्ड)

800 मीटर दौड
1. सोहनसिह (सेना)
2 कुलवन्तसिह (सेना)
3. भगवानसिह (दिल्ली)
समय 1 मिनट 55 2 सेकन्ड (नया रिकार्ड)

1,500 मीटर दौड
1. कुलवन्तसिह (सेना)
2 नीकासिह (सेना)
3 रणजीतराम (दिल्ली)
समय . 4 मिनट 42 सेकन्ड

3,000 मीटर स्टीपलचेज दौड
1 डालूराम (सेना)
2 इन्दरसिह (सेना)
3. गुलजारासिह (पेप्सू)
समय 9 मिनट 33 4 सेकन्ड

5,000 मीटर दौड
1. डालूराम (सेना)
2. करनालसिह (सेना)
3. गुरबचनसिह (सेना)
समय : 15 मिनट 31 5 सेकन्ड

10,000 मीटर दौड़
1. धनसिह (सेना)
2. बूलासिह (सेना)
3. रौनकसिह (पेप्सू)
समय · 32 मिनट 45 8 सेकन्ड

चलना

10,000 मीटर चलना

1. हरनायकसिंह (सेना)
2. अमरीकसिंह (पंजाब)
3 नत्थाराव (राजस्थान)

समय : 55 मिनट 2 सेकन्ड

50 किलोमीटर चलना

1. बी० दास (बंगाल)
2. भागसिंह (पंजाब)
3 लालसिंह (पेप्सू)
4 एच० रोज (बंगाल)
5 इन्दरजीत सिंह (दिल्ली)

समय 5 घंटे, 32 मिनट 24 1 सेकन्ड

मैराथन दौड 26 (मील)

1. छोटासिंह (पेप्सू)
2 सुर्जनसिंह (पेप्सू)
3 सुरतसिंह (दिल्ली)

समय 2 घंटे, 33 मिनट 21 4 सेकन्ड

110 मीटर बाधा दौड

1 गुरुदुर्रसिंह (सेना)
2 हरिश्वरसिंह (सेना)
3 अजमेरसिंह (पंजाब)

समय 15 6 सेकन्ड

400 मीटर बाधा दौड

1 जोगिन्दरसिंह (सेना)
2 प्रीतमसिंह (सेना)
3. दर्शनसिंह (पंजाब)

समय : 55 6 सेकन्ड

4,100 मीटर रिले दौड

1. बम्बई
2 दिल्ली
3. मद्रास
4. पेप्सू

समय · 44 2 सेकन्ड

4,400 मीटर रिले दौड

1. सेना
2. पेप्सू
3 मद्रास

समय · 3 मिनट 23 9 सेकन्ड (नया रिकार्ड)

दौड कर ऊंची कूद

1. अजीतसिंह (पंजाब)
2 के० चटर्जी (बंगाल)
3 दयालसिंह (सेना)

ऊंचाई 6 फीट 3 5 इंच

दौड कर लांघना

1 केहरसिंह (सेना)
2 भागसिंह (सेना)
3 कृपालसिंह (पंजाब)

फासला 22 फीट 7 75 इंच

भार फेंकना

1 लक्ष्मीप्रसाद (सेना)
2 कृष्णसिंह (पेप्सू)
3 बीघीराम (सेना)

फासला 142 फीट 1 इंच

डिस्क फेंकना

1 बख्शीश सिंह (पंजाब)
2 माखन सिंह (सेना)
3 ईशर सिंह (पेप्सू)

फासला . 131 फीट 1.25 इंच

जैवेलिन फेंक

1 सुरतसिंह (सेना)
2 राजगोपालन् (दिल्ली)
3 गोविन्दराम (दिल्ली)

फासला · 176 फीट

डिकैथलन्

1. गुरनामसिंह (पेप्सू) 4,367 प्वाइंट
2. एम० कौड्स (बम्बई) 4,345 "
3. एन० के० दास (उड़ीसा) 4,302"

उछलना, कदम लेना और कूदना

1. केहरसिंह (सेना)
2. सुदर्शनसिंह (सेना)
3. दर्शनसिंह (पजाब)

फासला : 46 फीट 10 इच

गोला फेकना

1. परदुमनसिंह (सेना)
2. मोहिन्दरसिंह (सेना)
3. ईशरसिंह (पेप्सू)

फासला : 44 फीट 10 इंच

बांस से कूदना

1. जार्ज (सेना)
2. भगवानसिंह (सेना)
3. पी० वासवन (तिरुवाकुर-कोचीन)

ऊंचाई : 11 फीट 11 इच

स्त्रियों के खेल

100 मीटर

1. मेरी डी० सूजा (बम्बई)
2. ए० काचातूर (बंगाल)
3. जोन टैलिस (बम्बई)

समय : 13 सेकन्ड

200 मीटर

1. मेरी डी० सूजा (बम्बई)
2. ए० काचातूर (बगाल)
3. स्टिफी डी० सूजा (बम्बई)

समय : 26.4 सेकन्ड

4,00 मीटर रिले

1. बम्बई
2. बंगाल
3. मध्यप्रदेश

समय : 52.5 सेकन्ड

80 मीटर बाधा दौड

1. मेरी ड़ी० सूजा (बम्बई)
2. मेरी सीमोज (बम्बई)
3. नीलिमा घोष (बंगाल)

समय : 12.7 सेकन्ड (नया रिकार्ड)

दौड कर ऊंचा कूदना

1. मेरी सीमोज (बम्बई)
2. पी० वसु (मध्य प्रदेश)
3. सी० ओडी (मध्य प्रदेश)

ऊंचाई : 4 फीट 2 34 इच

दौड़ कर दूर लाघना

1. स्टिफी डी० सूजा (बम्बई)
2. लूसी पाल (तिरुवाकुर-कोचीन)
3. मेरी कैस्टेलीन (बम्बई)

फ़ासला : 13 फीट 3 5 इच

गोला फेंकना

1. आर० थौर्नबर (बम्बई)
2. ए० मसावजी (मध्य प्रदेश)
3. एस० थामस (तिरुवाकुर-कोचीन)

फासला 29 फीट 3.25 इच

डिस्क्स फेकना

1. पी० प्राउडफुट (बम्बई)
2. ए० मजाओ (मध्यप्रदेश)
3. सी० भिडे (बम्बई)

फ़ासला : 90 फ़ीट 0.5 इंच

उन्तीसवां अध्या

1953 की घटनाओं की सूची

जनवरी

तारीख

1 भोपाल मे अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का अधिवेशन समाप्त हुआ ।

2 नई दिल्ली मे रेडियोलौजी की 7वी भारतीय काग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ ।

5 नई दिल्ली में गाधीवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन हुआ ।

5 इलाहाबाद मे अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का प्रारम्भ ।

6 डाक्टर सैफुद्दीन किचलू को स्टालिन शाति पुरस्कार दिया गया ।

7 रंगून में एशियन सोशलिस्टो का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ ।

12 दिल्ली मे राजकुमारी अमृतकौर ने वल्लभभाई पटेल चैस्ट इन्स्टीच्यूट का उद्घाटन किया ।

13 बम्बई के निकट प्रधान मत्री ने अम्बरनाथ मशीन टूल फैक्टरी का उद्घाटन किया । जनरल के० एम० करिअप्पा ने भारत के कमान्डर-इन-चीफ के पद से अवकाश ग्रहण किया ।

14 डाक्टर राधाकृष्णन ने कराएकुडी मे केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान सस्था का उद्घाटन किया ।

14 हैदराबाद के नानलनगर मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ ।

15 जनरल राजेद्रसिंह जी भारत के कमान्डर-इन-चीफ नियुक्त हुए ।

16 अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की विषय समिति ने पचवर्षीय आयोजना को स्वीकार किया ।

17 नानलनगर मे श्री जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय काग्रेस के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपना भाषण दिया ।

17 डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने गाधियन सेमीनार के सम्मुख भाषण दिया ।

17 अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने राज्यो के पुनस्संगठन के सम्बन्ध मे प्रस्ताव स्वीकार किया ।

18 नानलनगर मे अखिल भारतीय काग्रेस का अधिवेशन समाप्त हुआ ।

19 भारत से काबुल के हवाई मार्ग के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान में समझौता हुआ ।

19 डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध मे विशेषज्ञो की रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार किया ।

20 श्री जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद मे शारीरिक शिक्षा अकादमी का उद्घाटन किया ।

24 तिरुवांकुर-कोचीन में मछली व्यवसाय का विकास करने के लिये भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा नार्वे के साथ समझौता किया ।

13 M of I & B.

तारीख

28 भारत और वेस्ट इण्डीज के बीच पहला टैस्ट मैच बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ।

29 नई दिल्ली मे राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रीय नृत्य-नाटक और सगीत अकादमी का उद्घाटन किया।

29 न्यायाधीश वाचू ने आंध्र के सम्बन्ध मे अपनी जाच समाप्त कर ली।

29 पाकिस्तान ने किसी भी दशा मे युद्ध न करने की घोषणा के सम्बन्ध मे भारत के प्रधान मंत्री का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया।

30 उडीसा हाईकोर्ट ने उडीसा राज्य इस्टेट कानून को वैध घोषित किया।

31 भारत और इन्डोनेशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए।

फ़रवरी

2 दिल्ली में प्रधान मत्री ने अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्घाटन किया।

2 भारत और पाकिस्तान मे पासपोर्ट पद्धति मे उदारता से काम लेने का समझौता हुआ।

6 श्री सी० सी० देसाई लका मे भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त हुए।

6 भारतीय इलैक्शन कमीशन ने कांग्रेस, प्रजासोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तथा जनसंघ को अखिल भारतीय पार्टियों के रूप में स्वीकार किया।

10 इंग्लैंड के मजदूर नेता श्री एनुरिन बेवन नई दिल्ली मे आये।

10 भारत के रक्षा मत्री श्री एन० गोपालास्वामी का मद्रास मे देहान्त हो गया।

11 राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट के बजट अधिवेशन का उद्घाटन किया।

12 दूसरे टेस्ट मैंच में वैस्ट इण्डीज टीम भारत से 142 रनों द्वारा जीत गई।

19 आस्ट्रेलियन प्रेस डेलीगेशन भारत की तीन सप्ताह की यात्रा पर कलकत्ता पहुंचा।

21 प्रधान मत्री ने तल्लैया बांध और बोकारो बिजली स्टेशन का उद्घाटन किया।

21 श्री सुकुमार सेन सूडान के निर्वाचन कमीशन में नियुक्त हुए।

27 भारत के वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में नया बजट पेश किया।

28 मद्रास मे डाक्टर टी० विजयाराघवाचार्य का देहान्त हुआ।

मार्च

1 श्री ज्ञानसिंह राड़ेवाला ने पेप्सू के मुख्य मंत्रित्व से त्यागपत्र दे दिया।

5 बिहार के चांडिल नामक ग्राम में भूदान यज्ञ के प्रमुख कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे से विचार विमर्श के निमित्त मिले।

7 नई दिल्ली में प्रधान मंत्री ने भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

8 टर्की का पार्लियामेंट प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली पहुंचा।

10 बम्बई में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० के० टी० शाह का देहान्त हुआ।

11 श्री चन्द्रीकेश्वर प्रसाद नारायण सिंह पंजाब के राज्यपाल नियक्त हुए।

16 श्री महावीर त्यागी प्रतिरक्षा सगठन के मंत्री नियुक्त हुए।

17 पार्लियामेंट में प्रधान मंत्री ने भारत में विदेशी पाकेटों के विरुद्ध घोषणा की।

तारीख

24 होल्कर टीम रणजी ट्राफ़ी जीत गई ।

25 प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि पहली अक्तूबर को आंध्र राज्य का निर्माण किया जायेगा ।

28 संवादवहन के मंत्री ने घोषणा की कि 31 मार्च, 1954 तक भारत के प्रत्येक गांव में, जिसकी आबादी 2,000 से ऊपर है, एक डाकखाना अवश्य खोला जायेगा ।

30 भारत और बर्मा के प्रधान मंत्रियों ने एक साथ आसाम और बर्मा के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया ।

31 डाक्टर ग्राहम ने काश्मीर के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को पेश की ।

अप्रैल

1 बर्न में भारत के राजदूत श्री आसफअली का देहान्त हुआ ।

1 भारतीय वायु सेना ने अपनी 20वीं वर्षगाठ मनाई ।

8 श्री वालचन्द हीराचन्द का देहान्त हुआ ।

9 पार्लियामेंट ने खादी बिल पास किया ।

12 भारत के शिक्षा मंत्री ने रुड़की में केन्द्रीय निर्माण अनुसन्धान शाला का उद्घाटन किया ।

18 लोकसभा ने वित्त बिल पास किया ।

19 भारतीय रेलवे कार्यकर्ताओं के दो मुख्य संगठन मिल कर एक हो गये और इस संगठन का नाम भारतीय रेलवे कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय फेडरेशन रखा गया ।

28 प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा ।

30 जनरल करिअप्पा आस्ट्रेलिया में भारत के कमिश्नर नियुक्त हुए ।

मई

2 प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि युद्ध होने की स्थिति में भारत किसी गुट का साथ नहीं देगा ।

3 डमडम हवाई अड्डे से 25 मील दूर बी० ओ० ए० सी० का कोमेट विमान टूटा ।

4 भारत में अमेरिका के नये राजदूत श्री जार्ज एलेन ने राष्ट्रपति के सन्मुख अपने कागज़ पेश किये ।

11 डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी काश्मीर में अनियमित प्रवेश के आधार पर लखीमपुर में गिरफ्तार किये गये ।

15 प्रधान मंत्री ने सर चर्चिल के बड़े राष्ट्रों की कांफ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन किया ।

20 अमेरिका के सैक्रेटरी आफ स्टेट मि० जान फोस्टर डलेस नई दिल्ली पहुंचे ।

20 भारत सरकार ने शरणार्थियों को मुआवजा देने की एक नई स्कीम की घोषणा की ।

28 प्रधान मंत्री महारानी एलिज़ाबेथ के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली से लंदन को रवाना हुए ।

29 शेरपा तेनसिंह नोरकी तथा एडमण्ड हिलैरी मानव जाति के इतिहास में पहली बार संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुंचे ।

तारीख

30 भारत सरकार का 75 करोड का कर्ज पूर्ण रूप से बिक गया।

31 त्रिवेन्द्रम मे आइ० एफ० डब्ल्यू० जे० का दूसरा वार्षिक अधिवेशन समाप्त हुआ।

जून

2 लदन मे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ।

4 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने श्री जवाहरलाल नेहरू को डाक्टर ऑफ ला की मानर्नाय पदवी दी।

5 मद्रास विधान सभा के आध्र सदस्यो ने बहुमत से यह निश्चय किया कि करनूल को आध्र की राजधानी बनाया जाय।

10 लिस्बन भारतीय दूतावास बन्द कर दिया गया।

12 भारत ने यह स्वीकार कर लिया कि वह कोरिया के युद्धबन्दी कमीशन का सदस्य बनेगा।

23 श्रीनगर के अस्पताल मे डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी का देहान्त हुआ।

23 काहिरा मे भारत के प्रधानमत्री जनरल नजीब और श्री मोहम्मद अली से मिले।

23 रूस के राजदूत श्री आई० ए० बैनेडिक्टोव नई दिल्ली पहुचे।

जुलाई

1 तुगभद्रा के जलभंडार से सिचाई के लिये पानी छोड़ा गया।

2 श्री वेकटारमन् शास्त्री का देहान्त हो गया।

3 प्रधान मंत्री ने यह अपील की कि प्रजा परिषद् आन्दोलन समाप्त कर दिया जाय।

7 अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि पचवर्षीय आयोजना मे बेकारी की समस्या सुलझाने पर विशेष बल दिया जाय।

7 जम्मू में प्रजा परिषद् आन्दोलन समाप्त कर दिया गया।

8 काहिरा मे भारत और मिस्त्र के बीच व्यापारिक सधि हुई।

10 भारत सरकार ने कपड़ा और सूत की कीमतो और वितरण पर से कन्ट्रोल उठा लिया।

13 फारवर्ड ब्लाक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गया।

17 डाक्टर बी० वी० केसकर ने यह अपील की कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्धार किया जाय।

25 भारत के प्रधान मंत्री कराची मे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिले।

27 मद्रास विधान सभा ने आध्र राज्य बिल पास कर दिया।

अगस्त

1 स्टेट एअर कारपोरेशन का उद्घाटन किया गया।

4 पाकिस्तान के नये हाई कमिश्नर श्री गज़नफरअली खा नई दिल्ली मे पहुंचे।

9 सदरे रियासत ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पदच्युत कर दिया।

9 बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू और काश्मीर के नये प्रधान मंत्री नियुक्त हुए।

9 शेख अब्दुल्ला नजरबन्द कर लिये गये।

तारीख

10 गृह मंत्री ने यह घोषणा की कि पेप्सू मे 1954 मे आम चुनाव होगे ।

15 देश भर मे स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया गया ।

16 गोदावरी मे बहुत बड़ी बाढ आई ।

20 दिल्ली मे पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियो ने सम्मिलित रूप से यह निश्चय किया कि अप्रैल 1954 के अन्त तक जम्मू और काश्मीर के लिये प्लैबिसिट एडमिनिस्ट्रेटर (लोक-सम्मति व्यवस्थापक) को नियुक्त कर दिया जायगा ।

सितम्बर

1 भारतीय कस्टोडियन फोर्स का पहला दस्ता कोरिया पहुचा ।

1 प्रजा सोशलिस्ट नेता श्री अशोक मेहता पारडी सत्याग्रह के सम्बन्ध मे गिरफ्तार हुए ।

3 श्री सैयद जफर इमाम बिहार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए ।

4 मैसूर सरकार ने निश्चय किया कि भविष्य मे $16\frac{2}{3}$ सरकारी नौकरिया परिगणित जातियो और आदिवासियो को दी जायेगी ।

8 फिलिपाइन सरकार ने भारतीयो के आने पर से पाबन्दी हटा ली ।

14 भारत सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका मे भारतीय परिवारो का प्रवेश न होने देने की नीति का विरोध किया ।

15 श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित सयुक्त राष्ट्र सघ की जनरल असेम्बली के 8वे अधिवेशन की प्रधान चुनी गई ।

18 नई दिल्ली मे राज्यो के सूचना मत्रियो की दो दिन की काफ्रेस प्रारम्भ हुई ।

23 तिरुवाकुर-कोचीन विधान सभा मे सरकार के प्रति विश्वास का प्रस्ताव गिर गया और राज्य की विधान सभा भग कर दी गई । यह घोषणा की गई कि अगले निर्वाचन तक श्री ए० जे० जोन का मत्रिमडल काम चलाता रहेगा ।

25 बिहार मे देवगढ का वैद्यनाथ मदिर हिन्दूमात्र के लिये खोल दिया गया ।

अक्तूबर

1 आध्र राज्य का उद्घाटन हुआ और टी० प्रकाशम उसके प्रथम मुख्य मत्री नियुक्त हुए ।

1 श्री चन्दूलाल एम० त्रिवेदी ने आध्र राज्य के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की ।

3 मद्रास मे डा० अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का देहान्त हुआ ।

4 कलकत्ता मे वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई के उपमंत्री श्री एस० एन० बरगोहन का देहान्त हुआ ।

4 भारत सयुक्त राष्ट्र संघ की ट्रस्टीशिप कौसिल का सदस्य चुना गया ।

7 राष्ट्रपति ने पजाब की नई राजधानी चडीगढ का उद्घाटन किया ।

9 बम्बई मे राष्ट्रपति ने नौसेना की प्रथम रिव्यू देखी ।

14 इस्टेट ड्यूटी एक्ट जारी हुआ ।

14 विश्व बैंक ने भारत को 50 करोड पौड दामोदर वैली कारपोरेशन तथा लोहे के कार्यों के लिये उधार दिया ।

तारीख

15 भारत सरकार ने मैसूर सरकार को लक्कावल्ली कार्य के लिये 3 करोड़ रुपये , कर्ज जारी करने की अनुमति दी।

15 कोरिया में युद्ध बन्दियों का एक्स्प्लेनेशन प्रारम्भ हुआ।

22 भारत सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय राजाओं की व्यक्तिगत आय पर आय-कर लगाया जाय।

29 उत्तर पूर्वी सरहद की अबोर पहाड़ियों पर कुछ आदिवासियों ने सरकारी कार्यकर्ताओं और फौज के व्यक्तियों की एक टुकड़ी पर आक्रमण किया।

30 'ख' भाग के राज्यों के सम्बन्ध में गाडगिल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की।

नवम्बर

1 नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने भारतीय तार शताब्दी प्रदर्शिनी का उद्घाटन किया।

9 विशाखापटनम में भारत के उत्पादन मंत्री ने जलपुत्र नामक 1,000 टन के जहाज का जल प्रवेश किया।

11 रांची में राष्ट्रपति ने दूसरी अखिल भारतीय आदिवासी कल्याण कांफ्रेस का उद्घाटन किया।

15 प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हो रही इस बातचीत के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की कि अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देगा।

17 नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की दो दिनों की कान्फ्रेन्स समाप्त हुई।

21 पाकिस्तान ने भारत के 20 रोके हुए इंजन वापिस किये।

24 जनरल थिमैया न इस सम्बन्ध में रिपोर्ट की कि उनके मिशन का कार्य कितना कठिन है।

30 ज्यूरिच में श्री बी० एन० राव का देहान्त हो गया।

0 अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री रिचर्ड निक्सन नई दिल्ली पहुंचे।

लोकसभा ने व्यावसायिक कलह बिल पास किया।

दिसम्बर

2 भारत और रूस के बीच पंचवर्षीय व्यापारिक संधि हुई।

3 भारत के योजना मंत्री ने यह घोषणा की कि पंचवर्षीय आयोजना पर 150 से लेकर 170 करोड़ रुपये तक अधिक व्यय आयेगा।

11 प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि प्रस्तावित पाकिस्तान और अमेरिकन सैनिक संधि का प्रभाव सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया की शांति को भंग कर देगा। क्योंकि वह इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को तोड़ देगा।

15 यह घोषणा की गई कि मार्च 1954 में तिरुवांकुर-कोचीन और पेप्सू में नये निर्वाचन होंगे।

18 इंग्लैंड के मजदूर नेता श्री सी० आर० एटली ने घोषणा की कि संसार में प्रजातंत्र पद्धति के पनपने में भारत का महत्व बहुत अधिक है।

तारीख

21 भारत सरकार का जर्मनी के क्रुप्स कारखाने से यह समझौता हुआ कि भारत में 100 करोड़ रुपयों की लागत से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड नाम का इस्पात का कारखाना खोला जायगा ।

22 प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि राज्यों के पुनर्संगठन के उद्देश्य से एक कमीशन नियुक्त किया जा रहा है ।

24 भारतीय रेलवे के लिये अमेरिका और भारत में यह समझौता हुआ कि अमेरिका भारत को 2 करोड़ डालर देगा ।

30 भारत में अस्पृश्यता को अपराध घोषित करने वाला कानून गजट में प्रकाशित कर दिया गया ।

31 प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि वह किसी भी दशा में विदेशी सेना को भारत की भूमि पर नहीं आने देंगे ।

तीसवां अध्याय
वर्ष के कानून
1953

कानून 1	पेश होने का समय 2	प्रारम्भ करने वाले भवन में स्वीकृत होने की तारीख 3	दूसरे भवन में स्वीकृत होने की तारीख 4	राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने की तारीख 5
1 स्वीकृतिकरण कानून 1953	19 फरवरी 1953	19 फरवरी 1953	23 फरवरी 1953	5 मार्च 1953
2 भारतीय तटकर (संशोधन) कानून 1953	20 फरवरी 1953	4 मार्च 1953	9 मार्च 1953	16 मार्च 1953
3 संनियन अन्तरिम कर (वितरण) कानून 1953	27 फरवरी 1953	3 मार्च 1953	9 मार्च 1953	18 मार्च 1953
4 स्वीकृतिकरण (वोट ऑन एकाउन्ट) कानून 1953	3 मार्च 1953	3 मार्च 1953	7 मार्च 1953	19 मार्च 1953
5. स्वीकृतिकरण (रेलवे) कानून 1953	2 मार्च 1953	3 मार्च 1953	7 मार्च 1953	19 मार्च 1953
6 स्वीकृतिकरण (रेलवे) नं० 2 कानून 1953	3 मार्च 1953	3 मार्च 1953	7 मार्च 1953	19 मार्च 1953
7 पटियाला और पूर्वी-पंजाब राज्य संनियन स्वीकृति-करण कानून 1953	26 मार्च 1953	26 मार्च 1953	28 मार्च 1953	31 मार्च 1953
8 पटियाला और पूर्वी-पंजाब राज्य संनियन स्वीकृति-करण (वोट ऑन एका-उन्ट) कानून 1953	26 मार्च 1953	26 मार्च 1953	28 मार्च 1953	31 मार्च 1953
9 स्वीकृतिकरण (नं० 2) कानून 1953	26 मार्च 1953	26 मार्च 1953	28 मार्च 1953	31 मार्च 1953
10 हैदराबाद मुद्रा और कागजी मुद्रा (विविध व्यवस्थाएं) कानून 1953	27 मार्च 1953	28 मार्च 1953	31 मार्च 1953	31 मार्च 1953
11 निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन संशोधन कानून 1953	4 अगस्त 1952	20 फरवरी 1953 26 मार्च 1953	25 फरवरी 1953	9 अप्रैल 1953

1	2	3	4	5
12. खादी और अन्य करघा उद्योगो का विकास (कपडो पर अतिरिक्त उत्पादन कर) कानून 1953	14 फरवरी 1953	9 अप्रैल 1953	14 अप्रैल 1953	14 अप्रैल 1953
13 स्वीकृतिकरण (न० 3) कानून 1953	7 अप्रैल 1953	8 अप्रैल 1953	16 अप्रैल 1953	23 अप्रैल 1953
14 वित्त कानून 1953	27 फरवरी 1953	18 अप्रैल 1953	23 अप्रैल 1953	25 अप्रैल 1953
15 केन्द्रीय उत्पादन और नमक (सशोधन कानून) 1953	14 अप्रैल 1953	18 अप्रैल 1953	23 अप्रैल 1953	25 अप्रैल 1953
16 अनसूचित-क्षत्र (विधि सामजस्य) कानून 1953	28 मार्च 1953	9 अप्रैल 1953	25 अप्रैल 1953	6 मई 1953
17 पटियाला और पूर्वी पजाब राज्य यूनियन स्वीकृति-करण (न० 2) कानून 1953	2 मई 1953	2 मई 1953	8 मई 1953	15 मई 1953
18 भारतीय लाइट हाउस (सशोधन) कानून 1953	14 नवम्बर 1952	25 अप्रैल 1953	29 अप्रैल 1953	16 मई 1953
19 सिनेमैटोग्राफ (सशो-धन) कानून 1953	27 नवम्बर 1952	25 अप्रैल 1953	29 अप्रैल 1953	16 मई 1953
20. ससद के अफसरो का वेतन और भत्ता कानून, 1953	11 मार्च 1953	28 अप्रैल 1953	5 मई 1953	16 मई 1953
21 कन्ट्रोलर और आडिटर जनरल (सेवा की शर्ते) कानून 1953	15 अप्रैल 1953	29 अप्रैल 1953	7 मई 1953	17 मई 1953
22 पटियाला और पूर्वी पजाब राज्यो के विधान मण्डल (अधिकार दान) कानून 1953	6 अप्रैल 1953	30 अप्रैल 1953	12 मई 1953	17 मई 1953
23 भारतीय व्यापारिक जहाजरानी (सशोधन) कानून 1953	20 नवम्बर 1953	27 अप्रैल 1953	1 मई 1953	21 मई 1953
24 दिल्ली सडक-यातायात प्रशासन (सशोधन) कानून 1953	6 मई 1953	13 मई 1953	15 मई 1953	22 मई 1953
25. भारतीय आयकर (सशोधन) कानून 1953	26 मई 1952	25 अप्रैल 1953	1 मई 1953	24 मई 1953

1	2	3	4	5
26. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन कानून 1953	10 अप्रैल 1953	5 मई 1953	12 मई 1953	26 मई 1953
27. वायु कार्पोरेशन कानून 1953	21 मार्च 1953	8 मई 1953	14 मई 1953	28 मई 1953
28. विन्ध्यप्रदेश विधान मण्डल (निर्योग्यता के विरुद्ध सरक्षण) कानून 1953	2 अप्रैल 1953	13 मई 1953	16 मई 1953	28 मई 1953
29. चाय कानून 1953	17 दिसम्बर 1952	9 मई 1953	15 मई 1953	28 मई 1953
30. आन्ध्र राज्य कानून 1953	10 अगस्त 1953	27 अगस्त 1953	12 सितम्बर 1953	14 सितम्बर 1953
31. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सशोधन) कानून 1953	19 दिसम्बर 1952	5 अगस्त 1953	26 अगस्त 1953	18 सितम्बर 1953
32. आकडा सग्रह कानून 1953	19 दिसम्बर 1952	6 अगस्त 1953	27 अगस्त 1953	18 सितम्बर 1953
33. स्वीकृतिकरण (न० 4) कानून 1953	15 सितम्बर 1953	15 सितम्बर 1953	17 सितम्बर 1953	29 सितम्बर 1953
34. सम्पत्ति कर कानून 1953	11 अगस्त 1952	15 सितम्बर 1953	22 सितम्बर 1953	6 अक्तूबर 1953
35. समुद्री शुल्क (सशोधन) कानून 1953	24 अप्रैल 1953	17 नवम्बर 1953	26 नवम्बर 1953	5 दिसम्बर 1953
36. पुनर्वास वित्त प्रशासन (सशोधन) कानून 1952	15 नवम्बर 1953	17 नवम्बर 1953	25 नवम्बर 1953	10 दिसम्बर 1953
37. कर्मचारी प्रोविडेंट फड (संशोधन) कानून 1953	14 सितम्बर 1953	24 नवम्बर 1953	1 दिसम्बर 1953	12 दिसम्बर 1953
38. तिरुवांकुर-कोचीन उच्च-न्यायालय (सशोधन) कानून 1953	4 मार्च 1953	9 अप्रैल 1953	8 दिसम्बर 1953	15 दिसम्बर 1953
39. धोती (अतिरिक्त उत्पादन कर) कानून 1953	21 नवम्बर 1953	21 नवम्बर 1953	7 दिसम्बर 1953	16 दिसम्बर 1953
40. पालतू पशु पक्षी (सशोधन) कानून 1953	13 फरवरी 1953	18 फरवरी 1953	9 दिसम्बर 1953	16 दिसम्बर 1953
41. कलकत्ता उच्च न्यायालय (क्षेत्र का विस्तार) कानून 1953	22 अप्रैल 1953	27 अप्रैल 1953	9 दिसम्बर 1953	18 दिसम्बर 1953
42. रद्द और सशोधित करने का कानून, 1953	9 अप्रैल 1953	20 अप्रैल 1953	11 दिसम्बर 1953	23 दिसम्बर 1953

1	2	3	4	5
43 औद्योगिक सघर्ष (सशोधन) कानून 1953	18 नवम्बर 1953	30 नवम्बर 1953	10 दिसम्बर 1953	23 दिसम्बर 1953
44. मणिपुर न्यायालय शुल्क (सशोधन और प्रमाणीकरण) कानून 1952	15 नवम्बर 1952	3 दिसम्बर 1953	17 दिसम्बर 1953	23 दिसम्बर 1953
45. नारियल रेशा उद्योग कानून 1953	26 मार्च 1953	19 नवम्बर 1953 14 दिस० (क) 1953	2 दिसम्बर 1953	23 दिसम्बर 1953
46. फाटका (विनिमयन) सशोधन कानून, 1953	3 सितम्बर 1953	2 दिसम्बर 1953	15 दिसम्बर 1953	23 दिसम्बर 1953
47. भारतीय टैरिफ (दूसरा सशोधन) कानून 1953	13 सितम्बर 1953	14 सितम्बर 1953	21 दिसम्बर 1953	25 दिसम्बर 1953
48. भारतीय टैरिफ (तीसरा सशोधन) कानून 1953	10 सितम्बर 1953	15 दिसम्बर 1953	21 दिसम्बर 1953	26 दिसम्बर 1953
49. नमक चुगी कानून 1953	15 दिसम्बर 1953	21 दिसम्बर 1953	24 दिसम्बर 1953	26 दिसम्बर 1953
50. स्वीकृतिकरण (न० 5) कानून 1953	19 दिसम्बर 1953	19 दिसम्बर 1953	22 दिसम्बर 1953	26 दिसम्बर 1953
51. पटियाला और पूर्वी पजाब राज्य यूनियन का स्वीकृतिकरण (न० 3) कानून 1953	19 दिसम्बर 1953	19 दिसम्बर 1953	22 दिसम्बर 1953	26 दिसम्बर 1953
52. बेंकिंग कम्पनी (सशोधन) कानून 1953	16 नवम्बर 1953	3 दिसम्बर 1953	15 दिसम्बर 1953	30 दिसम्बर 1953
53. टेलीग्राफ (अवैध स्वामित्व) संशोधन कानून 1952	15 नवम्बर 1952	4 दिसम्बर 1953	17 दिसम्बर 1953	30 दिसम्बर 1953
54. भारत के रिजर्व बेंक (सशोधन और विविध व्यवस्था) कानून 1952	21 नवम्बर 1952	8 दिसम्बर 1953	19 दिसम्बर 1953	30 दिसम्बर 1953
55. भारतीय पेटेन्ट और डिज़ाइन (सशोधन) कानून 1952	4 अगस्त 1953	7 दिसम्बर 1953	19 दिसम्बर 1953	30 दिसम्बर 1953
56. निर्योग्यता के विरुद्ध सरक्षण (संसद और भाग 'ग' राज्यो के विधान मण्डल) कानून 1953	10 दिसम्बर 1953	16 दिसम्बर 1953	24 दिसम्बर 1953	1 जनवरी 1954

(क) राज्य सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन लोक सभा में पास था।

1	2	3	4	5
57. कन्टोनमेंट (संशोधन) कानून 1952	30 जुलाई 1952	11 फरवरी 1953 19 दिसम्बर 1953 (क)	10 दिसम्बर 1953	2 जनवरी 1954
58. प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और भवनों तथा अवशेषों (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) का संशोधन कानून 1953	15 अप्रैल 1953	20 अप्रैल 1953 19 दिसम्बर 1953 (क)	3 दिसम्बर 1953	2 जनवरी 1954

(क) लोक सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन राज्य सभा में पास हुआ ।

नोट:— अनुक्रम 1 से 9, 11 से 17, 17 से 23, 25 से 36, 39, 43, से 45 और 47 से 55 तक के कानून पहले लोक सभा में पेश हुए ।

अनुक्रम 10, 16, 24, 37, 38, 40 से 42, 46 और 56 से 58 तक के कानून पहले राज्य सभा में पेश हुए ।

इकत्तीसवां अध्याय

सामान्य जानकारी

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य

अध्यक्ष

आर० एन० बनर्जी

सदस्य

एन० गोविंदराजन

सी० बी० नागरकर

एन० के० सिद्धान्त

ए० ए० ए० फैज़ी

एस० वी० कानूनगो

कम्ट्रोलर और भारत के आडिटर-जनरल

वी० नरहरि राव

अग्रिमता का वारण्ट
(दिसम्बर 1953)

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3 राज्यपाल, राजस्थान के महाराजप्रमुख और राजप्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर

3. क भारत के उप-राष्ट्रपति

4. भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व गवर्नर-जनरल

4. क अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर लेफ्टीनेन्ट जनरल

5. अपने राज्यो मे 17 तोपों या उन से अधिक की सलामी प्राप्त करने वाले भारतीय राज्यो के नरेश

6. भारत मे विदेशी राजदूत
भारत में कामनवेल्थ सरकारो के हाई कमिश्नर

7. भारत के प्रमुख न्यायाधीश
लोक-सभा के अध्यक्ष

8. अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर राज्यपाल, राजस्थान के महाराजप्रमुख और राजप्रमुख

9. भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री

9. क. अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर लेफ्टीनेन्ट गवर्नर

10. अपने राज्यो से बाहर 17 या उस से अधिक तोपों की सलामी प्राप्त भारतीय राज्यों के नरेश

11. 'क' और 'ख' भाग के राज्यो के अपने अपने राज्यों में मुख्य मंत्री
12. 13 या 15 तोपों की सलामी प्राप्त भारतीय राज्यों के नरेश
13. पूर्णाधिकारापन्न मंत्री और एनवाय एक्स्ट्राँडिनरी
14. भारतीय यूनियन के लिये राज्य के मंत्री
आयोजना कमीशन के सदस्य
14. क. 'ग' भाग के चीफ कमिश्नर, जिन के मंत्रिमंडल उन के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर है
14 ख. अपने अपने राज्यों में 'ग' भाग के राज्यों के मुख्यमंत्री
14. ग. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
15. भारत के राजदूत और दौरे पर गये हुए राजदूत
भारत के दौरे पर आये हुए विदेशी राजदूत
दौरे पर आये हुए भारत के हाई कमिश्नर और भारत के दौरे पर आये हुए अन्य कामनवेल्थ देशों के हाई कमिश्नर
16. शा. द-फेयर और 'ए-पीड' एवं 'एड इंटेरिम' स्थानापन्न हाई कमिश्नर
17. चीफ़ आफ स्टाफ़ और प्रधान सेनाध्यक्ष, बशर्ते उन्हें पूरे जनरल या उस के बराबर का ओहदा प्राप्त हो
18 अपने अपने राज्यो के बाहर भाग 'क' राज्यो के मुख्य मंत्री
अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर भाग 'ख' राज्यों के मुख्य मंत्री
भारतीय यूनियन के उप-मंत्री
भारत के अटर्नी-जनरल
भारत के कम्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल
19. उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश
'क' और 'ख' भाग राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष
'क' और 'ख' भाग राज्यों के विधान-मंडलों के अध्यक्ष
20. चीफ़-आफ़ स्टाफ़ और प्रधान सेनाध्यक्ष, बशर्ते उन्हें लेफ्टीनेन्ट जनरल या उसके बराबर का ओहदा प्राप्त हो
21. 11 या ९ तोपों की सलामी प्राप्त भारतीय नरेश
22. 'क' और 'ख' भाग राज्यों के मंत्री
23. यूनियन पब्लिक सर्विसकमीशन के अध्यक्ष
प्रधान चुनाव-कमिश्नर
24. उच्च-न्यायालय के स्थायी-न्यायाधीश
25 भाग 'क' राज्यों के उप-मंत्री
26 लोकसभा के सदस्य
27. पूरे जनरल के ओहदे प्राप्त अफसर या उसके बराबर के ओहदे वाले अफसर
भारत के सोलिसिटर जनरल
राष्ट्रपति के सचिव
भारत सरकार के सचिव और
प्रधान मंत्री के प्रिन्सिपल निजी सचिव

अनुसूचित जातियो और जन जातियों के कमिश्नर
पुनर्वास सम्बन्धी मामलों के परामर्शदाता
स्थानापन्न चीफ़ आफ़ स्टाफ़ और प्रधान-सेनापति, जिनको मेजर-जनरल या उस के बराबर का ओहदा प्राप्त है
'ग' भाग के चीफ़ कमिश्नर जिन के मन्त्रिमडल उन के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है
बाहर से आगत भारत के पूर्णाधिकार प्राप्त मत्री और भारत आए हुए पूर्णाधिकार प्राप्त विदेशी मत्री
रेलवे-बोर्ड के अध्यक्ष
रेलवे वित्त-कमिश्नर

27. क. अपने अपने राज्यों के बाहर 'ग' भाग के मुख्य मत्री
27. ख. अपने अपने राज्यों और बाहर 'ग' भाग राज्यो के विधान मडलो के अध्यक्ष
27. ग. अपने अपने राज्यों के अन्दर और बाहर 'ग' भाग राज्यो के मत्री
28. रेलवे बोर्ड के सदस्य
कामनवेल्थ और विदशी मिशनो के मत्री, जो पूर्णाधिकार प्राप्त नही हैं
लेफ्टीनेन्ट-जनरल के ओहदे के या उस के समान ओहदा रखने वाले अफसर
29. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ, त्रिपुरा और मणिपुर के चीफ कमिश्नर अपने अधिकार क्षेत्र मे ;
भारतीय सरकार के अतिरिक्त सचिव
भारतीय टैरिफ बोर्ड के अध्यक्ष
केन्द्रीय विद्युत कमीशन के अध्यक्ष
केन्द्रीय जल-शक्ति सिचाई और नौका-नयन कमीशन के अध्यक्ष
भारतीय कृषि अनुसन्धान सभा के उप-प्रधान
वित्त-विभाग (सुरक्षा) के वित्तीय परामर्शदाता
केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष
सशस्त्र-सेना के मेजर-जनरल या उस के बराबर का ओहदा रखने वाले पी० एस० ओ०*
30. राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रधान
'क' भाग के राज्य सरकारो के प्रधान सचिव
वित्तीय कमिश्नर
केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य
भारतीय जल-सेना के स्क्वाड्रन के रीयर-एडमिरल
राजस्व बोर्डों के सदस्य

---

* यदि एक पी० एस० ओ० को लेफ्टीनेन्ट-जनरल का ओहदा प्राप्त है, तो उस की अग्रिमता इस अनुसूची की 28वी धारा मे वर्णित "लेफ्टीनेन्ट जनरल या उसी के समान ओहदा रखने वाले अफसरो" को प्राप्त व्यक्तियों के बराबर हो जायगी ।

31. स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधान संचालक
डाक-तार के प्रधान संचालक
गुप्तचर-विभाग के संचालक
रेलवे के जनरल मैनेजर
भारत सरकार के एस्टेब्लिशमेंट अफसर
भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी (मंत्रि-मंडल के ज्वाइंट-सेक्रेटरी भी शामिल है)
मेजर-जनरल या उस के समान ओहदा रखने वाले अफसर
भारत के प्रधान सर्वेयर
भारतीय टैरिफ़ बोर्ड के सदस्य
भारत में नागरिक वायु यात्रा के संचालक
सर्जन-जनरल
सप्लाई और डिस्पोज़ल के संचालक
आर्डिनेंस कारखानों के प्रधान संचालक
जल-सेना के ठहरने के लिये बन्दरगाहों और स्थानों के भारतीय जल-सेना से सम्बन्धित कोमोडोर-इन्चार्ज
हवाई कोमोडोर का ओहदा रखने वाले आई० ए० एफ० के कमांडर
समुद्री और हवाई बेड़े के सदर-मुकाम के पी० एस० ओ०, जिन्हें कोमोडोर और हवाई-कमोडोर का ओहदा प्राप्त है।
अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह, कच्छ, त्रिपुरा और मणिपुर के अपने अधिकारों के बाहर चीफ़-कमिश्नर
आल इन्डिया रेडियो के प्रधान संचालक
राष्ट्रपति के सेना सचिव (जब तक उन को सरकारी अतिथि सत्कार संस्था के प्रधान संचालक का स्थान भी प्राप्त है)
भारत में कामनवेल्थ और विदेशी मिशनों के कौन्सिलर
'क' भाग राज्यों के पुलिस के इंसपेक्टर जनरल
डिवीज़नों के कमिश्नर

नोट 1. अग्रिमता के प्राह्वान का नियम राज्य के सरकारी समारोहों के अवसरों के लिये ही है। अन्य अनौपचारिक अवसरों पर उन का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट 2. यह वारन्ट भारतीय राज्यों और 'ख' भाग के राज्यों के नरेशों की अग्रिमता के नियमों में कोई अन्तर नहीं लायगा और वे उन के स्थानीय रस्म-रिवाजों के अनुसार ही निर्धारित होंगे और न ही यह 15 अगस्त, 1947 के ठीक पहले नरेशों के स्थानीय आपसी अग्रिमता क्रम को प्रभावित करेगा।

नोट 3. अग्रिमता की तालिका में अफ़सर अपने प्रवेश की संख्यानुसार ही दर्जा प्राप्त करेंगे। एक संख्या में शामिल अफसरों की एक दूसरे के मुकाबले में अग्रिमता उन की प्रवेश तिथि के अनुसार निर्धारित होगी।

नोट 4. लोक सभा के सब सदस्यों को एक संग राज्य के प्रमुख समारोहों में आमंत्रित किये जाने के समय उनके बैठने का स्थान राजदूतों, भारत के प्रधान न्यायाधीशों लोक-सभा के अध्यक्ष, राज्यपाल आदि के बाद आयगा ।

नोट 5. गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल के मुकाबले में अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे 31 धारा में उस की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो ।

नोट 6. मेजर-जनरलों को भारतीय-जल-सेना के कमोडोर-इन्चार्ज और भारतीय वायु-सेना के कमोडारों के मुकाबले में अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे 31 धारा मे उन की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो ।

नोट 7. 'क' भाग की राज्य-सरकारो के प्रधान सचिवों को राजस्व-बोर्ड के सदस्यों के मुकाबले मे अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे धारा 30 मे उन की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो ।

नोट 8 अग्रिमता के वारण्ट-सम्बन्धी मामलो मे नई दिल्ली और लाल किला को दिल्ली राज्य से बाहर समझना चाहिये ।

नोबल पुरस्कार विजेता

डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर	साहित्य (1913)
डा० चन्द्रशेखर वेकट रमन	भौतिक-विज्ञान (1930)

रायल सोसायटी के भारतीय फैलो

1 कारसेटजी
2. एस० रामानुजम
3 डा० जे० सी० बोस
4 डा० मेघनाद साहा
5. डा० सी० वी० रमन
6 डा० बीरबल साहनी
7 डा० के० एम० कृष्णन्
8. डा० एम० एस० भटनागर
9 डा० एच० जे० भाभा
10 प्रो० एम० चन्द्रशेखर
11 प्रो० पी० सी० महलानोबिस

कृषि पण्डित

कृषि-अनुसन्धान की भारतीय कौंसिल प्रति वर्ष 'कृषि-पण्डित' की उपाधि उन कृषकों को प्रदान करती है जिन्होंने भारतीय कृषि-क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है । जिन कृषकों को यह उपाधि दी गई है, उन के नाम निम्नलिखित हैं :

वर्ष	नाम	फसल	उत्पादन
1949	गंगासरन किसान (हापुड़, यू० पी०)	आलू	548 मन प्रति एकड़
1950	रत्नप्रकाश (हापुड, यू० पी०)	आलू	679 मन प्रति एकड
1951	माधोकृपाल (हापुड़, यू० पी०)	आलू	726 मन 3 सेर 3 छटाक प्रति एकड
1951	के० वलिया गाउडर (थात्तमपत्ती, मद्रास)	धान	150 मन प्रति एकड़
1951	पदमसिंह (श्यामपुर, यू० पी०)	गेहूं	59 मन 25 सेर 11 छटांक प्रति एकड

वर्ष	नाम	फसल	उत्पादन
1952	जयपालचन्द्र (बुलन्दशहर यू० पा०)	आलू	735 मन 24 सेर प्रति एकड़
1952	जेगमा सी० संगाय्या (अलुर, कुर्ग)	धान	136 मन 5 सेर 14 छटांक प्रति एकड
1952	गु देवसिंह (कलालमाजरा, पंजाब)	गेहूं	71 मन 23 सेर 10 छटाक प्रति एकड
1952	विलायतीराम लम्बरदार (अगवार खाजू बाज, पंजाब)	चना	46 मन 2 सेर 6 छटाक प्रति एकड
1952	भीम-गान्डा दादा पटेल (तामादालगे, बम्बई)	ज्वार	84 मन 23 सेर 5 छटांक प्रति एकड
1952	वामन रामचन्द्र मराठे (बम्बई)	बाजरा	29 मन 11 सेर 10 छटांक प्रति एकड

पर्वतीय स्थान

नाम	वे राज्य जहां ये स्थित हैं	समुद्र तल से ऊंचाई (फुट में)
अल्मोडा	उत्तर प्रदेश	5,500
बंगलोर	मैसूर	3,000
चेरापूंजी	आसाम	4,455
कूनूर	मद्रास	6,740
डलहौजी	पंजाब	7,867
दार्जिलिंग	पश्चिमी बंगाल	7,168
गुलमर्ग	जम्मू और कश्मीर	8,700
कलिम्पोंग	पश्चिमी बंगाल	3,933
कसौली	पंजाब	6,200
कोडाई कनाल	मद्रास	7,000
कुल्लू और कांगड़ा घाटी	पंजाब	4,700
लैंसडाउन	उत्तर प्रदेश	6,060
महाबलेश्वर	बम्बई	4,500
माथेरान	बम्बई	2,650
माउंट आबू	बम्बई	4,500
मसूरी	उत्तर प्रदेश	6,600
नैनीताल	उत्तर प्रदेश	6,350
ऊटकमंड	मद्रास	7,500
पंचमढी	मध्य प्रदेश	4,500
रांची	बिहार	2,100
शिलोंग	आसाम	4,980
शिमला	पंजाब	7,000

सब से ऊंचे पर्वत

	(फुट)
एवरेस्ट (तिब्बत, नेपाल)	29,141
के. 2. गौडविन आस्टिन (कश्मीर)	28,250
कंचन जंघा (नेपाल, सिक्किम)	28,146

	(फुट)
नंगा पर्वत (काश्मीर)	26,653
गशेरब्रम (काश्मीर)	26,470
दिस्ताघित सर (काश्मीर)	25,868
मशेरब्रम (काश्मीर)	25,660
नन्दा देवी (उत्तर प्रदेश)	25,645
राकापोशी (काश्मीर)	25,550
कामेत (उत्तर प्रदेश, तिब्बत)	25,447
चोमो हारी (भूटान, तिब्बत)	23,996
बद्रीनाथ (उत्तरप्रदेश, तिब्बत)	23,190
गंगोत्री (उत्तर प्रदेश)	21,700
बंदरपुछ (पंजाब)	20,720

सब से लम्बे पुल—:

	(फुट)
सोन पुल	10,052
गोदावरी पुल	9,096
महानदी पुल	6,912
हार्डिंग पुल	5,380
विलिंगडन पुल	2,610
हावडा पुल	2,150
गोराइ पुल (1)	1,744
जुबली पुल	1,213
मेघना पुल	1,213

लखनऊ मे गोमती का पुराना लोहे का पुल भारत मे सब से पुराना है।

तौल और माप

फासला :—

1 मील	—	8 फर्लांग या 1,760 गज
1 लीग	—	3 मील
1 किलोमीटर	—	1 मील का $\frac{5}{8}$ वां भाग (3,280.89 फुट)
1 मीटर	—	1.0936 गज

भूमि :—

1 एकड	—	4,840 वर्गगज
1 वर्गमील	—	640 एकड़

द्रव्य :—

1 औंस	—	8 ड्राम
1 पाइंट	—	20 औंस

(1) यह भारत में सब से बड़ा कैंटीलिवर स्पॉन ब्रिज और दुनिया में तीसरा सब से बड़ा कैंटीलिवर ब्रिज है।

4 चाय के भरे चम्मच	—	2 मेवा के भरे चम्मच
	—	1 बडा चमचा
	—	$\frac{1}{2}$ औंस
1 किलोग्राम	—	2.2046 पौंड
1 मीट्रिक टन	—	2,204.6 पौंड

तोल

1 टन	—	26.89 मन
1 बुशल	—	60 पाउंड
1 क्विण्टल प्रति हैक्टर	—	58 मन प्रति बीघा
1 छटाक	—	5 तोला

कागज का माप

डबल क्राउन	—	20″×30″
डबल डिमाइ	—	22″×36″
डबल फुलस्केप	—	17″×27″
फुलस्केप	—	$13\frac{1}{2}$″×17″
क्राउन	—	15″×20″
डिमाइ	—	18″×22″
रायल	—	20″×26″
क्राउन ओक्टावो	—	$7\frac{1}{2}$″×5″
क्राउन क्वार्टो	—	10″×$7\frac{1}{2}$″
क्राउन फोलिओ	—	15″×10″

समय विभाजन

60 पल	—	1 दण्ड
$7\frac{1}{2}$ दण्ड	—	1 प्रहर
8 प्रहर	—	1 दिन

भारत में प्रथम

सब से बडी झील	वुलर झील, काश्मीर
सब से ऊंचा शिखर	नन्दा देवी (25,645 फुट)
सब से बडा शहर	कलकत्ता (हावडा, टौलीगंज आदि को मिला कर) 34,78,745 आबादी
सब से बडा झरना	गेरसोप्पा झरना (960 फुट ऊंचा) मैसूर राज्य
सब से बड़ा राज्य	मध्य प्रदेश (1,30,272 वर्ग मील)
सब से अधिक वर्षा	चेरापूजी (426 इंच प्रति वर्ष)
सब से अधिक वन प्रदेश वाला राज्य	आसाम
सब से बड़ा मुहाना	सुन्दरवन मुहाना (8,000 वग मील)
सब से लम्बा कैंटीलिवर स्पैन पुल	हावड़ा पुल

सब से बड़ा गुहा मन्दिर	हैदराबाद में एलोरा
सब से बड़ी मस्जिद	दिल्ली की जामा मस्जिद
सब से लम्बा आंगन	रामेश्वरम मन्दिर का आंगन (4,000 फुट लम्बा)
सब से लम्बा पुल	सोन पुल
सब से ऊंचा प्रवेशद्वार	बुलन्द दरवाजा, फतहपुर सिकरी, (176 फुट)
सब से लम्बी मूर्ति	गोमतेश्वर की मूर्ति (56 फुट ऊची) मैसूर राज्य
सब से लम्बा प्लैटफार्म	सोनपुर प्लैटफार्म
सब से लम्बी सडक	ग्राण्ड ट्रंक रोड, (1500 मील)
सब से ऊची मीनार	कुतब मीनार, दिल्ली
सब से बडा गुम्बद	गोल गुम्बद, बीजापुर
सब से बडा पशु मेला	सोनपुर मेला
सब से लम्बी नहर	नेपाल, अवध और रुहेलखण्ड मे
सब से बडा चिडिया घर	अलीपुर का चिडियाघर, कलकत्ता
सब से बडा अजायब घर	इण्डिया अजायब घर, कलकत्ता
सब से अधिक आबादीवाला राज्य	उत्तर प्रदेश 6 करोड 32 लाख

विदेश स्थित कूटनीतिज्ञ और व्यापार प्रतिनिधि

देश	नाम	पद	पता
		दूतावास	
अफगानिस्तान	भगवत दयाल .	राजदूत . .	भारतीय दूतावास, शेरे अरठा, काबुल
अर्जनटाइन .	रिक्त. .	राजदूत (चिली के लिये मंत्री भी)	भारतीय दूतावास, लावाल 462 (पाचवी मजिल) ब्यूनोस एयर्स
बेलजियम .	पी० ए० मेनन .	राजदूत (लक्समबर्ग के लिए मंत्री भी)	भारतीय दूतावास, 62, एविन्यू फ्रैंकलिन, रूज़वेल्ट, ब्रुसल्स
ब्राजील .	राजा योगेन्द्र सेन बहादुर, मडी के	राजदूत . .	भारतीय दूतावास, रुआ बाराओ दे फ्लामेंजो, 22 एप्ट० 801-802 रिओ दे जैनेरियो
बर्मा .	के० के० चेत्तूर .	राजदूत . .	भारतीय दूतावास, रानदेरिया बिल्डिग्स, फायरे स्ट्रीट, पो बाक्स न० 751, रगून
चीन .	एन० राघवन .	राजदूत . .	भारतीय दूतावास, 32 लीगेशन स्ट्रीट, (पूर्व), पेकिंग।
चेकोस्लोवाकिया	धर्मवीर .	शा० द-फेय .	भारतीय दूतावास, 22 थनोवस्का, प्राग—3

देश	नाम	पद	पता
मिस्र .	नवाब अली यावर जंग	राजदूत, (लेबनान गणतंत्र, जोर्डन के हैशमाइट राज्य, सीरिया और लीबिया के मंत्री भी)	भारतीय दूतावास नं० 29 शारिया हसन पाशा (फ्लैट 7), जमालक, पो० बाक्स 718, काहिरा
फ्रांस .	एच० एस० मलिक	राजदूत (नार्वे के लिये मंत्री भी)	भारतीय दूतावास, 15 रू एलफ्रेड दिहोदेनक, पैरिस
जर्मनी .	एस० दत्त .	राजदूत (भारतीय फौजी मिशन बर्लिन के अध्यक्ष भी)	भारतीय दूतावास, 262 कोब्लेनज़ोरस्ट्रासे, बोन
इंडोनेशिया .	बी० एफ० एच० बी० तैयबजी	राजदूत . .	भारतीय दूतावास, पो० बाक्स 178, 44 केबन सिरिह, जकार्ता
इरान .	ताराचन्द .	राजदूत . .	भारतीय दूतावास, एविन्यू-शाह रजा, तेहरान
ईराक .	खूबचन्द .	राजदूत-मंत्री .	भारतीय दूतावास, 8/8 सफी-उल दीन अल हिली स्ट्रीट, वजीरिया, बगदाद
आयर्लैंड .	बी० जी० खेर	राजदूत (ब्रिटेन मे भारत के राजदूत भी)	इंडिया हाउस, आलड्विच, लन्दन, डब्ल्यू० सी० 2
इटली .	बी० आर० सेन	राजदूत (यगोस्लाविया के लिये राजदूत भी)	भारतीय दूतावास, द्वारा फ्रान्सिस्को डैन्जे, 36 रोम
जापान .	एम० ए० रऊफ	राजदूत . .	भारतीय दूतावास (नैगाइ बिल्डिंग्स) 5 वी मंजिल नं० 13-20 चोम मारू-नौची, चियोदाकू, टोकियो
मैक्सिको .	जी० एल० मेहता	राजदूत (अमेरिका के लिये भी राजदूत)	भारतीय दूतावास, 2,107, मैसेच्युसेट्स एविन्यू, एन० डब्ल्यू० वाशिंगटन, 8 डी० सी०
नेपाल .	बी० के० गोखले	राजदूत . .	भारतीय दूतावास, काठमाडू
नेदरलैंड्स	बी०एन० चक्रवर्ती	राजदूत . .	भारतीय दूतावास, बुइटेन रूस्टवाग, 2 हेग
स्विट्ज़रलैंड	वाई० डी० गुंडेविया	राजदूत (आस्ट्रिया और वैटिकन के लिये मंत्री भी)	भारतीय दूतावास, 59 थुआ-न्रेस, बर्न
थाइलैंड .	गुरबचनसिंह .	शा० द-फेयर (अस्थायी)	भारतीय दूतावास, 37 थियाथाई रोड, बेंगकाक
टर्की .	सी० एस० झा	राजदूत . .	भारतीय दूतावास, नं० 44 किजिलिरमाक सोकाक, कोसेतेप, अंकारा

देश	नाम	पद	पता
अमेरिका .	जी० एल० मेहता	राजदूत (मेक्सिको के लिये भी राजदूत हैं)	भारतीय दूतावास, मैसेच्यु-सेट्स एविन्यू, एन० डब्ल्यू० वाशिंगटन, 8 डी० सी०
रूस .	के० पी० एस० मेनन	राजदूत (हंगरी के लिये राजदूत भी)	भारतीय दूतावास, नं० 6 और 8, उलित्सा ओबुखा, मास्को
युगोस्लाविया	बी० आर० सेन	राजदूत (इटली के लिये राजदूत भी)	——

हाई कमीशन

देश	नाम	पद	पता
आस्ट्रेलिया .	जनरल के० एम० करिअप्पा	भारत के हाई कमिश्नर (न्यूजीलैण्ड के लिये भी मान्यता प्राप्त)	सिविक सैन्टर, कैनबरा
कैनाडा .	आर० आर० . सक्सेना	भारत के हाई कमिश्नर	200 मैक्लेरन स्ट्रीट, ओटावा
लंका .	सी० सी० देसाई	भारत के हाई कमिश्नर .	गफ्फूर बिल्डिंग, फोर्ट कोलबो, पो० बाक्स 47, कोलम्बो
न्यूज़ीलेंड .	जनरल के० एम० करिअप्पा	भारत के हाई कमिश्नर (कैनबरा में निवास)	——
पाकिस्तान .	एम० एस० मेहता	भारत के हाई कमिश्नर	वालिका महल, जहांगीर सेठना रोड, न्यूटाउन, कराची—5
	बी० के० आचार्य	भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर	बैतुल अमन, मैमनसिंह रोड, पो० आ० रमना, ढाका
	एन० बी० राव	भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर	144 अपर माल, लाहौर
दक्षिण अफ्रीका	रिक्त. .	भारत के हाई कमिश्नर के सचिव	गोक्सन हाउस न० 52, कमिश्नर स्ट्रीट, पो० बाक्स—8,327, जोहानेसबर्ग, (प्रति वर्ष जनवरी से जून तक केपटाउन में निवास और इस अवधि के लिए पता निम्नलिखित है—पो० बाक्स 12, मार्कोनी हाउस, बैरक स्ट्रीट, केपटाउन, तार का पता यह है—हिकोमिण्ड, केपटाउन)
ब्रिटेन .	बी० जी० खेर	भारत के हाई कमिश्नर (आयर्लेण्ड के राजदूत भी)	इंडिया हाउस, आल्डविच, लन्दन डब्ल्यू० सी० 2

लीगेशन

देश	नाम	पद	पता
आस्ट्रिया .	वाई० डी० गुण्डे-विया	मंत्री (स्विटजरलैंड और वैटिकन के लिये मंत्री भी)	लीगेशन आफ इण्डिया, 17 गायेर गासे (एन्ट्रेन्स 2), स्पिटजीगासे वियना
चिली .	रिक्त . .	मंत्री (अर्जेन्टिना के लिये भी राजदूत)	——
डेनमार्क .	ए० सी० नम्बि-यार	मंत्री (स्वीडन और फिनलैंड के लिये भी मंत्री	लीगेशन आफ इडिया, स्ट्रैण्ड वागेओ, 47 स्टाकहोम
इथियोपिया .	मेजर जन० अटल	मंत्री . .	लीगेशन आफ इडिया, पो० बाक्स 528, एडिस-अबाबा
फिनलैंड .	ए० सी० नम्बि-यार	मंत्री (स्वीडन तथा डेनमार्क के लिये भी मंत्री)	लीगेशन आफ इडिया, स्ट्रैण्ड वागेओ, 47, स्टाकहोम
जोर्डन .	नवाब अली यावर जग	मंत्री (मिस्र के लिये राजदूत भी)	भारतीय दूतावास, न० 29 शरिया हसन पाशा (फ्लैट 7), जमालक, पो० बाक्स 718, काहिरा
लेबनान .	नवाब अली यावर जग	मंत्री (मिस्र के लिये राजदूत भी)	भारतीय दूतावास न० 29 शरिया हसन पाशा (फ्लैट 7), जमालक पो० बाक्स 718, काहिरा
लीबिया .	नवाब अली यावर जग	मंत्री (मिस्र के लिये राजदूत भी)	भारतीय दूतावास, न० 29 शरिया हसन पाशा (फ्लैट 7), जमालक, पो० बाक्स 718, काहिरा
लक्समबर्ग .	पी० ए० मेनन .	मंत्री (बेल्जियम के लिये राजदूत भी)	भारतीय दूतावास, 62 एविन्यू फ्राकलिन रूज-वेल्ट, ब्रूसेल्स
नार्वे .	एच० एस० मलिक	मंत्री (फ्रास के लिये राजदूत भी)	——
फिलिपीन	एम० आर० बेग	एनवाय एक्स्ट्रा आर्डि-नरी और मंत्री प्लेनि-पोटेन्शियरि	भारतीय लीगेशन, 510-512 ब्रुक बिल्डिग एस्कोल्टा, मनीला
स्वीडन .	ए० सी० नम्बि-यार	एनवाय एक्स्ट्रा आर्डि-नरी और मंत्री प्लेनिपोटेंशियरि (डेनमार्क और फ़िनलैण्ड के लिये मंत्री भी)	लीगेशन आव इडिया, स्ट्रैण्ड-वैगन, 47 स्टाकहोम

देश	नाम	पद	पता
सीरया .	जे० ए० थिवी .	एनवाय एक्स्ट्राआर्डिनरी और मत्री प्लेनिपोटेशियरि	लीगेशन आफ इण्डिया, शराइ आकिम, दमिस्क, सीरिया
वेटिकन .	वाई० डी० गुण्डेविया .	मत्री (आस्ट्रिया और स्विट्जरलैण्ड के लिये भी मत्री)	——

विशेष मिशन

दश	नाम	पद	पता
मलाया .	एम० गोपाल मेनन	भारत सरकार के प्रतिनिधि	इण्डिया हाउस, 31 ग्रेग रोड, पो० बाक्स० 836, सिगापुर
तिब्बत, भूटान और सिक्किम	बी० के० कपूर	सिक्किम मे राजनीतिक अफसर	सिक्किम मे राजनीतिक अफसर का दफ्तर, गगटौक बिल्डिग (सिलिगुरी, पश्चिमी बगाल से हो कर)
संयुक्त राष्ट्र सघ	आर० दयाल .	सयुक्त राप्ट्र सघ के केन्द्रीय दफतर मे भारत के स्थायी प्रतिनिधि (जिन को एनवाय एक्स्ट्रा आर्डिनरी और मत्री प्लेनिपोटेशियरि का दर्जा प्राप्त है)	सयुक्त राष्ट्रसघ मे भारतीय डेलीगेशन न्यू इण्डिया हाउस, 3 पूर्व 64 वीं स्ट्रीट, न्यूयार्क

कमीशन

देश	नाम	पद	पता
अदन .	ए० एस० धवन	भारत सरकार के कमिश्नर	भारत सरकार के कमिश्नर का दफतर, अदन
ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका	रिक्त . .	भारत सरकार के कमिश्नर (जो दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैंड के कमिश्नर और बेल्जियन कागो और रुआण्डा उरुण्डी के कौन्सल जनरल भी हैं)	इडिया हाउस, ड्यूक स्ट्रीट, पो० बाक्स 2,274 नैरोबी (केनिया)

देश	नाम	पद	पता
ब्रिटिश पश्चिमी इंडीज (ब्रिटिश गायना सहित)	बी० एन० नन्दा .	भारत के कमिश्नर	पो० बाक्स 530 (67 क्वीन स्ट्रीट) स्पेन का बंदरगाह, ट्रीनीदाद बी० डब्ल्यू० आई०
फ़िजी .	एन० वी० राज-कुमार	भारत के कमिश्नर .	विशाल भारतीय बिल्डिंग्स, वैमानू रोड, सुआ
गोल्ड कोस्ट .	रामेश्वर राव .	भारत के कमिश्नर	——
हौंगकौंग .	पी० आर० एस० मनी	भारत के कमिश्नर .	दीना हाउस, दुद्दल स्ट्रीट, हांगकांग
मौरीशस .	ए० एम० सहाय	भारत के कमिश्नर .	शा द मार, पोर्ट लूई, मौरीशस

कौंसुलेट जनरल और कौंसुलेट

देश	नाम	पद	पता
अलेक्जैण्डरिया	रघुनाथ सिन्हा .	भारत के कौन्सल जनरल	
कोपनहागेन .	विक्टर बी. स्ट्रेंड	भारत के आनरेरी कौन्सल जनरल	कौंसुलेट जनरल आव इंडिया, द्वारा लीगेशन आव इंडिया, स्ट्रेण्डवेगन 47—4, स्टाकहोम
जेनेवा .	एस० सेन .	भारत के कौंसल जनरल	भारत के कौंसुलेट जनरल, 1–3 रू शान्तेपौलत, जेनेवा
गोआ .	वी० एच० कोएल्हो	भारत के कौंसल जनरल	भारत के कौंसुलेट जनरल, रुआ आफेन्सो द अलबुकर्क, सिदाद द गोआ
हैलसिन्की .	जहो सावियो .	भारत के आनरेरी कौंसल जनरल	——
जद्दा (सौदी अरब)	एम० के० किदवई	भारत के कौंसल जनरल	भारतीय कांसुलेट जनरल, जद्दा
काशगर (चीन)	रिक्त .	भारत के कौंसल जनरल	भारतीय कौंसुलेट जनरल, चीनी बाग, काशगर
लासा (तिब्बत)	ए० के० सेन .	भारत के कौंसल जनरल	लासा के कौंसल जनरल, पो० आ०-ग्यासी, तिब्बत
मेशेद .	अब्दुल मजीद खान	भारत के कौंसल जनरल	भारतीय कौंसुलेट जनरल, खियाबान जहानबानी, मेशेद (ईरान)
न्यूयार्क .	ए० एस० लाल .	भारत के कौंसल जनरल (मंत्री का व्यक्तिगत दर्जा प्राप्त)	भारतीय कौंसुलेट जनरल, 3, ईस्ट—64 स्ट्रीट, न्यूयार्क

देश	नाम	पद	पता
पाण्डिचेरी .	केवलसिंह .	भारत के कौंसल जनरल	भारतीय कौंसुलेट जनरल, 7 रू द कैपासिन्ज, पांडिचेरी
सैगोन .	ओ० पी० मोहला	भारत के उप-कौंसल .	भारतीय कौंसुलेट जनरल, 213 रूकैतिनात, सैगोन
सानफ्रांसिस्को	एम० ए० हुसैन .	भारत के कौंसल जनरल	भारतीय कौंसुलेट जनरल 417 माटगुमरी स्ट्रीट, सानफ्रांसिस्को
शंघाई .	डी० मुरुगेसन .	भारत के कौंसल जनरल	भारतीय कौंसुलेट जनरल, 219/12 दी बण्ड, शंघाई
मेदन .	आगतसिंह .	भारत के कौंसल	भारतीय कौंसुलेट, 46 दाजालन जोकिया, मेदन (इण्डोनेशिया)
हनोइ .	रिक्त. .	कौंसुलर एजंट .	29, रू द ला शा, हनोइ

उप-कौंसुलेट

देश	नाम	पद	पता
जलालाबाद . (अफगानिस्तान)	डी० सरीन .	भारत के उप-कौंसल .	भारतीय उप-कौंसुलेट, जलालाबाद
कंधार (अफगानिस्तान)	के० एल० एस० पंडित	भारत के उप-कौंसल	भारतीय उप-कौंसुलेट, कंधार
जहीदन .	रिक्त. .	भारत के उप-कौंसल .	भारतीय उप-कौंसुलेट जहीदन (पूर्वी ईरान)

एजेन्सियां

देश	नाम	पद	पता
लंका .	पी० एस० मेनन.	भारत सरकार के एजेंट	पेराडेनिया रोड, कैन्डी
मलय .	टी० वी० रामकृष्ण राव	भारत सरकार के स्थानापन्न एजेंट	पो० बाक्स 59, ओरियन्टल बिल्डिंग्स, दूसरी मंजिल, कौलालम्पूर
ग्यांसी .	मेजर एस० एम० कृष्णत्री	भारतीय व्यापार एजेंट एवं सिक्किम स्थित राजनीतिक अफसर के सहायक	भारतीय व्यापार एजेंसी, ग्यांसी (तिब्बत), द्वारा— सिलीगुरी, प० बंगाल

देश	नाम	पद	पता
गरतौक .	लक्ष्मणसिंह .	भारतीय व्यापार एजेंट एवं सिक्किम स्थित राजनीतिक अफसर के सहायक	भारतीय व्यापार एजेंसी, गरतौक (पश्चिमी तिब्बत) यह दौरा करने वाला दफतर है और इस दफतर के नाम पत्र व्यवहार निम्न-लिखित पते पर करना चाहिये : द्वारा पी० ओ० गन्तौक, सिक्किम
यातुंग .	सोनाम तोबदन काजी	भारतीय व्यापार एजेंट और सिक्किम में राज-नीतिक अफसर के सहायक	भारतीय व्यापार एजेंसी, यातुंग, तिब्बत

भारत में विदेशी कूटनीतिज्ञ

राजदूतावास

देश	नाम	पद	पता
अफगानिस्तान	श्री अब्दुल हुसैन अजीज	राजदूत एक्स्ट्राआर्डि-नेरी और प्लेनिपो-टेंशियरी	24 रेटेंडन रोड, नई दिल्ली
अर्जेन्तीना .	म० म० श्री रेने लासन	"	128 इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली
बेल्जियम .	म० म० श्री स्टीफ़न हैलो	"	24 हार्डिंग एविन्यू, नई दिल्ली
ब्राजील .	म० म० श्री इल्देफोंसो फाल्काओ	"	8 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली
बर्मा .	म० म० श्री ऊ कियन्	"	40 रेटेन्डन रोड, नई दिल्ली
चीन .	म० म० जेन० युआन चुंग सियन	"	1 पुराना किला रोड, नई दल्ली
चैकोस्लोवेकिया	म० म० डा० लादि-स्लाव डुर्दिल	"	25 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली
मिस्र .	म० म० श्री इस्मा-इल कामिल	"	मेडन्स होटल, दिल्ली
फ्रांस .	म० म० काउन्ट स्टानिस्लास ओस्त्रो-रोग	"	16 हार्डिंग एविन्यू, नई दिल्ली
इण्डोनेशिया	म० म० डा० एल० एन० पालार	"	14 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली

देश	नाम	पद	पता
ईरान .	म० म० श्री ए० ए० हैकमत	राजदूत एकस्ट्रा-ऑर्डिनेरी और प्लेनिपोटेंशियरि	5, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली
इराक .	म० म० श्री मुहम्मद सलीम अलरादी	,,	21, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली
इटली .	म० म० डा० अलबेर्टो बेरिओ	,,	17, यार्क रोड, नई दिल्ली
जापान .	म० म० श्री टी० निशियामा	,,	3, सरकुलर रोड, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, नई दिल्ली
मैक्सिको .	श्री लुइस फर्नाडेज मग्रेगोर (सी० डी० ए०)	,,	होटल इम्पीरियल, नई दिल्ली
नेपाल .	श्री जे० एन० सिंघा (शा० द-फेयर)	,,	बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली
नेदरलैंड्स .	म० म० श्री बैरन एफ० सी० ए० वान पालांट	,,	10, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली
पोलैण्ड .	श्री जर्जी ग्रुदजिन्सकी	,,	——
थाइलैण्ड	म० म० लुआंग भद्रवादी	,,	15, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली
टर्की .	म० म० श्री नूमान ताहिर सैमेन	,,	मेडन्स होटल, दिल्ली
अमेरिका .	म० म० श्री जार्ज वी० एलेन	,,	17, रेटेन्डन रोड, नई दिल्ली
सोवियत रूस	म० म० श्री एम० ए० मैन्शिकोव	,,	6, कैनिंग रोड, नई दिल्ली
जर्मनी (सघीय गणराज्य)	म० म० डा० एर्न्स्ट विल्हेल्म मायेर	,,	1, अलबुकर्क रोड, नई दिल्ली
युगोस्लाविया	म० म० श्री डा० गोइको निकोलिस	,,	4, अलबुकर्क रोड, नई दिल्ली

हाई कमीशन

देश	नाम	पद	पता
आस्ट्रेलिया .	म० म० श्री डब्ल्यू० आर० क्राकर	हाई कमिश्नर .	24, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली
कनाडा .	म० म० श्री एस्काट एम० रीड	,,	4, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली
लका .	म० म० श्री कुमारस्वामी	,,	3, हार्डिंग एविन्यु नई दिल्ली
पाकिस्तान .	म० म० श्री गजनफरअली खां	,,	8, बी० हार्डिंग एविन्यू नई दिल्ली
ब्रिटेन .	म० म० सर एलेकजेण्डर क्लटरबक	,,	2, किंग जार्ज एविन्यू, नई दिल्ली

लीगेशन

देश	नाम	पद	पता
आस्ट्रिया .	श्री एलबिन लेख	शा० द-फेयर .	80, सेसिल होटल, दिल्ली
चिली .	म० म० श्री मिगुअल सेरानो फरनादेज	„ .	7, स्विस होटल, दिल्ली
डेनमार्क .	म० म० श्री टायबर्ग फ़ान्सन	एन्वाय एक्स्ट्राआर्डिनेरी और मंत्री प्लेनिपोटेशियरि	7, अलबुकर्क रोड, नई दिल्ली
इथियोपिया .	म० म० श्री गैब्रे मस्केल केफ्लरजी	„	29, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली
फिनलैंड .	म० म० मौंज ह्यूगो वाल्वान्न	„	39, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली
होली सी .	म० म० मोस्ट रेवरैण्ड मार्टिन	एपस्टोलिक इन्टर्नंशियो	8, अलीपुर रोड, दिल्ली
हंगरी .	म० म० श्री पीटरकोस (डेज़िगनेट)	एन्वाय एक्स्ट्राआर्डिनेरी और मंत्री प्लेनिपोटेंशियरि	बी 33, एन० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली
जोर्डन .	रिक्त . .	रिक्त . .	
नार्वे .	म० म० श्री कूण्ट लाइक	एन्वय एक्स्ट्राआर्डिनेरी और मंत्री प्लेनिपोटेंशियरि	29, सेसिल होटल, दिल्ली
फिलीपीन .	म० म० श्री नारसिसो रोमोस	„	78, मेडन्स होटल, दिल्ली
पुर्तगाल .	म० म० डा० वास्को वियरा गारिन	„	22, हार्डिंग एविन्यू, नई दिल्ली
स्वीडन .	म० म० श्री गुस्ताव आदुल्फ विक्यमान	„	11, रेटेन्डन रोड, नई दिल्ली
स्विट्ज़रलैंड	म० म० डा० मेक्स ग्रासिली	„	7, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली
सीरिया .	म० म० डा० यूसुफ लुत्फी बोस्तामी	„	एम्बेसेडर होटल,

परिशिष्ट

राष्ट्रीय नमूनों का परिमाप

भारत की आर्थिक स्थिति का अन्दाज़ा लगाने के लिये 1950-51 मे भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय नमूना परिमाप' का प्रारम्भ किया था। इस परिमाप द्वारा राष्ट्रीय आय और विकास आयोजना के सम्बन्ध में आवश्यक गणनायें और सामग्री एकत्र की जाती हैं। प्रारम्भ में यह देहानी क्षेत्रों के लिये खोला गया था, परन्तु अब शहरी क्षेत्रों मे भी यह कार्य हो रहा है।

परिमाप की आयोजना और सरकार के विश्लेषण का कार्य कलकत्ता के भारतीय स्टेटिस्टिकल इस्टीच्यूट को सौंपा गया था, जो पूना की गोखले इंस्टीच्यूट आफ़ इकौनोमिक्स एण्ड पोलिटिक्स के सहयोग से काम कर रही थी। पहली सस्था ने पश्चिमी बगाल मे कार्य किया है और दूसरी ने बम्बई के 12 दक्षिणी जिलो में।

वित्त सचिवालय के इकोनोमिक अफेयर्स विभाग द्वारा नियुक्त डायरेक्टरेट आफ नेशनल सैम्पल सर्वे ने बाकी क्षेत्रो मे कार्य किया। विभिन्न आर्थिक प्रवृत्तियों तथा विभिन्न कार्यों के उत्पादन और व्यय तथा घरेलू क्षेत्र में उपभोक्ताओ के व्यय के सम्बन्ध मे ये गणनाये एकत्र की गई हैं। ये सूचनाये एक के बाद दूसरी गश्तों में जमा की गई हैं। इस समय तक सात गश्ते की जा चुकी हैं। इन सातो गश्तो के सम्बन्ध मे निम्नलिखित तालिका से जानकारी प्राप्त की जा सकती है :

चक्कर	अवधि	क्षेत्र	नमूनो की सख्या		नमूने के परिवारों की संख्या	
			गाव	शहर	गाव	शहर
थम	अक्टूबर-मार्च 1951	देहाती	1,643	...	26,288	...
द्वितीय	अप्रैल-जून 1951	देहानी	1,106	...	10,947	...
तृतीय	अगस्त-नवम्बर 1951	देहाती और शहरी	863	490	10,165	3,378
चतुर्थ	अप्रैल-सितम्बर 1952	देहाती और शहरी	938	406	25,722	11,713
पचम	दिसम्बर 1952-मार्च 1953	देहाती और शहरी	739	405	12,878	5,942
षष्ट	मई-अगस्त 1953	देहाती और शहरी	949	409	13,150	5,133
सप्तम	अक्टूबर 1953	देहाती और शहरी				

निचली दो तालिकाओं में यह दिखाया गया है कि प्रत्येक घर में उपभोक्ताओं का क्या व्यय आता है। समय को दो भागों में बांटा गया है। पहली तालिका ग्रामीण घरों के सम्बन्ध में है।

(जुलाई 1949 से जून 1950 तक प्रति परिवार की खपत)

वस्तुएं	परिवारों की संख्या	उपभोक्ताओं का व्यय (रुपयों में)		योग का प्रतिशत
		प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति	
1 खाद्यान्न . .	3,139	442.61	85.03	38.70
2 दालें . .	3,139	40.89	7.86	3.58
3 खाद्य तेल . .	3,140	43.31	8.32	3.79
4 सब्जी .	3,141	26.72	5.13	2.34
5 दूध और दूध के पदार्थ	3,141	88.82	17.06	7.77
6 गोश्त, अंडे और मछली	3,141	24.57	4.72	2.15
7 फल . .	3,141	12.15	2.33	1.06
8 जलपान .	3,140	14.10	2.71	1.23
9 नमक .	3,138	4 82	0.93	0.42
10. मिर्च	3,139	31.00	5.95	2.71
11 चीनी .	3,139	29.28	5.62	2.56
कुल खाद्य .	...	758.27	145.66	66.31
12 पान . .	3,140	9.17	1.76	0.80
13 तम्बाकू . .	3,141	20.46	3.93	1.79
14 मादक वस्तुएं .	3,141	8.96	1.72	0.78
15 ईंधन और प्रकाश .	3,139	37.14	7.14	3.25
16 पुरुषों के वस्त्र .	3,123	36.01	6.92	3.16
17 स्त्रियों के वस्त्र .	3,123	42.36	8.14	3.70
18 बच्चों के वस्त्र .	3,123	9.84	1.89	0.86
19 फुटकर वस्त्र	3,123	6.35	1.22	0.56
20. टोपी आदि .	3,123	4.61	0.89	0.40
21 बिस्तर . .	3,123	9.92	1.91	0.87
22 कपड़े सिलवाने का व्यय	3,123	11.43	2.20	1.00
23 जूते . .	3,123	9.66	1.86	0.84
24 मोची को . .	3,123	1.12	0.21	0.10
25 प्रसाधन .	3,123	3.35	0.64	0.29
26 प्रसाधन सेवा .	3,123	5.74	1.10	0.50
27. मनोरंजन .	3,123	6.04	1.16	0.53
28 शिक्षा .	3,123	2.92	0.56	0.26
29 शिक्षा-सेवा .	3,123	4.95	0.95	0.43
30 पत्र-पत्रिकायें आदि .	3,123	0.50	0.10	0.04
31 चिकित्सा व्यय .	3,123	9.19	1.77	0.80

वस्तुएं	परिवारो की संख्या	उपभोक्ताओ का व्यय (रुपयो में)		योग का प्रतिशत
		प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति	
32. चिकित्सा सेवा	3,123	5.35	1.03	0.47
33. फुटकर पारिवारिक सामग्री	3,123	8.25	1.59	0.72
34. घरेलू और पारिवारिक सेवा	3,123	10.41	2.00	0.91
35 खाद्य मेवा	3,123	1.68	0.32	0.15
36. फर्नीचर	3,123	2.87	0.55	0.25
37. फर्नीचर सुधार	3,123	0.73	0.14	0.06
38. बर्तन	3,123	7.24	1.39	0.63
39. उत्सव समारोह	3,123	82.46	15 84	7.21
40. अनावर्तक व्यय	3,123	3.01	0.58	0.26
41 फुटकर (प्रदत्त के अतिरिक्त)	3,123	17.20	3 30	1.50
42 मकान का किराया और कर	3,123	6 51	1 25	0 57
भोजन के अतिरिक्त योग	...	1,143.70	219.72	100.00

भारत के देहाती क्षेत्रों में उपभोग्य वस्तुओं की प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति खपत (अप्रैल 1951 से जून 1951 तक)

वस्तु	नमूने के परिवारों की सख्या	उपभोक्ताओ का 3 महीनो का व्यय—90 दिन (रुपयो मे)		योग का प्रतिशत
		प्रति घर	प्रति व्यक्ति	
1 खाद्यान्न	10,870	154.28	29.04	39.42
2 दाल	10,855	15.43	2.96	4.02
3. खाद्य तेल	10,760	13.37	2.57	3.49
4. सब्जियां	10,860	8.74	1.67	2.27
5 दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ	10,870	24.04	4.50	6.11
6. गोस्त, अंडे और मछली	10,860	7.33	1.41	1.91
7 फल	10,860	7.07	1.29	1.75
8. जलपान	10,860	4.24	0.77	1.05
9. नमक	10,690	1.67	0.26	0.35
10. मसाले	10,859	9.90	1.93	2.62
11. चीनी	10,859	11 31	2.19	2.97
भोजन का योग	...	257.38	48.59	65.96

नोट :—1 वस्तु से लेकर 15 वस्तुओ तक के लिये नमूने के गांवों की संख्या 1,085 थी और 16 वस्तुओं से लेकर 42 वस्तुओं तक के लिये गावों की संख्या 1,079 थी। परिवार का औसत आकार 5.2।

वस्तु	नमूने के परिवारों की संख्या	उपभोक्ताओं का 3 महीनों का व्यय—90 दिन (रुपयों में)		योग का प्रतिशत
		प्रति घर	प्रति व्यक्ति	
12. पान . .	10,860	3.09	0.64	0.87
13 तम्बाकू . .	10,860	7.58	1.41	1.92
14. मद्य पदार्थ .	10,860	3.09	0.51	0.69
15. ईंधन और प्रकाश साधन	10,860	24.04	4.50	6.11
16. कपड़ा (सूती)	10,870	20.34	3.83	5.20
17. कपड़ा (रेशमी) .	10,870	0.52	0.10	0.14
18. कपड़ा (ऊनी) .	10,870	0.60	0.11	0.15
19. बिस्तर .	10,870	1.68	0.32	0.43
20. मनोरंजन .	10,870	2.22	0.42	0.57
21. शिक्षा .	10,870	2.10	0.39	0.53
22. दवा .	10,870	6 00	1.14	1.55
23. प्रसाधन-सामग्री	10,870	1.11	0.21	0 29
24. छोटी-मोटी वस्तुएं	10,870	2.43	0.45	0.61
25 वाहन	10,870	4.92	0 93	1.26
26. सेवायें .	10,870	22.20	4.17	5.66
27. फर्नीचर .	10,870	0.67	0.13	0.18
28. फुटकर सामग्री .	10,870	0.62	0.12	0.16
29. वाद्य-यंत्र	10,870	0.11	0.02	0.03
30 आभूषण	10,870	4.25	0 80	1.09
31. जूते .	10,870	2.39	0 45	0 61
32. बर्तन	10,870	1.08	0.20	0.27
33. उत्सव-समारोह	10,870	18.92	3.56	4.83
34. किराया	10,870	2.84	0.54	0.73
35 कर .	10,870	0.63	0.12	0.16
कुल अन्य व्यय	.	133.43	25 07	34 04
सर्व योग		390 81	73 66	100.00

नोट.—नमूने के गांवों की संख्या 1,142 थी ; परिवार का औसत आकार 5·31

GIPD—HS—13 M. of I. & B.—24-11-54—3000

सविस्तार विवरण के लिए अपने निकटस्थ एयर फोर्स रेक्रूटिंग एडजुटेण्ड को मिलिए अथवा लिखिए

AC-571

13 M of I & B.

दि

पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

(स्थापित १८९५)

प्रधान कार्यालय--८ अन्डर हिल रोड, दिल्ली।

अपने ३०० कार्यालयों तथा समस्त संसार में अपने
प्रतिनिधियों द्वारा बैंकिंग तथा एक्सचेंज की
पूर्ण सुविधाएं प्रस्तुत करता है।

डिपाजिट्स .. ७० करोड़ रुपये से अधिक

लेनदारी...... .....८६ करोड़ रुपये से अधिक

(३० जून, १९५४ के अनुसार)

बी० एन० पुरी

जनरल मैनेजर

FOR HEALTH, PROSPERITY AND EXERCISE

GET A WORLD RENOWNED

'AMARIND' TRICYCLE TO YOUR CHILD

AVAILABLE FROM LEADING DEALERS OF YOUR CITY

NU-LOOK

AMAR INDUSTRIE

MILLERGANJ LUDHIANA

Phone :—340 *Gram* :—**'AMARIND'**

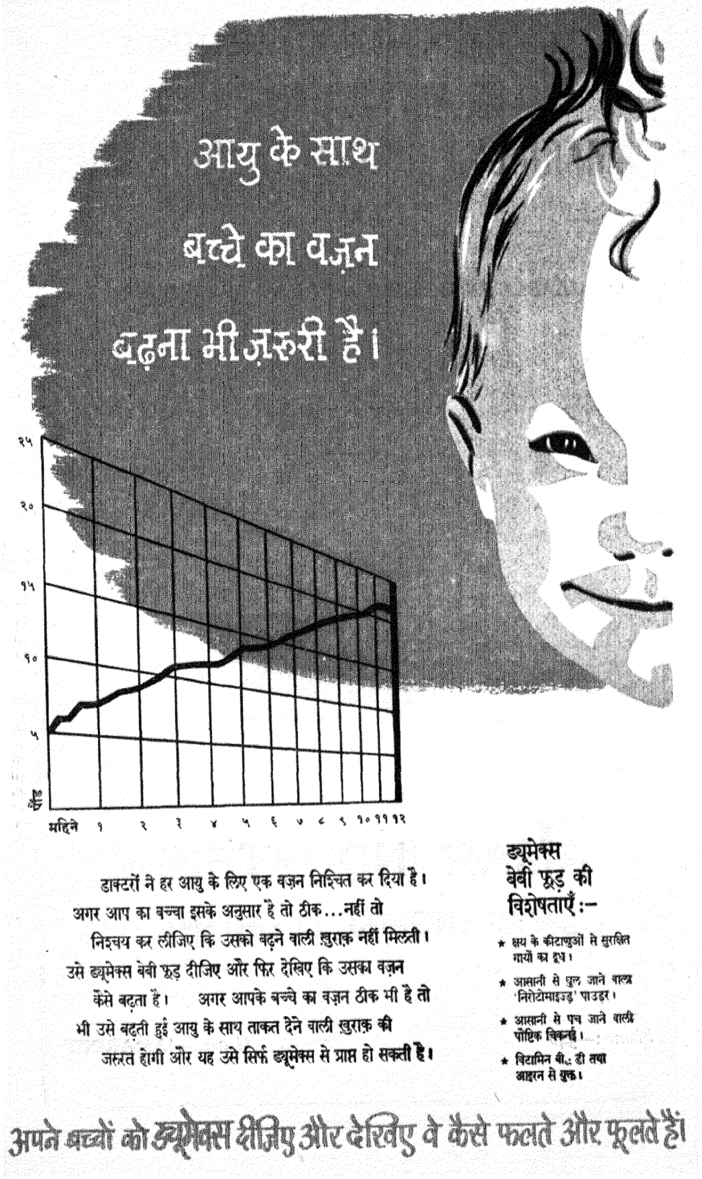
आयु के साथ
बच्चे का वज़न
बढ़ना भी ज़रूरी है।
२५
२०
१५
१०
५
महिने १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२
डाक्टरों ने हर आयु के लिए एक वज़न निश्चित कर दिया है।
अगर आप का बच्चा इसके अनुसार है तो ठीक...नहीं तो
निश्चय कर लीजिए कि उसको बढ़ने वाली ख़ुराक़ नहीं मिलती।
उसे ड्यूमेक्स बेबी फ़ूड दीजिए और फिर देखिए कि उसका वज़न
कैसे बढ़ता है। अगर आपके बच्चे का वज़न ठीक भी है तो
भी उसे बढ़ती हुई आयु के साथ ताकत देने वाली ख़ुराक़ की
जरूरत होगी और यह उसे सिर्फ ड्यूमेक्स से प्राप्त हो सकती है।
ड्यूमेक्स
बेबी फ़ूड की
विशेषताएँ :—
★ क्षय के कीटाणुओं से सुरक्षित गायों का दूध।
★ आसानी से घुल जाने वाला 'निरोटोमाइज़्ड' पाउडर।
★ आसानी से पच जाने वाली पौष्टिक चिकनाई।
★ विटामिन बी., डी तथा आइरन से युक्त।
अपने बच्चों को ड्यूमेक्स दीजिए और देखिए वे कैसे फलते और फूलते हैं।